

# उत्तर प्रदेश वार्षिक रिपोर्ट

१९६०-६१

खण्ड २

सामान्य प्रशासन, भूमि प्रशासन, शांति और व्यवस्था, न्याय वित्त आदि

## विषय-सूची

### अध्याय १—वर्ष की स्थिति

	पृष्ठ-संख्या
(१) वर्षा, बाढ़ और सामान्य दशाएं .. .. .	१

### अध्याय २—नियोजन

(१) नियोजन और विकास कार्य .. .. .	७
(२) प्रशिक्षण और अनुसंधान .. .. .	१८
(३) उत्तराखण्ड क्षेत्र में विकास कार्य .. .. .	२१

### अध्याय ३—उत्पादन और वितरण

(१) कृषि .. .. .	२६
(२) राजकीय फार्म .. .. .	४५
(३) सिंचाई .. .. .	४८
(४) नयी बस्तियां .. .. .	५१
(५) गन्ना विकास .. .. .	५३
(६) पशुपालन .. .. .	५६
(७) मत्स्यपालन .. .. .	६३
(८) वन .. .. .	६३
(९) रिहन्द बांध योजना .. .. .	७३
(१०) उद्योग .. .. .	७६
(११) फल उपयोग .. .. .	८६
(१२) खान और खदानें .. .. .	८८
(१३) सहकारिता आन्दोलन .. .. .	८८
(१४) खाद्य एवं रसद .. .. .	१०२

### अध्याय ४—यातायात, सड़कें और इमारतें

(१) सड़कें, पुल और भवन .. .. .	११५
(२) यातायात .. .. .	१२२

### अध्याय ५—जन-स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं

(१) जन-स्वास्थ्य .. .. .	१३७
(२) चिकित्सा सहायता .. .. .	१४४



	पृष्ठ-संख्या
(क) एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली .. ..	१४४
(ख) आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली .. ..	१५६
(ग) होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली .. ..	१५८

### अध्याय ६—शिक्षा, अनुसंधान आदि

(१) शिक्षा .. ..	१५६
(२) सैनिक स्कूल .. ..	१७३
(३) प्राविधिक और औद्योगिक शिक्षा .. ..	१७४
(४) प्राविधिक शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड .. ..	१७५
(५) रुड़की विश्वविद्यालय .. ..	१७६
(६) राजकीय वेधशाला, नैनीताल .. ..	१७७
(७) स्मारक सुरक्षा .. ..	१७८
(८) राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय .. ..	१७८
(९) संग्रहालय और पुस्तकालय .. ..	१७८
(१०) राजकीय अभिलेखागार .. ..	१८०
(११) साहित्यिक प्रकाशन .. ..	१८०
(१२) राजभाषा .. ..	१८०
(१३) सूचना और प्रचार .. ..	१८२

### अध्याय ७—कल्याण, उत्थान और सहायता तथा पुनर्वास

(१) अन्न-कल्याण .. ..	१८६
(२) समाल-कल्याण .. ..	१८४
(३) हरिजन-उत्थान और सुधार .. ..	१८६
(४) सहायता तथा पुनर्वास .. ..	००

### अध्याय ८—स्थानीय निकायों के कार्य

(१) पंचायते .. ..	२०४
(२) नगर महापालिकाएं .. ..	२०५
(३) नगरपालिकाएं .. ..	२०७
(४) जिला बोर्ड (अन्तरिम जिला परिषदे) .. ..	२०६
(५) नोटीफाइड एरिया .. ..	२१०
(६) टाउन एरिया .. ..	२११
(७) इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट .. ..	२१५
(८) नगर और ग्राम-नियोजन .. ..	२१५
(९) गृह-निर्माण .. ..	२१६
(१०) स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग .. ..	२१८

## अध्याय ६—प्रकीर्ण

				पृष्ठ-संख्या
(१) अर्थ और संख्या	..	..	..	२२०
(२) मुद्राण एवं लेखन-सामग्री	..	..	..	२२०
(३) सरकारी वर्कशाप	..	..	..	२२१
(४) श्री बदरीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर	..	..	..	२२२
(५) भेला	..	..	..	२२३
(६) पर्यटन	..	..	..	२२३
(७) चिडियाघर	..	..	..	२२३

## टिप्पणी

इस खंड में दिये गये विवरण सामान्यतः वित्तीय वर्ष १९६०-६१ से संबंधित है। जहाँ विशेष कारणों से वित्तीय वर्ष का अनुसरण करना संभव नहीं था वहाँ इस संबंध में नीचे दी गयी टिप्पणियों द्वारा आलोच्य समयावधि दर्शित कर दी गयी है।

---

# उत्तर प्रदेश राज्य-वार्षिक रिपोर्ट १९६०-६१

खंड १

अध्याय १

वर्ष की स्थिति

१-वर्षा, बाढ़ और सामान्य स्थित आदि

सामान्य

१९६०-६१ में सामान्यतः राज्य में मौसम प्रतिकूल रहा और वर्ष के उत्तरार्द्ध में कई बाढ़ आयीं।

कृषि की दृष्टि से १३६७ फसली वर्ष साधारण नहीं कहा जा सकता। राज्य में, विशेषतः पूर्वी जिलों में, सूखे की गंभीर स्थिति के कारण खरीफ की फसल नष्ट हो गयी। पिछली बरसात में मानसून देर में शुरू हुआ और जुलाई, १९५९ के दूसरे सप्ताह तक छिट-पुट और मामूली वर्षा होती रही। जुलाई के तीसरे, चौथे तथा अगस्त के पहले सप्ताहों में बारिश जरूर हुई, लेकिन सामान्यतः आवश्यकता से कम, अनिश्चित और कहीं कम तथा कहीं ज्यादा। अगस्त के दूसरे पखवारे के बाद बारिश एकाएक बन्द हो गयी और विशेषकर पूर्वी जिलों में सूखे के लक्षण दिखायी पड़ने लगे। सूखे की स्थिति सितम्बर, १९५९ के तीसरे सप्ताह तक बनी रही, जिससे बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, देवरिया, फैजाबाद, गोडा, बहराइच, मुल्तानपुर और प्रतापगढ़ जिलों में खरीफ की खड़ी फसल को काफी क्षति पहुंची।

१९६०-६१ में मौसम की स्थिति का विवरण

आलोच्य वर्ष के अप्रैल मास में मौसम मुख्यतः गरम और सूखा रहा। पहले हफ्ते में मेरठ, रहेलखंड, गोरखपुर और फैजाबाद डिवीजनों में छिटपुट वर्षा हुई। अप्रैल के शेष दिनों में राज्य में प्रायः बिलकुल ही वर्षा नहीं हुई। मई का पहला पखवारा भी सूखा ही गया, लेकिन दूसरे पखवारे में हल्की बूदा-बांदी प्रायः सारे राज्य में हुई।

जून के महीने में बदली छापी रही और अधिकांश जिलों में समय-समय पर बूदा-बांदी भी हुई। इसके बाद सारे राज्य में काफी बारिश हुई। जुलाई के दूसरे सप्ताह में मानसून ने अपना पूरा रंग दिखाया और मेरठ, रहेलखंड, गोरखपुर, कुमायू, लखनऊ और फैजाबाद डिवीजनों में अत्यधिक वर्षा हुई और दूसरे क्षेत्रों में भी भारी वरसात हुई। मौसम गरम रहा और बदली छापी रही। अगस्त के पहले पखवारे में कई जिलों, विशेषकर झांसी डिवीजन में अत्यधिक बारिश हुई और राज्य के शेष जिलों में औसत बरसात हुई। दूसरे पखवारे में अधिकांश जिलों में भारी वर्षा हुई और मेरठ तथा आगरा डिवीजनों में अत्यधिक पानी बरसा। सम्पूर्ण प्रदेश में मौसम नम रहा तथा बादल घिरे रहे।

सितम्बर के पहले सप्ताह में बरेली, शाहजहापुर, पीलीभीत, रामपुर, नैनीताल, हरदोई, सोतापुर, गोडा और बहराइच जिलों में अत्यधिक पानी बरसा और राज्य के शेष जिलों में हल्की बूदाबांदी हुई। फिर भी झांसी डिवीजन के जिलों में बरसात अपर्याप्त हुई। दूसरे पखवारे

में प्रायः समूचे राज्य में कहीं हल्की और कहीं काफी अधिक वर्षा हुई। सामान्यतः जहाँ पहले पखवारे में बदली छाई रही वहाँ मास के दूसरे पखवारे में आकाश साफ रहा। अक्तूबर के पहले पखवारे में पुनः बदली छा गयी और मैनपुरी, बरेली, बदायूँ, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, रामपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, बादा, झाँसी, जालौन, नैनीताल, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, खीरी और बहराइच जिलों में इस अवधि में अत्यधिक वर्षा हुई। शेष महीने में प्रायः वर्षा नहीं हुई और मौसम ठंडा तथा आसमान साफ हो गया। दिसम्बर के आखिरी सप्ताह को छोड़ कर नवम्बर और दिसम्बर के महीने में बरसात नहीं हुई। दिसम्बर के आखिरी हफ्ते में मेरठ, आगरा, ग्वालियर, कुमायूँ और उत्तराखण्ड डिवीजनों में हल्की बरसात हुई। फिर भी दिसम्बर खतम होते-होते आकाश में बादल छाये रहे।

जनवरी, १९६१ में पहले और आखिरी हफ्ते में सारे राज्य में हल्की और छिटपुट बरसात हुई और बाकी महीने भर पानी नहीं गिरा। महीने के अधिकांश हिस्से में मौसम ठंडा रहा और बादल घिरे रहे। फरवरी के पहले पखवारे में देहगढ़, अल्मोड़ा, गढ़वाल और खीरी जिलों में भारी बरसात हुई और शेष भागों में औसत वर्षा हुई। अधिकांशतः मौसम सूखा, ठंडा और साफ रहा। मार्च में मौसम प्रायः गरम, साफ और सूखा रहा और समय-समय पर गोरखपुर और फैजाबाद डिवीजनों के जिलों में तेज पछवा हवा चलती रही।

## बाढ़

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष भयंकर बाढ़ें आयीं। कुछ जिलों में तो ऐसी बाढ़ें पहले कभी आयीं ही न थीं। मानसून समय से आया। जुलाई, १९६० के पहले पखवारे में हुई भारी वर्षा से पटुची क्षति को छोड़ कर खरीफ की अच्छी फसल मिलने की सम्भावना थी। जुलाई के पहले पखवारे की भारी बरसात जो विशेषकर मथुरा, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, हरदोई, प्रतापगढ़ और बाराबंकी जिलों में हुई थी, वह पूरे मास की सामान्य औसत वर्षा से अधिक थी और उसके परिणामस्वरूप यहाँ की नीची जमीन में पानी भर गया और वहाँ की छोटी नदियाँ नालों में बाढ़ आ गयी। अगस्त, १९६० के पहले पखवारे में राज्य के कतिपय जिलों में पुनः ज्यादा पानी गिरने के फलस्वरूप खरीफ की अच्छी फसल पाने की आशा पर पानी फिर गया। फिर सितम्बर के प्रथम सप्ताह और अक्तूबर के पहले पखवारे में राज्य के कुछ जिलों में जैसे पीलीभीत, सीतापुर, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, बदायूँ, रामपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, जालौन, लखनऊ, हरदोई, खीरी, बहराइच और बाराबंकी में असाधारण बारिश हुई, फलतः भयंकर बाढ़ें आयीं और इन जिलों के निचले हिस्सों में पानी भर गया।

लखनऊ जिले में गोमती नदी की बाढ़ ने सभी पिछले रिकार्ड तोड़ दिये और बाढ़-स्तर ३७१.४५ फुट तक पहुँच गया, जबकि इसके पहले १९२३ का बाढ़ बिन्दु ३६८ फुट था जो अब तक की बाढ़ों में उच्चतम बिन्दु था। इस नदी ने लखनऊ नगर में तहलका मचा दिया और इसके मकानों तथा अन्य सम्पत्ति को अभूतपूर्व क्षति पहुँची। नगर के निचले क्षेत्र पानी में पूर्णतः डूब गये और इन क्षेत्रों के निवासियों की सामान्य जीवनचर्या लगभग एक सप्ताह तक अव्यवस्थित रही। गोमती नदी के इन पार और उस पार के क्षेत्रों को जोड़ने वाला लोहे का पुल बाढ़ से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ और उसका एक भाग तो पूरी तरह बह गया। इस वर्ष राज्य में बाढ़ों से हुई हानि का अनुमान नीचे के आंकड़ों से दिया जा सकता है —

### (१) प्रभावित क्षेत्र—

एकड़

(क) कृषि क्षेत्र ..	..	..	५२,४१,२२३
(ख) पानी लगा क्षेत्र ..	..	..	२७,६०,७४६
(२) प्रभावित गावों की संख्या ..	..	..	२७,३०१

## (४) जीवन-हानि

(क) मनुष्य

३१३

(ख) पशु

२,७,१५

## बाढ़ आदि संबंधी सहायता कार्य

बाढ़ और अत्यधिक वर्षा के सिलसिले में सरकार ने तत्काल ही पर्याप्त सहायता पहुंचायी ।  
३१ मार्च, १९६१ तक स्वीकृत राशियों का व्यौरा इस प्रकार था—

	रुपया
(१) मुफ्त सहायता, जिनमें बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के फलस्वरूप डूब गये या अंशतः क्षतिग्रस्त मकानों के लिये आर्थिक सहायता भी शामिल थी	२६,२५,१६२
(२) टेस्ट वर्क और सहायता कार्य	१६,६०,०००
(३) अधिनियम १२ के अधीन तकावी (जिसमें सामान्य आपद् और गृह निर्माण तकावी भी सम्मिलित थी)	१,०५,००,०००
(४) अधिनियम १६ के अधीन तकावी	१०,००,०००
योग	१,६१,१५,१६२

बाढ़ के सिलसिले में सरकार द्वारा दी गयी कुछ अन्य सहायता का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

(क) खाद्यान्नों की बढ़ती हुई कीमतों का सामना करने और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के निवासियों को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से भारत सरकार से बड़ी मात्रा में आयात किया हुआ गेहूं उपलब्ध किया गया और उसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाया गया । यह गेहूं दाम के दाम पर सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से बेचा गया किन्तु गोदामों से दूर देहातों तक गेहूं ले जाने के भाड़े के लिए सरकार ने आर्थिक सहायता दी । रियायती दरों पर मोटे अनाज जैसे चना, बाजरा, जौ, बैजरा, ज्वार, मक्का आदि बिक्री करने हेतु दिये गये । वर्ष में इस मद पर सरकार को १६.६४ लाख रुपया खर्च करना पड़ा । अल्मोड़ा, गढ़वाल, देहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के पहाड़ी जिलों से भी सरकार को निकटतम रेलवे गोदाम से वितरण केन्द्र तक प्रति मन ४ रुपया अधिक की दर से पूरा-पूरा परिवहन भाड़ा उठाना पड़ा । अकेले इसी मद पर सरकार को लगभग १८.५० लाख रुपये का खर्च उठाना पड़ा ।

(ख) बाढ़ के बाद मलेरिया, हैजा और पशुओं की बीमारियां सामान्यतः फैलती हैं । अतएव संबंधित अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उनकी रोकथाम संबंधी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये । लखनऊ नगर महापालिका के सहयोग से लखनऊ जिले में सफाई संबंधी व्यवस्था करने हेतु उत्तर प्रदेश के जनस्वास्थ्य तथा चिकित्सा निदेशक को ४,४५,००० रुपये की एक विशेष धनराशि दी गयी । पेल्यूडीन तथा अन्य औषधियों के वितरण और हैजे का टीका लगाने की भी व्यवस्था की गयी ।

(ग) वन विभाग द्वारा बांस, बल्लियों, फूस आदि इमारतों सामान की सप्लाई करने की व्यवस्था की गयी । ये सामान आपद्ग्रस्त व्यक्तियों को खरीद के भाव दिया गया और उनका परिवहन भाड़ा तथा अन्य प्रासंगिक व्यय सरकार ने वहन किया ।

इस संबंध में परिवहन भाड़ा तथा प्रासंगिक खर्च को पूरा करने के लिए जिला अधिकारियों को २,५५,००० रुपये की रकम दी गयी। जिला अधिकारियों को यह अधिकार भी दिया गया कि वे उपयुक्त व्यक्तियों को ये सामान मुफ्त दे सकते थे। और इस खर्च को 'भुक्त सहायता' के मद में डाल सकते थे।

(घ) जिन जिलों में मवेशियों के चारे के बारे में अभाव की आशंका थी, वहाँ सरकारी जंगली से जंगली घास सप्लाई करने का प्रबन्ध किया गया। बाढ़-प्रभावित क्षेत्रों के पास-पड़ोस के सुरक्षित सरकारी वनों को चराई के लिए खोल दिया गया। जहाँ जरूरी था सस्ती दरों पर भूमा सप्लाई किया गया और परिवहन भाड़ा तथा अन्य प्रासंगिक खर्चों को सरकार ने वहन किया।

(च) बाढ़ में बह गये गांवों को ऊँचे स्थलों पर बसाने के काम की ओर विशेष ध्यान देने के निर्देश जिला अधिकारियों को दिये गये। नियोजित आधार पर मकान बनाने में जनता को सक्रिय सहयोग देने के लिए कहा गया और इस कार्य के लिए गांव-समाज तथा वन विभाग की जमीन यथासंभव उपलब्ध करायी गयी।

(छ) बाढ़ प्रभावित जनता को रोजगार देने की सुविधा देने के उद्देश्य से वैभागीक कार्यों की गति तेज की गयी। जिन क्षेत्रों में इन कार्यों का कार्यान्वयन नहीं हो रहा था, वहाँ टेस्ट वर्क शुरू किये गये और १६,६०,००० रुपये इन कार्य के लिए स्वीकृत किये गये।

(ज) बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों के निर्माण और मरम्मत के लिए पहले किसानों के लोंगों की ऋण सीमा २५० रुपये प्रति परिवार थी। इस ऋण-सीमा को पंचमहानगरियों के लिए बढ़ा कर २,००० रुपये और अन्य नगरों के लिए १,००० रुपये कर दिया गया।

(झ) आलोच्य वर्ष के पहले शहरी क्षेत्रों के लिए गृह निर्माण संबंधी आर्थिक सहायता की सीमा प्रति परिवार ५० रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति परिवार २५ रुपये थी। इस सीमा को बढ़ा कर पंचमहानगरियों के लिए २०० रुपये, अन्य नगरों के लिए १०० रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ५० रुपये कर दी गयी।

(ट) पंच महानगरियों के किसानों के लोंगों को अधिक से अधिक ५०० रुपये प्रति परिवार आपदा अनुदान और राज्य के अन्य नगरों के लिए प्रति परिवार २५० रुपये का अनुदान देने की जिला अधिकारियों को अनुमति दी गयी।

(ठ) आर्थिक सहायता के आधार पर ग्राम सभाओं को देशी नावें सप्लाई करने का प्रबन्ध किया गया। वर्ष के आरम्भ में १,१२४ देशी नावें, २८ निरीक्षण बजरे तथा अन्य प्रकार की नावे उपलब्ध थीं। साथ ही ६२ नयी नावों के निर्माण के लिए धन की व्यवस्था की गयी।

(ड) रबी, १३६७ फसली के सरकारी मतालबों यथा मालगुजारी, तकावी, झहर तथा बीज के बकायों की वसूली खरीफ १३६८ की वसूली शुरू होने तक स्थगित कर दी गयी, क्योंकि बाढ़ और अत्यधिक वर्षा के कारण फसल की क्षति पहुंची थी।

## ओले और तूफान

मार्च के महीने में ओले पड़ने और तेज पछवा हवा चलने से रबी की उपज पर नुकसान-बेह प्रभाव पड़ा। उसके बाद अप्रैल के पहले हफ्ते में कई जिलों में तूफान आये। इससे जनहानि और पशुहानि तो हुई ही, साथ ही खलिहान में मड़ाई के लिए पड़ी उपज को भी

## अग्निकांड

अग्निकांडों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई। राज्य के लगभग ३७ जिलों से अग्नि-कांड की सूचनाएँ मिलीं और लगभग ४,१५२ आग इससे प्रभावित हुए। कुल मिलाकर ४२७ जनहानि और २,८०४ पशुहानि हुई तथा ४८,१२३ घर नष्ट हो गये। अग्निकांड सशाहजहापुर के जिले में सबसे अधिक तहलका मचा। वहाँ इसके फलस्वरूप १०३ जनहानि और ८३३ पशुहानि हुई। अग्निकांडों से वस्तु जनता को मुफ्त सहायता के रूप में वितरित करने के लिए सरकार ने ३,५४,००० रुपये की धनराशि स्वीकृत की।

## तकाबी

राजस्व वर्ष १९५६-६० में उर्वरक, खाद, कृषि-उपकरण, बैल, बीज, दुग्धशाला कार्य न लिए, गाँवों, मुधरे कोल्हूओं और कड़ाहों की खरीद तथा अग्निकांड बाढ़, सूखा, ओले पड़ने के कारण पीड़ित व्यक्तियों की सहायता और बाढ़ एवं अत्यधिक वर्षा से क्षति-ग्रस्त मकानों के निर्माण और मरम्मत तथा नल-नूत, रूट और पंपिंग प्लांट लगाने, गहरी बोरिंग कुएं गलाने, बाँधिया बनाने तथा उनकी मरम्मत, ट्रैक्टरों की खरीद, कृषि क्षेत्रों में भूमि संरक्षण कार्य करके उनका सुधार करने, पूर्वी जिलों के लिए पक्के कुओं की विशेष योजना और पहाड़ों जिलों में गूलों के निर्माण आदि के लिए २,५७,५६,३०७ रुपये की तकाबी (१,५३,४५,७१७ रुपये १८८४ के अधिनियम १२ के अधीन तथा १,०४,१३,५६० रुपये १८८३ के अधिनियम १६ के अधीन) दी गयी।

आलोच्य वर्ष में दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत ७७,१३,०५७ रुपये की कुल धनराशि स्थगित की गयी और कुल २,६७,१७,८०२ रुपये जमा हुए।

## राजस्व की छूट और स्थगन

फसली १३६७ की रबी की फसलों को ओले, पछुवा (हवा), सूखा तथा अग्नि से काफी नुकसान पहुंचा। इन विपत्तियों के फलस्वरूप हुए कष्टों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने सहायता के रूप में राजस्व में ४१,३२,१८२ तथा २,२६५ की क्रमशः छूट दी तथा स्थगन किया। फसली १३६८ की खरीफ के फसलों को भी बाढ़, अत्यधिक वर्षा तथा भूमि के जलग्रस्त होने के कारण व्यापक हानि उठानी पड़ी जिसके फलस्वरूप राजस्व में सहायता देने की आवश्यकता पड़ी। किसानों के क्लेशों को कम करने के लिए, राज्य सरकार ने राजस्व में ६७,६२,५६२ रुपयों तथा ७,३६,४६८ रुपयों की क्रमशः छूट दी तथा स्थगन किया।

## टिड्डियाँ

फसल सुरक्षा अमले ने उन सभी स्थानों का सर्वेक्षण किया जहाँ-जहाँ टिड्डियाँ गयी थीं, विशेष करके अलीगढ़, बदायूँ, फाँवा, शाहजहापुर, उन्नाव, रायबरेली, सहारनपुर, मेरठ, बुन्दशहर, मथुरा, आगरा, एटा, मैनपुरी, झाँसी, हमीरपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, मुजफ्फरनगर तथा आजमगढ़ जिलों में। यह पता लगाने के लिए कि किन्हीं क्षेत्रों में टिड्डियों ने अंडे दिये हैं या नहीं, कर्मचारियों के सभी संभव कदम उठाये परन्तु जिन जिलों में टिड्डियों का आक्रमण हुआ उनमें से किली में भी टिड्डियों के अंडे नहीं मिले। राजस्व, नियोजन तथा शिक्षा विभागों के अमलों के सहयोग से फसल सुरक्षा कर्मचारियों ने व्यापक रूप में नियंत्रक कदम उठाये, जिनके फलस्वरूप लगभग १,६६६ मनु टिड्डियाँ मारी गयीं। विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों, राज्य भर में सार्वजनिक कार्यकर्ताओं तथा ग्रामीणों को टिड्डियों विरोधी प्रयासों में प्रशिक्षित किया गया। टिड्डियों विरोधी प्रयासों से संबंधित साहित्य का भी वितरण किया गया।

## जोताईवाला क्षेत्र

बारी-बारी से फसलों की बुआई, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने तथा बुआई के वक्त मौसम अच्छा रहने के फलस्वरूप खरीफ की फसलों का क्षेत्र १६७८-५६ के २,६६,६५,४०६

एकड़ों की तुलना में सन् १९५६-६० में बढ़ कर २७१,०६,१५४ एकड़ हो गया। सितम्बर में वर्षा की कमी के कारण रबी की बुवाई के समय जमीन में नमी की कमी आ गयी जिसके फलस्वरूप रबी की बुवाई के क्षेत्र में कमी हो गयी। १९५८-५९ में २,४८,४५,७६६ एकड़ों से गिर कर आलोच्य वर्ष में यह २,४६,२६,८६३ एकड़ रह गया। जायद फसलों का क्षेत्र भी १९५८-५९ के २,३८,७२६ एकड़ों से घट कर २,२१,३८४ एकड़ रह गया।

राज्य भर में जोती गयी भूमि का क्षेत्र पूर्वगामी वर्ष के ५,२०,४६,६०१ एकड़ों की तुलना में इस वर्ष ५,१६,६०,४०१ एकड़ रहा। पूर्वगामी वर्ष के ४,०५,७३,४१५ एकड़ों की तुलना में इस वर्ष जोती हुई भूमि का वास्तविक क्षेत्र ४,०७,६१,८७८ एकड़ था।

### सिंचित क्षेत्र

वर्षा के एक प्रकार से अभाव के बावजूद सिंचन सुविधाओं में वृद्धि होने के फलस्वरूप राज्य में सिंचित क्षेत्र १९५८-५९ के १,२०,६१,८६६ एकड़ से बढ़ कर १,२६,५८,६३० एकड़ हो गया।

वर्ष में बनाये गये पक्के कुओं की संख्या १५,५६० थी। इस प्रकार के कुओं की अधिकतम संख्या अलीगढ़ जिले में थी। वास्तव में सिंचाई के उपयोग में आने वाले कच्चे और पक्के कुओं की संख्या आलोच्य वर्ष में क्रमशः १,५८,४१८ और ६,५४,४३६ थी।

### कीमतें

कृषि उपज की थोक कीमतों का स्तर जो पूर्व वर्ष मंदी की ओर था १९६०-६१ में महंगी की ओर बढ़ा। कृषि की थोक कीमतों का औसत सामान्य सूचकांक (१९४८=१००) ६७.६ था जबकि १९५६-६० में यह ६६.१ था, जिससे १.८ प्रतिशत की वृद्धि का पता चलता है। औद्योगिक थोक कीमतें (१९४८=१००) महंगी की ओर बढ़ती रही और औसत सामान्य सूचकांक १२४.० हुआ जबकि १९५६-६० में यह ११६.३ (संशोधन) था। कृषि समानान्तर सूचकांक (१९४८=१००) जिसका उद्देश्य कीमतों की घटी-बढ़ी का किसानों पर पड़ने वाले शुद्ध प्रभाव का परिलक्षण है, १९५६-६० के ८७.७<sup>१</sup> (संशोधन) से गिर कर ८४.४ हो गया।

---

नोट—जोताई वाले क्षेत्र तथा सिंचित क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेदों का संबंध ३० जून, १९६० को समाप्त होने वाले फसली वर्ष से है।



## अध्याय २

### नियोजन

#### १ नियोजन और विकास कार्य

##### सामान्य

इस वर्ष सामुदायिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को प्रगाढ़ रूप दिया गया, नयी योजनाएँ चालू की गयीं और तीसरी पंचवर्षीय योजना बनायी गयी। गावों में पंचायत चुनाव भी कराये गये। क्षेत्र विकास समिति और जिला परिषद विधेयक, १९६० विधान मंडल द्वारा पारित किया गया जो पंचायत की धारणा को मूर्तरूप देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम था। इस विधेयक द्वारा प्रस्ताव किया गया था कि खंड और जिला स्तरों पर विधि-सम्मत सस्थायें कायम की जायें और उन्हें कुछ अधिकार दिये जायें तथा गाव पंचायतों से उनका संबंध हो सके। सरकारी कार्यों के लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत की प्रगति की दिशा में इसके द्वारा निश्चित कदम उठाया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में उचित रूप में स्वायत्त शासन चलाना इसके जरिये सुनिश्चित हो गया। राज्य में इस वर्ष खाद्य उत्पादन १४१ लाख टन तक हो गया और इस प्रकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य से ऊपर पहुंच गया। खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के निमित्त छोटी सिंचाई के कार्यक्रम में प्रगढ़ता लाने के प्रयत्नों को और बल मिला।

##### योजना की तैयारी

सन् १९५६ में योजना आयोग ने राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का परिणाम २५३.०६ करोड़ रुपये के खर्च जाने का अनुमान किया था। राज्य योजना के प्रथम चार वर्षों में १७७.२४ करोड़ रुपये के व्यय होने का अनुमान था। सन् १९६०-६१ के वर्ष में राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के लिए २ करोड़ लागत के विशेष कार्यक्रम को छोड़कर अधिकतम ५३ करोड़ रुपये व्यय करना स्वीकृत हुआ। १९६०-६१ की राज्य विकास योजना की रूपरेखा तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा गया कि पूरी हो चुकी योजनाओं से पूरा-पूरा लाभ उठाया जाय और पूरक धन लगाने की बात को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाय। बड़ी योजनाओं की पूर्ति में शीघ्रता लायी जाय और नियोजित क्षेत्रिक विकास के विचार को व्यावहारिक रूप दिया जाय। वार्षिक योजना की रूपरेखा में तीसरी पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं के परीक्षण और पर्यालोकन पर होने वाले प्रारम्भिक व्यय को भी सम्मिलित कर लिया गया। इस वर्ष वार्षिक योजना के अन्तर्गत होने वाली धनराशियों का सदुपयोग शीघ्रता से करने के प्रयत्न किये गये। इस वर्ष के व्यय का संशोधित अनुमान ५४.७५ करोड़ रुपये था।

राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप बनाने का कार्य इस वर्ष हाथ में लिया गया और १४ कार्यदल संगठित किये गये ताकि तीसरी योजना की आवश्यकताओं के संबंध में और अध्ययन करने के लिए कार्याधार बन सके। कार्यदलों द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव और राज्य सरकार द्वारा किये गये और अध्ययन के फलस्वरूप ७२४.६४ करोड़ रुपये की लागत की तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप योजना आयोग के सम्मुख सितम्बर १९६० में प्रस्तुत किया गया।

आयोग ने राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजना पर अधिकतम ४६७ करोड़ रुपये व्यय किये जाने की संस्तुति की। इसमें उत्तराखंड योजनाओं पर व्यय होने वाले २८ करोड़

रुपये भी शामिल थे। तदनुसार मार्च, १९६१ में तीसरी पंचवर्षीय योजना का संशोधन और अंतिम प्रारूप प्रकाशित किया गया और उसे योजना आयोग तथा अन्य मंत्रालयों को प्रेषित किया गया।

विभिन्न स्तरों पर योजना की रूपरेखा बनाने के कार्य पर काफी ध्यान दिया गया और ग्राम, खंड तथा जिला योजनाओं को अंतिम रूप ग्राम पंचायतों, खंड विकास समितियों तथा अन्तरिम जिला परिषदों द्वारा दिया गया।

### स्थानीय विकास कार्य

स्थानीय विकास का कार्यक्रम पहले की भांति आरम्भ किया गया। इसके लिए भारत सरकार से ६८.१५ लाख रुपये की धनराशि मिली। राज्य सरकार ने राज्य-आत्म-सहायता अनुदान में से १६.५१ लाख रुपये को व्यवस्था की। बाद में इस धनराशि में ५,०६,२०० रुपये का एक अतिरिक्त अनुदान और जोड़ा गया।

ग्रामीण वर्ष में कृषि उपज में उल्लेखनीय वृद्धि करने वाली गांव सभाओं को पुरस्कार देने की योजना को कार्यान्वित किया गया और इस कार्य के लिए जिलों को ८.७६ लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी गयी। ग्राम सहायक सम्मेलन और 'भारत-दर्शन' पर्यटन के संगठन के लिए ३,१५,००० रुपये की धनराशि नियत की गयी।

### श्रमदान

वर्ष में श्रमदान कार्य छोटे पैमाने पर हुआ। श्रमदान कार्य का संगठन जिन महीनों में प्रायः किया जाता था (जनवरी-फरवरी) उन्हीं महीनों में पंचायत-चुनाव के सिलसिले में ग्रामीण जनता में काफी हलचल रही और कर्मचारी भी चुनाव प्रबन्ध तथा १९६१ की जनगणना के कार्य-संगठन में व्यस्त रहे। चूँकि लोगों का ध्यान दूसरी ओर था इसलिए श्रमदान की दिशा में जन-बल पूरी तरह मोड़ा नहीं जा सका। फिर भी श्रमदान के प्रति जो जनशक्ति परिलक्षित हुई वह उत्साहवर्द्धक रही और परिणाम अच्छे रहे। आर्थिक लाभ वाले कार्यों को केवल अधिक सुविधा प्रदान करने वाले कार्यों की तुलना में वरीयता दी गयी। श्रमदान द्वारा किये गये कतिपय कार्यों और उनकी सफलताओं का विवरण नीचे दिया गया है:—

(१) कच्ची सड़कों का निर्माण	.. ३,५३६ मील और १६२ गज
(२) कच्ची सड़कों की मरम्मत	.. ६,०६३ मील ४ फर्लांग और १७५ गज
(३) गूलों का निर्माण	.. १,२७८ मील, ७ फर्लांग और ११५ गज
(४) गूलों की मरम्मत	.. २,२८५ मील, ७ फर्लांग और २२८ गज
(५) पानी निकासी नालियों का निर्माण	७६ मील, ७ फर्लांग और १२७ गज
(६) कम्पोस्ट गड्ढों की खुदाई	.. ३,८३,१०६
(७) पुलियों का निर्माण	.. ८८२
(८) ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाना	१०,२५४ एकड़
(९) सिंचाई की नालियों का निर्माण	५६२ मील
(१०) स्कूल भवनों का निर्माण	३४५
(११) पोखरों की खुदाई	.. ५४८

## सामुदायिक विकास कार्यक्रम

सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जो आठ वर्षों से चल रहा था के अन्तर्गत लगभग ७०,००० गांव तथा ३३५ लाख ग्रामीण जनता आ गयी जो राज्य की कुल ग्रामीण जन-संख्या का ६६ प्रतिशत था।

वर्ष के दौरान में ४६ पूर्व प्रसार खंड १ अप्रैल, १९६० से और इसी प्रकार अन्य ४६ खंड १ अक्टूबर, १९६० से प्रारम्भ किये गये। ये खंड क्रमशः १ अप्रैल, १९६१ और १ अक्टूबर १९६१ तक विकास के प्रथम चरण में आ जाने थे।

३४ पूर्व प्रसार खंडों को जो १ अप्रैल, १९५६ को खोले गये थे और ३७ ऐसे ही खंडों को जो १ अक्टूबर १९५६ को खोले गये थे क्रमशः १ अप्रैल, १९६० तथा १ अक्टूबर, १९६० को प्रथम चरण वाला रूप दे दिया गया। सामुदायिक विकास मंत्रालय से ६ प्रथम चरण के खंड अलग से प्राप्त हुए और सीमावर्ती इलाकों के इतने ही छाया खंडों को १ अप्रैल, १९६० से प्रथम चरण खंडों के रूप में घोषित किया गया।

आलोच्य वर्ष में ५४ प्रगाढ़ विकास केंद्रों में से ३५ ने दूसरे चरण में प्रवेश किया। आलोच्य वर्ष भर में शेष १९ खंड प्रगाढ़ विकास केंद्रों के रूप में कार्य करते रहे।

३१ मार्च, १९६१ को विभिन्न ढंगों के खंडों का, जो कार्य कर रहे थे, विवरण निम्नलिखित है:—

पूर्व प्रसार खंड	..	..	..	६२
प्रथम चरण खंड	..	..	..	३६१
प्रगाढ़ विकास खंड	..	..	..	१९
द्वितीय चरण खंड	..	..	..	६६
योग ..				५६८

(क) बजट—प्रथम एवं द्वितीय चरणों के खंडों और प्रगाढ़ विकास खंडों में सामुदायिक विकास के कार्यक्रम को चालू रखने के लिए राज्य के बजट में ६३-बी-२ राष्ट्रीय प्रसार योजना मद में सीधा खर्च करने के लिए ७८३.८२ लाख रुपये का प्राविधान किया गया। [इसमें से योजनेस्तर (पहले प्रारम्भ किये गये) कार्यों के लिए १४२.५८ लाख रुपये और विकास के लिए ६४१.२४ लाख रुपये था।] 'एपी ऋण और अग्रिम' के मद में १०६.२६ लाख रुपये का प्राविधान किया गया। विभिन्न कार्यों में प्रगति लाने के निमित्त किये गये प्रगाढ़ प्रयासों के कारण इन दोनों ही मदों में काफी रुपये की कमी पड़ गयी और अन्य मदों से लेकर '६३-बी-२-रा० प्र० सो० यो०' में १७.८६ लाख रुपये और पी-ऋण और अग्रिम' में ४२ लाख रुपये रखे गये। फरवरी, १९६१ तक ६७१.४८ लाख रुपये खर्च किये जा चुके थे। सन् १९६०-६१ में अध्यापित रुपये की कोई सूचना नहीं मिली। खण्डों को खोलने का लक्ष्य पूरा हो गया।

आलोच्य वर्ष में राज्य की सिंचाई और भूमि को कृषि योग्य बनाने के कार्यों के लिए ६८.२० लाख रुपये का प्राविधान किया गया और ६०.८१ लाख रुपये की एक अन्य धनराशि खण्डों भवनो के निर्माण के लिए रखी गयी। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये धनराशियां कम पड़ गयीं। अतएव सिंचाई विभाग को १.४३ लाख रुपये और सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन और सड़क) को ८४६ लाख रुपये और विकास खण्डों में काम करने के लिए दिये गये।

(ख) कृषि—इनाम देने की योजना को जो १९५८-५९ में प्रारम्भ की गयी थी जारी रखा गया। इसमें खण्ड विकास अधिकारियों, ग्राम सेवकों और ग्राम सहायकों से पर्याप्त उत्साह का

संचार हुआ और स्वस्थ प्रतियोगिताओं की भावना जाग्रत हुई। इन प्रतियोगिताओं से एक नयी बात यह पैदा हुई कि अन्न का अधिक उत्पादन करने के लिए राज्य की कुछ गाव सभाओं ने दूसरी ग्राम सभाओं की चुनौती दी। राज्य भर में बादा जिले की बहेड़ी गाव सभा सब से अधिक धान के और आगरा जिले की अहरेरी गाव सभा गेहूँ के उत्पादन में सर्वप्रथम रही। बहेड़ी में लगभग ४० मन धान प्रति एकड़ और अहरेरी में लगभग ३८ मन गेहूँ प्रति एकड़ की पैदावार हुई।

आलोच्य वर्ष में यह महत्वपूर्ण निश्चय किया गया कि सिंचाई, पशुपालन और कृषि-कार्यक्रमों के लिए प्रथम चरण के खण्डों की रचनाओं वाले बजट में ३.६० लाख रुपये से बढ़ा कर ४.५० लाख रुपये नियत किये जायें। राज्य के कृषि संबंधी कार्यक्रमों की प्रगति में इससे काफी बल मिला।

कुछ महत्वपूर्ण अंगों में जो प्रगति हुई, वह निम्नलिखित है—

(१) बीज वितरण—आलोच्य वर्ष में खरीफ के ४.६२ लाख मन और रबी के १८.७० लाख मन बीजों का वितरण किया गया।

(२) खादों का वितरण—पूर्वगामी वर्ष के २१ ४७ लाख मन उर्वरकों की तुलना में इस वर्ष ३०.८८ लाख मन उर्वरक बांटे गये। खादों की अधिक खपत से यह साबित होता है कि किसानों का ध्यान खादों की उपयोगिता की ओर निरंतर आकर्षित हो रहा है। उर्वरकों के अतिरिक्त ०.८३ लाख मन हरी खादों के बीज भी बांटे गये।

(३) समुन्नत औजारों का वितरण—वर्ष भर में हर प्रकार के लगभग १.०६ लाख खेतों के समुन्नत औजारों को बांटा गया।

(४) कृषि संबंधी प्रदर्शन—समुन्नत कृषि उपायों और औजारों को अपनाने के लिए १.४८ लाख प्रदर्शन आयोजित किये गये।

(५) समुन्नत कृषि उपायों का प्रसार—जहां तक समुन्नत कृषि उपायों के प्रसार का संबंध है, प्रगति निम्नलिखित रही :—

	लाख एकड़
१—धान बोने का जापानी तरीका .. ..	१०.६५
२—गेहूँ की बुवाई का उत्तर प्रदेशीय तरीका .. ..	११.२४
३—कतार की बुवाई .. ..	४५.५०
४—फलीदार फसलों के क्षेत्र में वृद्धि .. ..	१.१
५—हरी खाद का उपयोग करने वाले क्षेत्र .. ..	७.३
६—गेहूँ और जौ की बुवाई का डब्लिंग तरीका .. ..	१.०

(६) कम्पोस्ट गड्ढे—वर्ष भर में लगभग ७.७१ लाख नये कम्पोस्ट गड्ढे खोदे गये।

(७) बाग—पूर्वगामी वर्ष में ० १५६ लाख एकड़ क्षेत्र की तुलना में इस वर्ष ०.१७ लाख एकड़ क्षेत्र में नये बाग लगाये गये। इस वर्ष फलों के ३०.५४ लाख और जलाने वाली लकड़ों के १६५२ लाख वृक्ष लगाये गये।

(८) ग्रामीण क्षेत्रों में तरकारी उगाने को प्रोत्साहन देने के निमित्त व्यवस्थित और सुनियोजित प्रयास किये गये। प्रत्येक क्रियाशील खण्ड से १०० रु० के मूल्य के तरकारी के बीजों के पैकेटों को ४ आने के नाम मात्र मूल्य पर बांटने को कहा गया।

(९) भूमि और जल संरक्षण—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत १६.६६ लाख एकड़ क्षेत्र में बन्धियो, ३८.६६ लाख एकड़ क्षेत्र में दौल बंधियो द्वारा और २.४८ लाख एकड़ क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती की गयी।

(१०) पौधों की सुरक्षा करना—यह अनुमान किया गया कि लगभग एक लाख एकड़ क्षेत्र में छिड़काव किया गया। बहुत से खण्डों में आम के भुनगों को मारने के लिए भी छिड़काव किया गया।

(११) ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाना—इस वर्ष दस चुने हुए खण्डों में ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए प्रारम्भिक कार्य किया गया।

(ग) पशु पालन—द्विकित्सा संबंधी सुविधाएँ—आलोच्य वर्ष के अन्त तक राज्य के खण्ड क्षेत्रों में १७० से अधिक पशु-चिकित्सालय तथा स्टॉक मैनों के अस्पतालों के भवनो का निर्माण किया जा चुका था।

विभिन्न रोगों के लिए वर्ष भर में २६.१४ लाख पशुओं का इलाज किया गया था।

महामारियों की रोकथाम के लिए पशुओं को पशु-जैंग तथा अन्य बीमारियों से बचाने के लिये लगभग ५० लाख टीके लगाये गये।

अभिजनन और नस्ल सुधार—शुद्ध नस्ल के ८,२३५ पशु बांटे गये। इनमें से १,५०० से अधिक साड़ थे। आलोच्य वर्ष में ८३,६८७ पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान कराया गया जब कि पूर्वगामी वर्ष में ऐसे पशुओं की संख्या ६४,७३६ थी। स्थानीय साड़ों द्वारा नस्ल खराब होने से रोकने के लिए ३७,६१० साड़ों को वधिया किया गया।

कुक्कुट विकास—आलोच्य वर्ष में शुद्ध नस्ल के ३४,१०१ समुन्नत पक्षियों, १५,३६२ मुर्गों और १८,३७६ मुर्गियों का वितरण किया गया। अच्छी नस्ल के अंडे सेने का कार्यक्रम पुरानी परिपाटी के अनुसार तथा दूसरे तरीके से ४० खण्डों में बड़ी सफलता से चलाया गया। राज्य की सभी कुक्कुट के शालाओं और कुक्कुट प्रसार इकाइयों में मुर्गीपालन के प्रशिक्षण का कार्यक्रम अपनाया गया।

जीरे (मछलियों के बीज)—आलोच्य वर्ष में गावों के कच्चे-पक्के तालाबों में छोड़ने के लिए लगभग १४.४३ लाख जीरे दिये गये।

(घ) उद्योग—१९५८ से पूर्व शैक्षिक और प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र फैली हुई अलग-अलग इकाइयों में चल रहे थे। इसलि ठीक से इनके निरीक्षण का प्रबन्ध करने के लिए यह निश्चय किया गया कि विभिन्न योजनाओं के कार्यों का एकत्रीकरण कर दिया जाय। १९५८-५९ के वर्ष से इन केन्द्रों का संचालन चार-चार प्रशिक्षण एवं उत्पादन इकाइयों को एक लक्ष् में करके हो रहा था।

विभिन्न प्रकार के समूहों का व्यौरा निम्नलिखित है—

१-५ शिल्पों के समूह	..	..	..	१
२-४ " "	.	..		३४
३-३ " "	..	..	..	१६
४-२ " "	..	..	..	१३
५—बिखरे हुए शिल्प	..	..	..	२८

पुनर्गठित योजनाओं के ध्येय और लक्ष्य निम्नलिखित थे।

१—कुटीर एवं लघु उद्योगों के आधार पर ग्रामीण शिल्पकारों एवं अन्य लोगों को उत्पादन के आधुनिक तरीकों में प्रशिक्षित करना।

२—वैज्ञानिक और आधुनिकतम समुन्नत औजारों को देकर प्राविधिक ज्ञान में वृद्धि करना।

- ३—कच्चे माल मिलने के लिए सुविधाएँ प्रदान करना ।
- ४—प्रशिक्षित शिल्पकारों की सहकारी समिति का संगठित करना ।
- ५—बाजारों और व्यवसायों से संबंधित आधुनिकतम तरीकों का ज्ञान कराना ।
- ६—प्रयासों में श्रम विभाजन, विशेषज्ञता और स्तरोन्नयन लाना ।
- ७—प्रशिक्षित व्यक्तियों, शिल्पकारों और उनकी सहकारी समितियों को सभी सम्भव आर्थिक और प्राविधिक सहायता देना और उनका पथ-प्रदर्शन करना ।
- ८—विभिन्न अखिल भारतीय समितियाँ और राष्ट्रीय क्षेत्रों की संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करना ।

हर डिवीजन में एक-एक आदर्श औद्योगिक समूह स्थापित करने के कार्यक्रम को भी प्रारम्भ किया गया । सन् १९६०-६१ में इस योजना के अन्तर्गत लगभग ५८० ग्रामीण शिल्पकारों को प्रशिक्षित किया गया ।

सामुदायिक विकास क्षेत्रों के ग्रामीण शिल्पकारों के दृष्टिकोण को और विस्तृत एवं प्रगतिशील बनाने की दृष्टि से “भारत-दर्शन” दौरे के आधार पर औद्योगिक महत्व के स्थानों के दौरे पर ले जाने का एक प्रस्ताव किया गया और एक टुकड़ी १५ फरवरी, १९६१ को “भारत दर्शन” के दौरे पर ले जायी गयी ।

१९६०-६१ के वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या २,३३८ थी । इसके अतिरिक्त ३,१५६ व्यक्ति प्रशिक्षित किये जा रहे थे । इन ३,१५६ में से, २,०३६ खण्ड क्षेत्रों के रहने वाले थे । इन प्रशिक्षित व्यक्तियों ने ६,८६,८३२ २६ रुपये की कीमत का सामान बनाया और उसमें से ६,०३,११६ १७ रुपये का सामान बेच दिया गया ।

२,३३८ प्रशिक्षित व्यक्तियों में १,५१० को ठीक से बसा दिया गया और ३३४ सहकारी समितियों जिनके ७,०२६ सदस्य थे संगठित की गयी । प्रशिक्षण पाये हुए व्यक्तियों को, औद्योगिक सहकारी समितियों को और शिल्पकारों को व्यक्तिगत रूप में ४६,८०० रुपये की आर्थिक सहायता दी गयी । इसके अतिरिक्त सामुदायिक विकास के धन में भी आर्थिक सहायता दी गयी ।

सन् १९६०-६१ में सामुदायिक विकास क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग द्वारा ऋण अथवा आर्थिक सहायता के रूप में निम्नलिखित धन उशिया दी गयी—

उद्योग का नाम	संगठित धनराशियों में	
	ऋण	सहायता
१—अन्न और दालों को बनाने धान कूटने और आटा चक्की	१२,०००	५,०००
२—रेशा .. .. .	६,०००	१२,२८०
३—ग्रामीण तैल .. .. .	६२,५००	५५,१५०
४—हाथ का बना कागज .. .. .	६,०००	..
५—ग्रामीण मिट्टी के बर्तन .. .. .	१,६२,५००	६७,०४०
६—ग्रामीण चमड़ा .. .. .	४६,१२५	५६,०६५

## नियत धनराशियां निम्नलिखित थीं:—

उद्योग का नाम	ऋण	सहायता
१—ग्रान् और दालो का बनाना, हाथ से धान कूटना एवं आटा चक्की .. .. .	१२,५००	५,०००
२—रेशा .. .. .	६,०००	१२,२८०
उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग समिति को हस्तान्तरित—		
३—ग्रामीण तेल .. .. .	६२,५००	६५,१५०
४—हाथ का बना कागज .. .. .	६,०००	..
५—ग्रामीण मिट्टी के बर्तन .. .. .	१२,५००	४५,५२०
६—ग्रामीण चमड़ा .. .. .	४३,१२५	४३,३७५

(ड) चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य—स्वास्थ्य कार्यक्रम में प्राथमिकता किये जाने वाले कामों में शुद्ध जल दिये जाने की व्यवस्था भी थी। ६,६६४ स्वच्छ पेयजल के कुओं का निर्माण किया गया और १५,१०६ कुओं का जीर्णोद्धार किया गया। राज्य के क्रियाशील खण्डों में १६,३०८ हाथ के पम्प लगाये गये। सेन्ट जान ग्रम्बुलेन्स असोसियेशन (भारत) नयी दिल्ली, द्वारा २३ ग्राम सेवकों या सामाजिक शिक्षा आगनाइजर्स को २३ प्राथमिक सहायता पेटिया दी गयी। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त ५,००० रुपये में से इनका मूल्य दिया जाना था। खण्ड क्षेत्रों में २३,२४,२१८ चेचक के टीके, १६,६०,६३७ हैजे और अन्य बीमारियों के टीके और ३७,०७६ बी० सी० जी० के टीके लगाये गये। मलेरिया निरोध के लिए, इसके अतिरिक्त १३,५४२ गावों में छिड़काव किया गया।

विभिन्न अस्पतालों के सहयोग से राज्य के प्रथम चरण खण्डों में नेत्र चिकित्सा संबंधी शिविरों का भी आयोजन किया गया।

(घ) शिक्षा—१९६०-६१ में ६,६६६ प्रौढ शिक्षा केन्द्रों का आयोजन किया गया और १,४६,६०१ प्रौढ व्यक्तियों को साक्षर किया गया। ३,५६१ पुस्तकालय खोले गये। इसी प्रकार ३,८४० (पाठशालाओं के १,८०६ को मिलाकर) सामुदायिक केन्द्र भी खोले गये।

सांस्कृतिक श्रवण योजना के अन्तर्गत ग्रामीण संस्थाओं को ६०५ रेडियो सेट दिये गये। १०८ विकास खण्डों और १२ प्रशिक्षण केन्द्रों को १६ मिलीमीटर के पूरे-पूरे सेट दिये गये। राज्य के सभी प्रथम चरण खण्डों को मिट्टी के तेल से चालित फिल्म प्रोजेक्टरों और पी० ए० ई० सेट देने का प्रबन्ध किया गया। आलोच्य वर्ष में ५,७८६ युवक क्लबों का आयोजन किया गया और ६७,६४२ सदस्य बनाये गये।

(छ) महिला और बाल कल्याण कार्यक्रम—महिलाओं और बच्चों के कार्यक्रमों के अन्तर्गत किये गये कार्यों की स्थिति अत्यन्त सतोषजनक रही। सन् १९६०-६१ में २३४ सहायक विकास अधिकारी (महिला) और ८७६ ग्राम सेविकाएं इस कार्य में संलग्न थीं। कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंगों की वार्षिक लक्ष्य पूर्तियां निम्नलिखित रहीं—

(१) प्रौढ महिलाओं की संख्या जो साक्षर बनायी गयीं ..	३१,७४१
(२) प्रारम्भ किये गये महिला मंडलों की संख्या ..	१६३७
(३) महिला मंडलों के सदस्यों की संख्या ..	२६,८१८
(४) संगठित किये गये महिला शिविरों की संख्या ..	५३५
(५) महिला शिविरों में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या ..	११,३१८
(६) प्रारम्भ की गयी बाल बाडियों की संख्या ..	२,२१६
(७) बाल बाडियों में उपस्थित होने वाले बच्चों की संख्या ..	३५,३७६
(८) लगाये गये निर्भूम चूल्हों की संख्या ..	५,३८१

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के कार्य-क्रम का आरम्भ सुव्यवस्थित : इस विचार से किया गया था कि ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो तथा वे अपनी जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहण कर सकें। ऐसा प्रतीत होता था कि इसका प्रभाव पड़ रहा है।

(ज) सहकारिता—सामुदायिक विकास क्षेत्रों में विशेषतया उनके आर्थिक विकास में सहकारिता का महत्वपूर्ण स्थान रहा। सन् १९६०-६१ से खण्ड क्षेत्रों में कुल मिला कर ७,४१२ समितियों को रजिस्टर किया गया। इस समितियों के ४.७६ लाख सदस्य थे और इनमें ५.७४० कृषि ऋण समितियाँ सम्मिलित थीं। समितियों में अंश पूँजी बढ़ा कर ११.७४ लाख कर दी गयी। प्राथमिक ऋण लेने वालों की, जिन्होंने समितियों से प्रत्येकालीन ऋण लिये, संख्या में यथेष्ट वृद्धि हुयी। ३१ मार्च, १९६१ तक इस प्रकार दी गयी धनराशि १३.७९ करोड़ थी। इस प्रकार २.७३ लाख रुपयों का औसत ऋण प्रत्येक खण्ड पर पड़ा। कृषि ऋण समितियों द्वारा ऋण दिये जाने का आधार सदस्यों की उत्पादन आवश्यकताओं को माना गया और ऋण का संबंध क्रय से कर दिया गया। इससे छोटे किसानों को ऋण मिलने में काफी सहायता मिली। उर्वरकों के लिए ऋण जहाँ तक संभव हो सके उर्वरकों के रूप में ही दिया गया। समुन्नत बीजों और औजारों के वितरण के लिए खण्डों में ५१ नये सहकारी बीज गोदाम खोले गये।

(झ) राष्ट्रीय बचत योजना—राज्य में राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में १३.५२ करोड़ रुपया जमा करना नियत किया गया। परन्तु केवल लगभग ११.०६ करोड़ रुपया ही एकत्रित हो सका। पोस्ट ऑफिस में खुले हुए सेविंग बैंक प्रकाशनों पर सूद के रूप में लगभग १.८३ करोड़ रुपया मिलना था। इस प्रकार कुल मिलाकर एकत्रित धनराशि १२.८९ करोड़ रुपयों हो जाने की आशा थी। यद्यपि इस वर्ष लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकी, फिर भी पूर्वगामी वर्ष की तुलना में इस वर्ष की एकत्रित धनराशि संतोषजनक रही।

अप्रैल, १९६० से भारत सरकार ने बिना सूद के १००६० और ५ रुपये वाले इनामी बाँडों को जारी किया। देश भर के विभिन्न केन्द्रों में हर तिमाही बाँडों की हर सीरीज के लिए लाटरी डाली गयी। इस वर्ष इनामी बाँडों की बिक्री के राज्य भर में कुल मिला कर १.३२ करोड़ रुपया जमा हुए।

राज्य स्तर पर प्रथम बार राज्य में सखनऊ स्थित भुवनालय में सितम्बर ५ और ६, १९६० को राष्ट्रीय बचत की एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें राज्य भर के २०० से अधिक गैर सरकारी और सरकारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

एकत्रित धनराशि के आधार पर कुमाऊँ को राज्य के सर्वोत्तम डिवीजन होने पर 'राज्यपाल संचय बैजयन्ती' प्रदान की गयी और 'मुख्य मंत्री संचय बैजयन्ती' गढ़वाल जिले को राज्य का सर्वोत्तम जिला होने के फलस्वरूप मिली।

राष्ट्रीय बचत योजना को और अधिक प्रसारित करने के लिए विकास खण्डों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना जागृत हो, इस विचार से राज्य सरकार ने निश्चय किया कि इस योजना में राज्य भर में प्रथम और द्वितीय आने वाले विकास खण्डों को क्रमशः १५,००० रुपये और १०,००० रुपये के नकद पुरस्कार दिये जायें। प्रत्येक खण्ड द्वारा इस योजना का प्रचलन किसकी आबादी में हुआ, इस आधार पर ये दोनों पुरस्कार दिये जाने थे और इनका उपयोग संबंधित खण्ड किसी भी विकास कार्य पर खण्ड विकास समिति से अनुमोदन प्राप्त करके कर सकता था।

(ज) लघु सिंचाई योजनाएं—नियोजन विभाग की लघु सिंचाई योजनाओं में निम्नलिखित योजनाएं सम्मिलित थीं :

(१) 'अधिक अन्न उपेजाओं' धनराशि में से जिन योजनाओं में ऋण दिये गये।

(२) योजनातर्गत खण्डों की धनराशि में से जिन योजनाओं में ऋण दिया गया।



पक्के कुएं—पक्के कुएं बनाने के लिये राज्य के विभिन्न जिलों में कुओं की लागत के अनु-सार ७०० से २००० रु० प्रति कुओं के हिसाब से तकावी के रूप में सूद सहित ऋण दिये गये। ऋण दिये जाने की तिथि के एक वर्ष के अन्दर यदि कुओं के निर्माण का कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा हो गया तो तकावी ऋण में २५ प्रतिशत की छूट दी जा सकती थी। विशेष मामलों में इस समयविधि में १ वर्ष की वृद्धि जिलाधीश द्वारा कर देने पर भी यह छूट मिल सकती थी।

टूटे-फूटे कुओं की मरम्मत—टूटे-फूटे कुओं के जीर्णोद्धार के निमित्त ४०० रुपये प्रति कुं के हिसाब से तकावी अग्रिम दी गयी। ऐसे मामलों में किसी प्रकार की सुप्त सहायता देना संभव नहीं था।

कुओं का सुधार—कुओं का गहरी खुदाई द्वारा सुधार करने के लिए प्रत्येक खुदाई के लिए अधिक से अधिक ५०० रु० तक की तकावी दी गयी। कुओं की गहरी खुदाई करने के लिये वैभाषिक विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क प्राविधिक सहायता उपलब्ध थी। इससे संबंधित सामान जैसे पाइप जाली इत्यादि सरकारी गोदामों से दाम के दाम पर प्राप्त हो सकते थे।

रहट लगा कर कुओं का सुधार—रहट लगा कर या अन्य किसी युक्ति द्वारा पानी खींचने के लिए ४०० रु० तक की तकावी उपलब्ध थी।

पम्पों का लगाना—पम्पिंग सेटों की खरीद के लिये २,५०० रु० तक की और विशेष परि-स्थितियों में जहां पानी ज्यादा गहराई पर मिलता था ३,००० रुपये तक की तकावी अग्रिम दी गयी।

निजी नलकूप—१०,००० रुपये की अधिकतम सीमा का ध्यान रखते हुए निजी नलकूपों के लिये अनुमानित लागत का २/३ अंश तकावी के रूप में अग्रिम दिया गया। इसके अतिरिक्त पक्की गूलों के लिये भी ५,००० रु० अग्रिम दिये गये।

जांसी डिवीजन, मिर्जापुर, इलाहाबाद के कुछ भाग और दाराणसी जिले की चकिया तहसील में निजी बांधियों का निर्माण—५,००० रु० की अधिकतम सीमा को ध्यान में रखते हुए इस योजना के अन्तर्गत, कार्यान्वित होने वाले प्रति एकड़ पर १५० रु० की दर से तकावी ऋण दिया गया।

ऋण दिये जाने की तिथि से एक वर्ष के भीतर कार्य के संतोषजनक ढंग से पूर्ण हो जाने पर अग्रिम दिये गये ऋण में २५ प्रतिशत छूट दी गयी।

पुरानी बांधियों की मरम्मत—उपयुक्त जिलों में पुरानी बांधियों की मरम्मत के लिए लाभा-न्वित प्रति तीन एकड़ पर १०० रु० तक का तकावी ऋण दिया गया। इस ऋण की अधिकतम सीमा प्रत्येक मामले में २,५०० रु० थी। पहाड़ी क्षेत्रों में गूलों का निर्माण गांव सभाओं द्वारा संतोषजनक ढंग से गूलों और तालाबों के निर्माण कर लेने पर अनुमानित लागत का आधा भाग तक आर्थिक सहायता के रूप में मिल सकता था। नये तालाबों का खोदना, पक्के कुएं इत्यादि खण्ड धनराशियों से केवल नये तालाब खोदने के लिये लाभान्वित प्रति एकड़ पर १०० रु० की दर से सहायता प्राप्य थी।

सभी तकावी ऋण मय सूद थे। अधिक अन्न उपजाओ धनराशियों से दिये गये ऋणों पर साढ़े ४ फीसदी और खण्ड धनराशियों से दिये गये ऋणों पर साढ़े ५ फीसदी सूद की दर रखी गयी। ऋण दिये जाने की तिथियों से २ वर्ष समाप्त होने पर इन ऋणों को वस छुमाही किश्तों में भुगतान होना था। परन्तु निजी नलकूपों के मामले में ये भुगतान १० वर्ष में होना था।

इसके अतिरिक्त पिछड़े की योजना के अन्तर्गत तकावी ऋण के रूप में देने के लिए ४.५० लाख रुपये का भी प्राविधान था।

आलोच्य वर्ष में पूर्वी जिलों में पक्के कुएं इत्यादि बनाने के लिए २,३१,७३० रुपये और छोटी पहाड़ी नालियां बनाने के लिए १,६१,००० रुपये व्यय किये गये। इससे उत्तरकाशी और जमोली जिलों के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

इस वर्ष 'अधिक अन्न उपजाओ' कोष में से १५७.५० लाख रुपया तकावी ऋण के रूप में दिया गया और १५५.५० लाख रुपया अग्रिम के रूप में दिया गया। ये ऋण निम्नलिखित निजी और छोटे-मोटे सिंचाई के कार्यों के लिए दिये गये :

- (१) १२,६१६ पक्के कुओं के निर्माण के हेतु,
- (२) १६५ पक्के कुओं की मरम्मत के लिए,
- (३) गहरी खुदाई करके ८३६ कुओं को उन्नत बनाना,
- (४) २,६८६ रहट लगाना,
- (५) १,०२६ पम्पिंग प्लान्ट लगाना,
- (६) ६२२ निजी नलकूप लगाना,
- (७) २,०६२ निजी बंधियों का निर्माण,
- (८) ३२ पुरानी बंधियों की मरम्मत,
- (९) पहाड़ी जिलों में गूलों का निर्माण (१,२६६ एकड़ में)

'अधिक अन्न उपजाओ' एवं खण्ड कोषों तथा अन्य स्रोतों से सहायता प्राप्त छोटी-मोटी निजी सिंचाई साधनों की उपलब्धियों की संख्या निम्नलिखित रही—

विषय	केवल १९६०-६१ के वर्ष भर में किया शील खण्डों की प्रगतिशील उप-लब्धियां		१९६०-६१ के वर्ष से कुल मिला कर जिलों की (जिनमें खण्ड और अखण्ड क्षेत्र सम्मिलित हैं) प्रगतिशील उपलब्धियां	
	१	२	३	
(१) निजी लगाये गये नलकूप	..	४४१	६६५	
(२) निर्मित पक्के कुएं	..	१०,५७७	१३,५२६	
(३) पक्के कुएं जिन की मरम्मत की गयी	..	३,६१६	४,६६४	
(४) खोदे गये कुएं	..	४,३२०	६,७८६	
(५) लगाये गये रहट	..	६,८७६	८,१६६	
(६) लगाये गये पम्पिंग सेट	..	७७०	१,०१८	
(७) निर्मित बंधियां	..	१,४०६	१,४६८	
(८) तालाब खोदे गये	..	२२०	३२६	
(९) मरम्मत किये गये तालाब	..	२,४६१	२,७३८	

## प्रान्तीय रक्षक दल

सन् १९६०-६१ में ८६० हल्का सरदार, ६,३४८ ग्रुप लीडर, १२,६५१ सेक्शन लीडर और ८७,८१८ रक्षक भरती किये गये। बिना हथियारों की फौजी शिक्षा ७,०६६ स्वयं-सेवकों को शिक्षा दी गयी और ६६ स्वयं सेवकों को हथियारों का उपयोग करना सिखाया गया।

७,३३६ दंगलों का आयोजन किया गया जिनमें २,१०,३१३ पहलवानों ने भाग लिया। खेलकूद की १४,४५८ प्रतियोगिताएं हुईं जिनमें ३,९४,४१७ व्यक्तियों ने भाग लिया। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के विषय में १,१४२ प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया जिनमें २५,९०० व्यक्तियों ने भाग लिया। ४९९ शरीर संबंधन केन्द्र तथा ७,२९२ अखाड़ों का आयोजन किया गया और १८९ व्यक्तियों को तैरना सिखाया गया।

प्रान्तीय रक्षक दल द्वारा भूमि संरक्षण का निम्नलिखित कार्य सम्पन्न किया गया:

विषय	उपलब्धियां (एकड़ों में)
(१) खेतों की मेड़बन्दी .. .. .	५६,६९९
(२) कंटूरबन्दी .. .. .	४५
(३) जमीन हप्तवार की गरी .. .. .	१३,३९९
(४) बांध .. .. .	७८३
(५) मध्यवर्ती फसलें .. .. .	७,८३९
(६) कंटूरवाली खेती .. .. .	११,६५४
(७) चारागाहों का विकास .. .. .	९७६
(८) फल वाले वृक्षों का आरोप .. .. .	१,४३,९७२
(९) वनरोपण .. .. .	२,०६५

## खेलकूद परिषद्

१९६०-६१ के वर्ष में उत्तर प्रदेश खेल-कूद परिषद् को राज्य में खेल कूदों को प्रोत्साहन देने के निमित्त ५,७४,६१७ रुपये का अनुदान निम्नलिखित तीन प्रमुख मदों में दिया गया :

	रुपया
(२) खेलकूद का विकास .. .. .	१,०९,२१७
(२) खेल-कूद का स्तर ऊंचा करना .. .. .	२,१४,७६४
(३) क्षेत्रिक स्टेडियमों का निर्माण .. .. .	२,५०,६३६

सहाय्यतार्थ अनुदान—राज्य के ६ खेल-कूद असोशियेशनों को खेल-कूदों को बढ़ावा देने के लिए २३,००० रुपये का सहाय्यतार्थ अनुदान दिया गया। इसी प्रकार खेलकूद को १० क्षेत्रिक परिषदों को अपने क्षेत्रों में खेलकूदों को प्रोत्साहन देने के निमित्त ३०,६०० रुपये का अनुदान दिया गया।

प्रशिक्षण—होनहार युवकों को विभिन्न खेलकूदों में प्रशिक्षित करने के लिए सिखाने वालों का एक पैनल प्रशिक्षण शिविरों को चलाता रहा। ये सिखाने वाले राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति थे जिन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया था।

खेलकूद को क्षेत्रिक परिषदों के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों में विभिन्न खेलकूदों के लिए १३८ प्रशिक्षण शिविरों का संगठन किया गया। प्रत्येक शिविर १४ दिन के लिए लगा और लगभग ३,००० प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षित किये गये।

राष्ट्रीय स्कूल खेलकूदों में भाग लेने से पूर्व उत्तर प्रदेश के स्कूली लड़कों की चुनी हुई टीमों को हाकी, फुटबाल और व्यायाम में प्रगाढ़ प्रशिक्षण दिया गया।

प्रतियोगिताएं—क्रिकेट, हाकी, वालीबाल, कुश्ती और टेबल-टेनिस की उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया और इसमें लगभग सभी विश्वविद्यालयों ने भाग लिया। इसी प्रकार विभिन्न खेलों की अन्तर्जिला प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन क्षेत्रों में खेलकूद की क्षेत्रीय परिषदों ने किया।

भारतीय व्यायाम एवं खेलकूद राज्योत्सव-भारतीय व्यायाम का चौथा राज्योत्सव जनवरी, १९६१ में मनाया गया। अन्य राज्यों की तीन व्यायामशालाओं, राज्य की तीन व्यायामशालाओं और ८ क्षेत्रीय टीमों ने इस उत्सव में भाग लिया।

हाकी और फुटबाल में अन्तर्क्षेत्रीय (राज्य) स्कूली लड़कों की चैम्पियनशिप-आलोच्य वर्ष में अन्तर्क्षेत्रीय स्कूली लड़कों के चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया और उसमें सभी शैक्षिक क्षेत्रों ने भाग लिया। प्रतियोगिताओं अत्यन्त सफल रहीं।

स्टैडियमों का निर्माण—मेरठ, वाराणसी, नैनीताल, गोरखपुर और झांसी में निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया था। इलाहाबाद, आगरा, बरेली और फैजाबाद में कार्य शीघ्र ही आरम्भ होने का था।

राष्ट्रपति का विवेकानुदान (डिस्क्रेशनरी ग्रांट)—राज्य के विभिन्न क्लबों और असोसिएशनों को आलोच्य वर्ष में ११,००० रुपये की स्वीकृति दी गयी।

बजट—१९६१-६२ में खेल और व्यायाम के विकास के लिए ३,६४,७०० रुपये का प्राविधान बजट में किया गया।

## २-प्रशिक्षण और अनुसंधान

### प्रशिक्षण कार्यक्रम

आलोच्य वर्ष में गैर सरकारी व्यक्तियों के लिए १७ प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा खण्ड विकास समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम को और प्रगाढ़ किया गया।

प्रारम्भिक प्रशिक्षण—सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए चूंकि विशेष प्रशिक्षण आरम्भ से ही आवश्यक समझा गया, इसलिए प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग सेवा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का प्रबन्ध किया गया। विभिन्न श्रेणियों के जिन कर्मचारियों को प्रारम्भिक प्रशिक्षण दिया गया उसका वहीरा निम्नलिखित है—

कर्मचारियों की श्रेणी				प्रशिक्षित कर्म- चारियों की संख्या
(१)	ग्राससेवक	..	..	४८२
(२)	सहायक विकास अधिकारी (कृषि)	..	..	१४२
(३)	सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)	..	..	३८
(४)	खण्ड विकास अधिकारी	..	..	२६
(५)	पंचायत राज इन्स्पेक्टर	..	..	२०
				(६ भास का जाब कोर्स)
(६)	मुख्य सेविकाएं	..	..	७१

कार्यकाल में प्रशिक्षण—आलोच्य वर्ष में तीन केन्द्रों में, बिचपुरी (आगरा), रुद्रपुर (नैनीताल) और गाजीपुर में सांख्यिक रिकार्डर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गयी। इन तीनों केन्द्रों में इन पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया और २७७ ग्राम सेवक प्रशिक्षित किये गये। २५६ अर्धप्रशिक्षित ग्राम-सेवकों को ६ मास के पाठ्यक्रम में और प्रशिक्षित किया गया। खण्डों में स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के निमित्त यह आवश्यक समझा गया कि ओवरसियरों और सैनिटरी इन्स्पेक्टरों को इसलिए एक संयुक्त पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया जाय ताकि वे एक दूसरे की कठिनाइयों को समझ सकें और पारस्परिक सहयोग से काम करें। इस उद्देश्य से दो-दो मास के दो पाठ्यक्रमों की व्यवस्था बख्शी के तालाब पर की गयी। इनमें ३४ ओवरसियरों और ४६ इन्स्पेक्टरों को प्रशिक्षित किया गया। प्लानिंग रिसर्च तथा ऐक्शन इन्स्टीट्यूट, लखनऊ में १० खण्ड विकास अधिकारियों तथा ११ सहायक विकास अधिकारियों (सांख्यिक शिक्षा) के लिए तीन घटिके एक नवीनीकरण पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गयी।

जून, १९६० में मथुरा के पशु चिकित्सा केन्द्र में १७ सहायक पशु चिकित्सकों ने एक महीने का प्रशिक्षण पूरा किया। १२ सहायक विकास अधिकारियों (उद्योग) को प्रशिक्षित करने के लिए रुद्रपुर में २ सप्ताह के एक विशेष कार्यक्रम की व्यवस्था की गयी। भूमि संरक्षण में प्रशिक्षित होने के लिए २५, २५ खण्ड विकास अधिकारियों के दो दलों को लखनऊ के रहमान खेड़ा नामक स्थान पर १५ दिन के लिए भेजा गया। इसी प्रकार १२ ग्राम-सेवकों को भूमि संरक्षण में प्रशिक्षित किया गया। एक-एक महीने के दो पाठ्यक्रमों का आयोजन पशु-निरीक्षक के लिए लखनऊ चक गंजरिया फार्म पर किया गया। इनमें ३३ सुपरवाइजरों ने भाग लिया और पाठ्यक्रम पूरा किया।

लखनऊ के विकास अन्वेषणालय ने गोबर गैस मशीन की सरम्मत करने और उसे फिट करने का प्रशिक्षण देने की एक योजना आरम्भ की और इटावा के अजीतबल खण्ड में एक सप्ताह के एक पाठ्यक्रम की व्यवस्था की। राज्य की विभिन्न प्रशिक्षण एवं प्रसार परियोजनाओं में लगे हुए २५ सहायक विकास अधिकारियों (कृषि इंजीनियरिंग) ने इसमें भाग लिया और पाठ्यक्रम को पूरा किया। बी० आर० कालेज, आगरा, राजकीय कृषि स्कूल कानपुर और राजकीय कृषि संस्था बुलन्दशहर में सहायक विकास अधिकारियों (कृषि) के लिए तीन अल्पकालीन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गयी। इनमें ११६ अधिकारी प्रशिक्षित किये गये।

भारत सरकार के केन्द्रों में नवीनीकरण, ध्वंसा एवं अन्य पाठ्यक्रम-नवीनीकरण और ध्वंसा पाठ्यक्रमों की अबधि तीन सप्ताह से तीन आत तक रही। आलोच्य वर्ष में १५४ खण्ड विकास अधिकारी, ५६ सहायक विकास अधिकारी और २६ गैरसरकारी तथा १५ अन्य व्यक्ति प्रशिक्षण के लिए भेजे गये।

भारत सरकार द्वारा एक तीन सप्ताह का अध्ययन पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें २५ खण्ड विकास अधिकारी, २२ जिला स्तर अधिकारी और २५ गैरसरकारी व्यक्ति सम्मिलित हुए। आलोच्य वर्ष में १३ इंस्ट्रक्टरों और एक प्रिंसिपल के लिए एक तीन महीने के पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था की गयी।

परियोजना कार्यचारियों के अध्ययन संबंधी दौरे और गोष्ठीयां सांस्कृतिक रिसर्च डेशन, बस्ती में गोरखपुर और वाराणसी डिवीजनों के लगभग ६०० प्रगतिशील किसानों की एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके लिए चुने गये किसान सामान्यतः वे थे जिन्होंने उन्नत कृषि प्रणालियों को अपनाया था। गोष्ठीकाल में उन्हें फलों के उत्पादन में प्रशिक्षित किया गया। इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों को दोनों डिवीजनों के दिलचस्प स्थानों पर भी ले जाया गया ताकि अन्ननास, केला और पपीता उगाने की तकनीक का अध्ययन करने का उन्हें अवसर मिले।

गैरसरकारी व्यक्तियों का प्रशिक्षण-नव निर्वाचित प्रधानों को सामुदायिक विकास के सिद्धांत और कार्यक्रम से परिचित कराने के निमित्त एक विस्तृत कार्यक्रम द्वारा उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए खण्ड मुख्यालयों में ७ दिवसीय शिविरों का आयोजन किया गया। इनमें ३२,६०८ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

गोष्ठी तथा सम्मेलन—२६ से ३१ मई तक रुद्रपुर (नैनीताल) में प्रिंसिपलों और इन्स्ट्रक्टरों का एक अध्ययन शिविर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा करने और अनुभवों का पारस्परिक आदान-प्रदान करने के लिए लगाया गया। प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण पंचायती राज) तथा कृषि उत्पादन पर अधिक बल दिये जाने के कारण इसकी आवश्यकता का विशेष महत्व हो गया। शिविर में विशिष्ट संस्तुतियों की गयीं जिनका संबंध संस्था तथा गैर संस्था संबंधी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का वैज्ञानिक विभाजन, पाठ्य योजनाओं की तैयारी, कक्षाओं में दी जाने वाली शिक्षा और खेतों में व्यावहारिक तथा खण्ड प्रसार कार्यक्रमों में समन्वय मूल्यांकन तथा निर्धारण से था।

विकास अन्वेषणालय—मई, १९६१ में विकास अन्वेषणालय ने अपने जीवन के ७ वर्ष पूरे किये। आलोच्य वर्ष में अन्वेषणालय ने अल्पवयस्क वर्ग, ग्रामीण उद्योग, सहकारी संस्थाओं, ग्रामीण स्वास्थ्य, भूमि संरक्षण, महिलाओं के कार्यक्रम और पंचायतों से संबंधित विशेष प्रसार कार्य में अपने अग्रगामी प्रयोगों को जारी रखा। प्रसारण की दृष्टि से अधिक प्रभावशाली परियोजनाओं पर बल दिया गया।

गत ७ वर्षों में अन्वेषणालय ने विभिन्न कार्य-अन्वेषण कार्यक्रमों को पूरा किया और इस क्षेत्र में गौरव का स्थान प्राप्त किया। देश की विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में किये गये अन्वेषणों के फलों का परीक्षण करने के निमित्त यह अन्वेषणालय एक अत्यन्त लाभदायक माध्यम सिद्ध हुआ है। अन्तराष्ट्रीय संगठनों के क्षेत्र में इसने अपना स्थान बना लिया है और संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ संगठनों की ओर से विदेश से कुछ अध्ययन कार्य इस अन्वेषणालय को सौंपे गये हैं। आलोच्य वर्ष के अन्त तक नवयुवकों के कार्यों, ग्रामीण उद्योगों, सहकारी समितियों पंचायतों, भूमि संरक्षण, ग्रामीण स्वास्थ्य, महिलाओं के कार्यक्रमों तथा जन सम्पर्क के क्षेत्रों में अन्वेषणालय ने ५० से ऊपर कार्य एवं अन्वेषण संबंधी परियोजनाओं की पूर्ति की। इनमें से कुछ के सफल परिणामों में सरकारी विभागों द्वारा व्यपहत (प्रयुक्त) एजेंसियों को तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों को विस्तृत प्रसार के लिए अवगत कराया गया।

अन्वेषणालय में १२ अनुभाग थे जो तीन विशेष शाखाओं में बंटे हुए थे।

(क) अग्र-गामी परियोजनाओं की शाखा—

(१) अल्पवयस्क वर्ग में विशेष प्रसार कार्य,

(२) ग्रामोद्योग,

(३) सहकारी समितियां,

(४) पंचायतें,

(५) भूमि संरक्षण,

(६) ग्रामीण स्वास्थ्य,

(७) महिला कार्यक्रम,

(ख) सांख्यिकी तथा मूल्यांकन शाखा—

(१) सांख्यिकी अनुभाग,

(२) ग्रामीण जीवन विश्लेषण अनुभाग।

(ग) जन संचार शाखा—

१—सूचना एवं प्रकाशन अनुभाग,

२—श्रव्य-दृश्य सहायता अनुभाग,

३—पुस्तकालय सेवा

अन्वेषणालय के विभिन्न अनुभागों के कार्यों एवं उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है:—

अल्प वयस्क वर्ग में विशेष प्रसार कार्य—इटावा, लखनऊ, सहारनपुर, बलिया, गोरखपुर तथा नैनीताल जिलों के ११ खण्डों के अग्रगामी क्षेत्रों में क्रिया एवं अनुशीलन के कार्यक्रमों के बाद में उठाये जाने वाले कदमों का संहत करना जारी रहा। इन अग्रगामी क्षेत्रों में ४५४ क्लब थे, जिनकी कुल सदस्य संख्या ६,००३ थी।

साग-सब्जी उगाने, सामूहिक फलोद्यान के रोपण करने, बछड़ा पालन करने, कुक्कुट पालन करने तथा रेशम उत्पादन करने वाली आर्थिक परियोजनाओं पर विशेष बल दिया जाता रहा। ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं, सहकारी समितियों एवं संगठनों के प्रतिनिधियों, शिक्षकों तथा अन्य व्यक्तियों को जो विभिन्न व्यवसाय एवं उद्योगों का प्रतिनिधित्व करते थे, मूल शिक्षा देने के लिए हलद्वानी, जिला नैनीताल में १८ फरवरी, १९६१ को एक जनता कालेज की स्थापना की गयी।

ग्रामोद्योग—ग्रामोद्योग के क्षेत्र में नियोजन अन्वेषण तथा क्रिया संस्थान ने काफी सफलतापूर्वक कई अग्रगामी परियोजनाओं को क्रियान्वित किया। ऐसे ही उद्योगों के चुनने पर बल दिया जाता रहा जिनमें प्रसार शक्ति अधिक थी।

अल्मोड़ा जिला के बागेश्वर स्थान में बारदार खालों को कमाने तथा शिकार की खालों को सुरक्षित रखने से संबंधित एक नयी परियोजना प्रारम्भ की गयी।

सहकारिता—वर्ष में एक डोभी (जौनपुर) और १ जुगरनगर (बरेली) में दो नयी गन्ना कोआपरेटिव प्रोसेसिंग समितियों का संगठन किया गया।

भूमि संरक्षण:—भूमि संरक्षण कार्य जो प्रारम्भ में १० एकड़ भूमि पर शुरू किया गया था अब इटावा जिले के भाग्यनगर और अजितमल खंडों के ४६ गांवों में किया जाने लगा जिसका क्षेत्रफल लगभग २८,००० एकड़ था।

### ३— उत्तराखंड डिवीजन में विकास कार्य

#### सामान्य

प्रशासनिक सुविधा के विचार से पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट खंड (जिसमें बेल और भेरंग पट्टियां हैं) में तहसील की सीमाओं में कुछ परिवर्तन किये गये और बल्ला और पल्ला अठिगांव की भट्टियों को दीदीहाट तहसील से हटा कर पिथौरागढ़ में शामिल कर दिया गया और कनाली चीला खंड और तल्ला अस्कोट और बाराबीसी की पट्टियां पिथौरागढ़ से दीदीहाट तहसील में शामिल कर दी गयीं। प्रशासनिक और आर्थिक कठिनाइयों के कारण अन्य गैर-सरकारी मांगों जैसे उत्तराखंड डिवीजन का क्षेत्र बढ़ाने अथवा उत्तराखंड और कुमायूँ डिवीजनों को मिला देने की पूर्ति नहीं की जा सकी।

तीनों जिलों में भवन निर्माण कार्य प्रायः ठीक चल रहा था। तदर्थ आवासों का या तो निर्माण कर दिया गया या फिलहाल उन्हें किराये पर ले लिया गया, साथ ही पक्के भवनों के निर्माण की योजना भी बतायी जा रही। चमोली जिले के मुख्यालय, गोपेश्वर कस्बे के लिए एक महायोजना को वर्ष के अन्त तक अन्तिम रूप दे दिया गया। चमोली को गोपेश्वर से मिलाने वाली सड़क लगभग पूरी हो चुकी थी। पानी की सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था के शीघ्र पूरी होने की आशा थी। उसके बाद निर्माण कार्य में अधिक गति लाने की आशा की जाती थी। चमोली में अलखनन्दा पर बननेवाले पुल का ढांचा तैयार हो गया था और उसे शीघ्र ढोकर पहुंचाया जाने वाला था।

कृषि योग्य भूमि की अध्याप्ति के सम्बन्ध में स्थानीय जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ढाई सौ ल के अन्तर पर तखला में जहाँ पर्यन्त भूमि उपलब्ध थी, उत्तरकाशी में भवन निर्माण-कार्य करना निश्चित हुआ।

पिथौरागढ़ की सरकारी बस्ती ठिकाता में भूतलों और वास्तव्यों के निर्माण-कार्य में प्रशंसनीय प्रगति रही। कस्बे को विनियमित क्षेत्र, घोषित कर दिया गया ताकि तदर्थ भूमि में संभव न हो। रेन्ट कंट्रोल आर्डर भी लागू कर दिया गया।

तहसील मुख्यालयों की व्यवस्था इस प्रकार की जा रही थी कि तीसरी योजना की सभी परियोजनाओं की भवन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाय।

आलोच्य वर्ष में निम्नित सभी पदों पर नियुक्तियाँ कर दी गयी थीं। ऐसा महसूस किया जाता था कि प्राविधिक अगले की, विशेषतः पी० एच० एस० डाक्टरों, कम्पाउण्डरों, सहायक पशु चिकित्सकों, स्टाकमैनो, भंगियों, दाइयों, धोबियों और पुलिस वायरलेस यूनिटों के लिए रेडियो मॉनिटरिंग अफसरों और रेडियो आपरेटरों की कुछ कमी है। उपर्युक्त व्यक्तियों की स्थानीय भरती की जा रही थी। मयूरा बोटनरी कालेज में उत्तीर्ण होने वाले चिकित्सकों के अगले दल में से उपर्युक्त सहायक पशु चिकित्सकों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव था।

मुख्यमंत्री जी जून १९६१ में और श्री राज्यपाल जुलाई, १९६१ में उत्तरकाशी आये थे। श्री राज्यपाल ने १२ जून से २२ जून, १९६१ तक बट्टीनाथ, जोशीमठ तथा समीपवर्ती क्षेत्रों का दौरा किया था। स्थानीय जनता में इन दौरों से यह धारणा उत्पन्न हुई कि शासन उनके कल्याण के सम्बन्ध में विशेष दिलचस्पी ले रहा है। नये जिलों में जो विस्तृत विकास कार्य हो रहा है उससे वे उत्साहित प्रतीत हुए। इन कार्यों द्वारा उनके और देश के भागों के मध्य जो भावात्मक कड़ियाँ हैं वे और सुदृढ़ होती प्रतीत होने लगीं। कई स्थानीय आवश्यकताएँ प्रकाश में आयीं और उन्हें तुरन्त पूरा किया गया।

सड़कों पर होने वाले कार्य की प्रगति सन्तोषजनक रही। सामग्री का अभाव, भूमि की अध्याप्ति में क्लिब, भारी सामग्री और यशोनों को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने से सम्बन्धित स्थानीय कठिनाइयों की छानबीन की जा रही थी और कार्य का इस प्रकार पूर्व नियोजन किया जा रहा था कि लक्ष्यों की उपलब्धियाँ बढ़ती हुई गति से प्राप्त होती रहें।

योजनाओं के और जिलों के अनुसार उपलब्धियों का विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिया जा रहा है:—

१९६०-६१ में अन्तिम अनुदानों और वास्तविक व्यय (संस्थापन के अधीन) जो भारत-तिब्बत सीमा विकास योजनाओं, विशेष विकास योजनाओं और बागवानी तथा छोटे-मोटे सिंचाई के साधनों के लिए दिये जाने वाले दीर्घकालिक ऋणों की योजनाओं के अन्तर्गत आते थे कुल संख्या निम्नलिखित है:—

१९६०-६१ के लिए वास्तविक व्यय		
अन्तिम अनुदान		(लाखों में)
		(लाखों में)
(क) भारत-तिब्बत सीमा विकास के अन्तर्गत	३१.४०	३१.८६
(ख) विशेष विकास योजनाएं ..	१०८.२८	११२.०८३
(ग) बागवानी के विकास हेतु ऋण	२.३६	२.३६
(घ) छोटी-मोटी सिंचाई के लिए ऋण	.२०	.१७५



## प्रशासन

**राजस्व**—तीन जिलाधीशों, १२ सिविल डिबीजन अफसरों, १२ सहसीलदारों, १२ नायब सहसीलदारों तथा अन्य कम से कम संभव अमले की नियुक्तियों की गयीं और ये लोग वर्धमान तक कार्य करते रहे। कलेक्टरियों, सहसीलों तथा अन्य कार्यालयों का कार्य सुचारु रूप से चलता रहा। तीन जिलों की ट्रेजरियों को जिन्हें पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तरकाशी की पुरानी सब ट्रेजरियों को उन्नत करके खोला गया था, अतिरिक्त भवन दिये गये और वे संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही थीं। भुंसियारी की सब ट्रेजरी पूरी हो गयी थी और काम भी करने लगी थी। शेष सहसील मुख्यालयों में अन्य सब ट्रेजरियां खोलने का कार्यक्रम चलाया जा रहा था और यह आशा की जाती थी कि ज्यों ही उनके लिए नये भवन निर्माण का कार्य पूरा हुआ, ये सब ट्रेजरियां काम शुरू कर देंगी।

**पुलिस**—पुराने पुलिस थाने और चौकियों को और दृढ़ किया गया। पिथौरागढ़ जिले के दीदीहट और भुंसियारी, उत्तरकाशी जिले में बारकोट तथा चमोली जिले में चमोली और कर्णप्रयाग के सहसील मुख्यालयों में नये थाने स्थापित किये जाने की स्वीकृति दी गयी। पिथौरागढ़ जिले में अस्कोट और थल, (उत्तरकाशी जिले के) पुरोला, और (चमोली जिले के) थरालीश्री और अहालचौरी स्थानों पर नयी चौकियां यातायात नियंत्रण और विदेशियों के यातायात को नियंत्रित करने के लिए स्थापित की गयी। ये सब सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रही थीं।

**प्रान्तीय रक्षक दल**—प्रत्येक खंड में प्रान्तीय रक्षक दल के आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था की गयी, जिसमें एक जिला संगठनकर्ता और एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता थे। ये कर्मचारी खंड में होने वाले व्यापक निर्माण कार्यों के लिए सज्जदों की व्यवस्था करने में सहायता पहुंचाते रहे और रजिस्ट्रेशन, तपतीश और फौजदारी के मामलों को छोड़ कर सामान्यतः पुलिस द्वारा किये जाने वाले अन्य समस्त कार्यों को करने में जिला प्रशासन को सहयोग देते रहे।

**पीने के पानी की योजना**—पीने के शुद्ध पानी के सप्लाई की योजना पहाड़ी क्षेत्रों की एक बड़ी आवश्यकता है, अतएव इस दिशा में यथोचित ध्यान दिया गया। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली और गोपेश्वर जिला मुख्यालयों की पानी सप्लाई योजना को अन्तिम रूप दिया गया और वर्ष में उनके लिए स्वीकृति प्रदान की गयी। पाइपों की सप्लाई कम थी, जमीन ऊबड़-खाबड़ थी और यातायात की कठिनाइयां थीं, फिर भी इन कार्यों के लिए लगभग एक लाख रुपये के बजट के आवश्यक पाइप तथा अन्य सामानों का संग्रह किया गया। चमोली स्थित स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग मुख्यालय के स्थायी इंडल द्वारा सर्वेक्षण और नक्शे की तैयारी का काम पूरा कर लिया गया और आगे का काम तेजी से हो रहा था। कार्य में तेजी लाने के लिए पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में वितरण उप-मंडलों की स्थापना की गयी।

**चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य**—तीनों जिला मुख्यालयों के पुराने अस्पतालों का स्तर ऊंचा करके उन्हें सुसज्जित जिला अस्पतालों का रूप दे दिया गया। प्रत्येक जिले में एक सिविल सर्जन और आवश्यक पी० एम० एस० अधिकारी, कम्पाउण्डरों आदि की नियुक्ति की गयी। इन अस्पतालों को एक्स-रे यूनिट, आयरेशन टेबुल और अन्य आधुनिक सामानों से सुसज्जित किया गया और आवश्यक दवाइयां, पलंग आदि की व्यवस्था की गयी।

पिथौरागढ़ में पहले सरदाना और जनाना अस्पताल एक ही इमारत में थे। उन्हें पृथक किया गया। सरदाना अस्पताल में शय्याओं की संख्या १४ से बढ़ा कर २४ और जनाना अस्पताल में ६ से बढ़ा कर १६ कर दी गयी। निजी प्रयत्नों से पिथौरागढ़ में एक क्षय क्लीनिक का निर्माण किया गया। सरकारी धन से इस क्लीनिक में क्षय रोगियों की चिकित्सा करने वाले चिकित्सकों आदि की व्यवस्था की गयी। यहाँ अन्तर्वासी रोगियों की संख्या ३० तक पहुंच गयी। क्षय रोगियों को वित्तीय सहायता भी दी गयी। क्षय रोगियों को अपने लिए पोषक भोजन की पूर्ति करने के हेतु इन तीनों जिलों में २६, २५० रु० की धनराशि वितरित की गयी।

पिथौरागढ़ जिलों में अस्कोट, बेनीनाग और गंगोलीहाट तीन अन्तरिम जिला परिषद् के औषधालयों को, जो ४३,००० रुपये का सहायता अनुदान दिया गया था उसका उपयोग आवश्यक औषधियों और चिकित्सा सम्बन्धी साज-सामानों की खरीद में किया गया। ये तीनों औषधालय अपने क्षेत्रों में बड़े लोकप्रिय हुए।

प्रत्येक जिले में तीन मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र खोले गये। इन केन्द्रों के लिए प्रशिक्षित दाइयों, मेहतरों और आवश्यक सामानों की व्यवस्था की गयी।

यातायात की दृष्टि से कठिन और छिट-फुट क्षेत्रों में औषधियों की स्थानीय उपलब्धि सुविधा में वृद्धि करने की दृष्टि से तीनों जिलों में से प्रत्येक को ५०/ प्राथमिक चिकित्सा पेटियां सप्लाई की गयीं।

प्रत्येक जिले में एक सचल एलोपैथिक औषधालय और दो नये आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना की गयी और पर्याप्त कर्मचारियों, साज-सामानों और साधनों की व्यवस्था करके १७ एलोपैथिक और २४ आयुर्वेदिक औषधालयों का सुधार किया गया। इन औषधालयों से स्थानीय लोगों को चिकित्सा सुविधा में काफी वृद्धि हुई।

पिथौरागढ़ में चालू किये गये सचल औषधालयों को अस्थायी रूप से सानदेव तिब्बती शरणार्थी शिविरों के साथ लगा दिया गया, ताकि शिविर के निवासियों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा मिल सके।

पिथौरागढ़ और चमोली जिलों को दस-दस हजार रुपये और उत्तरकाशी को पांच हजार रुपये की जिन धनराशियों का प्रविधान सफाई की व्यवस्था करते हेतु दिया गया था, उससे साफ पाखाने, पेशाब खाने और पानी निकासी नालियों आदि के निर्माण में विशेष सहायता मिली।

इनमें से प्रत्येक जिले के लिए १,५०० रु० की राशि का जो प्राविधान किया गया, उसका इन जिलों में खाद्य सामग्री में मिलावट की रोकथाम की योजना को कार्यान्वित करने में पूरी तरह उपयोग किया गया। इससे इस क्षेत्र के निवासियों के हाथ बासी और गन्दा भोजन बचने पर नियंत्रण करने में सहायता मिली।

## शिक्षा

उत्तरकाशी—तीस दो अध्यापकों वाली और १४ एक अध्यापक वाली प्रारम्भिक पाठशालाएं खोली गयीं। ये पाठशालाएं संतोषजनक कार्य कर रही थीं। उत्तरकाशी के गवर्नमेंट हाई स्कूल का स्तर ऊंचा करके उसे इन्टरमीडिएट स्तर का किया गया और ग्यारहवीं कक्षा में विज्ञान का विभाग भी आरम्भ किया गया। पुरोला के जूनियर हाई स्कूल को हाई स्कूल स्तर तक पहुंचाया गया।

जिले की विभिन्न संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां और अनावर्तक आर्थिक सहायता देने में ६,३६२ रु० की रकम इस्तेमाल की गयी। जादों को छात्रवृत्तियां देने के लिए दो हजार रुपये का एक विशेष अनुदान भी स्वीकृत किया गया, जिससे उपयुक्त मामलों में ३० रुपये प्रतिमास तक की छात्रवृत्तियां दी गयीं।

चमोली—दो अध्यापकों वाली १५ प्रारम्भिक पाठशालाएं (१३ लड़कों और ३ लड़कियों के लिए) खोली गयीं और संतोषजनक कार्य करती रहीं। सात जूनियर हाई स्कूल (६ लड़कों और एक लड़कियों के लिए) भी खोले गये।

योग्य और गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और अनावर्तक आर्थिक सहायता के रूप में ६,८४६ रुपये की रकम वितरित की गयी।

गोपेश्वर में गीतास्वामी हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रांतीयकरण किया गया। कर्णप्रयाग के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में साहित्य वर्ग का समावेश किया गया। इससे वहाँ के लोगों की एक दीर्घकालीन आवश्यकता की पूर्ति हुई।

उच्च और प्राविधिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ४० विद्यार्थियों को छात्र वृत्ति के रूप में ८,००० रुपये की धनराशि दी गयी।

पिथौरागढ़—पन्द्रह एक अध्यापक वाली प्रारम्भिक पाठशालाएं आरम्भ की गयी। इनमें से पांच पाठशालाओं में एक-एक अतिरिक्त अध्यापको का प्रबन्ध किया गया। इन पाठशालाओं में विद्यार्थियों की भर्ती सख्या ५० तक बढ़ गयी। कुल मिलाकर इन संस्थाओं में लगभग ७५० विद्यार्थी शिक्षा पा रहे थे। लड़कों के लिए ४ जूनियर हाई स्कूल और लड़कियों के लिए भी एक जूनियर हाई स्कूल खोला गया। मुसियारी के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की ११वीं कक्षा में विज्ञान और कला वर्ग का समावेश किया गया।

एक सौ उन्तालिस छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति और २४३ विद्यार्थियों को अनावर्तक आर्थिक सहायता दी गयी। कई विद्यार्थियों को जो स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा ले रहे थे, छात्र वृत्ति और अनावर्तक आर्थिक सहायता दी गयी।

पिथौरागढ़ राजकीय इंटरमीडिएट कालेज, कर्णप्रयाग राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की इंटरमीडिएट कक्षाओं में प्रदेशीय शिक्षा दल योजना आरम्भ की गयी, ताकि विद्यार्थियों में अनुशासन और समाज सेवा की भावना पैदा की जा सके।

## उद्योग

उद्योग—इन नये जिलों के लिए वर्ष में स्वीकृत उद्योगों से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित किया गया। इनके अन्तर्गत किये गये कार्य का विवरण निम्नांकित है :—

उत्तरकाशी—दंदा में एक शाल बुनाई केन्द्र तथा नकुरी में एक दरी बुनाई केन्द्र खोला गया। ये दोनों केन्द्र सन्तोषजनक कार्य कर रहे थे। उत्तरकाशी के कसीदाकारी एंव बुनाई केन्द्र के ठीक काम करने की रिपोर्ट मिली थी। रतडीसौरा में एक जल चर्खा लगाया गया। उत्तरकाशी में स्थापित बढईगीरी कारखाने एवं प्रशिक्षण केन्द्र में ११,००० रु० मूल्य का माल तैयार किया गया। दस हजार रुपये मूल्य का माल बेचा गया। जादों और कोलियों को बुनाई सिखाने के लिए दंदा में एक सचल प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र खोला गया। ऊनी माल का उत्पादन बढ़ा। पूर्वगामी वर्ष में ३५,००० रु० मूल्य का ऊनी माल तैयार किया गया था, जब कि आलोच्य वर्ष में ४१,००० रु० मूल्य का माल तैयार किया गया।

स्थानीय रूप में तैयार की गयी इन वस्तुओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए एक प्रदर्शन-कक्ष और बिक्री डिपो खोला गया।

चमोली—भुंटा में एक रिगाल उपयोग केन्द्र की स्थापना की गयी और इसकी एक शाखा गैरसाई में खोली गयी। ये सन्तोषजनक ढंग से काम करते रहे और १४,००० रु० मूल्य का सामान तैयार किया।

रुद्रप्रयाग में एक प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र स्थापित किया गया। इसमें महिला प्रशिक्षार्थियों के पहले दल को कसीदाकारी, दरी बुनाई और शाल बुनाई की ट्रेनिंग दी जाती रही।

चमोली में खोले गये बढईगीरी कारखाने एवं उत्पादन केन्द्र में आवश्यक मशीनों और साज-सामानों की व्यवस्था की गयी और थोड़े समय ही में यहाँ २०,००० रु० मूल्य का सामान तैयार किया गया। तीन जल चर्खों की खरीद की गयी। इनमें से दो जल चर्खें लगाये गये और सन्तोषजनक ढंग से चल रहे थे।

ऊन जमाने वाले (ऊन कार्डिंग) स्थानीय कारीगरों को सप्लाई करने के लिए ३ लाख ६० मूल्य का तिब्बती ऊन खरीदा गया। इस जिले में ऊन को स्टोर करने और कार्डिंग करने के लिए छः गोदाम बनाये गये।

चमोली में एक प्रदर्शन कक्ष और बिक्री डिपो स्थापित किया गया, जिसकी शाखाएं बद्रीनाथ, जोशीमठ और भुइताल में खोली गयी ताकि स्थानीय रूप से उत्पादित माल की बिक्री को बढ़ाया जा सके। इन डिपो में बिक्री के लिए भारी मात्रा में ऊनी सामान बिक्री के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है।

पिथौरागढ़—धारचूला में एक रंगाई और फिनिशिंग शोड खोला गया। दीदीहाट में एक ऊन केन्द्र और तीन जगहों पर जल-चर्खा केन्द्र खोले गये। कालिका में स्थापित प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र में विभिन्न औद्योगिक कार्यों से लगभग ७० कारीगरों को प्रत्यक्ष रूप से और १५० कारीगरों को परोक्ष रूप से पूर्णकालिक रोजगार मिल रहा था।

ऋण और छात्रवृत्ति—छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये निजी उद्योगों में लगे व्यक्तियों को उत्तरकाशी में ४०,००० रु०, चमोली में ७५,००० रु० और पिथौरागढ़ में ४५,००० रु० के ऋण दिये गये। आशा थी कि इस सहायता से स्थानीय उद्योगों में उल्लेखनीय सुधार होगा। उपयोगी व्यवसायों की उच्च प्राविधिक ट्रेनिंग प्राप्त करने हेतु इन तीनों जिलों में स्थानीय प्रशिक्षणार्थियों को १२,५०० रु० की छात्र-वृत्ति दी गयी।

### पशुपालन

पशु-पालन—पशुधन विकास सम्बन्धी सभी स्वीकृत योजनाएँ इन तीनों जिलों में चालू की गयीं। ३०,००० रु० की अनुमानित लागत पर प्रत्येक जिले में दुधारू गायें और भैंसें खरीदी गयीं और इच्छुक पशुपालकों को दी गयीं।

उत्तरकाशी—मौजूदा मेढा केन्द्रों के सुधार के लिए १,५०० रु० की धनराशि का उपयोग किया गया। उन्तालिस मेढे खरीदे गये और केन्द्रों में रखे गये, जब कि प्रजनन के मौसम में भेड़ पालकों को समुन्नत किस्म के १७ मेढे दिये गये। पिथौरागढ़ में ३३ मेढे खरीदे गये और मेढा प्रजनन केन्द्रों में रखे गये।

याक साड़ों की खरीद की गयी और प्रजनन कार्य के लिए उनका रख रखाव किया जाता रहा। भेड़ों की भी खरीद की गयी और सवाई आधार पर उनका वितरण किया गया। उत्तरकाशी में १,४००, पिथौरागढ़ में १,००० और चमोली में लगभग ६०० भेड़े दी गयीं।

इन तीनों में से प्रत्येक जिले में एक सचल चिकित्सालय और एक खच्चर केन्द्र खोला गया और आवश्यक कर्मचारियों और साज-सामानों से सुसज्जित किया गया। उत्तरकाशी यूनिट से आशा की जाती थी कि वे जादू लोगो (पहाड़ी लोगो की खानाबदोश पशुपालक जाति) के साथ चलती रहे।

चराई के अतिरिक्त व्यवस्था की तत्काल आवश्यकता प्रतीत हुई। अतएव आर्थिक सहायता और ऋणखंडों के माध्यम से गांव सभाओं को दिये गये ताकि वे मौजूदा चरागाहों का सुधार कर सकें। १९६०-६१ में इस सिलसिले में उत्तरकाशी में १०,००० रु०, पिथौरागढ़ में १६,००० रु० और चमोली में लगभग ७,००० रु० का उपयोग किया गया।

### बागवानी

उत्तरकाशी—पौध सुरक्षा की मौजूदा टीमों को कर्मचारियों और साज-सामानों से सुसज्जित करके मजबूत बनाया गया। बरोठी और बरकोट में दो ऊन केन्द्र स्थापित किये गये। ये केन्द्र बड़े लोकप्रिय सिद्ध हुए। बागवानी करने वाले अब बगीचे लगाने, उनका पोषण करने, काटने

छांटने के लिए अधिकाधिक प्राविधिक मांग करने लगे थे। अधिक फल वृक्षों को उगाने के लिए प्रत्येक टीस का कार्य क्षेत्र १० एकड़ तक बढ़ा दिया गया। बगीचों के लिए बाड़ा लगाने के आवश्यक सामान की व्यवस्था की गयी। मालियों की प्रशिक्षण कक्षाओं के लिए एक शेड का निर्माण किया गया। आलोच्य वर्ष ने रैथल हसिल फार्म में ३१ मालियों को प्रशिक्षित किया गया। इसी प्रकार चमोली में ६० मालियों को और पिथौरागढ़ में ६३ व्यक्तियों को बागवानी के उन्नत तरीकों की ट्रेनिंग दी गयी। प्रशिक्षण प्रवधि में अभ्याथियों को छात्रवृत्ति दी जाती रही।

फलोत्पादन और शाक सब्जी की खेती को बढ़ावा देने और उत्पादकों में रुचि पैदा करने के उद्देश्य से उत्पादकों के हाथ रियायती दरो पर बेचने के लिए प्रत्येक जिले में कई हजार फल वृक्षों और बड़ी मात्रा में साग-सब्जी के बीजों की खरीद की गयी। कतिपय उत्पादकों को शाक-सब्जी की बिक्री से शीघ्र ही काफी लाभ हुआ और यह योजना बड़ी लोकप्रिय सिद्ध हुई। उत्तरकाशी केन्द्र में १,७०० पौड फलों का सामान पैक किया गया और पिथौरागढ़ में मिश्रित फलों के १०३ पौड सामान की डिब्बे बन्दी या बोतल बन्दी की गयी।

बगीचेदारों को उत्तरकाशी में दीर्घकालिक ऋण के रूप में १.६० लाख रुपये की धनराशि वितरित की गयी। इसी प्रकार चमोली में १५,००० रुपये और पिथौरागढ़ में ६१,७०० रु० नये बगीचे तैयार करने अथवा पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार करने और बाड़ा आदि लगाने के लिए वितरित किये गये। तीनों जिलों में बगीचेदारों को सहायक अनुदान भी दिये गये।

इन जिलों की स्थानीय जनता इन प्रयासों से काफी प्रभावित हुई और उसने बगीचों का औद्योगिक महत्व अनुभव किया, जिससे इन क्षेत्रों के संपन्न लोगों की आशा की जा सकती थी। इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अधिकाधिक उत्पादक आगे आ रहे थे।

## सूचना

सूचना—विकास कार्यों और उस क्षेत्र में किये गये कार्यों का पूरा-पूरा प्रचार करने के लिए इन तीनों जिलों में प्रबन्ध किये गये।

चमोली जिले में १४२ सभाएं की गयी। अल्प बचत तथा अन्य विकास योजनाओं का प्रचार किया गया। १०२ चलचित्र प्रदर्शित किये गये और लगभग ७,००० व्यक्तियों से संपर्क स्थापित किया गया। खंड स्तर पर ६ विकास प्रदर्शनियां और मेले संगठित किये गये और जिला स्तर पर एक औद्योगिक विकास मेला और प्रदर्शनी आयोजित की गयी। १५ अगस्त, १४ नवम्बर और गणतंत्र दिवस को जिले भर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रबन्ध किया गया। ७५ दृश्य-श्रव्य केन्द्र खोले गये और ३५ रेडियो सेट और २६ सेट किताबें वितरित की गयी।

पिथौरागढ़ जिले में अंग्रेजी और हिन्दी में अनेक नये संवाद जारी किये गये। गांधी जयन्ती और जौलजीवी के मेले और जिला कलाकार सम्मेलन के अवसर पर पुस्तिकाएं प्रकाशित की गयी। जिनमें विकास कार्यों और लक्ष्यों आदि सम्बन्धी तथ्यों और आंकड़ों का समावेश किया गया था।

स्थानीय संपर्क स्थापित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर १५० चलचित्रों, जिनमें पूरी लंबाई के चलचित्र भी सम्मिलित थे, का प्रदर्शन किया गया।

विभिन्न माध्यमों अर्थात् प्रदर्शनी, भाषण, सांस्कृतिक प्रदर्शन, प्लेकार्ड प्रदर्शन, कठपुतली प्रदर्शन, चलचित्र आदि द्वारा समुचित प्रचार के हेतु जौलजीवी और रामेश्वर मेलों में प्रचार शिविर संगठित किये गये।

मूनाकोट, दीदीहाट और बेरीनाग के किसान मेलों में प्रदर्शन स्टाल लगाये गये और चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रदर्शन भी किये गये।

लजीवी और पिथौरागढ़ में दो पंचवर्षीय, योजना प्रदर्शनी आयोजित की गयीं।

पिथौरागढ़ में एक सूचना केन्द्र भी खोला गया। एक सौ बीस केन्द्रों में सामुदायिक श्रवण के लिए ४५ रेडियो सेट, १०० पुस्तकों के सेट और रैंको का वितरण किया गया। योजना सप्ताह में दीवारों पर चिपकाने वाले छ. पोस्टर मुद्रित और वितरित किये गये।

उत्तरकाशी जिले में ६५ सभाएँ की गयीं, जिसमें विकास योजनाओं का प्रचार किया गया, ७६ चलचित्र प्रदर्शनो का भी प्रबन्ध किया गया और मेलों में चार प्रचार शिविर सगठित किये गये। २० रेडियो सेट और किताबों के २२ सेट वितरित किये गये।

### सामुदायिक विकास कार्यक्रम

तीनों जिलों में खोले गये २१ विकास खंडों में सामान्य सामुदायिक विकास कार्यक्रम बिना किसी अडचन के चल रहा था। इन खंडों के अन्तर्गत उत्तराखंड डिवीजन के सभी क्षेत्र आ गये।

आलोच्य वर्ष में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के एक पद का सृजन किया गया। सीमा क्षेत्र योजनाओं को शीघ्र सम्पन्न करने के लिए तीन अधीक्षण अभियन्ता हल्के और ६ कार्यकारी मंडल बनाये गये। प्राविधिक सहायता देने के लिए राज्य मुख्यालय में एक पुल डिजाइन डिवीजन और एक एलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिवीजन की स्वीकृति दी गयी। आलोच्य वर्ष में नयी योजनाओं के सर्वेक्षण और उनको अंतिम रूप देने की दिशा में अधिकांशतः प्रयास किये गये। जो कार्य किये गये उनमें आर्थिक महत्व के ७ मोटर सड़कों का निर्माण मुख्य था अर्थात् द्वारा हाट-गनई रोड, नौगाव-पुरोला सड़क, उत्तरकाशी-बरकोट सड़क, घमसाली-भीरी सड़क, ऊबीमठ-चमौली सड़क, कर्ण प्रयाग-थराली सड़क और थल-तेजम सड़क। सर्वेक्षण पूरा करने के बाद १२२ मील सड़क की होशियारदारी की योजना को अंतिम रूप दिया गया। घमसाली-भीरी सड़क को छोड़ कर इन सभी सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू किया गया और सड़क निर्माण की इन योजनाओं पर अनुमानितः कुल १३ ५ लाख रुपया खर्च किया गया।

## उत्पादन तथा वितरण

### १--कृषि

#### सामान्य

यद्यपि जुलाई और अगस्त के महीने में अत्यधिक वर्षा के कारण ज्वार, बाजरा, मकई तथा कपास की फसलो को कुछ क्षति पहुंची, फिर भी इस अवधि में हुई वर्षा से धान की फसल को लाभ हुआ। राज्य के कुछ जिलों में अगस्त, सितम्बर तथा अक्तूबर के महीनों में धीरे वर्षा के फलस्वरूप भारी बाढ़ तथा पानी जमा होने की स्थिति के कारण खरीफ की खड़ी फसल को भारी क्षति पहुंची।

१९६१ के जनवरी और फरवरी के महीनों में स्थिर रूप से हुई वर्षा में सामान्यतः रबी की खड़ी फसल को बहुत लाभ हुआ, सिवाय उन भागों में जहाँ पानी अधिक बरस गया। इसके अतिरिक्त कुछ जिलों में पानी के साथ-साथ ओले भी पड़े जिसके फलस्वरूप खड़ी फसलो को स्थानीय रूप से क्षति पहुंची। फरवरी के उत्तरार्ध में मौसम की स्थिति से भी फसलो को कुछ हानि पहुंची।

कृषि क्षेत्र तथा फसल की उपज--विभिन्न फसलो की बोयी गयी भूमि का क्षेत्रफल तथा उपज का विवरण नीचे लिखे अनुसार है ---

फसल	क्षेत्र (एकड़ों में)	उपज (टनो में)
१--चावल .. .. .	१,०१,७६,२८५	३०,२१,७६७
२--ज्वार .. .. .	२२,१०,८७७	४,८८,८२६
३--बाजरा .. .. .	२६,५८,७२६	४,१३,५३८
४--मकई .. .. .	२५,६१,७१६	६,१८,६६७
५--गन्ना .. .. .	३२,८८,६५१	३८,६८,३७६
६--गेहूं .. .. .	६६,८४,०६०	३८,५४,२५६
७--कपास .. .. .	१,६१,४३७	४६,५१८ (गांठें)
८--जौ .. .. .	४५,४२,६६१	१६,५२,३८६
९--चना .. .. .	६३,३१,२४५	१७,६५,६५१

कृषि विकास तथा प्रसार सेवा--कृषि विकास तथा प्रसार सेवा द्वारा राज्य में अन्न उत्पादन तथा अन्य कृषि उत्पादन और कच्चे माल का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जाता रहा। इसलिए अधिक क्षेत्र में कृषि तथा उत्तम बीज और सुधरी कृषि प्रणाली का सहारा लिया गया, पहले की अपेक्षा अधिक भूमि में फल वृक्ष तथा साग-सब्जियां लगायी गयी और रासायनिक खाद, हरी खाद तथा कम्पोस्ट का प्रयोग किया गया और कीड़े-मकोड़े तथा रोगों के निरोधक उपायों का सहारा लिया गया। इस अभिप्राय से विकास विभाग के कर्मचारियों को खरीफ तथा रबी अभियानों के माध्यम से क्रियाशील बनाया गया। ये अभियान राज्य भर

में विशेष रूप से चलाये गये थे और उनके विभिन्न मदों के विरुद्ध सफल उपलब्धियां हुईं। कुछ विवरण नीचे दिये जा रहे हैं :—

	एकड़
१—वह क्षेत्र जिसमें हरी खाद का प्रयोग किया गया ..	६,२३,०००
२—वह क्षेत्र जिसमें जापानी ढंग से धान की खेती की गयी	१४,०८,०००
३—वह क्षेत्र जिसमें उत्तर प्रदेशीय ढंग से गेहूं की खेती की गयी	१५,००,०००
४—वह क्षेत्र जिसमें कतार से धान की बोवाई की गयी ..	८,७६,०००
५—वह क्षेत्र जिसमें कतार से मकई की बोआई की गयी ..	६,५०,०००
६—वह क्षेत्र जिसमें कतार से खरीफ की अन्य फसलें बोयी गयी थी .. .. .	१५,२३,०००
७—वह क्षेत्र जिसमें कतार से जौ की बोवाई की गयी ..	१६,१५,०००
८—वह क्षेत्र जिसमें फलीदार फसलें लगायी गयी ..	१८,५३,०००
९—वह क्षेत्र जिसमें फसली और साग-सब्जियों में लगने वाले कीड़ों तथा रोगों के नियंत्रण सम्बन्धी उपाय किये गये .. .. .	२५,२००

राजकीय कृषि फार्म—कृषि विभाग द्वारा परिचालित फार्म चार प्रकार के थे। इनमें से शैक्षिक फार्मों का कार्य विद्यार्थियों को कृषि के वैज्ञानिक तरीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण देना था। प्रत्येक विद्यार्थी को १/२० एकड़ खेत एलाट किया गया था। अनुसंधान फार्मों में ऐसे बीजों के विकास के तकनीकी शोध का कार्य होता था, जो राज्य के विभिन्न भागों के लिए उपयुक्त हो। इसके अतिरिक्त इनमें विभिन्न क्षेत्रों के कृषकों की स्थानीय समस्याओं तथा कृषि के विभिन्न पहलुओं की छानबीन करने का कार्य भी होता था। भूमि संरक्षण तथा ऊसर को कृषि योग्य बनाने वाले फार्मों में भूमि संरक्षण तथा राज्य की ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने सम्बन्धी समस्याओं के समाधान ढूँढ निकालने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी प्रकार बीज-संवर्धन फार्मों में अनुसंधान फार्मों से प्राप्त केन्द्रक बीजों के संवर्धन का कार्य होता रहा। १९६०-६१ वर्षावधि में भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण राज्य के बीज-संवर्धन योजना के अन्तर्गत केवल एक नया फार्म खोला जा सका।

उन्नत बीजों का वितरण—द्वितीय पंचवर्षीय आयोजनावधि में प्रत्येक खंड में एक कृषि तथा दो सहकारी बीज भंडार खोले जाने को थे। उसके अनुसार १९६०-६१ के अंत तक ८७६ उन्नत कृषि बीज भंडारों की स्थापना की जा चुकी थी। उन्नत बीजों, उर्वरकों तथा खाद के वितरण से संबद्ध विवरण नीचे दिये जा रहे हैं :—

	मन
१—उन्नत खाद्यान्नों के बीज .. .. .	३०,७५,३४०
२—उन्नत जूट के बीज .. .. .	१,८६०
३—उन्नत कपास के बीज .. .. .	६,०३२
४—उन्नत तथा स्थानीय चुने हुए तिलहन के बीज .. .. .	२३,६७७
उर्वरक तथा खाद—	टन
१—अमोनियम सल्फेट .. .. .	१,०५,१४४
२—यूरिया की खाद .. .. .	२,१२१
३—अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट .. .. .	३,८११



				टन
४—कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट	..	..	..	५,५२१
५—अमोनियम नाइट्रेट	..	..	..	१५३
६—चिली से प्राप्त खाद	..	..	..	२०२
७—अमोनियम क्लोराइड	..	..	..	६८
८—सुपर फास्फेट	..	..	..	३,४८३
९—हड्डी के चूरे की खाद	..	..	..	४९
१०—नाइट्रो फास्फेट	..	..	..	२००
११—अमोनियम फास्फेट	..	..	..	५८
१२—उर्वरक मिश्रण	..	..	..	५,६७२
१३—खली की खाद	..	..	..	१,०३९
१४—सैनई	..	..	..	६०८
१५—ढेंचा	..	..	..	५२३
१६—मूंग	..	..	..	३०५
१७—लोबिया	..	..	..	४९
१८—गुआर	..	..	..	३४७

				मन
१९—पाचित हड्डी की खाद	..	..	..	५७३
२०—छिछड़ा (पाचित मांस)	..	..	..	१९६
२१—सींग तथा खुर के चूरे की खाद	..	..	..	८
२२—रक्त खाद	..	..	..	४,५४४

				टन
२३—नगर कम्पोस्ट	..	..	..	५,१३,५८०
२४—ग्राम कम्पोस्ट	..	..	..	२४,२६,९९७

				घनफुट
२५—तालाबों के तलहटों का उपयोग	..	..	..	१,३४,२७,५३०

सहायक खाद्य फसले—खाद्यान्नों पर दबाव को कम करने के अभिप्राय से फल तथा साग-सब्जियों जैसी सहायक फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया जाता रहा। विस्तृत प्रचार तथा प्रयत्नों के फलस्वरूप नीचे लिखी उपलब्धियाँ हुई :—

(१) नये उद्यानों का क्षेत्रफल	..	..	२४,३९६	एकड़
(२) पुनर्जीवित पुराने उद्यानों का क्षेत्रफल	..	..	१०,८४८	”
(३) फलों के वितरित पौधे	..	..	१६,२१,३८२	”
(४) साग-सब्जियों के वितरित बीज	..	..	२०,१८७	पौण्ड
(५) रोग मुक्त आलू का वितरित बीज	..	..	३९,९९९	मन
(६) दीर्घकालिक ऋण	..	..	४,९८,९००	रुपया

पूर्वी जिलों तथा राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में खाद्य की स्थिति में सुधार करने के अभिप्राय से प्रस्तुत वर्ष विभिन्न योजनाएं चलायी जा रही थी। इनका कुछ विवरण नीचे प्रस्तुत है :—

(१) आलू—आलू के उत्पादन एवं संवर्धन के लिए शुद्ध एवं अच्छी जाति के बीज से ७५२ एकड़ अतिरिक्त भूमि में आलू की खेती आरम्भ की गयी। इसके लिए काश्तकारों के उर्वरक साधनों में वृद्धि करने के निमित्त २ रुपया प्रति मन बीज और १५ रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से आर्थिक सहायता दी गयी।

(२) शकरकंद—सामान्य बाजार दर से ५० प्रतिशत कम दर पर लगभग ४,६८२ मन शकरकंद की लतरे लोगों को वितरित की गयी।

(३) सिधाडा—सिधाडा की फसल ६२६ अतिरिक्त एकड़ भूमि में बोयी गयी और इस फसल की काश्त करने वाली ग्राम सभाओं को ५० रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से आर्थिक सहायता दी गयी।

(४) पपीता तथा केला—काश्तकारों को पपीते के ४,३६,६६२ पौधे दिये गये। इसके अतिरिक्त केले के १,०६,७५४ अंकुर ५० प्रतिशत रियायती दर पर वितरित किये गये।

फसल प्रतियोगिताएँ—पहले की ही भांति इस वर्ष भी गेहूँ, धान, मकई, बाजरा तथा आलू जैसी प्रमुख फसलों के लिए राज्य, क्षेत्र, जिला, तहसील, कस्बा, पंचायती प्रदालत तथा ग्राम सभा के स्तर पर फसल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

जूट विकास—जहाँ तक जूट विकास योजना के लक्ष्य तथा उपलब्धियों का सम्बन्ध है वे नीचे लिखे विवरण के अनुसार थी :—

विवरण	लक्ष्य	उपलब्धिया
१—जूट के रेशों का उत्पादन (गांठों में) ..	१,४०,०००	१,३६,४००
२—वह क्षेत्र जिसमें जूट की फसल थी (एकड़ में)	५०,०००	५२,२००
३—बीजों का वितरण (मनो में) ..	..	१,८६०
४—कतार में बोआई (एकड़ों में) ..	१५,०००	१३,६००
५—उर्वरकों का वितरण, जूट की फसल पर छिड़कने के लिए (टनों में) ..	१,०००	३६०

जूट की फसल की कटाई के प्रयोग मुख्य सांख्यिक के निर्देशानुसार किये गये और प्रति एकड़ २.६७ गांठ जूट रेशों की औसत उपज पायी गयी।

कृषकों को उत्तम किस्म के जूट के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता रहा। प्रस्तुत वर्ष २,४३३ प्रतियोगियों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया और विजेताओं को ६,१२० रु० पुरस्कार के रूप में दिये गये।

उन्नत प्रणाली से जूट के काश्त के तकनीक का विशेष क्षेत्र प्रशिक्षण कर्मचारी वर्ग ग्राम सेवक तथा प्रगतिशील जूट उत्पादकों को दिया गया। विभाग के १३ सदस्य नौकरी में रहते हुये प्रशिक्षण के लिए पश्चिम बंगाल के वारिकपुर स्थित जूट कृषि अनुसंधान संस्थान में भेजे गये। इसके अतिरिक्त ३८ सदस्यों ने बहराइच जिले के घाघराघाट स्थित राजकीय जूट फार्म में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

उत्तर प्रदेश की मिलों और फुटकर खरीदारों ने ३,८०,००० मन और सहकारी समितियों ने १,५१० मन जूट का रेशा खरीदा। आलोच्य वर्ष में कलकत्ते की मिलों तथा फुटकर रोज-गारियों ने २,५६,२६० मन जूट के रेशों का उपयोग किया। इसके अतिरिक्त पहले की भांति उत्पादकों ने अपनी आवश्यकताओं के लिए भी जूट का इस्तेमाल किया।

विभिन्न श्रेणी के जूट के मूल्य उत्पादकों के लिए लाभप्रद रहे। इनके भाव ३७ रु० से ५० रुपया प्रति मन के बीच रहे।

कपास के उत्पादन का लक्ष्य १,१०,००० गांठों का निर्धारित किया गया था। इसी प्रकार कपास की खेती के लिए २,८०,००० एकड़ों का लक्ष्य था। इस विरुद्ध इस वर्ष ४६,५१८ गांठों का उत्पादन हुआ था और १,६१,४३७ एकड़ भूमि में कपास की खेती की गयी थी।

अप्रैल और मई के महीने में, जो कपास की बोआई के मुख्य महीने हैं, मुख्य रूप से सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था अপর্যप्त होने के कारण, बरसात देर से प्रारम्भ होने तथा बाद की घोर और लगातार वर्षा के कारण उपज में कमी हुई। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूरी शूषि में बोआई नहीं की जा सकी और न ऐसे मौसम में समय से मिली-जुली खेती का कार्य ही किया जा सका। अन्त में अक्टूबर के पूर्वार्द्ध में जो वर्षा हुई वह खड़ी फसल के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुई। ऐसी अवस्था में उपज में कमी होना स्वाभाविक ही था।

निम्नलिखित तीन प्रसार योजनाएं आलोच्य वर्ष में चलती रही—

(१) कपास प्रसार योजना—इसका लक्ष्य राज्य में कपास की उपज तथा कपास का क्षेत्रफल बढ़ाना था।

(२) अमेरिकी कपास की ३२०-एफ तथा २१६-एफ किस्मों और देशी कपास नं० ३५/१ के बीज प्राप्त करने तथा राज्य के पश्चिमी भाग के ११ चुने हुए जिलों में उनके वितरण की योजना।

(३) बुन्देलखंड तथा राज्य के कुछ पूर्वी जिलों में बड़े पैमाने पर बीज डालने के प्रयोग की योजना। इसका आरम्भ इस अभिप्राय से किया गया कि इन क्षेत्रों में, जिनमें लगभग दो दशक पूर्व कपास की खेती बड़े पैमाने पर होती थी, फिर कपास की खेती आरम्भ की जाय।

आलोच्य वर्ष में २,२५७ टन अमोनियम सल्फेट का प्रयोग कपास की फसल के लिए किया गया था जब कि इस अवधि के लिए ५,००० टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

तिलहन—राज्य में तिलहन के उत्पादन में वृद्धि करने की योजना जारी रखी गयी। अंडी, तिल तथा मगफली की फसलें खरीफ के मौसम में तथा अलसी, राई और सरसों की फसलें रबी के मौसम में बढ़ाने के लिए हाथ में ली गयीं।

लाख विकास—इस वर्ष ४०,००० अन्न लाखों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। दिसम्बर, १९६० तक ३३,००० अन्न लाखों का उत्पादन किया जा चुका था।

पौध संरक्षण—राज्य पौध संरक्षण सेवा द्वारा फसलों, साग-मट्ठियों, फलों एवं फल वृक्षों के विभिन्न रोगों और कीड़ों तथा गोदाम में रखे अन्न के कीड़ों की रोकथाम के कार्य किये गये। कीड़ों के नियंत्रण का कार्य १,४१,२९७ एकड़ फसलों, १,५८,६५८ वृक्षों, १,५०० पौधघर के पौधों, ८,४३२ सजावट के पौधों तथा ५ एकड़ अगूर की बेलों, १,९१६ गोदामों और ३३,३३० अन्न खाद्यान्न, दालों तथा आलू पर किया गया। १,७२६ गोदामों में और ५५,४०९ बोरो पर गोदाम के कीड़ों तथा आलू में छेद करने वाले कीड़ों को नष्ट करने के उपाय किये गये। १,३२,२४७ अन्न रबी तथा खरीफ की फसलों के बीजों को भी रोगमुक्त रखने सम्बन्धी निरोधक उपाय किये गये।

इसके अतिरिक्त अग्रगामी चूहा विनाश योजना के कर्मचारियों द्वारा १०,४२७ एकड़ फसल क्षेत्र में जंगली चूहों से फसल के बचाव का अभियान चलाया गया। विकास विभागों के २४,८६४ कर्मचारियों को पौध संरक्षण तथा टिड्डी विरोधी उपायों में प्रशिक्षण दिया गया।

टिड्डियों का विनाश—आलोच्य वर्ष में टिड्डियों की पहली लहर राज्य के १६ जिलों, आगरा, मैनपुरी, एटा, मथुरा, बुलन्दशहर, मेरठ, प्रतापगढ़, रायबरेली, जौनपुर, आजमगढ़, अलीगढ़, झांसी, हमीरपुर, सहारनपुर, सुल्तानपुर तथा मिर्जापुर में आयी। इसके पश्चात् राज्य में भिन्न-भिन्न समय पर टिड्डियों के विभिन्न रंग-रूपों के ५ और दल आये। इसके नियंत्रण के अभियान बुलन्दशहर, आगरा और झांसी जिलों में किये गये और लगभग १,६९९ अन्न टिड्डियों नष्ट की गयी। टिड्डी नियंत्रण कार्य में भाग लेने वाले संबद्ध सरकारी विभागों के कर्मचारियों, और क्षेत्र कार्यकर्ताओं को राज्य के सभी जिलों में टिड्डियों विरोधी प्रशिक्षण दिया गया।

उत्तर प्रदेश—राजस्थान सीमा पर वन रोपण—उत्तर प्रदेश राजस्थान सीमा पर १६५६-६० तक १,०२२ एकड़ भूमि में वन रोपण किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र में वनरोपण का १,७५० एकड़ भूमि का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उपयुक्त भूमि के अभाव में आग प्रगति रुक गयी थी।

कृषि शिक्षा—कानपुर के राजकीय कृषि महाविद्यालय तथा बुलन्दशहर, चिरगाव (झासी और गोरखपुर के कृषि विद्यालयों में क्रमशः स्नातक तथा डिप्लोमा स्तर पर तक प्रति-क्षण देने का कार्य जारी रहा। महाविद्यालय में कुल ५५५ विद्यार्थी तथा विद्यालयों में ४३६ विद्यार्थी आलोच्य वर्ष में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे।

#### कृषि अनुसंधान

(१) गन्ना प्रकार तथा कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान—मध्य क्षेत्र में गन्ना की सी० ओ० ३६५, सी० ओ० एस० २४५ तथा सी० ओ० एस० ५१० किस्मों ने प्रति एकड़ उपज में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि दिखलायी और सी० ओ० एस० ३२१/सी० ओ० ४२१ तथा सी० ओ० ५२७ किस्मों के स्थान इन्होंने ले लिये। चार प्रमुख किस्मों जिनकी काश्त हो रही थी वे थी—सी० ओ० एस० ४२५, सी० ओ० एस० ५१०, सी० ओ० एस० ४२१ तथा सी० ओ० ५२७ दोनों मध्य मौसमी गन्ने की किस्में सी० ओ० ३४६ तथा बी० ओ० १७ पर्याप्त अच्छी उपज वाली तथा कानी रोग से लड़ने वाली सिद्ध हुई और इन्हें इस क्षेत्र के कुछ और जिलों के लिए उपयुक्त स्वीकार किया गया। बी० ओ० १७ को तराई तथा अर्द्ध जल-मग्न अवस्थाओं के उपयुक्त समझा गया।

सी० ओ० एस० ३२१, सी० ओ० एस० २४५, सी० ओ० ४२१, सी० ओ० ६६१ तथा सी० ओ० २५६ किस्मों के गन्ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के लिये चुनी गयी सूची में थे। सी० ओ० ५२७ और सी० ओ० एस० ५१० किस्मों को पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोने के लिए दिया गया। सी० ओ० ६७५ जो एक नयी उपयोगी किस्म थी, सामान्य बोवाई के लिये दी गयी।

सी० ओ० ८५६, जो एक पुरानी किस्म थी, पूरे पूर्वी क्षेत्र बोने के लिए दी गयी और बी० ओ० १७ जो मध्य मौसमी किस्म है, फैजाबाद हल्के के लिए दी गयी सी० ओ० ८५६ जो बोने के लिए चालू की जा चुकी थी, के अतिरिक्त बी० ओ० ३२ सी० ओ० १,००७ तथा १,०४१ किस्में भी बोने के उपयुक्त थी। बोने के लिये दी गयी किस्मों में सी० ओ० एस० ५१० तथा बी० ओ० १७ ने अच्छी उपज दी। ये दोनों किस्में पेड़ी के लिए बहुत अच्छी पायी गयी।

नैनीताल के फूलबाग में ऊँची भूमि के प्रकार सम्बन्धी प्रयोग में तराई सी० ओ० १६४६ प्रति एकड़ उपज में सर्वोत्तम सिद्ध हुई। लगभग उसी जैसी दूसरे स्थान पर सी० ओ० ८४६ पायी गयी। सी० ओ० ८५६ सी० ओ० १,०४६ सी० ओ० ८४६ तथा सी० ओ० एस० ५४६ किस्में रस की दृष्टि से सबसे अच्छी सिद्ध हुई। रुद्रपुर में सी० ओ० ५२७ किस्म प्रति एकड़ उपज में सबसे अच्छी निकली। ऐसी अवस्थाओं में जहाँ पानी जमा है सी० ओ० एस० २४५, जो तराई के हल्कों में खूब प्रचलित थी, सभी दृष्टियों से सबसे अच्छी पायी गयी।

कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान—ऐगलाल तथा गामा बी० एच० सी० द्वारा उपचारित गन्ने के सेट पर्याप्त विलम्ब से यहाँ तक कि ११ अप्रैल तक बोये जाने पर भी बहुत अच्छे जमे। ६४ प्रतिशत की सबसे अच्छी जमाई बोने के ५ सप्ताह बाद पायी गयी। ऐगलाल उपचारित गन्ने की प्रति एकड़ उपज भी अनुपचारित गन्ने की अपेक्षा अधिक हुई। हेण्टाक्लोरा कन्सेन्ट्रेट घोल के उपयोग से दीपको का सफल नियंत्रण किया जा सका।

कृषि अध्ययन तथा फफूंद अध्ययन सम्बन्धी पत्र-पत्र के मौसम में बोयी जाने वाली गन्ने की फसल पर दीमक तथा छेद कर देने वाले कीड़ों के विरुद्ध गामा बी० एस० सी० के प्रयोग से कुछ लाभ नहीं हुआ जबकि बसन्त में बोयी जाने वाली गन्ने की फसलों की इन कीड़ों से रक्षा करने में यह प्रभावशाली सिद्ध हुआ। इसकी प्रति एकड़ १ पौड की मात्रा थी जिसका मूल्य ३६ रुपये पड़ता है। हेण्टाक्लोरा का शक्तिशाली घोल (३ पौड प्रति एकड़) दीमकों तथा पड़ करने वाले कीड़ों के विरुद्ध प्रभावशाली

कीटनाशक सिद्ध हुआ। इस कीटनाशक का मूल्य ४५ रुपया प्रति एकड़ आता था। १ पौड बलोरेडेन तथा ३/४ पौड ऐंटीडीन चूर्ण के रूप में प्रति एकड़ में वाराणसी में प्रयोग किया गया और उससे दीनको पर नियंत्रण पाने में सफलता हुई। घाघराघाट राजकीय फार्म में ०.१ प्रतिशत एण्ड्रीन तथा ०.५ प्रतिशत डी० डी० टी० के गन्ने की पत्तियों पर छिड़काव से चिलौटा आरिसिलिया डी पर नियंत्रण में सफलता मिली। यह विचार किया गया कि यदि गन्ने को कीटनाशक में डुबा कर बोया जाय तो कीटनाशक दवा पर खर्च ३५ रुपया प्रति एकड़ से घट कर १.८० रुपया प्रति एकड़ हो जाने की संभावना थी। गामा बी० एच०-सी० तथा एण्ड्रीन का ई० सी० २० प्रतिशत का १२ औंस तथा १६ औंस दो गैलन किरासन तेल में मिला कर धुआं देने से पाइरिला पर नियंत्रण किया जा सकता है और उस पर क्रमशः ८.६५ रुपया तथा १०.८५ रुपया प्रति एकड़ खर्च पड़ता है। सफेद मक्खियों के विरुद्ध .०५ प्रतिशत एण्ड्रीन के छिड़काव के फलस्वरूप ६३.८ प्रतिशत मक्खियां मर गयीं। एण्ड्रीन, धोल ०.०२५ प्रतिशत गामा बी० एच०-सी० धोल, .०२५ तथा फोलीडाल .०५ प्रतिशत का छिड़काव गन्ने की पत्तियों पर करने से कीड़े मारने में सफलता मिलती और खर्च भी कम होता।

(२) कृषि रसायन—(क) मिट्टी का सर्वेक्षण—अलीगढ़, कानपुर, वाराणसी, रुद्रपुर, तथा झांसी की क्षेत्रीय मिट्टी अनुसंधान प्रयोगशालाओं में मिट्टी के सर्वेक्षण तथा विश्लेषण का कार्य जारी रहा।

(ख) राज्य फार्मों में खाद सम्बन्धी प्रयोग—खाद सम्बन्धी विवरण तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों और भट्टियों में उत्पादन होने वाले खाद्यान्नों में उनके प्रयोग के तरीकों के विवरण तैयार करने की दृष्टि से विभागीय अनुसंधान फार्मों में खाद सम्बन्धी कई प्रयोग किये गये। कार्बनिक तथा अकार्बनिक उर्वरकों और खादों के उपयोग से सम्बद्ध स्थायी परीक्षण पूरा फार्म में तथा नेत्रजनित उर्वरकों के प्रयोग के समय तथा फलियों के माध्यम से उनके उपयोग के सम्बन्ध में फैजाबाद तथा कलई फार्मों में दो परीक्षण जारी रहे। उनके परिणामों की परीक्षा की जा रही थी।

(ग) लोनी मिट्टी तथा सज्जीयुक्त मिट्टी का अध्ययन (१) प्रयोगशाला में अध्ययन—धकौनी, रहीमाबाद तथा रहमान खेड़ा, राजकीय फार्मों में घुलन परीक्षणों द्वारा प्राप्त मिट्टी के नमूनों को जो उपनिवेशक, भूमि संरक्षण, उत्तर प्रदेश द्वारा विकास कार्यों के लिए लिये गये थे, विश्लेषण किया गया।

(२) पर्यवेक्षक सर्वेक्षण—२०० एकड़ से अधिक ऊसर खंडों का सर्वेक्षण उन्नाव, अलीगढ़ और मेनपुरी जिलों में जारी रहा।

(घ) काश्तकारों के खेतों में साधारण उर्वरक परीक्षण—पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी राज्य के १८ जिलों में स्थित ७२ प्रयोग केंद्रों में उर्वरकों से सबद्ध प्रयोग जारी रहे। ऐसे परीक्षणों की संख्या १,०७८ थी। इन परीक्षणों द्वारा प्राप्त परिणामों से पौधों के तीनों पोषक तत्वों—नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम, के सम्बन्ध में उर्वरक का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ। नाइट्रोजन का प्रभाव प्रायः व्यापक था जब कि फास्फोरस का प्रभाव प्रदेश के पूर्वी जिलों में अपेक्षाकृत अधिक देखा गया। पोटेशियम का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित किया गया।

(ङ) आदर्श कृषि प्रयासों के अन्तर्गत उर्वरक अनुसंधान—गेहूँ पर विभिन्न नेत्रजनित, फास्फेटिक नेत्रजन एव फास्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों के प्रयोग से सम्बन्धित जटिल प्रयोग पूरा (कानपुर) तथा वाराणसी में किये गये। नेत्रजनित उर्वरकों का प्रभाव वाराणसी में बहुत स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ जब कि फास्फेटिक उर्वरकों का प्रभाव उल्टा रहा।

(३) तिलहन—तिलहनो, दालों और मोटे अनाजों में सुधार कार्य कानपुर के मुख्य अनुसंधान केंद्र तथा कांजापुर (कानपुर), केपरवा (बदायूँ) बेलाताल (हमौरपुर) और मेनपुरी के उप केंद्रों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत चल रहा था।

मूगफनी—जल्दी उपजने वाली किस्मों में टी०एम०बी० २, आर० बी० १, के १२-२४ तथा धारवाड-२ (टी०-३२) की उपज अच्छी हुई और देर से होने वाली किस्मों में ई० सी० १०८१ (टी० ३३), टी० ११-११, टी० २८ तथा टी० एम० बी० १ की इस वर्ष फिर अन्य किस्मों की अपेक्षा अच्छी उपज हुई। बड़े दाने वाली किस्मों के प्रकार सम्बन्धी प्रयोग में ई० सी० १६६६ (टी० ६६) तथा ५,२०२ और देर वाली किस्मों में के० १, एच० जी० १ तथा पी० बी० सीधी उगने वाली दूसरी से उत्तम पायी गयी।

तिल—बलुई भूमि वाले क्षेत्रों तथा बुन्देलखंड के हल्के में वितरण के लिए बी गयी टी-४ तथा टी-१२ नयी किस्मों के बीज का संवर्धन किया गया। एफ-४ की सकलित जाति में ३४ किस्मों सबसे होनहार पायी गयीं और वे आरम्भिक परीक्षण के लिए चुनी गयी। बलुई जमीन में तिल के विकास के लिए अधिक उपज वाली कान्हे बीज की ८८-एफ-३ किस्म के एक पौध वाली जाति को आगे और अध्ययन के लिए चुना गया।

अड़ी—विभिन्न स्थानों पर अड़ी की किस्म सम्बन्धी परीक्षणों में तराई ४, टी० ३ तथा ४२०३ नम्बर की किस्में कल्याणपुर (कानपुर) तथा खेठ से बोयी जाने वाली जातियों से उपज में अच्छी पायी गयी। ५४३२, टी० एम० बी० २ तथा तराई-४ किस्मों की प्रति एकड़ उपज ग्रामखुल (झासी) में, जो बुन्देलखंड की काली मिट्टी का नमूना है सबसे अधिक रही। होनहार जातियों से सकरित किस्में निकाली गयी और एफ० १ की कुछ कतारों का एक दृष्टि से अध्ययन किया गया कि उनकी सकरण-क्षमता का अन्दाज लगाया जा सके। अड़ी के सकरित बीज के उत्पादन में उपयोग तथा रखरखाव के लिए शत प्रतिशत गर्भ केसरित कतारों में उन्हें लगाया भी गया।

अलसी—टी० ३६७ तथा टी० ६०३ किस्में जो बुन्देलखंड क्षेत्र के लिए चुनी गयी थीं उनके बीज में वृद्धि की गयी। बुन्देलखंड में तथा अगहनी धान के बाद बोने के लिए अधिक उपज देने वाली तथा मुरझाने और मण्डूर रोग से सुरक्षित जल्दी होने वाली किस्म की अलसी के विकास के लिये ५ ऐसी जातियां, जो जल्दी होने वाली किस्मों के आरम्भिक परीक्षण में सबसे अधिक होनहार पायी गयी प्रकार सम्बन्धी परीक्षण के लिए चुनी गयी। जल्दी होने वाली पीले बीज वाली ऐसी किस्मों जिनमें प्रति एकड़ उपज तथा तेल अपेक्षाकृत अधिक हो, के विकास के लिए ३६० एफ-३ किस्म की अलसी का चुनाव एफ-२ की उपजों में किया गया। मुरझाये तथा मण्डूर रोग से सुरक्षित १० किस्मों की अलसी के प्रकार सम्बन्धी परीक्षण में टी ३/२, १६७/१ तथा ६६/४-१ किस्में विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों में अपेक्षाकृत अधिक उपज देने वाली सिद्ध हुई।

राई और सरसो—तोरिया अचोहर और टी-६ वितरण के लिये चुनी गयी। लहिया (पीली सरसो) के कानपुर तथा मेनपुरी फार्मों में परीक्षणों में ३६ तथा ५ नम्बर की किस्में सबसे अधिक होनहार मानी गयीं। सब मिला कर राज्य में जितने परीक्षण किये गये उनमें ११ तथा १६ नवम्बर की किस्में सबसे अच्छी सिद्ध हुई।

(४) दालें—अरहर की जल्दी फैलने वाली किस्म टी० २१, मूग की जल्दी होने वाली तथा बहुत जल्दी उपजवाली किस्म टी० ४४, मध्यम समय में पकने वाली तथा टी० १ से अधिक उपज देने वाली टी० १२-१०/२६ किस्म अन्तिम रूप से वितरण तथा बीज संवर्धन के लिए चुनी गयी।

लोबिया की टी० २० किस्म जो जल्दी होने वाली तथा अधिक उपज देने वाली किस्म थी, अन्तिम रूप से वितरण तथा बीज संवर्धन के लिए चुनी गयी। इसके अतिरिक्त सकरण के द्वारा अच्छे किस्म की अरहर, उड़द, मूंग, लोबिया, चना, मटर तथा मसूर के विकास का कार्य अभी चल रहा था।

(५) मोटे अनाज—४४०२ (टी४) किस्म का ज्वार जो इसके पूर्व वर्ष बीज संवर्धन के लिए चुना गया था, बाजरे की एक्स मिश्रित जाति तथा छोटे किस्म के मोटे

अनाजो में सुधरे किस्म के सावां की २५ तथा ४६ किस्में राज्य में काश्त के लिए कृषको को वितरित करने के लिए दी गयी ।

(६) धान—चावल के प्रसार से संबद्ध अनुसन्धान योजना का कार्य १९५८ में आरम्भ कर दिया गया था । इसका मुख्य केन्द्र फेजाबाद तथा उपकेन्द्र बाल चन्द्रपुर (बहराइच), बांसडीह (बलिया) तथा तिसुही (मिर्जापुर) में थे । द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में दो और उपकेन्द्र—एक पहाडी धान पर अनुसन्धान कार्य के लिए सफेरा (नेनीताल) में तथा दूसरा गहरे पानी में होने वाले धान के लिए बांसडीह (बलिया) में स्थापित किये गये । उपर्युक्त केन्द्रों पर किये गये अनुसन्धान कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने के अभिप्राय से विभिन्न क्षेत्रीय अनुसन्धान केन्द्रों तथा कृषको के खेतों पर भी छुषि मौसम की विभिन्न स्थितियों में भी प्रयोग किये गये ।

नगीना में क्वारी, कतिकी तथा अगहनी धानों की ५४५ किस्में (देशी तथा विदेशी) तथा गोरखपुर में ४१५ किस्में, जिनमें १०३ संकरित जाति की किस्में भी थीं, अलग करके बीज के लिए रखी गयीं । एक नयी किस्म 'सुधार' बोन के लिए छोड़ी गयी । यह जल्दी पकने वाली किस्म थी और इसके दाने मध्यम या मध्यम मोटे किस्म के होते थे । यह राज्य के वर्षा के पानी से सिंचित होने वाले तथा बाढ़ के पहले की स्थितियों के अनुकूल थी ।

नगीना में क्वारी धानों में एन० एस० ४२ तथा सी० एच० १० ने परीक्षण में अन्य किस्मों से काफी अधिक उपज दी । कतिकी धानों के परीक्षण में सी० एच० ४ उपज में सिवाय एन० एस० जे० १५७ तथा एन० एस० जे० ६८ के अन्य सभी किस्मों से अच्छी साबित हुई ।

गोरखपुर में क्वारी के खेतों के स्तर पर किये गये परीक्षण के फलस्वरूप एन० २२ किस्म के धान जिसे बोन के लिए सिफारिश की गयी थी की उपज सबसे अधिक हुई । आंकड़ों के अनुसार एन० एस० जे० ६२, एन० एस० ५२ तथा स्थानीय सरवा धान एन० २२ के बराबर पाये गये ।

खेत में आखिरी बार पाटा लगाने के समय प्रति एकड़ ६० पौण्ड नेत्रजन अमोनियम सल्फेट के रूप में देने का तरीका सबसे उपयुक्त तथा सस्ता पाया गया ।

अलोच्य वर्ष में नगीना के धान अनुसन्धान केन्द्र से कुल लगभग १८६ मन धान का बीज वितरित किया गया । कटक के केन्द्रीय चावल अनुसन्धान संस्थान के निदेशक के यहां से ५ प्रकार की संकरित किस्मों के ६५० से अधिक पौधे प्राप्त हुए थे । उनके एक-एक उत्पादन का अध्ययन किया गया और उनके एफ० ३ के अध्ययन के फलस्वरूप लगभग १०८ किस्में चुनी गयीं । उसी जगह से प्राप्त एफ० ३ तथा एफ० १० की सामग्री का भी अध्ययन किया गया ।

क्वारी और कतिकी जाति की लगभग ३३७ किस्में (देशी तथा विदेशी) चुनी गयीं, जिन्हें शुद्ध रखने के लिए अलग रखा गया जिससे उनके बीज की वृद्धि की जा सके । १९६० की खरीफ की फसल के समय क्वारी तथा कतिकी की किस्मों के दो आरम्भिक तथा तीन खेतों के स्तर पर परीक्षण किये गये । क्वारी धान की किस्मों में स्थानीय जुलिया के दुहरे, आरम्भिक परीक्षण में महत्वपूर्ण परिणाम निकले । इसके बाद नम्बर था बांकवा (स्थानीय) एन० एस० १३५, एन० एस० ३१ और एन० एस० ४२ का जो एक जैसे पाये गये । खेतों में ८ किस्म के क्वारी धानों के परीक्षण में एन० ४०, एन० २७ तथा सी० एच० १० के उत्साहजनक परिणाम निकले । इसी प्रकार ८ कतिकी धान की किस्मों का बेहन और रोपनी की स्थितियों में परीक्षण किया गया । टी० ४३ और टी० २१ उपज में स्थानीय बांकवा धान की अपेक्षा काफी अच्छे पाये गये । रोपनी की स्थिति में अन्य परीक्षणों में एन० एस० जे० १५७, एन० एस० जे० १६२, सी० एच० ४, एन० एस० जे० ६८ तथा एन० एस० जे० ६४ की उपज स्थानीय धान बांकवा से काफी अधिक रही ।

आलोच्य वर्ष में गहरे पानी में उत्पन्न होने वाली स्थानीय धानों के नमूने जोर-शोर से इकट्ठे किये गये और शुद्ध जाति के धानों को अलग किया गया। उनके बढाव तथा जड़ की मजबूती का अध्ययन किया गया। पानी में डूबे रहने से संबद्ध परीक्षण भी चार भिन्न-भिन्न किस्म के विभिन्न अवस्थाओं के धान के छोटे पौधों को भिन्न-भिन्न अवधि तक पानी में डुबाये रख कर किये गये। गहरे पानी में होने वाले धान की देशी तथा विदेशी किस्मों का खेत में सफल परीक्षण किया गया।

(७) रबी के अन्न तथा आलू—मण्डूर प्रतिरोधक गेहूँ के उत्पादन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा राज्य सरकार की संयुक्त आर्थिक सहायता से परिचालित योजना भी १९५६ से चल रही थी, क्योंकि मण्डूर द्वारा गेहूँ की फसल को प्रति वर्ष भारी क्षति पहुँचती थी। इसके अतिरिक्त राज्य की विभिन्न कृषि मौसम संबंधी स्थितियों के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए, प्रकार संबंधी परीक्षण पूरे उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों, राजकीय फार्मों तथा कृषकों के खेतों में किये गये।

१९५६-६० के अनुसंधान संबंधी स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार प्रयोग कार्य पूरी फसल के आकड़ों के अंकन तथा आकड़ों के अक संबंधी विश्लेषण के पश्चात् सफलतापूर्वक पूरे किये गये। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों, राजकीय फार्मों में तथा काश्तकारों के खेतों में बहुत से परीक्षणों द्वारा आकड़ों एकत्र किये गये और उनको रिकार्ड किया गया, विश्लेषण किया गया और उनसे एक नतीजे पर पहुँचा गया। इसी प्रकार १९६०-६१ के रबी की अवधि में प्रयोगों का स्वीकृत कार्यक्रम यथाविधि आरम्भ किया गया और राज्य भर में भारी संख्या में परीक्षणों का कार्यक्रम बनाया गया।

कृषि विभाग द्वारा विकसित उत्तर प्रदेशीय ढग से गेहूँ बोने की प्रणाली जिसे सामान्यतः और विस्तृत रूप से राज्य के काश्तकारों को पहले ही सस्तुत किया गया था, की जनप्रियता बढ़ती ही गयी।

शुद्ध जाति के लगभग २० मन गेहूँ, १० मन जौ तथा ३१८ मन आलू के बीज संवर्धन के लिए वितरित किये गये। उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों के बीज भंडारों तथा राजकीय कृषि फार्मों से गेहूँ के २,३२६ नमूनों तथा जौ के ८७० नमूनों के खेतों का परीक्षण किये गये जिससे उन के जमने तथा जाति की शुद्धता दर्ज की जा सके। गेहूँ और जौ की उन्नत जातियों की प्रदर्शन पेटिकाओं के बहुत से सेट तैयार कराये गये और जिले के कर्मचारियों को वितरित किये गये। इसके अतिरिक्त प्रदर्शनियों तथा गोष्ठियों आदि के लिए भी प्रदर्शन पेटिकाएँ तैयार की गयी थी। विभाग ने कई प्रदर्शनियों, किसान सम्मेलनों तथा किसान गोष्ठियों में भाग लिया और प्रदर्शनीय वस्तुओं, भाषणों तथा वाद-विवादों के माध्यम से कृषकों को अनुसंधानों के आधुनिकतम परिणामों से अवगत कराया गया।

कृषि विद्यालयों, कृषि महाविद्यालयों के छात्रों के बड़े-बड़े दल प्रगतिशील कृषक तथा अधिकारी, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों को देखने आये। कृषि अनुसंधान के परिणामों के सबध में हिन्दी तथा अंग्रेजी के कई प्रकाशन निकाले गये।

(८) कपास—राज्य में कपास संबंधी अनुसंधान कार्य, विभिन्न क्षेत्रों में चार योजनाओं के अन्तर्गत हो रहा था। इसका अभिप्राय ज्यादा उपज देने वाली, लम्बे रेशे की देशी और अमेरिकी कपास का उत्पादन तथा कपास के अधिकतम उत्पादन के लिए उपयुक्त कृषि प्रणाली का निश्चय करना था।

देशी कपास—दूसरे राज्य से प्राप्त मध्यम रेशे की देशी कपास का अध्ययन किया गया। बम्बई से प्राप्त सी० जे० ७३, मद्रास से प्राप्त के० ६ तथा हैदराबाद से प्राप्त गौरानी कपास का उपयोग ३५/१ के साथ संकरण के लिए किया जा रहा था। पंजाब की देशी कपासों के नमूने



उत्तर प्रदेश की जलवायविक स्थिति में अध्ययन के लिए चुने गये। दूसरे राज्यों से प्राप्त कपास की किस्मों से संकरित किस्मों से प्राप्त एफ० १ तथा एफ० २ सामग्री और ३५/१ के अध्ययन से ऐसी किस्में निकली जो उपज और गुण में अच्छी थी। कुछ किस्मों में रेशे ०.६८ इंच तक लम्बे थे जो देशी कपास के लिए अभूतपूर्व उपलब्धि थी।

प्रारम्भिक परीक्षण की अवस्था में १६७-३ के ३५/१ या सी० ५२० के साथ संकरणों में ३५/१ तथा रानी बेन से अधिक उपज वाली किस्में अब उपलब्ध थी जिनमें बिनौला निकालने के बाद कपास का प्रतिशत भी अधिक था और किस्म भी अच्छी थी। ३६/५ बी तथा १६७-३ के संकरणों से भी अच्छे किस्म की कपास निकली जिसमें बिनौले निकालने के बाद रुई का प्रतिशत भी अच्छा था और उपज भी अधिक थी।

विकसित अवस्थाओं में १६७-३ के सी ५२०, ३५/१ तथा ३६/५ बी के संकरण कटाई की दृष्टि से अच्छे तथा लिट की लम्बाई की दृष्टि तथा उपज दृष्टि से ३५/१ के समान थे। इन किस्मों का कटाई की दृष्टि से मूल्य ३५/१ के १३ एस के विरुद्ध २१ एस तथा २७ एस के एच० एस० डब्ल्यू० सी के बीच था।

ऊँची किस्मों की उपज पी० एम० निस्टेल/५ और एम० एम्ब और ऐम/६ उपज तथा रुई की दृष्टि में उसी वर्ग में आती थी जिसमें २१६ एफ बाद की किस्म का कटाई की दृष्टि से २१६ एफ के ३३ एस के विरुद्ध ४१ एस के समान थी। अन्य संकरित किस्म ईरान १/६× पी ऐम/४ के रेशे की मध्यमान लम्बाई ०.६८ इंच थी। उसका कटाई मूल्य ३६ एच० एस० डब्ल्यू० सी० थी।

वैज्ञानिक कृषि की दिशा में उर्वरक, काशत तथा कृषि क्रम के संबंध में राया और मेरठ में प्रयोग किये गये। उर्वरक संबंधी परीक्षण में यह पता लगा कि नेत्रजनित खाद के अधिक मात्रा में प्रयोग से कपास की उपज में वृद्धि हुई। पी२ ओ४ तथा के२ ओ का मुख्य प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं हुआ। बोआई में, 'आंकडा बीच-बीच में स्थान छोड़ने तथा उर्वरकों के उपयोग से संबद्ध परीक्षण' में निकटतर जगह छोड़ने से अधिक दूरी पर जगह छोड़ने की अपेक्षा उपज अधिक हुई और ५० पौण्ड एन० के० प्रयोग से बिना खाद की फसल की अपेक्षा अधिक उपज हुई। २१६ एफ से संबंधित एक दीर्घकालिक क्रमवार परीक्षण जो १६५६ से राया में चल रहा था, जारी रहा। मिश्रित फसल प्रयोग में शुद्ध जाति की ३५/१ अन्य किस्मों से अर्थोपार्जन में बहुत अधिक उत्तम सिद्ध हुई।

(६) तम्बाकू—तम्बाकू का कार्य दो योजनाओं के अन्तर्गत चल रहा था। ये योजनाएँ थी—(१) देशी तम्बाकू (हुक्का, बीड़ी तथा खैनी) के विकास की योजना, (२) भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति और राज्य सरकार के परस्पर सहयोग से नाटू तम्बाकू के प्रचलन तथा काशत की योजना।

एन० पी० एस० २१६, जो हुक्का में पीने वाली तम्बाकू की एक सुधरी हुई किस्म है, राज्य में बहुत अच्छी सिद्ध हुई और उसे ही काशतकार बो रहे थे। एन० पी० एस० २१६ का १६० किलोग्राम नाभि बीज का उत्पादन काशतकारों में वितरण के लिए किया गया। खैनी तम्बाकू की किस्मों में बोरी मालीनगर की सबसे अधिक उपज रही। इसी प्रकार बीड़ी में प्रयोग होने वाली तम्बाकू की किस्मों के परीक्षण में सेल्फ २२-६४ की सबसे अधिक उपज पायी गयी।

प्रति एकड़ में २०० पौण्ड नेत्रजनित खाद (जिसे आधी खली तथा आधा अमोनियम सल्फेट के रूप में हो) के प्रयोग से लगातार तीन वर्षों में बीड़ी वाली तम्बाकू की सबसे अच्छी उपज होती रही। १५० पौण्ड प्रति एकड़ नेत्रजनित खाद (आधा सोप के चूरे तथा आधा अमोनियम सल्फेट के रूप में) के प्रयोग से खैनी तम्बाकू की सबसे अच्छी उपज रही। इसकी पुष्टि गत तीन वर्षों में हो गयी थी।

जी० एफ० ए० तथा जी० एफ० बी०, डुम्बारा तथा डब्ल्यू० ए० एफ० किस्मों की नाटू तम्बाकू उत्तर प्रदेश में अच्छी प्रकार उपज रही थी और अक्टूबर तथा मार्च में इनके रोपण का उपयुक्त समय था ।

तम्बाकू की खेती के विभिन्न पहलुओं के संबंध में “इंडियन टोबैको तथा कृषि और पशुपालन” पत्रिकाओं में कई लेख प्रकाशित किये गये ।

तम्बाकू की खेती के प्रसार का कार्य भारत सरकार के सहयोग से फर्रुखाबाद तथा सहारनपुर क्षेत्रों में चल रहा है । आलोच्य वर्ष में हुए इस कार्य का विवरण नीचे प्रस्तुत है—

(१) एन० पी० एस० २१६ का बीज नि शुल्क वितरित	..	८० पौण्ड
(२) हुक्का में प्रयोग की नाटू की सुधरी जाति तथा रोगमुक्त सिगरेट की तम्बाकू की खेती जिस क्षेत्र में हुई..	..	१,०२० एकड़
(३) तम्बाकू की फसलों के उपयोग के लिए नियंत्रित दर पर अमोनियम सल्फेट की व्यवस्था ..	..	३,०६३ बोरे

(१०) भूमि संरक्षण—राज्य में भूमि संरक्षण का कार्य (१) भूमि संरक्षण अनुसंधान तथा (२) भूमि संरक्षण प्रसार—इन दो भागों में विभक्त किया गया था अनुसंधान कक्ष में कार्य और योजनाओं के अन्तर्गत विभक्त किये गये थे । ये योजनाएँ थीं:—

- (१) ऊसर भूमि तथा कटी भूमि को कृषि योग्य बनाना
- (२) भूमि संरक्षण प्रशिक्षण
- (३) भूमि संरक्षण प्रदर्शन
- (४) ऊसर को कृषि योग्य बनाने का प्रसार कार्य

प्रसार की दिशा में नीचे लिखी तीन योजनाएं परिचालित की गयी—

- (१) कृषीय भूमि में भूमि संरक्षण प्रसार योजना
- (२) सूखी कृषि की प्रगाढ़ता तथा परियोजनाओं के प्रदर्शन की योजना
- (३) खारों के कृषि के उपयोग के लिए सर्वेक्षण की योजना

इन योजनाओं के अन्तर्गत ४६,४५० एकड़ भूमि का सर्वेक्षण किया गया और कुल २०,०८८ एकड़ से अधिक भूमि में भूमि संरक्षण संबंधी कार्य किये गये । आगरा जिले की बाह तहसील की ६,४०० एकड़ क्षार भूमि का भी कृषि के लिए उपयोग की दृष्टि से सर्वेक्षण किया गया । आलोच्य वर्ष में ४७,३३५ गज भूमि में चौतरफा मेडबन्दी तथा कण्टूरबन्दी की गयी, ७७६ अवरोध बाधों से संबंधित १५ पक्के निर्माण कार्य भी पूरे किये गये ।

(११) पौध व्याधि विज्ञान—ज्वार में गेरुई रोग—१३ किस्म और जाति के ज्वार के प्रकार संबंधी गेरुई निरोधक परीक्षण जारी रखे गये । टी० ३, ५३/१ मालवा तथा ५३/३ ग्वालियर १ किस्में गेरुई रोग प्रतिरोधक पायी गयी ।

बाजरा में लगने वाला गेरुई रोग—बाजरे की १४ किस्मों पर गेरुई निरोधक परीक्षण किये गये और ये चौदहों किस्में कृत्रिम छूत में ग्रहणशील पायी गयीं ।

मृगफली के पत्तों पर धब्बे का रोग—१० जल्दी तैयार होने वाली तथा १० देर से तैयार होने वाली किस्मों के प्रकार सबधी परीक्षण स्वाभाविक छूत की स्थिति में किये गये । जल्दी तैयार होने वाली टी० एस० बी० २ में ४-७ प्रतिशत संक्रामकता पायी गयी । देर से तैयार होने वाली किस्मों में ५ प्रतिशत संक्रामकता थी । विभिन्न प्रकार की फफूंद नाशक दवाओं के छिड़काव के प्रभाव का इस रोग पर भी परीक्षण किया गया ।

जड़ सड़ने की बीमारी—जड़ सड़ने की बीमारी के विरुद्ध २६ किस्मों का परीक्षण किया गया और उसके फलस्वरूप ई०सी० १७३६ तथा ई०सी० १,०८१ किस्में रोग प्रतिरोधक पायी गयी ।

धान का ब्लास्ट रोग—फसल को तीन बार सेरिसन तथा चूने के मिश्रण (१:६ वजन में) के छिड़काव से उपज नियंत्रित खेतों की अपेक्षा अच्छी रही ।

खरबूजा—फल पर लगने वाली मक्खी—जब फसल पर पाइरो डस्ट का छिड़काव किया गया और जब खरबूजे की जड़ में नाली बना कर इस तरह सिचाई की गयी कि शेष बेल पानी से अलग सूखी जमीन पर रही तो फलों के सड़ने में बहुत कमी हुई ।

फलीदार बीजों का टीका—फलियों की उपज पर टीके के प्रभाव के अध्ययन के लिए विभिन्न फलियों जैसे डेंचा, सनई और सेसवनिया-सेपेसीसा के बीजों में निश्चित कीटाणुओं के टीके लगाये गये । टीके लगे बीजों में बिना टीका लगे बीजों की अपेक्षा कुछ अधिक उपज हुई । गेहूं मण्डूर ४५ चुनी हुई किस्मों का मण्डूर रोग के निरोधक तत्वों का पता लगाने के लिए पर्याप्त बड़े पौधों में काले, भूरे तथा पीले मण्डूर की कृत्रिम संक्रामक स्थितियों में परीक्षण किया गया । एन० पी० ७६०, ई० ३०६६, ई० ३१३३, ई० ३१२३ तथा ई० सी० ४०५ किस्में काले मण्डूर से मुक्त पायी गयी । पीले मण्डूर का प्रकोप अपेक्षाकृत कम था । एच० डी० ५२ (३०) सहित १७ किस्में पीले मण्डूर से मुक्त थी जब कि एस० ६१ में ४० प्रतिशत प्रभाव था । स्वाभाविक संक्रामकता की स्थिति में एक्स-६१, ई० २८३६ तथा ई० २८४२ किस्में तीनों प्रकार के मण्डूर रोगों से मुक्त पायी गयी । ई० २२० किस्म में काले तथा पीले मण्डूर का प्रभाव नहीं पाया गया ।

गेहूँ में लगने वाले मण्डूर के रासायनिक नियंत्रण के संबंध में किये गये प्रयोगों से पता चला कि काले तथा भूरे मण्डूर का प्रकोप डाइथेन-जेड-७८ या ३८१८ बी के तीन बार छिड़काव से सफलतापूर्वक कम किया जा सकता है और उपज में वृद्धि की जा सकती है । यह परीक्षण फिर किया जाना था ।

करनाल बन्ट—इस रोग की विरोधकता के संबंध में ४१ किस्मों पर परीक्षण किये गये । केवल ६ किस्में के-५३, के-५६, के-६१, के-६५, एन० पी० ७१८ तथा एन० पी० ८१३ ही बन्ट से प्रभावित हुई । अन्य किस्मों पर इस रोग का कोई प्रभाव परिलक्षित नहीं हुआ ।

जौ—गेहूँ रोग (कवर्डस्टर)—गेहूँ निरोधक जांच के लिए ३१ किस्मों पर परीक्षण किये गये जिनसे पता चला कि कम से कम ६ किस्मों के-१२, के-७०, के-७१, के-७२, बाजपुर स्थानीय तथा के-२४ पर इस रोग का २ प्रतिशत तक प्रभाव था । जौ की गेहूँ पर नियंत्रण के लिए फफूंद नाशक दवा के प्रभाव का परीक्षण किया गया । सबसे अधिक प्रभावोत्पादक सेरेसन १:३२० प्रयोग था । इसके बाद थिरन १:२२४, टिलेक्स १:३५८, अग्रोसन जी-एन १:३२० तथा हेक्सासन १:३५८ का नम्बर था ।

गेहूँ लगना (लूस स्मट)—इस गेहूँ की प्रतिरोधकता के लिये २५ किस्मों पर परीक्षण किया गया । सामान्यतः संक्रामकता के प्रभाव का प्रतिशत कम था । बहुत-सी किस्मों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा ।

चना—मुरझाना रोग (विल्ट)—इस रोग से ग्रस्त एक भूमि खण्ड में चने की २४ किस्मों का परीक्षण किया गया । १०६ किस्म का चना, पुनः रोग प्रतिरोधक पाया गया ।

आलू—लेट ब्लाइट—आलू में लगने वाले लेट ब्लाइट रोग के नियंत्रण में ६ फफूंदनाशक दवाओं के प्रभाव का परीक्षण किया गया । विल्टो ५० अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली पाया गया । यह परीक्षण फिर किया जाना था ।

बरसीम—फास्फो बेंकटीरिन तथा रिजोबियम बेंकटीरिया के प्रभाव से बरसीम चरी के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि परिलक्षित की गयी ।

उत्तर प्रदेश के किसानों को नि शुल्क ३,६६० टिन और दूसरे राज्यों को नाममात्र मूल्य पर ६२ टिन बरसीम के बीज दिये गये ।

**अमरुद—मुरझाना—(विल्ट) रोग—**बस्ती के फल अनुसन्धान केन्द्र में एक अमरुद विल्ट नर्सरी की स्थापना की गयी जिससे बस्ती के फलोत्पादकों द्वारा तैयार कलमों का विल्ट प्रतिरोधक परीक्षण किया जा सके । इसी प्रकार की विल्ट नर्सरियों की स्थापना इलाहाबाद तथा कानपुर में किये जाने की उम्मीद थी । क्लोन्स ३२-१८, ३२-१२ और सुप्रीम (फ्लोरिडा) पोपेनो (फ्लोरिडा) रिवरसाइड (कैलिफोर्निया), बनारसी, (आध्र), सफेदा (सिलोन), राल्फ्स (कैलिफोर्निया), हार्ट (नैनी), राल्फ्स (नैनी), धोलका (बबई) तथा नासिक (बबई) किस्में विल्ट प्रतिरोधकता में सक्षम पायी गयीं और इनमें से लगभग आधे दर्जन का प्रयोग सफेदा से कलम तैयार करने में हो रहा था ।

**व्याधिमुक्ति प्रमाण-पत्र—**आलोच्य वर्ष में विभिन्न प्रकार के बीजों के निर्यात के सिलसिले में १८ व्याधिमुक्ति प्रमाण-पत्र दिये गये ।

**सैम्पुलो की जाच तथा परामर्श—**प्रस्तुत वर्ष पौधों की व्याधियों के कई नमूने प्राप्त हुए । इनकी जाच की गयी और नमूने भेजने वालों को उन व्याधियों के नियंत्रण के उपाय बताये गये ।

**प्रकाशन—**अंग्रेजी में २१ तथा हिन्दी में १६ पत्र या तो प्रकाशित किये गये अथवा प्रकाशन के लिए भेजे गये ।

**कृषि अभियांत्रिकी—**कृषि अभियांत्रिकी प्रभाग में हो रहे मुख्य कार्यों का विवरण इस प्रकार था—

- (१) राज्य ट्रैक्टर संगठन के द्वारा कृषि के लिए भूमि तैयार करना,
- (२) जिला सीतापुर के नीलगाव स्थित उपकरण अनुसन्धान केन्द्र के द्वारा नये कृषि उपकरणों की डिजाइन तैयार करना तथा इससे सबद्ध अनुसन्धान कार्य,
- (३) इलाहाबाद स्थित उपकरण अनुसन्धान केन्द्र के माध्यम से कृषि उपकरणों का परीक्षण,
- (४) सरकार के अन्य विभागों तथा कृषकों को फार्म इंजीनियरिंग तथा खेत के फार्मों तथा उपकरणों के संबंध में तकनीकी परामर्श देना,
- (५) उन्नत कृषि उपकरणों का कृषकों के खेतों में प्रदर्शन,
- (६) कृषि उपकरणों के स्तर तथा उनके सामूहिक उत्पादन को स्थिर बनाने रखना ।

**राजकीय कृषि वर्कशाप—**राजकीय कृषि वर्कशाप, राज्य ट्रैक्टर संगठन तथा निजी ट्रैक्टरों की छोटी-बड़ी मरम्मत में मुख्य रूप से व्यस्त रही ।

**राज्य ट्रैक्टर संगठन—**राज्य ट्रैक्टर संगठन के पास ३३ ट्रैक्टर थे और कुल २,८६,१०७ रुपये मूल्य का कार्य हुआ ।

**कृषि क्रय-विक्रय—**कानपुर, हापुड, लखनऊ, वाराणसी तथा बरेली में स्थित ५ क्षेत्रीय कार्यालय तथा गोरखपुर, फैजाबाद, आगरा, झांसी और हल्द्वानी स्थित डिवीजनल कार्यालय, जो कृषि क्रय-विक्रय प्रभाग के अधीन थे, पूर्ववत् कार्य करते रहे । अनुसन्धान कार्य तथा छोटे दुकानदारों और उत्पादकों के तेल और घी के वर्गीकरण के लिए मुख्यालय में स्थापित प्रयोगशाला एक योग्य केमिस्ट के अधीन चल रहा था ।

**कृषि उत्पादन बाजार विधेयक में,** जनवरी १९६० में मंसूर में आयोजित गोष्ठी की सस्तुतियों तथा राज्य की स्थिति के अनुसार सशोधन किया गया । विधेयक जिस प्रकार विधान मंडल द्वारा पारित किया गया उसे निकट भविष्य में भारत सरकार के पास राष्ट्रपति की

स्वीकृति के लिये भेजा जाना था। इस प्रभाग द्वारा आलोच्य वर्ष में किये गये कार्यों के महत्वपूर्ण अंश नीचे लिखे शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित किये जा सकते हैं—

- (१) सर्वेक्षण, सर्वेक्षण रिपोर्टें सहित,
- (२) विकास कार्य,
- (३) बाजार की जानकारी में सुधार के लिये समन्वित योजना,
- (४) अन्य विभागों से सहयोग एवं संयोजन,
- (५) प्रकीर्ण।

माधोगंज और आगरा के रिफ्रिजरेटर तथा कोल्ड स्टोरेज और मूंगफली के क्रय-विक्रय के संबंध में भारत सरकार को सूचना भेजी गयी। उत्तर प्रदेश के मेलो, बाजारों, हाटों और उत्पादन विनियम आदि के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही थी।

पैकेज तथा साग-सब्जियों और फलों की पैकिंग में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के संबंध में सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया था। इसी प्रकार नींबू, सतरा आदि फलों, अड़ों तथा हड्डी के चूरे की खाद के संबंध में भी सर्वेक्षण पूरे किये गये।

जौनसार भावर तथा तराई क्षेत्रों सहित राज्य के पिछड़े क्षेत्रों का विशेष सर्वेक्षण किया गया और उनके विकास की एक योजना बनायी गयी और उसे भारत सरकार के कृषि क्रय-विक्रय परामर्शदाता के पास भेज दिया गया।

तृतीय पंचवर्षीय आयोजनावधि में राज्य के विभिन्न स्थानों में १० प्रयोगशालाओं तथा १५ रिफाइनरीज की स्थापना की स्वीकृति दी गयी थी, जहाँ घी, तेल तथा अन्य कृषि उत्पादनों के वर्गीकरण का काम होना था। आमो (दशहरी तथा फजली) तथा सेव के वर्गीकरण का कार्य जारी रहा और आलोच्य वर्ष में ८ लाख आमो तथा १,०७,००० सेवों का वर्गीकरण किया गया।

आलोच्य वर्ष में विभिन्न कृषि सामानों के पैकरो की संख्या के संबंध में विवरण नीचे प्रस्तुत है—

सामान	पैकरो की संख्या			
(१) सरसो का तेल	..	..	..	३२
(२) चावल (बासमती)	..	..	..	१५
(३) गुड़ ..	..	..	..	३६
(४) बाल (सुअर के)	..	..	..	१६
(५) अंडे	..	..	.	२१
(६) चन्दन का तेल	..	..	..	४
(७) आलू (खाने के)	..	.	..	६
(८) आम	..	..		३५
(९) सनई (रेशे)	..	..	.	३१
(१०) आटा	.	..	.	२
(११) घी ..	..	..	.	२६
(१२) शहद	..	..	-	१
(१३) सेव	..	..	.	३
(१४) मक्खन	..	..	.	२
(१५) बूरा	..	..	.	३

बाजार की जानकारी सुधार के लिए समन्वित योजना—बाजार की जानकारी में सुधार के लिए समन्वित योजना के अन्तर्गत निम्न बुलेटीने लगातार प्रकाशित की जाती रही —

(१) बाजार समाचार—बारह महत्वपूर्ण मंडियों में कृषि सामानों तथा उपज के मूल्यों के संबंध में प्रकाशित साप्ताहिक समीक्षा ।

(२) 'उत्तर प्रदेश में कृषि सामानों तथा उपजों के बाजार की जानकारी' नाम में पाक्षिक समीक्षा ।

(३) उत्तर प्रदेश के बाजारों में मूल्यों के संबंध में मासिक समीक्षा ।

हापुड, कामपुर तथा लखनऊ के बाजारों के भावों के संबंध में दैनिक बुलेटिन तैयार की जाती थी और 'ग्रामीण कार्यक्रम' के अन्तर्गत आकाशवाणी, नयी दिल्ली, लखनऊ और इलाहाबाद केन्द्रों से प्रसारण के लिए भेजी जाती थी । भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक राष्ट्रीय राज्य बाजार जानकारी परिषद् भी थी । इसकी तीन उप समितियां भी थी जो विभिन्न कृषि सामग्रियों के मूल्यों के संबंध में नीति-निर्धारण में परिषद् की सहायता करती थी । राज्य कृषि क्रय-विक्रय अधिकारी भी बाजार जानकारी समिति का एक सदस्य होता था ।

राज्य कृषि-क्रय-विक्रय संगठन विभिन्न कृषि उत्पादनों के भावों की सूचना उन सरकारी विभागों को देता था जो मांगते थे । १२ मंडियों के भावों की साप्ताहिक समीक्षा खण्ड विकास अधिकारियों, उप निदेशकों, जिला नियोजन अधिकारियों, सहकारी क्रय-विक्रय समितियों तथा राज्य के गोदाम मालिकों को वर्ष भर देता रहा ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिए कई योजनाएं बनायी गयी थी जिनमें मुख्य इस प्रकार हैं —

(१) कृषि क्रय-विक्रय संगठन अनुसन्धान तथा विकास आदि को सुगठित करने की योजना,

(२) धी वर्गीकरण योजना,

(३) बाजार के नियमन की योजना,

(४) बाजार की जानकारी के सुधार की समन्वित योजना,

(५) ग्रामों के विदेशों में निर्यात से संबद्ध योजना,

(६) कोल्ड स्टोरेज योजना

प्रचार—निकट भविष्य में वर्गीकृत सामानों के प्रचार के लिए प्रबन्ध किये जाने की आशा थी । भारत सरकार के कृषि क्रय-विक्रय परामर्शदाता अधिकारी नागपुर से बाजार के नियमन तथा वर्गीकरण के संबंध की दो फिल्में देने का निवेदन किया गया । राज्य के सिनेमाघरों में प्रदर्शन के लिए कई स्लाइड भी प्राप्त किये गये ।

प्रशिक्षण—दो कृषि क्रय-विक्रय निरीक्षकों को हैदराबाद सागली में बाजार सेक्रेटरी के प्रशिक्षण के लिए तथा एक को नागपुर में कृषि क्रय-विक्रय के एक वर्ष अवधि के कोर्स में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया । वर्ष के अन्त तक स्टाफ के दस सदस्य प्रशिक्षित किये जा चुके थे और आलोच्य वर्षावधि के अन्त में दो सदस्य अभी प्रशिक्षण पा रहे थे ।

कृषि सूचना ब्यूरो—कृषि विभाग के प्रसारण के लिए कृषि सूचना ब्यूरो एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में कार्य करता रहा । 'कृषि और पशु पालन' तथा 'कृषि समाचार' इन दो पत्रिकाओं के अतिरिक्त तकनीकी तथा प्रसार साहित्य बुलेटिन, ब्रोशयोर, प्रदर्शन पुस्तिकाओं, पोस्टरों तथा रबी और खरीफ अभियान संगठित करने के संबंध में प्रसारण कार्य, कर्त्ताओं के लिए नोट की शकल में सामग्री को प्रकाशित किया गया तथा खण्ड तथा जिले के कृषि पशुपालन नियोजन एवं गन्ना विभाग के कर्मचारियों तथा कृषकों के लाभ के लिए वितरित की गयी । अपने

सीमित साधनों के बावजूद सूचना कृषि ब्यूरो पर्याप्त कार्य करने में सफल रहा। इसके द्वारा निम्नलिखित प्रसार साहित्य प्रकाशित तथा ग्राम-स्तर तक वितरित किया गया—

प्रकाशन	प्रतियों की संख्या
(१) कृषि और पशुपालन .. .. .	५०,४५५
(२) कृषि समाचार .. .. .	७१,७३६
(३) विभागीय फार्म .. .. .	३१,३००
(४) खरीफ और रबी अभियान से संबद्ध पुस्तके .. .. .	१२,८६८
(५) ब्रोशयोर .. .. .	६,२१८
(५) पुस्तिकाएं .. .. .	२५,१६४
(७) कार्ड .. .. .	३,५६०
(८) परिपत्र .. .. .	४००
(९) पत्र .. .. .	१,३००
(१०) फोल्डर .. .. .	१,३५,६२०
(११) कवर .. .. .	६६२
(१२) फिलिप बुक्स .. .. .	१,६५३
(१३) पोस्टर .. .. .	६००
(१४) बुलेटिन्स .. .. .	१०,०००
(१५) पैम्फलेट .. .. .	१०,०००
(१६) प्रकीर्ण प्रकाशन .. .. .	१७,७६३
(१७) पुनर्मुद्रण .. .. .	६५५

फीचर लेख, प्रेम रिलीज, तथा फोल्ड कवरेज इस प्रभाग के मुख्य कार्य बने रहे। महत्वपूर्ण कृषि कार्यों के लगभग १,००० फोटोग्राफ लिये गये और उनका प्रयोग विभागीय प्रकाशनों को चित्रित करने, प्रदर्शन-सामग्री तथा सामान्य प्रचार के लिए किया गया। इस प्रभाग ने अलीगढ़ में आयोजित आलू गोष्ठी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के संबन्ध में चलचित्र भी तैयार किये जिससे उनका प्रयोग किसानों में प्रचार के लिए किया जा सके। पूर्व वर्षों की भांति बहुत से प्रदर्शन चित्र तथा प्रदर्शन माडलों की डिजाइनें बनी और उन्हें तैयार करके राज्य के विभिन्न भागों में स्थानीय तथा ग्रामीण प्रदर्शनियों में भेजा गया जिससे किसानों की जानकारी बढ़े। इस प्रभाग ने राज्य के विभिन्न भागों में आयोजित विकास प्रदर्शनियों में भी भाग लिया। ग्रामों की विदेशों में बिक्री के अभिप्राय से एक योजना तृतीय पंचवर्षीय आयोजना के तीसरे, चौथे और पाचवें वर्षों में कार्यान्वित के लिए स्वीकृत की गयी। इस योजना का अभिप्राय कुछ पश्चिमी देशों में ग्राम निर्यात करना था जिससे वहां इनके लिए बाजार बने और देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त हो।

## २--राजकीय फार्म

### पतनगर फार्म

पतनगर फार्म (जिसको पहले तराई राजकीय फार्म कहते थे), जो १६,००० एकड़ भूमि में था और जिसकी स्थापना राज्य के ग्राम विकास कार्य के लिए आधारभूत सामग्री की व्यवस्था के लिए की गयी थी, अपना कार्य करता रहा। इसका मुख्य कार्य राज्य के कृषि एवं पशुपालन विभाग के माध्यम से किसानों में वितरण के लिए उन्नत बीज एवं शुद्ध नस्ल के पशु-पक्षी उत्पन्न करना था।

कृषीय उत्पादन एवं वितरण—१९६०-६१ वर्षाविधि में इस फार्म में उगायी गयी मुख्य फसले थी, गन्ना, गेहूं, मकई, धान, चना, जई तथा तिलहन ।

उत्तम किस्म (प्रथम श्रेणी) का ममस्त बीज किसानों में वितरण के लिए कृषि विभाग को दिया गया । गन्ने का कुछ हिस्सा फार्म में बीज के रूप में उपयोग के लिए रख कर शेष चीनी मिलों को दे दिया गया । आलोच्य वर्ष में ७६,७०६ मन उन्नत बीज का उत्पादन हुआ कुछ बीज जैसे लाही और जई, जिनका बीज के रूप में उपयोग की आवश्यकता नहीं थी, बँच दिये गये । प्रस्तुत वर्ष में लगभग १६,१८,४५७ मन गन्ना पैदा हुआ और चीनी मिलों को दिया गया ।

कृषि से संबद्ध इंजीनियरी तथा प्रशिक्षण—फार्म के उपयोग में आने वाले विभिन्न किस्म के ७८ ट्रैक्टरों, १४ कम्बाइनो, १ बुलडोजर, १ मोटरग्रेडर, ३ थ्रॉशरो, ३ पम्पिंग सेटो, ३ सेण्ट्री-वय एल पंपो तथा ३१ ट्रकों की छोटी-बड़ी मरम्मत तथा रखरखाव के लिए फार्म में ट्रैक्टर वर्कशॉप था । इस वर्कशॉप में सामान्य मरम्मत के कार्यों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश कृषि विश्व-विद्यालय के छात्रों को कृषि इंजीनियरी का व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी थी ।

दुग्धशाला—दुग्धशाला के समस्त पशुधन की संख्या ५०१ थी । दूध देने वाले पशुओं में १८६ मुर्रा भैंसें तथा ४२ सहिवाल गायें थी । [यह कक्ष १९४८ में फार्म के साथ जोड़ दिया गया । इसमें पशुपालन विभाग द्वारा प्रदत्त ५ मुर्रा भैंसे तथा कुछ हरियाना जाति की गायें भी थी । इसका उद्देश्य यहाँ मुर्रा भैंसों तथा सहिवाल और हरियाना जाति की गायों को उन्नति जाति का बनाना था, जिससे राज्य भर में पशुधन के विकास के लिये शुद्ध जाति के उपयुक्त साडो तथा बछड़ों का वितरण किया जा सके ।]

आलोच्य वर्ष में इस दुग्धशाला में निम्न परिमाण में दुग्ध तथा दुग्ध से उत्पादित अन्य सामानों की बिक्री हुई—

					पोण्ड
दूध	..	..	..	..	४,४६,४८३
दुग्ध धरम (मिल्क शेक)	..	..	..	..	१,४५८.८०
क्रोम	..	..	..	..	५६.००
मक्खन	..	..	..	..	७,०१५.७०
घी	..	..	..	..	४,३६२.४०
खोया	..	..	..	..	१६५.००
मक्खन निकला दूध	..	..	..	..	६४,८१२.००

प्रस्तुत वर्ष इस दुग्धशाला में ६६ मुर्रा भैंसे, २७ सहिवाल साड तथा १२१ मुर्रा पडियाँ और ६१ सहिवाल बछियाँ पैदा हुई । इनमें से २२ मुर्रा भैंसे तथा १ सहिवाल सांड पशुपालन विभाग को हस्तांतरित कर दिये गये ।

हरियाना जाति के पशु जो आरम्भ में इस दुग्धशाला के लिए भेजे गये थे और वहाँ नांद में खिलाने की प्रणाली में अच्छी तरह उन्नति नहीं कर पाये थे, उन्हें पतनगर फार्म के तीनों खण्डों में स्थानान्तरित करना पड़ा । वहाँ वे अपेक्षाकृत कम खर्च पर पल रहे थे क्योंकि वहाँ खेतों में चराई की पर्याप्त सुविधा थी । इनका दूध नहीं दुहा जा रहा था जिससे इनके बछड़े प्रजनन के कार्य के लिए उपयुक्त विकास कर सके या फार्म में जुताई के काम आ सकें । प्रस्तुत वर्ष ११ हरियाना गायें, २६ बछड़े तथा ३७ बछियाँ पशुपालन विभाग को हस्तांतरित कर दिये गये ।

कुक्कुट—कुक्कुट फार्म की स्थापना १९५० में इस उद्देश्य से की गयी थी कि राज्य तथा राज्य के बाहर के उत्साही एवं इच्छुक कुक्कुट पालकों को शुद्ध नस्ल के पक्षी दिये जा सकें । इस फार्म में इच्छुक किसानों तथा राजकीय विभागों के कर्मचारियों को कुक्कुट पालन के आधुनिक



तरीको का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी थी। आलोच्य वर्ष में ६ प्रशिक्षार्थियों को कुक्कुट-पालन का प्रशिक्षण दिया गया। प्रस्तुत वर्ष के उत्पादन आदि का विवरण नीचे प्रस्तुत है—

१—उत्पादित अण्डों की संख्या	..	..	६८,३६३
२—चूजों की संख्या	..	..	१०,५३१
३—सैने योग्य अंडे जो विकास के उद्देश्य से दिये गये	..	..	२३,६६४
४—खाने के उपयोग के अण्डे	..	..	२८,२१४
५—विकास के उद्देश्य से दिये गये चूजे	..	..	२,८३४
६—विकास के लिए दिये गये पक्षी (नर एवं मादा)			३,७८६ तथा ४,३७१
७—खाने के उपयोग के लिए बिके पक्षी	..	..	३४५
८—प्रति मुर्गा दिये गये अंडों की औसत संख्या	..	..	१८१

मत्स्य—लगभग २८ मन मछलियां १,६७८ रु० ७ ने० प० में बेची गयी। इसके अतिरिक्त आलोच्य वर्ष में १२,६७६ बीज मछलियां फार्म के तालाबों में जमा करके रखी गयी।

फलोद्यान—शुद्ध जाति के फल-वृक्षों को मुनासिब कीमत पर किसानों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से १६५०-५१ में सरकार ने १,००० एकड़ भूमि में एक फलोद्यान की स्थापना का निश्चय किया और इसके अनुसार अच्छे किस्म के आम, चकोतरा, अमरुद, लीची, आवला, कटहल, केला तथा बेल के वृक्ष ८४५४ एकड़ क्षेत्र में लगाये गये। कुछ फल-वृक्षों ने फल देना आरम्भ कर दिया था और प्रस्तुत वर्ष में २,५०४ मन, ३ सेर फल तथा २४,१६० फल के पौधे बेचे गये। आलोच्य वर्ष में ३३,००३ फल पौधे भी तैयार हुये।

संकरित मकई का बीज उत्पादन—पिछले वर्षों संकरित मकई के बीज को उठाने में पर्याप्त कठिनाई का अनुभव किया गया क्योंकि इनके दानों में पिचके हुए होते थे। इसको दृष्टि में रखते हुए केवल ३० एकड़ में ही इसका बीज उत्पादन किया गया (इलिनायस १६५६)। इसमें से नीची भूमि में बोई गयी ६ एकड़ में अति वृष्टि के कारण फसल नहीं हुई। शेष २४ एकड़ में से १८ एकड़ में बीज वाली तथा ६ एकड़ में नर पौधों की फसल बोयी गयी थी।, अनुपयुक्त मौसम, डण्ठल सूखने की बीमारी तथा चिड़ियों द्वारा अत्यधिक हानि पहुंचाने के बावजूद कुल ३५२ मन २० सेर बीज (लगभग १६ १/२ मन प्रति एकड़) उत्पन्न हुया।

राजकीय पशु एवं कृषि फार्म—प्रस्तुत वर्ष पशुपालन विभाग के अधीन ११ राजकीय फार्म थे। इनके नाम तथा स्थान और इनके द्वारा पालित पशुधन की औसत संख्या का विवरण नीचे प्रस्तुत है—

फार्म का नाम	जिला	पशुधन दूध देने वाली गायों भैंसों की	
		का औसत	का औसत
१—अंधेशनगर	.. खीरी ..	६२	३८
२—आरजी लाइस	.. वाराणसी ..	१७७	६६
३—बाबूगढ़	.. मेरठ ..	२८३	६५
४—भरारी	.. झांसी ..	५०२	१३५
५—हस्तिनापुर	.. मेरठ ..	२६५	३५
६—हमीरपुर	.. ननीताल ..	१५६	..
७—माधुरी कुण्ड	.. मथुरा ..	४५२	१०४
८—मंझरा	.. खीरी ..	२६१	..
९—निबलेट	.. बाराबंकी ..	७०	..
१०—नीलगाव	.. सीतापुर ..	१८०	५०
११—सैदपुर	.. झांसी ..	१७२	३२
योग	.. ..	२,६१३	५२८
			४२३

प्रस्तुत वर्ष असाधारण वर्षा हुई। आरम्भ में व्यक्तिगत से पानी बरसा जिसका प्रभाव खरीफ की फसलो की बुआई तथा धान की रोपनी पर पड़ा। उसके पश्चात् सितम्बर में प्रायः घोर वर्षा हुई जिसके फलस्वरूप कई फार्मों में बाढ़ आ गयी गौर फसलो की उपज को क्षति पहुची, विशेष कर गन्ना और धान को। जाड़ो में भूमि की सतह पर न्यूनतम तापमान पानी जमने की स्थिति पर पहुंच गया था जिसके कारण कुछ फार्मों पर पाला पड़ने से फसलो को क्षति पहुंची।

उपर्युक्त फार्मों के २,६१३ पशुओं में से जो ६५१ पशु दूध देने वाले थे, उनसे २४,२६३ मन दूध प्राप्त हुआ और २८५ साढ़ भी वितरित किये गये। इसके अतिरिक्त कुक्कुट-पालन प्रभाग द्वारा विकासार्थ १४,१७६ पक्षी तथा २८,८७१ अंडे वितरित किये गये। क्षेत्र में विकास से कार्य के लिए १३६ मेढे भी वितरित किये गये।

### ३-सिंचाई

#### सामान्य

खरीफ के मौसम का आरम्भिक भाग, सिवाय जून में कुछ छिट-पुट वर्षा के, वस्तुतः सूखा ही रहा। नियमित मानसून जुलाई के प्रथम सप्ताह में आरम्भ हुआ और सितम्बर के अन्त तक रहा। यद्यपि बीच-बीच में अनावृष्टि रही। रबी पलेव की मांग सामान्यतः कम रही क्योंकि अक्टूबर, १९६० में दूर-दूर तक वर्षा हुई, विशेषकर शारदा नहर के क्षेत्रों में। नवम्बर तथा दिसम्बर, १९६० मौसम सामान्यतः सूखा रहा और उस अवधि में कोर सिंचाई की मांग अधिक रही। १९६१ के जनवरी तथा फरवरी महीनों में छिट-पुट पानी बरसा जिसका रबी की फसल पर लाभप्रद प्रभाव पड़ा।

सिंचाई के लिए उपलब्ध जल की सुविधाएँ पर्याप्त थीं और राज्य भर में उनका समान उपयोग हुआ।

१९६०-६१ में कुल सिंचित क्षेत्र लगभग ८१,३४,३५५ एकड़ (३७,६५,५०० एकड़, १९६० खरीफ तथा १९६१ की रबी में ४३,६८,८५५ एकड़) था जबकि इसके पूर्व वर्ष सिंचित भूमि ६१,०८,७२१ एकड़ (संशोधित) थी। यह कमी समय से वर्षा हो जाने के कारण हुई क्योंकि इससे कृत्रिम सिंचाई साधनों की मांग में कमी हुई। प्रस्तुत वर्ष सिंचाई की अतिरिक्त सुविधाओं की जो व्यवस्था की गयी थी इसका आभास सिंचित भूमि के क्षेत्र से नहीं मिल पाया।

#### चालू नहरे तथा ट्यूबवेल

वर्ष १९६०-६१ के अन्त में कुल लगभग ४३,८३० मील चालू नहरे तथा नालियाँ थीं। इनमें २५,८०० मील लम्बी सिंचाई नालियाँ सम्मिलित थीं अर्थात् २५,१०० मील मुख्य नहरें तथा उनकी शाखाएँ और वितरिकाएँ और १८,०३० मील अन्य सिंचाई नालियाँ जैसे जल विकास नालियाँ, ट्यूबवेल, गूले इत्यादि जिनमें ५०० मील लम्बी वे सिंचन नालियाँ भी थी जो आलोच्य वर्ष में चालू की गयी थी। वर्ष के अन्त में लगभग ६,६२८ ट्यूबवेल, जिनमें २०६ नये ट्यूबवेल भी शामिल थे, चालू किये गये।

वे सिंचाई साधन जिनका निर्माण पूरा हो गया था या चल रहा था

विभिन्न सिंचाई योजनाओं की कार्यान्विति की दिशा में आलोच्य वर्ष में जो प्रगति हुयी उसका संक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत है:—

नहरें—आयोजना की योजनाओं पर आलोच्य वर्ष हुए व्यय में से १६२.७५ लाख रुपये बड़ी तथा मध्यम योजनाओं और १२२.५४ लाख रुपये छोटी सिचाई योजनाओं पर खर्च हुए।

चन्द्रप्रभा बांध, नौगढ़ बांध, शारदा सागर (प्रथम चरण) नारायणी गंडक-पोखरा नहर, सिचाई अनुसंधान संस्थान का पुनर्गठन, बानगंगा नहर, अफजलगढ़ नहर। प्रार्जन बांध, प्रतापगढ़ शाखा, सपरार बांध, ललितपुर बांध, बेलन-टोस नहर, कल्याणीशर परियोजना तथा शारदा नहर पर १,०६२ मील सिंचन नाली के निर्माण के कार्य पूरे कर लिये गये। शारदा सागर (द्वितीय चरण) तथा नानक सागर बांध और इन योजनाओं से संबंधित सिचाई नालियों के निर्माण कार्य में प्रगति जारी रही। जिरगो बांध, अपरखजुरी बांध तथा बाल्मीकि सरोवर का अधिकांश कार्य पूरा कर लिया गया था और जो सिचाई नालियां बन रही थी उन्हें चालू कर दिया गया। रामगंगा परियोजना तथा मानाटीला बांध के अन्तर्गत सिचाई नालियों का निर्माण कार्य जारी रहा। रामपुर शाखा, इटावा शाखा तथा गगसी और बासर वित्तिकाओं के रिमार्डालिंग तथा इन पर के कई पुलों की जल-प्रवाह क्षमता को बढ़ाने के सिलसिले में कार्य हो रहा था। पूर्वी जमुना नहर का रिमार्डालिंग सिवाय हैडवर्क्स के रिमार्डालिंग तथा कुछ पुलों के निर्माण के पूरा हो गया था। आगरा नहर का रिमार्डालिंग कार्य भी पूरा हो गया। इसके अतिरिक्त टाडा, दोहरीघाट तथा कुआलो पप नहरे आंशिक रूप से कार्य कर रही थी। क्योंकि अभी भी कई पम्प फिट करने शेष रह गये थे। तीसरी आयोजना में कई योजनाओं की जाच-पड़ताल की गयी थी और उनसे सम्बद्ध परियोजनाएं तैयार कर ली गयी थी।

(जहां तक प्रस्तावित सरयू तथा गंडक नहरों का सम्बन्ध था, प्रस्तुत वर्ष उनकी विस्तृत जाच-पड़ताल हाथ में ली गयी थी। गंडक नहर के मार्ग के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से मंजूरी कर लिया गया था।)

छोटी सिचाई योजनाएं—१,५०० ट्यूबवेल लगाने की परियोजना के अन्तर्गत ६५७ ट्यूबवेल पर कार्य आरम्भ कर दिया गया था और ८५७ ट्यूबवेलों का निर्माण पूरा भी हो गया। ६६२ ट्यूबवेलों को बिजली दी गयी और वे चालू कर दिये गये। गूलों के प्रचार का कार्य चल रहा था। २०० मील ऐसी गूलें वर्ष के अन्त तक पूरी कर ली गयी थी। कण्डूर-गूलों तथा छोटी सिचाई नालियों के निर्माण का कार्य पहाड़ी जिलों में काफी आगे बढ़ गया था। मैदान की छोटी योजनाओं के कार्य जैसे दक्षिण उत्तर प्रदेश में बांधों और बाधियों का निर्माण तथा विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत जल-विकास नालियों के निर्माण का कार्य समाप्ति पर था। चन्द्र प्रभा बांध की क्षमता में वृद्धि करने का कार्य प्रस्तुत वर्ष हाथ में लिया गया और उसके शीघ्र पूरा हो जाने की आशा थी।

प्रस्तुत वर्ष ४४ सहकारी ट्यूबवेल ले लिये गये। (यह निश्चय किया गया था कि ऐसे ६७ ट्यूबवेल ले लिये जाय)। प्रथम पंचवर्षीय आयोजना से चले आ रहे कई ट्यूबवेलों तथा छोटी सिचाई योजनाओं के निर्माण कार्य प्रायः पूरे हो चले थे। पहाड़ी जिलों, पूर्वी जिलों, बुन्देलखंड के जिलों तथा मिर्जापुर में चल रही छोटी सिचाई योजना तथा कई जल-विकास नालियों की योजनाओं के निर्माण कार्यों का प्रायः ६० प्रतिशत कार्य पूरा कर दिया गया था। शेष कार्य तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में जारी रखा जाना था।

बाढ़ से सुरक्षा के कार्य—बाढ़ से सुरक्षा सम्बन्धी ६ करोड़ रुपये की लागत की योजनाएं प्रायः समाप्ति पर थी। प्रस्तुत वर्ष इन कार्यों पर ४२.६२ लाख रुपये खर्च हुए। कुण्डरा धुंगी बांध का निर्माण कार्य पूरा हो गया था। रामपुर जिले के दडियाल गांव की कोसी नदी की बाढ़ से सुरक्षा के लिए बनाये जा रहे बांध का २५ प्रतिशत, लखनौटी बांध के निर्माण कार्य का ४३ प्रतिशत, बाढ़ से लखनऊ की सुरक्षा के लिए गोमती नदी के दाहिने तट पर बन रहे बांध का ६४ प्रतिशत, देवरिया जिले के छितौनी बांध के निर्माण का ७० प्रतिशत, आलमपुर की सुरक्षा के लिए हो रहे कार्य का ४८ प्रतिशत और गंगा नदी पर

जिबपुर के निकट बन रहे रिटाथर्ड बांध के निर्माण का ८० प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका था। वाराणसी तथा भदोही तहसीलों की बाढ़ से सुरक्षा के कार्य का ६३ प्रतिशत तथा चक्रिया और चन्दौसी तहसीलों में सहायता एवं बाढ़ से सुरक्षा के कार्य का ५० प्रतिशत कार्य भी पूरा कर दिया गया। जल विकास योजनाओं पर किये गये कार्यों के प्रतिशत का विवरण नीचे प्रस्तुत है—

				प्रतिशत
(१)	जलालाबाद जल-निकास	..	..	६०
(२)	हचउन्ग्या जल-निकास	..	..	५०
(३)	सिकन्दरपुर जल-निकास	..	..	५०
(४)	पहले तथा तीसरे हल्के की छोटी जल-निकास		..	६०
(५)	जिन्धरा जल-निकास	..	..	५८
(६)	कचनारी जल-निकास	..	..	७५
(७)	सिधौरा नाला जल-निकास	..	..	६०
(८)	औसरगढ जल-निकास	..	..	२०
(९)	खैरौताल ..	..	..	६६
(१०)	चैन्दीताल	..	..	६६
(११)	छोटी कोसी जल-निकास	..	..	६०
(१२)	खूर्जा जल-निकास	..	..	८०

चादपुर सियाऊ सलरा जल-निकास तथा मथुरा के नौशील बन्ध के निर्माण का कार्य प्रस्तुत वर्ष आरम्भ कर दिया गया।

ग्राम जलपूर्ति योजनाएँ—प्रस्तुत वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में जलपूर्ति तथा सफाई योजनाओं पर ४.५७६ लाख रुपये खर्च हुए। इसके अतिरिक्त पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था के लिए ८८,६७६ रुपये खर्च हुए।

#### शारदा नहर के उद्गम पर सिल्ट एक्स्ट्रैक्टर का निर्माण

शारदा नहर पर बन रहे सिल्ट एक्स्ट्रैक्टर के निर्माण का कार्य जुलाई, १९६० में पूरा हो गया और मुख्य नहर जो निर्माण कार्य की सुविधा के लिए दूसरी ओर मोड़ दी गयी थी, पुनः १ अगस्त, १९६० से सिल्ट एक्स्ट्रैक्टर से होकर बहने लगी। इसके चेनल के हेड रेगुलेटर पर फाटक भी लगा दिये गये और सिल्ट एक्स्ट्रैक्टर तथा इसके चेनल से सम्बन्धी और शेष कार्य भी पूरे कर लिये गये।

#### नयी शारदा देवहा सहायक नहर

खटीमा बिजलीघर के नीचे की ओर नयी शारदा देवहा सहायक नहर निकालने का कार्य भी इस वर्ष पूरा हो गया। इस कार्य के पूरे हो जाने से आशा की जाती थी बिजलीघर को ७५० क्यूसेक अतिरिक्त जल प्राप्त होने लगेगा।

#### जमुना जल विद्युत् योजना, प्रथम चरण

जमुना जल विद्युत् योजना के प्रथम चरण का कार्य हाथ में लिया गया और देहरादून में दिसम्बर, १९६० में जमुना निर्माण क्षेत्र नाम के एक सगठन की स्थापना की गयी जिससे कार्य सुचारु रूप से चले। इस परियोजना के अन्तर्गत हुए कार्य की प्रगति का विवरण नीचे दिया जा रहा है—

(क) डाकपाथर के निकट जमुना नदी के आरपार बांध का निर्माण—इस कार्य के लिए टेडर मांग लिये गये थे और इंजीनियरों एवं ठेकेदारों के फर्म को यह कार्य दिया जा रहा था।

(ख) ककरीट लाइन्स पावर चैनल—इस पावर चैनल की खुदाई का कार्य आरम्भ कर दिया गया था और लगभग ०.५ करोड़ रुपये की लागत का मिट्टी का कार्य समाप्त किया जा चुका था।

(ग) बिजलीघर का निर्माण—५६,००० किलोवाट की प्रतिष्ठापित क्षमता के प्रस्तावित बिजलीघर के निर्माण के सिलसिले में बिजली विभाग ने पावर प्लाट के लिए टेडर आमंत्रित किये थे और उन पर निर्णय लिया जा रहा था। बिजलीघर से सम्बद्ध अन्य भवन निर्माण कार्य चुने गये जो प्लांट के अनुरूप बने डिजाइनों के अनुसार होने थे।

### जमुना जल विद्युत् योजना, द्वितीय चरण

जमुना जल विद्युत् योजना, द्वितीय चरण के लिए एक विस्तृत परियोजना विचाराधीन थी। कालनी से इचारी तक ले जाने वाली १६ मील लम्बी सड़क के निर्माण का कार्य आरम्भ किया जा चुका था और प्रथम ८ मील में कार्य हो रहा था।

### ४-उपनिवेशन

राज्य में उपनिवेशन योजनाएँ, १९४७ में, खाद्योत्पादन में वृद्धि तथा विस्थापित व्यक्तियों, राजनीतिक-पीड़ितों, भूतपूर्व सैनिकों, कृषि स्नातकों तथा डिप्लोमा होल्डरों और भूमिहीन व्यक्तियों आदि के पुनर्वास के उद्देश्य से आरम्भ की गयी थी। उपनिवेशन क्षेत्रों में कृषि लायक भूमि बनाने तथा पुनर्वास का कार्य प्रथम पंचवर्षीय आयोजना के अन्त तक प्रायः समाप्त हो गया था। तराई तथा अफजलगढ़ उपनिवेशन योजनाओं के अतिरिक्त अन्य योजनाएँ, जैसे काशीपुर, मनुनगर, दानागिरि और गंगा खादर योजनाएँ सामान्य जिला प्रशासन के अन्तर्गत विलीन कर दी गयी।

तराई राजकीय फार्म सहित तराई उपनिवेशन योजना में कुल १,०५,०७१ एकड़ और अफजलगढ़ उपनिवेशन योजना में २४,५६७ एकड़ भूमि थी। उपर्युक्त क्षेत्रों में से ७५,००० एकड़ भूमि तराई में तथा ६,६५७ एकड़ अफजलगढ़ में कृषि योग्य बनायी गयी। यह कार्य योजना के आरम्भ से १९६०-६१ तक हुआ था।

### मजराभा भूमि

आलोच्य वर्ष में तराई में और अधिक भूमि में खेती नहीं की गयी। वर्ष के अन्त में कुल मजराभा भूमि ६०,१३० एकड़ थी। (पूर्व वर्ष की रिपोर्ट में कुल मजराभा भूमि का क्षेत्रफल ७३,६०४ एकड़ बताया गया था और इसमें खान ग्रामों की यह १०,००० एकड़ भूमि भी सम्मिलित थी जो वास्तव में तराई योजना का अंग नहीं थी। कुछ और क्षेत्र जिसे मजराभा भूमि बताया गया था, बाद में पता लगा कि वहाँ बसने वालों ने उस वर्ष खेती आरम्भ नहीं की। इसके अतिरिक्त भूमि का कुछ भाग बाद को नहर विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया।)

अफजलगढ़ उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत १९६०-६१ में १,०५४ एकड़ भूमि में खेती हुयी जिसको मिला कर इस योजना के अन्तर्गत कुल ६,६८२ एकड़ भूमि में खेती होने लगी थी।

### फसल उत्पादन इत्यादि

इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत उपजायी गयी प्रमुख फसलें धान, मकई, गेहूँ, लाही और गन्ना थी।

भूतपूर्व सैनिक सहकारी निर्माण समितियों द्वारा एक चीनी मिल खोल दिये जाने के फलस्वरूप अफजलगढ़ उपनिवेशन योजना के क्षेत्र में गन्ने के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई।

किसानों में हरी खाद के उपयोग को जनप्रिय बनाने के उद्देश्य से तराई उपनिवेशन योजना क्षेत्र में कई प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। किसानों की ओर से इस कार्य में पर्याप्त सहयोग मिला। उन्हें हरी खाद के बीज भी दिये गये।

तराई बस्ती में रासायनिक उर्वरकों का वितरण किसानों में किया गया और कृषि के अन्य उन्नत तरीकों का आरम्भ भी किया गया। अफजलगढ़ में कल्लूवाला क्षेत्र में एक बन्धी का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया और आशा की गयी कि शीघ्र ही उस क्षेत्र में पूरी सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। भिक्कूवाला क्षेत्र में एक अन्य बन्धी के निर्माण का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया और जल्दी ही उसके अनुसार कार्य आरम्भ किये जाने की आशा थी। इन सुविधाओं को दृष्टि में रखते हुए, इस बस्ती में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग तथा कृषि के विकसित तरीकों के प्रयोग की काफी गुड़जाइश थी। इस बस्ती में स्थित बीज गोदाम में उन्नत जाति के एब रोग मुक्त बीज की व्यवस्था थी और किसानों को गन्ने की आधुनिकतम किस्मों के बीजों का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। गन्ने की फसल से अच्छे पैसों मिलने थे, अतः अधिकांश किसान गन्ने की नयी किस्में ही उत्पादित कर रहे थे।

अफजलगढ़ में आलोच्य वर्ष में गन्ने के उत्पादन में ५४,३०० मन की वृद्धि हुई किन्तु खाद्यान्नों तथा चरी और अन्य प्रकार की विविध फसलों के उत्पादन में क्रमशः लगभग २२,७६१ तथा ३८,८६० मनो की कमी हुई।

### बसाये गये परिवारों की संख्या

आलोच्य वर्ष में तराई बस्ती में दो परिवार बसाये गये जिनको मिला कर इस बस्ती में कुल ४,५१७ परिवार बसाये जा चुके थे।

अफजलगढ़ उपनिवेशन योजना में इस वर्ष भूतपूर्व सैनिकों के ७७ परिवार बसाये गये, जबकि इससे पूर्व वर्ष कुल ५० परिवार बसाये गये थे। ये परिवार गंगा खादर के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र के थे।

### विकास कार्य

तराई क्षेत्र में होने वाले विकास कार्य सन्तोषजनक रहे। आलोच्य वर्ष में १,१६५ एकड़ कृषि योग्य भूमि की, मेडबन्दी द्वारा रक्षा की गयी जिससे सिंचाई सुविधाओं का भरपूर उपयोग किया जा सके। रबी और खरीफ अभियानों के समय प्रायः सभी गावों में अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम के सिलसिले में प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। १४,५६२ एकड़ से अधिक क्षेत्र में जापानी ढंग से धान की खेती की गयी। ३,१४६ एकड़ से अधिक क्षेत्र में उत्तरप्रदेशीय ढंग से गेहूँ की बीआई की गयी और ३६,५२६ एकड़ से अधिक क्षेत्र में कतार से बुआई की गयी।

अफजलगढ़ उपनिवेशन योजना में पेयजल के ३ नये कुएँ बनाये गये तथा ८ कुओं की मरम्मत की गयी। गावों में स्वच्छ जल की व्यवस्था के लिए २८० हड-पम्प लगाये गये। लोगों के स्वास्थ्य की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया। अफजलगढ़ बस्ती में भ्रमदान एक नियमित कार्यक्रम था। इस बस्ती के लोगों ने सभी प्रकार के विकास कार्यों में विशेष दिलचस्पी दिखाई और मुरलीवाला गाववालों ने अपनी बस्ती तक १ मील लम्बी कच्ची सड़क का निर्माण किया और उसे मोटर चलने लायक बनाया।

### पीलीभीत उपनिवेशन योजना

६०० भूमिहीन श्रमिकों तथा ७५ शिक्षित बेकारों के पुनर्वास तथा कृषि योग्य पडती भूमि को कृषि योग्य बना कर राज्य खाद्योत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने दिसम्बर, १९५७ में पीलीभीत उपनिवेशन योजना को कार्यान्वित करने की स्वीकृति प्रदान की। इसके अन्तर्गत पीलीभीत जिले के शारदापार भूमि खंड के १०,००० एकड़ क्षेत्र को विकसित करना तथा उसे कृषि योग्य बनाना था।

यह भूमि सरकार के खर्चों से कृषि योग्य बनायी जाकर १० एकड़ प्रति भूमिहीन श्रमिक तथा २० एकड़ प्रति शिक्षित बेकार को दी जाती थी। ३१ मार्च, १९६१ तक २,३८४ एकड़ भूमि कृषि योग्य बना ली गयी थी और एक कमरे वाले पक्के आवासों में १६३ परिवार बसाये

जा चुके थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न सड़को, पुलों, लवईयों तथा भवनादि के निर्माण कार्य १९६०-६१ में पूरे कर लिये गये। (इन भवनों की अनुमानित लागत लगभग ७,३६,७०० रुपये थी)।

यह आशा की जाती थी कि यह योजना पूरी होने पर वहाँ लगभग १२ नरी बस्तिया बनें जायेंगी (जिसमें पक्के भवनों में ६७५ परिवार रहें होंगे)। यह भी उम्मीद थी कि करीब ७५ वर्ग मील का क्षेत्र सड़को के निर्माण द्वारा सुगम हो जायगा। इस पूरे क्षेत्र में बिजली लगाने की सम्भावना थी और आशा की जाती थी कि इसके द्वारा प्रति वर्ष २,८०० बने अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादित होने लगेगा।

### ५-गन्ना विकास

चीनी विकास कार्यक्रम पर विशेष बल दिया जाता रहा है क्योंकि चीनी उत्पादन की दिशा में अन्य क्षेत्रों से जोरदार प्रतियोगिता की सम्भावना के कारण इस कार्यक्रम का महत्व पर्याप्त बढ़ गया था। उत्तर प्रदेश चीनी मिलों, गन्ना बोधी जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल तथा गन्ना उत्पादन की दृष्टि से भारतीय सघ के राज्यों में सर्वप्रथम बना रहा, किन्तु कई कारणों से (जिनका उल्लेख पिछले वर्षों की रिपोर्ट में किया जा चुका है) प्रति एकड़ उपज तथा चीनी पड़ने के प्रतिशत में यह राज्य दक्षिण भारत के अन्य राज्यों, महाराष्ट्र तथा आन्ध्र राज्यों की तुलना में उतना ही बरीयता नहीं प्राप्त कर सका। अतः प्रति एकड़ उपज, गुण तथा चीनी की पड़त का प्रतिशत बढ़ाना मुख्य अभीष्ट था, जिसे बराबर दृष्टि में रखना था।

गन्ना विकास कार्य किन्हीं अनिवार्य सीमाओं के अन्तर्गत ही किया गया जिनके कारणों का ऊपर जिक्र किया जा चुका है। आलोच्य वर्ष में निम्न योजनाओं के अन्तर्गत कार्य किया गया—

- (१) आयोजना के अन्तर्गत योजनाएं { (क) उत्तर प्रदेश में गन्ने के काश्त में विकास तथा प्रगाढ़ता की योजना।  
(ख) चीनी मिल क्षेत्रों के चारों ओर कोलतार की सड़को तथा ककरीट के मार्गों के निर्माण की योजना।

(२) आयोजनेत्तर योजना .. मुख्य गन्ना विकास योजना।

### गन्ना विकास पर होने वाला व्यय

जहाँ तक इस कार्य पर खर्च का सम्बन्ध था, द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में इसके लिए आरम्भ में ५१२ ३८ लाख रुपये की धनराशि निर्धारित की गयी थी। बाद में इसमें कमी करनी पड़ी और अन्तिम रूप से ३५४.०७ लाख रुपये की रकम निश्चिन की गयी। प्रस्तुत वर्ष आयोजना के अन्तर्गत चल रही योजनाओं पर ५६.१३ लाख रुपये तथा आयोजनेत्तर योजनाओं पर ३० ८८ लाख रुपये खर्च हुए।

गन्नों में लगने वाला काना रोग (Red rot disease) के विरुद्ध समन्वित अभियान, जो भारत सरकार की आर्थिक सहायता से चल रहा था, भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति द्वारा संस्तुत कार्यक्रम के अनुसार चलाया गया। इस कार्य पर आलोच्य वर्ष में ४१,१०० रुपये खर्च हुए। (इसके लिए १,०४,६०० रुपये की व्यवस्था थी किन्तु पूरी रकम का उपयोग न हो सकने का कारण यह था कि गन्ने के बीज के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता बहुत सीमित रखी गयी थी।) 'चीनी मिल क्षेत्रों के चारों ओर ककरीट मार्ग तथा कोलतार की सड़को के निर्माण की योजना' के लिए बजट में ४३ ५० लाख रुपये का प्राविधान था। इस योजना की कार्यान्विति का उत्तरदायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपा गया था। इस कार्य पर वास्तविक खर्च कुल २६,४०,८०० रुपये हुआ।

प्रस्तुत वर्ष के लिए गन्ना उत्पादन का लक्ष्य ७१ ५० करोड़ मन निर्धारित किया गया था और प्रति एकड़ उपज का सशोधित लक्ष्य ४५० मन था। किन्हीं कारणों वश इन लक्ष्यों के

विरुद्ध इस वर्ष क्रमशः १०१ ६८ करोड़ मन तथा ४४५ मन की उपलब्धियां हुईं। आरम्भ में द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत गन्ने की बोआई के क्षेत्रफल में कमी करने का उद्देश्य बनाया गया था और विकास कार्य ११ ०० लाख एकड़ तक ही सीमित करने तथा औसतन प्रति एकड़ ६५० मन उपज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके लिए ५१२ ३८ लाख रुपये की रकम आयोजनाबद्ध के लिये स्वीकृत की गयी थी। बाद में जबकि धन की इस व्यवस्था में कमी करके इसे ३५४ ०७ लाख रुपये कर दिया गया, गन्ने की काश्त में रोक के किसी उपाय के न किये जाने के कारण गन्ने का क्षेत्र बढ़ कर २२.६६ लाख एकड़ हो गया। अतः उपलब्ध साधनों को अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र में बखेरना पड़ा और इसका परिणाम यह हुआ कि औसत उपज के लक्ष्य में कमी पड़ गयी। किन्तु कुल मिलाकर उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य के गन्ने के उत्पादन में वृद्धि हुई क्योंकि गन्ने बोये जाने वाले क्षेत्र में वृद्धि हो गयी थी।

राज्य की प्रायः सभी ७० चीनी मिलों ने १९६० के नवम्बर के आरम्भ से ही गन्ना पेरायी आरम्भ कर दी थी और अन्तिम चीनी मिल ने २७ जून, १९६१ को गन्ना पेरना बन्द किया। यह असामान्य रूप से लम्बा कार्यकाल रहा जो १७६ दिनों तक चलता रहा। इस अवधि में कुल ४० १२ करोड़ मन गन्ना पेटा गया और कुल ३८२ १६ लाख मन चीनी का उत्पादन हुआ जबकि इसके पूर्व वर्ष ३४ २८ करोड़ मन गन्ना पेटा गया था और ३३२ १८ लाख मन चीनी का उत्पादन हुआ था। १९५६ का उत्तर प्रदेश खाडसारी निर्माण लाइसेंसिंग आदेश कोल्हू तथा खाडसारी की ओर गन्ने के परिवेक्षण बहकाव पर रोक लगाने में सफल सिद्ध हुआ। इस वर्ष चीनी का औसत पड़ना ६.५३ प्रतिशत रहा जब कि इसके पूर्व वर्ष यह पड़ता ६ ६६ प्रतिशत रहा।

### मौसम की स्थिति

वर्ष के आरम्भ में मौसम प्रायः सूखा रहा। बाद को रूहेलखंड तथा केन्द्रीय क्षेत्र में हल्की वर्षा हुई और जोर का पछिन्ना हवा चलती रही। ऐसे मौसम का प्रभाव फसल पर स्वभावतः हानिकर ही हुआ।

जून के अन्त में बरसात के आरम्भ हो जाने पर मौसम में परिवर्तन हुआ। सूखी फसल जुलाई तथा अगस्त में वर्षा के कारण लहलहा उठी सिवाय उन क्षेत्रों के जहां वर्षा का पानी जमा रह जाया करता था। अक्टूबर के महीने में घोर वर्षा के कारण कुछ केन्द्रीय तथा पूर्वी जिलों में अभूतपूर्व बाढ़ आ गयी जिसके कारण कमजोर पौधों को क्षति पहुंची। शरत् में बोये जाने वाले खेतों में कमी हुई और शरत् की बोआई में अनपेक्षित विलम्ब हुआ। कीड़ों तथा रोगों से भी फसल को काफी क्षति पहुंची। जाड़े के महीने में सामान्यतः ठंड पड़ी तथा मौसम सूखा रहा, यद्यपि जनवरी में कहीं-कहीं हल्की वर्षा हुई और उसके बाद ओले पड़े जिसके फलस्वरूप राज्य के कुछ भागों में फसल को क्षति पहुंची।

आलोच्य वर्ष के अन्त में जाकर मौसम की स्थिति दूसरी फसल की गन्ने की बोआई के लिए अनुकूल हो गयी।

### गन्ने के बीज का वितरण

गन्ने के बीज के वितरण के कार्यक्रम में प्रस्तुत वर्ष कोई परिवर्तन नहीं किया गया और पुरानी तथा अस्वीकृत किस्मों के स्थान पर अधिक चीनी के पड़ता वाले तथा रोगों से बचने की क्षमता वाले गन्नों के बीज वितरित किये जाते रहे। बीज में पौधघर रखे गये जिससे अच्छे बीज की मांग पूरी की जा सके।

कुल मिला कर २,६६२ प्रारम्भिक तथा १३,४६४ माध्यमिक बीज पौधघर रखे गये जबकि इसके पूर्व वर्ष इनकी सख्या क्रमशः २,७८५ तथा १३,३२५ थी। लगभग ५५.५२ लाख मन गन्ने का बीज वितरित किया गया। पश्चिमी जिलों में प्रचार के लिये गन्ने की एक नयी किस्म सी० ओ ६७५ भी प्रचारित की गयी।



## खाद्य एवं उर्वरक

आलोच्य वर्ष में १३.१७ लाख मन रासायनिक उर्वरक तथा १.६१ लाख मन खली वितरित की गयी, जबकि इसके पूर्व वर्ष ११.११ लाख मन रासायनिक उर्वरक तथा १.३६ लाख मन खली की खाद बांटी गयी थी।

पौधे के ऊपरी हिस्से की छटाई का कार्य मनोयोगपूर्वक जारी रखा गया और वर्ष में १०.४८ लाख एकड़ में यह कार्य हुआ जबकि इससे पूर्व वर्ष केवल ८.०२ लाख एकड़ में छटाई हुई थी। यह अनुभव किया गया कि यदि मांग के अनुसार बांटने के लिए रासायनिक खाद काफी परिमाण में समय से प्राप्त हो सकती तो और अच्छा परिणाम प्राप्त किया जा सकता था।

भूमि की उर्वरता बढ़ाने की दृष्टि से सीमित पैमाने पर हरी खाद का उपयोग किया गया, क्योंकि हरी खाद के बीज की कीमतें बहुत बढ़ गयी थीं और उनकी प्राप्ति भी सुविधानुसार नहीं हो सकी। आलोच्य वर्ष में ०.२१ लाख मन बीज वितरित किये गये जबकि इसके पूर्व वर्ष ०.२७ लाख मन बीज वितरित किये गये थे।

## कम्पोस्ट

प्रस्तुत वर्ष में १११.३२ लाख मन कम्पोस्ट खाद का उत्पादन हुआ जबकि इसके पूर्व वर्ष कुल १०१.७३ लाख मन कम्पोस्ट तैयार हुआ था। इसके अतिरिक्त फ़ैक्टरी के कूड़े व कचरे से तैयार कम्पोस्ट इस वर्ष १०.२० लाख मन हुआ जबकि इसके पूर्व वर्ष इस प्रकार कुल १०.१४ लाख मन कम्पोस्ट तैयार हुआ था।

## क्षेत्र-प्रदर्शन

शाहजहापुर डी० एस० आर० की सिफारिशों के अनुसार विभिन्न प्रकार के क्षेत्र-प्रदर्शनों की व्यवस्था राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में की गयी। आलोच्य वर्ष में विभिन्न प्रकार के कुल १४,७७० क्षेत्र-प्रदर्शनों का आयोजन किया गया जबकि इसके पूर्व वर्ष इनकी संख्या १८,५८७ थी। ये प्रदर्शन कृषि बीज की किस्मों, उर्वरकों, पेड़ी लगाने, चक्र में बोवाई तथा फसल में लगने वाले कीड़ों आदि के सम्बन्ध में किये गये थे।

## सिंचाई

गन्ने की पुष्टि उपज के लिए सिंचाई सुविधाओं के महत्व को बराबर ध्यान में रखा गया, फिर भी बड़ी तथा छोटी सिंचाई परियोजनाएँ अभी भी सिंचाई की आवश्यकता की दृष्टि से अधूरी रहीं। विकास परिषदों तथा गन्ना सघों द्वारा प्रस्तुत की गयी सुविधाओं से गन्ना के किसानों को छोटी सिंचाई साधनों के निर्माण के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन मिला।

कुल मिला कर इस वर्ष १,०७४ निजी ट्यूबवेलों का निर्माण किया गया, ३,६८२ पक्के कुएँ बनवाये गये, २,८६८ कुओं में बोरिंग की गयी, २,२६६ रहटों की व्यवस्था की गयी तथा २३५ पम्पिंग मशीनें लगायी गयी। इसके पूर्व वर्ष ७८५ ट्यूबवेल का निर्माण हुआ था, ३,३७२ पक्के कुएँ खुदवाये गये थे, २,२०६ कुओं में बोरिंग की गयी थी, १,६४३ रहटें लगी थी और १७५ पम्पिंग मशीनें लगायी गयी थी।

## कीड़े तथा रोग

• आलोच्य वर्ष में ८०,५३४ एकड़ गन्ना क्षेत्र में बड़े और छोटे कीड़े तथा रोग लगे जिसमें से ६६,४८७ एकड़ में काश्तकारों को बिना अधिक आर्थिक क्षति पहुँचाये उन पर नियन्त्रण कर लिया गया। कीड़े और रोगों का प्रकोप विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न मात्रा में कहीं अधिक और कहीं मध्यम रहा।

## संचार

फ़ैक्टरी विकास योजना के अन्तर्गत राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ८५ मील कच्चा-रीट मार्ग का निर्माण किया और फ़ैक्टरियों के चारों ओर की सड़कों पर कोलतार लगाया और इस कार्य में कुल २६,४०,८०० रुपये खर्च हुए। गन्ना परिषद् संघ कार्यक्रम के अन्तर्गत ३६२ मील पक्की तथा कच्ची सड़को तथा ७१४ पुलों और पुलियों का निर्माण किया गया, जबकि इसके पूर्व वर्ष ३५८ मील सड़को तथा ७८३ पुलों और पुलियों का निर्माण हुआ था।

## प्रचार कार्य

प्रचार कार्य के सिलसिले में प्रस्तुत वर्ष ५७६ ग्रुप अधिवेशनों, २०४ प्रदर्शनियों, ३,१८,७६७ ग्राम सम्मेलनों तथा २६० चलचित्रों के प्रदर्शनों का आयोजन किया गया और ३६,१८६ पर्चे तथा पत्रियाँ बाँटी गयीं। इसके पूर्व वर्ष में ६७८ ग्रुप अधिवेशन, २०० प्रदर्शनियाँ, १,३०,४६३ ग्राम सम्मेलन तथा ३१४ चलचित्र-प्रदर्शन आयोजित किये गये थे तथा ३,५६,८७२ पर्चे-पत्रियाँ वितरित की गयी थीं।

## गन्ना प्रतियोगिता

गन्ना प्रतियोगिता का आयोजन गन्ना परिषदों तथा मधो और चीनी मिलों से प्राप्त चन्दे से किया जाता था। कुछ आर्थिक सहायता राज्य सरकार भी देती थी। गन्ना के काश्तकारों में गन्ने की प्रति एकड़ उपज बढ़ाने में पर्याप्त उत्साह एवं परस्पर प्रतियोगिता की भावना देखी गयी। गन्ना प्रतियोगिताओं का आयोजन क्षेत्र एवं राज्य स्तर पर किया गया और इनमें ५,८५८ किसानों ने (जिनमें बस्ती, फैजाबाद, बिजनौर तथा मुजफ्फरनगर के किसान, जिनके सम्बन्ध में परिणामों का अभी तक निर्णय नहीं हो पाया था, सम्मिलित नहीं हैं) भाग लिया। नैनीताल जिले के काशीपुर क्षेत्र के एक किसान द्वारा एक एकड़ में २,०५६ मन गन्ना उत्पादन की अधिकतम उपज की गयी थी।

## कृषि उपकरण

आलोच्य वर्ष में गन्ना बोने वालों को ७,०६७ उन्नति कृषि उपकरण तथा उन्नत उपकरणों के ८६० पुर्जे दिये गये।

## ६—पशुपालन

### पशु-चिकित्सा सहायता

राज्य भर में कुल ५१७ मवेशी अस्पताल थे। उनके सुचारुरूप से परिचालन तथा पशु रोगों की ठीक रोकथाम के लिए ५१ जिला पशु अधिकारी, ६० पशु चिकित्सा अधिकारी, ४१४ सहायक पशु सर्जन तथा १,५३६ स्टॉकमैन नियुक्त किये गये। अस्पताल में भर्तों तथा नियमित रूप से आकर चिकित्सा कराने वाले पशुओं की चिकित्सा के अतिरिक्त प्रस्तुत वर्ष ४८,७२,६४४ पशुओं को विभिन्न पशु रोगों के टीके लगाये गये। इस अवधि में मवेशी अस्पतालों में तथा बाहर कुल २,५६,४७० पशुओं को बधिया किया गया। राज्य में प्रदेशी-कृत अस्पतालों की कुल संख्या ३२ थी।

### रोग-निरोधक उपाय

मवेशियों को पोकनी से सामूहिक रोग मुक्ति के लिए आजमगढ़, बस्ती, फतेहपुर, इलाहाबाद, रामपुर, उन्नाव, सहारनपुर, बाराबंकी तथा लखनऊ जिलों में रोगमुक्ति अभियान जायी रहा। इसके अतिरिक्त मेरठ, मुजफ्फरनगर तथा मुरादाबाद जिलों में भी यह कार्य आरम्भ किया गया। इन १२ जिलों में से ८ जिलों में कार्य पूरा कर लिया गया। इस अभियान में १७,२४,८८७ मवेशियों को पोकनी के टीके लगाये गये।

## जैविक-उत्पादन प्रभाग

लखनऊ के जैविक उत्पादन प्रभाग ने सीरम तथा टीके की ६८,२८,६४५ मात्राएं तैयार कीं। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यकीय निर्माण संस्थाओं से भी १,३१,८३० मात्राएं प्राप्त की गयीं। प्रस्तुत वर्ष क्षेत्र कर्मचारियों को प्रयोग के लिए ७६,८६,१६० मात्राएं सीरम तथा टीके की वितरित की गयीं। बाहर से रोगों की आरम्भ की रोकथाम के लिए पर्वतीय क्षेत्रों तथा पड़ोसी राज्यों की सीमाओं पर स्थापित ६ सक्रामक रोगों के मवेशी अस्पताल पूर्ववत् कार्य करते रहे। मवेशियों के स्वेदज रोगों की सामूहिक चिकित्सा के लिए स्थापित २० केन्द्र भी कार्य करते रहे। भेड़ तथा बकरियों के संबंध में जान की बीमारी, गलघोटू, निमोनिया, कासिडियोसिस, खुरपका तथा मुंहपका आदि रोगों की जांच एवं रोकथाम के सफल उपाय किये गये। इसके अतिरिक्त अतगेल शीप पाम्स बैक्सीन तथा राउण्डवार्म इन्फेक्शन और फ्रेन्टिन के संबंध में परीक्षण भी किये गये। सामान्यतः होने वाले मुर्गियों के रोगों के निरोध के लिए सामूहिक टीके भी लगाये गये।

## पशु-विकास

विभिन्न राज्यकीय पशु-फार्मों में शुद्ध जाति की, १,२६५ गायें, तथा ८८२ भैंसे थी। प्रस्तुत वर्ष भी इस बात के प्रयत्न जारी रहे कि देशी मवेशियों में विकास के लिए उत्तम जाति के साड़ो तथा भैंसों का उत्पादन बढ़ाया जाय। शुद्ध जाति के १,०४४ साड़ ८०० भैंसे स्थानीय पशु-धन को उन्नत करने के उद्देश्य से सामान्य दरो पर वितरित किये गये।

इटवा जिले में दूध-उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से भंदवारी जाति की भैंसों के सुधार की योजना को उत्स ह प्रद सहयोग मिला और वर्ष के अंत में इस जाति की ५० दुधारू भैंसों के पालकों को आर्थिक सहायता दी जा रही थी। इस योजना की सुविधाओं ने और प्रचार करने के अभिप्राय से प्रजनन कार्य के लिए इस जाति के भैंसों भी छोड़े गये। प्रस्तुत वर्ष में १६५ अतिरिक्त पड़ियां मुख्य ग्राम खंडो, राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडो तथा प्रसार विकास खंडो के इच्छुक पालकों को पालने के लिए जमानत के आधार पर दी गयी।

पशुपालकों, विशेषकर मुख्य ग्राम खंडो के पशुपालकों में, अच्छे दुधारू पशुओं और बछड़ों के पालने की इच्छा और उत्साह उत्पन्न करने के अभिप्राय से पशुपालन विभाग द्वारा विभिन्न जाति के २४१ सांड तथा ६६ भैंसे खरीदे गये। पशुपालन क्षेत्रों में २,०७८ बछड़ों एवं पड़ियों के पालकों को आर्थिक सहायता दी गयी। इसके अतिरिक्त राज्य के बाहर से शुद्ध एवं उन्नति जाति के ५ बछड़े सांड भी खरीदे गये।

## गौशालाये तथा गोसदन

सरकार की आर्थिक सहायता से राज्य में चल रही गोशालाओं की संख्या ३५ थी। ५ राजकीय गोसदन, १७ जिला गोसदन तथा ५ निजी गोसदन भी राज्य में चल रहे थे। इनमें कुल ५,२०६ पशु पल रहे थे। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत वर्ष ५,१०८ घुमन्तू तथा वन्य मवेशी पकड़ कर गोसदनों में भेजे गये।

## दुग्धशाला विकास

तीन दलों को दुग्धशालाओं की स्थापना के लिए २५,००० रुपये के तकावी ऋण दिये गये। वाराणसी के राजघाट स्थित एफ० एन० ई० कृषि विद्यालय को दुग्धशाला की स्थापना के लिए २०,००० रुपये की आर्थिक सहायता दी गयी। इसके अतिरिक्त राजकीय पशु एवं कृषि फार्मों में चल रही छोटी दुग्धशालाओं का परिचालन किया गया।

## घोड़ा एवं खच्चर पालन

घोड़ा एवं खच्चर पालन कार्यक्रम राज्य के सत्तरह जिलों में चलता रहा। खच्चर एवं गदहा पालन उत्तराखंड डिवीजन तथा मैदान के एटा और मैनपुरी जिलों में सीमित रहा।

राज्य में काठियावाड़ी, अरब, टी०पी०ई० तथा भोटिया जाति के ४२ बीजश्व तथा ८ बीजखच्चर प्रजनन कार्य के लिए रखे गये थे और प्रस्तुत वर्ष उनसे १ ३६८ बार गर्भाधान कार्य लिया गया। ऐसे जिलों में जो इस कार्य के लिए चुने गये थे, बीजाश्वों तथा बीज-खच्चरों के पालन-पोषण के लिए अंतरिम जिला परिषदों को आर्थिक सहायता दी गयी। मुरादाबाद स्थित बीजाश्व केन्द्र, अन्तर् बीजाश्व के विश्राम तथा उपचार के लिए मुख्य स्थान के रूप में कार्य करना रहा और वहाँ नये बीजाश्वों को गर्भाधान का प्रशिक्षण भी दिया जाता रहा।

### मुख्य ग्राम योजना

मुख्य ग्राम योजना कृत्रिम गर्भाधान के तरीके से अच्छी जाति के साड़ों के उत्पादन तथा स्थानीय पशुधन को उन्नत करने के अभिप्राय से जारी रही जिससे राज्य में अच्छी जाति के साड़ों की कमी पूरी करने में सहायता मिले। प्रस्तुत वर्ष में विकास खंडों तथा मुख्य ग्राम खंडों में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों तथा ११६ कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्रों से युक्त ८३ मुख्य ग्राम खंड थे। कुल १,०६,४०४ गाय-भैंसों गर्भित की गयी तथा ४६,६५३ बछड़े तथा पड़वे बधिया किये गये। इसी प्रकार ६,२०,५७८ टीके भी लगाये गये।

११ पशुपालन प्रसार केन्द्रों में पालित साड़ों तथा भैंसों ने कुल २४,४७७ गाय-भैंसों को गर्भित किया। इसके अतिरिक्त इन संस्थाओं में नियुक्त कर्मचारियों ने प्रस्तुत वर्ष १५,३१४ बछड़ों-पड़वों को बधिया किया तथा १,६३,८३८ पशुओं को टीके लगाये।

किसानों को उपयुक्त किस्म के बछड़ों के लिए प्रोत्साहित करने के अभिप्राय से १,००० अच्छे किस्म के बछड़ों के पालन-पोषण के लिए आर्थिक सहायता दी गयी। ६ से ३० महीने तक के बछड़ों के लिए २० रुपया प्रति बछड़ा प्रति मास आर्थिक सहायता दी जाती थी।

राज्य के मुख्य ग्राम खंडों के इच्छुक पशुपालकों में तकावी ऋण के रूप में वितरण के लिए २,५०,००० रुपये स्वीकृत किये गये। इस ऋण से किसानों ने राज्य में पशुधन की वृद्धि के लिए ३५८ गायें तथा १७६ भैंसे खरीदीं।

### चरी तथा चारा

चरी तथा चारा के विकास का कार्य सतोषप्रद ढंग से जारी रहा। गाववालों तथा किसानों को प्रदर्शन करने के अभिप्राय से चार चराई-प्रदर्शन-क्षेत्र स्थापित किये। इनमें से प्रत्येक में १० एकड़ भूमि ली गयी थी। चार राजकीय पशु एवं कृषि फार्मों में २०० एकड़ भूमि में चरी तथा चारा बोया गया जिससे किसानों और पशुपालकों को वित्तपोषित (सस्ते) ढर पर सुधरे किस्म के चरी और चारे के बीज वितरित किये जा सकें।

### शूकर पालन

केन्द्रीय दुग्धशाला अलीगढ़ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की आर्थिक सहायता से सकरण द्वारा नयी जाति के सुअर के विकास के अभिप्राय से शूकर पालन के लिए एक अनुसंधान योजना परिचालित की गयी। चुने हुए इलाकों में उन्नत तरीकों से प्रगाढ़ शूकर-पालन के लिए आगरा तथा मेरठ हल्कों में दो शूकर-पालन विकास खंड आरम्भ किये गये। इसके पूर्व १६५६ में दो ऐसे खंड खोले जा चुके थे।

### भेड़ एवं ऊन विकास

पशुलोक की ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला पूर्ववत् ऊन के नमूनों के विश्लेषण का कार्य करती रही। भेड़-पालन का कार्य पर्वतीय क्षेत्र में १० फार्मों तथा मैदान में ५ फार्मों में जारी रहा। राज्य में ४४ बीज-मेढा केन्द्र तथा २८ भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र कार्य करते रहे। ऊन की किस्मों का मूल्यांकन करने के अभिप्राय से भेड़ों की चमड़ी के अध्ययन के लिए एक अनुसंधान

योजना भी प्रस्तुत वर्ष आरम्भ की गयी और प्रयोग के लिए चुनी गयी भेड़ों की चमड़ी के ४४ छोटे टुकड़े उनके चर्म संबंधी अध्ययन के लिए लिये गये।

### बकरी-पालन

जमुनापारी तथा बरबारी जाति की बकरियों के सुधार की योजना उनके जन्म क्षेत्रों में जारी रखी गयी। निजी बकरी पालकों को दूध के परिमाण के आधार पर आर्थिक सहायता दी गयी और इन जातियों के सुधरे बकरों को बीज-बकरा के रूप में प्रयोग के लिए खरीद कर छोड़ दिया गया। जमुनापारी बकरी पालन इकाइया, भरारी (झासी) स्थित पशु एवं कृषि फार्म, मथुरा स्थित जिला दुग्ध-प्रदर्शन फार्म, ऊरई (जालौन) स्थित भेड़ फार्म तथा आटा (जालौन) स्थित साड़ पालन फार्म में कार्य कर रही थी। एटा के मिशन कुक्कुट फार्म में बरबारी बकरी पालन की एक छोटी इकाई चल रही थी। अगोरा बकरी पालन योजना ग्वालदम (चमोली) में पूर्ववत् चल रही थी। अगोरा जाति की बकरियों का सुधार कार्य संतोषजनक एवं उत्साहप्रद रहा। वर्ष के अन्त में कुल १२६ शुद्ध जाति की तथा वर्गीकृत अगोरा बकरियां थी।

### कुक्कुट-विकास

राजकीय कुक्कुट फार्म तथा कुक्कुट प्रसार केन्द्रों द्वारा विकास कार्यों के लिए ४१,०६३ नर पक्षी तथा १,७६,६४३ सेये जाने योग्य अंडे रियायती दामों पर दिये गये। राज्य की तीन कुक्कुट सहकारी समितियों को १०,००० रुपये की आर्थिक सहायता दी गयी। इसके अतिरिक्त खंड वजट से कुक्कुट-गृहों के सुधार के लिए भी आर्थिक सहायता दी गयी।

कृत्रिम ढंग से अंडे सेने का कार्यक्रम जनप्रिय हुआ और सेये जाने योग्य प्राप्त अंडों में से कुछ को खंडों में कृत्रिम ढंग से सेये जाने के काम में लाया गया। राज्य के इच्छुक बत्ख-पालकों को ५० प्रतिशत रियायती दर पर १६२ तैयार अंडे तथा १४० बत्ख के अंडे भी बेचे गये। सस्ते कुक्कुट खाद्य तथा कुक्कुट गृहों के विकास से संबंधित अन्वेषण के अभिप्राय से परिचालित अनुसंधान योजनाओं पर पूर्ववत् कार्य होता रहा। कुछ प्रगतिशील कुक्कुट-पालकों को ५० प्रतिशत वित्तपोषित मूल्य पर अण्डा सेने के लिए इन्क्यूबेटर्स तथा पोषक मशीनें फास्टर मदर भी दी गयीं।

### चर्म-विकास

प्रस्तुत वर्ष मिर्जापुर जिले के दुहरी तथा राबर्ट्सगंज के पिछड़े इलाकों के विकास की विशेष योजना के अन्तर्गत चार ग्राम चर्म-शोधक सहकारी समितियों का गठन किया गया, उनकी रजिस्ट्री कर दी गयी और उन्हें आर्थिक सहायता दी गयी। प्रत्येक को ८,००० रुपये की आर्थिक सहायता मिली। इनके अतिरिक्त सहकारिता के आधार पर ऐसी ही तीन और समितियां खाल उतारने, सिझाने तथा पशुकाल के उपयोग (हड्डी, मांस के चूरे आदि का उत्पादन) के लिए गठित की गयी तथा उनकी रजिस्ट्री कर दी गयी। उन्हें ६,००० रुपये प्रति समिति के हिसाब से आर्थिक सहायता भी दी गयी। इसके अतिरिक्त पिछले वर्षों में स्थापित ३५ सहकारी समितियों के कार्य में और वृद्धि की गयी। लखनऊ के बल्ली का तालाब स्थित ग्राहर्स प्रशिक्षण केन्द्र का कार्य प्रगति करता रहा। लखनऊ शहर से बड़े तथा छोटे जानवरों तथा बकरियों के ५,२१६ शव एकत्र किये गये और लगभग १८,००० रुपये के मूल्य के खाल एवं चमड़े-मांस का चूरा, चर्बी, खून तथा हड्डियों का चूरा और हड्डियों का उत्पादन हुआ। इनमें से अधिकांश खाल और चमड़ा तथा मांस और हड्डियों का चूरा क्रमशः उसी केन्द्र के प्रशिक्षण प्रभाग तथा लखनऊ के चक गजरिया फार्म को दे दिये गये। केन्द्र के प्रशिक्षण प्रभाग ने २,१४५ किलोग्राम तल्ला एवं सुपतल्ला का चमड़ा तथा २,३६७ टुकड़े अस्तर का चमड़ा कमाया जिनकी कीमत लगभग १८,००० रुपये थी। उक्त केन्द्र चर्म-शोधन प्रभाग ने १६ प्रशिक्षार्थियों को चर्मशोधन के उन्नत क्रोम तथा वेजीटेबल तरीकों में प्रशिक्षित किया।

## कसाईखानों का सुधार

लखीमपुर-खीरी तथा फैजाबाद के म्युनिसिपल बोर्डों को उनके कसाईखानों के सुधार के लिए दस-दस हजार रुपये दिये गये जिससे खाने के लिए मांस का सफाई के साथ उत्पादन किया जा सके।

## प्रचार

राज्य के विभिन्न भागों में ४०० एकदिवसीय तथा ५० जिला पशु-प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। गोपाण्टमी सप्ताह के अवसर पर राज्य की सभी तहसीलों में कुल २३४ एकदिवसीय प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया और २४ गोशालाओं को प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए आर्थिक सहायता दी गयी। मथुरा के गिरिगोवर्धन तथा राजकीय पशुचिकित्सा महाविद्यालय में दो विशेष प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया गया।

कृषि और पशुपालन मासिक पत्रिका का इस अवसर पर एक 'गोवर्धन' अंक भी प्रकाशित किया गया और दूर-दूर तक वितरित किया गया।

## पशु क्रय-विक्रय

प्रस्तुत वर्ष कुक्कुट-उत्पादन तथा अण्डा क्रय-विक्रय सहकारी समितियों और ७ पशुपालन एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों का गठन किया गया। विभिन्न स्थानों में स्थापित १८ प्रोडिंग स्टेशनों पर अंडों के वर्गीकरण का कार्य आरम्भ किया गया। आगरा जिले के बागेश्वर पशु मेले में नीलाम द्वारा मवेशियों की विक्री की गयी जो बहुत सफल रही।

## प्रशिक्षण तथा कर्मचारी वर्ग

संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्निकल कोऑपरेटिव मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत एक अधिकारी को कुक्कुट-पालन में एक वर्ष के प्रशिक्षण के लिए चुना गया। दो अधिकारियों को पशुपालन के डिप्लोमा पाठ्यक्रम, दो अधिकारियों को कुक्कुट-पालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा एक अधिकारी को निरोधन औषधियों के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए भारतीय पशु-चिकित्सा अन्वेषणालय भेजा गया। दो पशु-चिकित्सा अधिकारियों और सात सहायक पशु-सर्जनों एम० बी० एस-सी० तथा ११ पशु-चिकित्सा अधिकारियों को बी० बी० एस-सी० एवं सक्षिप्त पशुपालन पाठ्यक्रम के लिए भेजा गया। इसी प्रकार ६ पशु-चिकित्सा प्राधिकारी कृत्रिम गर्भाधान के तकनीक के प्रशिक्षण के लिए भेजे गये। इसके अतिरिक्त मथुरा के उत्तर प्रदेश कालेज आफ वेटेरिनरी साइन्स एण्ड एनिमल हल्थ के १ पशु-चिकित्सा अधिकारी तथा दो जिला पशु अधिकारी रिफ्रेशर कोर्स के लिए तैनात किये गये।

लखनऊ के बख्शी-का-तालाब केन्द्र में खाल उतारने की विधि में प्रशिक्षण के लिए २८ उम्मीदवार चुने गये। चक गंजरिया स्थित पशुपर्यवेक्षक प्रशिक्षण कक्षा जारी रखी गयी और आलोच्य वर्ष में ६५ प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

तीन स्टाकमैन प्रशिक्षण कक्षाएं, जिनमें से प्रत्येक में १०० प्रशिक्षार्थी भर्ती थे, जारी रखी गयी और कुल ३०८ प्रशिक्षार्थियों में से २८५ प्रशिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। इनको पशुपालन विभाग में नौकरी मिल गयी। इलाहाबाद में कम्पाउन्डरी की प्रशिक्षण कक्षा में ४० प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण लेते रहे और उनमें से ३६ प्रशिक्षित किये गये। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत वर्ष दो और कम्पाउन्डरी प्रशिक्षण कक्षाएं, जिनमें से प्रत्येक में २० प्रशिक्षार्थी थे, बरेली तथा लखनऊ में आरम्भ की गयी, जिससे प्रशिक्षित एवं योग्य पशु चिकित्सा कम्पाउन्डरी की सेवाएं उपलब्ध हो सकें। इन केन्द्रों में प्रस्तुत वर्ष ४५ अप्रशिक्षित कम्पाउन्डरों को प्रशिक्षित किया गया।

शूकर-पालन तथा सुअर के मांस के उत्पन्न एवं डिब्बाबन्दी के प्रशिक्षण के लिए अलीगढ़ की केंद्रीय दुग्धशाला में एक ६ महीने की अवधि का डिप्लोमा पाठ्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सहयोग से आरम्भ किया गया। उपका उद्देश्य शूकर-पालन में वैज्ञानिक ढंग से लोगों को प्रशिक्षित करना था। इस प्रशिक्षण कक्षा में १० प्रशिक्षार्थी भर्ती किये गये।

**पशु-चिकित्सा महाविद्यालय तथा पशुपोषण अन्वेषणालय**

मथुरा के पशुचिकित्सा महाविद्यालय में ६०१ विद्यार्थी स्नातक तथा २८ स्नातकोत्तर परीक्षा में उत्तीर्ण हो कर निकले। १०० विद्यार्थी बी० बी० एस-सी० तथा पशुपालन डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रविष्ट हुए और एक वर्ष अवधि के सक्षिप्त पाठ्यक्रम में ११ विभागीय अधिकारियों ने प्रवेश लिया। एम० बी० एस-सी० के प्रथम वर्ष में २४ विद्यार्थियों में से आठ प्रदेश का एक विद्यार्थी पढ़ने नहीं आया और पंजाब के एक छात्र ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के १५ तथा अन्य राज्यों के कुल ७ छात्र रह गये। कालेज में १९६०-६१ सत्र में कुल ४९ छात्र शिक्षा पा रहे थे। आगरा विश्वविद्यालय की अप्रैल तथा जुलाई, १९६० में होने वाली विभिन्न वार्षिक और पूरक परीक्षाओं में कुल ४९९ परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, जिनमें से ४३२ उत्तीर्ण घोषित किये गये। कुल मिला कर १०९ विद्यार्थी बी० बी० एस-सी० तथा पशुपालन डिग्री परीक्षा में और १४ एम० बी० एस-सी० परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। १९६०-६१ में कालेज तथा राज्य के अन्य विभागों, जैसे हरिजन कल्याण, शिक्षा विभाग आदि के स्नातक कक्षा के छात्रों को १०८ छात्रवृत्तियां दी गयीं तथा फीस-भागी की व्यवस्था की गयी।

डिग्री पाठ्यक्रम के अंतिम तथा तृतीय वर्ष के छात्रों को व्यावसायिक दिलचस्पी वाले स्थानों, जैसे दिल्ली, करनाल, आइजटनगर, बंबई और कलकत्ता के शैक्षिक दौरों पर ले जाया गया। एम० बी० एस-सी० कक्षा के छात्र भी राज्य तथा राज्य से बाहर ले जाये गये। तृतीय वर्ष के छात्रों को पूर्व वर्षों की भांति व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए गर्मी की छुट्टियों में विभिन्न राजकीय पशु अस्पतालों में नियुक्त किया गया। कालेज के सलग्न कोठारी अस्पताल में सीनियर विद्यार्थियों के पर्याप्त डाक्टरों प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था थी।

राज्य प्रसार परियोजनाओं एवं विकास खंडों से सवद्ध प्रसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के एक मास के रिक्रेशर कोर्स की व्यवस्था जून, १९६० में कालेज में की गयी थी। तीस अधिकारियों ने यह प्रशिक्षण प्राप्त किया जिससे वाद-विवाद गोठियों का भी आयोजन था। यह प्रशिक्षण शिक्षा एवं अन्वेषण विशेषज्ञों तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा किया गया था।

कृत्रिम गर्भाणन के तकनीक के दो मास के प्रशिक्षण में जो १९६० के जून और जुलाई महीनों में आयोजित किया गया था, अधिकारियों के एक दल को प्रशिक्षण दिया गया। इनमें से ६ अधिकारी विभाग के तथा एक पंजाब राज्य के थे।

अधिकांश शिक्षक, विशेषकर स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाने वाले, अपना पर्याप्त समय पशुपालकों तथा क्षेत्र कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर शोध कार्यों में लगाते थे। इस सिलसिले में किये गये मौलिक कार्य को देश तथा विदेश की शोध पत्रिकाओं में प्रकाशनार्थ प्रस्तुत किया गया। पशुओं के पोषण पालन तथा रोगों के ऐसे विभिन्न पहलुओं पर जिनका पर्याप्त आर्थिक प्रभाव राज्य के पशु-उद्योग पर पड़ सकता था, पशु अन्वेषणालय के अन्य विभिन्न प्रभागों ने ध्यान देना जारी रखा।

पशु चिकित्सा महाविद्यालय के रोग एवं महामारी प्रभाग ने १ अप्रैल, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ को अवधि में जिन महत्वपूर्ण विषयों पर शोध एवं अनुसंधान कार्य किया उनका नीचे उल्लेख किया जा रहा है :—

(१) राज्य में पशुओं के मुख एवं खुर से संबद्ध विभिन्न रोगों के फैलने के संबंध में सर्वेक्षण प्रस्तुत वर्ष अन्तराष्ट्रीय खुर एवं मुख रोग अनुसंधान केन्द्र में ३२ सम्पुल भेजे गये।

(२) राज्य में अफ्रीकी घोड़ा बीमारी का विस्तार—विभिन्न समय में फैले इस रोग के २२ सैम्पुल लिये गये और उन्हें पूना के विरस (Virus) रिसर्च सेंटर तथा आई० बी० आर० आर० के पास रोगाणुओं को अलग करने के लिए भेजा गया।

(३) भेड़-बकरियों से पाये जाने वाले एपिथेलियो ट्रॉपिक रोगाणुओं का अध्ययन—भेड़-बकरियों से तीन बार फैले हुए एपिथेलियो ट्रॉपिक रोगाणुओं का विस्तृत अध्ययन किया गया। अभी और अध्ययन चल रहा था।

(४) पड़वों में फैलने वाला विरस (Virus)—मवेशियों को एसकारिस कीड़े से भी बड़ा कष्ट था। इनको फैलाने का काम पूरा—इन्फेक्चुएन्जा रोगाणु करता है, ऐसी रिपोर्ट मिली, जिसकी पुष्टि सयुक्त राज्य अमेरिका के अरबाना स्थित कालेज आफ वेटेरिनरी मेडिसिन, युनिवर्सिटी आफ इन्डियाना ने भी कर दी।

(५) ट्यूबरक्लोसिस तथा जास डिजीज—इन दोनों असाध्य छुत्तही बीमारियों के फैलने के सम्बन्ध में राजकीय पशु फार्मों में अग्रगामी प्रयोग के रूप में आरम्भिक सर्वेक्षण किया गया।

(६) चैप्टोस्पिरोसिस के सबध में शोध कार्य—शोध के परिणामस्वरूप यह पता चला कि यह रोग कुछ राजकीय पशु फार्मों में सामान्य रूप से विद्यमान था।

(७) सक्रामक नेक्रोहेपाटाइटिस तथा इम्मेच्योर केसिओलाइटिस—एक भेड़ फार्म में किये गये शोध से पता चला कि इम्मेच्योर लिवर फ्लक्स के भारी विस्तार तथा सीएल, नो वाई (Cl. novyi) की छूत के कारण अधिक संख्या में भेड़ों की मृत्यु होती थी।

उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त दूधित पदार्थों के २२६ नमूनों की परीक्षा की गयी और उनका परिणाम उनकी रोकथाम की उचित राय के साथ सबधित पशु-चिकित्सा अधिकारियों के पास इसलिए भेज दिया गया कि उनके आगे फैलने की रोका जा सके। क्षेत्र में कार्य करने वाले पशु-चिकित्सकों के लाभ के लिए पशु-रोगों के निदान के तरीकों के प्रशिक्षण के अभिप्राय से एक प्रगाढ़ पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गयी।

अंतिम वर्ष के छात्रों की सहायता से ३४ ग्रामों में सर्वेक्षण किया गया। ये ग्राम एक राजकीय पशु फार्म के १० मील के घेरे में स्थित थे। यह सर्वेक्षण इस अभिप्राय से किया गया था कि गांवों के मवेशियों में फैलने वाले बुसेलोसिस रोग का अन्दाज लगाया जा सके। कुल ५,६३१ मवेशियों की जांच की गयी और वे इस रोग से मुक्त पाये गये।

पशुपोषण अन्वेषण प्रभाग—पशु जाति प्रभाग में सांड तथा भैंसों के वीर्य के संरक्षण, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा गर्भ रहने का पड़ता, गरमी के दिनों में अनुकूल व्यवस्था द्वारा उत्पन्न वीर्य का मुरा भैंसों पर प्रभाव, बच्चा देने की कालावधि का हरियाना गायों के दूध के परिणाम तथा दूध देने की अवधि पर प्रभाव, एवं भैंसों और सांडों को कृत्रिम गर्भाधान कार्य के लिए प्रशिक्षण आदि जैसे विषयों का अध्ययन किया गया। विभिन्न संस्थाओं से आये हुए सैम्पुलों का विश्लेषण किया गया और विभिन्न फार्मों की खुराक की सूची की निरीक्षा की गयी। इन संस्थाओं तथा सर्वसाधारण को पशुओं की चरी तथा चारा के विकास से सबधित संतुलित खुराक की समस्याओं के विषय में उचित राय दी गयी। बुन्देलखंड क्षेत्र के किसानों को फूल लगने से पूर्व चरी को काट लेने के लाभ को दिखाने के अभिप्राय से फूलने के पूर्व तथा पश्चात् काटी गयी सेन ग्रास द्वारा तैयार चारा के पोष्य तत्वों के तुलनात्मक अध्ययन का आयोजन किया गया और विभिन्न महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गये।

जिला प्रदर्शन दुग्धशाला मथुरा—मथुरा की जिला प्रदर्शन दुग्धशाला में ३१ मार्च, १९६१ को १२० गायें, २३० बछड़े, २६ सांड तथा २८ बैल थे। प्रस्तुत वर्ष अलीगढ़ में आयोजित पांचवी राज्य पशु प्रदर्शनी में ४६०/२२ नं० की हरियाना गाय को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।



यह गाय प्रति दिन ४२ पौण्ड १२ औंस दूध देती थी और इसन अलीगढ प्रदर्शनी मे प्रायी हुई सभी जाति की गायो को दूध देने मे मात दे दी । प्रस्तुत वर्ष फार्म मे पालित ४३ बछड़े साड विकास कार्य के लिए दिये गये । इसके अतिरिक्त कृत्रिम गर्भाधान कार्य के लिए १४ साड विभाग को दिये गये ।

३१ मार्च, १९६१ को मुर्रा जाति के मवेशियो मे ७० भैसे, १३७ पड़वे, २५ भैसे तथा ४ जुताई के काम मे भेजे थे । ८ मुर्रा पड़वा भैसे विभाग को, विकास कार्य के लिए दिये गये और २ मुर्रा भैसे कृत्रिम गर्भाधान कार्य के लिए दिये गये । प्रस्तुत वर्ष हरियाना तथा मुर्रा जाति के मवेशियो द्वारा कुल १,६५,८८७ किलोग्राम दूध निकाला गया । वर्ष के अन्त मे फार्म मे कुल ४८ बकरियां तथा १२५ भेडे थी ।

कुक्कुट प्रभाग मे वर्ष के आरम्भ मे २,७१६ पक्षी थे । प्रस्तुत वर्षाविधि मे ५,४६४ चूजे निकाले गये । कुल मिला कर १,६८४ पक्षी विकास कार्य के लिए तथा सस्था के विभिन्न प्रभागो मे प्रयोग सम्बन्धी कार्यों के लिए ७२० पक्षी दिये गये । शेष को या तो अन्य फार्मों मे दे दिया गया या बेच दिया गया । चूजो सहित कुल १,३६५ पक्षी मर गये । वर्ष के अन्त मे ३,६७५ पक्षी शेष रह गये । प्रस्तुत वर्ष ५०,४७१ अडे उत्पादित किये गये जब कि २२० अंडे बाहर से प्राप्त हुए थे । ४,८२६ अडे विकास कार्य के लिए बेच दिये गये और १,०१६ अडे तथा १,६७६ भ्रूण यक्षा अडे विभिन्न शोध प्रभागो मे प्रयोग कार्यों के लिए दिये गये । १४,६८० अडे फार्म मे मशीन द्वारा सेये गये जिनमे प्रयोग कार्य के लिए रखे अडे भी सम्मिलित थे । बी० वी० एस-सी० तथा पशुपालन कक्षाओ के विद्यार्थियो को इस फार्म मे व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया और एम० वी० एस-सी० के दो छात्रो ने शोध के लिए कुक्कुट-पालन की समस्याओ को चुना ।

### ७-मत्स्य पालन

मत्स्य पालन के विकास तथा अनुसंधान से संबधित कार्य संतोषजनक ढंग से चलते रहे । कुल ४,१६,२१,१०० छोटी तथा ४७,८०,५५२ बीज मछलियां इकट्ठी की गयी और ४५,८५४ एकड़ विभागीय जलाशयो मे ६२,६४,२६८ बीज मछलियां स्टोक मे रखी गयी । नौकुचिया ताल, भीमताल, सातताल तथा नैनीताल मे संजोयी 'मिरर कार्प' बीज मछलियां संतोषप्रद ढंग से बढ़ रही थी । विभागीय मछली की दुकानों पर प्रस्तुत वर्ष २,८५४४३ मन मछलियां बिकीं जिनका मूल्य १,२७,५६० रुपये था ।

दिसम्बर, १९६० तथा निजी मत्स्य पालकों, राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडो तथा ग्राम समाओ को ४,००० की रियायती कीमत पर २२,६६,००० बीज मछलिया दी गयी । १५ सहकारी समितियो का गठन किया गया और उन्हे ६०,००० रुपये का सहायता अनुदान दिया गया । छोटी मछलियो तथा बीज मछलियो के पालन के लिए १० नर्सरी तालाब अधिग्रहित किये गये और १० नर्सरियो का सुधार किया गया । इसके अतिरिक्त ३ और तालाबों का सुधार किया गया और उनमे २२,८७,००० बीज मछलिया रखी गयी । १ मछली पालन वार्डन तथा ३ मत्स्य पालन निरीक्षक केन्द्रीय अन्तर्देशीय मत्स्य अन्वेषणालय बारिकपुर कलकत्ता मे अन्तर्देशीय मत्स्यपालन पाठ्य-क्रम मे प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किये गये ।

### ८-वन

#### विधि-निर्माण

आलोच्य वर्ष मे भारतीय वन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम १९६० कानून बन गया । इसके फलस्वरूप जिन कठिनाइयो के दूर होने की सम्भावना थी और जिन उद्देश्यों की पूर्ति की आशा थी उनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है :-

(१) जमींदारो ने काफी लम्बा-चौड़ा वन क्षेत्र कृषि योग्य बनाने के लिए पट्टे पर दे दिया

था जिससे बाद में उसमें खेती की जाय। ये पट्टे १९५० क उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि सुधार अधिनियम के बनने के पूर्व के वर्षों में दिये गये थे। इन पट्टों के बल पर काफी बड़ी सख्या में लोगों ने या तो जंगलों को काट कर भूमि साफ करना आरम्भ कर दिया था या फिर कार्य आरम्भ करने को उत्सुक थे। राज्य के सार्वजनिक लाभ के लिए इन वन क्षेत्रों का संरक्षण अत्यन्त आवश्यक था। १९५८ का भारतीय वन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम द्वारा राज्य सरकार को यह अधिकार दे दिया गया कि यह पट्टेदारों द्वारा जंगल के काटे जान पर नियंत्रण लगा सकती है। किंतु इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त नहीं था कि नये वन रोपण का उपक्रम करे या ऐसे वा क्षेत्र का रख-रखाव या विकास करे अथवा इससे संबद्ध कोई निश्चित कार्य करे।

(२) १९२७ के भारतीय वन अधिनियम की धारा ६८ के अन्तर्गत वन-अपराधों के विरुद्ध कार्यवाही में कठिनाई का अनुभव किया जा रहा था। इन धारा के अन्तर्गत वन अधिकारी, वन-अपराध के किसी मुकद्दमे को मुद्दालय से जिसके ऊपर अपराध करने का संदेह था, ५० रुपया मुआविजा लेकर मुकद्दमा उठा सकता था। ऐसे मुकद्दमों के दौरान में जिनमें अधिक बंड दिया जाना चाहिये था अनुभव किया जाता था कि ५० रुपया बंड की सीमा कठिनाई उत्पन्न करती थी। इसके अतिरिक्त वन-उत्पादनों का मूल्य ३० वर्ष पूर्व के मूल्य की अपेक्षा ८ से १० गुना बढ़ गया था। इस दृष्टि से ५० रुपया की सीमा निकुल अनुपयोगी थी।

(३) १९२७ के भारतीय वन अधिनियम की धारा ५२ (१) में इस बात का प्राविधान था कि उन तमाम उपकरणों, नावों, बैलगाड़ियों या श्वेडिशों को, जिनका संरक्षित वनों में किये गये अपराध में उपयोग किया गया हो, जप्त कर लिया जाना चाहिये। इसका अर्थ यह था कि वन अधिकारी ट्रकों, बसों, ट्रैक्टरों, साइकिलों आदि की जवतों नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये चीजें उक्त धारा की परिधि में नहीं आती थीं। सभ्यता के विकास तथा यातायात के मशीनों साधनों के उपयोग के साथ वन-अपराधों के लिए आधुनिक सवारियों का सामान्य रूप से प्रयोग होने लगा।

(४) इस बात की बार-बार आंग की जाने लगी थी कि टेहरी गढ़वाल के सोयम वनों की व्यवस्था ग्राम पंचायतों के नियंत्रण में दे दी जाय। इन वनों का प्रबंध हस्तान्तरित करने के पूर्व यह आवश्यक समझा गया कि इनको 'सुरक्षित वन' घोषित कर दिया जाय जिससे संबंधित ग्राम पंचायतों पर सरकार का नियंत्रण हो जाय और उन्हें ऐसा करने से रोका जाय जिसके फलस्वरूप इन बागों को कोई क्षति पहुंचाने की सम्भावना हो। ये वन सरकार के थे अतः उन्हें 'सुरक्षित वन' घोषित करने में भारतीय वन अधिनियम की उप धारा २९(३) के अन्तर्गत व्यक्तियों या संसुदायों के प्रस्तुत अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं थी। यह भी आवश्यक समझा गया कि ग्राम पंचायतों का गठन भारतीय वन अधिनियम के अन्तर्गत दिया जाय और इन सोयम वनों का प्रबंध पंचायतों आधार पर किया जाय।

### वनोपयोग परामर्श परिषद्

वनोपयोग परामर्श परिषद् की एक बैठक ८ अप्रैल, १९६० को लखनऊ में हुई। इसमें अन्य विषयों के अतिरिक्त—(१) रेजिन फैक्टरी की स्थापना की सभावना (२) वन-साधनों के संरक्षण की आवश्यकता, (३) औषधीय जड़ी-बूटियों के विकास, तथा (४) विभाग द्वारा कल्या के निर्माण के प्रश्नों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

### भूमि-व्यवस्था परिषद्

५ नवम्बर, १९६० को लखनऊ में भूमि व्यवस्था परिषद् की एक बैठक हुई। इस बैठक में अन्य विषयों के साथ-साथ—(१) बदरीनाथ के निकट बरफ या पहाड़ के टूट कर गिरने का रोक-थाम, (२) ढालू भूमि में कृषि की व्यवस्था, (३) ऊसर भूमि के सबसे अच्छे ढंग से उपयोग

तथा किसके द्वारा यह कार्य हो, (४) सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के किनारों पर वृक्षारोपण, तथा (५) उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के आगरा, अलीगढ़ तथा मथुरा जिलों के निकटस्थ सीमा क्षेत्रों पर वनरोपण संबंधी समस्याओं के विषय में भी विचार-विमर्श किया गया।

### साखू का स्वाभाविक पुनर्जीवन

साखू के स्वाभाविक पुनर्जीवन की समस्या से संबद्ध मामलों के शोध की ओर पूर्ववत् विशेष ध्यान दिया जाता रहा और स्वाभाविक पुनर्जीवन से संबंधित विभिन्न प्रयोग तथा अध्ययन किये गये।

यह देखा गया कि प्रस्तुत वर्ष साखू के बीज के लिए बुरा वर्ष रहा और हर जगह बहुत कम काम हुआ। इसके पूर्व का वर्ष भी पौधों के लिए खराब रहा। यद्यपि बीज की वृष्टि से अच्छा था जिससे अर्ध लचीली स्थिति में यह पुनर्जीवन भी बहुत कम समय रहा।

साखू के आगलगी के हिस्से में स्वाभाविक पुनर्जीवन और कतार से कटाई के जो परीक्षण उत्तर खोरी डिबीजन में किये गये तथा आगलगी की कतारों के अध्ययन से इस बात का आभास मिला कि —

(क) चराई से सुरक्षा होने पर साखू के पौधे बहुत जल्दी बढ़ते हैं।

(ख) चौड़ी कतारों में संकरी कतारों की अपेक्षा पौधों की वृद्धि और संवर्धन अच्छा होता है।

(ग) कतार के विस्तार की दिशा का पौधों की संख्या और वृद्धि में निश्चित और स्पष्ट प्रभाव पड़ता है ऐसा मालूम हुआ। सबसे उपयुक्त दिशा उत्तर दक्षिण या उत्तर दक्षिण और उत्तर पूर्व दक्षिण पच्छिम के बीच की होती है जब कि पूर्व पश्चिम सबसे अनुपयुक्त दिशा मालूम हुई। हो सकता है यह बीज के गिरने के समय चलने वाली वायु के प्रभाव के कारण हो क्योंकि उस समय पूर्व से पश्चिम की ओर हवा बहती है।

जब यह अनुभव किया गया कि चराई से सुरक्षित होने पर साखू के पुनर्जीवन की प्रगति पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो उन बहुत से खंडों में जहाँ घेरे नहीं थे उन्हें प्रस्तुत वर्ष इस प्रकार घेर दिया गया कि उनमें पशुओं का प्रवेश न हो सके।

साखू का कृत्रिम पुनर्जीवन—साखू के कृत्रिम पुनर्जीवन के सबंध में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे अन्वेषण के सिलसिले में साखू के विभिन्न आकार-प्रकार की अंकुरित जड़ों को लगाया और बढ़ाया गया। बचे हुए अंकुरित साखू के पौधे दूसरे वर्ष में काफी बड़े और पृष्ठ हुए किन्तु आरम्भ के वर्ष ५० प्रतिशत से कम ही पौधे बचे रहे और उनकी वृद्धि भी नहीं हुई।

### वृक्षारोपण, वनरोपण तथा सड़कों के किनारे वृक्षारोपण

वृक्षारोपण तथा वनरोपण से संबंधित कार्य, जो हाल के कुछ वर्षों से पर्याप्त गति से चल रहा था, १९६० से ४१,८७६ एकड़ भूमि में आरम्भ किया गया। विभाग के अधीन चल रहे वृक्षारोपण कार्य को मोटे तौर पर निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता है :—

(क) साखू तथा विभिन्न प्रकार के वृक्षों का रोपण जिसमें दियासलाई तथा खेल-कूद के सामानों के निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले वृक्ष भी सम्मिलित थे,

(ख) पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण,

(ग) नहरों के किनारों पर वृक्षारोपण, तथा

(घ) सुरक्षित बनो तथा पड़ती भूमि खंडों में वनरोपण की योजना के अन्तर्गत भूमि व्यवस्था तथा मुख्यालय हल्को में वन रोपण।

प्रत्येक मद के अन्तर्गत प्रस्तुत वर्ष हुए कार्य का विवरण नीचे प्रस्तुत है :—

(१) साखू तथा विभिन्न प्रकार के वृक्षों का रोपण—इस प्रकार के वृक्षों का रोपण बियासलाई, प्लाईवुड, खेलकूद के सामानों के निर्माण के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने तथा अन्य उद्योग-धन्धों में प्रयोग के अभिप्राय से किया जा रहा था। इन वृक्षों के रोपण के ढग में हाल में कुछ वर्षों में काफी सुधार हो गया था। इनमें से कुछ रोपण क्षेत्रों में ट्रेक्टरों से जुताई का कार्य लिया जा रहा था। ऐसे मामलों में भूमि साफ कर लेने के बाद ट्रैक्टरों से उसकी जुताई की जाती थी और तब १८ से २० फुट की दूरी पर पेड़ लगाये जाते थे। वृक्षों की जिन मुख्य किस्मों का रोपण किया गया वे थी साखू, खैर, शीशम, सागौन, हल्दी, शहतूत, सादन, गुटेल, सेमल, काजू, पाला, तून, सिरिस, बौरग इत्यादि। अर्थोपार्जन वाली फसलें जैसे लाही, सनई, ढेचा तथा अड़ी पेड़ों की कतारों के बीच की जमीन में वृक्षारोपण के पहले या कभी-कभी दूसरे वर्ष लगा दी जाती थी। इनके लगाने से घासों की उपज तो दब जाती ही थी उसके अतिरिक्त पर्याप्त अर्थोपार्जन भी होता था।

(२) पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण—टेहरी और कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्रों में विविध प्रकार के वृक्षों के रोपण के कार्य को और अधिक विस्तार दिया जा रहा था। जिस जाति के वृक्षों का मुख्य रूप से रोपण किया जा रहा था वे थी अशना, देवदार, सरो, चीड़, अखरोट, मँपुल, पहाड़ी शहतूत तथा सरई। जितने क्षेत्र में यह कार्य हुआ उसका विवरण नीचे प्रस्तुत है :—

					एकड़
कुमायू क्षेत्र में	..	..	..	..	१५,२२६
टेहरी क्षेत्र में	{ ..	..	..	..	१,६६५
			योग	..	१६,८९४

(३) नहर के किनारों पर वृक्षारोपण—नहर के किनारों पर वृक्षों का रोपण भूमि व्यवस्था हल्का के अधीन बढ़ाया गया। ६४ मील लम्बी नहर के किनारों की ६३२ एकड़ भूमि में शीशम, बबूल, खैर, सिरिस, सेमल, प्रोसोपिस, जुलीकलारा, तून, नीम, जामुन, काजी, महुआ, अर्जुन, काजू तथा आम आदि के वृक्ष या तो लगाये या बोये गये। इसका परिणाम उत्साहजनक रहा। (गत १३ वर्षों में नहरों के किनारों पर कुल १,२२६ मील तक वृक्ष लगाये गये)।

(४) सुरक्षित वन तथा वनेतर जिलों के पड़ती भूखंड—१९६० की वर्षा वधि में ४४१२ एकड़ सुरक्षित वन तथा भूमि व्यवस्था हल्का और मुख्यालय हल्का के पड़ती भूखंड में वनरोपण किया गया। इसमें वन-रोपण के लिए चुने गये जमुना और चम्बल की धाटी के सुरक्षित वन खंड तथा आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी और इटावा जिलों के पड़ती भूमि खंड जो उत्तर प्रदेश राजस्थान सीमा वन रोपण योजना तथा गोमती राप्ती वनरोपण योजना के अन्तर्गत सरकार के अधीन हो गये थे भी सम्मिलित थे। खारों में कण्टूरबन्दी और दरारों को भरने तथा पानी से घिरे हुए क्षेत्रों में मेड़बन्दी तथा वृक्ष लगाने और ऊसर क्षेत्र के अच्छी मिट्टी वाले भागों में पशु वेहन लगाने से अच्छी उपज होती रही। इसमें लगभग ८० प्रतिशत सफलता प्राप्त हुई। (पिछले १३ वर्षों में ५८,३३० एकड़ सुरक्षित वन और पड़ती के भूखंड में वृक्ष रोपण किया जा चुका था। इसमें उपनिवेशन क्षेत्रों की भूमि भी सम्मिलित थी।)

(५) सड़क के किनारे के वृक्ष—पिछले वर्ष के ११८ मील की तुलना में प्रस्तुत वर्ष (१९६०) लगभग ११६ मील की लम्बाई में सड़कों के किनारे वृक्ष लगाये गये। इस कार्य में प्रायः ६५ प्रतिशत सफलता मिली। नये लगाये गये वृक्षों की मनुष्यों तथा मवेशियों से रक्षा के लिए ३-३ फुट की गोल खाड़ियाँ बनायी गयीं और उनके चारों ओर बबूल की झाड़ियाँ लगायी गयीं। इससे वृक्षों को नमी भी मिलती थी। (१९६० में समाप्त होने वाले १३ वर्षों में लगभग १,३१४ मील की लम्बाई में सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किया गया।

## द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत परिचालित विकास योजनाओं के विवरण

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत परिचालित विकास योजनाओं पर हो रहे कार्यों का विवरण नीचे की तालिका में प्रस्तुत है :--

योजना	१९६०-६१ के लिए निर्धारित लक्ष्य	१९६०-६१ में उपलब्धियां
(१) कुमाऊं में फल वृक्षों का रोपण	५०० एकड़ भूमि में ४१,७०० रु० खर्च से २०,००० फल वृक्षारोपण	१३० एकड़ भूमि में १८,२१२ फल वृक्ष लगाये गये। पुराने लगाये गये वृक्षों की देख रेख की गयी तथा मिछिले न लगे वृक्षों के स्थान पर नये वृक्ष लगाये गये। इस कार्य में ४१,६७३ रु० खर्च हुए।
(२) निजी वर्गों तथा शासन में विलीन राज्यों तथा बस्तियों के निर्गत पड़ती भूखंडों और भूमि व्यवस्था हल्को में कार्य करने वाले कर्मचारियों के आवास तथा जल की व्यवस्था।	६४ भवनों, २ कुआँ और हैण्ड पंपों का निर्माण। व्यय ३,५५,६०० रुपया।	८३ भवन तथा ३ कुएँ निर्मित किये गये तथा १ भवन का निर्माण कार्य चल रहा था। इन कार्यों पर कुल ३,५६,३८६ रुपये व्यय हुए।
(३) वन शिक्षा, फारेस्टरों तथा फारेस्ट गाइडों का प्रशिक्षण।	२५ फारेस्टर तथा ७५ फारेस्ट गाइड, व्यय १,२८,३०० रुपया।	२४ फारेस्टर तथा ८६ फारेस्ट गाइड प्रशिक्षित किये गये और २५ फारेस्टर तथा ३६ फारेस्ट गाइड प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। पूर्वी हल्के में प्रशिक्षार्थियों के लिए एक भवन तथा पश्चिमी हल्के में कार्यालय तथा स्टॉक के लिए भवन का निर्माण किया गया। इन कार्यों में १,१६,७८२ रुपये व्यय हुए।
(४) लाख के काष्ठ का विकास	दक्षिणी हल्के तथा भूमि व्यवस्था हल्के के ६ ज्वी-जनो का विकास, व्यय ३२,७०० रु०।	आगलगी द्वारा जंगल की सफाई तथा १२,४६० वृक्षों पर तम्बर तथा उनके चारों ओर बाड़ा लगाने का कार्य किया गया। मिर्जापुर स्थित फोल्ड रिसर्च स्टेशन आफ लेक ( इडिया लेक रिसर्च इन्स्टीट्यूट ) को १६ मन बीज लाख दी गयी। ४५ मन, १५ सेर

लाख टेंडर द्वारा कुल ६०७ रु० ५० न० ५० पर बेची गयी। ७७ मन्, २६ सेर बिस्त्री के लिए स्टोक में थी। एक लाख-गोदाम का निर्माण पूरा हुआ। कुल व्यय ३२,६१५ रु० हुआ।

(१) पूर्वीय, पश्चिमी तथा दक्षिणी हल्को के १८ डिबीजनों तथा भूमि व्यवस्था हल्को के एक डिबीजन के वन्य जन्तुओं का संरक्षण किया गया।

(२) पहले से बने मचानों, सहायक वन्य जन्तु संरक्षक के क्वार्टरों और वन्य जन्तु रक्षकों की चौकियों, छोटे आवासों, डारमिटोरियो तथा मोटर सड़कों का रख-रखाव और सुधार।

(३) आशिक बने हुए वन्य जन्तु रक्षकों की चौकियों और सहायक वन्य जन्तु संरक्षकों के आवासों का निर्माण पूरा किया गया।

(४) जोल साल आरक्षित वन में एक मचान का निर्माण।

(५) धानगढी में एक फाटक का निर्माण

(६) डिकाल की डारमिटरी में विद्यार्थियों के लिए दो स्नानागार तथा शौचालय का निर्माण।

(७) चन्द्रप्रभा के आरक्षित वन में एक कृत्रिम झील का निर्माण।

(८) रामनगर के मेडिकल आफिसर के आवास के दो कमरों १ बरामदा तथा पाठशाला बाल का निर्माण।

(१) पूर्वीय, पश्चिमी तथा दक्षिणी हल्को के १८ डिबीजनों में तथा भूमि व्यवस्था हल्को के एक डिबीजन वन्य जन्तु संरक्षण।

(२) (एक) प्राकृतिक पाकों तथा आरक्षित वनों और (दो) मोटर सड़कों का रखरखाव-५६ मील।

(३) मचान-१८

(४) छोटे आवास-३

(५) डारमिटरी ३ तथा

(६) कर्मचारियों के आवास-२० कुल व्यय ४,०३,६०० रु०

(५) वन्य जन्तु संरक्षण

योजना		१९६०-६१ के लिए निर्धारित लक्ष्य	१९६०-६१ की उपलब्धिया
(८) कुमायू में प्रथम श्रेणी के वनों का विकास	..	१०० एकड़ भूमि में वृक्षारोपण तथा अन्य और कार्य, व्यय ₹, १३,९०० रुपये ।	१५० एकड़ भूमि में वृक्षारोपण किया गया तथा पुराने लगाये वृक्षों की देखरेख की गयी, कुल व्यय ₹, १२,०५५ रु० ।
(९) वन-संचार का विकास	..	८५० मील मोटर रोड । ५५० मील टेलीफोन लाइन तथा २ पुलों के निर्माण का कार्य । व्यय ₹, ८९,२०० रुपये ।	लगभग १५३ मील मोटर रोड, ५१५ मील टेलीफोन लाइन १३ पुलों जिनमें २ आइरिडिया पुल भी थे, तथा २ पुलियों का निर्माण किया गया । करीब १२८ मील पुरानी मोटर रोड का रखरखाव भी किया गया । इन कायों में कुल ₹, ८८,५२१ रुपये व्यय हुए ।
(१०) निजी वनों का प्रबंध	..	४,००० एकड़ से अधिक भूमि में वृक्षारोपण तथा वपन कार्य । व्यय: ₹, ५६,४०० रु०	(१) ४,२०२ एकड़ से अधिक भूमि में वृक्षारोपण तथा वपन । (२) १ पौध घर का रखरखाव । (३) पूर्वोक्त हल्के में ७,००० एकड़ से अधिक क्षेत्र में वृक्षवपन तथा पेड़ों पर फैलने वाली वन बेलों के काटने का कार्य किया गया । (४) टिकरी रेंज के सहायक अधिकारी के अवास का निर्माण तथा सोहेलवा रेंज के रेंज अधिकारी के क्वार्टर विशेष मरम्मत की गयी । (५) कुआना रेंज के लिए मकान खरीदा गया । इन कार्यों पर ₹, २२,९१६ रुपये खर्च हुए ।
(११) कर्मचारी वर्ग १० पी० एफ० एस० तथा फारेस्ट रेंजों का प्रशिक्षण ।	..	१० पी० एफ० एस० १०० आफिसर तथा ८ फारेस्ट रेंजों का प्रशिक्षण व्यय ₹, ०१,६०० रुपये ।	प्रशिक्षार्थी देहरादून के फारेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण पा रहे थे । इस कार्य पर ₹, २,८८७ रु० व्यय हुए ।
(१२) सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जिलों में गंगा खादों में वनरोपण ।	..	१,०८० एकड़ । व्यय ₹, १६,००० रुपये	१,०८० एकड़ से अधिक भूमि में सभी कार्य सम्पन्न । व्यय ₹, ०९,९५६ रुपये ।

(१३) मेरठ और बुलन्दशहर जिलों के गंगा-जमुना आवाह क्षेत्रों में बन रोपण ।

(१४) गढ़वाल और बिजनौर जिलों में गंगा और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में वनरोपण

२,७३१ एकड़ भूमि में वनरोपण, व्यय २,८५,५०० रु० ।

२३० एकड़ तथा दो इमारतें, व्यय १,११,३०० रुपये ।

१,६३७ एकड़ में सब कार्य पूरे कर लिये गये । इस कार्य में ७,४६,६८५ रु० व्यय हुए ।

(१) कन्टरबन्दी-२५ लकड़ी के बाध ।

(२) वनरोपण-३५० एकड़ भूमि में ।

(३) एक पौधघर पूरा किया गया और २०० बेहने तैयार की गयी ।

(४) दो इमारतें बनायी गयी । व्यय १,१०,४८४ रु० ।

### (पिछड़े क्षेत्रों का विकास)

(१५) इस क्षेत्र में औद्योगिक महत्व के वृक्षों का रोपण ।

६५० एकड़ . व्यय ३,१८,२०० रुपये

(२) महत्वपूर्ण औषधीय जड़ी-बूटियों का रोपण ।

२० एकड़ क्षेत्र में रोपणकार्य, व्यय ४०,८०० रु०

(२) १,६०० एकड़ में मिट्टी बोने योग्य बनायी गयी। इन कार्यों पर ३,१८,०६५ रु० व्यय हुए ।

(१) रोपित क्षेत्र-६.०५ एकड़

(२) एक पौधघर का रखरखाव किया गया तथा टेहरी हल्के में दो और पौधघर आरम्भ किये गये ।

(३) कुमायू हल्के में ४ पौधघर आरम्भ हुए । इन कार्यों पर ४०,७६१ रुपये व्यय हुए ।

नयी सड़कें २५४ मील और ४२ कड़ी, तथा १६६ और ३३ कड़ी, पुरानी सड़कों का सुधार । सड़कों का नक्शा तैयार हुआ-४३ मील ।

पुल ३२ (जिनमें थडियार के गोदाम तथा मजदूरी के झोपड़ों का निर्माण भी सम्मिलित है ।) इन कार्यों में १२,१३,६१६ रुपये व्यय हुए ।

(३) सड़कों पुलों आदि का निर्माण

नयी सड़कें-२७० मील । सड़कों का सुधार १८८ मील, सड़कों का नक्शा ५४ मील । पुल ३१

थडियार, में गोदाम का कार्य पूरा करना तथा मजदूरी के लिए झोपड़ियों आदि का निर्माण । व्यय १२,१२,५०० रु० ।



## वन-उपज की सप्लाई

(१) इमारती लकड़ी—विभिन्न एजेन्सियों द्वारा ३१ मार्च, १९६० को १,३७,१३,००० घनफुट लकड़ी वन से निकाली गयी। इसमें ११,४६,००० घनफुट लकड़ी रियायत प्राप्त तथा अधिकार प्राप्त लोगों द्वारा निकाली गयी थी।

(२) रेलवे स्लीपर—रेलवे को ६१,८५,६१० रुपये मूल्य के स्लीपर सप्लाई किये गये। इसके अतिरिक्त ५,६९,५६४.७१ रुपये मूल्य के कड़ी लकड़ी के लट्ठे तथा मुलायम पहाड़ी लकड़ी भारत सरकार के पूर्ति और निपटान विभाग के महानिदेशक को सप्लाई की गयी।

(३) ई धन की लकड़ी—शहरो में ई धन की लकड़ी का मूल्य निश्चित करने तथा जनता को लकड़ी मिलती रहने के उद्देश्य से सरकार ने १९६१ का उत्तर प्रदेश ई धन (बिक्री एवं मूल्य) नियंत्रण आदेश जारी किया। प्रस्तुत वर्ष ७,३४,००० घन फुट ई धन की लकड़ी विभागीय एजेंसी द्वारा वन से निकाली गयी, २,९७,२५,००० घनफुट क्रय एजेंसियों द्वारा और २,७९,४३,००० घनफुट रियायत प्राप्त तथा अधिकार प्राप्त लोगों द्वारा निकाली गयी।

(४) लीसा (रेजिन)—लगभग ३,८०,००० मन लीसा प्रस्तुत वर्ष निकाला गया। इसका अधिकांश बलटरबकगज (बरेली) स्थित इंडियन टरपेटाइन एंड रेजिन कं० लि० को रेजिन की सप्लाई के समझौते के अन्तर्गत सप्लाई किया गया। कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन के लिए छोटे कारखानों और सहकारी समितियों को भी लीसा उपलब्ध किया गया। सहकारी समितियों को सहायता देने के उद्देश्य से लीसा इकट्ठा करने तथा ढोने का आशिक कार्य सहकारी समितियों को सौंपा गया।

## अनुसंधान तथा प्रयोग

आलोच्य वर्ष में किये गये प्रयोगों तथा अध्ययनों के महत्वपूर्ण परिणामों का विवरण नीचे प्रस्तुत है—

(१) सर्पगंधा (*Rauwolfia Serpentina*) तथा आक्सिसम किलीमाड स्केरिकम (*Killimanud Scharicum occimurn*) का अन्तरोपण बहुत उत्साहजनक नहीं सिद्ध हुआ किन्तु राबोल्फिया कास्पेस्कान्स (*Rauwolfia canspescans*) का सफलतापूर्वक अन्तरोपण किया गया।

(२) सकरित चिनालो में से पापुलस एम्बेनेन्सिस को एक वर्ष में ५७" वृद्धि हुई।

(३) सकरित युकिडलेटस के रोपण का परिणाम उत्साहजनक रहा। इनके बहुत ही कम पौधे सूखे और जुलाई, १९६० में रोपित पौधों की ५-६" की वृद्धि हुई।

(४) साखू के वनों में स्पान्टैक्स का केवल एक छिड़काव घासफूस की वृद्धि रोकने के लिए काफी नहीं था।

## कार्य योजनाएं

सोन और बिजनौर वन डिवीजनों की कार्य योजनाएं तैयार कर ली गयी थी। उत्तरकाशी और पीलीभीत वन डिवीजनों की कार्य योजनाएं तैयार हो रही थी और उत्तरी एवं दक्षिणी दोआब और दक्षिणी खीरी वन डिवीजनों की कार्ययोजनाओं का सशोधन हाथ में लिया गया।

## वित्तीय स्थिति

वन विभाग से संबद्ध १९५९-६० और १९६०-६१ के राजस्व तथा व्यय के विवरण नीचे दिये जा रहे हैं। (खर्च के आकड़ों में आयोजना का खर्च भी सम्मिलित है)

वर्ष	राजस्व	व्यय	अधिक (शेष)
	रु०	रु०	रु०
१९५९-६० (वास्तविक) . .	६,२८,६३,८४७	२,७९,६९,०००	३,४८,९४,८४७
१९६०-६१ (संशोधित अनुमान)	६,२३,४६,४००	३,१२,८१,९००	३,१०,६४,५००

## ९-रिहन्द बांध योजना

आलोच्य वर्ष में रिहन्द बांध परियोजना के कार्य में काफी तेजी आ गयी।

### (१) निर्माण कार्य

वर्ष के अन्त में रिहन्द परियोजना से संबद्ध कार्यों में खुदाई का कार्य चल रहा था। बांध के बिजलीघर की इमारत की नींव की खुदाई का कार्य पूरा किया जा चुका था। प्रस्तुत वर्ष ७०.४९ लाख घनफुट कंकरीट डाली गयी। इसके सहित बांध तथा उसके लगाव में कुल ५८२.११ लाख घनफुट कंकरीट डाली जा चुकी थी।

बांध के जल-नियमन वाले भाग में तथा जल नियमन की शेष लम्बाई पर्याप्त पुरी अंचाई ई०एल० ८५२.०० तक उठ गयी थी और जल-नियमन के बड़े का निर्माण हो रहा था।

पेन्स्टाक फाटको के, कलकत्ता की फर्म से जो उन्हें बना रही थी, प्राप्ति में विलम्ब के कारण फाटको के लगने में विलम्ब की संभावना थी। फिर भी इस बात का प्रयास किया जा रहा था कि फाटको की प्राप्ति में शीघ्रता की जा सके। फिलहाल ५ फाटक लगाये जाने थे। पेन्स्टाक में फाटक लग जाने के बाद उसमें अस्थायी रूप से लगे बाड़े को अलग कर दिया जाना था और तब बिजली उत्पादन की इकाई का धूर्णन आरम्भ होने को था, जिससे व्यापारिक उपयोग के लिए उत्पादन आरम्भ करने के पूर्व सामान्य परीक्षा किया जा सके।

स्थायी उपकरण—(क) पेन्स्टाक फाटक निर्माण में विलम्ब होने के कारण अब प्रथम पेन्स्टाक फाटक के १९६१ के अप्रैल के अन्त तक मिलने की आशा थी। जो पांच ह्वीडिस्ट तथा सहायक उपकरण आस्ट्रिया से मंगाये जाने थे उनमें से २ पहुंच गये थे। तीसरा सेट जहाज द्वारा रवाना किया जा चुका था और शेष को शीघ्र ही तैयार कर के भेजे जाने की सूचना मिली थी।

(ख) १०० टन क्षमता के चतुर्पद आधार वाले क्रेन—दो के अतिरिक्त सभी पैकेज निर्माण-स्थल पर पहुंच गये थे। रेलों का जड़ना जारी था और क्रेन को खड़ा करने संबंधी आरम्भिक कार्य आरम्भ किये जा चुके थे। शेष दो पैकेजों के निर्माण-स्थल पर पहुंच जाने पर क्रेन को खड़ा करने का पूरा कार्य आरम्भ किया जाना था।

(ग) टा-इंटर-फाटक--सभी फाटको के लंगर तथा दहलीज की शहतीरे खड़ी कर दी गयी थी और उन्हें ककरीट में गाड़ दिया गया था तथा उनके पार्श्व के उपकरण भी प्रायः आधे भाग में लग चुके थे ।

(घ) जल-निकास फाटक और उनको उठाने का उपकरण--इन फाटको से संबद्ध अधिकांश सामग्री निर्माण-स्थल पर पहुंच गयी थी और शेष लायी जा रही थी ।

(ङ) २५ टन क्षमता के चतुर्पद आधार वाले क्रेन--यह क्रेन जिसकी आवश्यकता ड्राफ्ट ट्यूब फाटको के लगाने के लिए थी निर्माण-स्थल पर पहुंच गया था और उसे खड़ा किया रहा था ।

(च) ड्राफ्ट ट्यूब फाटक--इन फाटको का निर्माण सिचाई विभाग की बरेली की वर्कशॉप में हो रहा था । फाटको का निर्माण और उनके भेजने का क्रय संतोषजनक रहा ।

(छ) छिद्रण तथा भरण--नीवो का छिद्रण तथा भरण का काम प्रायः समाप्त हो चुका था । जल-निकास छिद्रों के छिद्रण का कार्य पूरे जोर-शोर में चल रहा था और मार्च, १९६१ के अन्त तक १०,८६० वर्गफुट छिद्रण का कार्य पूरा हो चुका था ।

बिजलीघर--बिजलीघर के प्रायः सभी प्रमुख कार्य पूरे कर लिये गये थे । केवल उनको अंतिम रूप देना शेष रहा । यह कार्य भी संतोषजनक ढंग से प्रगति कर रहा था । टेलरेस चैनलों की खुदाई प्रायः समाप्त थी और रेगुलेटर का निर्माण निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा था । ६६ किलोवाट के स्विचयार्ड का निर्माण कार्य भी संतोषजनक प्रगति कर रहा था ।

कई कठिनाइयों के बावजूद इस परियोजना की प्रगति का शेड्यूल यथावत बनाये रखा जा रहा था ।

## (२) बिजली के काम

(क) बिजलीघर तथा आउटडोर स्विचबोर्ड--मशीन तथा उपकरणों का निर्माण इंग्लैन्ड, चेकोस्लोवेकिया, पश्चिमा जर्मनी और स्विट्जरलैन्ड की वर्कशॉपों में प्रायः पूरा हो गया था ।

रिहन्द बिजलीघर की १, २, ३ और ४ नंबर की बिजली उत्पादक इकाइयों का निर्माण पूरा हो गया और ५वीं का निर्माण-कार्य चल रहा था । १, २, ३ तथा ४ नम्बर की इकाइयों में केबुल लगाने तथा बिजली लगाने का कार्य चल रहा था ।

बाध पर बिजली लगाने, बिजलीघर में रोशनी लगाने, जेनरेटर, ट्रांसफार्मर, बिजली लगाने, एयर कंडिशनिंग तथा गवाक्ष पाइप का प्रकीर्ण कार्य, लोड टेस्टिंग उपकरण इत्यादि कार्यों के लिए अनुबन्ध किये गये और इन मदों के कार्य हाथ में लिये गये ।

पिपरी के आउटडोर स्विचबोर्ड के नीव का कार्य तथा उसके ढांचे के उठाने का कार्य पूरा कर लिया गया और इसी प्रकार १३२ किलोवाट के मुख्य बसबारों और जैकबासों तथा ६६ किलोवाट के स्विच यार्ड पर तार लगाने का कार्य भी पूरा कर लिया गया । उप-बिजली-घर के उपकरणों जैसे ट्रांसफार्मर ओ०सी०, बी०, सी०टी०, पी०टी० इत्यादि को लगाने का कार्य चल रहा था । एक ६० एम० बी०ए० ११/१३२ किलोवाट के ट्रांसफार्मर को उठाने का कार्य पूरा कर लिया गया और दूसरे ट्रांसफार्मर के उठाने का कार्य प्रगति कर रहा था ।

(ख) १३२ किलोवाट ट्रांसमिशन लाइने—१३२ किलोवाट की ट्रांसमिशन लाइनों के निम्न सेक्शनों का निर्माण-कार्य हो रहा था :—

	मील
(१) पिपरी-राबर्ट्सगंज सेक्शन .. .. .	३४.७५
(२) राबर्ट्सगंज-मुगलसराय सेक्शन .. .. .	४४.५०
(३) राबर्ट्सगंज-मिर्जापुर सेक्शन .. .. .	४७.३८
(४) मुगलसराय-कर्मनासा सेक्शन (इस लाइन का निर्माण रेलवे की लाइनों के लिए बिजली को देने के अभिप्राय से हो रहा था)	२३.८५

योग .. १५०.४८

इन सेक्शनों में कुल ७२७ लोकेशन थे, जहाँ टावर उठाने थे। आलोच्य वर्ष के अन्त तक ७१६ लोकेशन पर स्टेब सैटिंग तथा ६७४ लोकेशन पर सुपरस्ट्रक्चर उठाने का कार्य पूरा हो चुका था। इन सेक्शनों में शेष कार्य चल रहा था।

सोन नदी को पार करने वाले टावरों की डिजाइन और नक्शा तयार कर लिया गया था तथा उनकी नींव का कार्य आरम्भ कर दिया गया था और वर्ष के अन्त में कार्य में प्रगति हो रही थी।

ट्रांसमिशन लाइनों के ढांचों के लिए अपेक्षित इस्पात के मिलने में कठिनाई का अनुभव किया जाता था। लगातार प्रयत्न के फलस्वरूप अपेक्षित इस्पात का केवल कुछ अंश ही बम्बई के फेब्रीकेटर वर्कशॉप को भेजा जा सका। (ग) १३२/३३/११ किलोवाट के ग्रिड सब-स्टेशन-ग्रिड उप-बिजलीघरों का निर्माण राबर्ट्सगंज, मुगलसराय तथा मिर्जापुर में हो रहा था। उप-बिजलीघरों के उपकरणों जैसे १३२ किलोवाट के ट्रांसफार्मर तथा ३३ किलोवाट का स्विच-गियर तथा पावर और कंट्रोल के बुल के लिए विभिन्न फार्मों को ठीके दिये गये। उप-बिजलीघरों के ढांचों के निर्माण का कार्य प्रगति कर रहा था और यह कार्य करने वाली वर्कशॉप को इस्पात सप्लाई करने का प्रबन्ध किया गया। इसके अतिरिक्त उप-बिजलीघर के कुछ उपकरण विदेशी निर्माताओं से मगाये गये।

### (३) भवन

रिहन्द के ग्रिड उप-बिजलीघरों की नींव के निर्माण के लिए ठीके दिये गये और उन पर कार्य आरम्भ किया गया।

बाहर के उप-बिजलीघर कंट्रोल रूम वर्कशॉप, स्टोर तथा साहूपुरी (मुगलसराय), राबर्ट्सगंज और मिर्जापुर के ग्रिड उप-बिजलीघर के ट्रांसफार्मर की मरम्मत की दुकानों के निर्माण का कार्य जारी रहा।

बिजली कानूनों का प्रशासन—बिजली निरीक्षक सगठन ने आलोच्य वर्ष में ४३ लाइसेंसदारों के कार्यों का निरीक्षण किया जिनमें नगरपालिका को सप्लाई करने वाली फर्म भी थी जबकि इसके पूर्व वर्ष ३२ लाइसेंसदारों के कार्यों का निरीक्षण किया गया था। ये निरीक्षण इस उद्देश्य से किये गये थे कि भारतीय बिजली नियमों का उचित ढंग से पालन होता रहे। इन मामलों में जिनमें लाइसेंसदारों के कार्यों में कोई नुकस पाया गया लाइसेंसदारों को उन्हें दूर करने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया।

१९६०-६१ वर्षावधि में बिजली के कारण हुई उन दुर्घटनाओं की संख्या १६० थी जिनकी सूचना निरीक्षालय को मिली थी जबकि इसके पूर्व वर्ष इन दुर्घटनाओं की संख्या

१९१ थी। इनमें से १७२ दुर्घटनाएं सांघातिक या छोटी थी। शेष १८ दुर्घटनाएं बहुत मामूली चोटों की थी। सभी प्राणहानि से सबद्ध तथा छोटी दुर्घटनाओं की जांच निरीक्षालय ने की और उचित कार्यवाही की गयी। किन्तु मामूली चोटों वाली दुर्घटनाओं के संबंध में निरीक्षालय द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

ऊपर की दुर्घटनाओं के अतिरिक्त बिजली की ५ और दुर्घटनाएं हुईं जो इन संस्थाओं में हुईं जो या तो प्रतिरक्षा विभाग या रेलवे अधिकार क्षेत्र में थी और उनकी रिपोर्ट निरीक्षालय में केवल सूचनार्थ की गयी। इन मामलों में निरीक्षालय से जांच की अपेक्षा नहीं थी। ग्रामीण क्षेत्रों में जो दुर्घटनाएं हुईं वे अनाधिकारी व्यक्तियों के हाईवोल्टेज लाइन के खम्भों पर चढ़ने के कारण हुईं। उपभोक्ताओं के घरों में हुई दुर्घटनाओं का कारण था या तो बिजली के उपकरणों और पुरजों का प्रयोग करने में असावधानी अथवा बिजली की फिटिंग आदि के रखरखाव में कोताही। जबकि १९५६-६० में निरीक्षालय द्वारा ४३ बिजली कंपनियों के लेखा की जांच हुई थी, आलोच्य वर्ष में केवल ३७ बिजली कंपनियों के हिसाब-किताब की जांच की जा सकी। इस कमी का कारण यह था कि लखनऊ में बाढ़ के कारण बिजली निरीक्षक के कार्यालय को वर्ष में एकाधिक बार एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाना पड़ा जिसके कारण कार्य में व्याघात पड़ा।

लाइसेंसदारों के हिसाब-किताब की निरीक्षा के फलस्वरूप निम्न बिजली कंपनियों की बिजली सप्लाई की दरों में कमी कर दी गयी.—

- (१) दी बाराबकी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड, बाराबकी।
- (२) दी अपर जमुना बैरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, मेरठ।
- (३) दी फर्रुखाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, फतेहगढ़।
- (४) दी किशोर इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन, बदायूं।
- (५) दी म्युनिसिपल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अन्डर टैकिंग, उन्नाव।
- (६) दी अलीगढ़ इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, अलीगढ़।

आय—आलोच्य वर्ष बिजली कर के रूप में ५५,८१,७३० रुपये वसूल किये गये जबकि इससे पूर्व वर्ष (१९५६-६०) में ५१,३१,०२६ रुपये वसूल हुए थे। बिजली निरीक्षालय की कुल आय-निरीक्षा शुल्क, वायरमेन की परमिट इश् करने, सुपरवाइजर का प्रमाण-पत्र तथा बिजली के ठेकेदारों के लाइसेंस की फीस, लाइसेंसदारों के हिसाब-किताब की परीक्षा की फीस आदि मिला कर प्रस्तुत वर्ष १,१०,०८८ रुपये थी जबकि १९५६-६० में यह आय १,०१,३१२ रुपये थी।

व्यय—आलोच्य वर्ष में निरीक्षालय पर कुल २,५६,७०० रुपया खर्च हुआ जब कि १९५६-६० में कुल खर्च २,४२,३५० रुपया हुआ था।

## १०—उद्योग

### सामान्य

१९६०-६१ वर्षविधि में बड़े माध्यम, लघु कुटीर तथा ग्रामोद्योगों में चतुर्दिक वृद्धि हुई। इससे पूर्व आरम्भ भारी उद्योगों, लघु एवं ग्राम उद्योगों तथा प्राविधिक शिक्षा के संबंध में तृतीय पंचवर्षीय आयोजना की रूप-रेखा तैयार की गयी। १९६० के पूरे उत्पादन का मूल्य २६,३५२.३४ लाख रुपये लगाया गया जो इससे पूर्व वर्ष के रेकार्ड पर ३८.२६ प्रतिशत की प्रगति दिखलाता था। इसी के अनुसार रोजगार में भी वृद्धि हुई जो २१.३४ प्रतिशत थी।

रिपोर्ट भेजने वाली फंक्टरिया, व्यक्ति जो रोजगार पर लगे तथा १९५६ और १९६० में उत्पादन के मूल्य का विवरण नीचे दिया जा रहा है:—

उद्योग का नाम		१९५६		१९६०	
रिपोर्ट भेजने वाली फैक्ट्रियों की संख्या	रोजगार पाने वाली की संख्या	उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)	रिपोर्ट भेजने वाली फैक्ट्रियों की संख्या	रोजगार पाने वाली की संख्या	उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)
(१) (काटन टेक्सटाइल ऐंड एलाइड मैन्युफैक्चरर्स)	३४	५५,५२६	४२	६३,१०६	३,६३३.३८
(२) (बलेन टेक्सटाइल ऐंड एलाइड मैन्युफैक्चरर्स)	१२	३,७४५	१६	४,८५०	५०५.६८
(३) (जूट टेक्सटाइल ऐंड इलाइड मैन्युफैक्चरर्स) जूट वस्त्र तथा सबड निरमाता	८	५,८४२	१०	६,०७६	३०२.६३
(४) सिलक टेक्सटाइल (रेशमी वस्त्र)	६	४२६	११	६४४	३२.०४
(५) काटन वेस्ट ऐंड जिनिंग	१७	४६६	२१	७५४	५८.३१
(६) होजरी ऐंड निर्दिग	१६	६१४	२१	८३५	५६.७३
(७) कैलेडरिंग, डाइंग ऐंड प्रिंटिंग	१६	४८५	२३	१,०८६	३०.४२
(८) ताला तथा छूरी, काटा आदि	११	६७१	१३	१,२६२	७८.६४
(९) हरीकेन लालटेन	३	६१३	३	६६३	३७.१७
(१०) साइकिल तथा साइकिल के पुर्जे	४०	२,०४३	४५	२,३६६	१८५.३८

रिपोर्ट भेजने वाली फैक्टरिया, व्यक्ति जो रोजगार पर लगे तथा १९५६ और १९६० में उत्पादन के मूल्य का विवरण नीचे दिया जा रहा है :-

१९६०

१९५६

उद्योग का नाम	रिपोर्ट भेजने वाली फैक्टरियों की संख्या	रोजगार पाले वालों की संख्या	उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)	रिपोर्ट भेजने वाली फैक्टरियों की संख्या	रोजगार पाले वालों की संख्या	उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)
(११) मशीन, मशीन के पुर्जे, औजार तथा कृषि उपकरण	..	३४	१,०७६	७२	३४	१,३७२
(१२) लोहा तथा इस्पात का फर्नीचर	..	११	५०८	२३.३३	११	५०१
(१३) लोहेतर धातुओं के उत्पादन	..	३३	१,१४७	१२५.६८	४४	१,६४७
(१४) मोटर तथा अन्य स्वचालित गाडियों के पुर्जे	..	२	१४	३.०५	४	१०५
(१५) इलेक्ट्रोप्लेटिंग	..	१५	२५४	६.६६	१३	२५७
(१६) बिजली के लैम्प तथा छोटे बल्ब	..	२	१,०६६	१०६.२१	७	१,३०४
(१७) टिन के डिब्बे	..	६	४२१	६१.६६	१५	६५७
(१८) प्रकीर्ण इन्जीनियरिंग आइटम रोलिंग एंड फाउन्ड्रीज	..	३४६	१६,६३६	१,१७७.७५	३६५	१८,७१६
(१९) चीनी	..	६६	५१,८७५	७,४२७.४७	७०	७०,४०६
(२०) चाय	..	१४	२,४५०	२२.००	१४	१,६८८
(२१) बनस्पति तेल	..	४	१,१२७	१,१३८.४५	४	१,४१८
(२२) तेल, दाल, चावल तथा आटा मिले	..	३१४	१०,३६१	३,१४८.१५	३२६	१२,७६०

(२३)	फल तथा सब्जी का निर्माण एवं डिब्बाबन्दी	४	८१	५.४२	५	४३.७१
(२४)	दुग्धशाला के उत्पादन	७	८१७	६१.२१	६	५५.०५
(२५)	झकरी उत्पादन	७	२८५	२४.५५	६	३२.७७
(२६)	बर्फ तथा कोल्ड स्टोरेज	८५	१,५८८	८६.६०	६६	१३३.८३
(२७)	तम्बाकू तथा संबद्ध उत्पादन	१४	२,६७४	७६६.००	१७	१,१२७.४६
(२८)	खादसारी	२०४	६,१४८	१५०.७२	२४५	२३३.११
(२९)	रासायनिक, चिकित्सा संबंधी तथा अन्य संबद्ध उत्पादन	४४	२,७५५	२०८.५६	४६	२४६.२५
(३०)	शराब की भट्टिया	१२	१,२६३	८८,०८०	१६	१०६.७७
(३१)	रंग तथा वानिश	८	४६२	६२.५३	८	६५.३१
(३२)	हड्डी का चूरा तथा संबद्ध उत्पादन	७	६२६	४४.०३	७	६०.५६
(३३)	साबुन	२	१४१	२५.५३	४	२०.१७*
(३४)	चपड़ा	७	२८६	६	६**	८.५५**
(३५)	श्रीवर्गिक गैस	२	७२	८.५६	२	१६.२४
(३६)	कत्था	४	५६४	३७.७२	४	५८.०८
(३७)	तेल, इत्र आदि	३	१२६	२२.०६	३	२७.७५
(३८)	कागज, स्ट्रॉबोर्ड तथा संबद्ध उत्पादन	१०	२,०८०	१८६.८६	१३	२१८.८०
(३९)	लेखन सामग्री तथा जिल्दबन्दी	७	१६६	३२.१३	८	२७.७८
(४०)	लकड़ी के फर्नीचर तथा संबद्ध उत्पादन	२५	७१८	२३.६१	२६	२८.२८
(४१)	प्लाई वुड	३	५६७	३४.८१	३	४२.६०
(४२)	काच तथा काच की बूड़िया	११६	१४,४५२	५०१.७३	१४६	४४६.५२
(४३)	मुद्रणालय	१७५	८,१६१	३०६.१८	१६०	३०५.२६†
(४४)	चमड़ा तथा चमड़े का सामान	७८	८,१०७	७०८.३६	८४	७७१.१४

\* इस उद्योग में सबसे बड़ी इकाइयों के उत्पादन में बहुत भारी गिरावट हुई है।

\*\* एक इकाई बन्द हो गई।

† इससे इस उद्योग की सबसे बड़ी इकाइयों में से एक की सूचना सम्मिलित नहीं है।



उद्योग का नाम	१९५६					१९६०				
	१९५६					१९६०				
	रिपोर्ट भेजने वाली फैक्टरियो की संख्या	रोजगार पाने वालों की संख्या	उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)	रिपोर्ट भेजने वाली फैक्टरियो की संख्या	रोजगार पाने वालों की संख्या	उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)	उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)			
(४५) मृत्तिका उद्योग	२	८७	२.१६	४	२३८	५.०५	५.०५			
(४६) प्लास्टिक के सामान	४	१८३	१७.८६	७	२८५	८.६७	८.६७			
(४७) बुझ के सामान	२	६०	३.१८	३	१३७	५.३८	५.३८			
(४८) फाउन्टेनपेन	७	१३३	५.८८	५	११५	४.६४	४.६४			
(४९) खेलकूद के सामान	७	२३१	१०.२५	७	३०७	१३.५७	१३.५७			
(५०) प्रकीर्ण उद्योग (इनमें रेयन, रेडीमेड कपड़े, टाई, बैटरी, सेपरेटर, पेय, अफीम तथा क्षार, रेजिन तथा तारपीन, दियासलाई, संगीत के साज, हाथ का बना कागज, नमक की सफाई, मोटर गाड़ी आदि की मरम्मत, चूना आर०सी०सी० और ह्यूम पाइप, ग्रेनाइट, पत्थर के सामान, दीवाल घड़िया आदि शामिल हैं)	४०	५,१८४	७६६.७०	७७	६,१३५	६०२.५२	६०२.५२			
योग ..	१,६११	२,१६,०६४	२१,२२६.६६	२,१६८	२,६२,२०१	२६,३५२.३४	२६,३५२.३४			

[इस उद्योग में लगी सबसे बड़ी इकाई के उत्पादन में बहुत गिरावट हुई है।]

एक निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम (निजी) के नाम से स्थापित किया गया और उसे कंपनी के रूप में पंजीकृत कर दिया गया। इस निगम की स्थापना इस अभिप्राय से की गयी कि जो राजकीय औद्योगिक संस्थाएँ इसके सुपुर्दे की जायें, उनमें सफलतापूर्वक कार्य हो। तृतीय पंचवर्षीय आयोजनाकाल में आरम्भ होने वाली कुछ राज्य परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा सकें। यह निगम एक स्वतंत्र निकाय के रूप में व्यावसायिक ढंग पर कार्य करेगा। सरकार इस निगम के शेयर की पूँजी के ढाँचे को स्थापित करने में भाग लेने की थी और तदनुसार उसने आरम्भ करने के लिए २५ लाख रुपये मूल्य के शेयर भी खरीदे।

आलोच्य वर्ष में उद्योग (विकास एवं नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत १३६ लाइसेंस दिये गये, जिनमें ८६ करोड़ रुपये की लागत लगने वाली थी। निम्नलिखित परियोजनाएँ सार्वजनिक क्षेत्र में आरम्भ करने के लिए भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में उचित-कदम उठाये गये:—

परियोजना	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)
१—एंट्री वायोटेक्स फैक्टरी, ऋषीकेश .. .. .	१०.००
२—उर्वरक फैक्ट्री, गोरखपुर .. .. .	२७.००
३—सिंगरोली कोयला क्षेत्रों का विकास .. .. .	१०.००
४—भारी बिजली परियोजना, ज्वालापुर. . . . .	४५.००
योग .. .. .	९,२००

लघु गुड़ निर्माण उद्योग, भारी मशीन टूल उद्योग, वायुयान फैक्ट्री, सूक्ष्म धातु फैक्ट्री आदि से संबद्ध आवश्यक परियोजना रिपोर्ट तैयार की गयी और उन्हें भारत सरकार के पास भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश वित्त निगम ने मध्यम तथा लघु उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। निगम द्वारा उदार ऋण योजना के अन्तर्गत १,३८,१६,००० रुपये तथा निगम ऋण के अन्तर्गत १,८३,६५,००० रुपये स्वीकृति किये गये। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत वर्ष सरकार द्वारा ५१.७८६ लाख रुपये ऋण के रूप में वितरण के लिए तथा १.१७ लाख रुपये अनुदान के रूप में वितरण के लिए स्वीकृति किये गये। इसमें से आलोच्य वर्ष ऋण के रूप में ५१.७०२ लाख रुपये तथा अनुदान के रूप में १.१७ लाख रुपये वितरित किये गये। छोटे उद्योगपतियों की सुविधा तथा राज्य में औद्योगीकरण की गति प्रदान करने के लिये कानपुर तथा आगरा में दो बड़े औद्योगिक आस्थान तथा देवबन्द (महारनपुर), काशी विद्यापीठ और लोनी (मेरठ) में तीन ग्रामीण औद्योगिक आस्थानों की स्थापना प्रायः समाप्त हो चुकी थी, साथ ही अतिरिक्त पांच और औद्योगिक आस्थान पहाड़ी जिलों में स्थापित किये जा रहे थे। इसके अतिरिक्त बस्ती, देवरिया, झांसी, एटा तथा बिजनौर में औद्योगिक आस्थान बनाने संबंधी प्रारम्भिक प्रवन्ध किये जा रहे थे।

स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा परिचालित अग्रगामी योजना के अन्तर्गत प्रगाढ़ वित्तीय सहायता दी गयी और उद्योगपतियों को कोयला, कोयले का चूरा, लोहा तथा इस्पात और लोहेत्तर धातुओं जैसे कंट्रोल की चीजों की सप्लाई का प्रबन्ध किया गया। आवश्यक कच्चा माल, पुरजों तथा मशीनों आदि को विदेशों से खाने के लिए "आवश्यकता प्रमाण पत्र" प्राप्त करने का भी प्रबन्ध किया गया। इसके साथ ही लघु उद्योगों की बढ़ती हुई बिजली की मांग पूरी करने का प्रबन्ध किया गया। गुण-बिज्ञानिक योजना का लघु उद्योगों, दस्तकारियों तथा कुटीर उद्योगों के उत्पादकों का स्तर ऊँच करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्हीं की सुविधा के लिए राज्य भर में २२ निरीक्षा दियो चलाये जा रहे थे। इसके फलस्वरूप उत्पादन की बिक्री

क्षमता में पर्याप्त वृद्धि हुई। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के अभिप्राय से उनके उत्पादनों को प्राथमिकता दी गयी और उनकी कुछ बर्तों को उद्योग निदेशालय के स्टोर्स परचेज सेक्शन ने सुरक्षित करा लिया था। उद्योगोन्मुख व्यक्तियों के लिए "हायर परचेज" आधार पर मशीनों का प्रबन्ध नयी दिल्ली स्थित राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा किया गया। छोटे उद्योगोन्मुखों को ५७.२८ लाख रुपये मूल्य की मशीनों की 'हायर परचेज' योजना के अन्तर्गत स्वीकृति दी गयी।

अन्य दिशाओं में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। ग्राम उद्योगों के आवश्यक विकास को गति देने के लिए आलोच्य वर्ष में कानून द्वारा स्थापित एक खादी एवं ग्राम उद्योग परिषद् का गठन किया गया। बिजली चालित करघा योजना की कार्यन्वित में भी पर्याप्त प्रगति हुई। खलीलाबाद तथा टांडा में दो केंद्रीय सूत निर्माण फैक्टरियां भी स्थापित की जा रही थीं, जिसमें बस्ती, गोरखपुर तथा फैजाबाद जिलों में स्थापित किये जाने वाले २६८ बिजली चालित करघों के लिए सूत दिया जा सके।

इस वर्ष का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था नये गठित उत्तराखंड डिवीजन के तीन जिलों में औद्योगिक विकास का प्रगाढ़ कार्यक्रम आरम्भ करना। कई जल चरखे इस क्षेत्र में सूत का उत्पादन बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध हुए, कई उपयुक्त स्थानों पर लगाये गये। इसी प्रकार राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए पिछले वर्ष तथा आलोच्य वर्ष ६ विशेष योजनाएं परिचालित की गयीं थीं। उनके कार्य को जोर-शोर से बढ़ाया गया। उद्योग की दिशा में हुए महत्वपूर्ण कार्यों के विवरण नीचे दिये जा रहे हैं:—

### १-भारी उद्योग राजकीय सीमेन्ट फैक्ट्री, चुरक

चुरक की राजकीय सीमेन्ट फैक्ट्री में जहां सितम्बर, १९६० को उत्पादन का सातवां वर्ष आरम्भ हुआ, १९६०-६१ में २,४३,९६१ मीट्रिक टन सीमेन्ट का उत्पादन हुआ। फैक्ट्री के विस्तार की परियोजना से संबंधित कार्य पूरे जोर-शोर से चल रहा था। चैकोस्लोवाकिया से आयात की हुई सीमेन्ट उत्पादन मशीन का अधिकांश भाग निर्माण-स्थल पर पहुंच गया था। यह आशा की जाती थी कि १९६१ के अन्तिम चतुर्थी में नई इकाई द्वारा उत्पादन आरम्भ हो जायेगा और ज्यों ही आरम्भिक कठिनाइयां दूर हो जायेंगी, फैक्ट्री में अब तक के ७०० टन प्रति दिन के उत्पादन के स्थान पर १,४०० टन सीमेन्ट प्रतिदिन उत्पादित होने लगेगा। अग्रगामी रिफ्रैक्टरी मशीन से जनवरी, १९६१ में उत्पादन होने लगा और यह आशा की जाती है कि प्रति वर्ष १,५०० टन पक्की ईंटें बनने लगेंगी।

तृतीय पंचवर्षीय आयोजना काल में फैक्ट्री के प्रसार कार्यक्रम में एक रिफ्रैक्टरी प्लान्ट, सफेद और रंगीन सीमेन्ट बनाने की मशीन तथा उत्तम किस्म की अत्युमिना सीमेन्ट बनाने की इकाई की स्थापना सम्मिलित थी।

### २-राजकीय सूक्ष्म यंत्र फैक्ट्री, लखनऊ

लखनऊ की राजकीय सूक्ष्म यंत्र फैक्ट्री ने अच्छी प्रगति की। ३६,००० पानी के मीटर तथा ३०० अनुवीक्षण यंत्रों के निर्माण के निर्धारित लक्ष्य से उत्पादन अधिक हुआ और ४३,११३ पानी के मीटर तथा ४४६ अनुवीक्षण यंत्रों का उत्पादन हुआ। फैक्ट्री ने "प्रेसरगाज" के निर्माण का कार्य भी हाथ में लिया। ४०० डिजाइनों और नकशों तैयार किये गये। आलोच्य वर्ष में औद्योगिक रत्नों का निर्माण करने वाली मशीन भी लगायी गयी और निर्माण के लिए टेक्निशियनों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। अपने किस्म की देश में यह पहली मशीन लगी थी। ५५ अप्रेंटिसेजों को तैयारिक तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा था।

तृतीय योजना काल में फैक्ट्री में और विस्तार किया जाना था और इस प्रसार कार्यक्रम में पानी के मीटरों तथा अनुवीक्षण यंत्रों के प्रस्तुत उत्पादन को दो गुना या यदि सम्भव हो सके तो

तीन गुना करना, एक डिजाइन एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करना और आण्टिकल औजारों के निर्माण के लिए एक अलग यूनिट की स्थापना करना था।

### ३-विकास कार्यक्रम

(क) उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम—२६ मार्च, १९६१ को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम नाम से एक निगम का पंजीकरण हुआ। इस निगम द्वारा राज्य के लिए उपयोगी समझी जाने वाली उद्योगों के संबंध में परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, उनके निजी क्षेत्र या अपने अधीन वित्तपोषित कम्पनी के रूप में अथवा स्वतंत्र रूप से स्थापना करने की दिशा में प्रयत्न करने, पहले के यूनिटों की ठीक ढंग से कार्य करने, कार्यों के पुनर्गठन, पुनर्वास आदि में सहायता करने तथा राज्य के विभिन्न भागों में अलग-अलग क्षेत्रों के विकास का कार्य किया जाना था।

(ख) औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना—बड़े तथा मध्यम उद्योगों के विकास के लिए सर्वेक्षण किये गये। चार औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का प्रस्ताव था। इनमें से दो गाजियाबाद तथा दो गोरखपुर, मिर्जापुर और झांसी जिलों के क्षेत्र में थे।

(ग) डिजाइन एवं अनुसंधान केन्द्र—लखनऊ की राजकीय सूक्ष्म यंत्र फैक्ट्री में एक डिजाइन एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए आदेश जारी किये गये जिसके लिए राज्य के तृतीय पंचवर्षीय आयोजना में ११ लाख रुपये निर्धारित किये गये थे।

(घ) खनिज पदार्थों का विकास—इस दिशा में प्रारम्भिक कार्य के लिए ४५,००० रुपयों की व्यवस्था की गयी थी।

(ङ) एन्टीबायोटिक्स—ऋषीकेश में रूस के सहयोग से १०.०० करोड़ रुपयों की अनुमानित लागत से एक परियोजना की स्थापना की जानी थी। इससे सम्बद्ध पूरे आंकड़े भारत सरकार को भेजे गये।

(च) उर्वरक फैक्ट्री की स्थापना—गोरखपुर में एक उपयुक्त निर्माण-स्थल चुन लिया गया था इस परियोजना की स्थापना में लगभग २७ करोड़ रुपये खर्च होने की आशा थी।

(छ) भारी बिजली कारखाना—ज्वालापुर (सहारनपुर) का निर्माण-स्थल भारी बिजली कारखाने की स्थापना के लिए अच्छा समझा गया और उसके अधिकांश आंकड़े भारत सरकार को भेज दिये गये।

### (१) हथकरघा विकास और (२) लघु उद्योग—

(क) बुनकर समितियाँ, उत्पादन तथा बिक्री आदि—१९६०-६१ में ६९ हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों का गठन किया गया, जिनको लेकर अब तक ऐसी १,२५३ समितियाँ हो गयीं और इनकी कुल सदस्य संख्या १,१८,१२१ हो गयी। इसके अतिरिक्त राज्य में ५१४ उत्पादन एवं विपणन बुनकर सहकारी समितियाँ भी थीं जिन्होंने १०,७१,२८,२९३ रुपये मूल्य का १०,५९,०९,५४५ गज हथकरघा से बुना कपड़ा तैयार किया।

१८७ सहकारी बिक्री डिपों में ३२,४९,४६७ रुपये मूल्य का ३१,३८,३९७ गज हथकरघा से बुने कपड़े की बिक्री हुई जबकि इसी अवधि में राजकीय ८० पी० हैंडीक्रेफ्ट अन्तर्प्रदेशीय बिक्री केन्द्रों में ६,५३,१९४ रुपये मूल्य का ३,२४,५१० गज कपड़ा बिका। कानपुर उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ के तीन केन्द्र तथा चार सचल बिक्री केन्द्रों में क्रम से ६८,६१८ रुपये तथा ४९,५८७ रुपयों मूल्य के ५०,२२४ गज कपड़े बिके।

(ख) रंगाई, गुण चिह्नीकरण तथा कैलेंडरिंग—६६ लघु रंगाईघरों ने २,००,८०२ पौण्ड सूत की रंगाई की थी तथा पिलखुआ और वाराणसी में खुले मध्यम रंगाई घरों में ५,७८५ पौण्ड

सूत की रंगाई तथा १२,५६५ पौण्ड सूत को साड़ी लगायी गयी। इसके अतिरिक्त सहकारी समितियों को सुधरे उपकरणों की खरीद के लिए २,७७,२०० रुपये दिये गये। १९६०-६१ कालावधि में ३०,५६,४३६ गज हैन्डलूम कपड़े पर गुण चिह्नानकन लगाया गया।

मऊ (आजमगढ़) स्थित राजकीय रंगाई, साड़ी तथा किर्निशिंग फैक्ट्री में २४,४८,६८६ गज हैन्डलूम कपड़े की कैलेण्डरिंग तथा ३२,२११ पौण्ड सूत पर साड़ी की गयी। इसी प्रकार खलीलाबाद के कैलेण्डरिंग कारखाने में ३२,४२,१३० गज कपड़े की कैलेण्डरिंग की गयी।

(ग) रेशम रंगाईघर—रेशम के बुनकरों की पक्के रंगाई की मांग पूरी करने के लिए खोले गये ६ रेशम रंगाईघरों में आलोच्य वर्ष में १२,४५० पौण्ड सूत की रंगाई की गयी।

## (२) औद्योगिक आस्थान

कानपुर और आगरा के दो बड़े औद्योगिक आस्थानों के अतिरिक्त द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना काल में १३ छोटे औद्योगिक आस्थानों की औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों तथा राज्य के देवबन्द (सहारनपुर), लोनी (मेरठ), काशी विद्यापीठ (वाराणसी), भीमताल (नैनीताल), देहरी (देहरी गढ़वाल), अल्मोड़ा, श्रीनगर और कोटद्वारा (पौड़ी गढ़वाल), झांसी, खलीलाबाद (बस्ती) देवरिया, एटा तथा बिजनौर के सामुदायिक विकास खंडों में स्थापना की स्वीकृति दी गयी थी जिनका निर्माण कार्य कुछ आस्थानों में बहुत आगे बढ़ चुका था। भारत सरकार ने राज्य में सहकारी समितियां तथा निजी लोगों द्वारा औद्योगिक आस्थानों की स्थापना की स्वीकृति दे दी थी। ऐसी सहकारी समितियां जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी थी, कानपुर, लखनऊ, शामली (मुजफ्फरनगर), देहरादून, गाजियाबाद और हावड़ा में एक-एक तथा मेरठ में दो थीं।

## (३) लकड़ी परिपक्व करने के यंत्र

इलाहाबाद तथा बरेली के लकड़ी परिपक्व करने के यंत्रों में क्रम से २,००० घन फुट तथा १,१०० घनफुट लकड़ी परिपक्व की गयी। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद केन्द्र में आलोच्य वर्ष में ४ विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था।

## (४) खेलकूद के सामान के विकास की योजना

आलोच्य वर्ष में २० प्रशिक्षणार्थी भर्ती किये गये और बरेली में राजकीय खेल-कूद सामान योजना के अन्तर्गत उनकी विभिन्न सामानों, जैसे टेनिस, बैडमिन्टन रैकेट, कैरम बोर्ड, हाकी स्टिक, व्यायाम आदि के सामानों आदि के निर्माण की टेक्नीक का प्रशिक्षण दिया गया। इस केन्द्र में ११,०७८ रुपया ५ न० पै० मूल्य के सामान उत्पादित किये गये और १२,१२४ रुपया ८ नये० पै० के सामानों की बिक्री हुई।

फरवरी, १९६० में गठित भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों की खेलकूद सामान निर्माण सहकारी समिति में प्रस्तुत वर्ष कुल ३६ सदस्य थे और हिस्से की पूंजी की रकम १,६५० रुपया थी।

## (५) प्लास्टिक प्रशिक्षण केन्द्र

इटावा के राजकीय प्लास्टिक प्रशिक्षण केन्द्र में १७ विद्यार्थियों को प्लास्टिक के विभिन्न प्रकार के सामानों के निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। प्लास्टिक के सामानों की नयी डिजाइनें बनाने तथा उनके निर्माण और करण में संस्थान की सहायता के लिए जापान के एक प्लास्टिक विशेषज्ञ की सेवा भी एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध की गयी थी।

## (६) ग्रामीण क्षेत्रों में सञ्चल, बड़ईगिरी तथा लोहारगिरी योजना

राज्य के विभिन्न भागों में प्रदर्शन करने के लिए एक-एक सञ्चल बड़ईगिरी तथा लोहारगिरी गाड़ियों की एक घुमन्तू यूनिट तैयार की गयी। इन गाड़ियों ने बिजली चालित मशीनों द्वारा बड़ी संख्या में व्यावहारिक प्रदर्शन किये। इन सञ्चल दलों ने गांव के कारीगरों की छोटी इकाइयों को प्राविधिक जानकारी कराने में बहुमूल्य कार्य किया।

## (७) प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना

(क) पिछड़े क्षेत्र, शैक्षणिक कक्षाओं तथा अतिरिक्त शैक्षणिक कक्षा योजना— १९६०-६१ में प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र जिनकी संख्या २४७ से २४३ के बीच रही, ४ इकाइयों के दल में (जिनमें एक इकाई महिलाओं के लिए सुरक्षित थी) कार्य करती रही और राज्य भर में ५६ विभिन्न शिल्पों में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण देते रहे।

ऐसे सभी झुंडों में ३,१५९ प्रशिक्षणार्थी थे जिनमें १,९६८, सामुदायिक विकास खंडों से आये थे। आलोच्य वर्ष में कुल २,३३८ व्यक्ति प्रशिक्षित किये गये जिनमें से ८६ प्रतिशत रोजगार में लग गये। प्रशिक्षण के दौरान में ६.८७ लाख रुपये कीमत के सामान का उत्पादन हुआ और ६.०३ लाख रुपये मूल्य के सामनों की बिक्री हुई। भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों और कारीगरों की ७५ सहकारी समितियों का गठन किया गया।

अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत ५८० कारीगर नई तकनीक और डिजाइनों बनाने में प्रशिक्षित किये गये। पूरा पाठ्यक्रम सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक तथा आदर्श अभ्यासों के रूप में तोड़ लिया गया था। सामुदायिक विकास क्षेत्रों के ग्रामीण कारीगरों के अल्पकालिक प्रशिक्षण की एक योजना भी परिचालित की गयी। प्रशिक्षणार्थियों के उद्योग के लिए मुख्यालय में १,५७,४०० रुपये मूल्य का कच्चा माल खरीदा गया।

प्रत्येक कमिश्नरी में २ प्रशिक्षण दलों की स्थापना का कार्यक्रम जारी रखा गया। कौन्ही (विलासपुर), औंध (बम्बई) तथा नयी दिल्ली के केन्द्रीय संस्थानों से ६ भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रस्तुत वर्ष ३६ प्रशिक्षकों को पुनर्प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में भेजा गया। ४४ चुने हुए स्थानों पर केन्द्रित सरम्मत की सुविधा प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त अपरेन्टिसशिप के पश्चात् ६ जात के प्रशिक्षण की एक योजना भी सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी। प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार से लगाने में सहयता के लिए वित्तपोषित दरों पर मुधरे उपकरणों की व्यवस्था का कार्य हाथ में लिया गया और उसे अल्पकालिक प्रशिक्षण के साथ संलग्न कर दिया गया।

(ख) सामान्य औद्योगिक प्रसार—नीचे की सतहों से नियोजन के सिद्धान्त आरम्भ किये गये। भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों की औद्योगिक सहकारी समितियां तथा अन्य लोगों की व्यवस्था संबंधी तथा तकनीकी सहयोग देने के लिए सरकार ने एक योजना स्वीकृत की। 'भारत दर्शन' की सी औद्योगिक यात्राओं के कार्यक्रम बनाये गये और भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों तथा कारीगरों का एक दल फरवरी, १९६१ में बाहर भेजा गया। सामुदायिक विकास क्षेत्रों के लिए एक ऐसा विस्तृत प्लान बनाया गया, जिसमें आदर्श योजनाएं थीं। इसी प्रकार सामान्य प्रसार कार्यों पर एक पुस्तिका भी क्षेत्र अधिकारियों के उपयोगार्थ तैयार करायी गयी।

प्रशिक्षणार्थियों, भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों तथा कर्मचारियों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करने के अभिप्राय से प्रोत्साहन पुरस्कारों का एक संशुद्ध तरीका आरम्भ किया गया। अधिकारियों के एक दल को पंजाब राज्य में औद्योगिक प्रसार कार्य के तुलनात्मक अध्ययन के लिए भेजा गया।

कुछ अन्य योजनाओं के अन्तर्गत कार्यों का विवरण भी आगे दिया जा रहा है जो प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत थीं।

राजकीय खिलौना विकास केन्द्र, बरेली—इस योजना के अन्तर्गत ११ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया। यहाँ २,६८६.५५ रुपये मूल्य के सामान तैयार किये गये और १६६०-६१ वर्षावधि में १,६५३.१७ रुपये मूल्य के सामानों की बिक्री हुई।

राजकीय सिलाई केन्द्र, डालीगंज, तखनऊ—प्रशिक्षण के लिए कुल ११३ व्यक्ति भर्ती थे जिनमें प्रस्तुत वर्ष ५० व्यक्तियों का प्रशिक्षण पूरा हुआ। यहाँ ६,६४४.२६ रुपये मूल्य के सामान तैयार हुए और १०,६४१.१० रुपये मूल्य के सामानों की बिक्री हुई।

राजकीय खेलकूद सामान निर्माण केन्द्र, नैनीताल—आलोच्य वर्ष में इस केन्द्र में ८ व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। इस केन्द्र में इस अवधि में १८१३.३७ रुपये मूल्य के सामानों का उत्पादन हुआ और १४२३.४४ रुपये मूल्य के सामान बिके।

(८) औद्योगिक, अग्रगामी परियोजना, देवबन्द—देवबन्द औद्योगिक अग्रगामी परियोजना का कार्य उसके १६ केन्द्रों सहित संतोषजनक ढंग से चल रहा था। वहाँ २८३ प्रशिक्षणार्थी विभिन्न शिल्पों एवं धंधों, जैसे लुहारगिरी, फलसंरक्षण, कांच की गुरिया, गंजी, बनियाइन तथा भोजे, साबुन, सिलाई, बड़ईगिरी, खिलौने तथा गुड़िया बनाना, कपड़े की छपाई, चमड़े के जूते बनाने आदि का प्रशिक्षण पा रहे थे। प्रस्तुत वर्ष ७१,२५५ रु० के मूल्य के सामान तैयार हुए और ६८० व्यक्तियों को रोजगार मिला। प्रशिक्षणार्थियों में अधिकांश धंधे में स्वतंत्र रूप से ले लिए गये। शेष लोगों को निजी वर्कशापों में नौकरी मिल गयी। नागल की बहुदेशीय इकाई जिसके लिए नये भवन का निर्माण हुआ था, संतोषजनक ढंग से प्रगति कर रही थी। केन्द्र में टाइल जूता निर्माण केन्द्र में १३ प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण ले रहे थे और इसमें १३,४७० रुपये मूल्य का सामान तैयार हुआ और १०,४०४ रुपये मूल्य के सामान बिके। ६३० व्यक्तियों को अम्बर चर्खा पर कताई का प्रशिक्षण दिया गया। इस क्रम में उनमें से प्रत्येक को लगभग २ रुपया प्रतिदिन की आय थी। तेल पेरने, फाइवर उद्योग, आटा चक्की, गुड़ एवं खांडसारी, हाथ से बना कागज, बर्तन आदि जैसे कुटीर उद्योगों की इस अवधि में अच्छी प्रगति हुई।

६ हथकरघा सहाकारी समितियाँ, जिनकी सदस्य संख्या ४७३ और हिस्से की पूंजी की रकम ६,२७१ रुपया थी, संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही थीं। इन समितियों ने इस अवधि में १२,०४,४२३ रुपये मूल्य के ७,२३,५६६ गज कपड़े बुने और १२,६४,२४० रुपये मूल्य के ७,२०,३२८ गज कपड़ों की बिक्री हुई। इसके अतिरिक्त २४ वस्त्रोत्तर समितियाँ जिनकी सदस्य संख्या ५३७, हिस्से की पूंजी १६,६७६ रुपये तथा कारोबारी पूंजी ६०,०३२ रुपये थी, प्रस्तुत वर्ष कार्य कर रही हैं।

आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के अभिप्राय से ४६ पाठियों को ५०,००० रुपये के ऋण तथा १६ व्यक्तियों को ५,००० रुपये के अनुदान दिये गये।

### (९) अग्रगामी वर्कशाप योजना

प्रस्तुत वर्ष पाँचों अग्रगामी वर्कशाप केन्द्रों में संतोषजनक प्रगति रही। उनमें मोटर मैकेनिक, विजली टनिंग, भूशोनमैन, फिटिंग, बड़ईगिरी, नक्काशी, मोल्डिंग तथा लुहारगिरी के कामों जैसे विभिन्न धंधों में प्रशिक्षण दिया गया।

### (१०) चमड़े की अग्रगामी परियोजनाएं—

चमड़े (जूते, चप्पल) की अग्रगामी परियोजना के अन्तर्गत चल रहे आगरा के केन्द्र में, सभी आवश्यक जशीने तथा कर्त, जो जूते बनाने के कार्य में, प्रशिक्षण के इच्छुक व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त थी, मौजूद थी। कुटीर कारीगर को इस केन्द्र द्वारा क्रय-विक्रय की सुविधा दी गयी और तकनीकी परामर्श भी दिया गया। आलोच्य वर्ष में १६८ उत्पादकों की सहायता की

गयी। इसके अतिरिक्त कुटीर कारीगरों को लागत मूल्य पर कच्चा माल तथा स्टैंडर्ड सामान देने का प्रबन्ध भी किया गया। अच्छे स्टैंडर्ड सांचे भी जूते के निर्माण के लिए प्रचलित किये गये और लगभग ६०,००० जोड़े लकड़ी के सांचे भी इस ध्येय में लम्बे लोगों को दिये गये। ६४३ कुटीर एवं लघु उद्योगों के निर्माताओं को सामान की सुविधाएं भी प्रदान की गयीं। वर्ष के अन्त में १० प्रशिक्षणार्थी जूते बनाने के आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण ले रहे थे। आलोच्य वर्ष के अन्त तक कुल १७० व्यक्तियों को प्रशिक्षण मिल चुका था। सरम्भत शुल्क के रूप में अर्जित २६,१६८ रुपये सरकारी खजाने में जमा किये गये।

चमड़े की अग्रगामी परियोजना, बस्ती—यह योजना १९५६-६० में आगरा जूता निर्माण परियोजना के ढंग पर प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र की स्थापना के उद्देश्य से आरम्भ की गयी थी। इस परियोजना में छोटी मशीनों की सहायता से जूता बनाने के कार्य में प्रति वर्ष २० व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था थी।

### (११) कांच की गुड़ियों के निर्माण का प्रशिक्षण केन्द्र

वाराणसी तथा पुर्विलपुर (अलीगढ़) में स्थित दो राजकीय कांच की गुड़िया के निर्माण के प्रशिक्षण केन्द्रों में कांच की सजावट के काम की छोटी गुड़ियां, नेकलेस तथा कांच के खिलौने के निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाता रहा। इन संस्थाओं में प्रस्तुत वर्ष १४ विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

### (१२) मिट्टी के बर्तन की निर्माण योजनाएं

(क) राजकीय मिट्टी बर्तन विकास केन्द्र, खुर्जा—जिला बुलन्दशहर में खुर्जा में १९४२ में स्थापित राजकीय मिट्टी बर्तन विकास केन्द्र की संतोषजनक प्रगति होती रही। इस केन्द्र से १०० बर्तन बनाने वाले संलग्न थे। उन्होंने आलोच्य वर्ष में बर्तन, काकरी, फूलदान, इनतुलेटर आदि के निर्माण के लिए २.२३ लाख रुपये मूल्य का कच्चा माल खरीदा। इसी अवधि में ३० प्रशिक्षणार्थियों को बर्तन निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया।

(ख) मिट्टी बर्तन केन्द्र, चुनार—चुनार (जिला मिर्जापुर) के मिट्टी बर्तन केन्द्र का कार्य भी संतोषजनक रहा। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले ६ परिवारों ने बर्तन तथा प्रोतिलेन के खिलौने बनाने के लिए १५,००० रुपये मूल्य का कच्चा माल खरीदा। इस केन्द्र के भवन-निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया और भवन-निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया गया था। १० फुट व्यास की दो भट्टियां और एक चिमनी का निर्माण पूरा हो गया था। अतिरिक्त संरक्षण मशीन जिनका मूल्य २८,००० रुपया था आलोच्य वर्ष प्राप्त हुई।

### (१३) अग्रगामी सैण्ड वाशिंग एवं सर्विस लेबोरेटरी

शंकरगढ़ (इलाहाबाद) के राजकीय अग्रगामी सैण्ड वाशिंग प्लान्ट एवं सर्विस लेबोरेटरी में आलोच्य वर्ष में सिलिका बालू के १०२ सैम्पलों का विश्लेषण किया। सैण्ड वाशिंग प्लान्ट में कई सैम्पल के ५,८६० मीट्रिक टन बालू की धुलाई की गयी।

### (१४) कांच के सामान के निर्माण का प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र

फिरोजाबाद (आगरा) के राजकीय गैस प्लान्ट-कम-साइन्ड्रिकल टेबल ब्लोइंग ट्रेनिंग कम-प्रोडक्शन सेंटर में आरम्भ में ६० व्यक्तियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध की गयीं। १५ चूड़ी बनाने वाली तथा अन्य कामगारों ने केन्द्र में अपना नाम लिखाया और उपलब्ध सुविधाओं से लाभ उठा रहे थे। गैस प्लान्ट के साथ संलग्न वैज्ञानिक कांच सामान निर्माण, प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, में टेस्ट ट्यूब, पिपेट आदि जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाता था। आलोच्य वर्ष में इस केन्द्र में ५ प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षित किये गये।



### (१५) खनिज-पदार्थों के परिक्षणार्थ अग्रगामी कार्य

कागपुर टेक्नालाजिस्ट लेबोरेटरीज में खनिज पदार्थों के परीक्षण के लिए अग्रगामी यंत्र योजना १९६०-६१ में कार्यान्वित की गयी जिससे उत्तर प्रदेश भूतत्सव एवं खदान निदेशालय द्वारा खोज से प्राप्त खनिज पदार्थों का परीक्षण किया जा सके और उनके उपयोग का पता लगाया जा सके। १,५०० रुपये मूल्य के रासायनिक पदार्थ तथा आवश्यक उपकरण और ६,८२० रु० मूल्य की विजली द्वारा चालित भट्टी आलोच्य वर्ग में खरीदी गयी।

### (१६) कटलरी योजना

३१ मार्च, १९६१ से शेरठ और हाथरस में परिचालित कटलरी योजना के १० वर्ष पूरे हुए। इसमें स्थानीय तथा बाहर की बड़ी-छोटी इंजीनियरिंग इकाइयों की मरम्मत आदि की सुविधा प्राप्त थी और हाथरस के केंद्र ने हाथरस के छरी निर्मातार्यों की भी सहायता की।

कैंचियों, अस्तुरे, लेखन सामग्री तथा फल तराशने के चाकुओं तथा अन्य संबद्ध वस्तुओं का भी निर्माण कराया गया और उन्हें राज्य सरकार तथा अन्य सरकारी विभागों के आर्डर के अनुसार सप्लाई किया गया। प्रस्तुत वर्ष दफ्तर तथा कारखाने की इमारत का निर्माण पूरा हुआ। इस वर्ष २४,३१३.६९ रुपये मूल्य के सामान बनाये गये और २१,७६१.५६ रुपये मूल्य के सामानों की बिक्री हुई।

### (१७) लोहेतर आलु योजना

मुरादाबाद के प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र में डलाई, टर्निंग, शोपिंग, खुदाई, पक्की कलाई कार्य आदि का प्रशिक्षण ३२ प्रशिक्षणार्थी ले रहे थे। प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति भी दी जाती थी। आलोच्य वर्ष में २२ प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षित किये गये। इस केंद्र द्वारा ०.३३ लाख रुपये मूल्य के सामान तैयार किये गये जिनमें से अधिकांश के लिए पहले से आर्डर प्राप्त हुए थे।

### (१८) ऋण एवं अनुदान योजना

ऋण एवं अनुदान योजना के अन्तर्गत तीन विभिन्न माध्यम द्वारा ऋण दिये जाते रहे। परियोजनाओं के लिए १०,००० रुपयों से कम रकम के ऋण की स्वीकृति जिला उद्योग समिति देती थी। १५,००० रुपया तक की रकम के ऋण की स्वीकृति पर राज्य ऋण एवं अनुदान समिति विचार करती थी और १५,००० रुपयों से अधिक लेकिन १,००,००० रुपये तक के ऋण के मामलों पर उत्तर प्रदेशीय वित्त निगम विचार करता था। पूर्वी, पहाड़ी तथा बुन्देलखंड जिलों के पिछड़े क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्रों के विकास की विशेष योजना के अन्तर्गत भी ऋण दिये गये। प्रस्तुत वर्ष क्रम से ५१,७०,२०० रुपये तथा १,१६,९८० रुपये ऋण तथा अनुदान के रूप में वितरित किये गये। पिछड़े क्षेत्रों की विशेष योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत वर्ष २१,६४,००० रुपयों के ऋण दिये गये। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश वित्त निगम के पास २५ लाख रुपये रख दिये गये थे।

### (१९) गुणचिह्नांकन योजना

प्रस्तुत वर्ष गुण चिह्नांकन योजना के अन्तर्गत ३ नये गुण चिह्नांकन केंद्र चिकन (लखनऊ), धातु के कलात्मक सामान (मुरादाबाद) तथा दरी (आगरा) के लिए खोले गए। इसके अतिरिक्त १९ निरीक्षण डियो पहले से कार्य कर रहे थे। स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना को प्रश्रय देने के अभिप्राय से विभिन्न सामानों के उन निर्मातार्यों को जिनके सामान वर्ष में सबसे अच्छे होते थे, तमगा तथा प्रमाण-पत्र दिये गये। इस योजना के अन्तर्गत चल रहे २२ निरीक्षा डियो संतोषजनक ढंग से कार्य करते रहे। इस अवधि में कुल १,६०,३१,९४६.७७ रुपये मूल्य के सामानों पर गुणचिह्नांकन किया गया।

## (२०) आदर्श तार की जाली का उद्योग, वाराणसी

वाराणसी में आदर्श तार की जाली के उद्योग के लिए उपयुक्त भूमि का अधिग्रहण किया गया और भवनों के निर्माण के लिए विभाग द्वारा अनुमान तैयार किये गये।

## (२१) गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्रैफ्ट्स

गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्रैफ्ट्स द्वारा दस्तकारी के सामानों की देश तथा विदेश में बिक्री की सुविधा दी जाती रही। १९६०-६१ में इस पूरे संगठन द्वारा १३, ३१,६४६ रुपया मूल्य के सामानों की बिक्री हुई। १०० डिजाइनों के निर्धारित लक्ष्य के स्थान पर १५० नयी डिजाइनें निकाली गयीं। इसके अतिरिक्त ५५,००० रुपया मूल्य के सामानों का निर्यात किया गया।

गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्रैफ्ट्स ने वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, झांसी तथा अलीगढ़ में आयोजित प्रदर्शनियों में भाग लिया। १९६० में ५ से १२ दिसम्बर तक इस संगठन के सभी प्रदर्शन कक्षों में छठा अखिल भारतीय हैन्डीक्रैफ्ट्स सप्ताह मनाया गया। अमौसी, सारनाथ तथा मंसूरी के प्रदर्शन कक्षों में आलोच्य वर्ष २५,३५५.३४ रुपये मूल्य के सामान बिके।

## (२२) सुगंधित तेल योजना

सुगंधित तेल योजना के अन्तर्गत गाजीपुर, सिकन्दरपुर (बलिया) तथा सिकन्दराराव (अलीगढ़) में तीन केन्द्र कार्य कर रहे थे। सुधरे भंभको तथा अन्य संबद्ध उपकरणों की कार्य-विधि का स्थानीय गंधियों, विद्यार्थियों तथा दिलचस्पी रखने वाले अन्य व्यक्तियों के समक्ष प्रदर्शन किया गया। सुगंधित तेलों तथा अन्य संबद्ध उत्पादनों के निर्माण की तकनीक एवं अन्य विवरणों का इन तीनों केन्द्रों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। सिकन्दराराव, सिकन्दरपुर तथा गाजीपुर केन्द्रों में क्रम से २, ३, तथा ४ अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए भर्ती किया गया। दो प्रशिक्षणार्थियों को २५ रुपया प्रति मास की छात्रवृत्ति दी गयी।

## (३) रेशम तथा अंडी कीट पालन

(१) रेशम के कीट पालने की योजना—रेशम के कीड़े पालने की योजना के अन्तर्गत राज्य के छः जिलों—देहरादून, सहारनपुर, पौड़ीगढ़वाल, नैनीताल, इटावा और गोरखपुर—में कार्य किया गया। वर्ष के उत्तरार्ध में देहरी गढ़वाल तथा अल्मोड़ा जिले भी इस योजना के अन्तर्गत ले लिये गये।

इस अवधि में ६०,५८० पौण्ड ककून का उत्पादन हुआ और १,९७,९९६ रोग मुक्त अंडे थे। राज्य के विभिन्न रेशमकीट पालन केन्द्रों में ६१ ग्रामीण बालकों को इस उद्योग के विभिन्न तकनीकों का २ मास का प्रशिक्षण दिया गया। ८ सदस्यों को उच्च प्रशिक्षण के लिए मंसूर अखिल भारतीय रेशमकीट पालन प्रशिक्षण संस्थान में भेजा गया। राज्य में १४ और प्रारम्भिक कीट पालन सहकारी समितियों का पंजीकरण किया गया जिनको लेकर कुल २२ पंजीकृत सहकारी समितियां हो गयीं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय समिति या संघ भी था। रेशम कीटों की जातियों में सुधार करने, रेशम कीट के पालने के तरीकों तथा शहतूत के काशत के संबंध में अनुसंधान कार्य केन्द्रीय रेशम, फार्म प्रेमनगर में जारी रखा गया।

(२) अंडी रेशम कीट पालन योजना—अंडी रेशम कीट पालन योजना के, जो १९५५-५६ में सुआर (रामपुर) और तमकुही (देवरिया) में आरम्भ की गयी थी, कार्यक्रम में इन जिलों के और बहुत से गांवों को भी सम्मिलित कर लिया गया और ८२५ कीट पालक परिवार उसमें भाग ले रहे थे। कुल मिला कर इस वर्ष ३,१८६ पौण्ड ककून का उत्पादन हुआ। १० व्यक्तियों को अंडे के काशत करने, रेशम कीट पालन तथा कताई का तीन महीने का प्रशिक्षण दिया गया। आसाम के तीलाबार स्थान में स्थित रेशम कीट पालन संस्थान में उच्च प्रशिक्षण के लिए २ कर्मचारियों को भेजा गया।

अंडी सिल्क की सूत कटाई का काम पारिश्रमिक के आधार पर लिया गया और इस प्रकार १८० पौंड सूत काटा गया। सूत को वस्त्र के रूप में बदलने के प्रयास पर जोर दिया गया और आलोच्य वर्ष में ११७.८३ मीटर कपड़ा तैयार हुआ।

#### (४) दस्तकारी की योजनाएं

(१) केन्द्रीय डिजाइन केन्द्र, लखनऊ—लखनऊ के केन्द्रीय डिजाइन केन्द्र में २० ग्रेजुएट्स को प्रशिक्षण देने का कार्य जारी रहा और यहां ६६३ नयी डिजाइनें निकाली गयीं। फरवरी, १९६१ में लखनऊ में नयी डिजाइनों की एक प्रदर्शनी आयोजित की गयी जिसमें बड़ी संख्या में दर्शक और कारीगर आये।

(२) हस्तशिल्प संग्रहालय लखनऊ—विभिन्न दस्तकारियों के अपने दुष्प्राप्य संग्रहों सहित लखनऊ का हस्तशिल्प संग्रहालय कारीगरों तथा दर्शकों के लिए पर्याप्त शैक्षिक महत्व बना रहा। देश के विभिन्न भागों तथा विदेशों से महत्वपूर्ण व्यक्ति इस संग्रहालय में आये।

सचल गाड़ियों द्वारा दस्तकारियों तथा हथकरघा से बने कपड़ों आदि का विस्तृत प्रचार होता रहा। १२ शिल्पकारों को सरकारी खर्च से भारत के विभिन्न हस्तशिल्प केन्द्रों को देखने के लिए भेजा गया। इसके अतिरिक्त आलोच्य वर्ष में २० दस्तकारी सहकारी समितियों को ऋण तथा अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता दी गयी।

चिकन कढ़ाई की योजना संतोषजनक रूप से चलती रही और प्रस्तुत वर्ष १०० नयी डिजाइनें निकाली गयीं। ६४,६३८ रुपये पारिश्रमिक के रूप में बांटे गये। प्रस्तुत वर्ष २,७३,२७७ रुपये मूल्य का सामान तैयार हुआ और २,४४,६०७ रुपये मूल्य के सामान की बिक्री हुई।

मिर्जापुर तथा भदोही ऊनी कालीन के विकास की योजना द्वारा स्थानीय कालीन उद्योग को सहायता मिलती रही। ७ कालीन सहकारी समितियां जिनको सदस्य संख्या ५५१ थी, शीर्ष समिति के साथ संबद्ध कर दी गयीं। रंगाई गृहों की स्थापना के लिए सहकारी समितियों को ३०,००० रुपये ऋण के रूप में दिये गये। इसके अतिरिक्त आलोच्य वर्ष में १,४१,८२७ रुपये अनुदान के रूप में वितरित किये गये।

(३) सींग उद्योग, संभल—संभल (मुरादाबाद) स्थित सीमा उद्योग केन्द्र, सामान्य सुविधा केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा था। इस केन्द्र में आलोच्य वर्ष ४,१०६.३२ रुपये मूल्य का सामान तैयार हुआ और ३,६५३.२८ रुपये मूल्य के सामान बिके।

(४) लैकर (पीतल पर सुनहरी वार्निश) उद्योग, अमरोहा—अमरोहा (मुरादाबाद) स्थित लैकर उद्योग को एक सामान्य सुविधा केन्द्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। इस वर्ष इस केन्द्र में ३,२२४.२४ रुपये मूल्य के सामान तैयार किये गये और २,८६६.७८ रुपये मूल्य के सामानों की बिक्री हुई।

(५) तारकशी उद्योग, मैनपुरी—तारकशी उद्योग के संबंध में ५ प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था और १५ अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण समाप्त कर लिया था। प्रस्तुत वर्ष प्रशिक्षार्थियों ने ६८३.६६ रुपये मूल्य का सामान तैयार किया और इस अवधि में ३६३.५२ रुपये मूल्य के सामान बिके।

(६) बेंत और बांस उद्योग, बहराइच—बहराइच स्थित बेंत और बांस उद्योग में, जिसे एक सामान्य सुविधा केन्द्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था, १,६१०.६८ रुपये मूल्य के सामान तैयार किये गये और १,७१०.२३ रुपये मूल्य के सामान की बिक्री हुई।

(७) बेंत और बांस उद्योग, गोरखपुर--गोरखपुर के बेंत और बांस उद्योग पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा। वहां १६ प्रशिक्षणार्थियों ने प्रस्तुत वर्ष प्रशिक्षण पूरा किया और ११ प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण ले रहे थे।

(८) वाराणसी के लकड़ी के खिलौने उद्योग का विकास--वाराणसी का लकड़ी का खिलौना उद्योग केन्द्र सामान्य सुविधा केन्द्र के रूप में कार्य करता रहा।

(९) वाराणसी के हाथीदांत उद्योग का विकास--वाराणसी में हाथीदांत उद्योग के विकास के संबंध में ५ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। १२ प्रशिक्षणार्थियों ने अपना प्रशिक्षण समाप्त कर लिया था। आलोच्य वर्ष में २,९८६.७२ रुपये मूल्य के सामानों का उत्पादन हुआ और २,७१८.६७ रुपये मूल्य के सामानों की बिक्री हुई।

(१०) खुरा का पारंपरिक चीनी-मिट्टी बर्तन उद्योग--खुरा स्थित पारंपरिक चीनी-मिट्टी बर्तन केन्द्र में ६ प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण समाप्त किया और वर्ष के अन्त में ६ प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण ले रहे थे।

(११) सूती वस्त्रों की छपाई तथा रंगाई, देवबन्द--देवबन्द में कलात्मक १० प्रशिक्षणार्थी सूती वस्त्रों की छपाई तथा रंगाई का प्रशिक्षण लेते रहे। इसके अतिरिक्त आलोच्य वर्ष में ६३ प्रशिक्षणार्थियों ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया। प्रस्तुत वर्ष में ५,८७२.८४ रुपये मूल्य के सामानों का उत्पादन किया गया और ४,६०७.४८ रुपये के सामानों की बिक्री हुई।

(१२) कलात्मक दरियों की बुनाई, देवबन्द--देवबन्द में कलात्मक सूती दरियों की बुनाई का प्रशिक्षण ५ प्रशिक्षणार्थियों को दिया जाता रहा। १२ प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया था। आलोच्य वर्ष में ११,३६५.९६ रुपये का सामान उत्पादन किया गया और ३,५८५.४२ रुपये मूल्य के सामान की बिक्री हुई।

(१३) गुड़िया तथा लकड़ी के खिलौने, देवबन्द--गुड़ियों तथा लकड़ी के खिलौने की योजना के अन्तर्गत देवबन्द में १७ व्यक्ति, आलोच्य वर्ष के अन्त में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। प्रस्तुत वर्ष २२ प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण समाप्त किया। ३,६९४.७४ रुपये मूल्य का सामान का उत्पादन किया गया और ३,५०७.६७ रुपये मूल्य की बिक्री हुई।

(१४) आबनूस उद्योग, नगीना--नगीना के आबनूस उद्योग में आलोच्य वर्ष के अन्त में सात व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। ९ प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया था। इस वर्ष १,९९४.६९ रुपये मूल्य के सामान तैयार हुए और २१२.४६ रुपये के सामान बिके।

## (५) ग्रामोद्योग योजनाएं

(१) पारंपरिक खादी विकास योजना--पारंपरिक खादी विकास योजना के अन्तर्गत कार्य प्रायः राज्य के पूर्वी भाग में स्थित २३ जिलों तक ही सीमित रहे। कुल ५२ कताई केन्द्र तथा ८ खादी बुनाई कक्षाएं कार्य कर रही थीं।

आलोच्य वर्ष में ८,००० कतुओं के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध ९,४९२ कतुओं को धुनाई तथा कताई का प्रशिक्षण दिया गया। इसी प्रकार ८० बुनकरों के प्रशिक्षण के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध ४३ बुनकर प्रशिक्षित किये जा चुके थे और ६५ प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण पा रहे थे। प्रस्तुत वर्ष ४१२९ मन सूत तैयार किया गया। इस अवधि में ४,५०,३५० रुपये सहायता अनुदान के रूप में वितरित किये गये।

(२) अम्बर चर्खा योजना--अम्बर चर्खा योजना के अन्तर्गत गोंडा, इलाहाबाद, आजमगढ़, देवरिया, बलिया, तथा सीतापुर के ६ प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्रों में एक साथ ही

प्रशिक्षण और उत्पादन आरम्भ किया गया। इन केन्द्रों पर १,८१४ कतुओं तथा १५५ बुनकरों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और ५,१६,००० रुपये मूल्य के कुल ३,२६,४१७ गज कपड़े बुने गये।

(३) पर्वतीय ऊन योजना—आलोच्य वर्ष में उत्तराखंड कमिश्नरी में पर्वतीय ऊन योजना के अन्तर्गत ८ प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, ७ बुनाई एवं रंगाई केन्द्र तथा १०० कताई केन्द्र कार्य कर रहे थे। २०० बुनकर वर्ष के अन्त में प्रशिक्षण ले रहे थे। जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका था उनमें ३१,५३३ कतुए तथा १४५ बुनकर थे। ४,४१,४५६.५८ रुपये मूल्य का कपड़ा तैयार हुआ तथा ३,४८,३६६.६२ रुपये कीमत के वस्त्र बिके। इसके अतिरिक्त ३६२ डिजाइनें निकाली गयीं। खादी परिषद् तथा श्री गांधी आश्रम को क्रमशः ६२,२६८.८४ रुपये तथा ६२,५४३.६८ रुपये मूल्य के ऊनी कपड़े सप्लाई किये गये।

(४) भारत-तिब्बत सीमा क्षेत्र-योजना—पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तरकाशी में सीमा क्षेत्र ऊन योजना परिचालित थी। इसके अन्तर्गत ७ ऊन प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र तथा २८ कताई केन्द्र थे। प्रस्तुत वर्ष में ३,८४३ कतुए तथा ७० बुनकरों को प्रशिक्षण दिया गया। ६० बुनकर प्रशिक्षण पा रहे थे। २,०३,०८७.२५ रुपये मूल्य के ऊनी कपड़े उत्पादित किये गये और १,३१,१६६.४४ रुपये मूल्य के कपड़े बिके। इसके अतिरिक्त २२६ डिजाइन निकाली गयीं और सीमांत क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में ५ जल चखें भी लगाये गये।

(५) बैरक कम्बल योजना—बैरक कम्बल योजना के अन्तर्गत तजीबाबाद, सुजफ्फर-नगर तथा मिर्जापुर के कारखानों में जिनमें से प्रत्येक के साथ दस कताई केन्द्र थे, ६१,१६४ कम्बल तैयार हुए। लगभग ६,००० कतुओं, २०० बुनकर परिवारों तथा २०० कुशल, अकुशल कर्मचारियों को आलोच्य वर्ष में पूरे समय का रोजगार मिला।

(६) कुटीर चर्मशोधन—उद्योग विभाग के अन्तर्गत गठित कुटीर चर्मशोधकों की सहकारी समितियों का कार्य संतोषजनक रहा और उन्होंने ३७.६४ लाख रुपये मूल्य के चमड़े का सामान तैयार किया और उसकी बिक्री की। चर्मशोधकों की औसत रोजाना आमदनी ३ रुपये थी, किन्तु सुधरी कार्यविधि के प्रचलन के फलस्वरूप अच्छे किस्म के चमड़े के उत्पादन में सुविधा के कारण कुछ चर्मशोधकों की दैनिक आय ५ रुपये तक हुई।

(७). गुड़ विकास योजना—गुड़-विकास योजना राज्य के ३७ जिलों के ५,२४५ गांवों में कार्यान्वित हो रही थी। इनमें से ७१ गांव उद्योग के आदर्श गांवों के रूप में चुने गये। १५७ गन्ना उत्पादकों को गुड़ तथा खांडसारी के उत्पादन के सुधरे तरीकों का प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण रामपुर, लखनऊ तथा वाराणसी में गठित केन्द्रों में दिया गया। गुड़ तथा खांडसारी सहकारी समितियों को सुधरे उपकरणों, साफ सुथरी भट्टियों, गुड़ की बिक्री के लिए, रिक्शों की खरीद के लिए १,२२,३०० रुपये ऋण के रूप में तथा २४,७०० रुपये अनुदान के रूप में वितरित किये गये। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत गन्ना उत्पादकों को कोल्हू और कढ़ाव खरीदने के लिए ३.०४ लाख रुपये तकावी ऋण के रूप में वितरित किये गये। राज्य भर में ६४७ कोल्हू और ३८८ कढ़ाव वितरित किये गये।

पूर्वी जिलों के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक योजना गुड़-विकास योजना के अन्तर्गत परिचालित की गयी तथा १,११६ कोल्हू और १५५ कढ़ाव ४.७३ लाख रुपये लागत के पूर्वी जिलों में वितरित किये गये। इसके अतिरिक्त ५,०३५ भंडियों का निर्माण किया गया और ५,८१,६६७ मन उन्नत गुड़ और ५०,६१३ मन खांडसारी शक्कर का उत्पादन किया गया। विभाग ने २३ गुड़ और खांडसारी सहकारी समितियों का गठन किया गया, २,२८७ सदस्य बनाये और हिस्से की पूंजी के रूप में ७५,५३३.८७ रुपये एकत्र किये। कुल मिला कर ८०,८०३ मन उन्नत गुड़ और ११,०२० मन खांडसारी शक्कर सहकारी समितियों तथा उनके सदस्यों द्वारा उत्पादित की गयी।

(८) ताड़-गुड़ योजना—ताड़-गुड़ उत्पादन राज्य के १५ जिलों में स्थित ६४ केंद्रों में किया गया। इन केंद्रों में उत्पादन का विवरण तथा उत्पादित गुड़ के मूल्य का विवरण नीचे दिया जा रहा है—

			मूल्य रुपया
(१)	नीरा ८,६८,००० गैलन	..	१,२८,६४५
(२)	ताड़-गुड़ ५,१३८ मन	..	१,०३,७६०
(३)	शक्कर १६३ मन	..	६,६३०
(४)	ताड़-गुड़ की भेली ६ मन	..	४८०
(५)	ताड़-गुड़ की मिठाइयां १,२२५ पौण्ड	..	२,१७४
(६)	ताड़ की पत्ती तथा रेशे के सामान	..	२१,४२,७५०

(९) ताड़-गुड़ सहकारी समितियाँ—२ ताड़-गुड़ सहकारी समितियों का गठन हुआ जिनको लेकर ऐसी समितियों की संख्या २२ हो गयी। उत्तर प्रदेश राज्य ताड़-गुड़ सहकारी संघ लिमिटेड, कानपुर सभी ताड़-गुड़ समितियों की शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता रहा। विभिन्न केंद्रों में २०० प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त १७ प्रशिक्षणार्थी पुनःप्रशिक्षण के लिए दहानू भेजे गये।

(१०) हाथ के बने कागज का केंद्र, कालपी—हाथ से बने कागज की योजना संतोषजनक प्रगति करती रही और उसे सरकार तथा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग से सहायता मिलती रही। कालपी के हाथ से बने कागज के केंद्र में स्थानीय रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा था। केंद्र से ४ स्नातक हाथ से बने कागज के निर्माण के उच्च प्रशिक्षण के लिए पूना भेजे गये। २.१० लाख रु० मूल्य की लुगदी का उत्पादन हुआ। इस उद्योग का क्रमिक प्रसार कालपी से कड़ा (इलाहाबाद), गरम पानी (नैनीताल), कालपी (बेहराइन), पोखरायां (कानपुर), रामपुर तथा लखनऊ में हो गया।

(११) दुनियादी ग्रामोद्योग—निम्नलिखित ग्रामोद्योग को सहकारी समितियों, पंजीकृत संस्थाओं तथा पब्लिक ट्रस्टों द्वारा सहायता प्राप्त हुई :—

- (१) ग्रामीण तेल
- (२) धान की हाथ से कुटाई तथा आटा चक्की
- (३) साबुन निर्माण तथा अखाद्य तैल
- (४) ग्रामीण मिट्टी के बर्तन
- (५) ग्रामीण चमड़ा
- (६) हाथ का बना कागज
- (७) गुड़ और खांडसारी
- (८) ताड़-गुड़
- (९) लोहारगिरी तथा बढ़ईगिरी
- (१०) कुटीर दियासलाई
- (११) रेशा

आलोच्य वर्ष में विभिन्न खादी एवं ग्रामोद्योगों की २२८ सहकारी समितियाँ गठित एवं पंजीकृत की गयीं जिनको लेकर ग्रामोद्योग सहकारी समितियों की कुल संख्या १,६३६ हो गयी। इन सहकारी समितियों, पंजीकृत संस्थाओं, तथा पब्लिक ट्रस्टों को, जो राज्य में ग्रामोद्योग के विकास कार्य में लगे हुए थे, ऋण तथा अनुदान के रूप में देने के लिए कम से ८,४०,४८७.५० रुपये तथा ५,३७,२५७.८६ रुपये निर्धारित किये गये थे।

इस वर्ष की महत्वपूर्ण घटना उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् की स्थापना की थी, जिसने १५ नवम्बर, १९६० में मुख्य मंत्री द्वारा विधिवत् उद्घाटन के पश्चात् कार्य करना आरम्भ कर दिया।

(१२) औद्योगिक सहकारी योजनाएं—आलोच्य वर्ष में ३४५ औद्योगिक सहकारी समितियां गठित एवं पंजीकृत की गयीं जिनको लेकर कुल औद्योगिक सहकारी समितियों की संख्या ३,३६३ हो गयी। विभिन्न अखिल भारतीय परिषदों आदि के अन्तर्गत गठित सहकारी समितियों का विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

(१) अखिल भारतीय हथकरघा परिषद्	..	१,२५६
(२) अखिल भारतीय ग्राम एवं खादी आयोग	..	१,६३६
(३) अखिल भारतीय हैंडलक्राफ्ट बोर्ड	..	१७४
(४) प्रकीर्ण	.. ..	३२१
	योग ..	३,३६३

औद्योगिक सहकारी समितियों की कुल संख्या १,५२,१३५ थी। उनकी चुकता हिस्से की पूंजी ६६.३८ लाख रुपये थी तथा सुरक्षित और अन्य निधियों की रकम ४६.३७ लाख रुपये और कारोबारी पूंजी ४६२.७० लाख रुपये थी।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी बैंक लि० द्वारा प्रस्तुत वर्ष में ४.६८ लाख रुपये वितरित किये गये। इस वर्ष बैंक को २.५६ लाख रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ। उत्तर प्रदेश औद्योगिक संघ लिमिटेड ने, जो क्रय-विक्रय के शीर्ष संगठन के रूप में कार्य कर रहा था, १९५८-५९ सहकारिता वर्ष की अवधि में ४५.४७ लाख रुपये के सामान की बिक्री की। इसके अतिरिक्त इटावा की प्रस्तावित बुनाई मिल द्वारा ३० जून, १९६० तक ४०.३६ लाख रुपये चुकता पूंजी के रूप में उगाहा गया।

१९६०-६१ वित्तीय वर्ष की अवधि में वर्कशापों के निर्माण के लिए औद्योगिक सहकारियों को अनुदान के रूप में १ लाख रुपये वितरित किये गये। इसके अतिरिक्त वस्त्रोत्तर समितियों को सुधरे उपकरणों के लिए अनुदान के रूप में १०,००० रुपये दिये गये।

(६) अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं तथा कार्य

(१) उद्योगों को सहायता—उद्योग विभाग ने लघु उद्योगों की, नियंत्रित वस्तुओं का कोटा नियत कर, सहायता करना जारी रखा।

कोयला

आलोच्य वर्ष में ३०,०४४ बैगन कोयला विभिन्न पार्टियों को एलाट किया गया। इसके अतिरिक्त १,००० बैगन कोयले का चूरा ३३ इकाइयों को निर्माण-कार्यों के लिए ईंट बनाने के हेतु दिया गया।

लोहा और इस्पात

(क) निर्माण सामग्री—३६० लघु उद्योगों की इकाइयों को १,३६४ टन लोहा और इस्पात एलाट किया गया, अतएव जिला उद्योग अधिकारियों द्वारा वितरण हेतु ५०० टन लोहा और इस्पात रखा गया।

(१) ५१७ विस्थापित फैब्रिकेटर्स को २,११० टन लोहा और इस्पात एलाट किया गया।

(२) एस० एस० आई कोटा में से ८५७ लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों को १५,५७० टन लोहा और इस्पात एलाट किया गया।

## आयात

लघु उद्योग इकाइयों को आयात लाइसेंस स्वीकृत करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की गयी तथा कच्चे माल, मशीनें और पुर्जें आयात करने के हेतु एसेनशिअल्टी प्रमाण-पत्र जारी किये गये ।

## अलौह धातुएं

आलोच्य वर्ष में प्रदेश की लघु उद्योग इकाइयों में वितरण हेतु भारत सरकार ने २८,०० टन तांबा, २५० टन तांबे के टुकड़े, १,८०० टन जस्ता, ३२० टन जर्मन सिलवर और ७०० टन पीतल के टुकड़े स्वीकृत किये थे । इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने इन इकाइयों के लिए ५३ टन सीसा भी दिया था ।

## विद्युत्

आवश्यक जांच-पड़ताल के बाद प्रदेश के उद्योगपतियों की बिजली संबंधी आवश्यकता की सिफारिश राज्य विद्युत् वितरण सभितियों से की गयी ।

## विविध

कपूर, पारा, नमक, केमिकल्स आदि वस्तुएं लघु उद्योगों में उपयोग के लिए देने के हेतु सिफारिश की गयी ।

## ट्रेडमार्क भंग करने के मामले और नकली वस्तुओं की बिक्री

ट्रेडमार्क उल्लंघन तथा नकली माल की बिक्री रोकने की योजना के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में ११६ मामले पकड़े गये और ५४ मामले मुकदमे चलाने हेतु पुलिस को सुपुर्द किये गये ।

## स्टोर्स परचेज

उद्योग निदेशालय का स्टोर्स परचेज विभाग सभी राजकीय विभागों के स्टोर्स के लिए सामान खरीदने का कार्य करता रहा । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए वस्तुओं की ज्यादातर खरीद आयोजन के पहले तीन वर्षों में कर ली गयी थी, अतएव इस वर्ष खरीद के आंकड़े कुछ कम रहे । आलोच्य वर्ष में ४,२५६ पात्र प्राप्त हुए और ४.५३ करोड़ रुपये की लागत के ठेकों को अन्तिम रूप दिया गया ।

रेट कान्ट्रैक्ट पर की जाने वाली खरीद में १.१५७ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई । आलोच्य वर्ष में ६६ रेट कान्ट्रैक्ट प्रबन्ध चालू रहे जब कि रेट कान्ट्रैक्ट पर रहने वाली वस्तुओं की संख्या ४,००० से अधिक थी ।

स्टोर्स परचेज विभाग ने राज्य विद्युत् बोर्ड के लिए २ लाख रुपये से अधिक की लागत के आयात लाइसेंस, फोलीफेज और सिगिल फेज विद्युत मीटरों हेतु प्राप्त किये ।

## वाणिज्य सूचना

विभाग की वाणिज्य सूचना शाखा उद्योग, व्यापार और वाणिज्य सम्बन्धी आंकड़े और तथ्य एकत्र कर इनसे उत्सुकता रखने वाली पार्टियों को अवगत कराती रही । शाखा के अन्य महत्वपूर्ण कार्य थे औद्योगिक विकास योजनाओं का समन्वय करना, औद्योगिक सर्वेक्षण करना और आंकड़े आदि तैयार करना । अपने उद्योग शुरू करने वालों को हर सम्भव सहायता दी गयी । इस शाखा से एक सन्दर्भ विभाग और एक वाणिज्य संग्रहालय भी सम्बद्ध रहा ।

आलोच्य वर्ष में पूछताछ सम्बन्धी १,५६७ पत्र प्राप्त हुए और उनके उत्तर दिये गये । इन पत्रों में लोगों ने लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करने, व्यापारिक प्रतिनिधित्व, यातायात की कठिनाइयों, बिक्री कर सम्बन्धी कठिनाइयों, वर्तमान नगर पालिका और टोल करों में संशोधन, स्थानीय और विदेशी फर्मों के झगड़ों का समझौता, स्थानीय फर्मों की वित्तीय स्थिति की जांच और विदेशी आयात से स्थानीय उद्योगों की सुरक्षा के सम्बन्ध में पूछताछ की थी ।

आलोच्य वर्ष में यह शाखा द्वितीय आयोजना के कार्यों को समन्वित करती रही तथा तृतीय पंचवर्षीय आयोजना में शामिल करने के लिए इसने प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया । पिछड़े



क्षेत्रों की योजनाओं के कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य को समन्वित करने की अपनी जिम्मेदारी का भी इसने निर्वह किया। जिला योजनाएं जिनमें विभिन्न मदों के लिए निर्धारित धनराशियां और भौतिक लक्ष्य दिये गये थे, तैयार की गयीं। औद्योगिक सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्यों के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। वर्ष १९५६ की औद्योगिक दृष्टिकोण रिपोर्ट पूरी की गयी। वर्ष के अन्त तक १४ जिलों की रिपोर्टें छप चुकी थी। शेष जिलों की रिपोर्टें विभिन्न प्रेशों के मुद्रणाधीन थी। वर्ष १९५८ के लिए ५ या इससे अधिक मजदूरों वाली इकाइयों के सर्वेक्षण का कार्य जारी था। वार्षिक पुस्तिका में शामिल करने हेतु फंक्टी अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड इकाइयों की संख्या तथा प्रत्येक के उत्पादन और मजदूरों की संख्या के बारे में पूरी जानकारी जमा की गयी।

केन्द्रीय प्रचार शाखा विज्ञापनों, दृश्य-श्रव्य साधनों, रेडियो, प्रकाशनों आदि के माध्यम से प्रचार कार्य करती रही। शाखा ने विभिन्न प्रदर्शनियों में भी भाग लिया। आलोच्य वर्ष में १३३ डिसप्ले और ३१८ वर्गीकृत विज्ञापन जारी किये गये। हयकरधा, बाराणसी के बोकेंड और गुणविन्हांकन योजना सम्बन्धी ३ छोटी विज्ञापन फिल्में भी बनायी और प्रदर्शित की गयीं। हिन्दी और अंग्रेजी में साप्ताहिक संवादपत्र नियमित रूप से प्रकाशित किया गया।

## ११-फल उपयोग

फल उपयोग निदेशालय जिसकी स्थापना सन् १९५३ में की गयी थी और जिसका मुख्यालय रानीखेत में रखा गया था आयोच्य वर्ष में योजनानुसार कार्य करता रहा। इस विभाग के मुख्य कार्य थे—

१—कुमाऊं में ४ पर्वतीय जिलों और उत्तराखंड के ३ जिलों में बागवानी विकास, शोध और प्रशिक्षण, पौध सुरक्षा आदि।

२—समस्त प्रदेश में फल-संरक्षण का विकास, फल संरक्षण प्रशिक्षण तथा फल-संरक्षण की समस्याओं पर शोध आदि।

आलोच्य वर्ष में निदेशालय ने बागवानी में उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से किये। यह कार्य ४ राज्य उद्यानों, १८ पौधगृहों, १२६१ एकड़ क्षेत्रफल के २ बागवानी फार्मों, और ४ बागवानी एवं पौध सुरक्षा सचल दलों तथा २ पौध सुरक्षा केन्द्रों के माध्यम से किये गये। राज्य उद्यानों ने जनता को अच्छे पौधे और बीज वितरित किये और उसके लिए एक आदर्श भी प्रस्तुत किया। सचल दलों और सुरक्षा केन्द्रों में भी पौधों और बीजों का वितरण किया। उन्होंने बीमारियों से पौधों के बचाव की कार्यवाही भी की। इन इकाइयों द्वारा आलोच्य वर्ष में किये गये कार्यों का विवरण इस प्रकार है—

१—फलदार पेड़ों का उत्पादन	..	६,३५,१०६
२—फलदार पेड़ों का वितरण	..	८,२४,४६३
३—तरकारी के बीजों का वितरण	..	१,४८२ पाँड
४—बीमारियों से पेड़ों की सुरक्षा	..	२,७५,३८६ पेड़
५—बागों का पुनरुद्धार	..	८,६६३ एकड़

समशीतोष्ण कटिबन्धीय फलों के उत्पादन, फलों और अन्य फसलों की बीमारियों से रक्षा तथा कुमाऊं के भूमि सम्बन्धी शोध कार्य पर्वतीय फल शोध केन्द्र चौबटिया में जारी रहे।

आलोच्य वर्ष में ६६ उम्मीदवारों को बागवानी में प्रशिक्षित किया गया। भारत-तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्र के भोटियों तथा नेपालियों ने भी यह प्रशिक्षण जो कि चौबटिया केन्द्र में दिया गया, ग्रहण किया।

जड़ी-बूटियों का उत्पादन—पर्वतीय क्षेत्रों में मिलने वाली महत्वपूर्ण जड़ी-बूटियों का पूर्ण उपयोग करने की दृष्टि से सरकार ने एक जड़ी-बूटी समिति नियुक्त की, जिसका उद्देश्य है विभिन्न जड़ी-बूटियों तथा औषधि के रूप में काम आने वाले अन्य पेड़ पौधों की खेती तथा विकास सम्बन्धी योजनाएं तैयार करना और सरकार को इस क्षेत्र में आवश्यक परामर्श देना था। योजना के अन्तर्गत चौबटिया केन्द्र में २५ एकड़ के एक फार्म में जड़ी-बूटियों आदि का उत्पादन आरम्भ किया गया। यह फार्म फल उपयोग

निदेशालय के तत्वावधान में स्थापित किया गया। सीमावर्ती क्षेत्रों के रेयथल, हरसिल, परलादि, बलन्टी, क्वेन्टी और सिरखा स्थित बहुउद्देशीय फार्मों में से प्रत्येक में से दो एकड़ भूमि जड़ी-बूटियों के उत्पादन के लिए सुरक्षित की गयी इस दिशा में उपर्युक्त फार्मों में निम्नलिखित कार्य किये गये—

- (१) पौधों की जड़ों, बल्बों और बीजों का उत्पादन और संरक्षण,
- (२) बड़े पैमाने पर खेती करने के तरीकों का अध्ययन,
- (३) जम्मू और कश्मीर के समान जलवायु में उत्पादन होने वाले पौधों को इस क्षेत्र की जलवायु के अनुकूल बनाना,
- (४) उचित पौधों का चुनाव और
- (५) सफलतापूर्वक उत्पन्न की गयी जड़ी-बूटियों की राजकीय औषधि विशेषज्ञ द्वारा रानीखेत में परीक्षा।

फल उपयोग निदेशालय ने आलोच्य वर्ष में राजकीय उद्यान चौबटिया, राजकीय उद्यान भरसर और बहुउद्देशीय फार्म बलन्टी में जाफरान की प्रायोगिक खेती भी सफलतापूर्वक की।

बागवानी-उपज का औद्योगीकरण शोध और प्रशिक्षण—निदेशालय की औद्योगीकरण सम्बन्धी योजनाएं फल प्रोसेसिंग फैक्ट्री रामगढ़ (नैनीताल) तथा उसकी डालीगंज (लखनऊ) स्थित शाखा फल संरक्षण फैक्ट्री फूलदाग (नैनीताल) और लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, बरेली, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल), देहरी-गढ़वाल, जोशीमठ, चमोली, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ स्थित १६ सामुदायिक डिब्बाबन्दी केंद्रों द्वारा सम्पन्न की गयी। इन इकाइयों की सहायता से उन फलों का जो कि नष्ट हो जाते थे और जिनसे उत्पादकों को कोई लाभ नहीं होता था उनके ४० प्रतिशत भाग का उपयोग किया गया और इससे उत्पादक फल के पदार्थ बनाने वाले तथा उपभोक्ता लाभान्वित हुये। सीजन के बाद कम मूल्य पर उत्पादकों और जनता के लाभार्थ विभिन्न सामुदायिक डिब्बाबन्दी केंद्रों में फलों और तरकारियों की डिब्बाबन्दी और सुरक्षा की गयी। इन इकाइयों द्वारा आलोच्य वर्ष में ५,८२,५६६ पौंड फलों और तरकारियों की प्रोसेसिंग और डिब्बाबन्दी की गयी।

फल संरक्षण और डिब्बाबन्दी इंस्टीट्यूट, लखनऊ में फल संरक्षण उद्योग की विभिन्न समस्याओं पर खोज की गयी। इस संस्था में जिन समस्याओं पर आलोच्य वर्ष में काम हुआ उनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

- (१) तरबूज से एक हल्का पेय तैयार करना।
- (२) अमरूद की टाफी बनाना।
- (३) आंवले का मुरब्बा बनाना।
- (४) आम के 'पलेक' तैयार करने के उचित तरीके निर्धारित करना।
- (५) जोनेथन और वाइनर सेव के रस से शराब (साइडर) बनाना।
- (६) आइसक्रीम में प्रयोग के लिए जमा किये आम के गूदे पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन।
- (७) मटर के दानों के लिए उचित रंगों का खोज।
- (८) सेब, फूलगोभी और आम, अमरूद, पपीता, आदि फलों की डिब्बाबन्दी।
- (९) फलों का सिरका बनाना।
- (१०) खीरे और ककड़ी के अचार में आने वाले उफान पर नियन्त्रण।

फल संरक्षण और डिब्बाबन्दी के तरीकों में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए १० सचल कक्षा दलों ने २० दिन के प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किये। विभिन्न जिलों में कक्षाएं आयोजित की गयीं और इन दलों ने आलोच्य वर्ष में ३,६२१ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया। इसके अतिरिक्त फलसंरक्षण और डिब्बाबन्दी का एक १६ महीने का स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स भी शुरू किया गया और आलोच्य वर्ष में १७ छात्र इसमें प्रशिक्षित हुए।

प्रशासकीय ढांचा—निदेशालय का शासकीय ढांचा इस वर्ष पिछले वर्ष के समान ही रहा।

## १२—खान और खदानें

चीनी तथा कागज मिलों को चूना पत्थर की सप्लाई मुख्य रूप से देहरादून क्षेत्र से होती रही। ३ खनिज सम्बन्धी रियायतें, १ खान सम्बन्धी लीज सिलिका बालू के लिए इलाहाबाद जिले में, एक भावी लाइसेंस सिलिका बालू के लिए बांदा जिले में और एक भावी लाइसेंस पायरोफिलाइट के लिए हमीरपुर जिले में आलोच्य वर्ष में स्वीकृत किये गये।

## १३—सहकारी आन्दोलन

सहकारिता के क्षेत्र में इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी २०,००० अखिल भारतीय लक्ष्य के विरुद्ध १०,२६३ साधन सहकारी समितियों का संगठन। इन नयी संस्थाओं के सम्बन्ध में एक उद्घाटन समारोह १० नवम्बर, १९५६ को आगरा में प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में हुआ था। दीर्घ आकार की समितियां बनाने की नीति छोड़ दी गयी क्योंकि यह संस्थाएं सहकारी आन्दोलन के दृढ़ सर्वतोमुखी विकास के लिए उपयुक्त नहीं समझी गयी। दूसरी ओर राष्ट्र विकास परिषद् द्वारा निर्धारित रूप और आकार की साधन सहकारी समितियों से ग्रामस्तर पर ग्रामीण जनता की उत्पादन, उपयोग और अन्य प्रकार की उचित आवश्यकताओं की पूर्ति होने के साथ-साथ सदस्यों में समझ-बूझ और सामाजिक एकता बढ़ने की ज्यादा सम्भावना दिखायी पड़ी।

ये संस्थाएं गांव सभा के आधार पर (३००० व्यक्तियों पर एक समिति) संगठित की गयी। आलोच्य वर्ष में इन्होंने सभी क्षेत्रों में विशेषतौर पर ऋण बिक्री, फार्मिंग और सहकासी शिक्षा में बहुत तेजी से उल्लेखनीय प्रगति की।

सभी प्रकार की समितियों की संख्या और उनकी सदस्य संख्या जोकि ३० जून, १९५६ को क्रमशः ६०५२५ और ३२.५१ लाख थी, बढ़कर ३० जून १९६० को क्रमशः ६७,६२० और ४०.५४ लाख हो गयी। इन समितियों की निजी पूंजी और कारोबारी पूंजी जो कि गत वर्ष १९.६० करोड़ रुपये और ६५.६२ करोड़ रुपये थी इस वर्ष बढ़ कर २४.२७ करोड़ रुपये और ९५.४७ करोड़ रुपये हो गयी। प्राइमरी कृषि सहकारी समितियां जिन गांवों में थीं उनकी संख्या और प्रतिशत जो कि गत वर्ष ५६,९४३ और ७८ प्रतिशत था इस वर्ष बढ़ कर ६६,०४७ और ९१.२ प्रतिशत हो गयी। इस वर्ष ग्रामीण सहकारिता के दायरे में लगभग २८ प्रतिशत जनता आ गयी जबकि गत वर्ष का प्रतिशत केवल २२ था।

प्राइमरी कृषि ऋण समितियां—प्राइमरी कृषि ऋण समितियों की संख्या ५०,१३३ से बढ़कर ५७,१३६ हो गयी। इन आंकड़ों में १०,२६३ सहकारी समितियां, ७३० बड़ी समितियां और ४६,१४३ बहु उद्देशीय समितियां शामिल हैं। आलोच्य वर्ष के अन्त में इन समितियों की सदस्य संख्या २१.९४ लाख से बढ़ कर २८.८३ लाख हो गयी। हिस्से की पूंजी और अमानतें भी बढ़ कर ७३९.५५ लाख और ९२.३६ लाख रुपये हो गयी जबकि गत वर्ष यह केवल ५६१.२६ लाख रुपये और ६६.८६ लाख रुपये थी। गत वर्ष के १८.०६

\* ३० जून, १९६० को समाप्त होने वाले सहकारी वर्ष से सम्बन्धित।

करोड़ रुपये और १४.६६ करोड़ रुपये के विरुद्ध इस वर्ष कारोबारी पूँजी और ऋण जो दिये गये बढ़कर २८.६४ करोड़ रुपये और २६.२२ करोड़ रुपये हो गये। इस वर्ष गत वर्ष से दूने ऋण दिये गये तथा पुराने ऋणों का बकाया का प्रतिशत लगभग ५० प्रतिशत गिरा अर्थात् ११.४ से ५.८ हो गया। अन्य राज्यों की अक्षा इस प्रदेश में सबसे कम प्रतिशत रहा और इस मद का अखिल भारतीय प्रतिशत २१ रहा। आलोच्य वर्ष में १०१ रुपये तक औसत प्रति सदस्य ऋण की सुविधा दी गयी जबकि गत वर्ष केवल ६८ रुपये तक ही दिये गये थे। साधन सहकारी समिति की और बड़ी समितियों ने सदस्यों की कृषि-सम्बन्धी आवश्यकता के आधार पर ऋण दिये जिनकी अवश्यनी सम्बन्धी कय-विकय समितियों द्वारा सदस्यों की अतिरिक्त उपज बेच कर होनी थी। ऋण नीति में यह परिवर्तन स्वस्थ वातावरण के निर्माण और सदस्यों में अत्यविश्वास जागृत करने के उद्देश्य से किया गया था। यह भी उद्देश्य था कि किसान कय-विकय समितियों द्वारा इस प्रकार से संगठित हो कि उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। इस योजना को लोगों ने काफी पसन्द किया और यह अनुभव किया गया कि सामान्य नियोजन और फ़िस के ढाँचे के अन्तर्गत यह कृषि उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम में अपने ढंग से काफी सहायक होती। साधन सहकारी समितियों की कुशलता और बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने उनके प्रबन्ध सम्बन्धी खर्चों के लिए ३०० रु० प्रति समिति के हिसाब से आर्थिक सहायता दी। प्रत्येक समिति में लेखा और अन्य रिकार्ड रखने के लिए एक अल्पकालिक गणक नियुक्त किया गया।

बैंक—उत्तर प्रदेश में बैंकों की संख्या पिछले वर्ष के समान ५६ रही। ये बैंक ४६ जिलों में स्थापित थे। क्षेत्र जितों में उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक की शाखाएँ काम करती रहीं। आलोच्य वर्ष में सहकारी बैंक ने काफी प्रगति की। बैंकों की सदस्य संख्या जो गत वर्ष ४३, ४४० थी, इस वर्ष बढ़कर ५१,३१४ हो गयी। निजी और कारोबारी पूँजियाँ ४७२.७३ लाख रुपये और १५१६.४७ लाख रुपये से बढ़कर क्रमशः ६६२.७१ लाख रुपये और २,४६१.३७ लाख रुपये हो गयी। निजी पूँजी से कारोबारी पूँजी के अनुपात का प्रतिशत २६.६ था जोकि इन बैंकों की वित्तीय दृढ़ता का प्रतीक है। इस मद का अखिल भारतीय प्रतिशत १६.६ था। इस वर्ष हिस्से की पूँजी और डिपॉजिट क्रमशः ५८५.८६ लाख रुपये और ७४४.३२ लाख रुपये थे जबकि गत वर्ष ये ४१२.७१ लाख रुपये तथा ५२६.३५ लाख रुपये थी। इन बैंकों के हिस्से की पूँजी में राज्य का अंशदान आलोच्य वर्ष में ६४.७० लाख रुपये से बढ़कर १४०.२० लाख रुपये हो गया। आलोच्य वर्ष में ऋण कार्यक्रम १,३८०.८८ लाख रुपये से बढ़कर २,५६४.६४ लाख रुपये हो गया। वर्ष के अंत में बकाया ऋण १७४३.८६ लाख रुपये था जबकि गत वर्ष यह ११५.४३ लाख रुपये था। वर्ष के अंत में ८१.४६ लाख रुपये ओवर ड्रॉ रहे जोकि बकाया ऋण का ४.६ प्रतिशत था जबकि गत वर्ष यह प्रतिशत ८.६ था। अखिल भारतीय स्तर पर यह प्रतिशत १३.७ था। इस वर्ष कुल ३४.८७ लाख रुपये का लाभ हुआ, जबकि गत वर्ष केवल २३.६४ लाख रुपये का लाभ हुआ था।

उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक—उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्य बैंकों में से एक था। बैंक के हिस्से की पूँजी और जमा की रकम १४२.६८ लाख रुपये तथा ६६३.८५ लाख रुपये से बढ़कर क्रमशः २११.७४ लाख रुपये और ७५०.२५ लाख रुपये हो गयी। बैंक की कारोबारी पूँजी जो कि गत वर्ष १३५२.८६ लाख रुपये थी, इस वर्ष २,११४.५८ लाख रुपये हो गयी। ऋण की अवधारणा ही ६६१.६८ लाख रुपये से बढ़कर २,२७८.८८ लाख रुपये हो गयी। बकाया ऋण से ओवर ड्रॉ का प्रतिशत २.७५ से घटकर १.६ हो गया। इस वर्ष १६.०५ लाख रुपये का लाभ हुआ जबकि गत वर्ष १३.१३ लाख रुपये का लाभ हुआ था।

अल्पवर्गी और मध्यम आय वाले वर्ग की आवास योजनाओं के अन्तर्गत बैंक ने क्रमशः ३०.१४ लाख रुपये और १.५० लाख रुपये आलोच्य वर्ष में दिये।

## उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि बंधक बैंक

यह बैंक जोफि राज्यस्तर का बैंक था मार्च, १९५६ में कृषि कार्यों के लिए दीर्घकालीन वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए खोला गया था। इस बैंक के हिस्से की पूजी में राज्य सरकार ने १५ लाख रुपये का अंशदान किया था और आलोच्य वर्ष में कार्य शुरू करने के लिए केवल आरम्भिक प्रबन्ध किया जा सका।

### कृषियेत्तर प्रारम्भिक ऋण समितियां

वैतन-भोगी जन ही इन समितियों के मुख्य रूप से सदस्य रहे। आलोच्य वर्ष में इनकी संख्या ६६४ और इनकी सदस्य संख्या २.१८ लाख रही। इन्होंने २५०.८४ लाख रुपये ऋण के रूप में दिये जबकि गत वर्ष १६४.१६ लाख रुपये ऋण दिया गया था। ऋण से ओवर ड्यू का प्रतिशत ३.७ से घटाकर ३.३ हो गया। ये संस्थाएं अपनी जमा की रकम पर ही मुख्य रूप से आश्रित रहती हैं। आलोच्य वर्ष में इनकी जमा की रकम १६१.०६ लाख रुपये से बढ़ कर २१२.१७ लाख रुपया हो गयी।

### प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन

आलोच्य वर्ष में प्रदेश में सहकारी बिक्री के विस्तार और विकास कार्यों की सबसे बड़ी संस्था प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन ने अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण रूप से पालन किया। फेडरेशन के मुख्य कार्य थे—

- (१) कृषि उपज की बिक्री की व्यवस्था करना।
- (२) उर्वरक, कोयला, चीनी, बीज, कृषि यन्त्र और भवन निर्माण सामग्री का वितरण करना।
- (३) प्रदेश की क्रय-विक्रय समितियों का निर्देशन और सहायता करना।
- (४) रानीखेत की औषधि फैक्ट्री, ६ घी की श्रेणी निर्धारित करने वाले केन्द्रों और एक प्रेस का संचालन करना।

१९५१-६० लाख रुपये का सामान फेडरेशन द्वारा इस वर्ष लिया—दिया गया जबकि गत वर्ष केवल ३४६.६० लाख रुपये के माल का व्यापार हुआ था। निजी और कारोबारी पूंजियां भी इस वर्ष ११६.३७ लाख रुपये और ३५३.६५ लाख रुपये से बढ़ कर क्रमशः १२६.२६ लाख रुपये और ३६०.०८ लाख रुपये हो गयीं। फेडरेशन ने उन क्रय-विक्रय समितियों की सहायता भी की जिन्हें संगठित व्यापार का मुकाबला करना पड़ रहा था और सहायता न मिलने पर जिनके नष्ट हो जाने की सम्भावना थी। फेडरेशन ने इन समितियों का स्टॉक खरीद लिया और प्रदेश में तथा बाहर भी उसकी बिक्री की व्यवस्था की। दामों की अस्थिरता के कारण गुड़ के व्यापार में हुई अप्रत्याशित हानियों के फलस्वरूप इस वर्ष लाभ केवल ५.०२ लाख रुपये का हुआ जबकि गत वर्ष १२.८२ रुपये का लाभ हुआ था।

### जिला सहकारी फेडरेशन

ये संघ जिले में बिक्री वितरण और उत्पादन सम्बन्धी योजनाओं को समन्वित और विकसित करने के कार्य करते रहे। यह प्रादेशिक फेडरेशन और जिले की इकाइयों के बीच कड़ी का भी काम करते रहे। इन्होंने इस वर्ष १,००५.६२ लाख रुपये का व्यापार किया जबकि गत वर्ष केवल ३४६.१० लाख रुपये का व्यापार हुआ था। इनकी निजी पूजी और कारोबारी पूंजी भी ८४.०४ लाख रुपये तथा २०६.८६ लाख रुपये से बढ़कर ६६.८१ लाख रुपये और २५६.५२ लाख रुपये हो गयी। लाभ ११.३४ लाख रुपये से बढ़ कर १२.८२ लाख रुपये तथा हानि ७.६८ लाख रुपये से घटकर ३.४७ लाख रुपये हो गयी।

## बीज भंडार

सहकारी बीज भंडार, जिन्होंने अपने सदस्यों को उन्नत बीज वितरित कर कृषि उपज की वृद्धि में काफी सहायता पहुंचाई थी, आलोच्य वर्ष में सन्तोषजनक ढंग से काम करते रहे। इन भंडारों की संख्या १,३३७ से बढ़कर १,५२८ हो गयी तथा इन्होंने २५.१२ लाख मन बीज (लगभग ५ करोड़ रुपये मूल्य के) वितरित किये जबकि गत वर्ष २४.०१ लाख मन बीजों का वितरण हुआ था। सफाई पर दिये गये बीजों की उगाही का प्रतिशत ६५.५ रहा जबकि गत वर्ष इस मद का प्रतिशत ६०.२ था। स्टाक में 'ए' श्रेणी के बीजों का प्रतिशत ६६ से बढ़ कर ७५ हो गया। आलोच्य वर्ष में ६४० ४३ टन उर्वरक, १३,७५२ मन खाद, और १,३०४ कृषि यन्त्र वितरित किये गये। पक्के बीज भंडारों की संख्या ६१० से बढ़ कर ६६४ हो गयी।

## दुग्ध यूनियन

प्रदेश में आलोच्य वर्ष में ७ दुग्ध यूनियनें थीं। इस वर्ष इन्होंने २.७५ लाख मन दूध का व्यापार किया जबकि गत वर्ष केवल २.३२ लाख मन दूध बेचा गया था। वाराणसी और मेरठ की दुग्ध यूनियनें हानि उठाकर भी चालू रखी गयी तथा उनके पुनर्गठन के लिए आवश्यक प्रयत्न किये गये। ४ यूनियनों के विस्तार के लिए सरकार ने ०.६६ लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। तृतीय आयोजना के अन्तर्गत दुग्ध पूर्ति कार्य-क्रम का और विस्तार करने का भी निश्चय किया गया।

क्रय-विक्रय समितियाँ—क्रय-विक्रय समितियों की संख्या ६८ से बढ़ कर ११८ हो गयी। इनके अतिरिक्त प्रदेश में २४ गन्ना यूनियनें भी थीं। क्रय-विक्रय समितियों की सदस्य संख्या और हिस्से की पूंजी ३.३० लाख और ५०.३६ लाख रुपये से बढ़ कर ३.६३ लाख और ६७.७३ लाख रुपये हो गयी। गत वर्ष के २४.५० लाख रुपये की तुलना में इस वर्ष इन समितियों को राज्य ने २६.४४ लाख रुपये का अशदान किया। ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में इन समितियों ने ४६ ३७ लाख मन वस्तुओं का जिनका मूल्य ६४७.५२ लाख रुपया था व्यापार किया। गन्ना यूनियनों का कार्य सन्तोषप्रद नहीं था। २४ में से केवल १७ यूनियनों ने ०.२१ लाख मन वस्तुओं का व्यापार किया। विशेष फसलों के व्यापार को और प्रोत्साहन मिला और इस वर्ष ४८,६१ मन कपास २८,२५७ मन जूट और २२५ मन फलों और तरकारियों का व्यापार हुआ। ४५ इंस्पेक्टरों को बिक्री व्यवस्था सम्बन्धी विशेष प्रशिक्षण दिया गया।

प्रोसेसिंग समितियाँ—आलोच्य वर्ष में प्रदेश में प्रोसेसिंग समितियों की संख्या १६ से बढ़ कर २३ हो गयी जिनमें से ८ विक्रय प्रोसेसिंग समितियाँ थी। गन्ना पेरार्ड, मंगफली सफाई, घान कुटाई खोया निर्माण और फलों तथा तरकारियों की डिब्बाबन्दी इन समितियों के मुख्य कार्य थे। विभिन्न कठिनाइयों के कारण ६ प्रोसेसिंग तथा ५ विक्रय प्रोसेसिंग समितियाँ कार्य प्रारम्भ नहीं कर सकी। गत वर्ष २ १० लाख मन की तुलना में ४.३५ लाख मन खाद्यान्नों आदि की सफाई इस वर्ष हुई। समितियों की हिस्से की पूंजी और कारोबारी पूंजी ४.६१ लाख रुपये और ७.१६ लाख रुपये से बढ़ कर ८ ५५ लाख रुपये तथा १२.७३ रुपये हो गयी। इस वर्ष ६.६१ लाख रुपये की बिक्री की गयी तथा ०.२६ लाख रुपये का लाभ हुआ जबकि गत वर्ष ४.७१ लाख रुपये की बिक्री की गयी थी तथा ०.११ लाख रुपये का लाभ हुआ था।

खेतिहर समितियाँ—खेतिहर समितियों की संख्या ८३ से बढ़कर ४१५ हो गयी। प्रति वर्ष २० खेतिहर समितियों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस वर्ष इनकी सदस्य संख्या ७८०६ से बढ़ कर ६५६२ हो गयी। फार्म एरिया गत वर्ष के ७३,६५० एकड़ की तुलना में बढ़कर ८४,०४६ एकड़ हो गयी। हिस्से की पूंजी २२.६४ लाख रुपये से बढ़

कर २३.७८ लाख रुपये, जमा २०.६६ लाख रुपये से बढ़ कर २६.६१ लाख रुपये निजी पूंजी २६.६२ लाख रुपया से बढ़ कर २८.७३ लाख रुपये और कारोबारी पूंजी ५५.०४ लाख रुपये से बढ़ कर ६६.२६ लाख रुपये हो गयी। ३६.७६ लाख रुपये की वस्तुएं बेची गयीं और ३.२१ लाख रुपये का लाभ हुआ जबकि गत वर्ष २१.४४ लाख रुपये का व्यापार तथा २.४० लाख रुपये का लाभ हुआ था। २३ समितियों में से प्रत्येक को ५,००० रुपये से अधिक का लाभ हुआ। सहकारी फार्मिंग इंस्टीट्यूट रामपुर ने १४२ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया। ऐसे केन्द्र और खोने की आवश्यकता का तीव्रता से अनुभव किया गया। बहुत-सी ऐसी सहकारी समितियों ने, जिनके क्षेत्रों में सिंचाई के समुचित साधन उपलब्ध नहीं थे, खेती के सुधरे तरीकों का प्रयोग करके विभिन्न फसलों की औसत पैदावार बढ़ायी। खेतिहर समितियों ने सामुदायिक विकास कार्य तथा लघु और कुटीर उद्योगों के संचालन का कार्य भी जारी रखा। सहकारी कृषि की प्रगति का प्रचार करने के लिए क्षेत्रीयस्तर पर सेमिनार किये गये तथा प्रचार साहित्य का वितरण किया गया।

### आवास समितियां

आवास समितियों की संख्या ४४१ से बढ़ कर ४६२ तथा सदस्य संख्या १६,३४७ से बढ़ कर १६,५४८ हो गयी। चुकता की हुई हिस्से की पूंजी और कारोबारी पूंजी १४.६४ लाख रुपये तथा ५४.५१ लाख रुपये थी। वर्ष में १,४२० एकड़ भूमि उपार्जित की गयी तथा ३४६ मकान बनाये गये। गृह निर्माण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक द्वारा वित्तपोषित रहा तथा इस बैंक ने अल्पायी तथा मध्यम आय वर्गीय योजनाओं के अन्तर्गत ३०.१४ लाख रुपये तथा १.२० लाख रुपये प्रदान किये।

### प्रशिक्षण और शिक्षा

सहकारिता का विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रसार हो रहा है और इसके स्वस्थ एवं लक्ष्य विकास के लिए आवश्यक है कि अधिकाधिक संख्या में अधिकारियों, गैर सरकारी व्यक्तियों, पदाधिकारियों आदि को सहकारिता के सिद्धान्तों और प्रक्रिया में प्रशिक्षित किया जाय। इस उल्लेख से २ व्यक्तियों को पूना में उच्च पर्सनेल प्रशिक्षण, १३२ को मेरठ फैजाबाद और दूसरे (पंजाब) में इण्टरमीडिएट पर्सनेल प्रशिक्षण और २४७ सुपरवाइजरी को ६ राज्य प्रशिक्षण केंद्रों में सबाडिनेट पर्सनेल प्रशिक्षण दिया गया। गैर सरकारी व्यक्ति प्रशिक्षण योजना, जो २८ जिलों में चालू थी, का प्रसार ५१ जिलों में इस वर्ष हुआ तथा कुल २१,१६२ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

### १४—खाद्य और रसद

सामान्य—वर्ष १९६०-६१ में प्रदेश में खाद्य स्थिति सन्तोषजनक रही। वर्षा और बाढ़ के कारण प्रदेश के कुछ भागों की दशा खराब होने की आशंका थी किन्तु सरकार द्वारा जागे नियन्त्रण कार्य-क्रमों, सरकारी गोदामों से पर्याप्त अन्न-संग्रह तथा सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा आयात गेहूँ और स्थानीय गेहूँ के वितरण के कारण स्थिति अच्छी रही।

मूल्य—फसल कटाई के दिनों में रबी के खाद्यान्नों के मूल्यों में कुछ कमी रही किन्तु बाद में बाजार में कम मात्रा में गेहूँ पहुंचने तथा केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल की अफवाहों के कारण दाम बढ़ गये। यह हालत कुछ ही समय तक रही और सितम्बर, १९६० में दाम फिर सामान्य स्तर पर पहुंच गये। बाद के महीने में गेहूँ और चावल के मूल्य तो क्रमशः और कम होते गये तथा कुछ बाजारों में तो वे गत वर्ष के इस काल के मूल्यों से भी नीचे पहुंच गये। दाने के मूल्य अधिक रहे क्योंकि इसका उत्पादन इस वर्ष कम हुआ था तथा अन्य

प्रदेशों में भी इसके दाम बढ़ गये थे। वर्ष के विभिन्न कालों में प्रदेश में खाद्यान्नों की जो स्थिति थी वह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है—

खाद्यान्न	१-४-६०	३०-६-६०	३०-९-६०	३१-१२-६०	३१-३-६१
	कीमत प्रति मन				
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
गेहूं	१६.६२	१६.४८	१६.६३	१६.७०	१६.५५
चना	१२ २२	१३ ६६	१५.५२	१५.६०	१५.८४
जौ	१०.४८	११.७१	१२.३७	१२.७०	१२.०८
ज्वार	११.४०	१३.०८	१२.३६	११.०६	१०.३६
बाजरा	१३.७६	१५.७२	१४.४२	१४.५७	१४.५२
मक्का	११.०७	१२.६२	११.६६	१२.३६	१२.६३
चावल-३	२० ००	२१ ०३	२०.८०	१८.८२	१६.३

सस्ते गल्ले की दुकानें—निर्धारित दरों पर सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा खाद्यान्न वितरण करने की योजना प्रदेश में चालू रही। रबी का अनाज बाजार में आ जाने के बाद इन दुकानों की बिक्री में कुछ कमी हो गयी किन्तु वर्षा आरम्भ होने के बाद मांग फिर बढ़ गयी। दाम स्थिर रखने और इन दुकानों द्वारा जनता को अतिरिक्त अन्न देने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये :—

(१) जिलाधीश को क्षेत्रीय खाद्यान्न नियन्त्रणों की राय से अपने क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकतानुसार बेछना आटा आदि की बिक्री के लिए अतिरिक्त दुकानें खोलने के लिए अधिकृत किया गया।

(२) कबाल नगरो, मेरठ, बरेली, सहारनपुर और रुडकी को छोड़कर शेष स्थानों में बिक्री की प्रति दिन प्रति दुकान अधिकतम सीमा बढ़ा कर २० मन कर दी गयी।

(३) भारत सरकार के आदेशानुसार उपभोक्ताओं को निर्धारित राशन के अतिरिक्त जितना भी अन्न वह चाहें किसी भी सस्ते गल्ले की दुकान से खरीदने की सुविधा प्रदान की गयी।

(४) बरेली, मेरठ और कबाल नगरो के उपभोक्ताओं को निर्धारित राशन के अतिरिक्त हर कार्ड पर २ रुपये का चावल हर मास खरीदने की अनुमति दी गयी। १ अक्टूबर, १९६० से जिन नगरो में मीट्रिक प्रणाली के बांट लागू किये गये वहाँ के उपभोक्ताओं का राशन प्रति यूनिट २ सेर से बढ़ा कर २ किलोग्राम कर दिया गया।

(५) बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए सस्ते गल्ले के अतिरिक्त दुकानें स्वीकृत की गयीं।

(६) जनवरी, १९६१ से सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा देशी गेहूँ की बिक्री में कुछ ढिलाई की गयी तथा उन क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को जिनके बाजारों में देशी गेहूँ उपलब्ध था एक बार में ५ रुपये तक ऐसा गेहूँ सरकारी दर पर खरीदने की सुविधा दी गयी।

मार्च, १९६१ में प्रदेश में सस्ते गल्ले की ५००१ दुकानें थीं।



खाद्यान्नों के मूल्य—सस्ते गल्ले की बूकानों में खाद्यान्नों की फुटकर बिक्री की दरें इस वर्ष इस प्रकार थीं—

खाद्यान्न				फुटकर भाव प्रति रुपया		
				सेर	छटांक	किलोग्राम
गेहूँ (आयात)	..	..	..	२	१०	२.४५०
गेहूँ (देशी) सफेद	..	..	..	२	६	२.२१५
गेहूँ लाल (कोठिया)	..	.	.	२	८	२.३३५
गेहूँ फार्म (मुपीरियर)	..	.	.	२	३	२.०४०
चावल पहली किस्म (अरवा)	..	.	.	१	६	१.४६०
चावल पहली किस्म (सेल्हा)	..	.	.	१	६-१/२	१.४८५
चावल दूसरी किस्म (अरवा विशेष)	.	.	.	१	६	१.४६०
चावल दूसरी किस्म (अरवा)	.	..	..	१	१३	१.६६०
चावल दूसरी किस्म (सेल्हा)	.	.	.	१	१३-१/२	१.७२०
चावल दूसरी -क-किस्म (अरवा)	..	..	..	१	११-१/२	१.६०५
चावल दूसरी -क-किस्म (सेल्हा)	.	.	.	१	१२	१.६३०
चावल तीसरी किस्म (अरवा)	.	..	..	२	.	१.८६५
चावल तीसरी किस्म (सेल्हा)	..	.	.	२	१२	१.८६५
चावल चौथी किस्म (अरवा)	..	.	.	२	३	२.०४०
चावल चौथी किस्म (सेल्हा)	..	..	..	२	४	२.१००
चावल पांचवीं किस्म (अरवा)	..	.	.	२	१०	२.४५०
चावल पांचवीं किस्म (सेल्हा)	..	..	..	२	११	२.५१०
मकई (आयात)	.	..	..	३	८	३.२६५
मक्का (आयात)	.	..	..	३	४	३.०३०
चना	}					
जौ						
बाजरा						
बेझड़ पहला और दूसरा				३	४	३.०३०

यह दरें मैदानी क्षेत्र में प्रचलित रहीं। मेरठ, आगरा, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, झांसी और इलाहाबाद नगरपालिकाओं के क्षेत्रों में सहकारी खाद्यान्न की बिक्री सीटिक बाट से की गयी। पर्वतीय क्षेत्रों—अल्मोडा, गढ़वाल, देहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में फुटकर भाव और एक्स गोदाम थोकभाव, यातायात के खर्च, आनुसागिक खर्च और फुटकर बिक्रेता के नाम (५ प्रतिशत से अधिक नहीं) को दृष्टि में रख कर निर्धारित किये गये। सरकार ने अन्तिम रेलवे स्टेशन गोदाम से अनाज संग्रह करने और वितरण करने के गोदाम तक ४ रुपये प्रति मन से अधिक होने वाला याता-

घात खर्च आंतरिक पर्वतीय प्रदेशों में वहन किया। जहाँ तक नैनीताल और देहरादून जिलों का प्रश्न है वहाँ अन्तिम रेलवे स्टेशन गोदाम से वितरण स्थान तक सामान ले जाने पर होने वाले यातायात खर्च और आनुसंगिक खर्च तथा लाभ सीमा (४ प्रतिशत से अधिक नहीं) को जोड़ कर बिक्री के फुटकर भाव निर्धारित किये गये।

बिक्री के लिए दिये गये खाद्यान्नों के स्टाक

कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ और बरेली की सस्ते गल्ले की दूकानों को सीधे केन्द्रीय स्टोरेज डिपो से आयात गेहूँ मिलता रहा। इन शहरों में शेष खाद्यान्नों तथा अन्य क्षेत्रों में सभी खाद्यान्नों की पूर्ति राज्य सरकार के गोदामों से हुई। केन्द्रीय और राज्य सरकार के गोदामों से १ अप्रैल, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक जो खाद्यान्न दिये गये उनका विवरण इस प्रकार है :—

			मन में	टन में
गेहूँ	..	..	५४,८३,९९८	२,०४,६८६
चावल	..	..	२३,३५,०४१	८७,१५४
मोटा अनाज	..	..	५,१०,७७१	१६,०६४
योग	..	..	८३,२९,८१०	३,१०,९०४

### आटा वितरण योजना

प्रदेश की रोलर आटे मिलों द्वारा तैयार किये गये गेहूँ के आटे आदि का उपयोग पूर्ण रूप से सस्ते गल्ले की दूकानों में वितरण के लिए किया गया। मई, १९६० में मिलों से कम आटा उठाया गया तथा सस्ते गल्ले की दूकानों की आवश्यकता पूर्ति के बाद जो आटा बच गया उसे बेचने की स्वीकृति दी गयी। इसी प्रकार बरसात आरम्भ हो जाने पर इन दूकानों द्वारा आटा की अधिकाधिक बिक्री करने का निश्चय किया गया। अगस्त, १९६० से भारत सरकार ने रोलर आटा मिलों का गेहूँ का मासिक कोटा, १६,३०० मीट्रिक टन से बढ़ा कर ५८,००० मीट्रिक टन कर दिया गया था। अतएव आटा योजना में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये :

(१) मैदा तैयार करने के लिये निर्धारित गेहूँ की मात्रा सबधी प्रतिबन्ध हटा दिया गया। किन्तु साथ-साथ यह निदेश भी दिया गया कि मिलें उन तरीकों की सूचना क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक को दें जब वे मैदा आदि "फाइन्स" और बेछना आटा तैयार करेंगे जिससे कि वे निरीक्षण विषयक कार्यक्रम बना सकें।

(२) क्षेत्रीय खाद्यान्न नियंत्रक जिला मैजिस्ट्रेट ने रोलर आटा मिलों से सस्ते गल्ले की दूकानों और व्यापारिक सस्थानों को उनकी आवश्यकतानुसार बेछना आटा, आटा, मैदा आदि देने की व्यवस्था की। शेष आटा तथा अन्य पदार्थों को मिलों ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित एक्स मिल दरों पर बेच दिया।

अप्रैल, १९६० से जनवरी, १९६१ तक सस्ते गल्ले की दूकानों तथा अन्य व्यापारिक संस्थाओं को १,३६,००० टन आटा, मैदा तथा गेहूँ से तैयार किये गये अन्य पदार्थ दिये गये।

### लाइसेन्स संबंधी आदेश

उत्तर प्रदेश खाद्यान्न विक्रेता लाइसेंसिंग आर्डर, १९५९ इस वर्ष भी जारी रहा। इसके अन्तर्गत बिक्री के लिए ५० मन या इससे अधिक अनाज रखने वाले दूकानदारों के लिए लाइसेन्स लेना अनिवार्य था।

राइस मिलिंग इन्डस्ट्री (रेगुलेशन) ऐक्ट, १९५८ और ५ राइस मिलिंग इन्डस्ट्री (रेगुलेशन ऐन्ड लाइसेंसिंग) रूल्स, १९५९ प्रदेश में २२ अप्रैल, १९५९ के बाद जारी रहे।

उत्तर प्रदेश के लाने ले जाने का प्रतिबन्ध

उत्तर प्रदेश फूडग्रेन्स (गवर्नमेंट) कंट्रोल आर्डर, १९५८ जारी रहा। इसके अन्तर्गत चावल और धान आदि को प्रदेश में लाने या यहां से उनका निर्यात करने पर प्रतिबन्ध लगा रहा।

उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (सीमा पर लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध) आर्डर, १९५९ का संशोधन कर गेहूं पर से ५ अप्रैल, १९६१ से प्रतिबन्ध हटा दिया गया।

उत्तर प्रदेश धान और चावल (लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध) आर्डर, १९५८ बिना किसी संशोधन के जारी रहा।

प्रतिबन्ध हटाना

५ अप्रैल, १९६१ को इन्टरजोनल व्हीट मूवमेंट कंट्रोल आर्डर, १९५७ रद्द कर दिया गया।

प्रदेश में काफी मात्रा में गेहूं उपलब्ध हो जाने के कारण उत्तर प्रदेश गेहूं प्रोक्योरमेंट (लेवी) आर्डर, १९५९, ८ अगस्त, १९६० को, गेहूं (उत्तर प्रदेश) द्वितीय मूल्य नियंत्रण आदेश, १९५९ और उत्तर प्रदेश गेहूं (लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध) आदेश, १९५९, ९ अगस्त, १९६० को रद्द कर दिये गये। उत्तर प्रदेश (अतिथि नियंत्रण) आदेश, १९५९ भी २५ नवम्बर, १९६० से हटा लिया गया।

नियंत्रण संबंधी अन्य कार्य

उत्तर प्रदेश रोलर मिल्स (गेहूं उपयोग नियंत्रण) आदेश, १९५९, जिसके द्वारा मिलों पर यह प्रतिबन्ध लगा था कि वे केवल भारत सरकार द्वारा दिया गया गेहूं ही इस्तेमाल करें, जारी रहा।

भारतीय मक्का (स्टार्च बनाने में मक्का के उपयोग पर प्रतिबंध) आदेश, १९५९ में संशोधन किया गया। संशोधन के फलस्वरूप १८ नवम्बर, १९६० से वह प्रतिबन्ध हट गया जिसके कारण मिले स्टार्च बनाने में भारत में पैदा की जाने वाले वर्ण सकर मक्के का प्रयोग नहीं कर सकती थीं।

उगाही

आकस्मिक आवश्यकताओं तथा कमी वाले क्षेत्रों की जरूरत की पूर्ति के लिए सुरक्षित स्टॉक रखने की नीति के अनुसार चावल और गेहूं की खरीद उगाही (लेवी) प्रणाली पर की गयी। ८ अगस्त, १९६० से गेहूं की उगाही बढ़ कर दी गयी क्योंकि बाजार की स्थिति संतोषजनक थी। चावल की उगाही जारी रही। जहां तक श्रेणियों का प्रश्न है कुछ सुधार किये गये तथा चावल की तीसरी श्रेणी में आने वाली सभी किस्में फिर तृतीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी (क) वर्गीकृत की गयी। निम्नलिखित कंट्रोल दरों पर २१ दिसम्बर, १९६० से तृतीय श्रेणी 'क' चावल की खरीद शुरू की गयी :—

चावल तृतीय 'क' (अरबा) १६ २५ रुपये प्रति मन या ४३ ५४ रु० प्रति क्विन्टल  
चावल तृतीय 'क' (सेला) १५.७५ रुपये प्रति मन या ४२ २० रु० प्रति क्विन्टल

## स्टाक की स्थिति—

३१ मार्च, १९६१ को राज्य सरकार के स्टాक की स्थिति इस प्रकार थी :—

			मन	मीट्रिक टन
गेहूँ	..	..	६,६३,४५८	२५,८८३
चावल	..	..	२३,८२,८२७	८८,६३७
मोटा अनाज	..	..	६,२३५	२३४
योग	..	..	३०,८२,५२०	१,१५,०५४

## चीनी

मई, १९५६ में जब मिलों में कम मात्रा में चीनी देना आरम्भ किया था और चीनी का दाम ०.६६ न०प० प्रति सेर से बढ़ कर १ रु० ४४ न०प० हो गया था, राज्य सरकार ने भारत सरकार के परामर्श से सहायतार्थ उपाय किये और कमी वाले क्षेत्रों को चीनी भेजी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश चीनी विक्रेता लाइसेंसिंग आदेश. १९५६ भी ३१ मई, १९५६ से जारी किया गया जिसके अन्तर्गत चीनी बेचने वालों को लाइसेंस दिये गये। जुलाई, १९५६ में प्रदेश में सभी उपभोक्ताओं को चीनी देने की एक योजना बनायी गयी जो १५ अगस्त, १९५६ से कार्यान्वित हुई। राज्य का चीनी का मासिक कोटा २५,००० टन निर्धारित किया गया। इस कोटा के विरुद्ध जिलों की आवश्यकतानुसार उनका मासिक कोटा निर्धारित हुआ तथा यह जिलों को प्रान्तीयसहकारी फेडरेशन अथवा जिला लाइसेंस प्राप्त चीनी विक्रेताओं द्वारा आयात हुआ। नवम्बर, १९६० से राज्य का कोटा घटा २०,००० टन कर दिया गया।

आलोच्य वर्ष के अन्तिम महीनों में चीनी मिलों में काफी बहुत बड़ा स्टॉक जमा हो जाने की सूचना प्राप्त हुई। अतएव उठा दी जाने वाली चीनी के ५० प्रतिशत भाग को जिले में पहुंचाने पर निर्बंध बिक्री करने की अनुमति दी गयी। शेष ५० प्रतिशत को उस भाग की निर्बंध बिक्री करने की अनुमति दी गयी जो सस्ते गल्ले की ढूँढ़ने या व्यापारिक संस्थान उनके जिले में पहुंचने के ७ दिन बाद तक न उठायें। चीनी विक्रेताओं को लाइसेंस देने के नियमों में भी ढिलाई की गयी। किसी भी व्यक्ति या फर्म को लाइसेंस के लिए प्रार्थना-पत्र देने की सुविधा दी गयी और जिला मैजिस्ट्रेट की उन्हें ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाली अवधि तक के लिए एक अस्थायी चीनी विक्रेता लाइसेंस प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया।

(राज्य में चीनी की स्थिति सतोषजनक हो जाने के कारण ११ अप्रैल, १९६१ से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी के वितरण संबंधी सभी प्रतिबंध हटा दिये गये। हर व्यक्ति और फर्म को जितना भी आवश्यकतानुसार चाहे चीनी खरीदने को छूट दी गयी। खुले बाजार के मूल्य भी धीरे-धीरे नियंत्रित मूल्य के स्तर तक पहुंच गये। कंट्रोल जारी रखा गया क्योंकि आशंका थी कि इसके हटाने पर शायद दाम एकाएक बढ़ जायें। फिर भारत सरकार विदेशों को चीनी निर्यात करना चाहती थी और इसके लिए भी नियंत्रण जारी रखना आवश्यक था।)

## लोहा और इस्पात

जहां तक लोहा और इस्पात का प्रश्न है कुछ किस्मों जैसे द्वितीय श्रेणी रेल स्टाइल्स, स्क्वायर्स, एंगिल्स, चैनल्स, ज्वाइंट्स, टीज आदि, की पूर्ति की स्थिति में काफी सुधार हुआ और फलतः लोहा इस्पात नियंत्रक कलकत्ता ने इन पर लगा वितरण संबंधी नियंत्रण हटा लिया। बार और राड की पूर्ति की स्थिति भी काफी सुधरी। देश में इस्पात उत्पादन में वृद्धि होने के कारण भारत सरकार ने यह प्रस्ताव किया कि चढ़रो (१४ जी से ऊपर वाली) और तारों को छोड़ कर शेष सब श्रेणियों पर से वितरण नियंत्रण हटा दिया जाय। स्थिति में

सुधार के ही कारण भारत सरकार ने सरकारी विभागों द्वारा लोहा और इस्पात के लिए मांग-पत्र देने की प्रक्रिया सरल कर दी। नयी विधि के अनुसार कोटा सर्टिफिकेट्स की जगह सरकारी विभागों और कानून सगठनों जैसे पोर्ट ट्रस्ट और नगरपालिकाएँ, को सीधे लोहा इस्पात नियंत्रण कलकत्ता को बैंगन या अधिक मात्रा के लिए मांग-पत्र देने की सुविधा मिली। बैंगन से कम मात्रा के लिए उन्हें नियंत्रित स्टाकिस्ट के यहाँ मांग पत्र देने के लिए कहा गया। १४ जी से ऊपर की चादरो और तारों की मांगों की पूर्ति राजकीय लोहा इस्पात नियन्त्रक द्वारा होती रही।

प्रत्येक राज्य को लोहा और इस्पात का बल्क कोटा देना भारत सरकार ने जारी रखा। भारत सरकार अब केवल चढ़रों और तारों का कोटा निर्धारित करने लगी। शेष वस्तुओं के लिए पूरी आवश्यकता के मुताबिक मांग-पत्र देने की व्यवस्था की गयी। १९६०-६१ में चढ़रों और तारों की जो अनुमानित मात्रा उपलब्ध होने की आशा थी वह इस प्रकार थी :-

				टन
चढ़रें	..	..	..	२०,२००
तार	..	..	..	२,६००
			योग	२२,८००

इस मात्रा की दृष्टि में ही निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के कोट निर्धारित किये गये।

आलोच्य वर्ष में वर्षा और बाढ़ का प्रकोप अनेक जिलों में रहा। फलतः भारत सरकार से बाढ़ सहायता कार्यों के लिए ४५०० टन जी० सी० शीट और २०० टन बी० पी० शीट का तदर्थ कोटा देने की सिफारिश की गयी और भारत सरकार ने १,००० टन जी० सी० शीट प्रदान की।

१०६०-६१ में प्रदेश को लोहा और इस्पात की जो प्राप्ति हुई उसका विवरण इस प्रकार है :-

काल	टन में प्राप्ति या †
अप्रैल से जून, १९६० ..	२१,७५६
जुलाई से सितम्बर, १९६० ..	१६,८३३
अक्तूबर से दिसम्बर, १९६० ..	१६,६६५
जनवरी से मार्च, १९६१ ..	२७,२२६

स्थिति संतोषजनक हो जाने के कारण अप्रैल, १९६० से तारों और चढ़रों को छोड़ कर शेष वस्तुओं के लिए कोटे नहीं निर्धारित किये गये।

#### स्लैक कोल

आलोच्य वर्ष में स्लैक कोल की पूर्ति की स्थिति संतोषजनक नहीं रही क्योंकि कोयला नियंत्रक ने बहुत से बैंगन भारत सरकार के इस्पात कारखानों में भेजे। भारत सरकार से इस प्रश्न पर राज्य सरकारों ने बातचीत की जिसके फलस्वरूप स्लैक कोल की पूर्ति की स्थिति में कुछ सुधार हुआ। सितम्बर और अक्तूबर, में वर्षा और बाढ़ के कारण स्थिति फिर खराब हो गयी। भारत सरकार से अनुरोध किया गया कि वह बाढ़ क्षेत्रों की जनता के सहायताार्थ १५,०००

† इन प्राप्तियों में केवल रजिस्टर्ड स्टाक होल्डरों द्वारा सूचित प्राप्तियाँ ही शामिल हैं। विकास योजनाओं, स्टील प्रोसेसिंग उद्योग, लघु उद्योग कोटा के अन्तर्गत हुई प्राप्तियाँ इसमें शामिल नहीं हैं।

वैगन स्लैक कोल का तदर्थ कोटा और स्वीकृत करे। केन्द्र ने इस अनुरोध पर १२,००० वैगन कोल स्वीकृत किया जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में वितरित कर दिया गया। २७ फरवरी, १९६१ को विभिन्न रेलवे के 'जनरल मैनेजरो' तथा रेल मंत्रालय और इस्पत खान ईंधन मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों का एक सम्मेलन प्रदेश के कोयला सकेट पर विचारार्थ बुलाया गया। भारत सरकार और रेलवे ने सुझाव दिया है कि प्रदेश में कोल डम्प खोले जायें। राज्य सरकार ने इस सुझाव का स्वागत किया और कहा कि यदि उसे आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जायें तो वह २७ स्थानों में कोल डम्प खोल देगी।

आलोच्य वर्ष में राज्य की स्लैक कोल की निर्धारित और प्राप्त हुई मात्रा इस प्रकार थी :—

मास	निर्धारित वैगनो की संख्या				प्राप्तियां (वैगनो की संख्या)	
	कृषि	कृष्येतर	सी० डी० पी०	योग		
अप्रैल, १९६०	८००	१८००	७३३	३३३३		१४८३
मई, १९६०	८००	१८००	७३४	३३३४		१३२३
जून, १९६०	८००	१८००	७३४	३३३४		१२७७
जुलाई, १९६०	१२००	२७००	११००	५०००		१०२
अगस्त, १९६०	१२००	२७००	११००	५०००		१२८३
सितम्बर, १९६०	१२००	२७००	११००	५०००		१६५०
अक्तूबर, १९६०	१२००	२७००	११००	५०००		२०२७
नवम्बर, १९६०	१२००	२७००	११००	५०००		२५६६
दिसम्बर, १९६०	१२००	२७००	११००	५०००		१४१५
जनवरी, १९६१	८००	१८००	७३३	३३३३		२१३
फरवरी, १९६१	८००	१८००	७३३	३३३३		५४८
मार्च, १९६१	८००	१८००	७३३	३३३३		६०७

संकेत

आलोच्य वर्ष में राज्य में सीमेन्ट की सप्लाई संतोषजनक नहीं रही। इसके कारण निम्नलिखित थे :—

- (१) कुछ यात्रित गड़बड़ियों के कारण ए० सी० सी० फैक्टरी लखौरी ने अपने सामान्य उत्पादन का केवल ५६ प्रतिशत सीमेन्ट ही बनाया।
- (२) सतना और ददरी में सीमेन्ट का उत्पादन घट गया।
- (३) वर्षाकाल में जनता द्वारा अधिक सीमेन्ट की माग की गयी।
- (४) सरकारी विभागों की माग भी बहुत बढ़ गयी क्योंकि यह द्वितीय आयोजना का अंतिम वर्ष था।
- (५) समुचित संख्या में वैगन उपलब्ध नहीं हुए।

सीमेन्ट की कमी को दृष्टि में रखते हुए जिला मैजिस्ट्रेटों को यह निर्देश दिये गये कि वह जब आवश्यकता समझे इसके वितरण पर कन्ट्रोल लगा दें तथा जिले में आने वाले सीमेन्ट की रेलवे रसीदों पर हस्ताक्षर करने की प्रणाली फिर जारी करें जिससे कि जखीरे बाजी न हो सके।

कमी वाले क्षेत्रों की अतिरिक्त सीमेंट की पूर्ति करने के लिए तुरन्त कार्यबाही की गयी। राजकीय सीमेंट फैक्टरी चुरक (मिर्जापुर) से ऐसे कमी वाले क्षेत्रों के लिए जो उनकी बिक्री ज़ोन से नहीं आते ५,००० टन सीमेंट के तदर्थ कोटे की व्यवस्था की गयी। इन उपायों के कारण सप्लाई की स्थिति में कुछ सुधार हुआ किन्तु सितम्बर-अक्तूबर, १९६० में वर्षा और बाढ़ के फलस्वरूप यह फिर खराब हो गयी। इस स्थिति का सामना करने के लिए राज्य सरकार ने अपने बाढ़ सहायता कार्य सबधी सामान्य कोटे के अतिरिक्त भारत सरकार से ५१-२२६ टन सीमेंट और प्राप्त किया। फलतः दिसम्बर, १९६० में समाप्त होने वाली तिमाही में स्थिति में कुछ सुधार हुआ, किन्तु यह फिर १९६१ की पहली तिमाही में खराब होने लगी।

१९६०-६१ में राज्य के लिए सीमेंट की निर्धारित और प्राप्त मात्रा इस प्रकार थी —

	निर्धारित टन	प्राप्त टन
द्वितीय—१९६० (अप्रैल से जून, १९६०) ..	१,६५,५३६	१,१२,६६२
तृतीय—१९६० (जुलाई से सितम्बर, १९६०) ..	१,६६,२६७	१,२३,३७३
चतुर्थ—१९६० (अक्तूबर से दिसम्बर, १९६०) ..	१,६४,०००	१,५८,३०३ (१,४४,००० सामान्य और ५०,००० बाढ़)
प्रथम—१९६० (जनवरी से मार्च, १९६१) ..	१,४७,३००	१,३५,२४६

#### साफ्ट/हार्ड कोक और स्टीम कोल

१५,००० वैन के पिछले कोटे की जगह इस वर्ष राज्य का १ अक्तूबर, १९६० से साफ्ट/हार्ड कोक और स्टीम कोल का वार्षिक कोटा १६,२०० वैन निर्धारित किया गया। यातायात की कठिनाइयों के कारण प्राप्ति में कुछ कमी रह गयी। इस वर्ष स्थिति काफी खराब रही जैसा कि निम्नलिखित आकड़ों से स्पष्ट है —

वर्ष	प्राप्त वैन
१९५८ ..	१०,२०७
१९५९ ..	९,५०६
१९६० ..	६,६४५

प्राप्तियों में कमी मुख्य रूप से अनुचित संख्या में वैन उपलब्ध न होने के कारण हुई। फलतः कोल नियंत्रण संगठन को बड़े उद्योगों आदि को कोयला देने में कठिनाई। ईंट पकाने वाले और घरेलू उपयोग के साफ्ट कोक को यातायात के क्षेत्र में सब से कम प्राथमिकता मिली।

#### जलाने की लकड़ी

घरेलू उपयोग के लिये लकड़ी की कमी होने के कारण जलाने की लकड़ी पर पुनः २४ फरवरी १९६१ से कंट्रोल जारी किया गया। इस योजना के अन्तर्गत कबाल नगरों को सबसे पहले जलाने की लकड़ी कंट्रोल दर पर देनी थी। आवश्यकता पड़ने पर अन्य नगरों में इस योजना का प्रसार करने की भी व्यवस्था थी। उन नगरों में भी जहाँ जलाने की लकड़ी की कंट्रोल की डिपॉथी, खुले बाजार में लकड़ों की बिक्री की व्यवस्था जारी रखी गयी। कंट्रोल की दुकानों का उद्देश्य खुले बाजार के मूल्य कम करना था।

## स्टीम कोल

वैंगनो की कमी का प्रभाव औद्योगिक क्षेत्र पर भी पड़ा। अनेक कारखानों और बिजली-घरों से स्टीम कोल की कमी की सूचनाएं प्राप्त हुईं। कारखाने जारी रखने के लिए उन्हें शीघ्रातिशीघ्र कोयला भेजने के उपाय किये गये।

### नमक

आलोच्य वर्ष में राज्य के विभिन्न जिलों में नमक की स्थिति सन्तोषजनक नहीं रही। भारत सरकार की नमक वितरण की क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत प्रदेश में नमक की पूर्ति होनी रही। वर्ष १९६० के लिए विभिन्न स्थानों से राज्य के लिए जो नमक के मासिक कोटे निर्धारित हुए वह इस प्रकार थे :—

#### (१) राजस्थान साल्ट सोलेंज डिवीजन, सांभर झील—

(क) सांभर ..	..	..	४२८	एम०	जी०	वैंगन
(ख) पचभद्र ..	..	..	१२८	"	"	"
(२) खारागोधा ..	..	..	८१६	"	"	"
(३) जामनगर ..	..	..	७८६	"	"	"

वर्ष १९६१ के लिए निम्न प्रकार से मासिक कोटा निर्धारित हुआ—

#### (१) राजस्थान साल्ट सोलेंज डिवीजन सांभर झील—

(क) सांभर ..	..	..	३५७	एम०	जी०	वैंगन
(ख) पचभद्र ..	..	..	१२८	"	"	"
(२) खारागोधा ..	..	..	८१६	"	"	"
(३) जामनगर ..	..	..	८८०	"	"	"

## नाप-तौल की मीट्रिक प्रणाली

उत्तर प्रदेश नाप-तौल (एनफोर्समेंट) अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत बने उत्तर प्रदेश नाप-तौल (एनफोर्समेंट) नियम १९६० सरकार ने ६ फरवरी, १९६० को विज्ञापित किया। चूंकि स्टैंडर्स आक्ट १९५६ (नं० ८६, १९५६ का) की व्यवस्थाओं को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को थी इसलिए उत्तर प्रदेश वेट्स ऐण्ड मेजर्स (एनफोर्समेंट) ऐक्ट, १९५६ की वह व्यवस्थाएं जो कि वेट्स से संबंधित थीं कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, झांसी और गोरखपुर की नगरपालिकाओं के क्षेत्रों में लागू की गयीं। जहां तक परिमाण (मास) की इकाइयों का प्रश्न है इन नगरों में केन्द्रीय अधिनियम की व्यवस्थाएं १ अक्टूबर, १९५८ से ऐच्छिक आधार पर लागू की जा चुकी थीं। उपर्युक्त नगरों और विशेष उद्योगों के लिए भारत सरकार द्वारा १ अक्टूबर, १९५८ से स्वीकृत २ वर्ष की ऐच्छिक अवधि ३० सितम्बर, १९६० को समाप्त हुई। १० नगरों के विशेष क्षेत्रों और निर्दिष्ट उद्योगों में मीट्रिक बाट का प्रयोग इस प्रकार १ अक्टूबर, १९६० से अनिवार्य हो गया। इस तारीख के बाद से इन क्षेत्रों में स्वीकृत बांटों की जगह किसी अन्य प्रकार के बांटों का प्रयोग करना जुर्म था तथा अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही होना निश्चित हो गया। भारत सरकार ने मीट्रिक वेट्स मेजर्स का प्रयोग कुछ और उद्योगों में, जो भारत सरकार के गजट में विज्ञापित तथा उत्तर प्रदेश सरकार के गजट में पुनः प्रकाशित किये जा चुके थे, करने की अनुमति दी। विभिन्न उद्योगों के लिए ऐच्छिक अवधिया भी स्वीकृत हुईं। यह स्पष्ट कर दिया गया कि इन उद्योगों में ऐच्छिक अवधि की समाप्ति पर मीट्रिक बांटों का प्रयोग अनिवार्य हो जायगा।



उन साल को किस्मो, क्षेत्रों और उद्योगों को छोड़ कर जो १ अप्रैल, १९६० से विज्ञापित किये गये थे भारत सरकार ने तत्काल देश में ऐच्छिक आधार पर व्यापारिक बांटों के प्रयोग की भी अनुमति दी और नये तथा पुराने बांटों के साथ-साथ प्रयोग के लिए २ वर्ष की अवधि निर्धारित की। १ अप्रैल, १९६१ से पूरे प्रदेश ने मीट्रिक बांट का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया गया था। भारत सरकार के निर्णय को दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सभी सस्ते चलने की दुकानों में १ अप्रैल, १९६१ से मीट्रिक बांट जारी करने का निर्णय किया।

व्यापारियों और उपभोक्ताओं को मीट्रिक बांटों से परिचित कराने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ने पोस्टर, सिनेमा, स्लाइडो, रेडियो वार्ताओं, पुस्तिकाओं आदि द्वारा इनका काफी प्रचार किया।

योजना के कार्यान्वयन के लिए खाद्य और रसद विभागीय अधिकारियों को वेल्स एण्ड मेजर्स का पदेन कन्ट्रोलर, डिप्टी कन्ट्रोलर और सहायक कन्ट्रोलर बनाया गया। मीट्रिक संगठन के लिए अभी तक इन्स्पेक्टर या मिनिस्टीरियल कर्मचारियों के प्रतिरिक्त कोई और पूर्णकालिक अधिकारी नियुक्त नहीं किये गये थे। जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है कि रीजनल फूड कन्ट्रोलर को पदेन उप-कन्ट्रोलर और वेल्स एण्ड मेजर्स तथा डिप्टी रीजनल फूड कन्ट्रोलर को रीजनल मार्केटिंग आफीसर और उस सचिव (मिबिल सप्लाइज) को पदेन कन्ट्रोलर वेल्स एण्ड मेजर्स और डिप्टी रीजनल मार्केटिंग आफीसर तथा जिला सप्लाय आफीसर को उनके क्षेत्र का पदेन सहायक कन्ट्रोलर वेल्स एण्ड मेजर्स बना दिया गया।

वेकिंग स्टैण्डर्ड लेबोरेटरीज की आवश्यक साज-सज्जा के लिए प्रयत्न किये गये तथा आशा थी कि सभी जिलों के मुख्यालय नगरों में खुलने वाली इस प्रकार की लेबोरेटरीज शीघ्र ही सज्जित हो जायगी।

कुछ अंशों तक साज-सज्जा का प्रबंध और कर्मचारियों की नियुक्ति हो जाने पर उत्पादकों, विक्रेताओं और मरम्मत करने वालों को लाइसेंस देने का कार्य अप्रैल, १९६० से शुरू किया गया। मीट्रिक बांटों के पुनरीक्षण और उन्हें विनियमित करने का कार्य भी शुरू किया गया तथा ४,३७,८८३ वेल्स एण्ड मेजर्स का पुनरीक्षण और चिन्हांकन हुआ। इन कार्यों तथा लाइसेंस की मद से सरकार को १,६१,५६५ रुपये ७८ न० प० की आय हुई।

### आवास

पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में केन्द्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं के कारण निर्माण कार्य में काफी प्रगति हुई। फिर भी अभी तक आवश्यकतानुसार रहने के लिए अकान उपलब्ध नहीं हो सके हैं। बड़े शहरों में विस्थापित तथा ग्रामीणों के आगमन के कारण स्थिति और भी खराब हो गयी है। निम्नलिखित तालिका से पिछले तीन वर्षों की मकानों की मांगों और उपलब्धियों की स्थिति स्पष्ट है:—

वर्ष	मकानों के लिए दिये गये प्रार्थना-पत्रों की संख्या	एलाट हुए मकानों की संख्या
१९५७ .. .. .	५८,२०६	१७,८७७
१९५८ .. .. .	५५,८२६	१६,५२७
१९५९ .. .. .	४६,८१४	१४,६०१

वर्ष १९५६ में कवाल नगरों में आवास की स्थिति इस प्रकार थी :—

नगर			प्रार्थना- पत्रों की संख्या	एलाउ मकानों की संख्या
कानपुर	..	..	१२,८०२	३,६४५
वाराणसी	..	..	१,२६७	४८५
इलाहाबाद	..	..	२,२०३	६६०
आगरा	..	..	३,२६८	१,२४२
लखनऊ	..	..	१४,४२६	६४३

## अध्याय—४

### यातायात, सड़कें और इमारतें

#### १—सड़कें, पुल और भवन

##### सड़कें और पुल

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस वर्ष १२,७१८ मील (अस्थायी) पक्की और ३,१७० मील (अस्थायी) कच्ची सड़कों का रखरखाव किया जबकि गत वर्ष ११,८१४ मील (अस्थायी) पक्की और ३,१३५ मील (संशोधित) कच्ची सड़कों का रख रखाव किया गया था। सड़क और पुल निर्माण के प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो कार्य अधूरे रह गये थे तथा अधूरे योजनेत्तर कार्य द्वितीय आयोजनाकाल में चलते रहे। द्वितीय आयोजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य भी जारी रहे। द्वितीय योजना के अन्तिम वर्ष के अत तक हुई प्रगति इस प्रकार है :—

#### प्रथम आयोजना की योजनाएँ जो जारी रही

	द्वितीय आयोजना में की गयी व्यवस्था (संशोधित)		द्वितीय आयोजना काल में मार्च, १९६१ के अत तक हुई प्रगति	
	लम्बाई (मील में)	लागत लाख (रुपयों में)	लम्बाई (मील में)	लागत लाख (रुपयों में)
<b>(क) पुनर्निर्माण</b>				
(१) स्थानीय पक्की सड़कें	६८	३७.४८	६४	३५.५६
(२) कच्ची पहाड़ी घोड़ा सड़कें।	१६७	११.३२	१३४	६.५१
(३) आधुनिकीकरण और सुधार।	२१२	६६.८७ (संशोधित)	२०२	६८.६४
योग ..	४४७	११८ ६७	४००	१११.०१
<b>(ख) नवनिर्माण</b>				
(१) पक्की सड़कें ..	३१८ (संशोधित)	१८५ १४ (संशोधित)	५२७	२३८.१६
(२) जिलों के अन्य पक्की सड़कें।	३१२	११४.८५	—	—
(३) सीमेंट बकरीट मार्ग	३३६	६४ ६०	१२५	३८.१३
(४) कच्ची सड़कें ..	६८	१३.३१	५७	६.६६
योग ..	१,०३७	४०८.२०	७०९	२८६.०१

		द्वितीय आयोजना में की गयी व्ययस्था (सशोधित)		द्वितीय आयोजना काल में मार्च, १९६१ के अन्त तक हुई प्रगति	
		लम्बाई (मील में)	लागत लाख (रुपयों में)	लम्बाई (मील में)	लागत लाख (रुपयों में)
(ग) बड़े पुल—					
(१) बड़े पुल	..	४१ (संख्या)	१३०.३०	४१ (संख्या)	१११.४७
(२) झूला पुल	..	८ (संख्या)	२६१		
योग	..	४९ (संख्या)	१३२.९१	४१ (संख्या)	१११.४७
(घ) अन्य कार्य—					
थोक रकम	..	..	३७.१६ थोक रकम	..	२३.२५
कुल योग	..	..	६९६.९४	..	५३१.७४

## द्वितीय आयोजनाकाल की नयी योजनाएं

		द्वितीय आयोजना में व्ययस्था		मार्च, १९६१ के अन्त तक हुई प्रगति (अस्थायी)	
		लम्बाई (मील में)	लागत लाख (रुपयों में)	लम्बाई (मील में)	लागत लाख (रुपयों में)
(क) पुनर्निर्माण—					
(१) स्थानीय पक्की सड़के		४१२	१३१.१७	१९७	८१.९६
(२) कच्ची पहाड़ी घोडा सड़के ।		४३४	१८४.५	२६३	६.९२
(३) आधुनिकीकरण	..	४६४	१८८.९३ (सशोधित)	३४६	११८.४६
योग	..	१३१०	३२४.५५	८०६	२०७.४०

		द्वितीय आयोजना में व्यवस्था		मार्च, १९६१ के अन्त हुई प्रगति (अस्थायी)	
		लम्बाई (मील में)	लागत (लाख रुपयों में)	लम्बाई (मील में)	लागत (लाख रुपयों में)
<b>(ख) नवनिर्माण—</b>					
(१) पक्की सड़के ..	६२६ (संशोधित)	४४६.७३	..	..	..
(२) जिले की अन्य सड़के पक्की की गयीं ।	८११	३२१.८०	८६२	४३०.०३	
(३) श्रमदान मार्ग	१००	२७.५०			
(४) राजकीय इस्टेट सड़के	२५	१०.००			
(५) कच्ची सड़के ..	३६६	२४.४०	१४५	१०.१५	
(६) श्रमदान की ३००	थोक रकम	७.५०	थोक रकम	३.६६	
मील सड़को का रख रखाव					
योग ..	२,२६१	८३७.६३	१,०३७	४४३.८४	
<b>(ग) बड़े पुल—</b>					
(१) झूला पुल ..	३५ (संख्या)	२२.००	१६	१४४.६६	
(२) बड़े पुल ..	५६ + ८ फेरीज	३२६.३२	(संख्या)		
योग ..	९१ (संख्या)	३४८.३२	१६ (संख्या)	१४४.६६	
(३) अन्य कार्य ..	थोक रकम	८५.५०	थोक रकम	३०.४२	
कुल योग ..	..	१,६१०.३०	..	८२६.६५	

### बेकारी सहायता योजनाएं

[ निम्नलिखित विवरण उन सड़को के बारे में है जिनकी स्वीकृति भारत सरकार ने अपनी बेकारी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत दी थी। भारत सरकार ने इनका पूरा खर्च उठाना स्वीकार किया तथा इनका कार्य जारी रखा गया। ]

		द्वितीय आयोजना में व्यवस्था		मार्च, १९६१ तक प्रगति (अस्थायी)	
		लम्बाई (मील में)	लागत (लाख रुपयों में)	लम्बाई (मील में)	लागत (लाख रुपयों में)
<b>(क) पुर्ननिर्माण—</b>					
(१) स्थानीय पक्की सड़के	६	०.४३	६	०.४६ (संशोधित)	
(२) पहाड़ी कच्ची घोडा सड़के	१०४	२०.०६	७५	७.४३	

	द्वितीय आयोजना में व्यवस्था		मार्च, १९६१ तक प्रगति (अस्थायी)	
	लम्बाई (मील में)	लागत (लाख रुपये में)	लम्बाई (मील में)	लागत (लाख रुपये में)
(३) आधुनिकीकरण तथा सुधार	२१	४८०	४	४.१६
योग ..	१३४	२५.२६	८८	१२.०५
(ख) नवनिर्माण---				
(१) पक्की सड़के ..	२६५ (सशोधित)	१८१.४०	३४१ (सशोधित)	१५३.८३
(२) जिलो की अन्य पक्की सड़के	५१ (सशोधित)	१५.६१		
(३) कच्ची सड़के और सुधार	६३	१२.५५		
योग ..	४३९	२०९.५६	४०५	१६३.२१
कुल योग ..	.	२१४.८५	..	१७५.२६

### केन्द्रीय सड़क कोष द्वारा पोषित योजना

द्वितीय आयोजना के कार्यों के अतिरिक्त प्रदेश में कुछ केन्द्रीय सड़क कोष द्वारा पोषित योजनाओं की सड़कों का निर्माण भी जारी रहा। इन श्रेणी की पुरानी और नयी योजनाओं का विवरण इस प्रकार है :—

कार्य का विवरण	द्वितीय आयोजना में व्यवस्था		३१ मार्च, १९६१ तक प्रगति (अस्थायी)	
	लम्बाई (मील में)	लागत (लाख रुपये में)	लम्बाई (मील में)	लागत (लाख रुपये में)
(१) जारी योजनाएं---				
(१) पुनर्निर्माण सुधार और आधुनिकीकरण	२१६	६१.८८० (सशोधित)	२१२	५६.४०
(२) नव निर्माण-नयी पक्की सड़के और जिलो की अन्य सड़कों को पक्की करना ..	६	१२.२८६ १.६३८	६	१४.३४
(३) पुल—	५	१६.३१६	३	१७.१२
बड़े पुल ..	..	(संख्या)	..	(संख्या)
(४) अन्य कार्य ..	..	थोक रकम ०.१४६	..	थोक रकम ०.१४५
योग ..	..	६४.६६६	..	८८.००५

कार्य का उपशीर्ष	द्वितीय पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था		मार्च, १९६१ तक उप- लब्धियाँ (अतः कालीन)	
	लम्बाई (मील में)	लागत (लाख रुपये में)	लम्बाई (मील में)	लागत (लाख रुपये में)
<b>२-नयी योजनाएं—</b>				
(१) आधुनिकीकरण एवं सुधार ।	१६ (संशोधित)	१५.८६८	६	६.१०
(२) नूतन निर्माण नयी पक्की सड़कें ..	४८ (संशोधित)	४३.८० (संशोधित)	२३	१६.६६
(३) कच्ची सड़कें ..	१२ (संशोधित)	१२.८०	१	१.२५
(४) पुल— झूला, नाव और बड़े पुल	४ (संख्या)	१७.८७१	..	३.६२
(५) अन्य कार्य ..	थोक रकम	२.६४१	..	०.०६
योग ..	..	६३.२८०	..	३०.७५
कुल योग ..	..	१८८ २४६	..	११८ ७५५

[नोट—नयी योजनाओं के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्था की सख्या में वह सख्या भी सम्मिलित है जिन कार्यों की व्यवस्था की स्वीकृति सन् १९६०-६१ में दी गयी थी। जारी रहने वाली योजनाओं के अन्तर्गत २ पुलों पर होने वाले व्यय पहले नयी योजनाओं में सम्मिलित कर लिया गया था और अब उसे ठीक कर दिया गया है।]

### सड़को का आधुनिकीकरण

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सड़को के आधुनिकीकरण के महत्व पर बल दिया गया था और कई महत्वपूर्ण राजमार्गों के उनकी पूरी लम्बाई भर आधुनिकीकरण प्रस्तावित किया गया।

१,०२७ (संशोधित) मीलो के आधुनिकीकरण की व्यवस्था की गयी। इनमें से मार्च, १९६१ तक ७७६ मील सड़को का आधुनिकीकरण किया जा चुका था।

चीनी मीलो के चारों ओर सड़क—प्रथम पंचवर्षीय योजना में सरकार ने चीनी मीलो के चारों ओर सड़को के निर्माण की स्वीकृति दी थी। उक्त योजनाकाल में इन सड़को में से कुछ का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका था और उनको पूरी करने की व्यवस्था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गयी। इन अपूर्ण कार्यों के अतिरिक्त, सरकार ने २४१.४३ लाख रुपये की लागत की १४६ मील लम्बी कोलतार की सड़को और २७१ मील लम्बी सीमेंट कंक्रीट की सड़को के नव निर्माण की स्वीकृति दी। ५५७ लाख रुपये की धनराशि आरक्षित रखी गयी ताकि किसी परियोजना पर अनुमानित धन से अधिक का व्यय उठे तो उससे पूरा किया जा सके। यह मजूर दिया गया कि इस योजना की लागत बराबर से चीनी मिल के मालिकों का सिडिकेट, राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार वहन करेंगी। मार्च, १९६१ तक १६० मील लम्बी सीमेंट

कईक्रीट और कोलनार की सड़को का निर्माण हो चुका था। मार्च, १९६१ तक इस योजना पर १४४ १२६ लाख (अतःकालीन) रुपये का कुल व्यय हुआ था।

पिछड़े और सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़को का विकास—१९५८-५९ से भारत-तिब्बत सीमा योजना के अन्तर्गत, १९५८-५९ से पिछड़े क्षेत्र योजना के अन्तर्गत और १९६०-६१ से अतिरिक्त पिछड़े क्षेत्र योजना के अन्तर्गत सरकार ने सड़को और पुलों के निर्माण की अनिश्चित परियोजनाओं की स्वीकृति दी। इन योजनाओं से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं :—

#### सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़को के विकास की योजना

कार्य का विवरण	द्वितीय पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था		मार्च, १९६१ तक उपलब्धियां (अतःकालीन)	
	लम्बाई (मीलो में)	लागत (लाख रुपये में)	लम्बाई (मीलो में)	लागत (लाख रुपये में)
१	२	३	४	५
(१) पुनर्निर्माण-कच्ची घोड़ा सड़कें।	२३	३.००	८	१०३
(२) नव-निर्माण नयी मोटर सड़कें।	६८	४१ ५०	५६	२३.६१
(३) पुल—				
(१) बड़े ..	१ (संख्या)	७५ }		३.६९
(२) झूला ..	१ (संख्या)	२० }		
योग ..	..	५४.००	..	२८.३३

#### पिछड़े क्षेत्रों की योजनाएं

कार्य का विवरण	कुल व्यवस्था		मार्च, १९६१ तक उपलब्धियां	
	लम्बाई (मीलो में)	लागत (लाख रुपये में)	लम्बाई (मीलो में)	लागत (लाख रुपये में) (अतःकालीन)
१	२	३	४	५
सड़कें—				
(क) नया निर्माण ..	१५३ (संशोधित)	१०७.४६ (संशोधित)	७४	४७.१५
(ख) आधुनिकीकरण ..	३		..	..
पुल ..	१२ (संख्या)		१ (संख्या)	८२५
योग ..	..	१०७.४६	..	५५.४०



## अतिरिक्त पिछड़े क्षेत्र योजना

कार्य का विवरण	कुल व्यवस्था		मार्च, १९६१ तक उप- लब्धियाँ	
	लम्बाई (मीलो में)	लागत (लाख रुपये में)	लम्बाई (मीलो में)	लागत (लाख रुपये में) (अतःकालीन)
१	२	३	४	५
१—नव निर्माण ..	६३	६१.४६	२	१.६६५
२—मोजूदा सड़को का सुधार तथा आधुनिकीकरण ।	६५	३६.६५	३	१६.५३७
योग ..	१८८	९८.११	५	१८.५३२

## बेरोजगार व्यक्तियों के पुनर्वास की योजना—

इन योजनाओं के अतिरिक्त लखीमपुर-खीरी और पीलीभीत जिलों में बेरोजगार व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए भूमि को कृषि योग्य बनाने की योजनाओं के अन्तर्गत सड़को के निर्माण का कार्य-क्रम प्रारम्भ किया गया । इसमें जो प्रगति हुई, उसका ब्योरा निम्नलिखित है :

कार्य का विवरण	द्वितीय पंचवर्षीय योजना में व्यवस्था		मार्च, १९६१ तक उप- लब्धि (अतःकालीन)	
	लम्बाई (मीलो में)	लागत (लाख रुपयों में)	लम्बाई (मीलो में)	लागत (लाख रुपयों में)
१	२	३	४	५
जारी रहने वाली योजनाएं—				
लखीमपुर खीरी में २००० एकड़ भूमि कृषि योग्य बनाने की योजना	२१	२०.६०५	२१	२१.६८ (अतःकालीन)
नयी योजना—भूमिहीन मजदूरों के लिए पीलीभीत जिले में बस्ती बसाने के लिए सड़को का निर्माण ..	१८	२२.७२८	१०	१३.६७ (अतःकालीन)
योग ..	३९	४३.३३३	३१	३५.३५

## राजकीय मार्ग—

१९६०-६१ में उत्तर प्रदेश के राजमार्गों की उन्नति के लिये भारत सरकार ने इतने कार्यों की स्वीकृति दी कि उनकी लागत अनुमानतः १००.४३७ लाख रुपये हो गयी । इसके अतिरिक्त

४६ लाख रुपये की एक और धनराशि इसलिङ् स्वीकृत की गयी कि उन के जरिये राजमार्गों का टी ह से रखरखाव और सम्भत हो लके। इस सम्भत मे वर्णकाल मे होने वाली टूट-फूट भी सम्मिलित थी। १९६०-६१ के कार्यक्रम मे सम्मिलित विशिष्ट परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित है :—

कार्य	अनुमानित लागत (रुपयों मे)	जो खर्च हुआ (रुपयों मे)	आलोच्य वर्ष के अंत तक भौतिक प्रगति
१	२	३	४
पुल—			प्रतिशत
(१) आजमगढ़ जिले के मऊ नामक स्थान मे टोस नदी पर पुल का निर्माण ..	१२,४८,८००	५,६२,०००	४३
(२) राजमार्ग २४ पर स्थित गढ़-मुक्तेश्वर मे गंगा पुल का निर्माण ..	७७,६७,०००	६०,६७,०००	८५
(३) गोरखपुर जिले मे घाट पर एक आर० सी० पुल का निर्माण ..	४१,४३,०००	२८,००,०००	७०
(४) गोरखपुर जिले मे बोर्ड घाट पर राप्ती के पुल तक प्रवेश मार्गों का निर्माण	६,५८,७००	३,८७,८००	३४
(५) मथुरा जिले मे कोसी उपमार्ग के नीचे पुल का निर्माण .. ..	१,१५,६००	..	..
(६) गढ़पुल तक मुरादाबाद की ओर से प्रवेश मार्ग .. ..	१०,५८,१००	८,५१,०००	८६
(७) अयोध्या मे सरयू (घाघरा) पर प्रस्तावित पुल के लिए नदी का बहाव मोड़ने के कार्य पर .. ..	८०,५२,०००	६८,६३,०००	६८
(८) इलाहाबाद के यमुना पुल की सड़क पर रोशनी की व्यवस्था .. ..	३१,४००	..	..
(९) अयोध्या और लकड़मंडी दोनों ओर पादवर्भित्तियों पर स्तम्भभित्ति का निर्माण तथा अयोध्या मे सरयू (घाघरा) पर प्रस्तावित पुल के लिए प्रवेश मार्गों का निर्माण .. ..	६,८५,०००	२,६३,४८०	३४
सड़कों को चौड़ा करना—			
(१) राजमार्ग २ की बम्बई-दिल्ली सड़क को मील नं० ७६६ से मील नं० ८१७ तक चौड़ा करना .. ..	१७,७१,०००	१७,४१,०००	६३.६
(२) राजमार्ग २ (कानपुर बड़ा) के किनारे (मील ५१ से ७० तक) की पटरियों को चौड़ा करना .. ..	८,८५,६००	..	.

कार्य	अनुमानित लागत (रुपयों में)	जो खर्च हुआ (रुपयों में)	आलोच्य वर्ष के अंत तक भौतिक प्रगति
१	२	३	४
(३) राजमार्ग २ (कानपुर तथा इलाहाबाद) के किनारों की पटरियों को चौड़ा करना .. ..	१५,३३,०००	..	प्रतिशत ..
(४) राजमार्ग २ के लखनऊ-बरेली सड़क को मील ११ से १६ तक चौड़ा करना .. ..	५,४६,८००	२,३६,७००	६४
(५) मेरठ जिले में गाजियाबाद से हापुड़ तक राजमार्ग (रूट नं० २४) को ऊँचा तथा चौड़ा करना .. ..	२३,२३,२००	..	..
(६) मेरठ जिले में हापुड़ से गढमुक्ते-श्वर तक राजमार्ग नं० २४ को ऊँचा और चौड़ा करना .. ..	२०,२७,२००	..	..
(७) लखनऊ और उन्नाव जिलों में लखनऊ-झासी सड़क को मील ४ से मील ७५ तक चौड़ा करना .. ..	२०,६३,०००	१८,२६,८००	१००
(८) राजमार्ग रूट नं० २८ के लखनऊ-गोरखपुर सड़क को मील ३ से मील ११ तक चौड़ा करना सीमेंट काक्रीट करना तथा रंगना— .. ..	४,३१,०००	४,०६,६००	६८.५
(१) मथुरा जिले में रा० रा० मा० २ की बम्बई-दिल्ली सड़क को मील ७७६ से मील ८१ तक की सीमेंट काक्रीटिंग .. ..	४१,१८,२००	६,५०,०००	१५
(२) आगरा जिले में रा० रा० मा० २ की बम्बई-दिल्ली सड़क को मील ७५६ से ७६५ तक की सीमेंट काक्रीट करना .. ..	३१,८६,०००	१,१०,०००	५
(३) देवरिया जिले में कसिया-तमकुही सड़क (रा० रा० मा० २८) के २००वें मील से २७६वें मील तक कोलतार करने के लिए .. ..	१६,१३,६००	..	..
(४) गोरखपुर-गाजीपुर सड़क (रा० रा० मा० २९) के ३५वें मील से ६२वें मील तक कोलतार करने के लिए .. ..	१२,६०,०००	१०,८६,८००	६४

कार्य	अनुमानित लागत ( पयों में )	जो खर्च हुआ (रुपयों में)	आलोच्य वर्ष के अन्त तक भौतिक प्रगति
१	२	३	४
प्रतिशत			
उपसार्ग, पटरियो पर पुल तथा प्रवेश मार्ग--			
(१) बम्बई-दिल्ली सड़क (रा०रा०मा० २) का कोसी कला के गिकट द११-द१२वें मीलो पर मोड़ना .. ..	७,१७,३००	२,६६,२५४	६०
(२) बम्बई-दिल्ली सड़क पर ७८१ मील से ७८० मील तक मथुरा के लिए एक उपसार्ग का निर्माण .. ..	१४,८०,७००	१२,२७,२८०	८६
(३) सेंट्रल रेलवे ओवर ब्रिज तक (मीलद७०/- १८-१९) मथुरा उपसार्ग पर (रा०रा०मा० २) प्रवेश मार्गों का निर्माण .. ..	२,८८,५००	२,३६,०००	८२
(४) मथुरा उपसार्ग पर सेंट्रल रेलवे के ७६६/१५- १६ और ७७३-७७४ मीलो पर मथुरा में ओवर ब्रिज के लिए प्रवेश मार्गों का निर्माण	२,७६,८००	२,७६,७४७	७२
(५) मथुरा जिले में बम्बई-दिल्ली सड़क के ७७८वें मील पर वर्तमान रेलवे फाटको के स्थान पर वाह में ओवर ब्रिज के लिए प्रवेश मार्गों का निर्माण .. ..	३,०१,२००	२,४८,३००	७५
(६) बम्बई-दिल्ली सड़क के ७७२वें मील पर फर्राह में रेलवे क्रासिंग के स्थान पर सेंट्रल रेलवे ओवर ब्रिज तक प्रवेश मार्गों का निर्माण .. ..	४,०६,२००	३,००,८००	७५
(७) आगरे में (रा०रा०मा० २) यमुना नदी पर एक उपसार्ग तथा पुल बनाने के लिये भूमि की अध्याप्ति .. ..	१,६६,४००	..	..
(८) जैनपुरी जिले में ए०ई०एफ० सड़क (रा० रा०मा० २) के जलमग्न भाग को ३६ से ४२ वें तथा ४६ से ४७ वें मीलो को ऊँचा करना .. ..	७,०५,३००	१८,१००	१
(९) लखनऊ-गोरखपुर सड़क के ७७ से द१ मील तक फैजाबाद में उपसार्ग के निर्माण हेतु भूमि की अध्याप्ति .. ..	३६,३००	..	..

कार्य	अनुमानित लागत (रुपयो में)	जो खर्च हुआ (रुपयो में)	आलोच्य वर्ष के अन्त तक भौतिक प्रगति
१	२	३	४
<b>ज्यामिति का सुधार—</b>			
(१) रा०मा०मा० २ (ग्रैन्डट्रंक रोड मील ४८८ से ५०० तक) के ४३६ से ४५१ मीलो के बीच कठोर मोड़ों को सरल बनाना	१,३२,६००	१,०५,०००	७५
(२) उन्नाव जिले में लखनऊ-झांसी सड़क के (रा०रा०मा०२५) के ४४ वें मील (किग६) के कठोर मोड़ों को सरल बनाना ..	७०,२००	६०,०००	६६

**इमारतें—**

विभिन्न विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण इमारतों का उल्लेख जिनका निर्माण-कार्य १९६०-६१ में पूरा हुआ, नीचे दिया जा रहा है —

कार्य का नाम	धनराशि जो व्यय हुई
१	२
	रु०
१—शाहजहापुर में मुख्य गन्ना अनुसंधान केन्द्र के विस्तार की योजना से संबंधित इमारत और मुजफ्फरनगर तथा गोरखपुर के उपकेन्द्रों से संबंधित इमारतें (गोरखपुर और मुजफ्फरनगर में कार्य पहले ही पूरा हो चुका था) .. ..	१,६१,००८
(२) लखनऊ के महानगर मोहल्ले में सी०आई०डी० के ३० इन्स्पेक्टरों और ३० सब-इन्स्पेक्टरों के लिए मकान .. ..	७,०४,५००
(३) १० इन्स्पेक्टरों, २६ सब-इन्स्पेक्टरों, ६२ विवाहित हेड कास्टेबिलों और ३०० विवाहित सिपाहियों के लिए क्वार्टर तथा २७५ सिपाहियों के लिए बैरकें .. ..	१५,००,०००
(४) लखनऊ के महानगर में पी०ए०सी० की तीसरी बटालियन के लिए इमारत तथा रंगरूटों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र .. ..	२१,३८,०००
(५) लखनऊ के महानगर में यू०पी० पुलिस रेडियो मुख्यालय के लिए इमारत .. ..	१५,४८,०००
(६) मेरठ में छठी बटालियन पी०ए०सी० के लिए इमारत .. ..	१८,००,०००
(७) लखनऊ के बनारसीबाग में स्थायी विकास प्रदर्शनी के लिये भवन	३,०२,०००

कार्य का नाम	धनराशि जो व्यय हुई
१	२
	रु०
(८) लखनऊ में खेल-कूद का स्टेडियम .. ..	१३,५०,०००
(९) इलाहाबाद में अदालती कमरो के नये खंड .. ..	२,९८,०००
(१०) लखनऊ के कला और शिल्प के राजकीय स्कूल के लिए इमारत ..	२,९१,७००
(११) लखनऊ के कला और शिल्प के राजकीय स्कूल के लिए नया भवन (संस्था के भवन के वर्तमान खंड का कार्य भी पूरा कर दिया गया) .. ..	१,९१,२००
(१२) कानपुर में श्रमायुक्त कार्यालय के भवन का उपभवन ..	२,७६,०००
(१३) मेरठ में औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र .. ..	६,११,८००
(१४) कानपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र .. ..	१७,९४,०००
(१५) इलाहाबाद के सेंट्रल प्रेस तथा लखनऊ के नये राजकीय प्रेस में दवाखाना, आराम-कक्ष, जलपान कक्ष, पुस्तकालय इत्यादि ..	२,५७,०००
(१६) कानपुर में हारकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट लेदर वर्किंग स्कूल तथा गवर्नमेंट सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट के छात्रावास .. ..	३,४७,६००
(१७) अल्मोडा में एक फार्म के विकास के लिए भवन (हवालबाग इलाके की अध्याप्ति की कार्यवाही भी पूरी की गयी) ..	१,८२,०४०
(१८) इलाहाबाद में छपाई का उत्तरी क्षेत्रिक स्कूल की स्थापना की योजना से संबंधित भवन .. ..	४,२५,५९७
(१९) सुल्तानपुर, सहारनपुर, ग्वाजमगढ़, अलीगढ़ और इटावा जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में अग्रगामी कारखाने स्थापित करने की योजना से संबंधित इमारत (कुछ भवनों में केवल बिजली लगना शेष था)	५,६९,०००
(२०) देवबन्द की औद्योगिक इलाबा (स्वीकृत तीस इकाइयां पूरी की गयी। अन्य इकाइयों पर स्वीकृति मिलनी थी) ..	८,५५,१००
(२१) लोनी, मेरठ और वाराणसी की काशी विद्यापीठ के औद्योगिक इलाके .. ..	५,९२,८००
(२२) रेशम बुनने वालों की वाराणसी में दक्षी जिस में १०० घर हैं	४,०६,०००
(२३) चुरक में अतिरिक्त चूने का पत्थर स्टॉक करने के लिए भवन ..	२३,५००
(२४) चुरक सीमेंट फैक्ट्री में १ कमरे वाले क्वार्टर .. ..	२,७८,१५०
(२५) चुरक में 'जे' टाइप क्वार्टर .. ..	१,७३,३५०
(२६) चुरक के हायर सेकेंडरी स्कूल भवन में अतिरिक्त निर्माण ..	२,३७,३००

विभिन्न विभागों की निम्नलिखित इमारतों का निर्माण कार्य चालू था—

कार्य का नाम	अनुमानित लागत
	रु०
१—आगरा में दुग्ध शाला के लिए भवन .. .. .	२६,००,०००
	(भूमि के मूल्य सहित)
२—पीलीभीत औपनिवेशीकरण योजना से संबंधित इमारतें ..	१८,०५,५००
३—पहाड़ी जिले में आलू की खेती के विकास की योजना के अन्तर्गत भवन .. .. .	१,२०,०००
४—देहरादून में रिजर्व पुलिस लाइन .. .. .	१८,००,०००
५—बरेली में पी०ए०सी० की आठवीं बटालियन के लिए नया भवन ..	२१,५०,०००
६—कानपुर में पी०ए०सी० की १४ वीं बटालियन के लिए भवन ..	२१,८८,०००
७—लखनऊ के बनारसी बाग स्थित विकास प्रदर्शनी भवन में एक और गृह-पाइव .. .. .	१,००,२८०
८—लखनऊ में प्रोग्रेस म्यूजियम के अहाते में सूचना निदेशालय के कार्यालय के लिए भवन .. .. .	५,२३,०००
९—नयी दिल्ली में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए आवास-गृह (नयी दिल्ली में ३० प्र० निवास) .. .. .	२,१७,७८०
१०—मुजफ्फरनगर में नयी दीवानी अदालत का भवन .. .. .	२,७८,०००
११—मथुरा में नयी दीवानी अदालत का भवन .. .. .	३,२३,७००
१२—एटा में नयी दीवानी अदालत का भवन .. .. .	२,१५,८००
१३—उत्तर प्रदेश में हरिजनो के लिए १० औद्योगिक इलाके स्थापित करने के लिए भवन .. .. .	२७,६०,५५०
१४—जिला नैनीताल में पटवाडांगर में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में कुत्ते के काटे के इलाज के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया के निर्माण की योजना से संबंधित भवन .. .. .	१,४६,६००
१५—लखनऊ में ट्रांसपोर्ट कमिशनर के लिए भवन .. .. .	४,५६,५२५
१६—कानपुर में एक अतिरिक्त क्षय निवारण उपचार-गृह (हरिहरनाथ शास्त्री नगर और बाबू पुरवा में राजकीय श्रम कल्याण केंद्रों के लिए २ भवन तैयार हो चुके थे) .. .. .	७,७८,०००
१७—कानपुर में क्षेत्रीय संराधन कार्यालय के लिए भवन .. .. .	२,६४,०००
१८—श्रम विभाग के अधिकारियों के लिए ७ निवास .. .. .	२,४५,०००
१९—कानपुर में जाजमऊ और जूही तथा मेरठ में गोबिन्दपुरी में श्रम कल्याण केंद्रों के लिए भवन .. .. .	३,१५,०००
२०—फीरोजाबाद, आगरा, सहारनपुर, नैनी (इलाहाबाद) तथा ऐशबाग (लखनऊ) में श्रम कल्याण केंद्रों के लिए भवन .. .. .	५,१६,८००
२१—आई०टी०आई०लखनऊ के लिए भवन .. .. .	३,७४,०००
२२—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोडा .. .. .	४,६१,४७०
२३— " " श्रीनगर .. .. .	५,७६,७४८
२४— " " इलाहाबाद .. .. .	६,११,८००

कार्य का नाम	अनुमानित व्यय
	₹०
२५— औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरेली .. ..	५,०७,४७२
२६— " " आगरा .. ..	४,६१,४७२
२७— " " वाराणसी .. ..	६,११,८००
२८—इलाहाबाद के राजकीय सेंट्रल प्रेस मशीन खंड, मोनोकार्पास्टिंग खंड तथा कागज के लिए गोदाम .. ..	८,८६,०००
२९—गोरखपुर के राजकीय प्राविधिक संस्था में छात्रावास ..	५,७३,८००
३०—लखनऊ में राजकीय प्राविधिक संस्था में छात्रावास ..	५,८५,५००
३१—बरेली और झांसी में नवीन डिप्लोमा संस्थाओं में छात्रावास	७,६५,८३३
३२—इलाहाबाद में मुद्रण कला की शिक्षा देने के लिए उत्तरी क्षेत्रीय स्कूल में छात्रावास .. .. .	१,३८,०००
३३—खुर्जा में मिट्टी के बर्तनों के विकास की योजना से संबंधित भवन	२,१३,१७४
३४—चौबटियां में पर्वतीय फल अनुसंधान स्टेशन के विकास की योजना से संबंधित भवन .. .. .	१,५५,३६०
३५—बरेली तथा झांसी में नवीन डिप्लोमा संस्थाएं आरम्भ करने के लिए भवन .. .. .	१३,६८,४००
३६—गोरखपुर के राजकीय प्राविधिक संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता में विस्तार की योजना से संबंधित भवन .. ..	४,७२,८००
३७—आगरा का औद्योगिक इलाका .. .. .	२२,११,३८०
३८—कानपुर का डिप्लोमा संस्थान .. .. .	१०,७७,०००
३९—गोरखपुर के राजकीय प्राविधिक संस्थान के लिए अतिरिक्त भवन	१,५७,३२०
४०—फतेहपुर के राजकीय प्रशिक्षण स्कूल के लिए भवन ..	१,३१,०००
४१—भीमताल, देहरी, श्रीनगर तथा अल्मोड़ा के पर्वतीय जिलों में छोटे औद्योगिक इलाकों के लिए भवन .. ..	७,००,६००
४२—कानपुर के एच० बी० टी० आई० में अनुसंधान कार्य के लिए अतिरिक्त भवन .. .. .	६,७२,१२१
४३—लखनऊ का राजकीय प्राविधिक स्कूल .. ..	११,५२,०००
सीमेट का कारखाना—	
४४—सिविल इंजीनियरिंग ऐंड फाउन्डेशन वर्क्स .. ..	४३.५२ लाख

### वाराणसी के घाट तथा बाढ़-नियन्त्रण कार्य

पहले चरण की योजना के अन्तर्गत वाराणसी के घाटों पर भरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य जिसकी लागत ५५.१२ लाख रुपये थी पूरा किया जा चुका था। कुछ घाटों, विशेषतया हनुमानघाट की और सुरक्षा होनी थी और इन घाटों के सामने काष्ठभित्तियां बनाने की एक योजना स्वीकृत की गयी। इसका कार्य भी ६० प्रतिशत भाग आलोच्य वर्ष में पूरा हो चुका था।

आलोच्य वर्ष में ५.३५५ लाख रुपये लागत का हल्द्वानी का सुरक्षा कार्य स्वीकृत हुआ और उसे आरम्भ कर दिया गया। १९६० की भीषण बाढ़ के बाद लखनऊ नगर की सुरक्षा



की योजना अत्यावश्यक हो गयी और इस व्यापक योजना को तैयार करने के लिए गोमती नदी के सर्वेक्षण की स्वीकृत दी गयी।

### सामुदायिक परियोजना कार्य

सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा खड मुह्यालयों में आवासिक और अनावासिक भवनों के निर्माण का कार्य किया गया।

वर्ष के आरम्भ में निम्नलिखित खंडों में सभी तरह के भवनों के निर्माण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंप दिया गया।

(१) प्रथम चरण के खंड .. .. .	३०८
(२) द्वितीय चरण के खंड .. .. .	३४
(३) आई०डी०खंड .. .. .	५३

वाद में ८१ और प्रथम चरण के खंडों की स्वीकृति दी गयी और ५३ आई० डी० खंडों में से २५ को द्वितीय चरण वाले खंडों में उनकी विकासावधि समाप्त होने पर परिवर्तित कर दिया गया। वर्षान्त में खंडों की कुल संख्या निम्न प्रकार थी:—

१—प्रथम चरण के खंड में .. .. .	३८६
२—द्वितीय चरण के खंड .. .. .	५६
३—आई० डी० खंड .. .. .	२८

योग .. ४७०

इन खंडों में भवन निर्माण कार्य की प्रगति संतोषजनक रही। आलोच्य वर्ष में १०१ खंड सभी प्रकार से पूरे हो गये थे, १५८ एम० ई०एस० चरण तक पूरे हुए थे और ६४ का कार्य प्रगति कर रहा था। शेष १५३ खंडों में से ११६ का स्थान अंतिम रूप से निश्चित नहीं हो सका था।

खंड मुख्यालयों पर मानव और पशु चिकित्सालयों के निर्माण का कार्य भी सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपा गया था। इन भवनों से संबंधित प्रगति नीचे दी जाती है:—

काम की किस्म	स्वीकृत-संख्या	स्थान अथवा आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं थी।	स्थान अथवा आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध थी पर कार्य नहीं हुआ	जहां कार्य की प्रगति हो रही थी।	कुल खंडों की संख्या
(१) नव-निर्माण ..	१५७	६४	३२	५६	३५
(२) प्राथमिक चिकित्सा केंद्र ..	४७				
(३) भरम्मत और लागत ..	१६०				
(४) परिवार नियोजन शाखा ..	१०				
पशु चिकित्सालय—					
(१) नव निर्माण ..	३७५	२५८	१३	६	६
(२) सुधार ..	६८				
(३) प्राथमिक सहायता चिकित्सालय ..	१७७				
(४) तृतीय श्रेणी के चिकित्सालय ..	४१				

श्रमदान द्वारा निर्मित ५६० मील लम्बी पक्की सड़कों को जो मुख्य सड़कों में जा कर मिलती थीं विभाग ने ठीक से रख-रखाव के लिए अपने अधीन कर लिया ।

### सार्वजनिक निर्माण विभाग अनुसंधान संस्थान

क्षेत्र अभियंताओं द्वारा भेजे गये दिन प्रति दिन के मसलो का सार्वजनिक निर्माण विभाग अनुसंधान संस्थान जाच-पड़ताल करता रहा और परीक्षाफलों के आधार पर प्राविधिक परामर्श देता रहा । वर्ष भर में कई मसलो पर गौर किया गया । प्रयोगशाला कार्य के अतिरिक्त, कड़े नियंत्रण में १ मील जमाई हुई मिट्टी की सड़क का निर्माण किया गया तथा एक मील की लम्बाई में ईंट की भराई 'स्प्रै ग्राट' निर्दिष्टियों सहित की गयी । विभिन्न प्रकार की उपश्रेणी की मिट्टियों की जाच-पड़ताल इस आशय से की गयी थी कि यालायात में वृद्धि होने के फलस्वरूप अधिक भार सहन करने के लिए पक्की सड़कों के ऊपरी परत कितनी मोटाई के हो ।

राष्ट्रीय राजमार्ग के आगरा-मथुरा खंड में सीमेंट की सिलिलियां डलवाने से पहले उपश्रेणी की मिट्टियों का भी परीक्षण किया गया । राष्ट्रीय राजमार्ग रुट नं० २ के मथुरा-आगरा खंड के उपमार्गों की मजबूती की भी जाच की गयी । लखनऊ-मोहान सड़क, बेनी-बरोनी सड़क तथा लखनऊ-सुल्तानपुर सड़क पर निर्माण की लागत में कमी करने के आशय से मिट्टी की जमाई के विभिन्न प्रयोग किये गये ।

लखनऊ जिले के चिनहट तथा अन्य गांवों के बहुत से घरों पर जलारोधों और क्षार न होने वाली मिट्टी का लेप किया गया । बड़े भवनों की भारवहन क्षमता तथा स्थिरीकरण से संबंधित अध्ययन किये गये और इस आशय की संस्तुतियां की गयीं कि वे बिना खतरे के कितना भार सहन कर सकते हैं । राज्य में प्रस्तावित भारी उद्योगों के लिए स्थानों के चुनाव का भी कार्य किया गया ।

विभिन्न भवनों के निर्माण की परियोजनाओं के लिए क्षेत्र में निर्मित ईंटों की कोटि के नियंत्रण का भी कार्य किया गया और राज्य भर के तमाम क्षेत्रों से भगा कर बहुत प्रकार की मिट्टियों का परीक्षण प्रथम श्रेणी की ईंटों का निर्माण करने वाले भट्टों को लगाने के लिए किया गया । इतनी कड़ी ईंटों को जो पत्थर की गिट्टियों की जगह ले सकें बनाने के संबंध में अध्ययन जारी रहा । बांदा जिले की संकुचित होने योग्य मिट्टियों से अच्छी ईंटों के निर्माण के लिए क्षेत्र प्रयोगों की भी संस्तुति की गयी ।

विभिन्न चूने-गारे और कंकरीटों में कड़ापन लाने के लिए उनमें सीमेंट का कितना अंश हो, इसी की खोजबीन में विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला सलग रही । वर्ष भर में २५ नमूनों का विश्लेषण किया गया । उत्तर प्रदेश के विभिन्न वर्गों के पत्थरों का प्रयोगशाला तथा क्षेत्र प्रक्रिया को सहसम्बद्ध करने का कार्य किया गया और यह निश्चय किया गया कि आगामी वर्ष में एक मील में लगभग ३० विभिन्न पत्थरों को एक ही में शामिल किया जाये ।

विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों के लिए, जिनमें आगरा जिले से आगरा-मथुरा रोड पर सीमेंट कंकरीट बिछाना शामिल था, सीमेंट कंकरीट के सम्मिश्रण तैयार किये गये । पहाड़ियों पर सफेद चूने का धीरे-धीरे जमाव, चिकनी मिट्टियों से सुर्खों का निर्माण तथा नीच की कंकरीट में बालू के स्थान पर चिकनी मिट्टियों तथा सीमेंट के स्थान पर सुर्खों को उपयोग में लाने के संबंध में भी कार्य आरम्भ किया गया ।

सन् १९५८-५९ में १,११२ नमूनों तथा सन् १९५९-६० में १,५५२ नमूनों की तुलना में इस वर्ष १,६६० नमूनों का परीक्षण किया गया ।

आलोच्य वर्ष में क्षेत्रीय अनुसंधान के लिए एक छोटी-सी संस्था कायम की गयी । कई क्षेत्रीय प्रयोग आरम्भ किये गये । इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य था ऐसी कड़ी ईंटों का निर्माण जो बहुत कम पानी सोखती हो । बूल के भट्टे तथा चिनहट में नीचे के खिंचाव वाले भट्टे पर प्रयोग पूरे पैमाने पर किये गये और ऐसी ईंटों का निर्माण किया गया जो बहुत कम पानी सोखती थी ।

## सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास

सीमावर्ती क्षेत्र में निर्माण-कार्य के लिए अतिरिक्त मुख्य अभियंता का पद अगस्त, १९६० से एक पद सृजन किया गया। सीमावर्ती क्षेत्र योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए तीन मंडल और ६ कार्यकारी डिवीजनों की स्वीकृति दी गयी। सीमावर्ती क्षेत्र योजनाओं के लिए एक ब्रिज डिजाइन डिवीजन तथा एक एलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल डिवीजन के निर्माण की भी स्वीकृति दी गयी।

आलोच्य वर्ष में अधिकांश प्रयास नयी योजनाओं के सर्वेक्षण तथा उन्हें अंतिम रूप देने की ओर ही किये गये। लगभग १ दर्जन मोटर सड़कों का निर्माण और सड़कों का उन्नयन तथा उन्हें सज्जत करना कार्य के मुख्य अंगों में सम्मिलित थे। इन सड़कों का सामरिक अथवा आर्थिक महत्व था और आलोच्य वर्ष में इस संबंध में किया गया कुल खर्च लगभग ३६.५ लाख रु. था।

पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तरकाशी में जिला मुख्यालय स्थापित करने के निमित्त तबई आवास निर्माण का कार्य भी जिसमें परिवर्तन तथा परिवर्धन सम्मिलित थे प्रारम्भ किया गया और इस कार्य पर कुल मिला कर लगभग १४ लाख रुपये व्यय हुए।

कतिपय विविध सड़कों के तथा भवन निर्माण परियोजनाओं का भी कार्य किया गया और उन पर कुल मिला कर लगभग १६.५ लाख रुपये का खर्च बैठा। सर्वेक्षण के लिए तथा सड़क निर्माण के लिये १२ लाख रुपये की लागत की विशेष सामग्री भी क्रय की गयी।

### वास्तु संबंधी खंड

राष्ट्रीय महत्व और महान जन सेवा संबंधी बहुत से महत्वपूर्ण भवनों की रूपरेखा वास्तु संबंधी शाखा ने तैयार की। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को वास्तु संबंधी परामर्श, रिपोर्ट, सार तथा कार्य की उच्च कोटि की प्राविधिक निरीक्षा एवं प्राविधिक सलाह भी दी गयी।

आलोच्य वर्ष में जिन विभिन्न योजनाओं के संबंध में रूपरेखाएं तैयार की गयीं वे करीब ६ करोड़ रुपये के मूल्य की थीं।

वित्तीय पक्ष—१९६०-६१ में विभाग द्वारा प्राप्त धनराशि कुल १,६६,१७,२०० रुपये थी।

१९६०-६१ में विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत व्यय के अंतिम अनुदानों की सख्याएँ निम्न प्रकार थीं—

	रु०
(१) मौलिक भवन निर्माण-कार्य .. .. .	३,८६,६७,०००
(२) भवनों की मरम्मत .. .. .	१८,२४,६००
(३) सड़कों मौलिक निर्माण-कार्य .. .. .	४,२४,१८,७००
(४) सड़कों की मरम्मत .. .. .	३,६५,१३,७००
(५) विविध-मौलिक निर्माण-कार्य .. .. .	५,१८,१००
(६) विविध-मरम्मत .. .. .	५,००,६००
(७) राष्ट्रीय राजमार्ग-मौलिक निर्माण-कार्य .. .. .	१,७१,६१,२००
(८) राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत .. .. .	५२,६७,०००
(९) शरणार्थियों का कार्य .. .. .	७६,६०,१००
(१०) बाढ-नियंत्रण कार्य .. .. .	१५,००,०००
(११) सामुदायिक परियोजना कार्य .. .. .	६०,७५,०००
(१२) ५४ अकाल सहायक कार्य .. .. .	१४,४३,०००
(१३) मिर्जापुर की सीमेंट फैक्ट्री और इलाहाबाद का अर्ध कुम्भ मेला .. .. .	२२,६७,०००
(१४) सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कों .. .. .	३०,६१,७००

योग .. १६,८२,३८,०००

## २-यातायात राजकीय रोडवेज

### (१) सेवाओं का विस्तार

राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह व्यवस्था की गयी थी कि उत्तर प्रदेश में रोडवेज सेवाओं का ४६४ अतिरिक्त मीलो में विस्तार किया जाय (अर्थात् कुल मिलाकर रोडवेज सेवाएं ६,९६४ मीलो की हो जायेंगी)। १०१ डीजल बसों, औजारों, संपन्नो, फर्नीचर, सज्जा के क्रय पर तथा भूमि की अध्याप्ति एवं भवनो के निर्माण पर ८५.५ लाख रुपया मलबन व्यय करके यह व्यवस्था की गयी। मार्च, १९६० के अन्त तक राज्य में रोडवेज सेवाओं का विस्तार ७,७३५ मीलो में हो चुका था। १९६०-६१ में रोडवेज सेवाओं का विस्तार ३२ अन्य मार्गों पर हो चुका था। रायबरेली-भोजपुर, रायबरेली-ऊंचाहार, कानपुर-गजनौर, लखीमपुर-ऐटा, शाहगंज-दोस्तपुर, कानपुर-बेलाबपूना, आजमगढ़-आमला, आजमगढ़-निजामाबाद, अतरौलिया-चांदपुर, नागल-विजनौर, आजमगढ़-मझवारा तथा कुठार-मैलानी मार्ग इन मार्गों में से प्रमुख थे जिन पर केवल राजकीय बसें ही चल सकती थीं। कानूनी कठिनाइयों के कारण मथुरा-गोवर्धन-बरसाना, कानपुर-बिठूर तथा सहारनपुर-दिल्ली मार्गों पर, पूर्वगामी वर्ष में यद्यपि अंतिम रूप से उन्हें अभिसूचित किया जा चुका था, केवल राजकीय बसें चलाना संभव न हो सका और इन मार्गों पर निजी चालकों की बसों के साथ राजकीय बसों का चलना जारी रहा। मार्च, १९६१ के अन्त तक राजकीय बस सेवाएं ६४० मार्गों पर उपलब्ध थीं और इनके द्वारा ८,३३५ मील की सड़कों का ३५,३११.६ मार्ग मीलो में कार्य किया जा रहा था।

### (२) भूमि की अध्याप्ति तथा भवनो का निर्माण

१९६०-६१ में मोदीनगर, वाराणसी (गोलगढ़ी), सराय आकिल, मुखरायां, मेंहदावल, नौगढ़, बखरावां, कादीपुर, रामपुर, हसनपुर और चुन्नीगंज (कानपुर) में बस-स्टेशनों तथा कारखानों का निर्माण करने के लिए भूमि की अध्याप्ति की गयी। सिकन्दराबाद, दवरी, पुरकाप्पे, मेरठ, कुलपहाड़, फर्रुखाबाद, सहसवान, सुल्तानपुर, बांसी, जगनेर, फरीह, फतेहपुर सीकरी, मोहम्मदी, रानीखेत, और पवाया में बस स्टेशनों तथा रानीखेत बस स्टेशन तथा कारखानों का निर्माण कार्य पूरा हो गया। लखीमपुर, शाहाबाद, मुरादाबाद, चन्दौसी और फंजाबाद में बस स्टेशनों पर तथा कानपुर की क्षेत्रीय वर्कशाप में कैंन्टीनो का निर्माण किया गया। आजमगढ़, ऊजरघाट, बदायूँ, मुजफ्फरनगर और रायबरेली में फोरमैनो के रहने के लिए क्वार्टर बनाये गये। वाराणसी में सहायक जनरल मैनेजर के कार्यालय के लिए भवन निर्माण कार्य भी पूरा हो गया। इसके अतिरिक्त कई बस स्टेशनों और कारखानों में अतिरिक्त निर्माण कार्य किया गया।

कानपुर की सेंट्रल वर्कशाप में मरम्मत कोशेड, स्टील यार्ड, सहायक ट्रेड शेड का निर्माण, पुराने लेखा विभाग को प्रशिक्षण केन्द्र का रूप देना, काम्प्रेसर कमरे का विस्तार और धुलाई की मशीन पर एक सायबान का निर्माण, मर्सीडीज और लेलैन्ड बसों के लिए सायबान का निर्माण तथा शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा किया गया।

### (३) रोडवेज की वर्कशापें

सम्पूर्ण राज्य में रोडवेज की वर्कशापों का जाल फैला हुआ था। कानपुर की केन्द्रीय वर्कशाप में अतिरिक्त ८ क्षेत्रीय तथा ४८ डिपो वर्कशापें थीं। कानपुर की केन्द्रीय वर्कशाप में ४६२ इंचों को फिर से नया किया गया और १२३ इंचों की लामियां दूर कीं और रोडवेज

विभाग के लिए गाड़ियों के ढांचे तथा अन्य सरकारी विभागों के लिए ६४ गाड़ियां के ढांचे तैयार किये गये ।

बाजार में बैटरिया कठिनाई से प्राप्त होने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए वर्कशॉप में बैटरियों के निर्माण तथा उनके मरम्मत का कार्य प्रारम्भ किया गया । आलोच्य वर्ष में सेन्ट्रल वर्कशॉप में ८७३ बैटरियों का निर्माण किया गया तथा ३०६ पुरानी बैटरियों को फिर नया किया गया । इसके अतिरिक्त ६७,८३५ बैटरी प्लेटों का भी निर्माण किया गया ।

कालपी रोड, कानपुर में एक नयी टायर रिट्रीडिंग शाखा स्थापित की गयी । वर्ष में ३,१८१ टायरों की रिट्रीडिंग की गयी, जिससे ४ लाख रुपये से अधिक की बचत हुई ।

केन्द्रीय वर्कशॉप में एक स्टोर शाखा भी थी, जिसने रोडवेज के लिए फालतू पुर्जों तथा अन्य सामान स्टोर सामग्रियों की थोक खरीद की । आलोच्य वर्ष रोडवेज के लिए १,४१,४५,२६५.७५ रुपये का सामान खरीदा गया ।

केन्द्रीय वर्कशॉप ने मरम्मत के भारी काम जैसे इंजिनो के नवीनीकरण और इंजिनो की गड़बड़ियों के सुधार का काम शुरू किया, जबकि क्षेत्रीय और डिपो वर्कशॉप ने मामूली मरम्मत और मोटर गाड़ियों के रखरखाव का काम किया । क्षेत्रीय वर्कशॉपों में पुराने और घिसे-पिटे फालतू पुर्जों को पुनः गाड़ियों में इस्तेमाल करने के योग्य बनाया गया । इससे १६६०-६१ में लगभग २ लाख रुपये की बचत हुई ।

#### (४) नगर बस सर्विस

राज्य की पंच महानगिरयो—आगरा, इलाहाबाद, बरेली, लखनऊ और वाराणसी में रोडवेज नगर बस सेवाएं चला रही थीं । इन सेवाओं के फलस्वरूप सस्ते और द्रुतगामी यातायात की व्यवस्था हो सकी और यह सेवा निरन्तर लोकप्रिय होती गयी । वर्ष १६५६-६० में नगर सेवाओं का उपयोग २,३७,६६,२४७ यात्रियों ने और आलोच्य वर्ष में २,६५,८३,६१० (अर्थात् २४ प्रतिशत) यात्रियों ने किया ।

#### (५) ट्रक और टैक्सि

गढ़वाल और कुमाऊं उप-क्षेत्रों में रोडवेज की नियमित ट्रक सेवा आरम्भ की गयी । १६६०-६१ के वर्ष में रोडवेज की ट्रकें १२,५१,३६४.७ मील चलीं और १५,५३,६८८ रुपये का राजस्व अर्जित किया । उसी अवधि में उत्तर प्रदेश सरकार के रोडवेज सगठन की टैक्सिया विभिन्न क्षेत्रों में ६,४१,६६५ मील चलीं और ३,६७,४८७ रुपये का राजस्व अर्जित किया ।

#### (६) विशेष अवसरों के लिए व्यवस्था

पहले की भांति मेलों और राष्ट्रीय महत्व के उत्सवों तथा राज्य में विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे जैसे विशेष अवसरों पर यातायात सुविधा प्रदान की गयी । वर्ष के दौरान में आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों में महारानी एलिजाबेथ और हिज रायल हाइनेस, ड्यूक आफ एडिनबरा का आगरा और वाराणसी का दौरा और हिज मैजिस्टी किंग आफ मोरक्को का आगरा का दौरा सम्मिलित हैं । ससद सदस्यों को लखनऊ, इलाहाबाद, मिर्जापुर, कानपुर और झांसी की विकास परियोजनाओं तक लाने ले जाने के लिए, स्थायी समिति के सदस्यों को लखनऊ की राजकीय सूक्ष्म यंत्र कारखाने के दौरे के समय, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थानों के दौरे के संबंध में, जन-कल्याण समिति, टाटानगर के लिए, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ और मथुरा जाने वाली 'भारत दर्शन दल' के निमित्त, कुरनूल राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय के छात्रों और अध्यापकों के हरद्वार, वाराणसी, आगरा और लखनऊ के दौरे के अवसर पर, बिहार राज्य के पंचायतो के मुखियों और सरपंचों को उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों को दिखाने के सिलसिले में तथा

विश्व बैंक संगठन के सदस्यों के लिए वाराणसी के दौरे के वक्त यातायात की विशय व्यवस्था की गयी। रेल मंत्री द्वारा चोपन रेल पुल के शिलान्यास के सिलसिले में यातायात की उपयुक्त व्यवस्था की गयी।

### (७) टेक्नीशियनों की ट्रेनिंग

कानपुर केन्द्रीय वर्कशाप में स्नातको, डिप्लोमा होल्डरों, मैकेनिकों आदि की ट्रेनिंग जारी रखी गयी। ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद उन्हें रोडवेज वर्कशाप संगठन में खपा लिया गया। अलोच्य वर्ष में केवल एक डिप्लोमा होल्डर और १० मैकेनिकों को ट्रेनिंग पाठ्यक्रम में भर्ती किया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधिक डिप्लोमा होल्डर अन्यथा उपलब्ध नहीं हुए। कई अवैतनिक अपरेटिवों को रोडवेज वर्कशाप में ट्रेनिंग लेने की अनुमति दी गयी। इस योजना से प्राप्ति की जाती थी कि रोडवेज की वर्कशापों के रिक्त स्थानों के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की उपलब्धि में सहायता मिलेगी। प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए प्राविधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को जर्मनी और ब्रिटेन विशेष प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। इनको भेजने का खर्च क्रमशः डैनलरवेज और सर्वथो प्रशोक लैलन्ड लिमिटेड द्वारा वहन किया जाना था। उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष में ६ टेक्नीशियनों ने जर्मनी में ट्रेनिंग प्राप्त की और ४ टेक्नीशियनों ने ब्रिटेन में ट्रेनिंग ली।

इंडस्ट्रियल सेन्टीनेन्स प्राइविटिटी तथा कास्ट एशउन्टेसी की राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् के दल के सदस्यों के रूप में रोडवेज के उप परिवहन आयुक्त और मुख्य लेखा अधिकारी क्रमशः ब्रिटेन, अमरीका और पश्चिमी जर्मनी गये।

### (८) कर्मचारी पारितोषिक योजना

डाइवरो और टेक्नीशियनों को कुशल कार्य संचालन के लिए पारितोषिक देने की योजना के अच्छे परिणाम निकले। १९६०-६१ के वर्ष में डाइवरो और टेक्नीशियनों को इजिन, बैटरी और टायरो के कुशल प्रयोग, तेज और मोबिल आयल के प्रति गैलन से अपेक्षाकृत अधिक मीलो की यात्रा करने और टूट-फूट कम करने के साथ में ५३,००० रुपये के पारितोषिक देने की स्वीकृत दी गयी।

इसके अतिरिक्त मेलो और प्रदर्शनियों के अवसर पर परिश्रम और कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए मानदेय प्रदान करने के निमित्त ४५,००० रुपये की स्वीकृत दी गयी।

### (९) कल्याण-कार्य

रोडवेज कर्मचारियों के लिए मनोरंजन तथा कल्याण कार्यों का संगठन प्रत्येक क्षेत्र में कमरे में खेले जाने वाले तथा मैदानी खेलों, गीत समारोहों और क्षेत्रीय खेलकूद आयोजनों के माध्यम से किया गया। कानपुर केन्द्रीय वर्कशाप में कर्मचारियों के कल्याण की देखभाल के लिए एक पूर्णकालिक श्रम-कल्याण अधिकारी काम करता रहा। कतिपय प्रमुख बस स्टेशनों पर डाइवरो के लिए रनिंग रूम की व्यवस्था थी। विभिन्न स्थानों पर टेक्निकल कर्मचारियों के लिए आवास क्वार्टरों की व्यवस्था के प्रश्न पर ध्यान दिया जा रहा था। काम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को संकट के समय सहायता देने के लिए एक धर्मादानिधि चलायी गयी थी, जिसमें संगठन के अधिकारियों ने स्वेच्छापूर्वक धन दिया।

### (१०) क्षेत्रीय परामर्शदाता समितियां

प्रत्येक क्षेत्र में क्षेत्रीय परामर्शदात्री समितियां थीं, जिनमें असरकारी सदस्य सम्मिलित थे। इन समितियों ने यात्रियों को सुविधाएं देने, टाइमटेबुल, रोडवेज सेवाओं की पर्याप्त व्यवस्था आदि के विषयों पर विचार किया, ताकि संगठन के कार्य संचालन में सुधार हो सके।

## अधिनियम और नियमों का प्रशासन

१९६०-६१ में उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कर नियम, १९३५ के नियम ३५ में इस आशय का सुधार किया गया कि यातायात विभाग के कर अधिकारियों को यह अधिकार दिया जा सके कि वे इस बात से संतुष्ट हो कि किसी मोटर गाड़ी का प्रयोग कप से कम इतनी महीने की अवधि में नहीं किया गया है, जबकि कर किस्त आखिरी बार अदा की गयी थी, तो वह कर के बकाये को साफ कर दें। इस व्यवस्था से वास्तविक कठिनाइयों में फसे लोगों को आवश्यक सुविधा मिल सकी।

### मोटर गाड़ी उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक

परिवहन विभाग की इंफोर्समेंट शाखा के पुनर्गठन के फलस्वरूप इस शाखा में काम करने वाले पुलिस कर्मचारियों के स्थान पर विभाग द्वारा प्रशिक्षित और भर्ती किये गये कर्मचारियों को नियुक्त किया गया। अपराध विधि संहिता के अधीन खानातलाशी, अभियुक्तों की गिरफ्तारी, जमानत लेने तथा मुकदमा चलाने के संबंध में पुलिस कर्मचारियों को पर्याप्त अधिकार दिये गये। मोटर गाड़ी अधिनियम की व्यवस्थाओं और उनके अधीन बनाये गये नियमों के प्रभावी प्रशासन को सुनिश्चित करने और कुशल कार्य संचालन के हित में यह आवश्यक समझा गया कि पुलिस कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अधिकारों को सिविलियन कर्मचारियों को दिया जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य विधान मंडल में मोटर गाड़ी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६० प्रस्तुत किया गया।

### रजिस्ट्री, लाइसेंस देना और कर-निर्धारण

वर्ष में क्षेत्रीय कार्यालयों ने राज्य में ७,३०० मोटर गाड़ियों की रजिस्ट्री की या उन्हें नया रजिस्ट्री चिन्ह दिया। इन कार्यालयों ने ८,३२४ नये ड्राइविंग लाइसेंस जारी किये और ३७,३६१ मौजूदा लाइसेन्सों को नया किया। आलोच्य अवधि में उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कर निर्धारण विभाग अधिनियम, १९३५ और इसके अधीन नियमों के अन्तर्गत सड़क कर और अन्य शुल्कों के रूप में २,८१,५५,८१४ रुपये ३० न० पै० की धनराशि संग्रह की गयी।

### यातायात नियन्त्रण

राज्य की पंचवर्षीय योजना के अधीन विकास कार्यों के लिए परिवहन की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के हेतु मोटर गाड़ियों का एक पर्याप्त बड़ा दस्ता तैयार करने के उद्देश्य से राज्य में निजी बस चालकों को रोड परमिट जारी करने में उदारता की नीति बरती गयी।

राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब के पड़ोसी राज्यों से अंतर्राज्यीय परिवहन व्यवस्था करने के लिए पारस्परिक प्रबन्धों का निर्णय किया गया। मार्च, १९६१ के अंत में निजी क्षेत्र में ११,२६६ पब्लिक कैरियर, १,७६४ प्राइवेट कैरियर, ३,६६६ स्टेज कैरिज और ४६५ कट्रेक्ट कैरिज थे जिसमें टैक्सिया भी थीं।

### द्राफिक का नियन्त्रण

आलोच्य अवधि में सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (इंफोर्समेंट) की अध्यक्षता में पुनर्संगठित परिवहन संगठन की इंफोर्समेंट शाखा ने मोटर गाड़ी अधिनियम और नियमों की व्यवस्थाओं के उल्लंघन के २१,६६१ मामलों का पता लगाया। अवधि के आरम्भ में ६,६६० मामले निपटारे के लिए बचे हुए थे। ट्रान्सपोर्ट मंत्रिस्ट्रेट की अदालत में प्रस्तुत किये गये मामलों में से १७,०५७ में दंड दिया गया और १२७ मामलों में बरी किया गया। २६७ मामलों में अपराधियों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया और २४२ मामले दायर किये गये।

अदालत के जुर्मानों के रुपये में ८,४६,८३५ रुपये की धनराशि वसूल की गयी। इन्सफोर्समेंट दस्तों ने अपने क्षेत्रों में मेलों और उत्सवों पर 'आत्मरक्षा प्रथम' अभियान भी चालू किया ताकि जनता सड़क पर चलने के उचित तरीकों से अवगत हो सके और इस प्रकार सड़क दुर्घटनाओं में कमी हो।

### नागरिक उड्डयन

हिन्द प्रॉविशियल फ्लाईंग क्लब ने लखनऊ मुख्यालय और इलाहाबाद कानपुर तथा वाराणसी की शाखाओं के जरिये अपना कार्य जारी रखा। यह क्लब भारत में प्रथम कोटि के वर्ग में रजिस्टर्ड है और पिछले कई सालों से देश में सबसे ऊँची उड़ान करता रहा है।

आलोच्य वर्ष में इस क्लब ने दिसम्बर, १९६० तक कुल ४,०८५.४५ घंटे की उड़ानों की जिसमें ३,४१६.२० घंटे की इंस्ट्रक्शनल उड़ान भी शामिल थी। दिसम्बर, १९६० के अन्त तक क्लब में ४६० सदस्य नामजद थे, जिनमें से ३१६ उडाकू सदस्य थे। क्लब में ८० छात्र-पाइलट (वायुयान-चालक) थे। वर्ष में (दिसम्बर, १९६० तक) नागरिक उड्डयन के डायरेक्टर जनरल ने १७ प्रशिक्षार्थियों को 'ए' लाइसेंस और ४ को 'बी' लाइसेंस प्राप्त हुए।

क्लब में ४२ वायुयानों का दस्ता था, जिसमें ११ पाइपर कब, १० एल-५, ८ चिपमंक, ४ ब्रीचक्रैफ्ट बोनाजार, ३ पाइपर सुपरक्रूजर, २ ट्रिवन ब्रीचक्रैफ्ट और एफ-एफ सिलवेस्टर, एक्स्पेडीटर, एयरो-४५ और प्राक्टर वायुयान सम्मिलित थे।

लखनऊ में गोमती की बाढ़ के अवसर पर बाढ़ में फसे लोगों के लिए खाने के पैकेट गिराने का काम भारतीय हवाई दस्तों के साथ-साथ क्लब को भी सौंपा गया। इस अवसर पर इसने जनता की सराहनीय सेवा की।



## अध्याय ५

### जन स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं

#### ३-जन-स्वास्थ्य\*

महामारी इत्यादि—राज्य ताऊन के प्रकोप से मुक्त रहा। इस रोग से संबंधित विश्व स्वास्थ्य संगठन ताऊन परियोजना जारी रही और उसके अन्तर्गत सभी ऐसे क्षेत्रों में जहां चूहों के मरने आथवा ताऊन से मनुष्यों के पीड़ित होने का समाचार मिला, विस्तृत जांच-पड़ताल की गयी। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को रोग के नियंत्रण में रखने से संबंधित परामर्श दिया गया।

पूर्वगामी वर्ष से अधिक इस वर्ष हंजे का प्रकोप रहा। रोग की रोकथाम के लिए सभी संभव निरोधक उपाय अपनाये गये। राज्य में लगने वाले बड़े मेलों में और कंदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री तथा यामनोत्री के तीर्थ मार्गों पर जाने वाले सभी यात्रियों को हंजे का निरोधक टीका लेना अनिवार्य कर दिया गया। ७१,२४,३०० से भी अधिक हंजा-निरोधक टीके लगाये गये।

चेचक का प्रकोप न अधिक न कम रहा। राज्य भर में प्रारम्भिक टीके तथा फिर से टीके लगाने का काम जारी रहा।

१ सितम्बर, १९६० से सुल्तानपुर में चेचक से मुक्ति पाने के लिए एक अग्रगामी परियोजना प्रारम्भ की गयी। इस परियोजना का मुख्य ध्येय यह था कि चेचक के मूलोच्छेदन के प्रयत्न बाकायदा टीके लगा कर और फिर से टीके लगा कर पहले एक जिले में किये जाय और इस प्रकार प्राप्त अनुभवों के आधार पर तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में चेचक की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए सामूहिक रूप से प्रयत्न किया जाये।

#### मलेरिया नियन्त्रण

जहां तक मलेरिया का संबंध है, राज्य में स्थिति सामान्य रही। स्थानीय मलेरिया की रोकथाम के लिए ४० यूनिटों ने अर्ध-स्थानिक मलेरिया की रोकथाम के लिए २७ यूनिटों ने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष भर काम जारी रखा।

निम्नलिखित विवरण में इन यूनिटों द्वारा १९६० में किये गये कार्यों के लक्ष्य एवं उपलब्धियां दी गयी हैं:—

	उपलब्धियां		
	लक्ष्य	पहला दौर	दूसरा दौर
(क) स्थानिक मलेरिया यूनिटें—			
१—गांवों की संख्या ..	५९,४५८	५९,४५८	५८,८२४
२—मकानों की संख्या ..	८४,०६,६५६	७९,२८,६५६	८०,३५,१६९
३—आबादी ..	४,१०,१७,३३७	३,८५,६७,४१०	३,९१,०३,८६१

\* यह १९६० के कैलेंडर वर्ष से संबंधित है।

उपलब्धियाँ				
		लक्ष्य	पहला दौर	दूसरा दौर
(ख) अर्थ-स्थानिक मलेरिया यूनिटें				
(१)	गावों की संख्या	४२,६००	४२,८५०	..
(२)	मकानों की संख्या	५२,१८,६८४	५०,४५,३८८	..
(३)	आबादी	२,६६,५८,२०६	२,५६,१८,६२२	..

अक्टूबर के महीने में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, सलतानपुर और रायबरेली के जिलों में भारी बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्रों में एक बार पुनः छिड़काव करना पड़ा क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में बाढ़ का पानी खिलकने के बाद मलेरिया फैलने की बड़ी आशंका थी। सरकार ने लखनऊ शहर के लिए ४४५ लाख रुपये और अन्य जिलों के बाढ़-प्रभावित क्षेत्रों के लिए, एक लाख रुपये की धनराशि बाढ़ हटने के बाद सकावक रोगों के नियंत्रण कार्यों के संपादन हेतु स्वीकृत की। भारतीय रेल कास्ट नोसाइटों से बाढ़-पहायता उपायों के लिए ६०,००,००० रुपये का एक अनुदान स्वीकृत किया गया। इन उपायों के फलस्वरूप इन अप्रत्याशित बाढ़ों के हटने के बाद कोई सकावक रोग नहीं फैला।

लखनऊ में भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र मलेरिया-निरोध समन्वय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मलेरिया के उन्मूलन संबंधी सीमा क्षेत्रीय समस्याओं पर व्यापक रूप से विचार विमर्श किया गया।

### फाइलेरिया फील पांच

वर्ष में फील पांच नियंत्रण की आठ यूनिटें तथा सर्वेक्षण करने वाली तीन यूनिटें काम करती रहीं। सर्वेक्षण यूनिटों ने उनके लिए निर्धारित जिलों का सर्वेक्षण पूरा किया। इन यूनिटों को नये जिले निर्धारित किये जा रहे थे और उनका मुख्यालय भी कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद को स्थानान्तरित किया जा रहा था ताकि निश्चित किये गये नये जिलों का प्रभावी अधीक्षण किया जा सके।

### बतौड़

बतौड़ के मामलों की दवादारु के लिए मिर्जापुर जिले के दक्षिणी भाग में एक सचल दल काम करता रहा। आलोच्य वर्ष में इस यूनिट ने १३८ गावों का दौरा किया और ५,०८७ भांगले बतौड़ के ४४५ सूजाक के और २,१३२ 'कन्टेक्ट' के मामलों का इलाज किया।

### बी० सी० जी०

तपेदिक के नियंत्रण के लिए रोकथाम के उपाय जारी रखने की ओर ध्यान दिया जाता रहा। राज्य के १५ जिलों में १६ बी० सी० जी० के दल काम करते रहे। कुल मिलाकर १६,४३,२५४ व्यक्तियों का क्षय रोग संबंधी परीक्षण किया गया और उनमें से ५,२५,०५२ को बी० सी० जी० के टीके लगाये गये।

### मातृ एवं शिशु कल्याण

प्रारम्भिक स्वास्थ्य यूनिट के अन्तर्गत ३६२ अन्य केन्द्रों के खोलने की स्वीकृति दी गयी। इस प्रकार राज्य में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्रों की संख्या बढ़कर १,५३६ हो गयी। इन केन्द्रों

के अधीक्षण के लिए प्रत्येक प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक स्वास्थ्य निरीक्षिका और जिला स्तर पर एक निरीक्षिका की व्यवस्था थी। दो क्षेत्रीय मातृ एवं शिशु कल्याण अधिकारियों की भी व्यवस्था की गयी। प्रशिक्षार्थियों की कम उपलब्धियों के कारण मुरादाबाद और देहरादून परिवारिका और मिडवाइफ प्रशिक्षण केन्द्रों को बन्द कर देना पड़ा। वर्ष में सहायक परिवारिका और मिडवाइफ के प्रशिक्षण के १० केन्द्र काल करते रहे। इन केन्द्रों में भी अभ्यर्थियों की भर्ती संख्या उपलब्ध स्थानों की तुलना में काफी कम थी। स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं के तीनों प्रशिक्षण केन्द्रों में १८० स्थान उपलब्ध थे, जबकि भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या १०३ थी।

प्रत्येक मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र में चार ग्रामीण दाइयों के प्रशिक्षण और प्रशिक्षण अभ्यर्थी में उन्हें छात्र बतलाने की व्यवस्था थी। यह अनुभव किया गया कि केन्द्र के बिल्कुल पड़ोस में प्रैक्टिस करने वाली दाइयों के प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद इस योजना में अभ्यर्थियों की भर्ती संख्या घट गयी। वर्ष में भारत सरकार के अनुरूप एक योजना भी, जिसमें व्यापक क्षेत्र आते थे, जारी रखी गयी।

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय शिशु संकट निधि (यूनीसेफ) द्वारा प्रदत्त सलाई रहित दूध का पाउडर भायी और दूध पिलाने वाली माताओं और बड़ी संख्या में बच्चों को मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्रों, औषधालयों, चिकित्सालयों आदि के माध्यम से दिया गया। गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताओं को जिनकी पारिवारिक आय १०० रुपये मासिक से कम थी, सलाई युक्त दूध सप्लाई करने की योजना ११ जिलों के चुने हुए गांवों और १४ नगरों में चालू रही। इस योजना के अधीन प्रजनन के ६ सप्ताह पूर्व से छः सप्ताह बाद तक ऐसी महिलाओं को प्रति महिला एक पौण्ड की दर से सलाई युक्त दूध सुपत सप्लाई किया जाता रहा।

### परिवार नियोजन

परिवार नियोजन की विद्या में काफी ध्यान दिया जाता रहा। आरम्भ में भारतीय रेडक्रास सोसाइटी द्वारा १९५१ में राज्य में स्थापित परिवार नियोजन उप-समिति के माध्यम से नियोजित पितृत्व की योजना का संगठन किया गया। सोसाइटी अब आठ केन्द्रों का संचालन कर रही थी। चूंकि जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए परिवार नियोजन आवश्यक समझा गया, अतएव राज्य ने भारत सरकार की सहायता से अतिरिक्त केन्द्र खोले। वर्ष के अंत में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत केन्द्रों की संख्या नगरों में २५ और ग्रामीण क्षेत्रों में १५० थी।

वर्ष में परिवार नियोजन की ट्रेनिंग के लिए सरकार ने चार लेडी डाक्टरों को बम्बई के परिवार नियोजन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्था में भेजा।

परिवार नियोजन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने जिन तीन अवैतनिक शिक्षा नेताओं की नियुक्तियाँ की थीं, उन्होंने प्रत्येक के लिए नियत पांच जिलों में काम जारी रखा।

रेडक्रास की परिवार नियोजन उप-समिति के नियोजन अन्वेषणालय की सहायता से एक अग्रगामी परियोजना चालू की, जिसका उद्देश्य यह अध्ययन करना था कि किस प्रकार परिवार नियोजन को अधिकाधिक लोगों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाय। इसके परिणाम स्वरूप जहाँ अभी तक केवल महिलाओं को परिवार नियोजन संबंधी मशविरा दिया जाता रहा, वहाँ पुरुषों को भी सलाह देना शुरू किया गया और इसके लिए रेडक्रास और सरकार द्वारा संचालित कुछ केन्द्रों में पुरुष सामाजिक कार्यकर्ता नियुक्त किये गये।

भारत सरकार ने एक परिवार नियोजन प्रशिक्षण सचल दल और एक परिवार नियोजन ओरिएण्टेशन दल की स्वीकृत दी। इसमें से पहले दल का काम सभी श्रेणियों के चिकित्साय और जन-स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना था और दूसरा दल विभिन्न स्थानों में त्रिविधसीय शिविर आयोजित करके सामान्य जनों का ओरिएण्टेशन करने के लिए था।

राज्य में सरकार तथा संगठनों द्वारा संचालित परिवार नियोजन केन्द्रों के कार्यों के विवरण नीचे दिये गये हैं:—

(१) व्यक्तियों की संख्या जिनसे संबंध स्थापित किया गया	६३,२८,०००
(२) व्यक्तियों की संख्या जिन्हें सलाह दी गयी	२१,६८१
(३) (क) प्रदर्शनियों की संख्या	२४
(ख) प्रदर्शनियों में उपस्थित	१०,०००
(४) सेमिनार	१५०
(५) निर्वाजीकरण—	
(क) पुरुष	७३३
(ख) महिलाएं	२,५४७
(६) गर्भ-निरोधक उपकरणों का वितरण—	
(क) डायफ्राम और जेली	१,८०१
(ख) शीट्स	३,१०२
(ग) फोम टेबलेट	११,८४६

### ग्रामीण स्वास्थ्य

नियोजन अन्वेषणालय की ग्रामीण स्वास्थ्य शाखा पहले की भांति स्वास्थ्य सुधार के प्रयत्नों के सबंध में उल्लेखनीय योग देती रही। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिल कर इस शाखा ने पर्यावरण स्वच्छता परियोजना और स्वास्थ्य शिक्षा परियोजना नामक दो परियोजनाएं शुरू कीं। पर्यावरण स्वच्छता परियोजना का उद्देश्य जैसे पानी सप्लाई में सुधार मँले कूड़े आदि की व्यवस्था में सुधार और गंदगी से पैदा होने वाली बीमारियों की जनता को जानकारी करा के जन स्वास्थ्य का सुधार प्रदर्शन करना था। कम से कम कीमत पर 'प्राई' किस्म के पाखानों के निर्माण और सप्लाई का प्रबन्ध चिनहट (जिला लखनऊ) पंचायत उद्योग में किया गया। यह अनुभव किया गया कि राजगीरो को थोड़ी ट्रेनिंग देकर इस किस्म के पाखानों का निर्माण किसी भी ऐसे गांव में किया जा सकता है जहां मोटी बालू और सीमेंट उपलब्ध हो। मेरठ खंड के चुने हुए १२ गांवों में सफाई कार्यक्रम-चालू किया गया जिसमें प्राई किस्म के पाखानों, मौजूदा कुओं के पुनर्निर्माण और हाथ के पम्पों की व्यवस्था सम्मिलित थी। वर्ष में ७४६ पाखानों और ५ हाथ के पम्पों को लगाया गया। चिनहट खंड में पूर्व वर्ष की भांति सफाई का काम चालू रहा और १६ कुओं का पुनर्निर्माण किया गया। बर्सा-का-तालाब में लगभग १४० सेनिटरी इन्स्पेक्टरों, ओवरसिरो और सामुदायिक विकास खंडों के प्राविधिक सहायकों को ग्रामीण स्वच्छता, विशेषकर पाखानों के निर्माण, की ट्रेनिंग दी गयी। नवम्बर, १९६० में एक राज्य व्यापी राजगीर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें प्रत्येक जिले के एक राजगीर को लिया गया। ये राजगीर खंडों के दूसरे राजगीरों के शिक्षक के रूप में काम करने को थे।

### औद्योगिक स्वास्थ्य

औद्योगिक स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना उद्योगों संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के अनुसंधान और कतिपय कार्यों में उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य सबंधी खतरों को कम करने की पर्याप्त व्यवस्था के सिलसिले में सलाह देने के लिए की गयी थी, काम करता रहा। इस संगठन के इन्चार्ज स्वास्थ्य अधिकारी ने कानपुर के ३६ उद्योगों और दूसरे ७ जिलों के १७ उद्योगों का निरीक्षण किया। इन उद्योगों को पर्याप्त सफाई, पीने के पानी की समुचित सुविधा, पाखानों, पेशाबघरों और थूकदानों का इन्तजाम, रोशनी के प्रबन्ध और जहां ऊंची गति से चिन्नारियां

पैदा होती है और मजदूर के आँख के लिए बराबर खतरा पैदा रहता है, वहाँ आँखों के बचाव की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया। इसके अतिरिक्त कानपुर के रसायन उद्योगों के मजदूरों के स्वास्थ्य तथा अधिक प्रतिशत में श्वास प्रणाली को पहुँचाने वाली हानि के संबंध में विशेष अनुसंधान किये गये। कानपुर के एक चमड़ा उद्योग में लगे ४०० मजदूरों का परीक्षण लम्बे असे तक चमड़े और चमड़ा कमाने वाले रसायनों के संपर्क में रहने के कारण पैदा होने वाले चर्म रोगों का पता लगाने के लिए किया गया। मीटर कक्षों में मर्क्यूरियल लिबरेशन के कारण विषैली गैस फैलने के खतरो को कम करने के उपायों का सुझाव एक बिजली सप्लाई कंपनी को दिया गया।

### मजदूरों का स्वास्थ्य

कर्मचारी राज्य बीमा के अधीन लगभग १,५०,००० कर्मचारी और उनके परिवार के ४,५०,००० सदस्य आ गये। ५२ अचल और ८ संचल औषधालयों, से जो योजना वाले नगरों के लिए ही शुरू किये गये थे, कर्मचारियों और उनके परिवार वालों को वहिर्वासी रोगी के रूप में चिकित्सा करने का प्रबंध किया गया था। अन्तर्वासी रोगी के रूप में चिकित्सा सुविधा देने के लिए कानपुर में १०० शैयाओं वाले एक अस्पताल का निर्माण किया जा रहा था। बीमाशुदा टी० बी० रोगियों और उनके परिवार के उपचार के लिए कानपुर में एक टी० बी० अस्पताल के भी निर्माण का प्रस्ताव था। इस योजना के अधीन १९६० में किये गये कार्यों का संक्षिप्त विश्लेषण निम्नांकित है :—

(१) नये रोगियों की संख्या, जिनका उपचार किया गया ..	५,६२,९९२
(२) पुराने रोगियों की संख्या, जिनका उपचार किया गया ..	२०,१९,३६४
(३) दैनिक औसत .. .. .	७,१५७
(४) तपेदिक के रोगियों की संख्या ..	१,६७५
(५) चिकित्सा अधिकारियों द्वारा रोगियों के घर जाकर जांच करने की संख्या ..	३,८५२
(६) एक्सरे तथा अन्य जांचों के लिए अस्पतालों को संदर्भित मामलों की संख्या	१८,५६६

### औषधि प्रतिमान नियन्त्रण

औषधि के निर्माण और बिक्री पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से राज्य को ग्यारह जोनों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक जोन एक ड्रग इन्स्पेक्टर के चार्ज में था। औषधियों के ७५२ नमूनों का संग्रह विश्लेषण के लिए किया गया और उनमें से ४८ नमूने निम्नस्तर के पाये गये। इस सिलसिले में ४३ व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और इनमें से ३३ मामलों में सजा दी गयी।

### खाद्य सामग्री में मिलावट

विश्लेषण के लिए संग्रह किये गये २८,७७८ नमूनों में से ५,३६८ में मिलावट पायी गयी। जिन विक्रेताओं के नमूनों में मिलावट घोषित की गयी उन पर मुकदमा चलाया गया।

### पोषक तत्व

जन-स्वास्थ्य विभाग की पोषक तत्व शाखा ने आगरा, लखनऊ और धाराणसी के कुछ परिवारों के भोजन का सर्वेक्षण किया और भोजन में सामान्यतः पशु-प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन 'ए', रिबोफ्लेविन और बिटामिन सी की कमी पायी गयी। लखनऊ जिले के नौबस्ता कला और

इस्माइलगंज गांव के स्कूली बच्चों का पोषक तत्व संबंधी क्लिनिकल सर्वेक्षण किया गया, जिससे मसूड़ों से खून आने, दांतों के कैरीज, एक्मेरोसिस और कजवटाइजा डिसचार्ज और बालों तथा चमड़ी के छूटने के लक्षण पाये गये। बच्चों में जिगर बड़ जाने के भी कुछ मामले पाये गये। १९५२-६० के शिक्षा सत्र में २१ शिक्षा सस्थाओं में अलाई रहित दूध के पाउडर के सेवन की योजना चालू रही। दूध पाने के पूर्व और बाद ने लम्बाई और वजन के रेकार्ड का क्लिनिकल सर्वेक्षण किया गया। इन ग्रुपों में कमी के लक्षण अर्थात् कजवटाइजा डिसचार्ज, बालों और चमड़ी का छूटना और रगुलर स्टोमैटाइटिस प्रवेक्षाकृत कम पायी गयी।

### जनता की स्वास्थ्य शिक्षा

स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो ने १७ ट्रांस्लाइट प्रदर्शनियों की और चल चित्रों, सिनेमा स्लाइडों, भाषणों, प्रदर्शनो, सेमिनारों और ग्रुप वाद-विवादों, पोस्टरों और पुस्तिकाओं के माध्यम से जनता को स्वास्थ्य शिक्षा देने का काम हाथ में लिया। इसके लिए प्रेस नोट भी जारी किये गये और रेडियो वार्ताएं प्रसारित की गयीं।

१९५५ में आरम्भ की गयी पांच स्वास्थ्य शिक्षा सचल यूनिटें वर्ष भर चालू रहीं। १ दिसम्बर, १९६० से अल्मोडा यूनिट को, चेचक अग्रगामी योजना चलाने के लिए, मुल्तानपुर तथा झासी यूनिट को, चेचक अग्रगामी योजना देने के लिए मिर्जापुर जिले की दूधो तहसील में स्थानान्तरित किया गया। शेष तीनों यूनिटें बस्ती, लखनऊ और मेरठ जिलों में काम करती रहीं।

भारत सरकार की सहायता से राज्य स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो का विस्तार स्वास्थ्य कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देने, शिक्षा प्रणालियों संबंधी परामर्श देने और देखने के उपकरण तथा अध्ययन में कार्य आने वाली अन्य सामग्रियों के निर्माण के निमित्त वैज्ञानिक आधार पर किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ब्यूरो के विकास में राज्य सरकार की सहायता के लिए एक विशेषज्ञ नियुक्त किया।

### हार्जिजन इंस्टीट्यूट

'प्रोविशियल हार्जिजन इंस्टीट्यूट' में ३ प्रयोगशाला सहायकों को प्रशिक्षित किया गया, आगरा नगर पालिका के एक कमिस्ट को जल-विश्लेषण की ट्रेनिंग दी गयी, लखनऊ स्थित राज्य आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थियों को सामाजिक और रोकथाम की औषधियों की ट्रेनिंग दी गयी, ११ लाइसेन्सिएट पब्लिक हेल्थ अधिकारियों को पोस्ट लाइसेन्सिएट पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया गया और जलकल के ५ इंजीनियरों को प्रयोगशाला कार्य में प्रशिक्षित किया गया। पानी के चार सौ सत्तर नमूनों का रासायनिक और ९१० का जीवाणु विषयक परीक्षण किया गया, कीटाणुनाशक औषधियों के २३ नमूनों के रासायनिक और जीवाणु विषयक दोनों ही परीक्षण किये गये, क्लिनिकल स्पेसीमन के २०५ नमूने जांचे गये, मल के ५०० नमूने के ० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ के पैथालॉजी विभाग को जठरान्नकोष (गैस्ट्रोएन्टराइटिस) पर शोध कार्य करने के लिए भेजे गये तथा २६३ निसृव नमूनों का रासायनिक विश्लेषण किया गया।

वर्ष भर में इंस्टीट्यूट ने हैजा निरोधक टीके की ४८,०४,४०० से भी अधिक खुराकें तैयार कीं।

### स्टेट वैक्सीन इंस्टीट्यूट

स्टेट वैक्सीन ने इंस्टीट्यूट चेचक निरोधक टीके की ८८,४६,१०० से अधिक खुराकें तैयार की। विश्व-स्वास्थ्य संगठन तथा यूनीसेफ ने इस इंस्टीट्यूट में जमाकर सुखाये गये चेचक

के टीको का निर्माण करने के लिये एक संयंत्र देना संजूर किया। इस संयंत्र के शीघ्र ही स्थापित होने की संभावना थी। यह महसूस किया गया कि जमा कर सुवाई हुई वैक्सीन जब उपलब्ध होगी तो वह बहुत दिनों से महसूस की जाने वाली एक कमी को पूरा करेगी और राज्यों के दुर्गम स्थानों तक पहुंच कर अपनी (कीटाणुनाशक) शक्ति बनाये रखेगी जबकि साधारण वैक्सीन की प्रवृत्ति अपनी शक्ति को खो देने की है।

वर्ष भर में इस इंस्टीट्यूट में २६,३४,४६० सी० सी० से अधिक कुत्ता काटने के इलाज के वैक्सीन बने।

बाहन, लाउडस्पीकर तथा माइक्रोफोन, डी० डी० टी० तथा अन्य कीटाणुनाशक औषधियों, मक्खन निकाला हुआ दूध का पाउडर, दवाओं तथा पूरक खाद्य पदार्थों के रूप में टी० सी० एम० युनिसेफ और स्वास्थ्य संगठन जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से राज्य में चलने वाली तथा मलेरिया एवं फाइलेरिया नियंत्रण योजनाओं, बी० सी० जी० के टीको तथा मातृत्व एवं शिशु कल्याण लिए सहायता प्राप्त होती रही। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा एवं जन-स्वास्थ्य कार्यक्रमों के विदेशी विशेषज्ञों का भी प्रबन्ध किया गया।

### राज्य स्वास्थ्य समिति

राज्य स्वास्थ्य समिति की २ बैठकें हुई—पहली ६ जुलाई, १९६० को और दूसरी २७ नवम्बर, १९६० को। स्थानीय निकायों तथा स्वीकृत संस्थाओं को, आधुनिक स्वच्छता संबंधी सुविधाओं को सुलभ करने में स्थानीय प्रयासों को, पानी देने की योजनाओं को तथा स्वास्थ्य कर्मचारियों को और बच्चों के खेल कूद के केन्द्रों की व्यवस्था को प्रोत्साहन देने के निमित्त समिति ने अनुदान देना जारी रखा। आलोच्य वर्ष में इस कार्य के लिए शासन के ६.५० लाख रुपये की व्यवस्था की। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में उन्नति लाने के लिए पेय जल की सप्लाई तथा उत्तरकाशी, ऋषीकेश, हरद्वार, विन्-याचल, गोला गोकर्ननाथ, बदरीनाथ और केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री यात्रा मार्गों पर, फुल्वरिया, विनायक, श्रीनगर तथा जोशीमठ के तीर्थयात्री केन्द्रों में यात्रियों के लिए सायबान बनाने के निमित्त शासन ने १,३१,३१८ रुपये की धनराशि दी। कानपुर (रा० कृ० मिशन), शामली, बिन्दकी, वाराणसी, टांडा, नगीना, मुरादाबाद, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोडा, कोट-द्वार, मंगलौर, रुड़की, ललितपुर, खुरजा, बिसवां, पीलीभीत, लखनऊ (मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी) इलाहाबाद (स्वराज भवन तथा कमला नेहरू अस्पताल), बहराइच, अलीगढ़, औरैया, जौनपुर, बरेली, बस्ती, कोच, कोसी, फैजाबाद और हापुड़ के नागरिक क्षेत्रों में स्वच्छता-सुधार तथा जल देने की व्यवस्था के लिए कुल मिला कर २,९१,२५० रुपये की धनराशि दी गयी। इसके अतिरिक्त, मिर्जापुर, देहरादून, लखनऊ, वाराणसी, मुरादाबाद, हमीरपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, पिथौरागढ़, बहराइच, बस्ती और फर्रुखाबाद के जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में जल-व्यवस्था तथा स्वच्छता के लिए १,२७,४३२ रुपये दिये गये।

बच्चों के स्वास्थ्य के विकास तथा नगरों और ग्रामों की घनी आबादियों में खेलकूद की सुविधाएं प्रदान करने के लिए, बच्चों के खेलकूद केन्द्रों की स्थापना के निमित्त कुल १ लाख रुपये के अनुदान दिये गये। आलोच्य वर्ष में राज्य के विभिन्न नगरों और ग्रामों में ऐसे ८२ केन्द्रों की स्थापना की गयी। इस प्रकार इन केन्द्रों की संख्या कुल मिलाकर ६९१ हो गयी।

आलोच्य समयवधि में, स्थानीय निकायों की विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं को जिनकी अनुमानित लागत ४८,८९,६६१ रुपये होगी, राज्य स्वास्थ्य समिति ने प्रशासनिक स्वीकृति दी।

### राज्य स्वास्थ्य परिषद्

आलोच्य वर्ष में राज्य स्वास्थ्य परिषद् की कोई भी बैठक नहीं हुई।

## २-चिकित्सा सहायता\*

### (क) एलोपैथिक प्रणाली

सामान्य—सन् १९६० का वर्ष, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना का अन्तिम वर्ष था, विभिन्न परियोजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के कार्य में तेजी ले आने वाला वर्ष था। इस वर्ष की एक उल्लेखनीय उपलब्धि यह थी कि कानपुर के गणेश शर्कर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज से ६८ डाक्टर पास होकर निकले। लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कालेज में एक आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया गया जो कि अपने ढंग का भारत में पहला कार्यक्रम था।

प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की योजना में चिकित्सा के निरोधात्मक एवं चिकित्सात्मक उपायों के समन्वय की व्यवस्था थी। ३१ दिसम्बर, १९६० तक खोले गये प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कुल संख्या ५०१ थी, जिसमें से १११ चिकित्सा विभाग द्वारा और ३९० नियोजन विभाग द्वारा खोले गये थे। इन केन्द्रों में से ९८ केन्द्र नियोजन विभाग द्वारा आलोच्य वर्ष में प्रथम चरण के खंडों में खोले गये थे।

आलोच्य वर्ष में अमरौहा (मुरादाबाद) के महिला अस्पताल का प्रान्तीयकरण किया गया। सात अन्य महिला अस्पतालों के प्रान्तीयकरण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था।

सन् १९६०-६१ में बजट में कुल ४,५४,५१,७०० रुपये की व्यवस्था की गयी थी।

एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली पर व्यय के लिए निम्नलिखित धनराशियों की व्यवस्था की गयी थी।

			रुपये
(१) सामान्य औषधि	..	..	६८,६२,०००
(२) अस्पतालों की साज-सज्जा	..	..	२१,६७,६००
(३) अस्पतालों में खुराक	..	..	२७,४०,७००

### ग्राम क्षेत्रों के लिए चिकित्सा सहायता

सन् १९५६ के वर्ष की समाप्ति पर उत्तर प्रदेश में ८४३ एलोपैथिक चिकित्सालय ग्राम क्षेत्रों में थे तथा ६०० आयुर्वेदिक औषधालय एवं यूनानी दवाखाने और ३२ राजकीय होम्योपैथिक दवाखाने थे। आलोच्य वर्ष में ९ एलोपैथिक महिला अस्पताल मसौली (बाराबंकी), डिबाई (बुलन्दशहर), कोटद्वार (गढ़वाल), महोबा (हमीरपुर), दातागज (बदायूँ), नवानगर (बलिया), छितौनी (देवरिया) टनकपुर (नैनीताल) और खलीलबाद (बस्ती) में खोले गये।

इस वर्ष १५ आयुर्वेदिक औषधालय मँदानी इलाकों में और ८ पहाड़ी क्षेत्रों में खोले गये।

### उत्तराखंड के लिए चिकित्सा सुविधाएं—

सीमान्त क्षेत्रों में विकास कार्य के संबंध में अल्मोड़ा, गढ़वाल और देहरा जिलों की पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी तहसीलों को अलग-अलग जिला बना दिया गया और इन तीन जिलों को उत्तराखंड नामक एक कमिश्नरी बना दी गयी। इन तीनों जिलों में एक-एक सिविल सर्जन और एक-एक जिला मेडिकल आफिसर की नियुक्ति की गयी और उनका कार्यालय स्थापित किया गया। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के अस्पतालों में अतिरिक्त साज-सज्जा, दवाइयों और कर्मचारियों की व्यवस्था कर उन्हें पूर्ण रूपेण जिला अस्पतालों

\* सन् १९६० के कैलेन्डर वर्ष से संबंधित



में परिणत कर दिया गया। इसके लिए उचित इमारतों के निर्माण का कार्यक्रम भी तैयार किया गया। आलोच्य वर्ष में इस कमिशनरी के लिये निम्नलिखित अन्य परियोजनाएं स्वीकृत की गयीं—

- (१) इन प्रत्येक तीनों जिलों के अस्पतालों के लिए एक-एक सचल औषधालय की व्यवस्था।
- (२) वर्तमान एलोपैथिक दवाखानों का स्तर उठाना।
- (३) ६ नये आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना।
- (४) इन तीनों जिलों में एक-एक नये मातृ-शिशु कल्याण केन्द्रों की स्थापना।
- (५) पिथौरागढ़ में एक नये टी० बी० क्लिनिक की स्थापना।
- (६) १५० प्राथमिक चिकित्सा बक्सों के सप्लाई की योजना।
- (७) क्षय रोगियों को १,५०,००० रुपये तक की आर्थिक सहायता की योजना।

सीमान्त क्षेत्र के छात्रों को प्राविधिक अध्ययन और स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां तथा अन्य आर्थिक सहायता स्वीकृत की गयी।

इसके अतिरिक्त 'भारत-तिब्बत सीमा निवास योजना,' के अन्तर्गत उत्तरकाशी के एक एलोपैथिक दवाखाना, चमोली के लिए एक कम्पाउन्डरों की यूनिट और एक मातृ शिशु कल्याण केन्द्र तथा पिथौरागढ़ के लिए एक आयुर्वेदिक औषधालय के स्थापना की भी स्वीकृति दी गयी।

### नागर क्षेत्रों के लिए चिकित्सा सुविधाएं

कमिशनरियों के सदर अस्पतालों तथा अन्य महत्व के अस्पतालों का, उनके लिए अधिक विशेषताओं की व्यवस्था कर, स्तर उठाने का कार्य और जिलों के सदर के अस्पतालों की वर्तमान चिकित्सा एवं शल्य क्रिया संबंधी सुविधाओं में सुधार करने का कार्य द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना अवधि में जारी रहा। सन् १९६० के वर्ष में कमिशनरियों के ६ अस्पतालों का स्तर उठाया गया और १४ जिला अस्पतालों का, चिकित्सा एवं शल्य क्रिया संबंधी व्यवस्था प्रदान कर, सुधार किया गया।

इस वर्ष देहरादून, फैजाबाद और बहराइच के जिला अस्पतालों और लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में दो चिकित्सा क्लिनिक की व्यवस्था की गयी।

### निर्माण कार्य

योजनाधीन कार्यक्रम के अन्तर्गत ११ ग्राम और १६ जनाने अस्पतालों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी और ३ मरदाने अस्पतालों के निर्माण की योजनाएं व तखसीनों की जांच की जा रही थी।

सहारनपुर, आगरा और मिर्जापुर में अस्पतालों का निर्माण कार्य पूरा हुआ। पौड़ी गढ़वाल, इलाहाबाद और बहराइच में अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा था।

योजनेतर कार्यक्रमों के अधीन सन् १९६० के वर्ष में राज्य के ४६ जिलों में ६,११,२६२.१३ रुपये की लागत से अस्पतालों और दवाखानों में नये निर्माण और उनकी व्यापक मरम्मत का कार्य तथा बाड़ों में परिवर्तन एवं परिवर्द्धन का कार्य किया गया।

विभाग के भवन निर्माण कार्य की देख-रेख के लिए एक अविभाजी अभियन्ता, एक ओवर-सियर और अन्य आवश्यक कर्मचारी चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य निदेशालय से सम्बद्ध रहे।

### केन्द्रीय औषधि भंडार से दवाओं की सप्लाई आदि

लखनऊ में उत्तर प्रदेश के चिकित्सा और जन स्वास्थ्य निदेशालय के मुख्य कार्यालय स्थित राजकीय केन्द्रीय मेडिकल स्टोर्स डिपो राज्य के अस्पतालों और चिकित्सालयों की दवाइयों, सजीवनी औषधियों, साज-सामान, शल्य चिकित्सा के सामान आदि संबंधी मांग को पूरा करता रहा।

सजीवनी औषधियों और जहंगी दवाइयों का स्टॉक बनाये रखने के लिए केन्द्रीय मेडिकल स्टोर्स डिपो द्वारा सन् १९६० के वर्ष में लगभग १,२०,६०० रुपये की दवाइया खरीदी गयी और मांग पर विभिन्न अस्पतालों तथा दवाखानों को उनकी सप्लाई की गयी। क्षय रोग से पीड़ित पुलिस कर्मचारियों की चिकित्सा के लिए १२,४०७ रुपये को लागत से स्टोर में क्षय-निरोधक औषधियों का स्टॉक तैयार किया गया और राज्य के विभिन्न पुलिस अस्पतालों को इन औषधियों की सप्लाई की गयी। इसी प्रकार स्टोर के लिए निर्धारित आवर्तक और अनावर्तक अनुदानों में से लगभग १० लाख रुपये राज्य के विभिन्न अस्पतालों की साज-सज्जा और शल्य चिकित्सा के औजार आदि राज्य के विभिन्न जिला और महिला अस्पतालों तथा चिकित्सा सस्थाओं को दिये गये। इस मद में महत्वपूर्ण खरीद एक्स-रे प्लेट, ड्राई-थर्मो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आदि की थी। आलोच्य वर्ष में इलेक्ट्रो-मेडिकल साज-सज्जा की मरम्मत आदि पर ७५,००० रुपये व्यय किये गये।

### आलोच्य वर्ष में शय्याओं की संख्या में वृद्धि

आयोजनाधीन कार्यक्रम, 'जिला, तहसील और अन्य अस्पतालों में शय्याओं की संख्या बढ़ाओ' के अन्तर्गत प्यारेलाल शर्मा, अस्पताल मेरठ, जिला और महिला अस्पताल, जौनपुर तथा जिला और महिला अस्पताल, बलिया के लिए स्वीकृत की गयी अतिरिक्त शय्याओं के हेतु आवश्यक कर्मचारी एवं साज-सज्जा की व्यवस्था की गयी। शय्याओं की कुल संख्या में ११६ की वृद्धि हुई।

### दवाओं के लिए अलाटमेंट

राज्य के अस्पतालों और दवाखानों में दवाओं के अलाटमेंट में हुई वृद्धि के फलस्वरूप सरकार ने ४१ लाख रुपये की स्वीकृति दी। यह स्वीकृति धनराशि सरकार द्वारा निर्धारित इस मापदण्ड के अनुसार वितरित की गयी कि प्रत्येक राजकीय दवाखाने के लिए कम से कम २,५०० रुपये दवाओं के लिए निर्धारित किये जाने चाहिए।

### खुराक का अलाटमेंट

राज्य के विभिन्न अस्पतालों और दवाखानों में खुराक के अलाटमेंट में वृद्धि करने के हेतु राज्य सरकार द्वारा दो लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी। फलस्वरूप राज्य के अस्पतालों को उनकी मांग के अनुसार अतिरिक्त धनराशि स्वीकृति की गयी।

### सेवाएं

वर्ष के आरम्भ और अन्त में विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत पदों की संख्या निम्न प्रकार थी—

पद	वर्ष के आरम्भ में	वर्ष के अन्त में
१—सिविल सर्जन .. .. .	५१	५४
२—अस्पतालों के सुपरिन्टेन्डेंट .. .. .	६	८
३—पी० एम० एस० (प्रथम) अधिकारी .. .. .	२४४	२६०
४—पी० एम० एस० (महिला) (प्रथम) अधिकारी .. .. .	६५	७९
५—पी० एम० एस० (द्वितीय) पी० एम० एस० अधिकारी	१,०६४	१,१११
६—पी० एम० एस० (महिला) (द्वितीय) पी० एम० एस०		
एस० (महिला) अधिकारी .. .. .	२५२	२६५

७—अध्वेत्तनिक चिकित्सा अधिकारी .. ..	३७	४४
८—नर्स चिकित्सा अधिकारी .. ..	१,३४३	१,४०२
९—शिक्षार्थी नर्स (प्रशिक्षण में) .. ..	८४१	८४२
१०—शिक्षार्थी मिडवाइफ .. ..	१००	१५०
११—स्वास्थ्य निरीक्षक .. ..	२०५	३०६
योग .. ..	४,२०८	४,५२७

लगेवेट अस्पताल रामनगर (वाराणसी) के लिए मेडिकल सुपरिन्टेण्डेंट के एक पद का और इलाहाबाद के एम० डी० आई० हॉस्पिटल के लिए एक पद का सृजन किया गया। नगर परिवार नियोजन केन्द्रों के लिए पी० एम० एस० (महिला) (अध्यापक) के १० अस्थायी पदों का सृजन किया गया।

**राज्य नर्सिंग सेवा**—राज्य के अस्पतालों में नर्सिंग सेवा सन्तोषजनक रूप से कार्य करती रही। वर्ष के आरम्भ और अन्त में विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत पदों की संख्या तथा ३१ दिसम्बर, १९६० को कार्य करने वाली महिला कर्मचारियों की वास्तविक संख्या का विवरण निम्न प्रकार है:—

पद	स्वीकृत पद		वास्तविक संख्या
	१ जनवरी, १९६०	३१ दिसम्बर, १९६०	३१ दिसम्बर, १९६०
<b>गजटेटेड—</b>			
१—सीनियर मैट्रन .. ..	२	२	२
२—मैट्रन .. ..	२६	२६	१९
३—सहायक मैट्रन .. ..	८	१२	७
४—सिस्टर द्यूटर .. ..	१६	१६	१५
<b>नान-गजटेटेड—</b>			
१—सिस्टर और वाडर मास्टर .. ..	२९९	३२४	२५४
२—स्टाफ नर्स .. ..	६६२	१,०११	७४८
३—सिस्टर द्यूटर .. ..	..	१४	..
योग .. ..	१,३४२	१,४०५	१,०४५

इस प्रकार, जहां तक नर्सिंग सेवा का सम्बन्ध है, कर्मचारियों की संख्या में ३६० की कमी थी।

आलोच्य वर्ष में जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र में २०७ उम्मीदवारों की भरती की गयी और नयी दिल्ली स्थित नर्सिंग के कालेज में बी० एस० सी० (आनर्स) का पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए ३ उम्मीदवारों को नामांकित किया गया।

जनरल नर्सिंग और मिड वाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् २२१ उम्मीदवारों की नियुक्ति स्टाफ नर्स के रूप में की गयी और १२ उम्मीदवारों की नियुक्ति सीधे इंटरव्यू के बाद की गयी। आठ स्टाफ नर्सों की पदोन्नति सिस्टर के पद पर की गयी।

नर्सिंग सेवा का मापदंड ऊँचा उठाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के नर्सिंग कर्मचारियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण हेतु भेजने का प्रयास किया गया। नयी दिल्ली के नर्सिंग कालेज में एक सहायक मैट्रन, एक सिस्टर और ३ स्टाफ नर्सों को स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। अन्तर्राष्ट्रीय बाल सहायता कोष की सहायता से एक सिस्टर को मद्रास स्थित राजकीय जनरल हॉस्पिटल में पेंडियाट्रिक नर्सिंग रिक्रेशर कोर्स के लिए भेजा गया। दो मैट्रन और एक सैनिटरी मैट्रन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से एक मास की अल्प कालिक अवधि के लिए नर्सिंग सुपरिन्टेण्डेंटों के रिक्रेशर कोर्स के लिए भेजा गया। इसी प्रकार विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से दो सिस्टर ट्यूटरो को ८ सप्ताह सिस्टर ट्यूटरो के रिक्रेशर कोर्स के लिए भेजा गया। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत एक स्टाफ नर्स को क्षय रोग परिचर्या प्रशिक्षण के लिए आस्ट्रेलिया भेजा गया। एक स्टाफ नर्स को साइकियाट्रिक ट्रेनिंग के लिए बंगलौर भेजा गया।

### चिकित्सा शिक्षा

चिकित्सा सहायता पहुँचाने की योजनाओं का मुख्य लक्ष्य ठीक प्रकार के काफी संख्या में चिकित्सा कर्मचारियों का उपलब्ध करना रहा। कानपुर में एक मेडिकल कालेज की स्थापना हो जाने के फलस्वरूप डाक्टरों की संख्या में वृद्धि होनी थी। सन् १९६० में तीनों मेडिकल कालेजों से ३१६ डाक्टर पास होकर निकले जबकि विगत वर्ष २४२ डाक्टर पास हुए थे। इन मेडिकल कालेजों में विशेषज्ञ भी तैयार हो रहे थे। सन् १९५६ और ६० के वर्ष में इन कालेजों में भरती हुए छात्रों और पास होकर निकलने वाले डाक्टरों का विवरण निम्न प्रकार है—

वर्ष	सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज आगरा		गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर		के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ		योग	
	भरती	पास	भरती	पास	भरती	पास	भरती	पास
१९५६	..	६८	८६	१०२	..	१४७	१५६	३४७ २४२
१९६०	..	६६	७३	१५४	६८	१४४	१७५	३६७ ३१६

### (१) गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर

आलोच्य वर्ष में गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर के विस्तार के सम्बन्ध में और कार्यवाही की गयी। ७२ शय्याओं के एक मातृत्व अस्पताल, ३० शय्याओं के एक बाल अस्पताल १०० शय्याओं के एक कैंसर अनुसन्धान संस्था और २० शय्याओं के एक चेस्ट सर्जरी यूनिट की इमारतों का निर्माण चल रहा था।

भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार कालेज के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत स्टाफ की नियुक्ति केवल कुछ अध्यापकों को छोड़कर वर्ष के अन्त तक की जा चुकी थी। मेडिकल कालेज से सम्बद्ध लाला लाजपत राय, उर्सला हार्समैन मेमोरियल, एलाइड हार्समैन मेमोरियल, डफरिन और छतहे रोगों के अस्पतालों का जिनमें शय्याओं की कुल संख्या ७८४ है, पढ़ाई की दृष्टि से अधिक उपयोगी बनाने के उद्देश्य से और सुधार किया जाना था। इन अस्पतालों के लिए कुल ५ लाख ६० हजार रुपये मूल्य के साज-सज्जाओं की स्वीकृत दी गयी।

## (२) सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में आगरा के सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज को विस्तार की भी व्यवस्था की गयी थी। आलोच्य वर्ष में कालेज में भरती किये जाने वाले छात्रों की संख्या में कम से कम २५ की प्रति वर्ष और वृद्धि करने के उद्देश्य से कर्मचारियों, साज-सज्जा तथा अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था की गयी। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्तर्राष्ट्रीय बाल कोष की सहायता से भारत सरकार द्वारा आरम्भ किये गये केन्द्र के तन्मये पर सितम्बर, १९५६ से जिस पीडियाट्रिक केन्द्र में अपना कार्य आरम्भ किया था वह सन् १९६० में एक स्वावलम्बी इकाई बन गया।

## (३) के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ

द्वितीय आयोजना के अन्तर्गत आरम्भ किये गये विशिष्ट चिकित्सा सम्बन्धी यूनिट, जैसे न्यूरोसाइकियाट्रिक क्लीनिक, गाइडेड क्लीनिक, चैस्ट सर्जरी यूनिट, नेशनल शिगाला सेटर, सामाजिक और निरोधात्मक चिकित्सा, पैथालोजी, बैक्टीरियोलोजी और फारमा कालोजी के स्तरोन्नति किये गये विभाग सन्तोषजनक रूप से कार्य करते रहे।

इस कालेज में १ जुलाई, १९६० से एक आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो कि भारत में इस प्रकार का पहला कार्यक्रम था, आरम्भ किया गया। इस प्रशिक्षण में गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज और सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा के स्नातक भी सम्मिलित हो सकते थे।

एक नया सर्जिकल ब्लॉक, जिसमें आधुनिक साज-सज्जा से युक्त चार आपरेशन थियेटर थे, खोला गया।

## (४) दन्त चिकित्सा कालेज, लखनऊ

लखनऊ के दन्त चिकित्सा कालेज में पूर्वगामी वर्ष में भरती किया गया ४० छात्रों का दल इस वर्ष द्वितीय वर्ष में पहुंचा और फलस्वरूप बड़े हुए काम को देखते हुए अधिक कर्मचारी और साज-सज्जा की स्वीकृति दी गयी।

इस वर्ष ४१ छात्रों को, जिनमें एक जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा मनोनीत किया गया था, बी० डी० एस० पाठक्रम में भरती किया गया और इनमें से १८ ने सफलतापूर्वक पाठक्रम को पूरा किया।

## प्रशिक्षण और अनुसंधान

### (१) डाक्टरों के लिए उच्च प्रशिक्षण

चिकित्सा अधिकारियों को विभिन्न विशिष्ट चिकित्सा सम्बन्धी विषयों में प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत २३ डाक्टरों को उच्च प्रशिक्षण के लिए देश की विभिन्न संस्थाओं में भेजा गया। इनमें से ३ क्लीनिकल पैथालोजी कोर्स डिप्लोमा के लिए, ३ को ट्रापिकल डिजीजेज कोर्स के डिप्लोमा के लिए, ५ को आर्थोपिडिक्स कोर्स के डिप्लोमा के लिए, २ को लखनऊ में गायनोकालोजी और आन्सट्रेटिक्स कोर्स के डिप्लोमा के लिए, १ को अनेस्थी-शिया कोर्स के डिप्लोमा के लिए, १ को डी० जी० ओ० कोर्स, १ को रेडिएशन प्रोटेक्शन की ट्रेनिंग के लिए बम्बई, २ को रतिज रोग पाठक्रम के लिए और ५ को डी० टी० डी कोर्स के लिए दिल्ली भेजा गया।

१६ पी० एम० एस० (महिला) (द्वितीय) अधिकारियों ने सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज आगरा में स्नातकोत्तर पाठक्रम में भाग लिया और उसे सफलतापूर्वक पूरा किया। ६ पी० एम० एस० एस० (महिला) अधिकारियों ने आगरा स्थिति एल० एल० और

डफरिन अस्पताल में रिफ्रेशर कोर्स में भाग लिया। इन पाठ्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए काफी संख्या में उम्मीदवार आये।

दो प्रधिकारियों को पीडियाट्रिक्स में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेश भेजा गया। इनमें से एक को कोलम्बो योजना के और दूसरे को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रसारित योजना के अन्तर्गत भेजा गया। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत अलोगडू के नेत्र चिकित्सालय की एक महिला डाक्टर को आषटोमेलोजी में प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा गया और इसी योजना के अन्तर्गत एक डाक्टर क्षयरोग चिकित्सा में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक योजना के अन्तर्गत एक अधिकारी को फिजिशियोलोजी में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा गया। सामान्य रूप से यह सब अधिकारी प्रशिक्षण संस्थाओं से भेजे गये थे।

## (२) अन्य चिकित्सा कर्मचारियों का प्रशिक्षण

राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायक कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में तेजी ले आयी गयी। आलोच्य वर्ष में परिचारिकाओं के लिए ६, रिफ्रेशरिनिस्ट एवं आर्प्टो-शियनो के लिए २ और प्रयोगशाला सहायकों के लिए १२ प्रशिक्षण केन्द्र राज्य में कार्य करते रहे। इन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को छात्रवृत्तियाँ भी दी गयीं। सरकारी डाक्टरों के लिए एनेस्थीशिया में लघु पाठ्यक्रम तथा प्रैक्टिस करने वाले दन्त चिकित्सकों के लिए अस्पताल व्यवस्था के विषय में एक संक्षिप्त पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गयी। इन में से कुछ पाठ्यक्रमों ने अन्य राज्यों में आये हुए उम्मीदवारों को भी भरती किया गया। कुछ रोग-कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का भी प्रस्ताव था।

उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा फार्मासिस्ट एवं मिडवाइफों का प्रशिक्षण बन्द कर दिया गया था। किन्तु यथाशीघ्र इसे पुनः प्रारम्भ करने का प्रयत्न किया जा रहा था। राज्य में महिला फार्मासिस्टों की बेहद कमी थी और महिला अस्पतालों की काफी बड़ी संख्या ऐसी थी जिनमें महिला फार्मासिस्ट नहीं थी।

प्रशिक्षित फार्मासिस्टों के वेतन-क्रम १ अप्रैल, १९६० से ४५-१०० रुपया प्रतिमास से संशोधितकर ७५-५-१००-४० रो०-५-१२० रुपया प्रति मास कर दिया गया। १ दिसम्बर, १९६० से सरकार ने ७५-१२० रुपया के वेतन-क्रम की एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली की उन महिला फार्मासिस्टों को ८० ६० प्रतिमास का प्रारम्भिक वेतन देना स्वीकार कर लिया जिन्होंने मिडवाइफरी पाठ्यक्रम पास कर लिया था।

## (३) चिकित्सा अनुसन्धान

पूर्वगामी वर्ष की भांति चिकित्सा अनुसन्धान के लिए ५०,००० रुपया स्वीकृत किया गया। इसका संचालन राज्य चिकित्सा अनुसन्धान परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा था। मुख्य विषय, जिनमें अनुसन्धान किया जा रहा था, निम्नलिखित थे—

(१) फेफड़े के क्षय रोग सम्बन्धी मामलों, विशेषकर शल्य चिकित्सा सम्बन्धी मामलों, के विषयों में फेफड़े के कार्य परीक्षण।

(२) रक्त, भ्रूज और रेथेरोमा पर लम्बाकू का प्रभाव।

(३) हैलमिनथिक संक्रमण और ग्राम स्वास्थ्य केन्द्र सरोजनी नगर, लखनऊ के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत रहने वालों के स्वास्थ्य पर उसके प्रभाव का सर्वेक्षण।

(४) स्कूल के छात्रों में श्रवण शक्ति सम्बन्धी खोज।

(५) चमड़ा उद्योग में काम करने वालों पर प्रगट होने वाले विभिन्न रोग-लक्षणों का सर्वेक्षण।

(६) कानपुर के स्कूल और कालेज के विद्यार्थियों की लम्बाई, वजन, सीने की नाप और शक्ति सामर्थ्य के सम्बन्ध में छानबीन।

(७) शरीर के सामान्य तापमान पर कुत्ते के गले के भीतर की रक्त नालिकाओं की शल्य क्रिया।

(८) चूहों में प्रयोगात्मक रूप से पैदा किये गये सर्बिक्स के कार्शिनीमा नामक रोग का साइटोलॉजिकल और हिस्टोलॉजिकल सम्बन्धी तुलनात्मक अध्ययन।

(९) बोकल कैन्सरी के कैन्सर रोग के सक्रमण के निदान सम्बन्धी अध्ययन।

(१०) फीटल हिमोग्लोबिन के सम्बन्ध में इम्यूनोलॉजिकल अध्ययन।

(११) वंशगत रोगशास्त्र में नस्ल का योग के सम्बन्ध में प्रायोगिक अध्ययन।

### उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

स्टेट मेडिकल फैकल्टी यथावत परीक्षाओं का संचालन करती रही। उन परीक्षाओं के सम्बन्ध में और सन् १९६० की विभिन्न परीक्षाओं में सफल हुए उम्मीदवारों का विवरण निम्नलिखित है—

परीक्षा	सफल उम्मीदवार
(१) डिप्लोमा नर्सिंग परीक्षा .. .. .	२२०
(२) सर्टीफाइड नर्सिंग परीक्षा .. .	६
(३) डिप्लोमा मिडवाइफ परीक्षा .. .. .	२१६
(४) हेल्थ विजिटरो की परीक्षा .. .. .	१२५
(५) ब्राकजीलियरी नर्स मिडवाइफ परीक्षा .. .. .	११२
(६) एक्स-रे टेक्नीशियनों की परीक्षा .. .. .	६
(७) जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियनों की परीक्षा .. .. .	१७
(८) रिफ्रेक्शनलिस्ट और ग्राफ्टीशियनों की परीक्षा .. .. .	१२

### उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिषद्

उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिषद् चिकित्सा शिक्षा के नियन्त्रण, डाक्टरों, हकीमों और वैद्यों के पंजीकरण और चिकित्सा आचरण संहिता से सम्बन्धित अपना कार्य पूर्ववत् करता रहा। इसकी एक साधारण बैठक और इसकी समितियों की चार बैठकें आलोच्य वर्ष में हुईं। इस वर्ष ३५४ डाक्टरों का पंजीकरण किया गया।

दवाखानों और मेडिकल हालों के लिए निर्धारित मापदंड के अनुसार आवश्यक न्यूनतम साज-सज्जाओं के सम्बन्ध में प्रस्ताव परिषद् द्वारा तैयार किये गये।

### उत्तर प्रदेश नर्स और मेडिकल परिषद्

उत्तर प्रदेश नर्स और मिडवाइफ परिषद् नर्सों, मिडवाइफों आदि के पंजीकरण करने का, इनकी शिक्षा की व्यवस्था करने का और इनकी आचरण संहिता सम्बन्धी अपना सामान्य कार्य करती रही। आलोच्य वर्ष में परिषद् ने २७८ नर्सों, २१८ मिडवाइफों, ४० सहायक मिडवाइफों और ६५ हेल्थ विजिटरो का पंजीकरण किया इस प्रकार नर्सों, मिडवाइफों, सहायक मिडवाइफों और हेल्थ विजिटरो की कुल संख्या क्रमशः २,४४४, १,६३६; १,२६३ और २५८ तक पहुंच गयी।

नर्सिंग शिक्षा का स्तर अंचा करने के उद्देश्य से परिषद् ने नर्सों मिडवाइफो सहायक मिडवाइफो और हेल्थ विजिटर्स की शिक्षा एवं उनके प्रशिक्षण से सम्बन्धित संशोधित नियम-मावली सरकार के समक्ष प्रस्तुत की।

### उत्तर प्रदेश दन्त चिकित्सा परिषद्

उत्तर प्रदेश दन्त चिकित्सा परिषद् ने १८ नये दन्त चिकित्सकों का पंजीकरण रजिस्टर के भाग 'क' में किया। रजिस्टर में से ६ नाम भाग 'ख' से स्थानान्तरित कर भाग 'क' में कर लिये गये। आलोच्य वर्ष में भाग 'क' के ८६ सर्टिफिकेटों को नया किया गया। भाग 'ख' के २८७ सर्टिफिकेटों को नया किया गया। भाग 'क' के अन्तर्गत पंजीकृत दन्त चिकित्सकों की कुल संख्या १०४ थी और भाग 'ख' के अन्तर्गत २८७ थी। सन् १९६० के वर्ष में ६८ डेंटल मेकेनिकों के सर्टिफिकेटों को और ५६ डेंटल हार्डजिनिस्टों के सर्टिफिकेटों को नया किया गया। आलोच्य वर्ष में क्रमशः १७ और ३७ डेंटल मेकेनिकों और डेंटल हार्डजिनिस्टों को पंजीकृत किया गया। इस प्रकार वर्ष के अन्त तक डेंटल मेकेनिकों की और डेंटल हार्डजिनिस्टों की कुल संख्या क्रमशः १८४ और १२७ तक पहुंच गयी।

### उत्तर प्रदेश फार्मसी कौंसिल

उ० प्र० फार्मसी कौंसिल ने इस वर्ष ८६१ फार्मसिस्टों का पंजीकरण किया जबकि पूर्वगामी वर्ष में १३९९ पंजीकरण किया गया था।

३१ दिसम्बर, १९६० को पंजीकृत फार्मसिस्टों की कुल संख्या ४,४०९ थी जबकि सन् १९५९ में यह संख्या ५,३३८ थी। इस वर्ष ४,२२० सर्टिफिकेटों को नया किया गया जबकि पूर्वगामी वर्ष में ३,९३९ सर्टिफिकेट नये किये गये थे। श्रेणी विभाजन के अनुसार फार्मसिस्टों का विवरण निम्न प्रकार से है—

धारा ३१ की उपधारा 'क' के अन्तर्गत	उपधारा 'ख' के अन्तर्गत	उपधारा 'ग' के अन्तर्गत	उपधारा 'घ' के अन्तर्गत	योग
१०	८४	१,६२७	२,६८८	४,४०९

## विशेषज्ञों की सुविधाएं

### (१) क्षय रोग

इधर हाल के वर्षों में अस्पतालों में क्षय रोग के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या जो कि सन् १९५६ में १,९८,४२८ थी सन् १९५९ में बढ़ कर ३,६५,८६९ तक पहुंच गयी। इससे यह पता चलता है कि लोगों में अस्पताल में भरती होकर चिकित्सा कराने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह स्वीकार किया जाने लगा कि इस रोग का उन्मूलन बहुत कुछ रहन-सहन के स्तर में और सुधार करने पर निर्भर करता है। पर इस बीच चिकित्सा नियन्त्रण के उपायों को अपनाया जाना था। चिकित्सा विज्ञान में हुई प्रगति के फल-स्वरूप अब क्षय रोग का उसकी प्रारम्भिक दशा में उपचार कर लेना सम्भव हो गया है।

जहां तक नियन्त्रण उपायों का सम्बन्ध है राज्य में क्षय रोग के १० सेनेटोरियम और अस्पताल थे। उनमें ७ का संचालन सरकार द्वारा और शेष का सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता था। इन सब में कुल मिलाकर शय्याओं की संख्या १,००० थी। सबसे बड़ा सेनेटोरियम भुवाली का सेनेटोरियम था जिसमें शय्याओं की संख्या ३४६ थी। जिला अस्पतालों और छुतहे रोग के अस्पतालों में क्षय रोग वार्ड संलग्न थे जिनमें शय्याओं की कुल



संख्या २५० थी। फनेहगढ़ में एक मिशन अस्पताल भी है जिसमें शय्याओं की संख्या २८ थी।

इस रोग की चिकित्सा एवं इसके नियन्त्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान हाल में क्षय रोग क्लिनिकों का खोला जाना था। भारत सरकार की सहायता से तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित ढाँचे पर १६ क्षय रोग क्लिनिक स्थापित किये गये। इनमें से अन्मोडा, खीरी, कानपुर और पितौरागढ़ के क्लिनिक इस वर्ष स्थापित किये गये। क्षय रोग के इन क्लिनिकों का उद्देश्य क्षय रोग के रोगियों को उनके घर पर ही एकल-रे पैथोलॉजी सम्बन्धी परीक्षा आदि जैसी निशुल्क चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना था। इसके अतिरिक्त क्षय रोग के २१ और क्लिनिक थे। इनमें से ८ का संचालन राज्य सरकार द्वारा और शेष का स्वेच्छिक संस्थाओं द्वारा किया जाता था।

नियन्त्रण का दूसरा महत्वपूर्ण उपाय बी० सी० जी० का टीका था। राज्य में १६ बी० सी० जी० के टीके लगाने वाले दल कार्य कर रहे थे। जब तक कि रहन सहन के स्तर में पर्याप्त सुधार नहीं हो जाता तब तक बी० सी० जी० का टीका ही क्षय रोग के नियन्त्रण का सबसे सस्ता एवं प्रभावपूर्ण उपाय था।

## (२) कुष्ठ रोग

कुष्ठ रोग की चिकित्सा के लिए प्रयास जारी रहे। यह रोग राज्य के पूर्वी जिलों में और हिमालय की तराई के क्षेत्रों में अधिक व्यापक था और इधर हाल के वर्षों में इस ओर ध्यान दिया गया। विभिन्न कुष्ठ नियन्त्रण कार्यों की देखभाल के लिए और उनमें समन्वय स्थापित करने के लिये राज्य में पूरे समय के लिए एक राज्य कुष्ठ अधिकारी था। कुष्ठ रोग के नियन्त्रण के लिए राज्यों में कई संस्थाएं थी और कई अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध थी। आलोच्य वर्ष में कुष्ठ रोग की निम्नलिखित संस्थाएं कार्य करती रही—

संस्थाएं	शय्याओं की संख्या
<b>राजकीय संस्थाएं</b>	
(१) कुष्ठ रोग अस्पताल, बहराइच .. .. .	६४
(२) कुष्ठ रोग गृह, मेरठ .. .. .	४०
(३) राजा कालीशंकर कुष्ठ आश्रम, वाराणसी .. .. .	४५
<b>निजी संस्थाएं</b>	
(१) कुष्ठ गृह और अस्पताल, नैनी, इलाहाबाद .. .. .	२५०
(२) कुष्ठ आश्रम, अल्मोड़ा .. .. .	१२०
(३) कुष्ठ आश्रम चन्दग, अल्मोड़ा .. .. .	११०
(४) कुष्ठ गृह और अस्पताल, जमुर्दगंज, फैजाबाद .. .. .	२७०
(५) कुष्ठ अस्पताल, लखनऊ .. .. .	३५
(६) मैकलेरेन कुष्ठ अस्पताल, देहरादून .. .. .	८८
(७) कुष्ठ आश्रम, रुडकी, सहारनपुर .. .. .	१६
(८) श्रीमती भगवान देवी कुष्ठ अस्पताल, कानपुर .. .. .	५३
(९) कुष्ठ आश्रम, मुरादाबाद .. .. .	५०
(१०) कुष्ठ अस्पताल हल्द्वानी, नैनीताल .. .. .	७२
(११) कुष्ठ अस्पताल, प्रागरा .. .. .	५०
(१२) कुष्ठ आश्रम, भीनमर, गढ़वाल .. .. .	१५
(१३) कुष्ठ सेवा आश्रम, गोरखपुर .. .. .	७३
(१४) कुष्ठ कालोनी, मुनी की रीती, टिहरी गढ़वाल .. .. .	१२०
(१५) गुप्ता कुष्ठ आश्रम, खीरी .. .. .	१०

राज्य सरकार इन सब निजी संस्थाओं को सान्धान्य रूप से २ लाख ६० हजार रुपये का अनुदान दिया करती थी ।

उपरोक्त संस्थाओं के अतिरिक्त वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, खीरी, बहराइच, बस्ती, बाराबंकी और अजमेरगढ़ में ८ सहायक केन्द्र थे और देहरादून में एक चिकित्सा केन्द्र था । कुष्ठ रोग निवारण के लिए चल रही भारत सरकार की अग्रगामी योजना के अन्तर्गत ये केन्द्र कार्य कर रहे थे । कुष्ठ रोग के निरोध के लिए प्रगढ़ रूप से बड़े पैमाने पर चिकित्सा कार्य करने के अतिरिक्त ये क्लीनिक सर्वेक्षण कार्य और सम्पर्क बनाये रखने का कार्य करते थे । देहरादून स्थित अध्ययन और चिकित्सा केन्द्र, चिकित्सा कार्य के अतिरिक्त कुष्ठ रोग के विषय में शिक्षित करने, चिकित्सा के परिणामों का मूल्यांकन करने, रोग के प्रकार व उसकी तीव्रता का सर्वेक्षण करने और बी० सी० जी० के टीके के प्रभाव के सबध में अध्ययन करने का भी कार्य करता रहा ।

वाराणसी, कानपुर और देवरिया में ३ चर्म रोग क्लीनिक थे जिनका संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाता था ।

झांसी और हमीरपुर में दो संचल कुष्ठ रोग दल कार्य कर रहे थे । ये दल एक गांव से दूसरे गांव में जाकर चिकित्सा कार्य करते थे, रोग के संधंध में सर्वेक्षण कार्य करते और रोग निरोधात्मक उपायों का प्रचार करते थे ।

नये चिकित्सा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की एक योजना की स्वीकृति सरकार ने दी और गोरखपुर के सिविल सर्जन को इस सबध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए आदेश दिये गये । इसी संबंध में एक ज्येष्ठ जन स्वास्थ्य अधिकारी को कुष्ठ निरोधक कार्यों के लिए ४ मास का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु चिलकल्लापल्ली (आंध्र प्रदेश) भेजा गया । वापस लौटने पर उसे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना था । राज्य कुष्ठ अधिकारी को अध्ययन के लिए विदेश भेजा गया । आलोच्य वर्ष में कुष्ठ निरोधक कार्यों के लिये हिन्द कुष्ठ निवारण सघ की उत्तर प्रदेश शाखा को राज्य सरकार द्वारा एक लाख रुपये का अनावर्तक अनुदान दिया गया ।

राज्य के जिला अस्पतालों और शाखा दवाखानों में भी कुष्ठ रोग के मरीजों की चिकित्सा का भी प्रबंध किया गया ।

### (३) रतिज रोग

रतिजरोग देहरादून जिले के जौनसार बाघर क्षेत्र में और देहरी गढ़वाल जिले के आसपास के क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला था । दिसम्बर, १९५६ में जौनसार बाघर क्षेत्र का एक छिट-पुट नमूना सर्वेक्षण, वहां स्थित एक सर्वेक्षण दल द्वारा, किया गया । इस क्षेत्र के लिए चकराता में एक रतिज रोग अस्पताल कार्य कर रहा था और एक संचल रतिज रोग टोली भी थी जो कि मरीजों के घर पर ही उनका उपचार करती थी ।

इन रोगों से पीडित व्यक्तियों का उपचार निम्नलिखित संस्थाओं में किया जाता था—

- (१) रतिज रोग क्लीनिक दुहरी, मिर्जापुर ।
- (२) मोती लाल नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद ।
- (३) उर्सला हार्समैन मेमोरियल अस्पताल, कानपुर ।
- (४) रतिज रोग क्लीनिक, क्रास्थबेट अस्पताल, नैनीताल ।
- (५) रतिज रोग क्लीनिक, प्यारे लाल शर्मा अस्पताल, मेरठ ।
- (६) शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल, वाराणसी ।
- (७) रतिज रोग विभाग, सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा ।

राज्य के अन्य सभी जिला अस्पतालों में इन रोगों की बाह्य चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध थी ।

### (४) नेत्र चिकित्सा

राज्य में आचलिक (जोनल) आधार पर नेत्र चिकित्सा के लिए विशेष उपाय किये जाते रहे । आचलिक नेत्र चिकित्सा सहायता योजना के अधीन राज्यके ग्राम क्षेत्रों में सीतापुर और अलीगढ़ के नेत्र चिकित्सालयों और लखनऊ आगरा तथा कानपुर के मेडिकल कालेजों के नेत्र चिकित्सा विभागों द्वारा जिला नेत्र चिकित्सा समितियों के सहयोग से काफी बड़ी संख्या में नेत्र चिकित्सा शिविर खोले गये ।

योग्य आप्टीशियन और रिफ्रेक्शनलिस्ट तैयार करने के उद्देश्य से जिससे कि यह लोग नेत्र चिकित्सकों के सहायक के रूप में कार्य कर सकें और अयोग्य व्यक्तियों को इस कार्य से मुक्त किया जा सके, अलीगढ़ के गांधी नेत्र चिकित्सालय में और सीतापुर के नेत्र चिकित्सालय में इन लोगों के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले गये । इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता था । प्रति वर्ष प्रत्येक स्कूल में २० छात्र भर्ती किये जाते थे । आलोच्य वर्ष में गांधी नेत्र चिकित्सालय अलीगढ़ से १२ छात्र उत्तीर्ण हुए । आशा की जाती थी कि अस्पतालों के नेत्र चिकित्सा विभाग में यह लोग लग जायेंगे ।

अलीगढ़ के गांधी नेत्र चिकित्सालय का नेत्र बैंक, दान द्वारा प्राप्त सामग्री की कमी के कारण विशेष प्रगति न कर सका और बहुत से मरीजों को जो कि अस्पताल में नयी आखें लगवाने गये थे, निराशा वापस लौटना पड़ा । सन् १९६० के वर्ष में और जनवरी, १९६१ के महीने में ८ मरीजों की नयी आखें लगायी गयी ।

काटेक्ट लेंस केंद्र, जिसका आरम्भ सन् १९४७ में हुआ था संतोषजनकरूप से कार्य करता रहा । सन् १९६० के वर्ष में काटेक्ट लेंसों के फिट करने के अतिरिक्त कास्मेटिक शेलों के उत्पादन के सम्बन्ध में काफी टेक्निकल कार्य किया गया । इस वर्ष ४२ कास्मेटिक शेल फिट किये गये ।

### (५) कैंसर

कानपुर में कैंसर के इलाज के लिए १०० शय्याओं का एक नया अस्पताल खोला जा रहा था । इस अस्पताल के लिए इमारत कानपुर के जे० के० इंस्टीट्यूट द्वारा बनवायी जा रही थी ।

इलाहाबाद के कमला नेहरू अस्पताल कैंसर कक्ष (विंग) के रख-रखाव के लिए जिसमें २४ शय्याओं का प्रबंध था, सरकार ने ६५,४६० रुपये की एक धनराशि स्वीकृत की ।

### रक्त बैंक

राज्य में ३ रक्त बैंक संतोषजनक रूप से कार्य करते रहे । डी० सी० बी० परीक्षा पास करने के बाद ८ अधिकारियों को रक्त बैंक के कार्य में प्रशिक्षित किया गया । जिससे कि यह लोग विभिन्न कमिशनरियों के सदर में स्थित रक्त बैंकों का कार्य संचालन कर सकें । ४७ अधिकारियों और लखनऊ के मेडिकल कालेज के स्नातकोत्तर छात्रों को आपत्तिकालिक रक्त बैंक की टेक्निक में प्रशिक्षित किया गया । आपत्तिकाल में चौबीस घंटे रक्त की आप्लाई करने के कार्य में यह अधिकारी काफी सहायक सिद्ध हुए ।

स्वैच्छिक रक्त दाताओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रक्त बैंक के सम्बन्ध में तीन वार्ताएं प्रसारित की गयी । इस विषय में जनता को शिक्षित करने के उद्देश्य से स्थानीय सभाचारपत्रों में कई लेख व सवाद पत्र आदि प्रकाशित कराये गये । काफी बड़ी संख्या में पुलिस व पी० ए० सी० के कर्मचारियों के रक्त की परीक्षा, उनका ब्लड ग्रुप निश्चित करने के उद्देश्य से की गयी ।

### अस्पताल सील की बिक्री

अस्पताल सील की बिक्री का सातवां अभियान जो कि २६ जनवरी, १९६० को आरम्भ किया गया था, २ अक्टूबर, १९६० को समाप्त हुआ। अभियान के दौरान में अस्पताल सील की बिक्री जिला स्वास्थ्य अधिकारियों की देख-रेख में आयुर्वेदिक औषधालयों एवं यूनानी दवाखानों में भी की गयी और समाचारपत्रों, पोस्टरों तथा सिनेमा स्लाइडों द्वारा काफी प्रचार किया गया। अस्पताल सील की बिक्री सतोषजनक रही।

### टी० बी० सील की बिक्री

उत्तर प्रदेश में टी० बी० सील की बिक्री के अभियान का संचालन उत्तर प्रदेश टी० बी० एसोसियेशन लखनऊ द्वारा किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्षय रोग के स्थानीय मरीजों को सहायता पहुंचाना और जनता को इस रोग के उत्पन्न होने के कारण तथा रोकथाम के उपायों के प्रति सचेत करना था। टी० बी० सील की बिक्री के दसवें (१९५९-६०) अभियान के अन्तर्गत टी० बी० सील की बिक्री से कुल ६७,७०९ रुपये एकत्र हुए।

### (ख) आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली

आयुर्वेदिक और यूनानी विभाग के कार्य कलापो में निरन्तर प्रसार होता रहा। मुख्य कार्य ग्राम-क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का प्रसार किया जाना था।

आलोच्य वर्ष के आरम्भ में राज्य में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालयों और यूनानी दवाखानों की कुल संख्या क्रमशः ५०० और ९० थी। सन् १९५९-६० के वर्ष में सरकार ने १० और दवाखाने खोले, जिनमें ८ आयुर्वेदिक औषधालय एवं २ यूनानी दवाखाने थे। इनमें प्रत्येक में ४ शय्याओं का इनडोर वार्ड भी था। राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय एवं यूनानी दवाखानों की इमारतों के निर्माण के लिए बजट में २,७४,००० रुपये की व्यवस्था की गयी। पहले के दवाखानों और औषधालयों की उपयोगिता बढ़ाने के उद्देश्य से फर्नीचर तथा अन्य साज-सज्जा के लिए ८७,००० रुपये की व्यवस्था की गयी।

जिला बोर्डों और नगरपालिकाओं द्वारा संचालित आयुर्वेदिक औषधालयों तथा यूनानी दवाखानों की कुल संख्या क्रमशः ४३० और ३८ थी। इनमें से ८३ को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता मिलती थी। शहर व ग्राम क्षेत्रों के एक बड़ी संख्या में वैद्यों व हकीमों को और औषधालयों तथा दवाखानों को काफी उदारतापूर्वक आर्थिक, सहायता दी जाती थी। यह सहायता स्वास्थ्य मन्त्री के उस कोष से दी जाती थी जो दातव्य कार्यों के लिए उनके पास रहती थी।

### आयुर्वेदिक और यूनानी राजकीय फार्मसी

आयुर्वेदिक और यूनानी राजकीय फार्मसी, जिसके द्वारा राज्य के औषधालयों एवं दवाखानों को दवाइयां सप्लाई की जाती थी, संतोषजनक रूप से प्रगति करती रही। आलोच्य वर्ष में फार्मसी द्वारा ७०९ मन विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाएं तैयार की गयी।

रामपुर खास में एक आयुर्वेदिक औषधालय तथा एक यूनानी दवाखाना था। बाराणसी जिले के रामनगर में एक औषधालय कार्य कर रहा था। राजकीय आयुर्वेदिक, कालेज लखनऊ में एक इन्डोर और एक आउटडोर वार्ड भी था। इस कालेज से सबद्ध अस्पताल में शय्याओं की संख्या १२० थी, जिनमें से २० शय्याएं किंग्स इंग्लिश हास्पिटल में थी। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना अवधि के अन्त तक इस विभाग की विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यान्वित होने पर लगभग ८०० व्यक्तियों को काम मिल जायगा। इस वर्ष १६ नये आयुर्वेदिक एवं यूनानी दवाखाने (पुरुषों के लिए) खोले गये। इन सभी में चार शय्याओं का एक-एक इनडोर वार्ड भी था।

बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों को दवाओं के रूप में काफी सहायता पहुंचाई गयी। इसके अनिरीकृत विभाग के वैद्य और हकीमों को इन क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता कार्य के लिए भेजा गया। सन् १९६० के अर्थ कुम्भ मेले के अवसर पर तीर्थ यात्रियों को चिकित्सा सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से तीन आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित किये गये।

### राजकीय आयुर्वेदिक कालेज

आयुर्वेदिक और यूनानी शिक्षा के विकास के लिए राज्य के आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजों को सरकार ने उदारतापूर्वक अनुदान दिया।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज में, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध था, लगभग ६५ छात्र थे।

लखनऊ के राजकीय आयुर्वेदिक कालेज में आवश्यक साज-सज्जा एवं टेक्निकल स्टाफ की व्यवस्था की गयी, ताकि प्रति वर्ष ४० छात्रों को सुगमता पूर्वक भरती किया जा सके। सरकार द्वारा नियुक्त उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुसार कालेज में आयुर्वेदाचार्य का एक नया पाठ्यक्रम सन् १९५६ से चालू किया गया। सन् १९५६ में इस पाठ्यक्रम में ११ छात्र और सन् १९६० में ३४ छात्र भरती किये गये।

इस कालेज के छात्रों को और अधिक टेक्निकल सुविधाएं पहुंचाने के और शय्याओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए यह आवश्यक था कि उसकी इमारतों और अस्पतालों में उचित परिवर्तन एवं परिवर्धन किया जाय। इस कार्य के लिए सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना अवधियों में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए ७,६२,३०० रुपये की धनराशि स्वीकृत की। यह रुपया प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में स्वीकृत किये गये ७,२४,००० रुपये की धनराशि के अतिरिक्त था।

### बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन्स

आलोच्य वर्ष में बोर्ड ने ३६० वैद्यों और ४५ हकीमों को पंजीकृत किया और इस प्रकार पंजीकृत वैद्यों और हकीमों की कुल संख्या क्रमशः २४,५८५ और ६,४३५ तक पहुंच गयी।

इस वर्ष बोर्ड से संबंध आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजों के निर्धन एवं योग्य छात्रों को २५-२५ रुपये प्रतिमास की १५ छात्रवृत्तियां दी गयीं। योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के लिए राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के बजट में ४,२०० रुपया की व्यवस्था की गयी।

### सामान्य

सन् १९४६ से ही विभिन्न क्षेत्रों में विभाग ने काफी प्रगति की। राजकीय आयुर्वेदिक औषधालयों और यूनानी दवाखानों की संख्या २५० से बढ़ कर ६०० तक पहुंच गयी। ग्राम क्षेत्रों के लोगों को चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के हेतु अनेक वित्तपोषित योजनाएं आरम्भ की गयीं। विभाग के कार्यकलापों पर और अधिक प्रभावपूर्ण नियन्त्रण एवं देख-रेख रखने के उद्देश्य से सन् १९५८ में सहायक निदेशक (आयुर्वेद) के एक अलग पद का सृजन किया गया।

आयुर्वेद और तिब्बी अकाडमी संतोषजनक रूप से अपना कार्य करती रहीं। उपयुक्त पाठ्य-पुस्तकों का चयन करने और आयुर्वेद की पुस्तकों का संस्कृत से हिन्दी में अनुवाद कराने के उद्देश्य से सरकार ने एक सम्पादक मण्डल की भी नियुक्ति की।

### (ग) होम्योपैथिक चिकित्सा, प्रणाली

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के तत्वावधान में ५ १/२ वर्ष का एक डिग्री कोर्स आरम्भ किया गया। ६० शय्याओं वाले एक अस्पताल की भी व्यवस्था की गयी। आलोच्य वर्ष में सरकार ने कालेज और अस्पताल के लिए १,८५,६०० रु० स्वीकृत किये। इस धनराशि में से ४८,००० रुपये साज-सज्जा के लिए, ३७,६०० रुपये कालेज और अस्पताल में रख-रखाव के लिए और १,००,००० रु० इमारतों के निर्माण के लिए थे। इस कालेज के आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने का प्रश्न विचाराधीन था। यह प्रस्ताव था कि जैसे ही कोई उपयुक्त भूमि मिल जाय, कालेज के लिए भारत सरकार की सहायता से एक इमारत का निर्माण किया जाय।

## अध्याय ६

### शिक्षा, अनुसंधान इत्यादि

#### १-शिक्षा

#### पूर्व-प्रारम्भिक शिक्षा

सन् १९६०-६१ के वर्ष में पूर्व प्रारम्भिक-शिक्षा को और प्रोत्साहन मिला। निम्न-लिखित नये नर्सरी स्कूलों को नियमित आर्थिक सहायता की सूची में सम्मिलित किया गया—

- (१) नर्सरी स्कूल, सिविल लाइन्स, गोरखपुर।
- (२) महिला सभा बाल मंदिर नर्सरी स्कूल, न्यूडण्डी, मुजफ्फरनगर।
- (३) थियोसोफिकल माटेसरी इन्फेंट स्कूल, इटावा।
- (४) माटेसरी स्कूल एवं बेसिक स्कूल, बरेली।
- (५) गुलाबराय माटेसरी स्कूल, बरेली।

आलोच्य वर्ष में उपरोक्त स्कूलों को १२,५०० रुपये का एक आवर्तक अनुदान स्वीकृत किया गया।

उन १२ नर्सरी स्कूलों को रखरखाव के लिए ८५,००२ रुपये का एक आवर्तक अनुदान स्वीकृत किया गया जिन्हें सन् १९५६-५७, १९५७-५८, १९५८-५९ और १९५९-६० की आर्थिक सहायता की नियमित सूची में सम्मिलित किया गया था।

#### माध्यमिक शिक्षा

(१) अंतरिम जिला परिषदों द्वारा शिक्षा पर व्यय—आलोच्य वर्ष के लिए अंतरिम जिला परिषदों द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय की जाने वाली निम्नतर धनराशि का सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्धारण किया गया —

	रु०
(१) बालको के लिए जूनियर हाई स्कूल ..	१,०५,१६,६७०
(२) अनिवार्यक्षेत्र क्षेत्रों में बालको के लिए सामान्य प्रारम्भिक पाठशालाएं .. ..	२,४५,४५,०७०
(३) अनिवार्यक्षेत्र क्षेत्रों में इस्लामिया स्कूल और मकतब ..	७,१८,२१०
(४) अनिवार्यक्षेत्र क्षेत्रों में हरिजनो की शिक्षा ..	५,०८,४३०
(५) अनिवार्यक्षेत्र क्षेत्रों में बालिकाओं की प्रारम्भिक शिक्षा .. ..	१५,३१,८२०
(६) बालको के लिए अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा ..	१४,३१,१५०
(७) बालिकाओं के लिए अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा ..	२७,४४०
(८) भूतपूर्व प्रारम्भिक पाठशालाएं .. ..	३,६४,००,५५०
(९) बालिकाओं के लिए जूनियर हाई स्कूल ..	१०,०६,४३०
योग ..	७,६६,८६,०७०

व्यय के इस मद से राज्य का अंशदान ६,५०,०७,३३० रुपये और परिषद् का १,१६,८१,७४० रुपये था।

२—बेकारी सहायता योजना के अन्तर्गत नये स्कूल खोलना—इस वर्ष भारत सरकार द्वारा प्रेरित “शिक्षित बेकारों की सहायता” योजना के अन्तर्गत राज्य के ग्राम क्षेत्रों में १,६०० जूनियर बेसिक स्कूल खोले गये।

३—ग्राम क्षेत्रों में दुनियादी प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार और विकास के लिए अनुदान—आलोच्य वर्ष में अर्त्तरिम जिला परिषद् को देने के लिए निम्नलिखित कार्यों के हेतु अनुदान स्वीकृत किये गये :—

उद्देश्य	धनराशि (रुपये में)
(१) द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना की परियोजना संख्या ६ के अन्तर्गत सन् १९६०-६१ में जूनियर बेसिक स्कूलों के सुधार के लिए ..	२१,३४,१२२ (आवर्तक)
(२) उपरोक्त परियोजना के अन्तर्गत रामपुर और टिहरी जिलों में जूनियर बेसिक स्कूलों के सुधार के लिए ..	५३,६००
(३) द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना की परियोजना संख्या ५४ के अन्तर्गत सन् १९६०-६१ में अध्यापकों की ‘वार्षिक वेतन वृद्धि पर होने वाले व्यय’ के भुगतान के लिए ..	३४,६६,६६६ (आवर्तक)
(४) द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना की परियोजना संख्या ८ के अन्तर्गत पहली से पाचवी कक्षा तक की फीस माफ होने से हुए घाटे की पूर्ति के लिए ..	२६,५७,६२५
(५) हरिजन छात्रों के संबंध में उपरोक्त कार्य के लिए ..	५,०२,६८०
(६) द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना की परियोजना संख्या ३ के अन्तर्गत सन् १९५८-५९ तक खोले गये २,७५० जूनियर बेसिक स्कूलों के रखरखाव के लिए ..	४६,६२,५६६ (आवर्तक)
(७) उपरोक्त कार्य के लिए, द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना की परियोजना संख्या ३ के अन्तर्गत जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा रामपुर और टिहरी-गढ़वाल में खोले गये जूनियर बेसिक स्कूलों के लिए ..	८८,३८४ (आवर्तक)
(८) भारत सरकार की परियोजना के अन्तर्गत बालिकाओं की शिक्षा के प्रसार के लिए और महिला अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए ..	७२,००० (अनावर्तक)
(९) रामपुर और टिहरी-गढ़वाल जिलों के भूतपूर्व राजकीय प्राइमरी स्कूलों के रखरखाव के लिए जो प्रारम्भिक शिक्षा प्रसार परियोजना के अन्तर्गत खोले गये थे ..	३४,१३१ (आवर्तक)
(रामपुर— ११,४८६ रुपये और टिहरी गढ़वाल २२,६४५ रुपये)।	



## उद्देश्य

धनराशि  
(रुपयों में)

(१०) शिक्षित बेकारों को सहायता परियोजना के अन्तर्गत सन् १९५९-६० में खोले गये १,३८८ जूनियर बेसिक स्कूलों के रख-रखाव के लिए .. .. .	२०,६९,५०८ (आवर्तक)
(११) उपरोक्त परियोजना के अन्तर्गत रामपुर और टिहरी गढ़वाल जिलों में सरकार द्वारा खोले गये ३७ नये जूनियर बेसिक स्कूलों के रखरखाव के लिए .. .. .	५५,१६७ (आवर्तक)
(१२) शिक्षा विभाग की एक परियोजना के अन्तर्गत मेरठ और वाराणसी के अन्तरिम जिला परिषदों की लड़कियों के स्कूलों की इमारतों के निर्माण के लिए .. .. .	१०,००० (अनावर्तक)
४—नगर क्षेत्रों में बुनियादी प्रारम्भिक पाठशालाओं (बेसिक प्राइमरी, स्कूलों) के विकास के लिए अनुदान—नगर पालिकाओं और कंटोमेन्ट बोर्डों को निम्नलिखित कार्यों के हेतु जो अनुदान दिये गये उनका विवरण निम्नलिखित है—	
(१) १७ नगरपालिकाओं में लड़कियों के लोअर मिडिल स्कूलों में सातवीं और आठवीं कक्षाएँ खोलने से संबंधित व्यय के लिए .. .. .	३६,३७६ (आवर्तक)
(२) लड़कियों के प्राइमरी स्कूलों में खोले गये बेसिक कक्षाओं से संबंधित आकस्मिक व्यय के लिए .. .. .	१६,६०६ (आवर्तक)
(३) नगरपालिका और कंटोमेन्ट बोर्ड के अध्यापकों को १ मार्च, १९५९ से क्रमशः २ रु० ५० पैसे और ५ रु० की दर से अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिये जाने से संबंधित व्यय के लिए .. .. .	३,८६,२३५
(४) जूनियर हाई स्कूलों के कक्षा ६ में फीस माफ किये जाने से हुए घाटे की पूर्ति के लिए .. .. .	१,५६,६६४
(५) उन सभी अध्यापकों को, जिनका वेतन १ जून, १९५७ को ६५ रु० प्रतिमास से अधिक नहीं था (अर्थात् वेतन, व्यक्तिगत वेतन यदि कोई हो तो और महंगाई भत्ता मिला कर) ५ रु० प्रतिमास की दर से अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिये जाने से संबंधित सम्पूर्ण व्यय के लिए .. .. .	६,७१,३७५
(६) उन अध्यापकों के महंगाई भत्ते में, जिनका भत्ता उनके आधारभूत वेतन में १ जनवरी, १९५७ से मिला दिया गया था, सरकार के अनादान से संबंधित व्यय के लिए .. .. .	७,९६,२४८
(७) १ अप्रैल १९५६ से अपने जूनियर हाई स्कूलों के प्रधान अध्यापकों के संबंधित वेतन क्रम के लागू किये जाने के फलस्वरूप अतिरिक्त व्यय के लिए .. .. .	३३,४८२

(८) नगरपालिकाओं के जूनियर हाई स्कूलों के जे० टी० सी० अध्यापकों का वेतन-क्रम सशोधित करने के सम्बन्ध में हुए सम्पूर्ण अतिरिक्त व्यय के बराबर सरकार के प्रशदान के लिए .. ..	२५,०४६
(९) नगरपालिकाओं के अधीन उन २६६ बालिकाओं की प्रारम्भिक पाठशालाओं से संबंधित आकस्मिक व्यय के लिए जिन्हें सन् १९४७-४८ से १९५७ तक बेसिक स्कूलों में परिवर्तित कर दिया गया था .. ..	७,७८८
(१०) द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत (परियोजना सख्या ६) जूनियर बेसिक स्कूलों (प्राइमरी स्कूलों) के सुधार से संबंधित व्यय के लिए .. ..	८४,७०६
(११) द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत (परियोजना सख्या ६-क) कक्षा १ से ६ तक घाटे की पूर्ति के लिए .. ..	११,६६३
(१२) उत्तर प्रदेश की नगरपालिकाओं, महापालिकाओं और कंटोनमेंट बोर्डों में कक्षा १ से ५ तक के हरिजन छात्रों की फीस माफी से संबंधित घाटे की पूर्ति के लिए .. ..	६,८१८
(१३) राज्य के कंटोनमेंट बोर्डों, आर्डिनेंस फैक्टरियो और रेलवे प्रशासनों द्वारा चलाये जाने वाले प्राइमरी स्कूलों के रख-रखाव के लिए .. ..	६०,३३७ (५७,३३७ + ३,००० आवर्तक)

५—अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा—राज्य के ६५ नगरपालिकाओं में लड़कों के लिए अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा जारी रही। इनमें से १० नगरपालिकाओं में लड़कियों के लिए भी अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा जारी रही। सन् १९६०-६१ में सरकार ने ५०,७७,७८० रुपये के लगभग एक आवर्तक अनुदान स्वीकृत किया जो कि बोर्ड द्वारा लड़कों के अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा पर किये जाने वाले सम्पूर्ण व्यय के तीन-चौथाई के बराबर सरकार का अशदान था और इसी प्रकार लड़कियों की शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार ने १३,५६,३०४ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया।

ग्राम क्षेत्रों में लड़कों के लिए अनिवार्य शिक्षा २६ जिलों में कुछ चुने हुए क्षेत्रों में चालू थी। इन क्षेत्रों में से ३ में लड़कियों के लिए भी अनिवार्य शिक्षा चालू थी।

६—पाठ्य पुस्तकें—आलोच्य वर्ष में बेसिक रीडर भाग ३ (हिन्दी) और बेसिक अक-गणित भाग ३ (हिन्दी) को जिन्हें बेसिक रीडर भाग १ और २ तथा बेसिक अकगणित भाग २ के बाद लिखा गया था कक्षा ३ के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। इसी प्रकार बेसिक अक-गणित भाग ३ (उर्दू) भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। इन पुस्तकों के पाठ्यक्रम, विषय, भाषा, चित्र आदि का बच्चों की रुचि और वातावरण का ध्यान रखते हुए पूर्ण रूप से संशोधन किया गया। नया बेसिक रीडर भाग ४ (हिन्दी) और नया बेसिक अकगणित भाग ४ (हिन्दी और उर्दू) तैयार किया जा रहा था। सन् १९६०-६१ में शिक्षा सत्र में कुल ८७,८६,६०० पुस्तकें मुद्रित की गयीं।

#### माध्यमिक शिक्षा—

१—बहु-उद्देशीय स्कूल—आलोच्य वर्ष में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का बहु-उद्देशीय स्कूलों में परिवर्तन करने की योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित स्कूलों में प्रत्येक में

१२० - ३०० रुपये प्रतिमास के प्रशिक्षित स्नातको के वेतन-क्रम में एक-एक मनोवैज्ञानिक अध्यापक की नियुक्ति जुलाई, १९६० से की गयी—

- (१) लडको के लिए राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, सीतापुर।
- (२) लडको के लिए राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, बिजनौर।
- (३) लडको के लिए राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, मैनपुरी।
- (४) लडकियों के लिए राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, जौनपुर।
- (५) लडको के लिए राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, फतेहगढ़।

इनके अतिरिक्त उपरोक्त योजना के अन्तर्गत देवरिया, पीलीभीत और कानपुर के राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के इन्टरमीडिएट की कक्षाओं में जुलाई, १९६० में टेक्नीकल ग्रुप का पाठ्यक्रम भी जारी किया गया।

२—स्कूलों का प्रान्तीयकरण—गीता स्वामी उच्चतर माध्यमिक स्कूल गोपेश्वर (जिला चमोली) का २७ अक्टूबर, १९६० को प्रान्तीयकरण किया गया।

३—राजकीय जूनियर हाई स्कूल का स्तर उठाना—राजकीय जूनियर हाई स्कूल पुरोला (उत्तरकाशी) का स्तर सन् १९६०-६१ के शिक्षा मंत्र से उच्चतर माध्यमिक (साहित्यिक वर्ग) स्तर तक कर दिया गया।

४—लडकियों के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का स्तर उठाना—फतेहपुर और ललितपुर (झासी) के लडकियों के राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का स्तर आलोच्य वर्ष में इंटर्मीडिएट तक का कर दिया गया।

५—नव-निर्मित जिलों में स्कूल कक्षाएं खोलना—पिथौरागढ़, उत्तर काशी और चमोली के नये बनाये गये जिलों में जुलाई, १९६० से सरकार ने निम्नलिखित स्कूल कक्षाएं खोलने की स्वीकृति प्रदान की—

जिला	प्राइमरी स्कूल	जूनियर हाई स्कूल	उच्चतर माध्यमिक स्कूल (नयी कक्षाएं आदि)
१	२	३	४
पिथौरागढ़	१५	५	जुलाई, १९६० से मुनसियारी के राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल की कक्षा ६ व १० में विज्ञान की पढाई आरम्भ की गयी। जुलाई, १९६० से मुनसियारी के राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल का स्तर साहित्य-वर्ग में इंटर्मीडिएट तक कर दिया गया।
उत्तरकाशी	३०	३	जुलाई, १९६० से उत्तर काशी के गवर्नमेंट हाई स्कूल का स्तर साहित्य वर्ग में इंटर्मीडिएट तक कर दिया गया।
चमोली	१५	७	जुलाई, १९६० से जोशीमठ के राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल की कक्षा ६ व १० में विज्ञान की पढाई आरम्भ की गयी।

६—संगीत की शिक्षा आरम्भ करना—आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित लड़कियों के राज-कीय जूनियर हाई स्कूलों में एक विषय के रूप में संगीत की पढाई आरम्भ की गयी :—

- (१) गवर्नमेन्ट गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल, टुडला ।
- (२) गवर्नमेन्ट गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल, करबी ।
- (३) गवर्नमेन्ट गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल, विन्दावा ।
- (४) गवर्नमेन्ट गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल, मऊ ।

७—प्रारम्भिक अनुदान—आलोच्य वर्ष में ४७ गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को आर्थिक सहायता की सूची में सम्मिलित किया गया ।

८—हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् (बोर्ड), उत्तर प्रदेश—सन् १९६२ को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए निम्नलिखित नये पाठ्यक्रम निर्धारित किये गये—

- (१) व्यावसायिक भूगोल (साहित्यिक वर्ग के अन्तर्गत इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए) ।
- (२) फ्रेंच (इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए) ।
- (३) कलात्मक मेटल-क्राफ्ट (पुराने ढांचे के अनुसार हाई स्कूल टेक्निकल परीक्षा के लिए) ।

सन् १९६३ की परीक्षा के लिए भूगोल, मनोविज्ञान और मुद्रण के पाठ्यक्रमों का संशोधन किया गया ।

सन् १९६० की बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में काफी बड़ी संख्या में छात्र बैठे। विभिन्न परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों का विवरण निम्नलिखित है :—

हाईस्कूल—

लड़के	..	..	..	..	२,०५,७४८
लड़कियां	..	..	..	..	२०,६२२
योग					२,२६,३७०

इंटरमीडिएट—

लड़के	..	..	..	..	६६,४१८
लड़कियां	..	..	..	..	१३,०२८
योग					१,०९,४४६

उपरोक्त परीक्षाओं में बैठे और सफल हुए उम्मीदवारों का विवरण निम्नलिखित है :—

हाईस्कूल परीक्षा—				बैठने वाले छात्रों की संख्या	सफल हुए छात्रों की संख्या
लड़के	..	..	..	१,६४,५६१	७४,६६१
लड़कियां	..	..	..	१६,३०७	११,४६२
योग				२,१३,८६८	८६,१२३
इंटरमीडिएट परीक्षा—					
लड़के	..	..	..	८६,५४५	३६,६११
लड़कियां	..	..	..	११,५००	६,१४२
योग				९८,०४५	४२,७५३

## विश्वविद्यालय की शिक्षा

१—विधि—निर्माण—विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में हाल में उत्पन्न कुछ नयी बातें सरकार की गंभीर चिन्ता के कारण बनी रही। यह बहुत तीव्रता पूर्वक अनुभव किया गया कि निर्वाचन पद्धति द्वारा उपकुलपति नियुक्त करने की प्रणाली उतनी यतोषजनक सिद्ध नहीं हुई जितनी की आशा की गयी थी। वास्तव में इससे विश्वविद्यालयों में गुटबंदी होने लगी और इसका कुप्रभाव न केवल उप-कुलपति के चयन पर पड़ा अपितु विश्वविद्यालयों के प्रशासन पर भी पड़ा। केवल यही नहीं इस प्रणाली के अन्तर्गत उपकुलपति के चुनाव का क्षेत्र व्यवहार रूप में बहुत ही संकुचित हो जाता था क्योंकि जो लोग सफलतापूर्वक चुनाव अभियान चला सकते थे वही इस पद पर आ सकते थे जबकि योग्य और प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्तियों के लिए चुनाव जा सकना संभव न होता था। यह बात विश्वविद्यालयों शिक्षा के हित में नहीं। इस कारण ने यह निश्चय किया गया कि विभिन्न विश्वविद्यालय अधिकारियों में उचित परिवर्तन कर दिया जाय और निर्वाचन पद्धति के स्थान पर चुनाव प्रणाली अपनायी जाय। गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम में निर्धारित उपकुलपति के चुनाव की प्रणाली काफी उपयुक्त समझी गयी और फलस्वरूप आवश्यक सशोधनों के साथ इस प्रणाली को ही एकरूपता के आधार पर आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ और गोरखपुर विश्वविद्यालयों तथा साथ ही वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए भी अपना लिया गया।

२—नवीन सहायता प्राप्त डिग्री कालेज—आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित डिग्री कालेजों को सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं की सूची में सम्मिलित किया गया—

- (१) डी० ए० बी० कालेज, बुलन्दशहर।
- (२) अग्रवाल डिग्री कालेज, इलाहाबाद।
- (३) एम० एल० कैं० कालेज, बलरामपुर, गोडा।

उपरोक्त कालेजों को सन् १९६०-६१ में लगभग १,००,४०० रुपये आवर्तक अनुदान देने की स्वीकृति दी गयी।

मदन मोहन ट्यूटोरियल कालेज, इलाहाबाद को भी इस वर्ष नियमित सहायता प्राप्त संस्थाओं की सूची में सम्मिलित किया गया।

३—दार्नासह विष्ट गवर्नमेंट डिग्री कालेज, नैनीताल—सन् १९५६ तक नैनीताल के दार्नासह विष्ट डिग्री कालेज में केवल कला और विज्ञान के ही विभाग (फैकल्टी) थे। सन् १९६० के शिक्षा ऋत्र से वाणिज्य विभाग खोला गया। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में कालेज में स्नात-कोत्तर स्तर तक कला, विज्ञान और वाणिज्य के तीनों विभाग थे।

सामान्य शिक्षा की परियोजना, जोकि इस कालेज की एक नयी विशेषता, थी इस वर्ष सफलतापूर्वक जारी रही। नियमित कार्यक्रम के अनुसार कालेज के पढाई के घटों में ही विभिन्न विषयों पर पूर्व-स्नातक कक्षाओं में सामान्य शिक्षा के ५३ लेक्चर दिये गये। ट्यूटोरियल और छात्रों को काम देने की पद्धति जोकि इस कालेज की एक दूसरी नवीन विशेषता थी, तथा पूर्व-स्नातक कक्षाओं के लिए अनिवार्य शारीरिक शिक्षा (पी० टी०) की योजना भी सफलतापूर्वक कार्य करती रही।

कालेज के विभिन्न प्रोफेसरों की देख-रेख में ४० अनुसंधान छात्र कार्य करते रहे। कालेज के १ अनुसंधान छात्रों को इस वर्ष आगरा विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि मिली।

कालेज में अनुसंधान की तीन परियोजनाएं अन्य परियोजनाओं के अतिरिक्त जारी रही। इन चीजों में से एक वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद् द्वारा प्रेरित थी, दूसरी एटमिक एनर्जी

कमीशन द्वारा और तीसरी कृषि अनुसंधान की भारतीय परिषद् द्वारा प्रेरित थी। इन तीनों परियोजनाओं को उत्तर प्रदेश की वैज्ञानिक अनुसंधान समिति द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त थी।

कालेज का ७ वा पदवीदानोत्सव ६ जन, १९६० को विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति श्री बी० बी० गिरि की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।

इस वर्ष की एक उल्लेखनीय घटना यह रही कि कालेज के प्रिन्सिपल, अध्यापको, कर्म-चारियों तथा छात्रों के सम्पत्तिदान और श्रमदान के फलस्वरूप एक बड़े कमरे का, जिसके फर्श का क्षेत्रफल ३,२०० वर्गफुट था, निर्माण-कार्य पूरा किया गया।

आगरा विश्वविद्यालय का चौथा युवक मेला भी इस कालेज में ११ से १३ अक्टूबर, १९६० तक मनाया गया। इस उत्सव का संगठन आगरा विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था और इसमें भाग लेने वालों की संख्या ३५० थी जोकि २१ संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते थे।

४—गवर्नमेंट रजा डिग्री कालेज, रामपुर—गवर्नमेंट रजा डिग्री कालेज, रामपुर की इस वर्ष की उल्लेखनीय घटना एन० सी० सी० का आरम्भ किया जाना था। यह योजना कालेज के छात्रों से काफी लोकप्रिय रही।

१८-१९ फरवरी, १९६१ को कालेज प्लानिंग फोरम के तत्वावधान में रामपुर से १० मील दूर सैदनगर नामक गाव में एक समाज सेवा शिविर सगठित किया गया, जहाँ अन्य कार्यों के अतिरिक्त पुरुषों और महिलाओं की अलग-अलग सभाओं में छात्र बालकों और बालिकाओं द्वारा भाषण दिया गया। छात्र बालकों ने गाव वालों के साथ श्रमदान में भी भाग लिया।

५—काशी नरेश राजकीय डिग्री कालेज, ज्ञानपुर (वाराणसी)—काशी नरेश राजकीय डिग्री कालेज, ज्ञानपुर में स्नातकोत्तर कक्षाओं तक कला, विज्ञान और वाणिज्य में शिक्षा दी जाती थी। पूर्वगामी वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कालेज में भरती हुए छात्रों की संख्या में २० प्रतिशत की वृद्धि हुई।

जुलाई, १९६० से इस कालेज में एन० सी० सी० की योजना लागू की गयी और इस वर्ष केडेटों की संख्या लगभग २०० थी।

कालेज के खेलकूद संघ ने इस वर्ष लगभग २,५०० रुपये की लागत से एक टेबुल टेनिस शैड का निर्माण किया।

६—विश्वविद्यालय अनुदान समिति, उत्तर प्रदेश—२० अप्रैल, १९६० को उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय अनुदान समिति का दूसरी बार गठन किया गया। पुनर्गठित समिति के कार्यों में निम्नलिखित कार्य और जोड़े गये :—

(१) नये विश्व-विद्यालयों की स्थापना के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना और इनमें से प्रत्येक के लिए उपयुक्त ढाँचे का सुझाव देना।

(२) उच्च शिक्षा से संबंधित सभी शैक्षिक विधि निर्माण संबंधी और प्रशासकीय मामलों में सरकार को सलाह देना।

(३) विश्वविद्यालयों और कालेजों के सम्पत्ति और पावना का अभिलेख (रेकार्ड) रखना और कालेजों के आर्थिक स्थिति के बारे में सरकार को रिपोर्ट देना।

आलोच्य वर्ष में समिति की चार बैठकें हुईं। इनमें से दो लखनऊ में और दो इलाहाबाद में हुईं। इन बैठकों में विश्वविद्यालयों और डिग्री कालेजों की मांगों पर विचार किया गया और अनेक महत्वपूर्ण वित्तीय एवं शैक्षिक मामलों के बारे में निश्चय किया गया। मेरठ में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने संबंधी एक प्रस्ताव तैयार करने की ओर समिति ने ध्यान दिया और कुमाऊ क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना भी समिति के विचाराधीन रही।

राज्य के डिग्री कालेजों को इमारतों के निर्माण के लिए तथा फर्नीचर, वैज्ञानिक उपकरणों और पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों आदि की खरीद के लिए आलोच्य वर्ष के बजट में निर्धारित डेढ़ लाख रुपये की धनराशि में से अनावर्तक अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में समिति ने सरकार के विचार के लिए प्रस्ताव तैयार किये। साथ ही सरकार के विचार के लिए राज्य के सहायता-प्राप्त डिग्री कालेजों को तीसरी योजना के अन्तर्गत १० लाख रुपये का 'विकास अनुदान' स्वीकृत करने के संबंध में भी समिति ने प्रस्ताव तैयार किये।

उत्तर प्रदेश की वैज्ञानिक अनुसंधान समिति का कार्यालय जोकि अभी तक उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय समिति के कार्यालय के साथ ही आरम्भ में ही एक ही इमारत में था, १ जुलाई, १९६० से हट कर अलग इमारत में चला गया जहाँ से वह स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा।

### प्रशिक्षण संस्थाएं—

१—सेन्ट्रल पेडागॉजिकल इंस्टीट्यूट—इलाहाबाद स्थित गवर्नमेंट सेन्ट्रल पेडागॉजिकल इंस्टीट्यूट पूर्व वर्षों की भांति ही अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में कार्य करता रहा। इसका मुख्य कार्य शिक्षा विभाग को एल० टी० परीक्षा के लिए छात्राध्यापकों को प्रशिक्षित करना और शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करना था। इसके कार्यों में उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना भी था और टेक्नीकल शिक्षा के संबंध में विभाग के विशेषज्ञ संस्था के रूप में भी यह कार्य करता था। इसके अतिरिक्त 'इन सर्विस' जनरल और 'इन सर्विस' हिन्दी नामक दो प्रकार के 'इन सर्विस' प्रशिक्षण भी इस संस्था के कार्यों में सम्मिलित थे। आलोच्य वर्ष में इन दोनों वर्गों के अध्यापकों के दो दलों को प्रशिक्षित किया गया। आलोच्य वर्ष में हुए प्रशिक्षण कार्य के सबंध में विवरण निम्न प्रकार है—

				प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
१				२
एल० टी० (नियमित)	..	..	..	७५
एल० टी० ('इन-सर्विस' अध्यापक)	..	..	..	७०
हिन्दी अध्यापक	..	..	..	५२

बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार जूनियर हाई स्कूल के विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों का संशोधन किया जा रहा था। आलोच्य वर्ष में तीसरी कक्षा के गणित और हिन्दी का पाठ्यक्रम संशोधित कर तैयार किया गया और उसे प्रकाशित किया गया।

इस संस्था के प्रसार सेवा विभाग ने २ सेमिनार, १ शिविर और ६ कार्यशालाओं का संचालन किया, जिनमें से विज्ञान, गणित और इतिहास की कार्यशालाएं उल्लेखनीय रही। आलोच्य वर्ष के अंत तक ३३ प्रकाशन निकाले गये। सेन्ट्रल पेडागॉजिकल इंस्टीट्यूट से सबद्ध अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्था ने वर्ष के अंत तक अंग्रेजी पढ़ाने की आधुनिकतम प्रणाली के संबंध में २६६ अध्यापकों को प्रशिक्षित किया। आलोच्य वर्ष में अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्था ने दो प्रकाशनों को पूरा किया। यह प्रकाशन—(क) टीचिंग इंग्लिश—ए गाइड फार टीचर्स, और (ख) ५ पूरक पुस्तकों का एक सेट, जिसमें ५ रीडरें भी थी, थे।

जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों के हैंड बुक विभाग ने हैंडबुक का दूसरा भाग भी अंतिम रूप से तैयार कर लिया तथा यह काम जून, १९६० तक समाप्त हो गया। इस कार्य के

लिये नियुक्त किये गये समीक्षकों द्वारा किये गये सुझावों के आधार पर प्रारूप में आवश्यक परिवर्तन किये गये।

बुनियादी शिक्षण प्रदर्शन स्कूल जोकि जनवरी, १९५८ में आरम्भ किया गया था. अपना कार्य करता रहा।

२—राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ—राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण विद्यालय, जिसने सन् १९४८ में इलाहाबाद में अपना कार्य आरम्भ किया था और जिसे सन् १९५० में लखनऊ स्थानान्तरित कर दिया गया था इन उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित करता रहा जिन्हें वाणिज्य वर्ग और कृषि वर्ग में मान्यता प्राप्त थी।

११वीं और १२वीं कक्षाओं के लिए इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषयों के लिये विस्तृत नोट तैयार करने के उद्देश्य से एक 'इन-सर्विस' ट्रेनिंग आरम्भ की गयी।

विद्यालय के प्रसार सेवा विभाग के एक सेमिनार कला अध्यापकों का 'इन-सर्विस' ट्रेनिंग और एक गृह विज्ञान कार्यशाला का संचालन किया।

३—राजकीय बेसिक ट्रेनिंग कालेज वाराणसी—राजकीय बेसिक ट्रेनिंग कालेज, वाराणसी में जो कि एक विशेष किस्म की संस्था थी पढ़ाये जाने वाले विषयों में कृषि एक मुख्य विषय था। महिला छात्राध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए कताई-बुनाई और गृह शिल्प के विषय भी आरम्भ किये गये। आलोच्य वर्ष में ६६ छात्राध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे जिनमें से ३५ महिला छात्राध्यापिकाएँ थीं।

४—राजकीय जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज—मुजफ्फरनगर, इलाहाबाद और लखनऊ के जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज संतोषजनक रूप से कार्य करते रहे। नियमित पाठ्यक्रमों के साथ निम्नलिखित 'इन-सर्विस' प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी संगठित किये गये—

कालेज का नाम	'इन-सर्विस' ट्रेनिंग
(१) राजकीय जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज, मुजफ्फरनगर।	द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना की परियोजना संख्या २६ (ख) के अन्तर्गत आर्ट मास्टर्स की 'इनसर्विस' ट्रेनिंग संगठित की गयी और आलोच्य वर्ष में राजकीय एवं सहायता प्राप्त संस्थाओं के ४० आर्ट मास्टर्स को प्रशिक्षित किया गया।
(२) राजकीय जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद।	स्कूलों के सबडिप्टी इन्स्पेक्टरों की दो दलों में तीन-तीन मास की 'इन सर्विस' ट्रेनिंग जिसमें ३५ सब-डिप्टी इन्स्पेक्टरों ने ट्रेनिंग प्राप्त की।
(३) राजकीय जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज, लखनऊ।	बुनियादी शिक्षा की प्रणाली में और भाषा अध्यापकों की 'इन-सर्विस' ट्रेनिंग।

५—महिलाओं के लिए राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय—इलाहाबाद स्थित महिलाओं के लिए राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय एक वर्षीय एल० टी० पाठ्यक्रम के लिए अध्यापकों को तैयार करता रहा।

१५ जुलाई, १९६० से ३० अक्टूबर, १९६० तक और २५ अक्टूबर, १९६० से २५ जनवरी, १९६० तक इतिहास में दो इन सर्विस पाठ्यक्रम संगठित किये गये। प्रशिक्षार्थियों के लिए एक मूल्यांकन कार्यशाला भी संगठित की गयी।



भारत सरकार द्वारा प्रेरित शारीरिक दक्षता अभियान के एक केन्द्र के रूप में विद्यालय को चुना गया।

लखनऊ राजकीय महिला प्रशिक्षण विद्यालय द्विवर्षीय सी० टी० पाठ्यक्रम के लिए महिला अध्यापको को तैयार करता रहा।

इलाहाबाद स्थित गृह विज्ञान का राजकीय विद्यालय राज्य के बालिका विद्यालयों के (गर्ल्स कालेजों में पढाये जाने वाले गृह विज्ञान के सर्टीफिकेट कोर्स के लिए अध्यापको को तैयार करता रहा। नियमित प्रशिक्षण के अतिरिक्त 'इन सर्विस' ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की गयी। २५ अक्टूबर, १९६० से २४ जनवरी, १९६१ तक १६ अध्यापको ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया।

राजकीय नर्सरी ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद नर्सरी स्कूलों के लिए (सी० टी० कोर्स) अध्यापको को प्रशिक्षित करता रहा। सन् १९६० में कालेज ने २६ प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापको तैयार किये।

प्रथम वर्ष की कक्षा में भरती की संख्या २३ थी।

६—राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण विद्यालय—पूर्व की भांति रामपुर के शारीरिक प्रशिक्षण विद्यालय में ग्रेजुएटो और अंडर-ग्रेजुएटो की भरती जारी रही और उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण में सर्टीफिकेट और डिप्लोमा के लिए प्रशिक्षित किया जाता रहा। उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के शारीरिक शिक्षा के अप्रशिक्षित अध्यापको के लिए यह विद्यालय पुनर्ध्यापन पाठ्यक्रम की व्यवस्था करता रहा।

महिलाओं के लिए इलाहाबाद स्थित राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण विद्यालय ने लड़कियों के लिए पी० टी० अध्यापको तैयार किये।

७—राजकीय जूनियर ट्रेनिंग कालेज—राज्य में राजकीय ट्रेनिंग कालेजों की कुल संख्या ६ थी। इनमें से दो महिलाओं के लिए थे। ये संस्थाएँ सतोषजनक रूप से कार्य करनी रही।

८—नार्मल स्कूल—राज्य में कुल १११ गवर्नमेन्ट नार्मल स्कूल थे, जिनमें से १७ स्कूल बालिकाओं के लिए थे। आलोच्य वर्ष में यह सब भी सतोषजनक रूप से कार्य करते रहे।

**मनोविज्ञान शाला, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद**

सन् १९६०-६१ के शिक्षा सत्र में स्कूल मनोवैज्ञानिक सेवा का और अधिक विस्तार किया गया। मैनपुरी, फतेहगढ़, बिजनौर और सीतापुर के लड़कों के और जौनपुर के लड़कियों के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में एक-एक मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति की गयी।

मनोवैज्ञानिक शाला ने, उसके केन्द्रों ने २५ स्कूल मनोवैज्ञानिकों ने ८वीं, १०वीं और १२वीं कक्षाओं के लगभग १५,००० विद्यार्थियों को ग्रुप आधार पर शिक्षा एवं व्यवसाय संबंधी तथा लगभग ४०० व्यक्तियों को व्यक्तिगत आधार पर शिक्षा, व्यवसाय और निजी मार्ग-प्रदर्शन संबंधी परामर्श प्रदान किये।

मनोवैज्ञानिकशाला ने, उसके केन्द्रों और मनोवैज्ञानिकों ने ६ स्कूलों को ६वीं कक्षा के प्राविधिक पाठ्यक्रमों में भरती करने में, तथा १६ स्कूलों को छठी कक्षा में भरती के लिए उम्मीदवार छांटने में सहायता दी। मनोविज्ञान शाला राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय में भरती के लिए उम्मीदवार छांटने के कार्य में भी लगी रही। भारत सरकार द्वारा विशेष योग्यता पर छात्र-वृत्तियाँ प्रदान करने हेतु उम्मीदवारों की भली-भांति जांच और उनके अंतिम चुनाव के लिए मनोविज्ञानशाला ने एक चुनाव केन्द्र के रूप में कार्य किया। राज्य के पुलिस विभाग को पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद में भरती के लिए थानेदारों के उम्मीदवारों के और सहायक पब्लिक प्रासिक्यूटो के उम्मीदवारों के चुनाव में भी मनोविज्ञानशाला ने सहायता की।

जिला मनोवैज्ञानिकों ने निम्नलिखित संस्थाओं को उनके पाठ्यक्रमों में भरती के लिए और छात्रवृत्ति देने के लिए उम्मीदवार छांटने में सहायता दी :—

- (१) हरकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर ।
- (२) उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, उद्वरपुर ।
- (३) राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, धाराणसी ।
- (४) लाल बाग गर्ल्स स्कूल, लखनऊ ।
- (५) सिटी माटेसरी स्कूल, लखनऊ ।
- (६) गवर्नमेन्ट पालीटेक्नीक, मेरठ ।
- (७) जूनियर टेक्नीकल स्कूल, दौराला ।

लड़कों के ५५ और लड़कियों के ३ राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के ११ प्लस अवस्था ग्रुप के सभी विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया । इस प्रकार जो आरुड़े एकत्र हुए उनका विश्लेषण किया गया और एक रिपोर्ट तैयार की गयी ।

कक्षा ८ में पिछड़े हुए लड़कों का पता लगाने के लिए इलाहाबाद के गवर्नमेन्ट इंटरमीडियेट कालेज में एक अग्रगामी योजना चालू की गयी । इसका उद्देश्य उनके पिछड़ेपन के कारणों का निश्चित करना और उसे दूर करने के लिए विशेष अध्यापन का कार्यक्रम निश्चित करना था ।

कक्षा ९ (टेक्नीकल) चुनाव के सिलसिले में एक फालोअप अग्रगामी योजना आरम्भ की गयी ।

मनोविज्ञान शाला ने कक्षा ८ के लिए मैकेनिकल एप्टीच्यूड टेस्ट और ज्योमेट्री अटेंशन टेस्ट जैसे कुछ टेस्ट तैयार किये और बी० पी० टी० १३ फार्म बी० के लिए सामान्य नियम तैयार किये । पहले से प्रयोग में आने वाले एम० ए० टी० की बैटरी के लिए 'व्याख्यात्मक' संकेत तैयार किये गये ।

इस संस्था ने प्रकाशन के लिए टी० ए० टी० का एक पूर्ण मैन्युअल तैयार किया जिसमें उसके प्रशासन एवं व्याख्या संबंधी पूरा-पूरा विवरण था । दशवहारिक मनोविज्ञान वार्तामाला भाग २, जिसमें सन् १९६० की बातोंओं का संकलन था और 'पाठ्य विषय' और 'व्यवसाय जगत' नामक दो पुस्तिकाएँ भी प्रकाशित की जा रही थीं । यह पुस्तकें विद्यार्थियों, अध्यापकों, अति-भाषकों, टेक्नीशियनों और साधारण लोगों के लिए थी ।

### प्रदेशीय शिक्षा दल

मई/जून, १९६० में प्रदेशीय शिक्षा दल के ५०० केडेटों और ४० अध्यापकों का वार्षिक-कालिक शिविर भंसूरी में हुआ । यह शिविर ३० दिनों का था । सैनिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त कैडेटों ने श्रमदान भी किया ।

प्रदेशीय शिक्षा दल के चुने हुए २,५०० केडेटों का टुकड़ियों में, वार्षिक प्रशिक्षण शिविर फैजाबाद में हुआ । प्रत्येक शिविर का कार्यकाल १४ दिनों का था । छठा शिविर लखनऊ में राज्य युवक समारोह के साथ-साथ जनवरी, १९६१ में हुआ । इस युवक समारोह में २,३०० से अधिक छात्रों ने भाग लिया ।

प्रदेशीय शिक्षा दल के कैडेटों, खेलकूद (एथेलेटिक) की टीमों और युवक मंगल दलों को राज्य के सभी जिलों से चुना गया जबकि शेष छात्रों को स्थानीय स्कूलों से चुना गया । इस समारोह में १० से १७ वर्ष की कच्ची उम्र के लड़के थे जिन पर अनुशासन और व्यवस्थित जीवन का विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है ।

### सामाजिक शिक्षा

शिक्षा प्रसार विभाग के १,३३२ पुस्तकालय, प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों में थे । इन पुस्तकालयों को पुस्तकों और कुल पत्रिकाओं का वार्षिक कोटा दिया जाता था । किताबों की खरीद के लिए ७५,००० रुपये निर्धारित किये गये थे ।

इस वर्ष के बजट में सहायता प्राप्त निजी ग्राम पुस्तकालयों के लिए ४,००० रुपये की व्यवस्था की गयी थी। इन पुस्तकालयों की उनकी स्थिति के अनुसार ३६ रुपये, ६० रुपये और ९६ रुपये की दर से अनुदान दिया गया।

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत आरम्भ किये गये सचल पुस्तकालय ने एक-एक सप्ताह के १३ शिविर चलाये। मुख्य माल के पुस्तकालय में विभागीय अधिकारियों के प्रयोग के लिए ३,८३९ पुस्तकें थी।

सभी १,३३२ पुस्तकालयों में अध्ययन कक्ष थे। इनके अतिरिक्त राज्य भर में फैले हुए २,६०० वाचनालय थे। इन वाचनालयों में पत्रिकाएं सप्लाई करने के लिए और मासिक पत्रिका, नव-ज्योति के प्रकाशन के लिए इस वर्ष के बजट में ४५,००० रुपये की व्यवस्था थी।

प्रसार सेवा के ५ और सचल दल के ४ वाहनो द्वारा गांवों में फिल्म दिखलाये गये। ३१ जनवरी, १९६१ तक कुल ५०७ फिल्म शो हुए।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १०,००० रुपये की आकस्मिक प्रकाशन व्यवस्था में नव साक्षरों के लिए निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित की गयीं.—

- (१) महाभारत की कहानियां—भाग १ और २
- (२) एक कथा सुनो (अस्पृश्यता निवारण)
- (३) चेचक,
- (४) नहर निकली
- (५) धानी चूनरिया
- (६) महारानी लक्ष्मी बाई

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत स्थापित दोनों सचल दलों में से एक ने प्रतापगढ़ जिले में और दूसरे ने इलाहाबाद जिले में शिविर लगाया। इन दलों ने साक्षरता कक्षाएं, खेल-कूद के क्लब, वाचनालय आदि संगठित किये और अक्सर राष्ट्रीय एवं सामाजिक उत्सव भी मनाये। आलोच्य वर्ष के अन्त तक लगभग ४६७ प्र दों को साक्षर बनाया गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्थापित प्रदर्शन दल ने उन वस्तुओं का प्रदर्शन किया, जिससे अच्छी खेती, अच्छी दस्तकारी और अच्छे रहन-सहन के लिए गांव वालों को प्रोत्साहन मिले। दल ने इस वर्ष सात ऐसे प्रदर्शन किये।

राज्य भर में २३ से २६ जनवरी, १९६१ तक सामाजिक शिक्षा सप्ताह मनाया गया।

माघ मेला के अवसर पर तीर्थ यात्रियों के लाभार्थ एक सामाजिक शिक्षा शिविर का संचालन किया गया। मेले में एक वाचनालय की भी व्यवस्था की गयी और तीर्थयात्रियों के लिए ९ फिल्म शो भी हुए।

### दृश्य-श्रव्य शिक्षा

दृश्य-श्रव्य शिक्षा योजना के अन्तर्गत पूर्वगामी वर्षों की भांति फिल्म और फिल्मस्ट्रिप्स तैयार की गयी। निम्नलिखित फिल्म और फिल्म स्ट्रिप अंतिम रूप से तैयार की गयीं :—

फिल्म

- (१) महाकवि निराला,
- (२) यमुना,
- (३) बालघर शिविर,
- (४) वाराणसी,
- (५) विभागीय समाचार,
- (६) सरल मशीन

## फिल्म स्ट्रिप--

(१) ऊन और उसकी उपयोगिता,

(२) जौनपुर ।

राज्य फिल्म पुस्तकालय के लिए, जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना की एक परियोजना के अन्तर्गत की गयी थी, फिल्मों की खरीद के हेतु बजट में ३८,००० रुपये और ५,००० रुपये की व्यवस्था की गयी । वर्ष के अन्तर्गत ११६ फिल्में, २० फिल्म स्ट्रिप्स और २७२ स्लाइडें खरीदी गयी ।

राज्य भर में पुस्तकालय के ६६ सदस्य थे और औसतन निकासी प्रतिवर्ष लगभग २,५०० फिल्मों और २०० फिल्म स्ट्रिप्स की थी ।

दृश्य-श्रव्य शिक्षा के राज्य बोर्ड की दसवी बैठक २ और ३ जनवरी, १९६१ को हुई । आगामी तीन वर्षों में तैयार की जाने वाली फिल्मों और फिल्म स्ट्रिप्स की प्रस्तावित सूची को बोर्ड ने अंतिम रूप दिया ।

मई-जून, १९६० के वाराणसी के उद्योग प्रदर्शनी में एक दृश्य-श्रव्य प्रदर्शनी सगठित की गयी । इसी उद्देश्य से जनवरी, १९६१ में हुई बरेली की राज्य खिलौना प्रदर्शनी में एक स्टाल लगाया गया ।

राज्य भर में शिक्षा सस्थाओं द्वारा जनवरी, १९६१ में सामाजिक शिक्षा सप्ताह के साथ-साथ दृश्य-श्रव्य सप्ताह भी मनाया गया ।

अध्यापकों के लिए, प्रोजेक्टरों के प्रयोग करने के संबंध में एक संक्षिप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम २० से २५ मई, १९६० तक सगठित किया गया ।

इसके अतिरिक्त फिल्म मूल्यांकन के संबंध में फतेहपुर जिले के धाता गांव में १२ से २२ मई, १९६० तक, हमीरपुर जिले के कबाई गांव में भी इसी अवधि में और मिर्जापुर के ० बी० डिग्री कालेज में २६ अगस्त से ३ सितम्बर, १९६० तक तीन प्रयोग आयोजित किये गये । प्रथम दो प्रयोगों का उद्देश्य गांव के प्रौढ़ों पर फिल्मों का प्रभाव आकना था और इसी प्रकार तीसरे प्रयोग का उद्देश्य डिग्री कालेज के छात्रों पर यह प्रभाव देखना था ।

## राज्य शैक्षिक खिलौना प्रदर्शनी

राज्य शैक्षिक खिलौना प्रदर्शनी जनवरी, १९६१ में बरेली में हुई । इस प्रदर्शनी को देखने लगभग एक लाख व्यक्ति गये, जिनमें स्कूलों के छात्र भी थे । इस प्रदर्शनी में २६ विभाग थे ।

## सामान्य

आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित सस्थाओं के लिए एस० एस० ई० एस० के वेतन-क्रम में सहायक अध्यापिकाओं के १४ पदों की स्वीकृति दी गयी—

(१) लड़कियों के लिए गवर्नमेंट इंटरमीडियेट कालेज, ललितपुर	..	८
(२) लड़कियों के लिए गवर्नमेंट इंटरमीडियेट कालेज, फतेहपुर	..	३
(३) लड़कियों के लिए गवर्नमेंट इंटरमीडियेट कालेज, हल्द्वानी	..	३

आलोच्य वर्ष में सर्वोफाईड टीचर्स ग्रेड में ८७ सहायक अध्यापिकाओं का चुनाव पूरा किया गया । यह चुनाव सन् १९५६-६० में विज्ञापित १४० पदों के संबंध में था ।

द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना की परियोजना संख्या ५६ के अन्तर्गत सी० टी० ग्रेड के तीन अध्यापकों के पद की स्वीकृति दी गयी । सन् १९६०-६१ में निम्नलिखित संस्थाओं में प्रत्येक

के लिए दो एल० टी० ग्रेड के सहायक अध्यापिकाओं के ६ पदों की स्वीकृति दी गयी—

- (१) लड़कियों के लिए राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, श्रीनगर
- (२) लड़कियों के लिए राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, भाव बहादुरनगर, (बुलन्दशहर)।
- (३) लड़कों के लिए पी० एन० गवर्नमेंट इंटरमीडियेट कालेज, रामनगर (वाराणसी)।

आलोच्य वर्ष में राज्य जन सेवा आयोग द्वारा चुने गये सी० टी० ग्रेड में ८ उम्मीदवारों को और एल० टी० ग्रेड में सहायक अध्यापिकाओं के लिए १३० उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया।

बाबू और मैनपुरी के लड़कियों के गवर्नमेंट इंटरमीडियेट कालेजों के दो पी० टी० अध्यापकों के पदों को सी० टी० ग्रेड से उठाकर एल० टी० ग्रेड में कर दिया गया।

आलोच्य वर्ष में स्कूलों के ६८ सब-डिप्टी इसपेक्टरों और लड़कियों के स्कूलों की ८ महिला सहायक इसपेक्टरों की नियुक्ति की गयी।

### इमारतें

२७१ लाख २३ हजार रुपये की अनुमानित लागत से अनेक इमारतों के निर्माण की व्यवस्था पहले द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गयी थी, पर बाद में योजना की अधिकतम धनराशि में कमी हो जाने के और कुछ परियोजनाओं के सांस्कृतिक मामलों तथा वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग को सौंप दिये जाने के कारण इमारतों के निर्माण के लिए ११६ लाख ३२ हजार रुपये की ही व्यवस्था रह गयी।

सन् १९६०-६१ के अन्त तक लगभग ८७ लाख २० हजार रुपये की लागत से अनेक इमारतों का निर्माण-कार्य पूरा किया गया। १० बहु उद्देशीय स्कूलों में टेक्नीकल विंग, ६ वितरक पुस्तकालयों से संबंधित इमारतें, ५ मनोवैज्ञानिक केन्द्र, महिलाओं के लिए शारीरिक शिक्षा विद्यालय की इमारत, रामपुर, ज्ञानपुर और नैनीताल डिग्री कालेजों के लिए होस्टल की इमारतें, १० जूनियर हाई स्कूलों की इमारतें, लड़कियों के ६ उच्चतर माध्यमिक स्कूल, लड़कों के २ उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और कई और इमारतों का निर्माण-कार्य पूरा किया गया।

भारत सरकार की एक योजना के अन्तर्गत ४१,६५,२०० रुपये के अनुमानित मूल्य के १२ नार्मल स्कूल के भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गयी। १९६०-६१ के अन्त तक उन पर ३१.१२ लाख रुपये व्यय किया जा चुका था।

सीमावर्ती क्षेत्र में ३,३२,८६० रुपये के अनुमानित मूल्य के १८ प्राइमरी स्कूलों, २ जूनियर हाई स्कूलों एवं एक हायर सेकेंडरी स्कूल के भवनों के निर्माण की भी व्यवस्था की गयी। इन भवनों में १,६१,४७० रुपये की अनुमानित मूल्य के १० प्राइमरी स्कूलों, एक जूनियर हाई स्कूल और एक हायर सेकेंडरी स्कूल के भवनों के निर्माण का कार्य पूरा हो गया।

### २—सैनिक स्कूल

१५ जुलाई, १९६० से लखनऊ में एक सैनिक स्कूल खोला गया।

शुरू में स्कूल में ५२ कंटेनर भरती किये गये। ५० कंटेनरों की प्रति वर्ष भरती में वृद्धि करके अन्त में कंटेनरों की संख्या २५० होनी थी। प्रतियोगिता परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर स्कूल में दाखिला किया गया, बशर्ते कि परीक्षार्थी का शरीर स्वस्थ हो। चूंकि स्कूल का उद्देश्य लड़कों को केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी में प्रवेश पाने के योग्य बनाना था, इसलिए पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी रखा गया। हिन्दी की शिक्षा देने पर भी जोर दिया गया ताकि वे लड़के जो केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में असफल हो जायें, तो किसी अन्य परीक्षा में बैठने अथवा अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने में उन्हें कोई अड़चन महसूस न हो।

पाठ्यक्रम पाच वर्ष का रखा गया। इस प्रकार पाचवें वर्ष तक प्रत्येक लड़के को हाई-स्कूल का समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करा देने और केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के योग्य बना कर राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी में भरती करा देने का विचार किया गया।

प्रत्येक क्वेट को कुल मिला कर १,००० रु० प्रति वर्ष फीस के रूप में देना होता है। इस धनराशि के अन्तर्गत पढ़ाई एवं परीक्षा की फीस, भोजन-व्यय, वरदी, पुस्तकें और लेखन-सामग्री, अध्ययनकालीन यात्रा का व्यय, खेल की सामग्री और चिकित्सा सम्बन्धी देख-रेख सभी कुछ सम्मिलित है। यह धनराशि रियायती है, क्योंकि प्रत्येक क्वेट पर वास्तविक व्यय इसके दूने से भी अधिक करना पड़ता है। यह फीस पाच-पांच सौ की दो किस्तों में ली जाती है, पहली किस्त जुलाई में स्कूल खुलने पर और दूसरी किस्त जाड़े की छुट्टियों के बाद स्कूल के पुनः खुलने पर।

अपनी इमारत के बन जाने तक, लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित लीलावती मुंन्धे विद्यालय के भवन में इस खेलने की व्यवस्था की गयी। यह इमारत पोस्ट वार सविसेज रिकान्ट्रक्शन फण्ड ट्रस्ट के अधीन है और लखनऊ-कानपुर रोड के ६वें मील पर स्थित है। इन इमारतों में परिवर्तन और सुधार करके इन्हें एक निवासनीय (residential) संस्था के योग्य बना लिया गया है। इसी सड़क के ११वें मील पर स्कूल के लिए स्थाई भवन का निर्माण होना था। इसके लिए आवश्यक भूमि पहले ही ली जा चुकी थी। भवन के निर्माण के कार्य के पूरे हो जाने और भवन के अगले २-३ वर्षों में तैयार हो जाने की आशा की गयी थी।

### ३-प्राविधिक एवं औद्योगिक शिक्षा

उद्योगों का निदेशालय प्राविधिक तथा औद्योगिक शिक्षा की ओर ध्यान देता रहा। शालोच्य वर्ष में ३० सरकारी और ७८ सहायता प्राप्त संस्थायें कार्य करती रही। प्रशिक्षण लगभग मुफ्त दिया जाता रहा। हाई स्कूल (प्राविधिक) के छात्रों से ४ रु० मात्र की फीस प्रति-मास ली जाती थी। फीसों में पूरी और आधी माफ भी की गयी। कुछ संस्थाओं को छोड़ कर, छात्रावास में रहने की फीस १ से ३ रु० तक ली गयी। कुछ संस्थाओं में राज्य के कई छात्रों को ५० रु० प्रतिमास प्रति छात्र को छात्रवृत्तियां दी गयीं।

इनसे सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित हैं :—

संस्था का नाम	छात्रवृत्ति-प्राप्त	
	छात्रों की संख्या	
(१) इंस्टीट्यूट आफ माइनिंग ऐण्ड जियालाजी, धनबाद ..	८	
(३) श्री जे० जे० कालेज, आफ ऐग्रीकल्चर, बम्बई ..	२	
(३) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइन्स, बंगलौर ..	७	
(४) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर ..	८	
(५) जे० के० इंस्टीट्यूट आफ एप्लाइड फिजिक्स, इलाहाबाद	२	
कुल योग ..	२७	

विभिन्न संस्थाओं की अन्तिम (फाइनल) परीक्षा में १,६६८ तक छात्र सम्मिलित हुए। जिनमें १,४६० सफल घोषित किये गये। शालोच्य वर्ष में विभिन्न संस्थाओं के छात्र प्रदेश के अन्तर्गत और उसके बाहर भी शैक्षिक पर्यटन के लिए भेजे गये। निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा शिक्षित बेकार नवयुवकों के लिए सहायता योजना में २,६४,००० रुपये की धनराशि दी गयी, जिसमें १,७६,३०० रु० की धनराशि का उपयोग किया गया।

- (१) राजकीय पोलिटेकनिक, लखनऊ।
- (२) राजकीय सेंट्रल टेक्स्टाइल इंस्टीट्यूट, कानपुर।
- (३) राजकीय लैबर इंस्टीट्यूट, कानपुर।

योजना के अन्तर्गत प्रत्येक छात्र को प्रतिमास २५ रुपया की छात्र वृत्ति दी गयी। आलोच्य वर्ष में राजकीय संस्थाओं के ५ शिक्षकों ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्ट्रक्टर, कोनो (विलासपुर) से इंस्ट्रक्टर का प्रशिक्षण प्राप्त किया। १० नवीन संस्थाओं को भी सहायक अनुदान दिया गया और ८ सहायता प्राप्त संस्थाओं को अतिरिक्त आवर्तक अनुदान दिया गया जैसा कि नीचे अंकित है :—

संस्था का नाम	प्रदत्त धनराशि रु०
(१) हरिजन आश्रम, इलाहाबाद .. ..	२,५००
(२) सी० एच० जी० एन० टेक्निकल इंस्टीट्यूट, मानिकपुर (इटावा) .. ..	२,०००
(३) बधिर एवं मूक विद्यालय, लखनऊ .. ..	२,०००
(४) महिला शिल्प कुटीर, स्टेशन रोड, आगरा .. ..	२,४००
(५) टेक्निकल कालेज के साथ अनुलग्न लेदर स्कूल, दयालवाग, आगरा .. ..	३,०००
(६) महिला शिल्प विद्यालय, नजरबाग, लखनऊ .. ..	२,०००
(७) महिला शिल्प कला केन्द्र, आजमगढ़ .. ..	१,०००
(८) श्रद्धानन्द अनाथ बनिता आश्रम, देहरादून .. ..	२,०००

इस वर्ष प्रादेशिक सरकार ने ३,३७,४५७ रुपये का ऋण स्वीकृत किया।

#### ४—प्राविधिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण बोर्ड

प्रादेशिक प्राविधिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण बोर्ड ने प्रथम बार नीचे दी गयी सारिणी में उल्लिखित परीक्षाओं को चालू किया। (इसमें पाठ्यक्रमों, विषयों तथा छात्रों की संख्याओं का भी विवरण दिया गया है) —

परिषद् (बोर्ड) के द्वारा १९६०-६१ में चालू परीक्षाएं	निर्धारित पाठ्यक्रम	विषय	परीक्षित छात्रों की संख्या
(१) प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षा	त्रिवार्षिक उपाधि पत्र (डिप्लोमा)	सिविल इंजीनियरिंग	१,०१९
	" "	मेकेनिकल इंजीनियरिंग	१८०
	" "	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	१४७
	द्विवर्षीय उपाधि-पत्र	प्रिंटिंग टेक्नोलोजी ..	३७
	" "	लेदर टेक्नोलोजी ..	१०
	त्रिवर्षीय उपाधि-पत्र	टेक्सटाइल टेक्नोलोजी एवं टेक्सटाइल केमेस्ट्री	२२
	द्विवर्षीय प्रमाण-पत्र	ड्राफ्ट्समैन शिप	१५
		कुल योग ..	१,४३०

परिषद् (बोर्ड) के द्वारा १९६०-६१ में बालू परीक्षाएं	निर्धारित पाठ्यक्रम	विषय	परीक्षित छात्रों की संख्या
(२) दूसरे वर्ष की वार्षिक परीक्षा	त्रिवर्षीय उपाधि-पत्र	सिविल इंजीनियरिंग	५६७
	" "	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	१४७
	" "	मेकेनिकल इंजीनियरिंग	२१४
कुल योग			८२८
३-अन्तिम वर्ष की परीक्षा	त्रिवर्षीय उपाधिपत्र	सिविल इंजीनियरिंग	५८
	" "	मेकेनिकल इंजीनियरिंग	१७८
	" "	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	१०६
	" "	आर्किटेक्चर	१२
	द्विवर्षीय उपाधिपत्र	प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी	५५
	" "	लेदर टेक्नोलॉजी	६
	द्विवर्षीय (पुराना) उपाधिपत्र	सिविल इंजीनियरिंग	१३०
	" "	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	२
	" "	सर्वेयर	७
	" "	कम्प्यूटर	१४
	" "	ड्राफ्ट्समेनशिप	१९
कुल योग			५६०

इसके अतिरिक्त भी बोर्ड ने पूरक परीक्षाओं की व्यवस्था की। इस परीक्षा के योग्य घोषित परीक्षार्थियों की संख्या १,०५३ थी।

आलोच्य वर्ष में बोर्ड ने इंजीनियरिंग वोकेशनल स्कूल, नखतऊ के लिए स्वीकृत अन्तःकालीन सम्बन्ध को समाप्त कर दिया। क्योंकि यह उचित स्तर का न हो सका था। बोर्ड ने निर्देशक, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ५ जूनियर टेक्निकल स्कूलों को अपने से सम्बद्ध किया, तथा बोर्ड इन स्कूलों की केवल अन्तिम प्रमाणपत्रीय परीक्षा की व्यवस्था करता था।

### ५--रुड़की विश्वविद्यालय

रुड़की विश्वविद्यालय ने इस वर्ष और अधिक प्रगति की। विभिन्न कक्षाओं में विद्यार्थियों को पूर्व की भांति प्रतियोगिता-परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर ही प्रवेश दिया गया (जो कि आलोच्य वर्ष में मई, १९६० में हुई थीं)। १९६०-६१ में की जाने वाली भरती से सम्बन्धित आकड़े नीचे दिये जा रहे हैं :

पाठ्यक्रम	प्रविष्ट छात्रों की संख्या
स्नातकोत्तर (इंजीनियरिंग)	७८
एम० एस-सी०	१४
अन्डर ग्रेजुएट	८४६
डिप्लोमा	७१०
फारेन स्कालर्स (विदेशी छात्र)	८२



प्रयोगात्मक विज्ञान (एप्लाइड साइन्स) के सर्वसाधन सम्पन्न विभाग, यथा एप्लाइड फिजिक्स, एप्लाइड केमिस्ट्री, एप्लाइड मेटेमेटिक्स, एप्लाइड जियोफिजिक्स, एप्लाइड जियोलॉजी, सितम्बर, १९६० से एम० एस-सी० की उपाधि देने के लिए स्थापित किये गये। (इनका पाठ्यक्रम २ वर्ष का था)।

डिग्री पाठ्यक्रमों (डिग्रीकोर्स) की अवधि विश्वविद्यालय अनुदान समिति की इच्छानुसार ३ वर्ष से ४ वर्ष कर दी गयी।

शिक्षकों की स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ। अधिक से अधिक नये लोगों को लेने का प्रयास जारी रखा गया। शिक्षकों का अधिक लाभप्रद जगहों पर चले जाने का क्रम भी जारी रहा।

आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित इमारतों के निर्माण पर २६,१५,१४१ रुपये व्यय हुआ :—

- (१) मेकनिकल इंजीनियरिंग लेबोरेटरी ब्लॉक,
- (२) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेबोरेटरी ब्लॉक,
- (३) साइन्स ब्लॉक (फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेटेमेटिक्स),
- (४) इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का छात्रावास (डी०) ब्लॉक,
- (५) ओवरसीयर स्टूडेंट्स का छात्रावास,
- (६) कम्युनिटी हाल,
- (७) डब्लू० आर० डी० टी० सी०—कम—फोटोप्रोसेसिंग बिल्डिंग।

छात्रों में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं पायी गयी।

### ६—राजकीय वेधशाला, नैनीताल

विभिन्न अनुसंधान जिसमें चन्द्रमा के फोटो लेने की प्रक्रिया और कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण सम्मिलित है इस वर्ष आरम्भ हो गयी। चन्द्रमा की १४० सफल पट्टिकाएँ प्राप्त हुईं और कृत्रिम उपग्रहों के १,०८३ मार्ग अभिलिखित हुए।

इस वेधशाला में डवार्फ सेफीड सी० वार्ड० अवशरार्थ के ऊपर निश्चित समय को जानने और पूर्व कालिक परीक्षणों द्वारा बतलाये गये समय के परिवर्तन का निर्णय करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक निरीक्षण जारी रहे।

प्लानिंग आब्जर्वेशन—दिसम्बर, १९६० में मंगल के पीछे वाले अन्तिम भाग के चारों ओर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए लाल और हरे फिल्टरों द्वारा ग्रह के फोटोग्राफ लिये गये। फोटो के साइज को निगेटिव पर लगभग २ मिलीमीटर तक का बढ़ा कर देने के लिए १५" रेफ्लेक्टर के साथ "बाली अटैचमेन्ट" का प्रयोग किया गया और १७६ उपयोगी फोटोग्राफ लिये गये।

गत वर्ष प्राप्त १५" का रेफ्लेक्टर टेलिस्कोप काम में लगा दिया गया और १०" टेलिस्कोप का एक कैमरा बना लिया गया। एक प्रेडिग मानोक्रोमीटर के लिए आर्डर दे दिया गया। वर्ष के मध्य से ही वर्कशॉप में काम होने लगा था। कुछ और अधिक सामान—वेलर प्रेसीजन टूल रूम लाये, एक आर्क वोल्टेज यूनिट, एक गैस वोल्टेज यूनिट, एक स्प्रै पेन्टिंग यूनिट, एक १० इंच ग्राइन्डर और एक वोल्फ फ्लेक्सिबल शाफ्ट ग्राइन्डर प्राप्त किये गये।

पुस्तकालय—आलोच्य वर्ष में पुस्तकालय में खगोल विद्या, भौतिक और मेटेमेटिक्स से संबंधित लगभग २०० पुस्तकें और आयीं। पांच और पत्रिकाओं के पुराने अंक भी प्राप्त किये गये और वेधशाला ६० पत्रिकाओं को चन्दा बेकर मंगाती रही।

**इमारतें**—मुख्य प्रशासकीय ब्लॉक और-कर्मचारी वर्ग के आवासगृहों के निर्माण का कार्य शीघ्रता से आगे बढ़ा और यह आशा की गयी कि वेधशाला मनौरा पीक पर शीघ्र ही चली जायगी।

**सामान्य**—पूर्वनिदेशक के कोडाइकनाल चले जाने पर सहायक ज्यो.तेविंद (असिस्टेन्ट एस्ट्रोनामर) ने वेधशाला के निदेशक की हैसियत से १ अप्रैल, १९६० को कार्यभार संभाल लिया।

### ७—स्मारकों की सुरक्षा

पुरातत्व विभाग द्वारा निम्नलिखित स्मारकों की मरम्मत का कार्य किया गया—

- (१) पैरियार का प्राचीन मंदिर, (उन्नाव जिला)।
- (२) भारत माता का मंदिर, (वाराणसी जिला)।
- (३) छत्ती पलना का मंदिर या चौरासी खम्भा और योगमाया का मंदिर, (मथुरा जिला)।
- (४) श्री सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर, ग्राम सिधौली, (सीतापुर जिला) (पुनर्नवता कार्य)।

पुरातत्व विभाग से संबंधित कार्य पुरातत्व विभाग के इंजीनियर की देख-रेख में चलता रहा। पुरातत्व अधिकारी के पद के योग्य कोई व्यक्ति के मिलते ही उसकी नियुक्ति कर दी जाये, ऐसा प्रस्तावित किया गया।

### ८—राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय

राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय, लखनऊ में २४३ छात्र थे, जिनमें ५६ छात्राएँ भी सम्मिलित थीं। इथोपिया के एक छात्र को मिलाकर कुल ७५ छात्रों को विभिन्न उपाधि-पत्र दिये गये तथा सयुक्त राष्ट्र अमेरिका के भी दो छात्र विद्यालय में प्रविष्ट हुए।

गृह निर्माण कला (आर्टिटेक्चर) का एक केवल त्रिवाषिक उपाधिपत्राधीन पाठ्यक्रम रखने का निर्णय किया गया जोकि राजकीय प्राविधिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण बोर्ड से संबद्ध था। साथ ही यह भी निर्णय किया गया कि आर्टिटेक्चर के चतुर्थ और पंचम वर्ष के विद्यार्थियों को रुइकी विश्व-विद्यालय में स्थानान्तरित कर दिया जाये। लियो प्रोसेस फोटो मेकैनिकल कोर्स के अन्तर्गत तीन रंग के ब्लाको को बनाने की शिक्षा देना भी सम्मिलित कर लिया गया।

इस वर्ष अप्रत्याशित गोमती की बाढ़ से विद्यालय की संपत्ति और इमारतों को बहुत क्षति हुई।

### ९—संग्रहालय और पुस्तकालय

**राजकीय संग्रहालय** लखनऊ—राजकीय संग्रहालय की बनारसीबाग (लखनऊ) स्थित नई इमारत का ईंट, पत्थर, चूना संबंधी कार्य समाप्त हो गया और विद्युतीकरण कार्य वर्ष के अन्त में प्रगति पर था।

संग्रहालय द्वारा ८८ कलात्मक वस्तुओं को प्राप्त किया गया। इनमें पत्थर तथा पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ, शस्त्रास्त्र, हाथी दात के बने सामान, फरमान, रंगीन चित्र और कला से संबंधित अन्य वस्तुएँ सम्मिलित थीं।

संग्रहालय के पुस्तकालय की ओर भी वृद्धि हुई और लगभग ३३० पुस्तकें तथा १०० पत्रिकाएँ संग्रहालय के कर्मचारियों एवं अन्य अनुसंधान के छात्रों की अनुसंधान सुविधा के लिए प्राप्त की गयीं।

संग्रहालय का नित्य प्रति का कार्य काल प्रातः साढ़े नौ बजे से सायं साढ़े चार बजे (शीतकाल में) एवं प्रातः साढ़े नौ बजे से सायं साढ़े पांच बजे तक (ग्रीष्मकाल में) जनता की भाग पर परिवर्तित कर दिया गया। पहले यह ८ बजे से ११½ बजे प्रातः तथा डेढ़ बजे से ५½ बजे सायं तक हुआ करता था। राजकीय संग्रहालय की दोनो शाखाओं—लाल बारादरी तथा कैसर बाग आर्किपैजिकल प्रशाखा को देखने के लिए कुल मिलाकर १,६२,०२४ दर्शक आये जिनमें कई सम्मानित व्यक्ति भी थे। गंगा स्नान के दिन सबसे अधिक संख्या में (२,३८०) दर्शक आये।

जहाँ तक स्मरण है राजकीय संग्रहालय में स्थित वस्तुओं का मिलान कभी नहीं हुआ था। बहुत-सी अनियमितताएँ देखी जाने के फलस्वरूप वस्तुओं का मिलान किया गया। १,०४,८३२ वस्तुओं का मिलान किया गया और उसका पता लगाया गया। ५,६२५ वस्तुएं खोयी हुई पायी गयीं और उन वस्तुओं को खोजने के लिए या फिर बट्टेखाते में डाल देने के लिए कार्यवाही हो रही थी।

राजकीय संग्रहालय के अधिकारी को जोकि निदेशक की हैसियत से कार्य करते थे (श्री एम० एम० नागर) १ सितम्बर, १९६० से अनिवार्य निवृत्ति दी गयी और स्पेशल ड्यूटी पर कार्य करने वाले एक अधिकारी को उनका कार्य भार सौंप दिया गया। संग्रहालय में रखी मुद्राओं के विशाल संग्रह का, जिनमें कि अधिकांश सूचीबद्ध नहीं थे—मिलान तथा सूचीबद्ध करने के लिए एक मुद्रा-शास्त्री की नियुक्ति की गयी। एक सहायक क्युरेटर, एक फोटोग्राफर एवं आर्टिस्ट, एक लेबोरेटरी असिस्टेन्ट और एक गाइड लेक्चरर की भी नियुक्ति की गयी।

**पुरातत्व संग्रहालय मथुरा**—पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा द्वारा आलोच्य वर्ष में ४६१ वस्तुएं क्रय की गयीं, जिनमें ११३ पत्थर की, २३६ पकी हुई मिट्टी की, ७ कासे की मूर्तियां या पात्र, ८ पैन्टिंग, २० मिट्टी की सीलिंग, २ लकड़ी पर की गयी नक्काशी की वस्तुएं, १ हाथीदांत का टुकड़ा, एक ताबे की प्लेट और १०३ सिक्के सम्मिलित थे।

कई पत्थर की मूर्तियों और पक्की हुई मिट्टी की मूर्तियों अथवा पात्रों को जिन पर नक्सों का हानिकारक प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा था, का रासायनिक उपचार और उन्हें सुरक्षित रखने का कार्य किया गया। संग्रह की पुरानी इमारत जोकि राजस्व विभाग से वापस ले ली गयी थी तथा जिसमें इसको पहले स्थानान्तरित कर दिया गया था और जिसमें पत्थर के ऊपर की गयी अत्युत्तम आलंकारिक पच्चीकारी की वस्तुएं रखी थी, की मरम्मत की गयी और इसमें अतिरिक्त दर्शनीय सामग्री रखने का प्रबन्ध किया गया। वर्तमान संग्रहालय के भवन के विस्तार की कार्य इस वर्ष जारी रखा गया ताकि वह पूरा हो जाये। बने हुए भाग में गैलरियों के अतिरिक्त एक मुद्राकक्ष, फोटोग्राफी लेबोरेट्री, एक स्टुडिओ और एक पुस्तकालय रखना प्रस्तावित किया गया था। केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय तथा सरकारी जिला पुस्तकालय, दिसम्बर, १९४९ में इलाहाबाद में स्थापित केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश, में पुस्तकों का संग्रह विशेषतया ऐसे प्रकाशनो का था जोकि प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स ऐक्ट (१८६७ अधिनियम, २५) के नियमों के अन्तर्गत सरकार को प्राप्त हुए थे। आलोच्य वर्ष में लगभग ३,००० पुस्तकें प्राप्त हुईं। पुस्तकालय में आलोच्य वर्ष में काफी राइट वाली १,२०० पुस्तकें प्राप्त हुईं। पुस्तकालय में ५,००० से अधिक पाठक आये और उन्होंने लगभग ६,००० पुस्तकों का उपयोग किया। वाल-पुस्तकालय के लिए लगभग ५०० अंग्रेजी और हिन्दी की किताबें प्राप्त की गयीं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अल्मोड़ा, मेरठ, मथुरा, आगरा, बरेली, कानपुर, झांसी, वाराणसी और गोरखपुर के ६ सरकारी जिला पुस्तकालयों में पुस्तकाध्यक्षों की नियुक्ति की गई और आलोच्य वर्ष में अल्मोड़ा, मथुरा और मेरठ के जिला पुस्तकालयों में सदस्य बनाना आरम्भ हुआ।

**सार्वजनिक पुस्तकालय, इलाहाबाद**—इलाहाबाद के सार्वजनिक पुस्तकालय में दुर्लभ पुस्तकों, पुरानी पत्रिकाओं, सरकारी प्रकाशनो, पालियाभट सबधी पत्रादि तथा (मुख्यतः १६वीं सदी की) ब्लू बुक्स का अच्छा खासा संग्रह था। उत्तर प्रदेश और इसके निकटवर्ती राज्यों के अनुसंधानकर्त्ताओं को तथा उच्च अध्ययन में लगे हुए लोगों को अनुबंधान कक्ष में कार्य करने के

लिये विशेष सुविधायें प्रदान की जाती रही। यह कक्ष प्रति दिन आरान्ह ३ घंटे खुला रहता था। सामान्य अध्ययन कक्ष प्राच्य कक्ष तथा पुस्तकें देने वाला प्रभाग नित्य प्रति १० घंटे के लिए खुला रहता था। पुस्तकालय हर सप्ताह में बृहस्पति के दिन बन्द रखा जाता था ताकि वे लोग जो कार्य दिवसों में पुस्तकालय नहीं जा सकते थे, रविवार के दिन आ सकें।

## १०-राजकीय अभिलेखागार

विभिन्न फलेबंदियों से कई अभिलेख तथा प्रकाशन, जिनमें २४७ पुरानी छपी हुई पुस्तकें सम्मिलित थी, प्राप्त किये गये। उत्तर प्रदेश की स्वतंत्रता आन्दोलन समिति का इतिहास के कार्यालय से ८,००० पत्रावलिया पुनः स्थानान्तरित की गयी। ६७,०२९ पृष्ठों पर सख्या अंकित की गयी, १,३४२ शीटों को सुरक्षित किया गया, ३६६ शीटों को भरम्भत की गयी और ४२,२६२ शीटों की सिलाई की गयी। १२७ किताबों को जिल्दबन्दी की गयी। ३०,५८६ मदों को, जिनमें अभिलेख, पुस्तकें और पत्रावलिया थी, छाटा गया और व्यवस्थित रूप से रखा गया। इसके अतिरिक्त बंडलों, पत्रावलियों, रजिस्ट्रो को और अभिलेख के खंडों को, जिनकी सख्या कुल मिलाकर २१,६७३ थी, की झडाई-पुछाई की गयी और उनको धुआ देकर सुरक्षित रखा गया। लखनऊ स्थित राजस्व बोर्ड के कार्यालय में एक प्राविधिक सहायक के नेतृत्व में सुधार करने वालों का एक दल इसलिए भेजा गया ताकि छोटा छतरमंजिल की इमारत के गिर जाने के फलस्वरूप जिन पुराने नक्शों को पानी से नुकसान पहुंचा था उनमें सुधार किया जा सके। अभिलेखों के २,८०१ खंडों, ७७८० पाण्डुलिपियों और २,४६५ दस्तावेजों का मिलान किया गया और उन्हें व्यवस्थित किया गया। फारसी की ३०० पाण्डुलिपियों और दस्तावेजों को तथा संस्कृत की २८० पाण्डुलिपियों का प्रविष्टिलेख किया गया और गढ़वाली भाषा के २२५ पत्रों को लिपिबद्ध किया गया।

अनुसंधान कक्ष में प्रदेश पाने के लिए छः अनुसंधान-कर्त्ताओं ने प्रार्थना-पत्र दिये। इनमें से केवल चार ने इस सुविधा से लाभ उठाया। तीनों अनुसंधान कर्त्ताओं ने, जिन्हें अनुसंधान कार्य सबधी सुविधाएँ पूर्वगामी वर्षों में दी गयी थीं, अपना कार्य जारी रखा।

असरकारी व्यक्तियों से १०८ पाण्डुलिपि और ६६ दस्तावेज क्रय किये गये और ६६८ खंड, १२३ पत्रावलिया तथा ६१ बंडलों की माग की गयी।

## ११-साहित्यिक प्रकाशन

आलोच्य वर्ष से पजीकृत किये गये प्रकाशनों की कुल संख्या १,५८५ थी। हिन्दी प्रकाशनों की संख्या, जो कि ६८६ थी, अन्य भाषाओं के प्रकाशनों से अधिक थीं। अंग्रेजी में ३५५, संस्कृत में ५६, उर्दू में २८, बंगाली में चार अरबी में २, फारसी में २, गुरुमुखी में २, नेपाली में २ और मराठी में एक, पुस्तकें प्रकाशित हुई। हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू इत्यादि में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं की संख्या १४१ थी।

## १२-राज्यभाषा

प्रादेशिक सरकार की भाषा नीति (जिसको प्रादेशिक सरकार के ८ अक्टूबर, १९४७ के परपत्र में घोषित किया गया और १९५० के उत्तर प्रदेश भाषा अधिनियम में तथा जिसे २० जुलाई, १९५८ की प्रादेशिक सरकार की प्रेस विज्ञप्ति में समाविष्ट किया गया) आलोच्य वर्ष में और आगे कार्यान्वित की गयी। दफ्तर के कामों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तरीके अपनाये गये और यह निर्णय किया गया कि जहां तक हो सके केन्द्रीय सरकार और उसके अधिकारी वर्ग के साथ हिन्दी में ही पत्र-व्यवहार किया जाय।

प्रादेशिक सरकार ने यह अनुभव किया कि अब वह समय आ गया है जब पंचायत राज् आधुनिक के अधीन समस्त अभियोगों का निर्णय और सिविल, क्रिमिनल तथा माल के नुकदमों के निर्णय जो कि जटिल नहीं हैं और जिनकी अपील हाई कोर्ट में होने की संभावना नहीं है, हिन्दी में लिखे जायें। इस बात को ध्यान में रख कर सरकार ने उच्च न्यायालय, बोर्ड आफ रेवेन्यू तथा उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधीशों को उचित कार्यवाही करने की नलाह देने हुए पत्र भेजा।

२ अप्रैल, १९६० की सरकारी विज्ञप्ति द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि उच्च स्तरीय और कठिन हिन्दी को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये ताकि सभी जगह सरकारी दफ्तरों में माधारण हिन्दी के शब्दों और वाक्यों के प्रयोग का एक सामान्य वातावरण निर्मित हो जायें। परिणाम-स्वरूप यह कहा गया कि दफ्तरों में प्रयोग की जाने वाली हिन्दी साधारण और आसानों से समझ में आने योग्य होनी चाहिये।

### अल्प संख्या भाषाभाषियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था

प्रादेशिक सरकार ने उर्दू को प्रोत्साहन और उत्तर प्रदेश के अल्प संख्यकों की भाषा को संरक्षण देना जारी रखा। प्रदेश में अल्प संख्यकों की भाषा के संरक्षण हेतु भारत सरकार के अल्प-संख्यक भाषा आयुक्त ने फरवरी, १९६१ में मुख्य मंत्री से बातचीत की।

[तत्कालीन आचार्य जे० बी० कृपलानी संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक भाषा समिति की (८ अगस्त, १९६१ के अध्याधारण गजट में प्रकाशित राज्य सरकार के प्रस्ताव स्वरूप) नियुक्ति हुई। इस समिति का काम था उर्दू की वर्तमान सुरक्षा का निरीक्षण करना और उसके कार्यान्वयन में होने वाली कठिनाइयों तथा कमियों का पता लगाना। इसके अतिरिक्त उर्दू के उत्थान के लिए आगे जिन तरीकों को अपनाया जाना आवश्यक है उनका पता लगाना भी इस कमेटी का ही काम था।]

आलोच्य वर्ष में अल्प संख्यक भाषा आयुक्त की दूसरी और तीसरी रिपोर्ट के लिए आवश्यक सामग्री भेजी गयी। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अल्प संख्यकों की भाषा-सुरक्षा के स्वीकृत प्रस्तावों के विषय में उठाये गये कदमों के संबंध में जानकारी दी गयी थी।

### अखिल भारतीय ग्रंथ-सूची के हिन्दी और उर्दू संस्करणों का प्रकाशन

अखिल भारतीय ग्रंथ-सूची के हिन्दी और उर्दू संस्करणों के प्रकाशन हेतु किये गये प्रस्ताव को सिद्धान्तरूप में प्रादेशिक सरकार द्वारा सहमति दे दी गयी किन्तु १९५९ की ग्रंथ-सूची के हिन्दी और उर्दू के संस्करणों का मुद्रण कार्य नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता के प्रधान पुस्तकाध्यक्ष की सहायता से मार्च, १९६० में प्रारम्भ हुआ और राष्ट्रीय ग्रंथ-सूची १९५८ तथा कौमी किताबियत शौब-ए-उर्दू १९५८ का प्रकाशन १९६० की जुलाई में हुआ। इन प्रकाशनों में डिलीवरी आफ बुक्स ऐंड न्यूज पेपर्स, ऐक्ट १९५४ के अन्तर्गत कलकत्ता की नेशनल लाइब्रेरी में प्राप्त हिन्दी और उर्दू (१९५८) के प्रकाशनों का एक आधिकारिक अभिलेख भी संलग्न था।

आलोच्य वर्ष में राष्ट्रीय ग्रंथ-सूची के १९५९ के संस्करण तथा कौमी किताबियत-शौब-ए-उर्दू (१९५९-६०) के संस्करण से संबंधित कार्य दूसरे वर्ष के अंत तक पूरे होने की आशा थी।

ऐसी आशा की जाती थी कि ये प्रकाशन उपयोगी सिद्ध होंगे और हिन्दी तथा उर्दू रचने वाले लोग उनसे लाभ उठावेंगे।

निरीक्षकों द्वारा संभव न थी, उन्हें ही मरम्मत के लिए क्षेत्रीय सर्विस स्टेशनों पर लाया गया। भेड़नऊ स्थित मुख्य कार्यालय में एक रेडियो इंजीनियर के अधीन सब साधनों से सुसज्जित एक वर्कशॉप भी थी।

देहाती रेडियो गोष्ठी—देहाती रेडियो गोष्ठी योजना का कार्य भी सतोषप्रवृत्त रहा, जिससे सामान्य जनता को अच्छी प्रकार सूचित करने और प्रबुद्ध करने के लिए नवम्बर, १९५६ में चलाया गया था। देहाती रेडियो गोष्ठी जो एक क्लब के रूप में थी और जिसके २० के आस-पास सदस्य थे, उस गांव में आयोजित की जा सकती थी जहां सामुदायिक श्रवण योजना के अन्तर्गत एक रेडियो सेट लगाया गया हो। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि हर गांव में यह गोष्ठी हो जहां सरकार द्वारा रेडियो दिया गया हो। राज्य के ४७ जिलों में १९६०-६१ की अवधि में १८९ देहाती रेडियो गोष्ठियां कार्य कर रही थी। कुछ कठिनाइयों के कारण राज्य के ७ पहाड़ी और सीमावर्ती जिलों में इस कार्यक्रम को चालू करना संभव नहीं सका।

आल इंडिया रेडियो 'देहाती रेडियो गोष्ठी' शीर्षक से एक विशिष्ट विषय का कार्यक्रम प्रत्येक मंगलवार को ६-४५ बजे से सवा सात बजे तक ब्राडकास्ट करता है।

एक मासिक पत्रिका 'देहाती रेडियो गोष्ठी पत्रिका' प्रदेश के प्रधान कार्यालय से विशिष्ट रूप से इस योजना के अन्तर्गत प्रकाशित होती है। इसकी प्रतियां गोष्ठी की सभी बुलाने वालों को मुफ्त भेजी गयी हैं।

कठपुतली प्रदर्शक दल आदि—आलोच्य वर्ष में चार कठपुतली का नाच दिखाने वालों का दल और चार भजन मंडलियां नियुक्त की गयीं। कठपुतली नचाने वालों का दल राष्ट्रीय बचत योजना के प्रचार के लिए रखा गया और भजन गाने वाले, सरकार की विकास संबंधी गति विधि को ग्रामीण जनता को उनकी बोलियों में बतलाने के लिए नियुक्त किये गये।

लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, देहरादून, मथुरा, बादा, अल्मोडा, मेरठ, बलिया और रायबरेली जिलों के देहाती में खुले हुए स्थानों में नाटक खेलना १९६०-६१ में प्रारम्भ किया गया। भारत सरकार ने ११,८५० रु० की राज सहायता इन दस देहाती नाट्य मंडलियों के लिए प्रदान की।

जिला सूचना अधिकारियों को ट्रेलर से युक्त चार नयी जीपें खरीद कर जिले के काम के लिए दी गयीं।

फिल्म—इस वर्ष में निम्नलिखित नौ फिल्मों निर्मित हुई :—

- १—वनवासी थारू (रंगीन)
- २—हमारे सीमान्तवासी (रंगीन)
- ३—एक दिन की बात
- ४—एबोकेन वेस
- ५—फेदारनाथ
- ६—क्वालिटी मार्किंग स्कीम
- ७—सैनीटेशन एंड सिविक सेन्स
- ८—पी० डब्ल्यू० डी० प्रोजेक्ट
- ९—न्यूज मैगज़ीन न० ३।

लेबर कालोनीज, मिर्जापुर के बर्तन तथा वाइल्ड लाइफ इन तीन फिल्मों के निष्कर्ष का काम प्रगति कर रहा था।

राज्य के अन्तर्गत प्रसार कार्य के लिए निम्नलिखित फिल्मों के १६ मिलीमीटर के आकार के ६० प्रिन्ट्स तैयार हो गये थे ।

- १—वनवासी धारू
- २—एक दिन की बात
- ३—तैनीटेशन ऐण्ड सिविक सेन्स
- ४—पी० डब्ल्यू० डी० प्रोजेक्ट
- ५—न्यूज मैगजीन नं० ३
- ६—पारस पत्थर

७—एक प्रबुद्ध नागरिक के गणतंत्र में कर्तव्य जो सिनेमा स्लाइड तैयार किये गये उनका विवरण नीचे दिया जाता है ।

राज्य के विभिन्न सिनेमा घरों में उनके प्रदर्शन की व्यवस्था की गयी—

विषय	स्लाइडों की संख्या		
	रंगीन	काली और सफेद	
१	२	३	
१—पंचवर्षीय योजना	२०	२००	.. ..
२—दीवाली के उपहार	३००	..	.. ..
३—बड़े दिन के उपहार	३००	..	.. ..
४—जन्म दिन के उपहार	२७५	..	.. ..
५—वैवाहिक उपहार	२७५	..	.. ..
६—प्राइज बान्ड्स	५८०	..	.. ..

भेड़ चराई सबधी ७-७ स्लाइडों के १० सेट भी तैयार किये गये ।

किसान मेले और प्रदर्शनों—इस वर्ष सूचना विभाग ने विभिन्न स्थानों पर या तो प्रदर्शनियों की व्यवस्था की या उनमें भाग लिया । जिन प्रदर्शनियों ने विभाग में भाग लिया उनमें आधेयुक्त प्रदर्शनी, वाराणसी, नौचंदी का मेला, मेरठ, देवा मेला की प्रदर्शनी और भावनगर की प्रदर्शनी सम्मिलित थी । भारत सरकार के सहयोग से इसने नैनीताल, कानपुर और सुल्तानपुर में प्रदर्शनियों की व्यवस्था की । लखनऊ की प्रदर्शनी में अल्पबचत योजना के प्रचार की विशेष व्यवस्था की गयी । गढ़वाण, बसोली और पिथौरागढ़ में भी एक-एक प्रदर्शनी की व्यवस्था की गयी । लखनऊ स्थित प्रदर्शनी भवन बनारसी बाग में अल्प बचत योजना के महत्व का प्रदर्शन करने वाली एक प्रदर्शन इकाई की स्थापना की गयी । एक चल प्रदर्शनी ने गाजीपुर, बलिया और बनारस जिले के ग्रामों में भ्रमण किया ।

इसके अतिरिक्त जिलों की इकाइयों ने जिलों के स्तर पर ग्रामीण जनता में सरकारी कार्यक्रमों के प्रचार के लिए विभिन्न किसान-मेले तथा प्रदर्शनियों में भाग लिया ।

लखनऊ स्थित प्रदर्शनी भवन बनारसी बाग में राज्य सरकार द्वारा विविध क्षेत्रों में की गयी प्रगति और उपलब्धियों का प्रदर्शन करने के लिए एक स्थायी प्रदर्शनी की भी व्यवस्था की गयी ।

पुराने तथा बेकार हो गये सामानों को बदलने के लिए ७ प्रोजेक्टर, ६ जेनरेटर और ४ एम्प्लीफायर आलोच्य वर्ष में खरीदे गये ।

रबी अभियान, पंचवर्षीय योजना और अल्प बचन के सिलसिले में विशेष प्रचार किया गया । इसके अतिरिक्त जिलों में प्रदर्शन के लिये बड़े बोर्ड लगाये गये ।

उत्सव, सांस्कृतिक समारोह आदि—पूर्वगामी वर्षों की भांति स्वतंत्रता दिवस-समारोह तथा अन्य राष्ट्रीय उत्सवों से संबंधित समारोहों के आयोजन में विभाग भाग लेता रहा । आलोच्य वर्ष में इस काम के लिए बजट में १ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी ।

गत वर्षों की भांति लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस (१५ अगस्त) के अवसर पर लोक-गीत समारोह और १४ नवम्बर, बाल दिवस के अवसर पर एक लोक नृत्य समारोह का आयोजन किया गया । प्रदेश के विभिन्न जिलों की लोक-गीत और लोक-नृत्य की मंडलियाँ उत्सव में भाग लेने के लिये आमन्त्रित की गई थी । लोक-गीत समारोह में फैजाबाद और गोडा की मंडलियों ने क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया तथा देहरादून जिले की जौनपुर भावर क्षेत्र की लोकनृत्य-मंडली लोक-नृत्य उत्सव में सर्वश्रेष्ठ रही । यह मंडली गत वर्षों की भांति प्रादेशिक सरकार द्वारा दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय लोक-नृत्य समारोह में भाग लेने के लिए भेज दी गयी जो कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर संगीत-नाटक अकादमी के तत्वावधान में आयोजित किया गया था । फैजाबाद की लोक-संगीत मंडली जो कि लोक-संगीत समारोह में प्रथम आयी थी, भी आल इंडिया रेडियो द्वारा आयोजित प्रोग्राम 'राष्ट्र निर्माताओं के गीत' में भाग लेने के लिए भेज दी गयी । गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा आयोजित भव्य समारोह शोभायात्रा में भाग लेने के लिए इस वर्ष टेबलू न भेजा जा सका ।

अन्तर्प्रदेशिक सांस्कृतिक-शिष्टमंडल विनिमय के प्रोग्राम के अन्तर्गत एक सांस्कृतिक शिष्ट-मंडल पश्चिमी बंगाल से लखनऊ मार्च के अन्तिम सप्ताह में आया और एक सांस्कृतिक प्रदर्शन भी किया । इस प्रदर्शन में टिकट द्वारा प्रवेश की व्यवस्था थी और टिकट की बिक्री द्वारा प्राप्त राज्य सरकार के राजस्व के मद में जमा कर दी गयी ।



## अध्याय ७

### कल्याण, उत्थान एवं सहायता तथा पुनर्वास

#### १—श्रम कल्याण\*

मिलबन्दी, हड़ताले, तालाबन्दी इत्यादि ।

रिहन्द बांध के मजदूरों द्वारा एक हड़ताल किये जाने के अतिरिक्त श्रम स्थिति सामान्यतः शांतिपूर्ण रही । रिहन्द बांध की हड़ताल ने एक समय ऐसा रूप धारण किया कि गोली चलाने की आवश्यकता पड़ गयी परन्तु अन्त में स्थिति काबू में आ गयी और काम पुनः चालू हो गया ।

मिलबन्दी के ५१ और बैठकी के १,०६८ मामले हुए जिनका प्रभाव क्रमशः ४,०५१ एवं ७५,८०३ मजदूरों पर पड़ा जबकि पूर्वगामी वर्ष में ये संख्याएँ ६,३३८ और ३२,३६७ थीं । १९६० में छुट्टी किये गये मजदूरों की संख्या २,६१८ थी जबकि १९५९ में यह संख्या १,०१२ थी । वर्ष भर में कुल मिला कर ५८ हड़ताले हुईं जिनसे २१,१६८ मजदूर प्रभावित हुए और कुल मिलाकर १,१४,०३० काम के दिनों की हानि हुई जबकि पूर्व वर्ष में ५५ हड़ताले हुई थी जिनसे १३,०५५ मजदूर प्रभावित हुए थे और कुल १,४७,०७३ काम के दिनों की हानि हुई थी ।

#### संस्थान बोर्ड और राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण

आलोच्य वर्ष में संस्थान बोर्डों के समस्त ५,०८१ मामले निर्णय के लिए आये, जिनमें से ४,१७२ मामले निपटाये गये । इन ४,१७२ मामलों में ऐसे १,३३२ मामले भी सम्मिलित थे जिन्हें या तो वर्ष के अन्त तक वापस ले लिया गया था या जो जमा कर दिये गये थे । ६६१ मामलों में समझौता हो गया था । संस्थानीय कार्यवाही से अलग ६७ समझौते हुए जिनमें से ३७ समझौते यू० पी० इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट, १९४७ के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में रजिस्टर किये गये ।

#### अधिनिर्णय

अधिनिर्णय के लिए श्रम अदालतों तथा औद्योगिक न्यायाधिकरणों के पास ६२६ मामले भजे गये । इनमें से आलोच्य वर्ष में ६५८ मामले निपटाये गये ।

मध्यस्थ द्वारा निर्णय किये जाने वाले ६० मामलों में से २६ निर्णीत हुए । राजकीय कारखानों की विवादों में हल करने के लिए स्थापित स्थायी संस्थान बोर्डों को ४३ नयी शिकायतें प्राप्त हुईं और १९५९ की १२ शिकायतों को मिलाकर ५५ शिकायतें हो गयीं । इनमें से ४२ शिकायतें निपटा दी गयीं । इस प्रकार फँसने के लिए १३ शिकायतें रह गयीं ।

#### फैसलों का क्रियान्वयन

आलोच्य वर्ष में श्रम अदालतों तथा औद्योगिक न्यायाधिकरणों ने ऐसे ३८६ फैसले दिये जिनमें क्रियान्वयन आवश्यक था । इनमें से २३ फैसलों में क्रियान्वयन स्थापित कर दिया गया और वर्ष के अन्त तक २६ ऐसे भी मामले थे जो क्रियान्वयन के लिए परिपक्व नहीं थे । शेष

---

\* इसका सम्बन्ध १९६० के कैलेंडर वर्ष से है ।

३२७ फंसलो में से २५६ का क्रियान्वयन किया गया। ५ फंसलो के क्रियान्वयन किये जाने की पुष्टि मजदूर यूनियनो द्वारा होनी शेष थी और ४३ फंसलों के क्रियान्वयन हो जाने की जांच हो रही थी।

बीस फंसलो का क्रियान्वयन शेष रहा था। इनमें २० में से ६ में मालिको ने समादेश प्रस्तुत किये और एक मामले में मजदूरों ने अपील दायर की। एक मामले में फंसले के अन्तर्गत दिये गये पैसे का भुगतान लेने मजदूर नहीं आये और दो मामलो में फंसले के क्रियान्वयन किये जाने से सम्बन्धित शर्तों में मतभेद रहा। ६ मामलो में मालिको द्वारा अपनाये गये रुख के कारण फंसलो का क्रियान्वयन नहीं हो सका। दो मामलो में जिन कारखानो को फंसलो का क्रियान्वयन करना था वे हीरे बन्द हो गये। मालिकों के पास धनाभाव के फलस्वरूप २ अन्य मामलो में फंसले क्रियान्वित न किये जा सके।

### अनुशासन संहिता

मालिको और मजदूरों द्वारा अनुशासन संहिता के नियमों की अवहेलना सम्बन्धी शिकायतों की संख्या क्रमशः ३६ और २८ रही। जांच करने पर इनमें से अनुशासन भंग सम्बन्धी ८ शिकायतें साबित नहीं हो सकीं। १६ शिकायतों में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी और १२ शिकायतें आपसी समझौते से रफा हो गयीं। शेष २५ मामलो में सम्बन्धित लोगों से कहा गया कि वे अनुशासन संहिता के नियमों का पालन किया करें।

### मूल्यांकन एवं कार्यान्वयन समिति

फंसलो समझौते और निबटारों के कार्यान्वयन में शीघ्रता लाने के लिए तथा उन्हें और अच्छा रूप देने के लिए जनवरी सन् १९६० में श्रम यन्त्री की अध्यक्षता में एक मूल्यांकन एवं कार्यान्वयन समिति स्थापित की गयी थी। इससे पूर्व के लेख खंड में वर्णित मामलो के अतिरिक्त अनुशासन संहिता के नियमों को भंग करने की ५५ शिकायतें समिति के सामने आयीं। इनमें से ७ मामलो आपसी समझौते से सुलझ गये और ऐसे २२ मामलो में जो जांच करने पर सही निकले मजदूरों के संगठनों को इस प्रकार के नियम भंग न करने की सलाह दी गयी। १७ मामलो में नियमभंग सिद्ध नहीं हो सके और शेष ६ मामलो में जांच जारी थी।

### कारखानों और न्यायलरो का निरीक्षण

आलोच्य वर्ष में फेक्ट्रीज ऐक्ट के प्रति २,६७२ कारखाने उत्तरदायी रहे। इनमें से १,५६४ कारखानो ने अपने लाइसेन्स नये कराये और २५ नये कारखानो को लाइसेन्स दिये गये। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में १५८६ कारखानों ने लाइसेन्स प्राप्त किये जबकि सन् १९५६ में ऐसे कारखानो की संख्या १,३७० थी। १,०२३ कारखानो के मामलो में उनके द्वारा आवश्यक खानापुरी न किये जाने के फलस्वरूप उनके लाइसेन्स नये नहीं किये जा सके या जारी न किये जा सके और शेष ६० कारखानो ने उनका मामला विचाराधीन होने के कारण लाइसेन्स देने के लिए प्रार्थना नहीं की। पूर्व वर्ष के ५,५८,६३८ रुपये की तुलना में इस वर्ष ५,६३,२७५ रुपये लाइसेन्स शुल्क के रूप में वसूल किये गये।

कारखाना निरीक्षण कार्यालय ने वर्तमान भवनों की इमारतों में वृद्धि करने अथवा नये भवनों के निर्माण के लिए १,२२६ नक्शे प्राप्त किये। इनमें से ५४२ नक्शे स्वीकृत किये गये।

निरीक्षण कार्यालय ने कारखाना अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, उत्तर प्रदेश मार्टिनीटी बनीफिट्स अधिनियम तथा रोजगार सम्बन्धी बाल अधिनियम के अन्तर्गत कुल ७,६८४ निरीक्षण किये। उक्त कार्यालय में ६६८ शिकायतें आयीं जिनमें से ८६१ का निबटारा किया गया। इसके अतिरिक्त विविध प्रकार की १३५ और शिकायतें भी प्राप्त हुईं जिनमें से १३२ वर्ष भर में निपटा दी गयीं।

फैक्टरी अधिनियम १९४८ की धारा ४६ के अन्तर्गत फैक्टरी कल्याण अधिकारियों के सम्बन्ध में बनाये गये नियमों को १४० कारखानों में लागू किया गया जिनमें १२१ कारखानों में सुयोग्य कल्याण अधिकारियों को नियुक्त कर दिया था।

फैक्टरी अधिनियम, १९४८ तथा मजदूरी भुगतान अधिनियम, १९३६ की धाराओं का उल्लंघन करने के कारण कारखानों के विरुद्ध ७२२ मुकदमों चलाये गये जिनमें से २८७ से सजा दी गयी मजदूरी भुगतान अधिनियम १९३६ के अन्तर्गत और उसके नियमों के अनुसार मजदूरों को उनकी मजदूरी न दिये जाने के फलस्वरूप ५२ हिदायतें जारी की गयीं।

पूर्वगामी वर्ष के १८२ कारखानों की तुलना में आलोच्य वर्ष में २८६ कारखाने ५० पी० फैक्टरीज रूल्स, १९५० के नियम १८ के प्रति उत्तरदायी पाये गये। इस नियम के अनुसार फुजले के उपयोग का प्रबन्ध फुजला समिति द्वारा अनुमोदित होना चाहिये। २८६ कारखानों में से ३३ कारखानों द्वारा फुजला के प्रबन्धों का अनुमोदन किया गया और ६६ कारखानों को यह सलाह दी गयी कि वे अपने फुजला का उपयोग इस प्रकार करें कि फुजला जांच समिति की रिपोर्ट में दी हुई सीमाओं तक पहुंच जायें। भारतीय व्वायलर्स अधिनियम, १९२३ के अन्तर्गत ३७ व्वायलरो और ३७ एकोनोमाइजरो की रजिस्ट्री की गयी। इस प्रकार व्वायलरो और एकोनोमाइजरो की कुल सख्या क्रमशः ३,०२८ एवं १५६ हो गयी। आलोच्य अवधि में २,२०,४६६ रु० की एक धनराशि और ८,२८० रुपये की दूसरी धनराशि निरीक्षण और रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में प्राप्त हुई।

राज्य से बाहर ३७ व्वायलर भेजे गये और राज्य में ५७ व्वायलर लंगाये गये। आलोच्य वर्ष में, व्वायलरो के १,७६३ खुले निरीक्षण, १,२१४ जल-परीक्षण, ५१ भाप सम्बन्धी परीक्षण और २,०५० आकस्मिक निरीक्षण किये गये। इसके अतिरिक्त एकोनोमाइजरो के ५२ खुले परीक्षण, ६६ जल परीक्षण, ८२ भाप सम्बन्धी, परीक्षण तथा १६६ आकस्मिक निरीक्षण भी किये गये।

भारतीय व्वायलर्स अधिनियम, १९२३ की धाराओं का उल्लंघन करने के फलस्वरूप ४ मालिकों के विरुद्ध मुकदमों चलाये गये। पूर्व वर्ष के अनिर्णीत मुकदमों को मिलाकर निबटाये जाने वाले मुकदमों की कुल सख्या १८ रही। फैसले हुए ६ मामलों में ६२० रु० जुर्माना किया गया।

प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के व्वायलर सहायकों की परीक्षा में क्रमशः २३४ और ६१६ परीक्षार्थी बैठे। इनमें से १५६ और ५१७ को सफल घोषित किया गया। परीक्षार्थियों से परीक्षा-शुल्क के रूप में १२,७७५ रुपये प्राप्त हुए। दो परीक्षार्थी वेल्डरो की परीक्षा में बैठे। इनमें से केवल एक उत्तीर्ण हुआ। परीक्षा-शुल्क के रूप में ८५ रुपये प्राप्त हुए।

### चाय बागान मजदूर अधिनियम, १९५१

चायबागान मजदूर अधिनियम, १९५१ के अधीन उत्तर प्रदेश के कारखानों के चीफ इन्स्पेक्टर चायबागान के चीफ इन्स्पेक्टर भी रहे। आलोच्य वर्ष में चायबागानों के ५६ निरीक्षण किये गये। इस अधिनियम के अन्तर्गत १५ मुकदमों चलाये गये। पूर्व वर्ष के १० अनिर्णीत मुकदमों को मिलाकर कुल २५ मुकदमों इस अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करने के फलस्वरूप मालिकों पर चलाये गये। ६ मुकदमों में दण्ड दिया गया और २६० रु० जुर्माना किया गया। ३५ शिकायतें प्राप्त हुईं और उन्हें वर्षान्त तक रफा कर दिया गया।

### उत्तर प्रदेश दूकान एवं व्यावसायिक संस्थान अधिनियम, १९४७

गतवर्ष की भांति उत्तर प्रदेश दूकान एवं व्यावसायिक संस्थान अधिनियम, १९४७ की सभी धाराएँ राज्य के ६० नगरों में लागू रहीं। अधिनियम की धाराएँ २,४,१०,१२

१४ १६, १८, २१, २६ से ३१ तक ३४ और ३५, ३८ कस्बों में लागू रहें। १९६० में इन अधिनियमों की धारा ३४ की कस्बों के क्षेत्रों में लागू की हुई है। इस प्रकार आलोच्य वर्ष के अन्त तक इस अधिनियम की धारा ६६ कस्बों में लागू रहें। इसके अतिरिक्त इस नियम की धारा ३४, लखनऊ, फर्रुखाबाद, कन्नौज, वाराणसी और मेरठ के समीपस्थ क्षेत्रों में लागू रहें।

आलोच्य वर्ष से ७४, ४६८ निरीक्षण किये गये जबकि पूर्वगामी वर्ष में इनकी संख्या ६४, ३१३ थी। आलोच्य वर्ष में कुल चालानों की संख्या पूर्व वर्ष के कुछ चालानों को मिलाकर ८३४ थी जबकि पूर्वगामी वर्ष में चालानों की संख्या १,१०२ थी। इनमें से ६५६ मामलों में सजा दी गई और १८, २४८ रुपये जुर्माने किये गये। प्राप्त शिकायतों, पिछले वर्ष की गैर निबटाई शिकायतों को शामिल करके—की कुल संख्या २,२२४ थी जिनमें से २,०७७ रफा की गयी। अधिनियम की धारा ३४ की अधीन ७ अस्थायी और २२ अस्थायी छूट दी गयीं।

#### न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८

आलोच्य समयावधि में ऊनी दरी उद्योग अल्मोडा और गढ़वाल जिलों के चाय बागानों में नौकरी करने अल्मोडा, नैनीताल, गढ़वाल, देहरा, गढ़वाल, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तर काशी के सभी फार्मों और खेतों में नौकरी करने वालों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर निर्धारित की गयी। छठी और सातवीं श्रेणियों की स्थानीय संस्थाओं में भी पूरे तीन-चौथाई और आठवें समय काम करने वालों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित की गयीं।

आलोच्य वर्ष में १६, २८१ निरीक्षण किये किये। शिकायतों की कुल संख्या—गतवर्ष की बाकी शिकायतों को मिलाकर ६७० थीं जिनमें से ३६४ निबटा दी गयीं। अनुसूचित नौकरियों से सम्बन्धित २,६२८ नये संस्थानों में जिनमें १६, ०६१ व्यक्ति कार्य करते थे, यह अधिनियम लागू किया गया।

#### औद्योगिक नौकरी (स्टैंडिंग आर्डर्स) अधिनियम, १९४६

औद्योगिक नौकरी (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ के अन्तर्गत अमायुक्त सर्टिफाइंग अफसर को हस्तगत से कार्य करते रहे। सर्टिफाइंग अफसर के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई इलाहाबाद का उद्योग न्यायाधिकरण करता रहा। आलोच्य वर्ष में अधिनियम के अन्तर्गत ४१ नये औद्योगिक अधिष्ठानों के लिए स्थायी आदेश प्रमाणित किये गये।

राज्य की चीनी मिलें जिनके लिए सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ३ के अधीन सामान्य स्थायी आदेश निर्धारित कर दिये थे, आलोच्य वर्ष में इस अधिनियम की व्यवस्थाओं से मुक्त रहें।

आलोच्य वर्ष में ७३६ निरीक्षण किये गये। मालिकों के विरुद्ध चलाये गये १० मामलों में से ८ सजा दी गयी और २, ४६० रुपये जुर्माना किया गया।

यह अधिनियम राज्य के निम्नलिखित संस्थानों में बिना इसके विचार किये कि उनमें कितने कर्मचारी हैं पूर्ववत् लागू रहा—

- (१) उत्तरी भारत मालिक संघ कानपुर के सदस्य,
- (२) उत्तर प्रदेश आयल मिलर्स असोसियेशन कानपुर के सदस्य,
- (३) बिजली के कारखाने,
- (४) जल-कल,
- (५) कांच उद्योग,
- (६) सभी आयल मिलें जो फैक्टरीय अधिनियम के अन्तर्गत कारखानों के रूप में रजिस्टर्ड हैं,

(७) वे जिनके मालिक स्वेच्छा से अधिनियम के अधीन अपने स्ट्रेडिंग आर्डर्स को प्रमाणित करने के लिए प्रार्थना करते हैं,

(८) ऐसे समाचार-पत्र संस्थान जिनमें २० से अधिक कर्मचारी काम करते हैं।

आलोच्य वर्ष में इस अधिनियम की धाराएं कपड़े की मिलों, इन्जीनियरिंग कारखानों, चमड़े के कारखानों, मुद्रणालयों, रुई ओटने और गाठ बनाने के कारखानों, आटा, दाल और चावल की मिलों, लाख के कारखानों, जिसमें ५० से अधिक मजदूर काम करते थे लागू की गयीं। कारखाना अधिनियम, १९४८ के अधीन रजिस्टर्ड तेल मिलें भी इस अधिनियम के अन्तर्गत रहें।

### कर्मचारी राज्य बीमा योजना

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना सबसे पहले कानपुर में फरवरी, १९५२ में लागू की गयी थी और बाद में यह योजना १४ अन्य नगरों में चालू की गयी। इस योजना के अधीन २,१२,५०० व्यक्ति रहे। आलोच्य वर्ष में यह योजना किसी नये नगर में लागू नहीं की गयी। इस योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को विभिन्न प्रयोजनों के लिये सन् १९६० में २१,१५,३७४ रुपये दिये गये। उन सभी स्थानों में जहाँ यह योजना लागू थी १४ नवम्बर, १९५६ से श्रमिकों के परिवारों को भी इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाली चिकित्सा सहायता दी जाने लगी।

### कर्मचारी प्राविडेंट फंड अधिनियम

सन् १९५२ में जब कर्मचारी प्राविडेंट फंड अधिनियम पहले पहल लागू किया गया तो इसके अन्तर्गत केवल ६ उद्योग अर्थात् सीमेंट, सिगरेट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तथा सामान्य इन्जीनियरिंग उत्पादन, लोहा तथा इस्पात, कागज तथा सूती वस्त्र उद्योगों को लाया गया। १९६० तक इसे ४५ उद्योगों और संस्थानों पर लागू किया जा चुका था जिनमें पांच श्रेणी के चाय बागान और चार श्रेणी की खानें थी। ३१ दिसम्बर, १९६० से इस अधिनियम को उन सभी संस्थानों पर लागू कर दिया गया था जिनमें २० या इससे अधिक व्यक्ति काम करते थे। इसके अधीन ८५२ कारखाने थे जिनमें १,७५,००० से अधिक व्यक्ति काम करते थे।

### चीनी मिल श्रमिकों के लिए गृह-निर्माण योजना

चीनी मिलों के श्रमिकों की गृह निर्माण योजना के अधीन कल्याण और विकास कोष में ६१,१०० रुपये की धनराशि दी गयी। इस प्रकार दिसम्बर, १९६० तक कुल ४८,६८,५०० रुपये कोष में जमा किये गये, इसमें से ४५,३०,६६६ रुपये गृह निर्माण खाते में जमा हुए। आलोच्य वर्ष में २ अन्य मिलों ने निर्माण-कार्य आरम्भ किया। इस प्रकार ऐसी मिलों की संख्या कुल मिलाकर ६३ हो गयी। १,३८० मकानों का निर्माण पूरा हो गया और ८६ मकानों का निर्माण-कार्य प्रगति करता रहा। लगभग सभी मिलों में जहाँ निर्माण-कार्य पूरा हो गया श्रमिकों को क्वार्टर अलाट कर दिये गये।

### वित्तपोषित औद्योगिक गृह-निर्माण योजना

भारत सरकार की वित्तपोषित औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत अन्य उद्योगों के श्रमिकों के लिए गृह-निर्माण कार्यक्रम से तीव्र प्रगति रही। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधियों में बनने वाले २५,६५६ मकानों में से आलोच्य वर्ष के अन्त तक २२,७७६ मकान बन कर तैयार हो गये थे। इनमें से सन् १९६० में १,७८६ क्वार्टर बन कर तैयार हुए। १७२ एक कमरे वाले और ४४२ दो कमरे वाले क्वार्टरों के निर्माण के लिए ६ मालिकों को आर्थिक सहायता देना स्वीकृत किया गया। इसी प्रकार २ सहकारी समितियों को २३ एक कमरे वाले और २२ दो कमरे वाले क्वार्टरों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत की गयी। एक

कमरे वाले २४८ और दो कमरे वाले १६४ क्वार्टरों के निर्माण के लिए १० मालिकों से और १२० दो कमरे वाले क्वार्टरों के निर्माणार्थ एक सहकारी समिति में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। ये प्रार्थना-पत्र विचाराधीन थे।

### चायबागान के मजदूरों के लिए गृह-निर्माण योजना

चायबागान श्रमिकों के लिए गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत मजदूरों के लिए क्वार्टर बनाने के हेतु मालिकों को गृह-निर्माण की कीमत का ८० फीसदी तक कर्ज देने की व्यवस्था थी। परन्तु अभी तक राज्य के चायबागानों के मालिकों की ओर से कोई कदम उठता देख नहीं पड़ा।

### श्रम-कल्याण केन्द्र

राज्य में कुल ६५ श्रम-कल्याण केन्द्र थे। इन केन्द्रों में श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को निःशुल्क चिकित्सा, मनोरंजन, सामाजिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक सुविधाएँ प्रदान की जाती रही। 'सी' श्रेणी के दो केन्द्रों को 'बी' श्रेणी के केन्द्रों में उन्नत किया गया।

सन् १९६०-६१ में कल्याण कार्यों के लिए १८ लाख ३ सौ रुपये बजट में नियत किये गये थे। आलोच्य वर्ष में रोगियों की प्रतिदिन की औसत उपस्थिति ६,७७० थी। कुल मिलाकर १,२६,६०६ सेर ताजा दूध और ८३,६०८ सेर दूध का पाउडर बच्चों, दूध पिलाने वाली माताओं, गर्भिणी स्त्रियों और रोगियों को बाटा गया। दाइयों ने १,०३२ शिशुओं की प्रतिदिन मालिश की और उन्हें स्नान कराया। मिडवाइफों ने ५,६२० पूर्व प्रसव के तथा ३,४८६ प्रसवोत्तर स्त्रियों की देख-भाल की और ३,३२२ बच्चों को जनाया।

छे सौ इश्तालिस संगीत के कार्यक्रम, १६ नाटक, ४३ बेबी शो, १० विविध मनोरंजन के कार्यक्रम तथा २०७ सिनेमा शो दिखाने का प्रबन्ध किया गया। औसतन २,४८२ तथा ३,०६० श्रमिकों ने क्रमशः मैदानों और भवनो में खेले जाने वाले खेलों में भाग लिया। १२५ श्रमिकों को योग की शिक्षा दी गयी।

श्रम-कल्याण केन्द्रों के वाचनालयों में प्रतिदिन की औसत उपस्थिति २,६४६ रही। पुस्तकालयों के ५,१८५ सदस्य थे और दी जाने वाली किताबों की संख्या ६०,६२६ थी।

सिलाई के क्लासों में ८७३ स्त्रियाँ औसतन प्रतिदिन आती रही और उनके द्वारा १६,१२४ रुपये मूल्य के कपड़े सिले गये।

श्रम-कल्याण केन्द्रों में स्काउट इकाइयाँ और गाइड कम्पनियाँ बड़ी संख्या में संगठित की गयीं। विभिन्न खेलों और त्योहारों के अवसर पर इन्होंने समाज-सेवा शिविरों की व्यवस्था की।

### ट्रेड यूनियन

राज्य में ३१ मार्च, १९६० को १,०५२ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनों थीं जबकि ३१ मार्च, १९५६ को इनकी संख्या १,०२१ थी। इनमें से केवल ७४८ यूनियनों ने जिनकी कुल सदस्यता २,६३,३६५ थी वार्षिक नक्शे प्रस्तुत किये। ट्रेड यूनियन के निरीक्षकों तथा सहायक निरीक्षकों ने आलोच्य वर्ष में ५६२ निरीक्षण तथा ७२१ जांच-पड़ताल की।

दो रेफ्रेशर पाठ्य-क्रमों का आयोजन किया गया तथा जिनमें ६५ ट्रेड यूनियन कर्मचारियों को ट्रेड यूनियनवाद के तरीकों और तकनीक में प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त २७ ट्रेड यूनियन कर्मचारियों को अन्य राज्यों के विभिन्न भागों में ले जाया गया ताकि वे उन स्थानों की ट्रेड यूनियनों के कार्य-कलाप के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें।

१५ ट्रेड यूनियनो को सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए ताकि उनके उनके सदस्य लाभ उठा सकें १५,००० रुपये की आर्थिक सहायता दी गयी।

ट्रेड यूनियन हालो के निर्माणार्थ ५०,००० रुपये की धनराशि बजट में रखी गयी। सरकार ने लखनऊ के भारतीय चीनी मिल कर्मचारी फेडरेशन को इसमें से ३०,००० रुपये लखनऊ में एक ट्रेड यूनियन हाल बनाने के लिए मंजूर किये।

यू० पी० इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स रूलस, १९५७ के नियम २६ और ३० के अधीन आलोच्य वर्ष के ५८ रजिस्टर्ड यूनियनो के ३१६ अफसर रक्षित कर्मचारी घोषित किये गये।

### वर्क्स कौंसिले

३७ में से २३ कारखानो में वर्क्स कौंसिले बनायी गयीं। यू० पी० स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधीन औद्योगिक कारखानो को भी वर्क्स कौंसिलें बनाने वाले नियमो के अन्तर्गत लाया गया और इन कारखानो में वर्क्स कौंसिलें बनाने का कार्य किया जा रहा है।

### वृद्धावस्था की पेंशन

आलोच्य वर्ष में वृद्धावस्था की पेंशन दिये जाने के लिये १,३२० प्रार्थना-पत्र स्वीकृत हुए। इस प्रकार इस पेंशन को पाने वालो की कुल संख्या ७,२०२ हो गयी। इनमें से १,८०६ व्यक्ति मर गये। इस प्रकार वर्षान्त में जिन्दा पेंशनरो की संख्या ५,३९६ रह गयी।

### रोजगार दफ्तर

आलोच्य वर्ष में २० और रोजगार दफ्तर खोले गये। उत्तर काशी, बनौली और पिथौरागढ़ को छोड़कर राज्य के अन्य सभी जिलो में अब रोजगार दफ्तर खुले हुए हैं।

दो सामुदायिक विकास खंडो में—एक जिला इलाहाबाद के मंसनपुर नामक स्थान में और दूसरा गोरखपुर के बडहलगंज नामक स्थान में रोजगार सम्बन्धी सहायता और सूचना ब्यूरो स्थापित किये गये।

आलोच्य वर्ष में नौकरी की तलाश करने वाले ५,८८,०७२ व्यक्तियो ने रोजगार दफ्तरों में अपने नाम दर्ज कराये जबकि पूर्वगामी वर्ष में इनकी संख्या ४,७३,४३५ थी। राज्य भर के रोजगार दफ्तरों में सरकार और साधारण मालिको से ६४,५१४ रिक्त स्थानो की सूचना प्राप्त हुई और ६४,६६० प्रार्थियो को नौकरी दिलायी गयी। रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टरो में ३१ दिसम्बर, १९६० को प्रार्थियो की संख्या २,२६,१७१ थी जबकि यही संख्या ३१ दिसम्बर, १९५६ को १,६५,१६३ थी।

पहली मई, १९६० से राज्य भर में रोजगार दफ्तर (कम्पल्सरी नोटिफिकेशन ग्राफ वेकेन्सीज) अधिनियम, १९५६ लागू कर दिया गया था। इस अधिनियम के अधीन धारा ३ के अन्तर्गत दी हुई श्रेणियो को छोड़कर सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में जहाँ २५ या इससे अधिक व्यक्ति कार्य करते हों, सभी नौकरी देने वाले व्यक्तियो के लिए यह आवश्यक कर दिया गया है उनके यहां के रिक्त स्थानो पर नियुक्ति करने से पूर्व उनकी सूचना रोजगार दफ्तरों में दी जाया करे। इस अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा न करना दण्डनीय जुर्म करार दिया गया है।

### रोजगार संबंधी सूचना—

रोजगार सम्बन्धी सूचना एकत्रित करने के लिये जो योजना १९५६ में राज्य के ७ जिलो में चल रही थी उसे आलोच्य वर्ष में १० और जिलो में चलाया गया। इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, बरेली, गोरखपुर और मेरठ जिलो से सम्बन्धित तिमाही रोजगार संबंधी सूचनाएं

नियमित रूप से जारी होती रही और सभी सम्पन्न लोगों में वितरित होती रही। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण और रोजगार निदेशालय में एक विशेष जांच इस आशय से की कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से सरकारी क्षेत्र में कितनी अनिश्चित नौकरियों की गुंजाइश हो गयी है।

### व्यावसायिक अनुसंधान एवं विश्लेषण

व्यावसायिक अनुसंधान एवं विश्लेषण कार्यक्रम का उद्देश्य देश में सभी ज्ञात व्यवसायों का प्रामाणिक परिमाण और विवरण तैयार करना था। विभाग ने भारत सरकार के सहयोग से व्यवसायों का राष्ट्रीय वर्गीकरण का प्रारम्भिक संस्करण प्रकाशित किया। इसमें देश में उपलब्ध सभी व्यवसायों की छोटो-छोटी संख्याएँ दी हुई हैं।

राज्य व्यावसायिक सूचना इकाई ने व्यवसाय के प्रत्येक श्रेणी के लिए शिक्षा का आधार तल और न्यूनतम प्रशिक्षण की जानकारी करने के लिए गहरा अध्ययन किया। इसमें यह भी ध्यान रखा गया कि किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाय और उसमें कितना समय लगेगा। एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाने के लिए जहाँ पर संभव हो किन धार्मिक आवश्यकताओं की जरूरत पड़ती है—इस सम्बन्ध में भी इकाई ने सूचना एकत्रित की। इन योजना को चलाने के लिए फोर्ड फाउन्डेशन द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस योजना के अन्तर्गत व्यावसायिक सूचना इकाई ने १०७ औद्योगिक इकाइयों में संपर्क स्थापित किया और १,०५३ प्रस्तावनाएँ पूरी की।

### व्यावसायिक पथ-प्रदर्शन तथा रोजगार संबंधी परामर्श

आलोच्य वर्ष में लखनऊ के उपक्षेत्रीय रोजगार कार्यालय में १९५७ में प्रारम्भ की गयी व्यावसायिक पथ-प्रदर्शन इकाई के अतिरिक्त छ और व्यावसायिक पथ-प्रदर्शन इकाइयाँ इलाहाबाद, आगरा, कानपुर, मेरठ, अल्मोडा, झांसी, गोरखपुर और बरेली में स्थापित की गयी। वाराणसी और अलीगढ़ में स्थित विश्वविद्यालय रोजगार ब्यूरो ने विश्वविद्यालय के छात्रों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति की।

### पूल एवं आकस्मिक नियुक्ति योजना

कानपुर की ऊर्जा, सूती एवं तेल मिलों में बालू पूल एवं आकस्मिक नियुक्ति योजना के अन्तर्गत १९,४४१ व्यक्ति रजिस्टर किए गये और १२,२५६ व्यक्तियों को रोजगार में लगाया गया जबकि पूर्वगामी वर्ष में ये संख्याएँ क्रमशः १६,४०५ और १२,९८८ थीं। कुल मिलाकर १५,५८१ रिक्त स्थानों की सूचना दी गयी और १५,०३५ जालीय वर्ष में भर दिये गये।

### वस्तुकार प्रशिक्षण योजना

वस्तुकार प्रशिक्षण योजना का और विस्तार किया गया और बलिया और श्रीनगर में २ औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र खोले गये। इनमें दो प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती रही—

१—इंजीनियरिंग और भवन निर्माण व्यवसायों में प्राविधिक प्रशिक्षण,

२—कुटीर एवं लघु उद्योगों में व्यावसायिक प्रशिक्षण।

व्यवसायिक और प्राविधिक ट्रेडों की परीक्षाओं में २,५७१ अभ्यर्थी बैठे।

औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों के लिए विदेश बनावट की वर्कशॉप के भवनो का निर्माण और उन्हें औजारों तथा अन्य सामान से सुसज्जित करने का कार्यक्रम निर्धारित योजनानुसार चलता रहा। व्यावसायिक ट्रेडों की राष्ट्रीय कौंसिल द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण नीतियों को कार्यान्वित करने में राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए व्यावसायिक ट्रेडों में प्रशिक्षण की एक राज्य कौंसिल समिति की गई। राज्य भर में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समन्वय भी यह कौंसिल स्थापित करेगी।



## २-समाज-कल्याण

### नगर समाज-कल्याण समितियाँ

जिला स्तर पर समाज कल्याण के क्षेत्र में सरकारी और स्वैच्छिक प्रयत्नों में समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में जिलामुखी के सभापतित्व में नगर समाज कल्याण समितियों की स्थापना की गयी थी। ये समितियाँ जिले में किसी भी कल्याणकारी योजना को चलाने के लिए स्वतंत्र थी।

### आर्थिक सहायता

स्वैच्छिक संस्थाओं को उनके कार्य कलापो को विकसित करने और ठीक सगठित करने के लिए आर्थिक सहायता दी गयी। सन् १९६०-६१ के वजट में मूक, बधिर और अन्धों की संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए ६०,००० रुपये की व्यवस्था की गयी।

विधवाभ्रमों एवं अनाथालयों को आर्थिक सहायता देने के लिए ५०,००० रु० की धनराशि रखी गयी। समाज-कल्याण की विभिन्न संस्थाओं और सगठनों को आर्थिक सहायता देने के लिए वजट में २,३८,००० रुपये एक मुश्त व्यवस्था की गयी।

इसके अतिरिक्त ५,४०,००० रु० की धनराशि सन् १९६०-६१ में राज्य समाज-कल्याण सलाहकारी समिति को इस शर्त पर दी गयी कि समिति भी इनमें ही धन अपनी ओर से मिलाकर अपने कार्यालय और ग्रामीण क्षेत्रों की महिला मंगल योजनाओं को सुचारु रूप से चलाती रहे।

### उद्धार-संगठन

उद्धार-संगठन की योजना के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त दो उद्धार अधिकारी थे—एक देहरादून में और दूसरा वाराणसी में। इन संगठनों का मुख्य कार्य महिलाओं और बालिकाओं को नैतिक खतरों से बचाना था।

### महिला मंगल योजना

महिला मंगल योजना ३३ जिलों में चल रही थी। इन सभी जिलों में जिला स्तर पर महिला मंडल के कार्यक्रमों की देखरेख करने के लिए महिला मंगल के जिला आर्गनाइजरो की जो ३३ जगहें थीं उन्हें समाप्त कर दिया गया। खंड स्तर पर यह कार्य ग्राम सेविकाओं और ग्राम लक्ष्मियों की सहायता से सहायक विकास अधिकारी (सामाजिक शिक्षा महिला) की देखरेख में चलता रहा।

महिला मंगल केन्द्रों में से अधिकांश क्रियाशील खंडों में स्थित थे और प्रत्येक खंड में एक-एक सहायक अधिकारी (सामाजिक शिक्षा) और १० से १२ तक ग्राम सेविकाएँ थीं। प्रत्येक ग्राम सेविका की सहायता ३-४ ग्राम लक्ष्मियाँ करती थी।

महिला मंगल योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों का कुछ विवरण नीचे दिया जाता है—

१—योजना के अन्तर्गत आने वाले जिलों की संख्या	..	३३
२—जिनमें काम किया गया ऐसे ग्रामों की संख्या	.. ..	६७६
३—महिला मंगल केन्द्रों की संख्या	.. ..	३२८
४—साक्षर बनायी गयी प्रौढ़ महिलाओं की संख्या	.. ..	४७,७१६
५—महिलाओं और बालिकाओं की संख्या जिन्हें दत्तकारी की शिक्षा दी गयी	.. ..	८३,८०६
६—बालबारी कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या	.. ..	४३,२१३
७—दवा के बक्से की सहायता से इलाज किये गये मरीजों की संख्या	.. ..	७४,२२७

## रक्षा-गृह

लखनऊ, वाराणसी, मथुरा, मेरठ और गोरखपुर में १९६१ के फरवरी मास में पांच रक्षा-गृह १९५६ के महिलाओं और बालिकाओं के अन्तर्गत व्यापार अधिनियम के अधीन स्थापित किये गये । इनमें ५० सदस्यों तक के रहने की सीमित व्यवस्था थी । ये गृह इस इरादे से स्थापित किये गये थे कि इस अधिनियम के अन्तर्गत एकड़, गयी अहिताओं और बालिकाओं को इनमें रखकर पुनर्वास के लिये लम्बे अरसे तक प्रशिक्षित किया जाये । (ये रक्षा गृह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा अपनायी गयी एक योजना के अनुसार कायम थे) ।

## युवक मंगल योजना

युवकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए सत्तर भर में शिविरों का संगठन सर्वोत्तम माध्यम माना गया है । शिविरों के संगठन की ओर बराबर उचित ध्यान दिया जाता रहा । आलोच्य वर्ष में राज्य के २५ जिलों में २५ युवक शिविर संगठित किये गये जिनमें १,२५० युवकों ने भाग लिया ।

ग्रामीण बालिकाओं को भी ग्रामीण युवक कार्यक्रम पसन्द आने लगा है । आलोच्य वर्ष में राज्य स्तर पर लखनऊ में पहली बार एक ग्रामीण युवनी समारोह का आयोजन इल्लिए किया गया ताकि उन्हें इसका अवसर मिल सके कि वे अपनी कलात्मक एवं सृजनात्मक प्रवृत्तियों का प्रदर्शन, शारीरिक, सांस्कृतिक और दस्तकारी की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर कर सकें । ७०० ग्रामीण बालिकाओं ने इस समारोह में भाग लिया ।

## कानपुर का शिशु पालन-गृह—

कानपुर में विभाग एक शिशुपालनगृह का संचालन कर रहा था जिसमें ४० बच्चों के लिए जगह थी । यह गृह मध्यमवर्ग की उन माताओं के लिए था जो काम पर जाते समय अपने बच्चों को शिशु पालन-गृह में छोड़ जाती थी ।

## बाल अधिनियम, १९५१

बाल अधिनियम, १९५१, के अधीन आगरा में २० और वाराणसी में ६० बाल सेवा समितियां संगठित की गयीं ।

## गृहविज्ञान शाखा

रुद्रपुर (नैनीताल) और देहरादून (मेरठ) में २ नये गृहविज्ञान विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये । इस प्रकार इनकी संख्या ८ हो गयी । आलोच्य वर्ष में इन प्रशिक्षण केन्द्रों में २४३ ग्राम सेविकाओं को प्रशिक्षित किया गया ।

## निगरानी योजना

निगरानी योजना के अन्तर्गत, मस्थाओं द्वारा देखरेख से पृथक, चरित्रसुधार देखरेख की भी व्यवस्था है जिसके अनुसार व्यक्तियों से निजी सम्पर्क और उनके चरित्र की यदाकदा जांच करके सहानुभूति-पूर्वक पथ-प्रदर्शन किया जाता है ।

आलोच्य वर्ष में यह अधिनियम राज्य के २ और नगरों में लागू किया गया जिससे अधिनियम के अन्तर्गत आनेवाले जिलों की संख्या २२ हो गयी ।

## उत्तर प्रदेश महिला और बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, १९५६

आलोच्य वर्ष में बन्द की गयी संस्थाओं के २९ सदस्यों का स्थापित लाइसेंस शुदा संस्थाओं को किया गया और इन संस्थाओं को ६,०९१ रुपये निर्वाह भत्ते के रूप में दिया गया ।

### महिलाओं और बालिकाओं का अनैतिक व्यापार (दमन) अधिनियम, १९५६

महिलाओं और बालिकाओं का अनैतिक व्यापार (दमन) अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किये गये :—

१—रजिस्टर किये गये मुकदमों की संख्या	..	..	८०
२—चालान किये गये व्यक्तियों की संख्या	..	..	१७४
३—दोष प्रमाणित होने वाले मुकदमों की संख्या	..	..	११
४—दोषी प्रमाणित व्यक्तियों की संख्या	..	..	१३
५—खारिज होने वाले मुकदमों की संख्या	..	..	११
६—विचाराधीन मुकदमों की संख्या	..	..	५८

(इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित रक्षागृहों में संबंधित विवरण पहले दिया जा चुका है ।)

### प्रशासकीय ढांचा—

समाज कल्याण का कार्य सन्तोषपूर्वक ढंग से चल रहा और समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत कुछ अतिरिक्त कार्यक्रम भी आ गये । १० पी० फर्स्ट आफेंडर्स प्रोबेशन ऐक्ट, १९३८ से संबंधित कार्य जो पहले यू० पी० के जिलों के इन्स्पेक्टर जनरल के प्रशासकीय नियंत्रण में होता था ३ जून, १९६० से समाज कल्याण निदेशक के प्रशासकीय नियंत्रण में कर दिया गया । यू० पी० बाल अधिनियम, १९५१ को लागू करने से संबंधित कार्य भी जिसे पहले गृह विभाग देखता था मई, १९६०, से समाज कल्याण विभाग को सौंप दिया गया । वृजुर्ग और अनाथ शरणार्थी महिलाओं के लिए स्थापित गृहों के प्रशासन का कार्य जो पहले सहायता एवं पुनर्वास विभाग में होता था, १ सितम्बर से समाज कल्याण विभाग में होने लगा ।

विभाग को मुख्यतः तीन अनुविभागों का—पुरष, महिला और युवा-कार्य देखना पड़ता था । इन तीन शाखाओं से संबंधित सभी योजनाओं का कार्य उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण निदेशक के प्रशासकीय नियंत्रण में होता था ।

महिलाओं और बालिकाओं का अनैतिक व्यापार (दमन) अधिनियम, १९५६ की धारा २१ के अधीन स्थापित ५ नये रक्षागृहों के लिए ५ अधीक्षक के पदों का २५० इ०—२५—३७५—ई० बी०—२५—५०० रुपये वेतन-क्रम में सृजन किया गया ।

### ३—हरिजन उत्थान एवं सुधार

हरिजन सहायक विभाग ने अस्पृश्यता के निवारण का अपना कार्यक्रम चालू रखा । यह कार्य तीन प्रकार से होता रहा—(१) कानून द्वारा (२) सामाजिक शिक्षा द्वारा, जिसमें समझा-बुझाकर और शिक्षा देने के साधन अपनाये गये, और (३) ऐसे उत्तर प्रदान करके जिनसे शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोग आत्म-विश्वास और आर्थिक-जीवन तथा दैनिक जीवन की परिस्थितियों में सुधार कर सकें । आलोच्य वर्ष में विभाग के कार्य कलाप में काफी वृद्धि इसलिये हो गई कि यह वर्ष द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष था और उसे वर्ष भर के कार्य के अतिरिक्त पिछले सालों में रह गयी कमी को भी पूरा करना पड़ा । १९६०-६१

में कुल २३६.८७ लाख रुपये खर्च किये गये । हरेलोन संवर्धन योजना के अन्तर्गत वर्षों के मुकाबले में यह धराया कि (१९५२-५३ में ११८.३६ लाख रुपये खर्च हुए थे) ।

### प्रशासकीय ढांचा

आलोच्य वर्ष में विभाग में प्रशासकीय ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । निदेशक की, जो उत्तर प्रदेश सरकार के हरिजन सहायक विभाग के पतेन उपसचिव भी रहे सहायता दो उप-निदेशक, तीन सहायक निदेशक और ५२ जिला हरिजन कल्याण अधिकारी (जिनमें मुख्यालय के अधिकारी भी सम्मिलित हैं) और एक अकाउन्ट्स अधिकारी ने की । वस्तुओं और प्राविधिक शिक्षा केन्द्रों की संस्थाओं में वही कर्मचारी रहे । विमोचित जातियों के पुनर्वास वाली बस्तियों से संबंधित अमला उनके पूरे हो जाने के कारण हटा लिया गया । जिला नैनीताल के मालघन और नामक स्थान पर ३-५ हरिजन परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की गयी ।

### शिक्षा संबंधी सुविधाएं

सन् १९६०-६१ में विकास योजनाओं पर १,०७,४८,६७९ रुपये खर्च किये गये । इसमें का अधिकांश भाग, प्रीमियम, छात्रवृत्ति, परीक्षा-शुल्क, पुस्तकें आदि शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए रखा गया । परिगणित जाति के विद्यार्थियों को पढ़ाई, खेलकूद एवं अन्य फीसों में छूट देने के फलस्वरूप शिक्षा संस्थाओं को जो आर्थिक हानि उठानी पड़ी, उसको पूरा करने के लिए उन्हें आलोच्य वर्ष में ५७.५२ लाख रुपये का व्यय सहन करना पड़ा । इस योजना के अनुसार कुल ६,९३,९९० विद्यार्थी लाभान्वित हुए । परिगणित तथा अन्य पिछड़े जातियों के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्तियों और अनावर्तक सहायता के रूप में ५०.९३ लाख रुपये दिया गया । पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत जिन विद्यार्थियों को लाभ हुआ उनकी संख्या १६,७५३ थी । पिछड़े वर्गों जिनमें मोमिन अन्तर्गत सम्मिलित हैं और विमोचित जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिये जाने में क्रमशः १७.८० लाख और ७.४६ लाख रुपये व्यय हुए ।

ऊपर लिखी जातियों के हाई स्कूल श्रेणी तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तक सहायता जिला स्तर पर जिला हरिजन सहायता समिति द्वारा दी गयी । हाई स्कूल श्रेणी के ऊपर वाले विद्यार्थियों को हरिजन कल्याण विभाग ने सीधे छात्रवृत्तियां दी । इसी प्रकार परिगणित जाति के विद्यार्थियों को पढ़ाई, खेलकूद इत्यादि की फीसों में छूट देने के फलस्वरूप हायर सेकेंडरी स्कूलों को होने वाली आर्थिक हानि की पूर्ति स्कूलों के जिला निरीक्षकों द्वारा की गयी और अन्य संस्थाओं को हानि की पूर्ति जिनमें इससे ऊंची अथवा प्राविधिक शिक्षा दी जाती थी हरिजन सहायक विभाग ने स्वयं की ।

### प्राविधिक प्रशिक्षण

हरिजन सहायक विभाग द्वारा चलाये जाने वाले गोरखपुर, नैनीताल और बख्शी का तालाब (लखनऊ) स्थित प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्रों में परिगणित एवं अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थी निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा प्राप्त करते रहे । १९५९-६० के प्रारम्भ से नैनीताल केन्द्र में ओवरसियरी की शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों को वहां से हटा कर पावर डिपार्टमेंट द्वारा चलाये जाने वाले स्कूल में रख दिया गया । नैनीताल केन्द्र में मोटर मैकेनिक और एलेक्ट्रीशियनों के पाठ्यक्रमों का और बड़ौदागिरी और दर्जौगिरी सिखाने का प्रबन्ध किया गया । बख्शी का तालाब (लखनऊ) में मोल्डिंग, बड़ौदागिरी, लोहारों, कैलिको की छाई और दर्जौगिरी की कक्षाएं तथा टर्नर, एलेक्ट्रीशियन और मोटर मैकेनिक की कक्षाएं जारी रही । गोरखपुर केन्द्र में ट्यूबवेल अपरेटरो, एलेक्ट्रीशियन और जेनरल मैकेनिक की कक्षाएं चलती रही । हरिजन विद्यार्थियों को प्राविधिक प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त, इन संस्थाओं द्वारा

अस्पृश्यता निवारण का कार्य इस रूप में होता रहा कि वे कुल भर्ती होने वाले विद्यार्थियों की सख्या के ३० प्रतिशत ऐसे गैर-हरिजन विद्यार्थियों को प्रवेश देती रही जो हरिजन विद्यार्थियों के साथ रहने और खाने-पीने की तैयार थे । परिगणित जातियों के उन विद्यार्थियों को भी जो टूलर अथवा मिस्त्री, प्रशिक्षण, पा रहे थे या जो शार्ट हेन्ड और टाइप करना सीख रहे थे छात्रवृत्तियों और अनावर्तक सहायताएं दी गयी ।

### अस्पृश्यता निवारण

अस्पृश्यता निवारण के लिए उठाये गये विभिन्न कदमों में से राज्य भर में एक अस्पृश्यता विरोधी सप्ताह मनाना भी था ।

एक समान कार्यक्रम सभी जिलों के लिए बनाया गया जिसमें निम्नलिखित कार्य सम्मिलित थे.—

१—ग्रामीण क्षेत्रों में उचित प्रचार,

२—अस्पृश्यता निवारण में सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वैच्छिक सगठनों के सहयोग,

३—सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा विशेष निर्माण-कार्य का निर्धारण,

४—अस्पृश्यता निवारण करने में शिक्षा संस्थाओं द्वारा विशेष सहायता,

५—अन्तर्जातीय भोजन एवं मनोरंजन के कार्य-क्रमों की व्यवस्था ।

आलोच्य वर्ष में प्रचार पर कुल ६४,३६४ रु० व्यय किये गये । गांधी जयन्ती समारोह के सिलसिले में हर साल अस्पृश्यता निरोधक सप्ताह मनाने के लिए उपयुक्त कदम उठाये गये । १९६०-६१ की अवधि में उन स्वैच्छिक सगठनों को, जो राज्य में अस्पृश्यता के कारण तथा अनुसूचित जातियों के उन्नयन संबंधी उपयोगी काम कर रहे थे, शिविर और सम्मेलन आयोजित करने तथा अन्य विकास कार्यों के लिए ३४,००० रु० का अनुदान दिया गया ।

### आर्थिक उन्नति आदि

पिछड़े वर्गों की रहन-सहन की स्थिति सुधार के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों को पीने के पानी की व्यवस्था और अनुसूचित जातियों तथा अविज्ञापित जातियों को मकानों के निर्माण तथा सुधार के लिए सहाय्यार्थ अनुदान का प्राविधान किया गया । अनुसूचित जाति के लोगों को मकान की जमीन खरीदने के लिए सहायता दी गयी ।

लघु-उद्योग शुरू करने तथा अनुसूचित जातियों एवं अविज्ञापित जातियों को बैल, खेती के औजार तथा भूमि सुधार संबंधी कार्यों के लिए सहायता देने हेतु भी आवश्यक व्यवस्था थी ।

वर्ष भर में अनुसूचित जातियों के क्षय रोगियों के उपयुक्त उपचार तथा उत्तर रक्षा पर सहाय्यार्थ अनुदान देने के लिए १५,००५ रु० की धनराशि व्यय की गयी ।

राज्य के अविकसित ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति के लिए केन्द्रीय सरकार ने १९५६-६० तथा १९६०-६१ के लिए कुछ योजनाओं को स्वीकार कर लिया था जिन पर ५५ लाख रुपये व्यय होने थे । इस पूरी धनराशि में से मिर्जापुर जिले के दुहड़ी और रावटसंगज क्षेत्रों को पेय जल की समस्या तथा उस क्षेत्र के अधिवासियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए १३.१०७ लाख रुपये व्यय करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया । कुमायू डिवीजन के पहाड़ी जिलों में मेहरो के क्वार्टरों के निर्माण के लिए ५ लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी । संबंधित नगरपालिकाओं की देख रेख में इन क्वार्टरों का निर्माण हो रहा था । विकास खंडों से पक्का कुआँ बनाने के लिए कर्म लेने वाले किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए कुछ विशेष पिछड़े हुए जिलों को १२.४२ लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी ।

## आश्रम के ढंग के स्कूल

• गत वर्ष आश्रम के ढंग के जो दो स्कूल दलाये गये थे—एक लखनऊ जिले के काकोरी में तथा दूसरा इलाहाबाद के हरिजन आश्रम में—वे इस वर्ष भी चालू रहे। अविज्ञापित जातियों के बच्चों को इन स्कूलों में निवास, भोजन तथा शिक्षा की निशुल्क व्यवस्था की गयी। आश्रम के ढंग के इन स्कूलों को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य अविज्ञापित जातियों के बच्चों की उनके माता-पिता के कुप्रभाव से दूर रखना था। अखिल भारताय अपराध निरोधक संस्था, काकोरी स्कूल का प्रबंध कर रही थी और हरिजन आश्रम, इलाहाबाद, इलाहाबाद के स्कूल का प्रबंध कर रहा था। इन दोनों संस्थाओं को कुल ₹ ३६,०६८ रुपये का अनुदान दिया गया। इन स्कूलों में कुल १७० विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इस वर्ष में ऐसे तीन और स्कूल—हरद्वार, रामपुर, तथा गोरखपुर में खोलने के लिए प्रारंभिक कार्यवाही की गयी।

## बस्तियों में अविज्ञापित जातियों को सुविधाएं

अविज्ञापित जातियों के उन सदस्यों के हित की देखभाल के लिए, जो अपराधी जातियों की बस्तियों में रहते हैं, हरिजन सहायक विभाग, कल्याणपुर (कानपुर), गोरखपुर और मुरादाबाद की तीनों बस्तियों का प्रबंध करता रहा। इन बस्तियों के निवासियों को, उनके बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं के अलावा कृषि-भूमि भी दी गयी। कल्याणपुर में एक कपड़े की सिलाई का कारखाना चलाया जा रहा था जिसमें मुख्यतः पुलिस के कपड़े तैयार किये गये। मुरादाबाद में एक बुनाई का कारखाना था जिसमें बस्तियों के निवासियों को रोजी मिली थी। इन बस्तियों के ५१० निवासियों तथा अन्य जिलों के लोगों की खीरी, मथुरा, बहराइच और इटावा जिलों में भूमि तथा उद्योग में लगाने के लिए प्रयास किये गये। इस वर्ष में मैनपुरी, एटा, बाराबंकी और शाहजहापुर जिलों में बस्तियों की स्थापना के लिए ₹ २,५०,४२० रुपये के अनुदान स्वीकृत किये गये। वर्ष की समाप्ति तक ये योजनाएं लगभग पूरी हो गयी थीं।

## मलधान चौर, जिला नैनीताल में शिल्पकारों का पुनर्वासन

गत वर्ष भारत सरकार ने एक विशेष अनुदान स्वीकृत किया था जिसकी सहायता से हरिजन सहायक विभाग ने कुमायूँ डिवीजन के ३८५ शिल्पकार परिवारों को, जिनके पाम आजीविका का कोई साधन नहीं था, बसाने की एक प्रमुख योजना को कार्यान्वित किया। यह योजना ₹ ६५७-५८ में ३०,००० रुपये के छोटे से अनुदान से शुरू की गयी थी। राजस्व विभाग द्वारा दी गयी ₹ १६० एकड़ भूमि के विकास हेतु बसने वालों को आर्थिक सहायता देने के लिए उक्त अनुदान को राजस्व परिषद् को सौंप दिया गया। ₹ ६५८-५९ की अवधि में ५०,००० रु० का दूसरा अनुदान गृह-निर्माण एवं कृषि की उन्नति के लिए दिया गया। ₹ ६५९-६० की अवधि में इस योजना के प्रबंध के लिए हरिजन सहायक विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। ₹ ६५९-६० तथा ₹ ६६०-६१ में भारत सरकार ने ५५० लाख रुपये की धनराशि इस योजना को पूरा करने के लिए स्वीकृत की। इस सहायता से ३८५ गृहों, सिंचाई तथा पीने के पानी के कुओं का निर्माण, भूमि को ट्रैक्टरों में जोतने आदि की व्यवस्था संभव हुई। ६ औद्योगिक सहकारी समितियों और एक यूनियन की रजिस्ट्री एवं स्थापना हुई और उनको ३७,५०० रु० की धनराशि ग्रामीण उद्योग शुरू करने के लिए दी गयी। बसने वालों को बैल खरीदने के लिए ₹ १,१५५ लाख रुपये की धनराशि दी गयी। इस योजना को पूरे जोर-शोर से चलाने के लिए वहां एक अधिकारी तथा उसके कर्मचारियों की नियुक्ति हुई।

## सेवाओं में प्रतिनिधित्व

सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर और ध्यान दिया गया। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री राधाकृष्ण की अध्यक्षता में एक समिति सेवाओं में अनुसूचित जातियों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व की जांच करने तथा इस प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने और अनुसूचित जातियों के सदस्यों के सुरक्षित प्रतिशत तक इनका प्रतिनिधित्व लाने के उपायों

के संबंध में सिफारिश करने के लिए, बत दी रही। स्थिति में नए सिफारिश सरकार को प्रस्तुत कर दो और वर्ष की समाप्ति तक अगस्त १९६२ में विचारणीय रही।

#### ४—सहायता तथा पुनर्वास

##### सामान्य

१९६०-६१ में सहायता एवं पुनर्वास विभाग के काम प्रचार के कार्य-कलाप पर परीक्षण हुआ। पिछले १२ वर्षों में यह विभाग कार्य कर रहा था, इसका उद्देश्य पाकिस्तान से आये विस्थापितों को आरम्भिक सहायता देना तथा उनके अपने पुनर्वास की व्यवस्था करना था, जो कि अधिकांशतः पूरा किया जा चुका था। १९६१-६२ के वित्तीय वर्ष में अवशिष्ट काम पूरा हो जाने की आशा थी।

विस्थापित लोग अत्यंत लज्जत व असुखी थे और अब यह हलूम किया जाने लगा कि कुछ समय तक उनके हितों की रक्षा आवश्यक हो जाती है, परंतु पूर्ण वांछनीय न होगा कि उनके ऊपर विशेष ध्यान रखा जाय, क्योंकि इससे उनके समाज की भावना पनपेगी जो उनके पूर्णरूप में पुनर्वास होने के क्रम में बाध रहेगी। एवं पुनर्वासन तभी हो सकेगा जब विस्थापित आय जनता में घुल-मिल जायें और आम जनता के दृष्टिकोण से अपनी समस्याओं को देखना सीखेंगे। देश के पुनः निर्माण के सामान्य समस्याओं के अभिन्न अंग के रूप में ही विस्थापितों की समस्याओं पर विचार किया जा सकेगा और विशेष जनता की विकास योजनाओं के साथ पुनर्वास स्वयं अवशेष कार्यों के विचार देने से ही उनके हितों की रक्षा हो सकेगी। अतएव इस अवधि में विस्थापितों से संबंधित बहुतों कार्य अन्य विभागों को हस्तांतरित कर दिये गये। इसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:—

हस्तांतरित काम का स्वरूप	विभाग का नाम जिसे काम सौंपा गया
१—विस्थापित विद्यार्थियों की वित्तीय सहायता	शिक्षा विभाग
२—विस्थापित विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने वाली शैक्षिक संस्थाओं को सहायताएं अनुदान	शिक्षा विभाग
३—गृहों में विस्थापित महिलाओं का रख-रखाव	समाज कल्याण विभाग
४—गृहों के बाहर रहने वाले लोगों की भर्त्ता अन्तुदान	समाज कल्याण विभाग

##### अवशेष कार्य

इस वर्ष के अन्त तक जो काम हुआ और जिसका अवशेष रहा उसका तखसीना नीचे दिया जा रहा है—

##### पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों का भूखि पर पुनर्वास

शुरु में राज्य सरकार उत्तर प्रदेश पूर्वी पाकिस्तान से आये ३,००० विस्थापित परिवारों को पुनर्वासित करने के लिए सहमत थी, पर भारत सरकार के कहने पर सरकार ने इस सख्या को बढ़ा कर ५,००० करने का निश्चय किया। पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों के पुनर्वासन के हेतु बहुत सी योजनाएं वित्तीय सहायता के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत की गयीं। उसने ३० योजनाएं स्वीकृत कीं, जिनका उद्देश्य ४,३२० परिवारों को पुनर्वासन प्रदान करना था। प्रदेश के बहुत से जिलों में इन परिवारों को बसाना था। आरंभ में भारत सरकार ने यह सहस्रसूत

किया कि यदि इनमें से कोई योजना १९६१-६२ के अन्त तक पूरी तौर से कार्यान्वित न हो सके तो यह उचित होगा कि उसे त्याग दिया जाय। इस सम्बन्ध में मई, १९६१ में निर्णय लिया गया। इसलिए कुछ स्वीकृत योजनाएं कार्यान्वित नहीं हुई और दूसरी अन्य योजनाओं के अन्तर्गत विस्थापित परिवारों की संख्या कम कर दी गयी।

इस प्रकार सरकार ने लगभग २८ योजनाओं को कार्यान्वित किया जिनका उद्देश्य ३,८४३ परिवारों को बसाना था। इस काम के लिए चुने गये जिलों के नाम तथा हर का एक को सुपुर्द किये गये परिवारों एवं योजनाओं की संख्या निम्नलिखित है :—

जिले का नाम	योजनाओं की संख्या	पुनर्वासित होने वाले परिवारों की संख्या
१—नैनीताल .. .. .	६	१,३८६
२—पीलीभीत .. .. .	१५	१,५१६
३—रामपुर .. .. .	१	१६०
४—बहराइच .. .. .	३	३००
५—बिजनौर .. .. .	२	२६१
६—बरेली .. .. .	१	१६०
योग .. .. .	२८	३,८१३

वर्ष के अन्त तक ३,८१३ परिवारों में से २,६६३ बंगाली परिवार निम्नांकित जिलों में पुनर्वास के लिए आये थे :—

जिले का नाम	परिवार
१—नैनीताल .. .. .	१,११६
२—पीलीभीत .. .. .	८५८
३—रामपुर .. .. .	१५३
४—बिजनौर .. .. .	२८४
५—बहराइच .. .. .	२७६
योग .. .. .	२,६६३

शेष परिवारों के लिए भूमि अधिग्रहण करने, मकानों का निर्माण करने और भूमि को ट्रेक्टर से जोतने का कार्य चालू था और यह आशा थी कि १९६१-६२ के अन्त तक ये परिवार भी आ जायेंगे।

पुनर्वास हेतु प्रत्येक परिवार को निम्नलिखित सहायता दी गयी :—

- (क) ५ से ८ एकड़ भूमि,
- (ख) बुआई की आरम्भिक लागत तथा बैल एवं कृषि औजारों के क्रय के हेतु ५०० रु० का ऋण दिया गया,
- (ग) रख-रखाव सम्बन्धी सहायता यह सहायता ६ माह के लिए दान के रूप में स्वीकृत की जाती थी। यह अवधि शिविर छोड़ने की तारीख से या पहली फसल की कटाई की तारीख से जो भी पहले पड़ती थी, उससे गिनी जाती थी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित माप के अनुसार हर प्रौढ़ को प्रतिमास १३, २० ३ से ८ साल के हर बच्चे को हर मास ८ ६० रु० और इससे कम उम्र के बच्चों को हर मास ५ रु० दिया जाता था। पर हर दिशा में यह दान अधिक से अधिक प्रति परिवार



४० रु० था। पर यह दान उन बड़े परिवारों के लिए प्रति परिवार प्रति मास ६० रु० तक बढ़ाया जा सकेगा जिन्हें शिविरो में ऊँची दरों पर नकद दान मिलते थे)।

(घ) एक क्वार्टर जिसमें एक कमरा, एक बरामदा और एक रसोईघर और जिसकी लागत लगभग १,५५० रु० और १,६०० रु० के बीच में आती थी, की व्यवस्था की गयी। (सम्बन्धित परिवार के लिए यह लागत ऋण के रूप में मान ली जाती थी)।

(ङ) भूमि को ट्रेक्टर से जोतने तथा दो पट्टेला देने के लिए ६ रु० प्रति एकड़ के हिसाब से अतिरिक्त ऋण की व्यवस्था।

विस्थापितों के पुनर्वासन में भूमि देने, निवास-गृहों के निर्माण और कृषि के लिए परिवारों को आर्थिक सहायता देने का ही काम नहीं था, अपितु अन्य सहायताएं भी हैं जिसमें बाजार तक आदमियों तथा सामान ले जाने की सड़क की सुविधा और शिक्षा एवं चिकित्सा की पर्याप्त सुविधाएं सम्मिलित हैं। ऊपर लिखित २८ स्वीकृत योजनाओं में समय-समय में जो कुछ सुविधाएं स्वीकृत की गयी, वे निम्नांकित हैं :—

१—सड़कें	..	..	..	४७
२—पीने के पानी के कुएं	..	..	..	५८
३—चिकित्सा सुविधाएं—				
(क) अस्पताल	..	..	..	३
(ख) औषधालय	..	..	..	३
४—स्कूल—				
(क) प्राइमरी	..	..	..	२१
(ख) जूनियर हाई स्कूल	..	..	..	३
(ग) पंचायतघर	..	..	..	१
(घ) घेराबन्दी (फेंसिंग)	..	..	..	३० मील

१—पूर्वी पाकिस्तान से आयी निराश्रित विस्थापित महिलाओं तथा लड़कियों का पुनर्वास—नवम्बर, १९५३ में डालीगंज, लखनऊ में एक उत्पादन केन्द्र स्थापित हुआ। इसमें उन पूर्वी पाकिस्तान से आयी निराश्रित एवं असहाय विस्थापित महिलाओं का पुनर्वासन हुआ जो चुनाव के आवास उद्योग गृहों में आमदनी वाले व्यवसायों एवं धंधों में प्रशिक्षित हो चुकी थी। इस हर उत्पादन केन्द्र में जिसमें शुरू में ६८ प्रशिक्षार्थी थे, अब ५४ प्रशिक्षार्थी हो रह गये। निराश्रित विस्थापित महिलाओं का पुनर्वासन निम्न प्रकार से हुआ :—

१—विविध धंधों में प्रशिक्षित लोगों के लिए काम की व्यवस्था,

२—जवान लड़कियों के विवाह का प्रबन्ध,

३—आवश्यक प्रशिक्षण एवं अभिरुचि रखने वालों के लिए रोजगार की व्यवस्था,

४—उनके आश्रितों को शिक्षित करके और विभिन्न प्रकार के उद्योग-धंधों में जवान लड़कों को प्रशिक्षित करके परिवार की जिम्मेदारियों को लेने के योग्य बनाना।

जिन परिवारों का पुनर्वासन न हो सका वे भी आत्म निर्भर हो रहे थे। यह आशा की गयी कि वे भी कुछ ही वर्षों में सरकार पर भार स्वरूप नहीं रहेंगे। पुनर्वास सम्बन्धी गृह-निर्माण राज्य सरकार ने विस्थापितों के लिए दुकानें बनाने हेतु ६०,००० रु० की ऋण नगरपालिका काशीपुर, नैनीताल, तथा २,५०,००० रु० का ऋण नगर महापालिका वाराणसी को दिया। १९६०-६१ की अवधि में पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापितों के लिए काशीपुर नगर पालिका ने ७७ दुकानें बनवायीं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इलाहाबाद

की नैनी उद्योग बस्ती, भैरठ की गोविन्दपुरी नयी बस्ती में, लखनऊ के बटलर पैलेस और रुड़की की रामनगर बस्ती में विकास सम्बन्धी कार्य किया।

इवैक्यूई इंटरेस्ट (सेपरेशन) ऐक्ट, १९५१—मिश्रित विस्थापित संपत्ति में मिश्रित विस्थापित एवं अविस्थापित हितों के बिलगाव की व्यवस्था करने के दृष्टिकोण से केन्द्रीय कानून, जिसे इवैक्यूई इंटरेस्ट (सेपरेशन) की सज्ञा दी गयी, १९५१ में बनाया गया। उत्तर प्रदेश इवैक्यूई इंटरेस्ट (सेपरेशन) अनुपूरक ऐक्ट, १९५३ ने उसका अनुगमन किया। (३ से १५ दिसम्बर, १९५२ से लागू किया गया) उत्तर प्रदेश इवैक्यूई इंटरेस्ट (सेपरेशन) अनुपूरक कानून, १९६० के द्वारा भी कानून में एक संशोधन किया गया, जो १५ अक्टूबर, १९६० से लागू किया गया।

इस कानून को लागू करने के उद्देश्य से राज्य को दो वृत्तों में बांटा गया जिसके रीजनल हेडक्वार्टर लखनऊ और भैरठ थे। राज्य के न्यास सेवाओं के दो अधिकारियों को समर्थ अधिकारों के रूप में नियुक्त किया गया और इन हेडक्वार्टरों पर रखा गया। समर्थ अधिकारियों के अतिरिक्त राज्य सरकार ने ग्रामीण सम्पत्ति की बिक्री की देखभाल करने के लिए एक बिक्री अधिकारी की भी नियुक्ति की। इस कानून के अन्तर्गत पूरे किये जाने वाले कार्य का बहुत बड़ा हिस्सा वर्ष की समाप्ति तक पूरा किया जा चुका था।

क्लेम (दावा) संगठन—भारत सरकार के पुनर्वासि मंत्रालय ने क्लेम संगठन को मई, १९६०, में सीधे अपने अधिकार में ले लिया।

## अध्याय ८ स्थानीय निकायों के कार्यकलाप १-पंचायतें

### सामान्य

आलोच्य वर्ष में तीसरी पंचवर्षीय योजना, जन-गणना, और पंचायत चुनाव की तैयारी में व्यस्त रहने के बावजूद गांव पंचायतों ने गत वर्ष की अपेक्षा अधिक रचनात्मक कार्य किया। रचनात्मक कार्यों की स्थिति में जो सुधार हुआ उसका श्रेय सरकार की नीति को है। गांव पंचायतों के खाते विकेंद्रित कर दिये गये और हर गांव पंचायत ने निकटतम डाकखाने में 'सेविंग बैंक' में अपना खाता खोल लिया। धन की आवश्यकता पड़ने पर प्रधान को रुपया निकालने का अधिकार था। नियोजन विभाग ने संचार-साधन एवं जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों के लिए बिना किसी शर्त के एक ही बार गांव पंचायतों को अनुदान दिया। इन सुविधाओं ने गांव पंचायतों को अपने बल पर काम करने का अवसर प्रदान किया।

### जल-सप्लाई एवं स्वच्छता आदि

आलोच्य वर्ष में गांव-पंचायतों ने पानी पीने के १५,०४१ कुएं बनवाये और २१,३०६ हण्ड पम्प लगवाये। पानी पीने के २२,५२१ पुराने कुओं की मरम्मत की गयी।

अपने क्षेत्रों में गांव पंचायतों ने १,२२,०६१ सोखते और ११,०४४ शौचालय बनवाये।

### सड़के, गलियां आदि

इस वर्ष में ३६१ मील पक्की तथा २,६३२ मील कच्ची सड़के बनवायी गयी। ५१० मील पक्की तथा १०,३२५ मील कच्ची सड़कों की मरम्मत की गयी। गांव की गलियों में कुल ४१३ मील लम्बाई में खडजे लगाये गये।

### पंचायतघर

इस अवधि में क्रमशः ८७६ पंचायतघर तथा ६४२ स्कूलों की इमारतें बनायी गयी।

### शिक्षा

इस अवधि में गांव पंचायतों ने ३,५६१ पुस्तकालय स्थापित किये और ६०५ रेडियो सेट खरीदे।

### कृषि एवं अन्य कार्य-कलाप

गांव पंचायतों को तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूप-रेखा तैयार करने का काम दिया गया और उन्होंने ग्राम-योजनाएं बनायी। रबी और खरीफ अभियान चलाने की योजना बनी और उसे गांव पंचायतों ने कार्यान्वित किया। इस अवधि में कुछ पंचायतों ने अपने-अपने क्षेत्रों में गेहू तथा धान की औसत उपज में वृद्धि करने के सराहनीय कार्य किये। उन्होंने ३६,३४,२७५ फलदार वृक्ष तथा ३५,६२,३५६ ईधन के वृक्ष लगाये।

कुछ गांव पंचायतों ने जलाशयों और रेगुलेटर्स का भी निर्माण कराया और कुछ ने सिंचाई हेतु नहरें खुदवायी। कुछ पंचायतों ने पम्पिंग सेट लगवाये और पानी निकासी हेतु नाले खुदवाये।

## श्रमदान

विगत वर्षों की भांति गांव पंचायतो के सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में जनता का सन्तोषजनक सहयोग था। इस अवधि में १,३४,६७,८०० रुपये की कीमत का श्रमदान हुआ। जनता द्वारा दिये गये नकद चन्दे तथा अन्य प्रकार के चन्दों की सम्मिलित कीमत, १,२५,०२,७४६ रुपये आयी। इस अवधि में जनता के चन्दे में जो थोड़ी-बहुत कमी आयी उसका प्रमुख कारण यह था कि दिसम्बर, १९६० तथा जनवरी-फरवरी, १९६१ के महीनों में लोग पंचायत के चुनावों में व्यस्त थे।

## २-नगर महापालिकाएं

प्रदेश के पांच महानगरों—कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ में नगर महापालिकाओं की स्थापना के फलस्वरूप महापालिकाओं की परिधि में नये क्षेत्र सम्मिलित कर लिये गये। इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में बहुत-सी समस्याएं उत्पन्न हो गयीं जैसे नये स्कूलों, चिकित्सालयों और औषधालयों की व्यवस्था और सफाई, जल-सप्लाई, रोशनी, भवनों का निर्माण, सड़कें, जल निकासी की व्यवस्था, आदि। विविध समस्याएं जो उनके सम्मुख आयी और कठिनाइयाँ जिनमें प्रमुख धनाभाव की कठिनाई थी, इन सबके होते हुए भी नगर महापालिकाओं ने जनता को आवश्यक सुविधाएं देने का प्रयास किया और इन्हीं दिशा में सराहनीय काम किया। १९६०-६१ की अवधि में विविध क्षेत्रों, जैसे शिक्षा, जनस्वास्थ्य एवं सफाई, सड़कों एवं भवनों के निर्माण आदि, में उल्लेखनीय प्रगति हुई। इस अवधि में महापालिकाओं द्वारा सम्पादित कुछ मुख्य कार्यों का विवरण नीचे दिया जाता है:—

### शिक्षा

अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा योजना के अधीन कानपुर नगर महापालिका ३२५ स्कूल चला रही थी जिसमें लड़कों के १६१ तथा लड़कियों के १६४ स्कूल थे। इन स्कूलों में ६३,००० से अधिक लड़के और लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। महापालिका लड़कों के ६ जूनियर हाई स्कूल तथा लड़कियों के १० जूनियर हाई स्कूल चला रही थी जिनमें लगभग ४,०६८ लड़के और लड़कियाँ शिक्षा पा रहे थे। साथ ही यह महिलाओं का एक नार्मल स्कूल भी चला रही थी। प्रौढों के लिए १२ स्कूल थे। इनके अतिरिक्त लड़कों के चार तथा लड़कियों के तीन कालेज थे। इन कालेजों में लगभग ४,७६४ लड़के और लड़कियाँ शिक्षा पा रहे थे। नगर में एक मांटेसरी स्कूल भी था जिसमें ३०० बच्चे शिक्षा पा रहे थे। इन शैक्षिक संस्थाओं के अतिरिक्त महापालिका एक संगीत महाविद्यालय भी चला रही थी। महापालिका की परिधि में आये नये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए १८ नये स्कूलों के निर्माण की व्यवस्था भी महापालिका ने की।

आगरा नगर महापालिका लड़कों के १०३ और लड़कियों के २४ स्कूल चला रही थी। इनमें दो उच्चतर माध्यमिक स्कूल भी सम्मिलित थे। इन संस्थाओं में लगभग २१,८५० लड़के और लड़कियाँ शिक्षा पा रहे थे। अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा योजना भी चालू थी। १६ स्कूलों में छात्रों को दोपहर में दूध देने की व्यवस्था की गयी।

वाराणसी नगर महापालिका लड़कों के ८६ बेसिक स्कूल, लड़कियों के १८ बेसिक स्कूल, लड़कों के ६ तथा लड़कियों के ५ जूनियर हाई स्कूल, १ इन्टर कालेज, १ महिला उद्योग केन्द्र और एक चमड़ा उद्योग स्कूल चला रही थी।

इलाहाबाद नगर महापालिका की अधिकार परिधि क्षेत्र में ६ से ११ वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा दी जा रही थी। महापालिका नर्सरी एवं प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, प्रौढों के लिए हाई स्कूल, व्यायामशालाएं, महिला शिल्प भवन और चमड़ा उद्योग स्कूल चला रही थी।

लखनऊ नगर महापालिका १०४ बेसिक तथा ३ जूनियर हाई स्कूल चला रही थी। महापालिका की स्थापना के फलस्वरूप जो क्षेत्र इसकी परिधि में आये उनमें अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा की योजना कार्यान्वित की गयी। नगर में ७४ प्राइमरी स्कूल थे। महापालिका ३३ अन्य शैक्षिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता दे रही थी।

### सड़कें तथा पुल

कानपुर नगर महापालिका ने सड़कों, गलियों तथा फुटपाथों आदि के विकास के लिए तथा उसकी परिधि में आये ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के विकास के लिए अपने सशोधित बजट में १६,००,००० रुपये की व्यवस्था की। गोविन्द नगर पुल के निर्माण की योजना भी तैयार की जिन्हें रेलवे अंत्रालय की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया था। इस पूरे काम की अनुमानित लागत ५,००,००० रुपये थी। आगरा नगर महापालिका ने ६ ७७ मील लम्बाई के फुटपाथों तथा ३ ४० मील लम्बाई के पानी निकासों के नानों का निर्माण कराया। वाराणसी नगर महापालिका ने अपने बजट में सड़कों के निर्माण के लिए २५,०१,००० रुपये का प्राविधान किया। इस काम पर करीब ४ लाख रुपये की धनराशि व्यय हुई।

इस अवधि में इलाहाबाद नगर महापालिका ने सड़कों को चौड़ा करने तथा फुटपाथों की रसाई, सजावट, एवं मरम्मत पर लगभग ८१,६८८ रुपये व्यय किये और सरकार के विविध अनुदानों से लगभग १,४६,८२५ रुपये व्यय किये। महापालिका में बाग बाबा शीतलदास, मलूकराज बख्शी बाजार, मिर्जापुर, दरियाबाद, मोहिले नगर, लूथर रोड, दारागज दरियाबाद सहायक पाइप लाइन आदि में नयी पाइप लाइने बिछायी गयी। इस कार्य पर ४१,००० रुपये की धनराशि व्यय हुई।

लखनऊ नगर महापालिका ने सड़कों की मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया। इस अवधि में महापालिका ने सड़कों की मरम्मत पर लगभग २,५०,००० रुपये व्यय किये। मरम्मत की गयी सड़कों की लम्बाई २० मील थी।

### भवन-निर्माण

राज्य सरकार ने कानपुर नगर महापालिका को महापालिका कार्यालय भवन के निर्माण हेतु १० लाख रुपये का ऋण स्वीकार किया। मुख्य भवन तथा सभा भवन (असेम्बली हाल) के एक तल्ले के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था और बाकी निर्माण कार्य चालू था। इस अवधि में महात्मा गांधी मार्ग पर विस्थापितों के लिए एक बाजार का निर्माण हुआ। जर्जों के लिए दो फ्लैट बनाये गये और एक का निर्माण जारी था। गोविन्द नगर तथा परम पुरवा में करीब ७२ क्वार्टर बनाये गये। मेडिकल अफसर के लिए गोविन्द नगर अस्पताल में एक आवास-गृह बनाया गया। खलासी लाइन्स बिल्डिंग में एक होम्योपैथिक औषधालय खोला गया। नवाबगज के मालुशिशु केंद्र में सुधार किया गया। गोविन्द नगर में एक लड़कियों के स्कूल की इमारत बन रही थी और बी०आर०डी० गर्ल्स कालेज में कुछ और कमरे बनाये जा रहे थे। बाबूपुरवा, हरिहर शास्त्री नगर, कारबोलो नगर, किदवई नगर आदि में प्राइमरी स्कूलों की इमारतों का निर्माण जारी था।

आगरा नगर महापालिका के ताजगंज और बलकेश्वर में हरिजनो के ५० क्वार्टर बने। इस वर्ष में ५ स्कूलों की इमारतों का निर्माण शुरू किया गया।

वाराणसी नगर महापालिका ने गत वर्ष महापालिका कार्यालय भवन का निर्माण शुरू किया था। आलोच्य वर्ष में काफी प्रगति हुई और करीब ४ लाख रुपये व्यय हुए। निर्माण की पूरी लागत २१ लाख रुपये आकी गयी थी।

इलाहाबाद नगर महापालिका ने संग्रहालय भवन के बढ़ाने का काम हाथ में लिया और २,१६,००० रु० व्यय किये। एक नये महापालिका भवन का निर्माण १,७०,००० रुपये

की लागत से हुआ। महापालिका ने लीडर रोड पर १६ नयी डुकाने तथा सिविल लाइन्स में ११ नयी डुकाने बनवाये। कीडगज और मनफोर्डगज में नये उद्यान बनाये गये।

लखनऊ नगर महापालिका ने अधिक निर्माण कार्य महानगर और रिवर बैंक कालोनी में किया जहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास-गृह बने थे। आलोच्य वर्ष के अन्त तक महानगर योजना के अधीन १,३७० प्लॉट प्रकान बनाने के लिए लोगों को बेचे गये। इनका वर्गीकरण 'ए', 'बी०', 'सी०' प्रकार के प्लॉटों में किया गया। 'ए' प्रकार के प्लॉटों का क्षेत्रफल १६,००० वर्गफुट, 'बी' प्रकार के प्लॉटों क्षेत्रफल ६,६०० वर्गफुट और 'सी' प्रकार के प्लॉटों का क्षेत्रफल ३,२०० वर्गफुट था। उन्हें क्रमशः ४० न० पै०, ४४ न० पै० और ५० न० पै० प्रति वर्ग फुट की दर से बेचा गया। महानगर योजना 'न लाभ हो न नुकसान हो' के आधार पर बनी थी।

### जन स्वास्थ्य एवं सफाई

जून और जुलाई, १९६० के मासों में कानपुर में हैजे का प्रकोप हुआ, महापालिका ने इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाया। लगभग ६५,००० व्यक्तियों को टीका लगाया। जिन क्षेत्रों में हैजा फैला था उनमें कुत्तों तथा अन्य पानी के साधनों को सक्रमण-विहीन किया गया। कटे हुए फल बेचने वालों का जातान किया गया। लगभग ८६५ व्यक्तियों को यह रोग हुआ जिसमें ११८ व्यक्ति मरे।

महापालिका १० एलोपैथी, ६ होम्योपैथी और ६ आयुर्वेदिक औषधालय तथा १ यूनानी औषधालय चला रही थी। इसके अलावा ३ मातृ-शिशु केन्द्र भी काम कर रहे थे। गोविन्द-नगर अस्पताल में ६० शैयाओं की व्यवस्था थी।

इस वर्ष में आगरा नगर महापालिका ने आभशोथ (गैस्ट्रोइन्टेस्टिस) की महामारी को रोकने के लिए प्रभावकारी उपाय किये। नगर की सफाई की दशा में सुधार करने के लिए सफाई कर्मचारियों में वृद्धि की गयी। महापालिका में एक नया होम्योपैथिक औषधालय खोला।

४ अप्रैल से २६ अप्रैल, १९६० तक वाराणसी नगर महापालिका ने सफाई अभियान आयोजित किया। इस अवधि में नगर की हर गली, हर उप-गली को सफाई की गयी। नगर में किसी प्रकार का संक्रामक रोग नहीं फैला।

इलाहाबाद नगर महापालिका ने संक्रामक रोगों के प्रकोप को रोकने के लिए उपाय किये और नगर की सफाई के लिए एक विशेष सफाई दल लगाया गया। बहुत से सुहृत्लों के लिए कूड़ेखानों की व्यवस्था की गयी।

लखनऊ नगर महापालिका ३ एलोपैथिक, १ होम्योपैथिक, २ आयुर्वेदिक और २ यूनानी औषधालय, १ संक्रामक रोगों का अस्पताल, १ मातृ-शिशु केन्द्र, एक महिला औषधालय अपने धन से चला रही थी। अक्टूबर, १९६० में गोमती नदी में भयानक बाढ़ आने के फलस्वरूप महापालिका के जन स्वास्थ्य विभाग का काम बढ़ गया। बाढ़ के बाद महापालिका से बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों की सफाई का काम हाथ में लिया। डी० डी० टो० का छिड़काव किया गया और सचल औषधालय खोले गये। नगर में किसी प्रकार का संक्रामक रोग नहीं फैला। बाढ़ के दौरान पानी तथा बिजली की सप्लाई सुचारु रूप से चलती रही।

### ३-नगर पालिकाएं

नागरिक सुविधाओं के क्षेत्र में सुधार के क्रम को गति देने के लिए नगर महापालिकाओं ने गहरी दिलचस्पी ली, यद्यपि उनके रास्ते में कठिनाइयाँ थी, विशेषकर वित्तीय अभाव की।

#### जन-स्वास्थ्य एवं सफाई

चिकित्सा-सहायता एवं जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत नगरपालिकाओं ने महत्वपूर्ण कार्य किये। अधिकतर नगरों में हैजा, गैस्ट्रोइन्टेस्टिस तथा चेचक महामारी के रूप में फैले थे

और नगरपालिकाओं ने व्यापक पैमाने पर इनके टीके लगाने की व्यवस्था की। जन स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में ऐसे रोगियों का सुप्त इलाज किया गया और उनके घरों में दवाएं छिड़की गयीं। नलों और कुओं की सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया।

नगर पालिकाओं के साधनों के अनुसार सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था की गयी। सड़कों के कोनों तथा आम जगहों पर शौचालय एवं पेशाबघर जनता के लिए बनाये गये। राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम के श्री गणेश से सफाई के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय घटना घटी। अगले छ वर्ष में प्रदेश की नगर पालिकाओं ने पिछले प्रकार के ५१ चिकित्सालय एवं औषधालय चलाये। २१ अक्टूबर, १९६० तक ११२ अस्पतालों को ५६,८४० रुपये की वित्तीय सहायता दी गयी।

### शिक्षा

अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा के कार्यक्रम के अन्तर्गत लड़कों और लड़कियों के बहुत से स्कूल खोले गये। ३१ अक्टूबर, १९६० तक १,३८१ स्कूल नगर पालिकाओं के प्रबन्ध में थे। शिक्षा पाने वाले लड़कों तथा लड़कियों की संख्या २,५०,४४५ थी। प्रौढ शिक्षा की भी व्यवस्था की गयी और बहुत से पुस्तकालय भी स्थापित किये गये।

### सार्वजनिक निर्माण

नगरपालिकाओं ने बहुत-सी सड़कों, इमारतों और पुलों का निर्माण एवं मरम्मत करायी। ३ अक्टूबर, १९६० को नगरपालिकाओं की तारबोल वाली सड़कों की कुल लम्बाई १,१६९.९६ मील तथा पक्की सड़कों की कुल लम्बाई ४७७.४१ मील थी। ऐसी सड़कों के निर्माण, रखरखाव और मरम्मत पर ७०.४६ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान था।

नगर पालिकाओं की इमारतों, चुंगी-चौकियों और चुंगी की सीमाओं के रखरखाव एवं मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया गया। कुछ नगर पालिकाओं ने प्राइमरी स्कूलों की इमारतों में हटरी के क्वार्टर, सार्वजनिक शौचालय विस्थापितों के लिए दुकानें इत्यादि का निर्माण कराया।

### तदर्थ समितियों का गठन

वृहद् योजनाओं की तैयारी, उनमें संशोधन, परिवर्तन अथवा सुधार सम्बन्धी विषयों पर नगर पालिकाओं को सलाह देने के लिए तथा उनके कार्यान्वित एवं लागू करने के सुझाव प्रस्तुत करने के लिए रामपुर, सहारनपुर, सीतापुर, मेरठ, देहरादून, गोरखपुर तथा बरेली नगरों में तदर्थ समितियाँ बनायी गयीं। आशा थी कि शीघ्र ही ये समितियाँ कार्य शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश नगर पालिका ऐक्ट की धारा २९६(२) से के अन्तर्गत सरकार द्वारा १९५९-६० को अवधि में प्रदेश में ऐसी समितियों के गठन सम्बन्धी नियम बना दिये गये थे।

### नगरपालिकाओं के आर्थिक विकास सम्बन्धी कार्य-कलाप

स्वायत्त शासन की केन्द्रीय परिषद् के अनुरोध पर राज्य सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया कि नगर पालिकाओं द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए औद्योगिक कार्य किये जाने चाहिये। वे इस मत के थे कि इसका अर्थ यह नहीं कि नगर पालिकाएं जो अब तक नागरिक सुविधाओं और सार्वजनिक सेवाओं तक ही सीमित थीं वे इन अपने परम्परागत कार्य कलापों से हट जायेगी। श्री गणेश करने के विचार से बड़ी नगरपालिकाओं को पहले पहल सम्बन्धित नगर पालिका के क्षेत्र में (१) उन वस्तुओं का उत्पादन जिनमें विशेष सुविधा हो (२) औद्योगिक एवं वाणिज्य सम्बन्धी आस्थानों की स्थापना करने की अनुमति दी जानी चाहिये। यह महसूस किया गया कि ऐसा करने में अपनी आय बढ़ाने के अतिरिक्त नगरपालिकाएं कुटीर उद्योग का विकास एवं उन्नति करेगी और इस प्रकार राज्य के औद्योगीकरण में सहायक होगी।

### चित्रकूट धाम तथा निकटवर्ती क्षेत्रों का विकास

चित्रकूट धाम तथा निकटवर्ती क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सरकारों ने संयुक्त रूप से इस क्षेत्र का विकास करने का निश्चय किया।

इसके लिये हर प्रदेश के सम्बन्धित क्षेत्रों के लिये एक स्थानीय विकास प्रशासन स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में इस प्रशासन के अधिकार चित्रकूट धाम की नगरपालिका को सौंप दिये गये हैं। समस्त क्षेत्र के विकास कार्य-क्रम को समन्वित करने के उद्देश्य से दोनों सरकारों ने एक संयुक्त सलाहकार समिति की स्थापना की। पूरे तौर से विकसित हो जाने पर यह क्षेत्र तीर्थ यात्रियों को आकृष्ट करने के अलावा पर्यटकों को बड़ी संख्या में आकृष्ट करने लगेगा।

(चित्रकूट धाम एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। यहां साल भर पर्यटक तथा तीर्थ यात्री आते हैं। स्थान की धार्मिक महत्ता के अलावा, यह क्षेत्र चतुर्दिक नैसर्गिक सुषमा से परिपूर्ण है। इस क्षेत्र में साल में दो मेले लगते हैं। जिनमें काफी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। चित्रकूट शहर इस राज्य में पड़ता है पर बहुत से धार्मिक स्थान और दर्शनीय स्थल सीमा के उस पार मध्य प्रदेश में स्थित हैं। सफाई तथा अन्य सुविधाओं की जो व्यवस्था अब तक रही, वह अपर्याप्त थी।)

## ४-जिला बोर्ड

(अन्तरिम जिला परिषद)

### शिक्षा

साधनों की कमी के बावजूद अन्तरिम जिला परिषदों ने ग्रामीण जनता की शिक्षा की वृद्धि जिम्मेदारी वहन की। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती रही। जिलों के आकड़े जिनका उल्लेख आवश्यक है नीचे दिये जा रहे हैं—

मेरठ	..	..	१,१४५	स्कूल
पोड़ी-गढ़वाल	..	..	१,१०७	"
गोरखपुर	..	..	९७७	"
कानपुर	..	..	८९६	"
अल्मोड़ा	..	..	८९१	"
बलिया	..	..	८०५	"
शाहजहापुर	..	..	८०४	"
वाराणसी	..	..	७५६	"
बरेली	..	..	७५४	"
जौनपुर	..	..	७४०	"
बादा	..	..	६८९	"
नैनीताल	..	..	५७२	"

तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शिक्षा पर अधिक जोर दिया जा रहा है और विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में और यह आशा की गयी कि तीसरी योजना के अन्त तक सम्पूर्ण राज्य के गांवों का जाल बिछ जायगा।

आलोच्य वर्ष में कृषि, शिक्षा, सामाजिक शिक्षा तथा अन्य विविध कार्य-कलापों पर विशेष ध्यान दिया गया। इन शैक्षिक संस्थाओं के अध्यापकों और छात्रों ने श्रमदान में भाग लिया।

### सार्वजनिक निर्माण

वित्तीय साधनों की कमी के बावजूद अन्तरिम जिला परिषदों ने तारकोल वाली सड़कों एवं पक्की सड़कों और इमारतों की मरम्मत एवं रख-रखाव, पुलिया और नयी सड़कों के निर्माण



कार्य के सम्बन्ध में उपयुक्त कदम उठाये। सरकारी अनुदान, परिषद् के फंड तथा जनता के स्वैच्छिक श्रमदान से बहुत-सी पक्की सड़को को तारकोल वाली सड़को तथा कच्ची सड़को को पक्की सड़को में परिणत किया गया। नयी कच्ची सड़को तथा फुटपाथों का भी निर्माण किया गया। जौनपुर में पक्की सड़को की लम्बाई बढ़कर ५२ १/२ मील हो गयी। पहाडी जिलों को कुछ सड़को नव सीमांत जिलों को हस्तारित कर दी गयी।

### चिकित्सा सहायता एवं जन-स्वास्थ्य के उपाय

ग्रामीण क्षेत्रों में महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए उचित उपाय किये गये। जिन क्षेत्रों में सक्रामक रोगों के फैलने का भय था उनमें टीका लगाने के शिविर स्थापित किये गये। जहाँ पर टीका लगाने वालों की कमी थी वहाँ पर यह कार्य अध्यापकों को दे दिया गया, जिन्हें इसकी ट्रेनिंग दी जा चुकी थी। ये परिषदें बहुत से ग्रामीण बैद्यों, हकीमों, और डाक्टरों को वित्तीय सहायता देती रही। मलेरिया निरोध के लिए डी० डी० टी० का छिड़काव किया गया, कुओं की सफाई की गयी और पैलूडोन की टिकिया मुफ्त बाटी गयी। बहुत से औषधालयों पर प्रशिक्षित डाक्टर नहीं थे, जिनके अभाव में प्रशिक्षित कम्पाउण्डर ही उन पर काम कर रहे थे। राज्य भर में पशु-चिकित्सालयों और औषधालयों से बारबार सहायता मिलती रही और बढ़िया करने, कृत्रिम गर्भाधान और टीका लगाने का काम भी जारी रहा।

### मेले और प्रदर्शनियाँ

राज्य के विभिन्न जिलों में परिषदों की देखरेख में लगाये गये मेलों का आयोजन एवं प्रबन्ध अत्यन्त सफल रहा। जनता के लिए इन मेलों में चिकित्सा एवं सफाई का प्रबन्ध किया गया और बहुत-सी पशु-प्रदर्शनियाँ भी आयोजित की गयीं। ग्रामीण जनता को शिक्षित करने के लिए कुछ प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया गया।

## ५-नोटीफाइड एरिया

### सफाई एवं जल-सप्लाई

राज्य की नोटीफाइड एरिया समितियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में सफाई की हालत सुधारने के लिए पर्याप्त उपाय किये। नोटीफाइड एरिया में जल-सप्लाई के मुख्य साधन कुएँ और नलकूप रहे। ऐसी आशा की गयी कि मिर्जापुर की अहरोरा नोटीफाइड एरिया तथा देहरी-गढ़वाल की नोटीफाइड एरिया निकट भविष्य में पाइप द्वारा जल सप्लाई करने लगेंगी।

### जन-स्वास्थ्य के उपाय

इस अवधि में सामान्यतया सभी नोटीफाइड एरिया सक्रामक रोगों से मुक्त रहे। इन रोगों को रोकने तथा इनसे बचाव करने के लिए व्यापक पैमाने पर टीका, हैजे तथा चेचक का, दवाओं का मुफ्त वितरण, कुओं में दवा डालने और डी० डी० टी० के छिड़काव आदि काम किये गये। अगस्त, सितम्बर, १९६०, की अवधि में गैस्ट्रोइंटेस्ट्रियल रोगियों को मुफ्त दवा बांटने का प्रबन्ध काधला नोटीफाइड एरिया कमेटी ने किया। १२,००० व्यक्तियों को हैजा-निरोधक इंजेक्शन लगाने की व्यवस्था की गयी। बहराइच जिले की भिग नोटीफाइड एरिया ने चेचक की शुरुआत को रोकने के लिए चेचक के टीके लगाने की व्यवस्था की।

### सड़को का निर्माण एवं अन्य भवन निर्माण कार्य

सार्वजनिक कार्यों के सम्पादन में इन कमेटियों ने गहरी दिलचस्पी ली। ये अपनी सड़को और गलियों की मरम्मत रखरखाव के काम भी करती रही। उनके वित्तीय साधनों के सीमित होते हुए भी सरकार ने उन १६ नोटीफाइड एरिया कमेटियों में प्रत्येक को ५,००० रु० का सहाय्यार्थ अनुदान स्वीकृत किया, जिन्होंने इसके पहले सड़को के निर्माण तथा मरम्मत सम्बन्धी स्वीकृत अनुदान का इस्तेमाल कर लिया था। ककराला नोटीफाइड एरिया कमेटी को बाबा

अन्तरिम जिला परिषद् की सड़क के उस हिस्से की मरम्मत के लिए ५,००० रु० दिया गया जो इसके क्षेत्र में पड़ती थी और जिसकी मरम्मत नितान्त आवश्यक थी। इन नोटीफाइड एरिया कमेटियों ने उपयुक्त अवसरों पर मेले, प्रदर्शनियों और खेल-कूद प्रतियोगिताओं के आयोजन किये। पशुओं के मेलों की भी व्यवस्था की गयी।

### सड़क की रोशनी

नोटीफाइड एरिया में रोशनी का मुख्य साधन मिट्टी के तेल के लैंप रहे। पर अब ये कमेटियाँ रोशनी की हालत सुधारने के लिए कोशिश कर रही थीं। बदायूँ जिले की कांथला नोटीफाइड एरिया कमेटी ने सड़कों पर जहाँ रोशनी की व्यवस्था नहीं थी वहाँ रोशनी का प्रबन्ध करने के लिए ५,००० रु० की काफी बड़ी रकम खर्च की। कांथला नोटीफाइड एरिया कमेटी के क्षेत्र में बिजली के बल्ब बढ़कर १४५ हो गये।

### शिक्षा

नोटीफाइड एरिया कमेटियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में शिक्षा-सुविधाओं के प्रसार के लिए या तो प्राइमरी और बेसिक शैक्षिक संस्थाएँ स्वतः चलायीं या निजी संस्थाओं को चन्दा देकर सहाता की। बदायूँ जिले की ककराला नोटीफाइड एरिया कमेटी ने अपने यहां एक उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोलने के लिए प्रार्थना की जो सरकार के विचाराधीन थी।

## ६—टाउन एरिया

### सड़कें तथा अन्य सार्वजनिक कार्य

प्रदेश की टाउन एरिया कमेटियों ने सार्वजनिक कार्यों के सम्पादन में विशेष उत्साह दिखाया, यद्यपि वे स्थानीय निकाय ही थे जिनके वित्तीय साधन में अत्यन्त सीमित थे।

साहारनपुर जिले की नाकुर टाउन एरिया कमेटी ने ४,६०० रु० की लागत से एक सीमेंट की सड़क बनायी और ननौता टाउन एरिया कमेटी ने दो ४०० फुट लम्बे पानी निकासी के नलों में सीमेंट लगवायी। कानपुर जिले की बिल्हौर टाउन एरिया कमेटी ने १०० रु० व्यय करके एक पक्का पानी निकासी के लिए नाला बनवाया और १८० रु० की लागत से तीन कुओं की मरम्मत की। देहरादून जिले की चौहारपुर टाउन एरिया कमेटी ने १,१८३ रु० की लागत से लगभग १,००० फुट लम्बा एक नया नाला बनवाया तथा वर्ष की समाप्ति तक दो मुख्य सड़कों को ६,००० रु० की लागत से सीमेंट से बनवाया। वाराणसी जिले की चकिया टाउन एरिया कमेटी ने एक ४५० फुट लम्बी तथा दूसरी ५०० फुट लम्बी सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया और ६०० वर्गफुट में खंडजा लगवाया। २ मील लम्बी सड़क तथा १ मील लम्बे पानी निकासी के नाले के निर्माण के लिए इटावा जिले की बहुत-सी टाउन एरिया कमेटियों ने ७३,३१६ रुपये व्यय किये। नैनीताल की टनकपुर टाउन एरिया कमेटी ने पुरानी गलियों को पक्का करने के सिलसिले में २०,००० रु० व्यय किया। अलीगढ़ जिले की खैर टाउन एरिया कमेटी ने सार्वजनिक कार्यों पर १०,००० रु० व्यय किया। जलाल टाउन एरिया कमेटी ने २५,००० रु० की लागत से एक सीमेंट की सड़क बनवायी। बिजयगढ़ टाउन एरिया कमेटी ने ७ सड़कें और तीन पानी निकासी के नाले बनवाये। अलीगढ़ जिले की माड़ू टाउन एरिया कमेटी ने वर्ष के अंत तक ७०० फुट लम्बा पानी निकासी का नाला निर्मित कराया। पीलखाना टाउन एरिया कमेटी ने एक सीमेंट की सड़क तथा एक पुल बनवाया। हमीरपुर जिले की मौवहा टाउन एरिया कमेटी ने दो सड़कों का काम पूरा किया जिसका निर्माण कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका था। रामपुर जिले की शाहाबाद टाउन एरिया कमेटी ने ऐसे ही कार्यों पर १,१५० रु० व्यय किया। रामपुर जिले की सौर (Suar) टाउन एरिया कमेटी ने दो पुलों के निर्माण के अलावा ४,२०० फुट में खंडजा लगवाया और ८,००० फुट लम्बे बानी की निकासी के नाले बनवाये। विलासपुर टाउन एरिया कमेटी ने १२,००० रु० की लागत से सार्वजनिक कार्य शुरू किया।

रामपुर जिले की टाउन एरिया कमेटी ने खड्जा लगाने पर २,००० रु० व्यय किया। टाडा टाउन एरिया कमेटी ने सार्वजनिक कार्यों के लिए १०,००० रु० तथा पानी निकासी के नालों और नालियों के निर्माण के लिए १३,००० रु० लगाये। मिलाख टाउन एरिया कमेटी ने सार्वजनिक कार्यों पर १०,००० रु० व्यय किया और अल्मोड़ा जिले की बागेश्वर टाउन एरिया कमेटी ने १,५०० फुट लम्बी नयी सार्वजनिक सड़क, १,६०० फुट लम्बी पानी निकासी के नाले और १,००० फुट खड्जे के निर्माण पर २०,००० रु० व्यय किये। पिथौरागढ़ टाउन एरिया कमेटी ने ३ मोटर चलाने योग्य सड़को को सीमेंट से पक्का बनवाया और आधी मील लम्बी एक नयी सड़क बनवायी। गोरखपुर जिले की नौतनवा तथा गोला टाउन एरिया कमेटियों ने सड़को के निर्माण तथा मरम्मत पर क्रमशः ३,३३३ रु० तथा ७२६ रु० व्यय किये। बुलन्दशहर की विभिन्न टाउन एरिया कमेटियों ने सड़क, पानी निकासी के नालों तथा खड्जों के निर्माण पर निम्न प्रकार से व्यय किया।

टाउन एरिया कमेटी का नाम	सार्वजनिक कार्यों की मदें	सही लागत रुपये
(१) औरंगाबाद	.. सड़कें	.. २,०००
(२) सियाना	.. सड़के	.. ६,३६८
(३) गुलौठी	.. सड़के, खड्जा तथा नाले	.. ७,१६५
(४) शिकारपुर	.. "	.. १२,११३
(५) भौन बहादुरनगर	.. "	.. १४,०८०
(६) बाबुपुरा	.. "	.. ३,८२२
(७) छतारी	.. "	.. ७,१७५
(८) पहसू	.. "	.. ४,८३५
(९) काकोरी	.. "	.. ४,६८६

गाजीपुर जिले की मुहम्मदाबाद और सैदपुर की टाउन एरिया कमेटियों ने सार्वजनिक कार्यों पर २,००० रु० व्यय किया। इलाहाबाद जिले की फूलपुर टाउन एरिया कमेटी ने २१,२ फर्लांग लम्बी सड़क बनवायी।

### सफाई एवं जन-स्वास्थ्य के उपाय

टाउन एरिया कमेटियाँ अपने-अपने क्षेत्रों की सफाई का सतत प्रयास करती रही और इन्होंने महामारियों के प्रकोप से बचने के लिए भी बचाव के उपाय किये। इलाहाबाद जिले की भारवाडी टाउन एरिया कमेटियों ने चेचक के टीके लगाने की बड़े पैमाने पर व्यवस्था की। बुलन्दशहर जिले की सभी टाउन एरिया कमेटियों ने गन्दे नालों की सफाई के लिए मेहतरो की व्यवस्था की। पीने के पानी को गन्दगी तथा धूल से बचाने के लिए सभी कुओं की आम सफाई की गयी। सभी टाउन एरिया कमेटियों ने महामारी के प्रकोप एवं फैलाव को रोकने के लिए बचाव सम्बन्धी उपाय किये और दवाएं बंटवायी तथा टीके लगवाने के लिए उत्साहित किए। सभी टाउन एरिया कमेटियों के क्षेत्रों में मलेरिया अधिकारियों ने डी० डी० टी० के छिड़काव की व्यवस्था की। गांधी जयन्ती के अवसर पर पिथौरागढ़ टाउन एरिया कमेटी ने सफाई सप्ताह मनाया और सफाई की हालत को सुधारने के लिये सभी गन्दे नालों और गली-कूचों की सफाई करवायी। सीतापुर जिले की लहरपुर टाउन एरिया कमेटी ने बाल्टिओ और टोकुरियो में पखाना ढोने की परम्परा को बन्द कर दिया और पखाना ढोने के लिए १५ गाडिया खरीदी। बस्ती जिले की मेहदावल टाउन एरिया कमेटी ने डी० डी० टी० के छिड़काव की व्यवस्था की और हैजा, चेचक और प्लेग की महामारी के प्रकोप एवं फैलाव को रोकने के लिये उपाय किये। मैनपुरी जिले की टाउन एरिया कमेटियों ने डी० डी० टी० के छिड़काव की व्यवस्था की और

आम सफाई पर ध्यान दिया। झांसी जिले की एरिच (Erich) टाउन एरिया कमेटी ने कूड़ा-गाड़ी खरीदी तथा हमीरपुर की मौदहा टाउन एरिया कमेटी ने उसी काम के लिए एक ट्रैक्टर खरीदा। सफाई की सामान्य स्थिति को सुधारने के साथ देहरादून की बौहारपुर टाउन एरिया कमेटी ने पशुवध-गृह का निर्माण कराया। रामपुर की नाकुर टाउन एरिया कमेटी ने महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए व्यापक रूप से टीका लगाने के हेतु एक टीका लगाने वाले की नियुक्ति की।

### जल-सप्लाई

टाउन एरिया कमेटियों के क्षेत्रों में जल सप्लाई में मुख्य साधन कुएँ तथा हैंड पाइप ही रहे, क्योंकि इनके सीमित वित्तीय साधनों के कारण इन कमेटियों द्वारा वाटर वर्क्स की सुविधा प्रदान करना कठिन था। जल सप्लाई के क्षेत्र में इन कमेटियों का कार्य सामान्य तथा कुओं की सफाई तक ही सीमित रहा। मिर्जापुर जिले की राबर्ट्सगंज, नैनीताल जिले की टनकपुर और खीरी जिले की खोरी टाउन एरिया कमेटियों की जल सप्लाई योजनाओं को सरकार ने स्वीकृति प्रदान की। हमीरपुर जिले की मौदहा टाउन एरिया कमेटी की जल सप्लाई योजना के लिए सरकार ने १ लाख रुपये का ऋण स्वीकार किया। पिथौरागढ़ टाउन एरिया कमेटी की जल-सप्लाई योजना, जिस पर ३,२४,००० रु० व्यय होने का अनुमान था, को सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी। गाजीपुर जिले की मुहम्मदाबाद टाउन एरिया कमेटी की जल-सप्लाई योजना भी सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी थी जिसके निकट भविष्य में कार्यान्वित होने की आशा थी। सरकार ने बौहारपुर टाउन एरिया के लिए भी एक जल-सप्लाई योजना की स्वीकृति दे दी जहाँ नल कूप द्वारा पानी का वितरण होता था। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए १३,००० रु० स्वीकृत किया गया। फर्रुख टाउन एरिया कमेटी ने हैंड पम्पो की मरम्मत पर २,५०० रु० व्यय किये।

### सड़क पर रोशनी

टाउन एरिया कमेटियों में मिट्टी के तेल के लैंपों द्वारा ही सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था थी। वित्तीय कठिनाइयों के कारण अधिकतर टाउन एरिया कमेटियों के लिए सड़कों पर बिजली की रोशनी की व्यवस्था करना सम्भव न था। जिन कमेटियों ने यह सुविधा दे रखी थी उन्होंने सड़क की रोशनी को ठीक तरह से चालू रखा।

देवरिया जिले के रुद्रपुर टाउन एरिया में बिजली की रोशनी की व्यवस्था हो गयी थी और वर्ष के अन्त में रामपुर टाउन एरिया में बिजली की रोशनी की व्यवस्था की जा रही थी। कानपुर जिले की पुखराया तथा अकबरपुर टाउन एरिया में बिजली की व्यवस्था हो चुकी थी और मुख्य सड़कों पर बिजली की रोशनी दी जा चुकी थी। द्वारा टाउन एरिया कमेटी ने इस अवधि में अपने क्षेत्र के अन्तर्गत बिजली लगाने पर ७,००० रुपये व्यय किये। वाराणसी जिले के गोपीगंज की तथा इटावा जिले के जसवन्तनगर की टाउन एरिया में सड़कों पर और रोशनी की व्यवस्था की गई। रामपुर जिले की विलासपुर टाउन एरिया कमेटी को १३,००० रु० की लागत से बिजली के खम्भे लगाने के लिए सरकार से स्वीकृति मिली। पिथौरागढ़ टाउन एरिया के विद्युतीकरण की योजना स्वीकृति की गयी। मैनपुरी जिले की सियाना टाउन एरिया कमेटी की गलियों की रोशनी की व्यवस्था पर ६,००० रु० व्यय कर रही थी।

### पार्क, उद्यान एवं बच्चों के खेल-कूद के मैदान

टाउन एरिया कमेटियाँ धनाभाव के कारण पार्कों, उद्यानों एवं बच्चों के खेल-कूद के मैदानों के निर्माण में अधिक प्रगति न कर सकी। कानपुर जिले की झीझक टाउन एरिया कमेटी ने गांधी व्यायामशाला के लिए काफी जमीन की व्यवस्था की। नैनीताल जिले की टनकपुर टाउन एरिया कमेटी ने शिविर लगाने के मैदान में खेल एवं मनोरंजन के लिए पार्क बनवाया। टनकपुर

टाउन एरिया कमेटी से ६०,००० रु० की लागत से एक पार्क का निर्माण हो रहा था। इस पार्क में एक जनता पुस्तकालय, गर्मी के लिए भवन, तथा एक फौवारे का निर्माण प्रस्तावित था। रामपुर जिले की टाउन एरिया कमेटी, मिलक (Mil. k) ने एक टाउन हाल बनाने का प्रस्ताव रखा और उससे सम्बन्धित उद्यान लगाना शुरू कर दिया। शाहाबाद टाउन एरिया कमेटी को बच्चों के पार्क के निर्माण के लिए १,००० रुपये स्वीकृत किये गये। टाउन एरिया कमेटी विलासपुर और टांडा ने खेल-कूद केन्द्रों का निर्माण कराया। अल्मोड़ा जिले की बागेश्वर टाउन एरिया कमेटी ने ३,००० रु० की लागत से खेल-कूद के लिए एक पार्क बनवाया और आगामी वर्ष में एक और पार्क बनवाने की योजना थी। पिथौरागढ़ टाउन एरिया कमेटी ने श्रमदान द्वारा ५,००० रु० की लागत का एक पार्क बनवाया। इस पार्क में कुछ खेल की सामग्री की भी व्यवस्था की गयी। मैनपुरी जिले की जसराना और फरहा टाउन एरिया कमेटियों ने बालकों के खेल-कूद के केन्द्रों की स्थापना की और खेल-कूद के सामान की भी व्यवस्था की।

### सार्वजनिक संस्थाओं की सहायता

पिछले वर्षों की भांति टाउन एरिया कमेटियां अपने क्षेत्रों में धर्मादा, शैक्षिक एवं चिकित्सा संस्थाओं की सहायता देती रही। मुजफ्फरनगर जिले की बुधना टाउन एरिया कमेटी ने डी० ए० वी० उच्चतर माध्यमिक स्कूल, बुधना को १०० रुपये स्वीकृत किये। थाना भवन टाउन एरिया कमेटी ने लाजपत राय उच्चतर माध्यमिक स्कूल को २०० रु० का अनुदान स्वीकार किया। वाराणसी जिले की गोपीगंज टाउन एरिया कमेटी ने राम संस्कृत पाठशाला और इस्लामिया स्कूल को क्रमशः १८० रु० तथा १२० रु० की वित्तीय सहायता प्रदान की। इटावा जिले की सभी टाउन एरिया कमेटियों ने अपने क्षेत्रों में अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा संचालित चिकित्सा संस्थाओं की सहायता दी। नैनीताल जिले की टनकपुर टाउन एरिया कमेटी ने नेशनल अस्पताल को ६०० रु० की वित्तीय सहायता प्रदान की और दो उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को १५,००० रु० और ५०० रुपये का सहाय्यता अनुदान स्वीकृत करने का प्रस्ताव किया। झांसी जिले की इरिच टाउन एरिया कमेटी ने एक जूनियर हाई स्कूल एवं प्राइमरी स्कूल भवन के निर्माण के लिये सरकार की स्वीकृति लेकर अन्तरिम जिला परिषद् को १०,००० रु० दिया। साथ ही उसने एक जूनियर रेडक्रास, महारानी लक्ष्मीबाई नेत्र चिकित्सालय और बुन्देलखंड विकास प्रदर्शनी में से प्रत्येक को १०० रु० स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव रखा। रामपुर जिले की मिलक, सौर, विलासपुर और टांडा टाउन एरिया कमेटियों ने नेत्र-सहायता-संस्था को ५०० रु० की वित्तीय सहायता दी। मैनपुरी जिले की टाउन एरिया कमेटियों ने अन्तरिम जिला परिषद् के बहुत से चिकित्सालयों को निम्न सहायता दी—

टाउन एरिया कमेटी				अनुदान रु०
(१) कुरौली	..	..	..	१००
(२) भोगांव	..	..	..	३००
(३) सजराना	..	..	..	२५
(४) करहल	..	..	..	३००

बलन्दशहर जिले की टाउन एरिया कमेटियों ने संक्रामक रोगों के प्रकोप एवं फैलाव को रोकथाम हेतु २०० रु० की वित्तीय सहायता स्वीकृत की। इन टाउन एरिया कमेटियों द्वारा दिये गये अन्य अनुदानों का विवरण निम्न लिखित है :

टाउन एरिया कमेटी	क्लिनिक	पुस्तकालय	चिकित्सालय	स्कूल
(१) गुलौटी	..	..	..	५००
(२) राबूपुरा	..	..	६०	३००

(३) जेवर ..	२०	..	..	५६०
(४) मौन बहादुर नगर ..	१००	..	..	..
(५) छतारी ..	२०	..	..	..
(६) काकोरी ..	..	६०	५०	..
(७) शिकारपुर ..	१००	..	..	१५०
(८) ददरी ..	५०	५०	..	..
(९) पहासू ..	२०	..	२००	..

छतारी और ददरी की टाउन एरिया कमेटी ने नेत्र सहायता कोष में अलग-अलग २५ रु० की वित्तीय सहायता भी दी।

### ७—इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट

गाजियाबाद—मेरठ डिवीजन के आयुक्त की अध्यक्षता में इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, गाजियाबाद २० काम करने लगा, जिसे यू० जुलाई, १९६० से पी० टाउन इम्प्रूवमेन्ट ऐक्ट, १९१६ की धाराओं के अन्तर्गत राज्य सरकार ने बनाया था। दिल्ली के विकास के फलस्वरूप, इस प्रदेश का निकटवर्ती नगर, गाजियाबाद तेजी से विकास करने लगा। आवास एवं औद्योगिक क्षेत्रों के बेतरतीब तथा अनियोजित विकास को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से गाजियाबाद में तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में 'भवन निर्माण विनियम' कानून लागू किया गया तथा १९५६ में एक निर्धारित एवं नियन्त्रणकर्ता प्रशासन की स्थापना की गयी। इस नगर के भवन निर्माण कार्यकलाप तथा विकास रुक न जाय इस हेतु राज्य सरकार ने औद्योगिक एवं आवास सम्बन्धी भूमि की बढ़ती हुई की पूर्ति हेतु भूमि के अधिग्रहण तथा विकास कार्यक्रम भागों को अपने हाथों में लिया।

आलोच्य वर्ष में 'मास्टर प्लान' के अनुसार नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश द्वारा गाजियाबाद के विकास सम्बन्धी बनायी गयी ६ योजनाओं पर ट्रस्ट ने विचार किया। पहली तथा चौथी योजना सम्बन्धी आवश्यक सर्वेक्षण तथा भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी कामों की तैयारी की गयी। सहानी दरवाजे के बाहर की भूमि पर आवास तथा दुकान की मिली-जुली कई मजिल की इमारत बनाने का निश्चय किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजनाबद्धि में ट्रस्ट ने गाजियाबाद नगर पालिका की सीमा के भीतर तथा बाहर ५,००० एकड़ भूमि को अधिग्रहण करने और विकास करने के लिए भी चुना। राज्य सरकार ने ट्रस्ट को कर्मचारियों, सामानों और अन्य कार्यों पर ध्यय करने के लिए १ लाख रुपये का सहायतार्थ अनुदान प्रदान किया और भूमि अधिग्रहण करने तथा विकास करने के लिए २३ लाख का ऋण दिया।

### ८—नगर तथा ग्राम नियोजन

प्रदेश के सरकारी विभागों एवं स्थानीय निकायों को उनके गृह-निर्माण तथा नगर-नियोजन योजनाओं के बनाने तथा उन्हें चालू करने में नगर तथा ग्राम-नियोजन विभाग सहायता प्रदान करता रहा और इसने निम्नलिखित बड़ी तथा छोटी योजनाएं बनायीं :

(१) बड़ी योजनाएं ..	..	..	४
(२) गृह-निर्माण योजनाएं ..	..	..	६२
(३) औद्योगिक आस्थानों की योजनाएं ..	..	..	१६
(४) ग्रामीण विकास योजनाएं ..	..	..	२२८
(५) विविध नियोजन तथा निर्माण सम्बन्धी योजनाएं ..	..	..	२२१

विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य शुरू किये गये :—

(१) नव-निर्मित उत्तराखण्ड के जिलों के नियोजन और तदनुसार भवनों की योजनाओं की तैयारी।

(२) विभिन्न स्थानों पर राज सहायित औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत भवनों के नक्शे तथा डिजाइन की तैयारी।

(३) गन्दी बस्तियों की सफाई योजना के अन्तर्गत प्राप्त किये गये स्थलों की उन्नति सम्बन्धी योजनाएँ।

(४) मास्टर प्लान की तैयारी के लिए गोरखपुर, सहारनपुर और मेरठ का सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण।

(५) रवीन्द्र रंगशाला, लखनऊ का नियोजन एवं निर्माण।

(६) बरेली में खेल-कूद स्टेडियम योजना।

(७) निम्न एवं मध्यम श्रेणी के लोगों की गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत व्यक्तियों एवं स्थानीय निकायों द्वारा तैयार की गयी गृह-निर्माण की स्कीमों की निरीक्षा।

औद्योगिक नगरों के बेतरतीब विकास को नियंत्रित करने में यह विभाग सहायक रहा और उसने नगर एवं ग्राम-नियोजन से सबद्ध बहुत-सी गृह-निर्माण परियोजनाओं और विकास योजनाओं के बारे में भी सलाह दी।

## ६—गृह निर्माण

आलोच्य वर्ष में गृह-निर्माण विभाग बहुत-सी गृह-निर्माण योजनाओं का गचालन करता रहा।

### औद्योगिक गृह-निर्माण योजनाएँ

संपूर्ण देश के औद्योगिक नगरों में आवास की कमी के कारण तथा कम किराया देने की क्षमता के कारण औद्योगिक मजदूरों को जिन जगहों में रहना पड़ता है, उसका ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने प्रथम पंच वर्षीय आयोजना की अवधि में औद्योगिक प्रसार कार्यक्रम के एक अंग के रूप में राज-सहायित औद्योगिक आवास योजना का शीर्षण किया। इस योजना में मजदूरों के लिए आधा ऋण तथा आधी सहायता देकर छोटे-छोटे २ कमरे तथा २ कमरे वाले क्वार्टर के निर्माण की व्यवस्था की गयी। इस योजना के अन्तर्गत निर्मित क्वार्टर औद्योगिक मजदूरों को कम किराये पर देने थे। इस प्रदेश में यह योजना १९५२ में चालू की गयी। पहली तथा दूसरी पंच-वर्षीय योजनाओं में स्वीकृत इस योजना के पहले से छठे चरण तक २५,००० गृहों का कानपुर, लखनऊ, आगरा, फिरोजाबाद, नैनी, रामपुर, हाथरस, गोविंदपुरी, शिकोहाबाद, बरेली, गोरखपुर, मिर्जापुर, वाराणसी में निर्माण हुआ और आलोच्य वर्ष की समाप्ति तक ६४० लाख रुपये व्यय हुए। चालू वर्ष में १,८३० क्वार्टर पूरे किये गये और ६६ ७५ लाख रुपये व्यय हुए। तीसरी आयोजना में ३०० लाख रुपये की लागत से ७,८३० और क्वार्टरों के निर्माण की व्यवस्था की गयी।

### निम्न आय वालों के लिए गृह-निर्माण योजना

आलोच्य वर्ष में राज्य सरकार ने भारत सरकार की निम्न आयीय वर्ग गृह-निर्माण योजना को चालू रखा। इस योजना के अन्तर्गत निम्न आयीय वर्ग के लोगों को आवास गृहों के निर्माण के दीर्घकालीन सस्ते ऋण देने की व्यवस्था की गयी। प्रदेश में यह योजना बड़ी ही लोकप्रिय सिद्ध हुई और इसके अन्तर्गत दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ६,२२६ आवास-गृह निर्मित हुए। कुल ४,४२,५८,७४२ रुपये ऋण के रूप में दिये गये।

आलोच्य वर्ष में स्थानीय निकायो, यू० पी० कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ और विभिन्न शैक्षिक एवं धर्मादा संस्थाओं को गृह-निर्माण के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को ऋण देने के लिये ५१,०३,५६४ रुपये का ऋण दिया गया।

गंदी बस्तियों के हटाने एवं इम्प्रूवमेन्ट की स्कीम—द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में देश के ६ बड़े नगरों—दिल्ली बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद और कानपुर से गन्दी बस्तियों को हटाने के कार्य को शुरू करने के विचार से भारत सरकार ने गन्दी बस्ती हटाने एवं इम्प्रूवमेन्ट की योजना चलायी। इस योजना के अन्तर्गत ६ बड़े नगरों की गन्दी बस्तियों के निवासियों को घर बनवाचे के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गयी जिसमें आधा धन ऋण और आधा सहायता के रूप में था। अन्य स्थानों के लिए ६२ १/२ प्रतिशत ऋण और ३७ १/२ प्रतिशत सहायता के रूप में दिया गया। यह योजना १९५७ में राज्य में चालू की गयी और कानपुर के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य बड़े नगर—लखनऊ, आगरा, वाराणसी और इलाहाबाद इस योजना के अन्तर्गत लाये गये। आलोच्य वर्ष में लखनऊ, कानपुर, और इलाहाबाद की नगर महापालिकाओं को उनकी गन्दी बस्ती हटाने की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ४८५ लाख रुपये ऋण तथा सहायता के रूप में स्वीकृत किये गये। इन नगरों तथा आगरा में १,०५१ क्वार्टर बनाये गये जिनका विवरण निम्नलिखित है :

कानपुर	..	..	..	..	६१२
लखनऊ	..	..	..	..	३४८
इलाहाबाद	..	..	..	..	३४
आगरा	..	..	..	..	७३
					१,०५७

द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में पांच नगरमहापालिकाओं को ऋण एवं सहायता के रूप में कुल १८६ लाख रुपये स्वीकृत किये गये और ४,०३० क्वार्टर बनाये गये। ३१ मार्च, १९६१ तक १,२७५ क्वार्टरों का निर्माण हो रहा था।

कानपुर और आगरा में गन्दी बस्ती सुधार की दो परियोजनाएँ चालू की गयी और दोनों नगर महापालिकाओं में से प्रत्येक को ५ लाख रुपये का ऋण दिया गया। इस अवधि में इन परियोजनाओं का सुधार कार्य शुरू किया गया और ३१ मार्च, १९६१ तक कानपुर और आगरा नगरपालिकाएं क्रमशः २५,४८५ रु० और २,५०,६३२ रुपये व्यय कर चुकी थी।

गन्दी बस्तियों के हटाने की योजना के अमल में आने पर ज्ञात हुआ कि गन्दी बस्तियों का अधिग्रहण बड़ा संहगा है—विशेषकर बड़े नगरों के भीतर। साथ ही गन्दी बस्तियों को जल्दी हटाने के लिए वर्तमान अधिग्रहण विधि अत्यन्त असुविधाजनक है। ऐसी बस्तियों के अधिग्रहण करने की विधि में तेजी लाने और मुवाविजा की नीची रकम दर तय करने के लिए विधान सभा में यू० पी० गन्दी बस्ती (हटाने एवं सुधार) विधेयक, १९६० पेश किया गया। प्रस्तावित कानून में गन्दी बस्तियों के हटाने तथा सुधार करने के लिए समर्थ अधिकारी के लिए 'समरी पावर' का प्राविधान किया गया। यह विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सम्यक परीक्षण हेतु भेज दिया गया।

ग्रामीण गृह-निर्माण परियोजनाएं—गांवों के समन्वित विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गांव गृह-निर्माण परियोजनाओं के सिलसिले में ग्रामीण क्षेत्रों में आवास गृहों के निर्माण एवं सुधार के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गयी। यह योजना सामुदायिक विकास खंडों के चुने हुए गांवों में केंद्रित की गयी। सब मिलाकर अब तक ५८० गांव चुने गये और



३१८ गावों में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण पूरा किया गया। ५०३ गावों के मास्टर प्लान भी तैयार कर लिये गये थे।

आलोच्य वर्ष में १८२ गाव चुने गये। इनमें से अधिकतर गावों तथा १६५६-६० में चुने गये गावों के सामाजिक, आर्थिक एवं शारीरिक सर्वेक्षण पूरे कर लिये गये और मास्टर प्लान भी बना लिये गये। १,८१८ गृहों के निर्माण के लिए ११,०१,१७० रु० की धनराशि वितरित की गयी जिसमें से ४८६ आवास गृह पूरे किये और शेष का निर्माण जारी था। इस प्रकार दूसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में ३,६६८ गृहों के निर्माण के लिए ३१.६७ लाख रु० की कुल धनराशि वितरित की गयी, जिसमें ५८५ गृह बन चुके हैं और शेष या तो बन रहे हैं या उन पर काम लगा है।

**भूमि अधिग्रहण एवं विकास योजना**—भारत सरकार द्वारा १६५६-६० की अवधि में भूमि अधिग्रहण एवं विकास योजना का श्रीगणेश किया गया। इस योजना का उद्देश्य गृह-निर्माण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भूमि का अधिग्रहण एवं विकास करना था। इस योजना को भारत सरकार से प्राप्त ऋण की सहायता से चलाया जा रहा था। राज्य सरकार ने विविध गृह-निर्माण योजनाओं के कार्यान्वयन के सिलसिले में काफी भूमि अधिग्रहण कर तथा उसके विकास के लिए स्थानीय निकायों को ऋणों का वितरण किया।

आलोच्य वर्ष में कानपुर, इलाहाबाद और लखनऊ की नगर महापालिकाओं तथा गाजियाबाद के इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को ४७ २० लाख रुपये का ऋण दिया गया। इस प्रकार दूसरी पंचवर्षीय योजनावधि में इस योजना के लिए ५७ २० लाख रुपये की धनराशि दी गयी। गाजियाबाद में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण करने और उसके विकास करने की योजना चलायी गयी और कानपुर के काकादेव क्षेत्र में भूमि विकास का काफी काम किया गया।

**मध्यम वर्ग आयीय गृह-निर्माण योजना**—मध्यम वर्ग आयीय गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत ६,००० रु० से १५,००० रु० वार्षिक आय वालों मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के लिए दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था थी, जिसका श्रीगणेश राज्य में १६५८-५६ की अवधि में किया गया था। आलोच्य वर्ष में उपयुक्त व्यक्तियों के गृह-निर्माण के लिये ऋण देने हेतु यू० पी० क्रोअपरेटिव बैंक, लिमिटेड और अनेक स्थानीय संस्थाओं को ३० लाख रुपये का ऋण दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत दूसरी पंचवर्षीय आयोजनावधि में १०१ लाख रुपये की धनराशि ऋण रूप में दी गयी।

## १०—स्वशासन इजीनियरिंग

**नगरों की जल-सप्लाई एवं गन्दे पानी की निकासी**—दूसरी पंचवर्षीय आयोजना के लिए निर्धारित जल-सप्लाई तथा गन्दे पानी की निकासी की योजनाओं के कार्यों की पूर्ति पर विशेष बल दिया गया। सम्बन्धित स्थानीय निकायों के अलावा कानपुर नगरमहापालिका को इन कार्यों के लिए कुल १५२ लाख रुपये का ऋण दिया गया। वर्तमान जल-सप्लाई तथा गन्दे पानी की निकासी के कार्यों के प्रसार एवं पुनर्संगठन के कार्य के साथ-साथ इस धनराशि से (बाराबंकी, गोण्डा, राय बरेली, सुल्तानपुर, महोबा, बहेड़ी, चुनार, शिकोहाबाद, बड़ौत, लखीमपुर खीरी, कालपी, कौच, टनकपुर, पुरानी बस्ती, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, शामली, भदोही, बिन्दकी, पोखरायाँ, अहरोरा, मऊरानीपुर, अतरौली, सिकन्दरा राओ, चौहारपुर, कांथला) की २७ नयी जल-सप्लाई योजनाएँ और मोवाना तथा गोरखपुर की दो गन्दे पानी की निकासी की योजनाएँ चालू की गयीं।

बाराबंकी, गोण्डा, राय बरेली, सुल्तानपुर, महोबा, बहेड़ी, चुनार, शिकोहाबाद, बड़ौत, लखीमपुर खीरी, कालपी, अमरोहा और शामली में नये वाटर वर्क्स बन कर तैयार हो गये।

इस प्रकार अब तक कुल ८६ बाटर वर्क्स तथा २७ गन्दे पानी की निकासी के कार्य पूरे किये गये।  
अवशेष कार्यों के पूरा होने में और समय लगने की संभावना थी।

**ग्रामीण जल-सप्लाई**—अलोच्य वर्ष में देहरादून जिले की कोलागढ़ की जल सप्लाई के, नये कार्य के अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में जल सप्लाई के सिलसिले में देहरादून जिले के ४० गांवों, बादा जिले के पाथा क्षेत्र के ६० गांवों, उन्नाव जिले के २० गांवों, गढ़वाल भाबर गवर्नमेन्ट इस्टेट में हाल्द्व खाता सर्किल के १७ गांवों और जल-सप्लाई तथा सफाई योजना के अन्तर्गत लखनऊ जिले के चिनहट विकास खण्ड के १६ गांवों और मेरठ जिले के मेरठ विकास खण्ड के १२ गांवों में ५,३४,७६० रुपये की लागत से कार्य हो रहा था।

इस अवधि में देव प्रयाग तथा देहरी की जल सप्लाई परियोजनाओं का कार्य चालू था।

**मत्त-मूत्र उपयोग योजना**—इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, हरद्वार, आगरा और देहरादून में मल-मूल उपयोग योजना के अन्तर्गत कार्य जारी था जिसे गत वर्ष 'अधिक अन्न उपजाओ' अभियान के सिलसिले में शुरू किया गया था अलोच्य वर्ष में इन योजनाओं के लिए ७.६ लाख रुपये तक की धनराशि स्वीकृत की गयी थी।

**सीमान्त क्षेत्रों में जल-सप्लाई**—नवनिर्मित स्वशासन इंजीनियरिंग विभाग के चमोली डिवीजन ने पिथौरागढ़, गोपेश्वर, उत्तरकाशी, और चमोली में जल-सप्लाई की योजनाएं (२,८७,००० रु० और २,७३,६७१ रु० की लागत) से शुरू की गयीं और कार्य चालू था।

तीसरी पाली के एवज में, जिसकी नितान्त आवश्यकता समझी गयी, एक माहिना शाखा राजकीय मुद्रणालय में प्रयोग के रूप में चालू की गयी, जिसका कार्य सतोषजनक रहा। यह शाखा, जो पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास के लिये खोली गयी थी, बहुत बड़ी सख्या में फाइल बोर्ड, लिफाफे आदि बनाने में सहायक हुई। यह काम कम खर्च में तथा समय के भीतर पूरा किया गया।

अपरेटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के अन्तर्गत सरकारी मुद्रणालयों में लोगों को विभिन्न क्राफ्टों में प्राविधिक प्रशिक्षण देने का कार्य जारी रहा। नार्दर्न रोजनल स्कूल आफ प्रिंटिंग टेक्नोलोजी के अन्तिम वर्ष कई प्लान्ट की ट्रेनिंग भी दी गयी। कुछ सफल छात्रों को रोजगार भी दिया गया।

विद्युत् शक्ति की सप्लाई पर व्यय को कम करने की दृष्टि से ३० सी० को १० सी० विद्युत् शक्ति को बदलने की एक योजना चलायी गयी और उस पर कुछ अमल भी हुआ। रोटेशन शक्ति को हाई टेंशन शक्ति में परिवर्तित किया गया और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ट्रांसफार्मर लगाया गया।

बाहर से आने वाले तथा बाहर जाने वाले मालों के लिए अब तक कोई पर्याप्त शेड की व्यवस्था न थी, इसलिए एक शेड बनाया गया। लखनऊ में स्थित सभी सरकारी विभागों को लेखन सामग्री की सप्लाई की सुविधा देने के लिए नवीन राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ में एक लेखन-सामग्री का डिपो खोला गया। इसके फलस्वरूप रेलवे चार्जों (फेट) में काफी बड़ी बचत की आशा की गयी।

जगह की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने एक अलग मशीन का कमरा, मेकेनिकल कम्पोजिंग का, एक ब्लाक, कागज का गोदाम, कागज और माल, रद्दी कागज और सरकारी गाड़ियों कारखाने के लिए शेडों के निर्माण के लिए स्वीकृति दी। सरकार लखनऊ के मुद्रणालय के लिए तथा इलाहाबाद के प्रमुख मुद्रणालय के निम्नतम कर्मचारियों तथा वाच एवं वार्ड के लिए कुछ क्वार्टरों की व्यवस्था की और पुराने क्वार्टरों की बड़े पैमाने पर मरम्मत करने की स्वीकृति दी।

अधिक स्थायी पदों की व्यवस्था करने के सरकारी निर्णय से ५ साल में अधिक काल की नौकरियों वाले कर्मचारियों को लाभ हुआ।

आलोच्य वर्ष में प्रबन्धकर्ताओं और श्रमिकों के आपसी सवध में और सुधार हुआ।

### ३—सरकारी वर्कशाप

४७.५० लाख रुपये के काम के भार के साथ वित्तीय वर्ष १९६०-६१ प्रारम्भ हुआ। इस अवधि में ४३.४७ लाख रुपये की कीमत के आर्डर प्राप्त किये गये। इस प्रकार वर्कशाप द्वारा किये गये कुल काम की ६०.६७ लाख रुपये हो गयी। सिंचाई की विभिन्न वर्कशापों, रुड़की मेरठ, बरेली, और झांसी, ने वर्ष भर में ५०.०० लाख की कीमत का काम किया। इस प्रकार १९६१-६२ के लिए ४०.६७ लाख रुपये की कीमत का काम बच रहा। इन आर्डरों में मुख्यतया सरकारी विभाग, अन्य प्रदेशों और रेलवे के आर्डरों का काम किया गया। इनका विवरण निम्नलिखित है—

				लाख रुपयों में
१—सिंचाई विभाग	..	..	..	२१.७५
२—विद्युत् विभाग	..	..	..	०.७६
३—सार्वजनिक निर्माण (भवन एवं सड़कें)	..	..	..	६.१२
४—नियोजन विभाग	..	..	..	२.६१

	लाख रुपयों में
५—रेलवे तथा डाइरेक्टर जनरल ग्राफ सप्लाय तथा डिस्पोजल्स	६.६८
६—स्वशासन इंजीनियरिंग विभाग .. ..	०.६४
७—अन्य प्रदेश .. ..	१.८४
८—विविध विभाग .. ..	३.००

इस वर्ष में जो मुख्य काम किये गये उनके विवरण निम्न प्रकार थे :—

१—बहुत-सी सिचाई परियोजनाओं के लिए उठाने के यंत्रों सहित बाढ और स्लूइस दर-वाजो, नलकूपों की फिटिंग के सामान, मोटरो और पम्पो के फुटकर धुर्जे, सूराख करने के यंत्र और टेकेल्स आदि माताटीला बांध के लिए ब्लक हेड गेट्स तथा रिहन्द बाध के लिए ट्रैश रैक्स ।

२—सब-स्टेशनों की फोर्सिंग, ट्रांसमिशन टावर, हाइडल फिटिंग और संबंधित यंत्र ।

३—सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए १२० फुट से २२५ फुट तक के एक स्पेन वाले स्पात के पुल तथा पीपे के पुल ।

४—गाडियो और डिब्बों, पानी के जम्बो, सिगनल के खम्भो, एम० एस० स्टेजिंग्स, सिगनलों के लिए पाइंट रॉडिंग, स्टीय ब्रेक वाल्व, ग्रसेम्बली और परिवर्तित इंजिनो द्वारा खींचने का तरीका ।

५—मिट्टी तोड़ने वाली मशीन के पुर्जों का निर्माण, भारी और हल्की फेरस एण्ड नान फेरस कास्टिंग ।

#### ४—श्री बदरीनाथ और श्री केदारनाथ मन्दिर

श्री बदरीनाथ और श्री केदारनाथ समूह के मंदिरों का प्रशासन श्री बदरीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा किया जाता रहा । आलोच्य वर्ष में श्री बदरीनाथ मंदिर के पवित्र मठ के दर्शनार्थ ८१,८६४ यात्री और केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए ६३,००० यात्री गये । इन मठों के दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों को सुविधा उपलब्ध करने के प्रयास जारी रहे । एक सफाई इन्स्पेक्टर के अधीन मेहतरों का एक दल पूरी अवधि के लिए सफाई का उचित प्रबन्ध करने हेतु रखा गया । समिति के सामने बदरीनाथ और केदारनाथ के लिए पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने की एक योजना थी । बदरीनाथ और केदारनाथ के रास्ते में प्रसिद्ध तीर्थस्थलों में भी इस योजना का प्रसार करना था । जोशीमठ और बदरीनाथ में समिति के कतिपय विश्राम-गृहों में सैण्टिक टैंक टाइप लैंड्रिनो का निर्माण किया गया । बदरीनाथ और गुप्तकाशी में सभी सामानों से सुसज्जित एक एक औषधालय भी थे । इस अवधि में बहुत से बीमार तीर्थयात्रियों और अन्य रोगों का उपचार किया गया ।

सामान्य शिक्षा एवं धार्मिक उपदेश—आलोच्य वर्ष में जोशीमठ में चल रहे श्री बदरीनाथ वेद-वेदांग महाविद्यालय का तीसरा साल था । इस वर्ष में इस महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वालों की कुल संख्या ७० थी । इस समिति ने संस्कृत एवं आयुर्वेदिक शिक्षा के प्रचार के लिए विभिन्न स्कूलों में अध्ययन करने वाले योग्य छात्रों में ३,७७८.६५ रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की । संस्कृत की शिक्षा देने वाली बहुत-सी संस्थाओं को ३,२४० रुपये का अनुदान उपलब्ध किया गया ।

ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी की एक योजना के अनुसार श्री बदरीनाथ और श्री केदारनाथ पवित्र मठों के दर्शनार्थ आये हुए गरीबों और साधुओं को निशुल्क भोजन और बीमार तथा अपाहिज लूले-लगडे यात्रियों को ले जाने के लिए गढ़वाल सदाबर्त फंड के अधिकांश राजस्व का उपयोग किया गया जो इस समिति के प्रबन्ध एवं प्रशासन में था ।

## ५—मेला

प्रयाग का १९६०-६१ का माघ मेला एक साधारण मेला था। (कुंभ या अर्धकुंभ के बाढ़ पड़ने वाला माघ मेला बहुधा छोटा होता है।) सरकार ने मेला के लिए आवश्यक प्रबन्ध किये। गंगा के दाहिने किनारे पर भूखि की कमी के कारण मेला अरैल तथा झंसी की तरफ लगा। यात्रियों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की सुविधा प्रदान करने के लिए पोरे का पुल बनाया गया और नदी के किनारे की और कटाव से बचाने के लिए भी आवश्यक व्यवस्था की गयी। यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए और बहुत से प्रबन्ध किये गये। मेला के सामान्य प्रशासन के लिए १,५३,६०० रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गयी।

## ६—पर्यटन

इस अवधि में पर्यटन के सिलसिले में ३५० लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गयी। पर्यटन संबंधी कार्य-कलापो का दो वर्गों में विभाजन किया गया—(१) राज्य में वर्तमान पर्यटन स्थलों का प्रचार और उन स्थलों तक जाने की उपलब्ध सुविधाएँ (२) इन सुविधाओं में वृद्धि।

मथुरा, हरद्वार, मिर्जापुर और चित्रकूट गे में निम्न प्राथीय वर्ग के लिए होटलों के निर्माण तथा श्री कंदारनाथ के रास्ते में यात्रियों के ठहरने के लिए शेडों के निर्माण के प्रस्ताव विचाराधीन थे।

## ७—चिड़ियाघर

जंगली पशुओं और पक्षियों को उनकी स्वाभाविक अवस्थाओं में प्रदर्शित करना चिड़ियाघर, लखनऊ का एक महत्वपूर्ण कार्य रहा। वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक मूल्य के अतिरिक्त इस संस्था ने बच्चों तथा सामान्य जनता के स्वस्थ मनोरंजन के लिए सुविधा प्रदान की। अक्टूबर, १९६० की बाढ़ से क्षतिग्रस्त भवनों की भरसमत के लिए सरकार ने १ लाख रुपये की धनराशि स्वीकृति की। आलोच्य वर्ष में पशुओं के समूह में एक उल्लेखनीय वृद्धि हुई और वह थी अफ्रीका के एक शेर के जोड़े की। कुछ दुर्लभ पक्षियों ने चिड़ियाघर के आकर्षण में वृद्धि की। इमारतों के संबंध में बहुत से सुधार हुए। शेर के लिए एक नया कटघरा, कार्यालय-भवन और नौकरों के क्वार्टरों का निर्माण किया गया। वैज्ञानिक अनुसंधानों की प्रयोगशाला के केन्द्र और वन्य पशुओं के वारे में नवीनतम ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए एक पुस्तकालय की भी व्यवस्था की गयी।

चिड़ियाघर के बगीचों में पानी की सप्लाई और बढ़ाने के लिए कदम उठाये गये। चिड़ियाघर की बेकार जमीन को सींचने तथा हिरनों के लिए हरे चारों की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार ने दो वर्तमान कुंओं में पम्पिंग मोटर लगाने के लिए ८,००० रु० के अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था की है।

राज्य स्वास्थ्य बोर्ड ने घास के मैदानों (लानों) में फिर से घास उगाने और बोने के लिए ४,००० रुपये स्वीकृत किये। यह कार्य चल रहा था और शीघ्र ही पूरे किये जाने की आशा थी।

चिड़ियाघर के दर्शनार्थियों की संख्या में अक्टूबर, १९६० की बाढ़ के कारण कमी हुई थी, क्योंकि यह लगभग तीन सप्ताह बन्द रहा। इस अवधि में चिड़ियाघर देखने वालों की संख्या ४,५७,४०० थी।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १७ जनरल (पब०)— १९६३—१,२५० । (हि०)

## विषय-सूची

### अध्याय १—सामान्य प्रशासन

	पृष्ठ-संख्या
१—उत्तर प्रदेश सरकार .. .. .	१
२—प्रशासकीय कार्य .. .. .	२

### अध्याय २—भूमि-प्रशासन

१—जमींदारी विनाश और भूमि-सुधार .. .. .	६
२—सर्वेक्षण, बन्दोबस्त तथा भूमि अभिलेख कार्य .. .. .	११
३—भूमि-अभिलेखन .. .. .	१३
४—काश्तकारी क्षेत्र .. .. .	१४
५—राजकीय आस्थान .. .. .	१५

### अध्याय ३—शांति एवं व्यवस्था

१—पुलिस .. .. .	१७
२—सार्वजनिक जुआ अधिनियम आदि .. .. .	२४
३—बंदी गृह .. .. .	२४

### अध्याय ४—विधि निर्माण

१—विधि निर्माण का क्रम .. .. .	२६
--------------------------------	----

### अध्याय ५—न्याय प्रशासन

१—अदालतें .. .. .	३१
२—दीवानी न्याय .. .. .	३१
(क) उच्च न्यायालय .. .. .	३१
(ख) दीवानी अदालतें .. .. .	३२
३—फौजदारी न्याय व्यवस्था .. .. .	३७
४—माल की अदालतें .. .. .	४०
५—रजिस्ट्रेशन .. .. .	४१
६—लीगल रिमेम्बरेंसर की शाखा .. .. .	४२
७—उत्तर प्रदेश के महा प्रशासक और शासकीय न्यायधारी कार्यालय .. .. .	४२

### अध्याय ६—स्वायत्त शासन

१—पंचायतें .. .. .	४४
२—अतरिम जिला परिषद् .. .. .	४६
३—नगर महापालिकाएं .. .. .	४७
४—नगर पालिकाएं .. .. .	४६
५—टाउन एरिया .. .. .	५०
६—नोटिफाइड एरिया .. .. .	५१

### अध्याय ७—सार्वजनिक राजस्व और वित्त

पृष्ठ-संख्या

१—केंद्रीय राजस्व	..	..	.	५२
२—राज्य का राजस्व	..	.	.	५२
३—भूमि राजस्व, नहर वकाया आदि की बट्टी	..	.	.	५५
४—वृहद्-जोतकर	.	.	.	५७
५—स्टाम्प		..	..	५८
६—आबकारी	..	..		५८
७—बिक्री-कर	..	..	.	५९
८—मनोरजन और बाजीकर	..	..	..	६०

### अध्याय ८—राजनीतिक

१—चुनाव	..	..	..	६१
२—राजनीतिक कार्य-कलाप	..	..		६३

### अध्याय ९—समाचार-पत्र

टिप्पणी—इस खंड में सम्मिलित किये गये विवरण सामान्यतः १९६०-६१ से सम्बन्धित है। जहाँ विशेष कारणों से वित्तीय वर्ष से संबंधित आंकड़े देना सम्भव नहीं हो सका, वहाँ विवरण की अवधि पाद-टिप्पणी के रूप में जोड़ दिया गया है।

# उत्तर प्रदेश राज्य की वार्षिक रिपोर्ट,

१९६०-६१

खण्ड २

अध्याय १

सामान्य प्रशासन

उत्तर प्रदेश सरकार

श्री घराहगिरि बैकट गिरि के पश्चात् १ जुलाई, १९६० से डा० ब्रह्मगुल रामकृष्ण राव ने राज्यपाल का पदभार सम्भाला।

वर्ष के आरम्भ में राज्य-मन्त्रियों सहित मन्त्रियों की कुल संख्या १० थी। डा० सम्पूर्णानन्द के कांग्रेस विधान मंडलीय दल के नेतृत्व से पद-त्याग कर देने के उपरान्त राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष श्री चन्द्रभानु गुप्त निर्विरोध कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता चुने गये। डा० सम्पूर्णानन्द के मुख्य-मन्त्रित्व में संचालित शासन ने ७ दिसम्बर, १९६० को पद-त्याग कर दिया और उसी दिन श्री चन्द्रभानु गुप्त के मुख्य-मन्त्रित्व में नयी सरकार बनी। उसी दिन मुख्य मन्त्री, मन्त्रि-मंडल के तीन अन्य मन्त्री, ५ राज्य-मन्त्री तथा ४ उप-मन्त्रियों ने अपने पद की शपथ ग्रहण की। कुछ दिनों के अनन्तर श्रीमती सुचेता कृपालानी ने मन्त्रि-मंडल के मन्त्री के रूप में अपने पद की शपथ ग्रहण की। २६ जनवरी, १९६१ को श्री हरगोविन्द सिंह मन्त्रि-मंडल के सदस्य नियुक्त हुये। उसी दिन श्री अलगूराय शास्त्री की नियुक्ति राज्य-मन्त्री के रूप में हुई। उसके कुछ ही दिनों के बाद श्री गिरधारी लाल की नियुक्ति मन्त्री के रूप में हुई। वर्ष के अन्त में उत्तर प्रदेश मन्त्रि-मंडल के सदस्यों और उनके विभागों की नामावली नीचे प्रस्तुत है—

## मन्त्री

नाम	विभाग
(१) श्री चन्द्र भानु गुप्त	.. मुख्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन, नियोजन, उद्योग, विद्युत, सूचना, खाद्य एवं पूर्ति, स्वास्थ्य और हरिजन कल्याण।
(२) श्री हुकुम सिंह बिसेन	.. न्याय, राजस्व और सहायता एवं पुनर्वास।
(३) श्री चरण सिंह	.. गृह एवं कृषि।
(४) आचार्य जुगल किशोर	.. शिक्षा एवं समाज कल्याण।
(५) श्रीमती सुचेता कृपालानी	.. सामुदायिक परियोजनाएं, ग्राम एवं लघु उद्योग तथा श्रम।
(६) श्री हरगोविन्द सिंह	.. वित्त।
(७) श्री गिरधारी लाल	.. सार्वजनिक निर्माण।



## राज्य-मंत्री

नाम	विभाग
(१) श्री मंगला प्रसाद	.. महाकारिता एवं संसदीय मामले ।
(२) श्री मुजिफर हसन	.. यातायात ।
(३) श्री राममूर्ति	.. सिचाई ।
(४) श्री सीताराम	.. आबकारी ।
(५) श्री कैलाश प्रकाश	.. स्वायत्त शासन ।
(६) श्री अलगूराय शास्त्री	.. अर्थ एवं सांख्यिकी तथा वन ।

७ दिसम्बर, १९६० को डा० जवाहर लाल रोहतगी, श्री रऊफ जाफरी, श्री शांति प्रपन्न शर्मा तथा श्रीमती प्रकाशवती सूद की उपमन्त्री के पदों पर नियुक्ति हुई । २६ जनवरी, १९६१ को सर्वश्री रामस्वरूप यादव, बसी नकवी, धरमसिंह तथा उदय शंकर दुबे उपमन्त्री नियुक्त किये गये । उसी दिन श्री कृपाशंकर अवैतनिक ससदीय सचिव नियुक्त हुए । डा० रामनारायण पांडे पहले ही १६ जनवरी, १९६१ को अवैतनिक ससदीय सचिव नियुक्त किये जा चुके थे ।

वर्ष के अन्त में निम्नलिखित उपमन्त्री तथा अवैतनिक ससदीय सचिव अपने पदों पर कार्य कर रहे थे—

## उपमन्त्री

नाम	जिस मन्त्री के साथ सम्बद्ध थे
(१) डा० जवाहर लाल रोहतगी	मुख्य मन्त्री ।
(२) श्री रऊफ जाफरी	.. मुख्य मन्त्री ।
(३) श्री शांति प्रपन्न शर्मा	.. मुख्य मन्त्री तथा ससदीय मामलों के राज्य मन्त्री
(४) श्रीमती प्रकाशवती सूद	.. शिक्षा मन्त्री ।
(५) श्री रामस्वरूप यादव	.. शिक्षा मन्त्री ।
(६) श्री बसी नकवी	.. श्रम मन्त्री ।
(७) श्री धरमसिंह	.. मुख्य मन्त्री ।
(८) श्री उदयशंकर दुबे	.. राजस्व मन्त्री ।

## अवैतनिक संसदीय सचिव

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| (१) डा० रामनारायण पांडेय | मुख्य मन्त्री ।               |
| (२) श्री कृपाशंकर        | .. यातायात के राज्य मन्त्री । |

## २—प्रशासकीय कार्य

## कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण

न्यायपालिका से कार्यपालिका को पृथक् करने सम्बन्धी घोषित नीति से सम्बद्ध योजना को १४ और जिलों में प्रसारित किया गया । यह योजना राज्य के २० जिलों में पहले से ही

धेच रही थी। दूसरे वर्ष इस योजना को शेष जिलों में, जिनमें पहाड़ के ७ जिले भी शामिल थे, परिचालित किया जाता था।

### भारतीय प्रशासन सेवा

तृतीय पंच-वर्षीय आयोजना के आरम्भ के फलस्वरूप बड़े हुये चतुर्दिक कार्यकलाप के लिए राज्य द्वारा और अधिक अधिकारियों की माग पूरी करने के लिए इस वर्ष भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए निर्धारित भारतीय प्रशासन सेवा श्रेणी के अधिकारियों की संख्या को २४१ से बढ़ाकर २४६ कर दी।

### नये विभागों का सृजन

शासन के कार्यों में वृद्धि होने के फलस्वरूप सचिवालय के कार्यों में भी विशेषनाम नियोजन, खाद्य एवं पूर्ति, सहायता, यातायात तथा चिकित्सा शाखाओं में काम बढ़ा। इस बड़े हुये काम को पूरा करने के लिए इन शाखाओं में से प्रत्येक में एक-एक नये विभाग का सृजन किया गया। इनके अतिरिक्त उत्तराखण्ड डिवीजन के विकास कार्य की देख-रेख के लिए एक नया विभाग भी खोला गया।

### संगठन एवं कार्य-प्रणाली शाखा

अप्रैल, १९६० में संगठन एवं कार्य-प्रणाली शाखा खोली गयी जिसमें संगठन एवं दफ्तरो में कार्य-प्रणाली के निर्धारण कार्य को पूरे समय करने के लिये तीन अधिकारियों की नियुक्ति की गई। उप-सचिव तथा अनु-सचिव के एक-एक पद ऐसे थे, जो पहले ही से सचिवालय में चले आ रहे हैं। इस सम्बन्ध में उनका उपयोग किया गया और दो० पी० सी० एस० अफसरों की नियुक्ति की गयी। उपसचिव तथा अनुसचिव को क्रमशः संगठन एवं कार्य प्रणाली शाखा के उप-निदेशक तथा सहायक निदेशक का नाम भी दिया गया। सहायक निदेशक के एक पद का सृजन किया गया और उत्तर प्रदेशीय वित्त एवं लेखा सेवा का एक अधिकारी उस पर लगाया गया। यह निश्चय किया गया कि कार्यालय निरीक्षणालय से ४ निरीक्षकों को इन अधिकारियों के कार्य में सहायता देने के लिए माग लिया जाय। आरम्भ में तीन कार्यालय निरीक्षकों को संगठन एवं कार्यप्रणाली शाखा के साथ सरकार के वित्त मन्त्रालय के दिल्ली स्थिति विशेष पुनर्गठन टोली के पास अल्पकालिन प्ररिक्षण के लिए तैनात कर दिया गया। बाद को यह निश्चय किया गया कि इन कार्यालय निरीक्षकों के स्थान पर उसी बतन-क्रम में संगठन एवं कार्य-प्रणाली शाखा अधिकारियों की नियुक्ति की जाय और सचिवालय के सहायक अधीक्षकों में से ही यह नियुक्ति उस समय की जाय जब कि कोई निरीक्षक अवकाश प्राप्त करे। आलोच्य वर्ष में एक संगठन एवं कार्य-प्रणाली अधिकारी नियुक्त किया गया और दो कार्यालय निरीक्षक शाखा में कार्य करते रहे।

संगठन एवं कार्य-प्रणाली शाखा ने कार्य-अध्ययन की प्रणाली अपनायी। यही प्रणाली सफलतापूर्वक कई अन्य देशों तथा भारत सरकार की विशेष पुनर्गठन टोली द्वारा अपनायी गयी थी। यह निश्चय किया गया कि सचिवालय कार्य-अध्ययन सर्वप्रथम शाखा के बाद शाखा का और विभाग के बाद विभाग का आरम्भ किया जाय। इसका आरम्भ सर्वप्रथम मुख्य सचिव शाखा और गृह-सचिव शाखा से हुआ। इलाहाबाद स्थित कार्यालय निरीक्षणालय के सहयोग से लोक सेवा आयोग के कार्यालय का कार्य अध्ययन भी आरम्भ किया गया।

### कार्यालयों का निरीक्षण

कार्यालयों के निरीक्षणालय के दफ्तरो के काम के तरीकों को आसान बनाने तथा अनावश्यक कार्यों को समाप्त करने की ओर मुख्य रूप से ध्यान दिया। लम्बी-लम्बी निरीक्षण टिप्पणियां न लिख करके केवल मुख्य बातों पर ही जोर दिया गया। कार्यालय के निरीक्षकों ने यथासम्भव उन कार्यालयों के कर्मचारियों को सहायता देने का प्रयास किया।

कुल १,०१५ कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षणालय द्वारा कर्मचारियों से सम्बद्ध उन ६८ मामलों की जांच की गयी, जो उन्हें सौंपे गये थे। इसके अतिरिक्त संगठन एवं कार्यप्रणाली शाखा द्वारा लोक-सेवा आयोग के कार्यालयों के कार्याध्ययन में भी सहयोग दिया गया। जांच के लिए जो ६८ मामले उसे सौंपे गये थे, उनमें से ८६ के विषय में रिपोर्टें पूरी कर ली गयीं।

कार्यालयों के मुख्य निरीक्षक तथा तीन निरीक्षक कार्याध्ययन के तकनीक में ६ हफ्ते के प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय की विशेष पुनर्गठन टोली के पास भेजे गये थे। विभागीय कार्यालयों के निरीक्षण के सम्बन्ध में निरीक्षणालय को अब संगठन एवं कार्य प्रणाली का ढंग अपनाना था। चतुर्दिक निरीक्षण की एक प्रणाली आरम्भ की गयी और प्रत्येक विभाग के लिए निरीक्षणालय द्वारा उसी के अनुसार कार्य होना था। यह विचार किया गया कि इस प्रणाली के अन्तर्गत निरीक्षकों का एक दल एक साथ ही एक विभाग के कई कार्यालयों का सभी स्तरों पर निरीक्षण आरम्भ करेगा और यह सामान्य निरीक्षण न होगा वरन् इनके सिलसिले में गठन एवं आकार से सम्बद्ध मामलों का भी विस्तार से निरीक्षण होगा। उल्लिखित प्रणाली से शिक्षा एवं यातायात विभागों का चतुर्दिक निरीक्षण आलोच्य वर्ष में पूरा किया गया।

### लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश

पिछले कुछ वर्षों से लोकसेवा आयोग का कार्य बहुत बढ़ गया था, अतः आयोग के कार्यालय में बड़े हुए काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी थी। आयोग के कार्यालय में स्थान की कमी का अनुभव किया जा रहा था और नये भवन के निर्माण अथवा अतिरिक्त स्थान की किसी अन्य व्यवस्था के विषय में विचार किया जा रहा था। आयोग के कर्मचारियों के लिए दो आवासों का निर्माण भी किया गया और तीसरे का निर्माण हो रहा था।

### परिवार नियोजन के सिलसिले निर्वीजीकरण हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश

परिवार नियोजन के अन्तर्गत निर्वीजीकरण कराने वाले सरकारी कर्मचारियों को शासन के पहले के निश्चय अनुसार मिलने वाली कार्य के ६ दिनों तक के विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा अब राज्य के औद्योगिक कर्मचारियों को भी दे दी गयी।

### जाड़े में कुमायूँ डिवीजन के कार्यालयों में लकड़ी के कोयले की व्यवस्था

देहरादून जिले के पहाड़ी क्षेत्रों तथा कुमायूँ डिवीजन में स्थित सरकारी दफ्तरों में कार्य के दिनों में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के प्रयोग के लिए लकड़ी का कोयला देने का आदेश दे दिया गया था। यह व्यवस्था वहाँ भी कर दी गयी, जहाँ जाड़े के महीनों में अगोठी की व्यवस्था आवश्यक समझी गयी (१५ नवम्बर से १५ मार्च तक की अवधि में)। यह आदेश उत्तराखण्ड डिवीजन में काम करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए भी आवश्यक संशोधनों के साथ लागू कर दिया गया। लकड़ी के कोयले की कमी के कारण यह तय किया गया कि उसके स्थान पर उसी परिमाण में सौफ्ट कोक इस्तेमाल किया जाय और लकड़ी के कोयले का इस्तेमाल केवल उसी समय किया जाय जब सौफ्ट कोक के मिलने में कठिनाई हो।

### विस्थापित व्यक्तियों को फीस में रियायत

राज्य सरकार ने यह निश्चय किया कि पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित लोगों को फीस की जो सुविधा दी गयी थी, उसे ३१ दिसम्बर, १९६१ तक और जारी रखा जाय।

## छुट्टियाँ

छुट्टियों की सूची में इस वर्ष संशोधन किया गया और १९६१ के लिए छुट्टियों की संख्या २४ से घटाकर २० कर दी गयी। इनमें से दो ऐसी थीं जो केवल बैंक कर्मचारियों के लिए थीं। साम्प्रदायिक छुट्टियों की प्रथा समाप्त कर दी गयी और उसके स्थान पर ११ निर्बंधित छुट्टियाँ घोषित की गयीं, जिनमें से प्रत्येक सरकारी कर्मचारी अपनी पसन्द की कोई दो छुट्टियाँ ले सकता था। इस प्रकार साम्प्रदायिक छुट्टियों के विरुद्ध यह आरोप कि उनके विषय में यह धारणा उत्पन्न हो सकती थी कि उनके द्वारा धर्म-निर्पेक्ष भारतीय संघ के सिद्धान्तों के विरुद्ध साम्प्रदायिक भावनाओं को बल मिलने की सम्भावना थी, दूर हो गया। प्रत्येक राज्य कर्मचारी को अब एक वर्ष में नीचे लिखे अनुसार बिना भेद-भाव के २५ छुट्टियाँ लेने की छूट थी—

- (१) निगोशिएबल इस्ट्रुमेण्ट ऐक्ट के अन्तर्गत घोषित मार्वाजनिक छुट्टियाँ।
- (२) निर्बंधित छुट्टियाँ।
- (३) सरकार के प्रशासनिक आदेश द्वारा घोषित अतिरिक्त छुट्टियाँ।
- (४) स्थानीय छुट्टियाँ।

राज्य कर्मचारी गृहस्थों के लिए आवश्यक मामान आदि खरीद सके, इसके लिए यह निश्चय किया गया कि १ दिसम्बर, १९६० से महीने के अन्तिम शनिवार, जबकि सामान्यतः उनके पास पैसे नहीं रह जाते, के स्थान पर महीने के दूसरे शनिवार को सभी कार्यालयों तथा संस्थाओं में पूरे दिन की छुट्टी दे दी जाया करे। यह आदेश राज्य की ट्रेजरी और सब-ट्रेजरीज को छोड़कर सभी राजनियंत्रित संस्थाओं पर लागू था।

## अष्टाचार के विरुद्ध अभियान

राज्य सेवाओं में फैले हुए अष्टाचार के उन्मूलन के लिए १९४६ से आरम्भ किये गये विभिन्न कार्यों को जारी रखा गया। जिन मामलों में वादी के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना रहती है, उनमें वादी को परेशान किये जाने से रोकने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया। फरवरी, १९६१ में राज्य के सभी अधिकारियों के पाम इस आशय के आदेश भेज दिये गये कि सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की जाच के सिलसिले में शिकायत करने वालों का नाम पता आदि उन लोगों को, जिनके विरुद्ध शिकायत की गयी हो, तब तक नहीं बताया जायगा, जब तक कि जाच का कार्य उस स्थिति पर न पहुँच जाय जहाँ नियमानुसार यह बताना आवश्यक हो।

## उत्तर प्रदेशीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण

प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जिसकी स्थापना १९४७ के उत्तर प्रदेशीय अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही (प्रशासनिक न्यायाधिकरण) नियम के अन्तर्गत हुई थी, अपना कार्य पूर्ववत् करता रहा। आलोच्य वर्ष ५ नये मामले इस न्यायाधिकरण को सौंपे गये। ३१ मार्च, १९६१ तक इस न्यायाधिकरण द्वारा किये गये कार्य का विवरण नीचे प्रस्तुत है—

(१) न्यायाधिकरण को सौंपे गये मामलों की संख्या	.. ६३
(२) निर्णीत मामलों की संख्या	.. ५२
(३) वे मामले जो निर्णय के पहले वापस ले लिये गये	.. २
(४) निर्णय दिये जाने के लिए शेष मामले	.. ६*

वे ५२ मामले, जिनका निर्णय दिया गया, ६७ राज्य कर्मचारियों से सम्बन्धित थे, जिन में से २९ पदच्युत कर दिये गये, एक कार्य-मुक्त किया गया, ३ को निकाल दिया गया, ३ को अनिवार्य सेवा निवृत्ति मिल गयी और १४ को अन्य दण्ड दिये गये। शेष लोगों में से १६ दोष-मुक्त पाये गये और एक ने स्वयं पद-त्याग किया।

\*इनमें से चार मामले सरकार के पास अनिर्णीत थे।

## जिला भ्रष्टाचार निरोधक समितियाँ

उत्तराखण्ड डिवीजन के जिलों को छोड़कर राज्य के अन्य सभी जिलों में भ्रष्टाचार निरोधक समितियाँ कार्य करती रही। जिला भ्रष्टाचार विरोधी समितियों के अध्यक्षों के गत वर्ष आयोजित अखिल प्रदेशीय सम्मेलन में शासन द्वारा किये गये निश्चयों के अनुसार आलोच्य वर्ष में उत्तर प्रदेशीय भ्रष्टाचार निरोधक समिति का गठन किया गया। मुख्य मन्त्री इस समिति के अध्यक्ष तथा गृह-मन्त्री उपाध्यक्ष थे। इस समिति में १० और सदस्व मनोनीत किये गये थे, जो भ्रष्टाचार निरोधक समितियों के अध्यक्ष में से लिये गये थे और उत्तराखण्ड डिवीजन को छोड़कर प्रत्येक डिवीजन में से एक-एक के हिसाब से लिये गये थे। जून, १९६० में प्रत्येक समिति के लिए पूरे समय का कार्य करने के निमित्त एक-एक कनिष्ठ लिपिक तथा हिन्दी का एक-एक टाइपराइटर और समिति कार्यालय के लिए मकान भाड़ा स्वीकृत किया गया। इन मदों की व्यवस्था के महत्व की दृष्टि से राजल के आकस्मिक निधि से पैसे निकाल गये। यह आशा की गई कि इन सुविधाओं की व्यवस्था हो जाने पर यह भ्रष्टाचार निरोधक समितियाँ अपना कार्य सुचारु रूप से करेगी।

पूर्व वर्ष की भांति प्रत्येक समिति ने १९६०-६१ वर्ष में भ्रष्टाचार एवं घूसखोरी के विरुद्ध प्रचार के लिए ४७५ रुपये की स्वीकृत किये गये।

## विलीनीकृत राज तथा औपनिवेशिक बस्तियाँ

(क) दातव्य भत्ते पेशान इत्यादि—गत वर्षों की भांति कुछ लोगों को पहले से मिलने वाले दातव्य भत्ते, पेशानों को मिलने वाली पेशाने राजाओं के सम्बन्धी एवं नौकरो को मिलने वाले भत्ते इस वर्ष भी दिये जाते रहे।

(ख) निर्धारित उद्देश्यों के लिए अनुदान आदि—गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी निम्नलिखित आवर्तक अनुदान तथा भुगतान दिये—

(१) रामपुर में चिरकाल से चले आ रहे दातव्य कार्यों के लिये . . . . . ५०,००० रुपये

(२) रामलीला, मन्दिरों तथा अन्य दातव्य सस्थाओं के लिये महाराज बनावस को . . . . . १,००,००० रुपये।

(ग) देहरी-गढ़वाल मंदिर ट्रस्ट—महाराज देहरी-गढ़वाल के पराकर्ष से देहरी-गढ़वाल के मंदिरों की व्यवस्था के लिये ट्रस्ट बनाने सम्बन्धी ट्रस्ट सविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा था।

(घ) रैनपुर मंदिर ट्रस्ट, चर्खारी—इस मंदिर की व्यवस्था सम्बन्धी ट्रस्ट सविदा को अंतिम रूप दिया जा चुका था और उसे कार्यान्वित करने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही की जा रही थी।

## चलचित्रों का प्रदर्शन

स्थायी सिनेमाघर जो आय के मुख्य साधन थे, उनकी संख्या २३० से बढ़कर २४३ हो गयी। दूसरी ओर संचल सिनेमाघरों की संख्या, भेलो तथा प्रदर्शनियों में थोड़े समय के लिए होने वाले प्रदर्शनों को छोड़कर इस अवधि में १७५ से घट कर १६४ हो गयी।

## झंडा दिवस

भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों को आर्थिक कठिनाई से उबारने तथा प्रतिरक्षा सेनाओं के काम काम करने वालों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए धन एकत्र करने के

निमित्त ७ दिसम्बर, १९५६ को वार्षिक सड़ा दिवस मनाया गया। उस दिन एकत्र धन के सही आंकड़ों का पता तो अभी तक नहीं था लेकिन ऐसा पता चलता है कि १५ मई, १९६१ तक १,८०,५०० रुपये की रकम केन्द्रीय सैनिक, नाविक एवं वायुसैनिक परिषद् में जमा की जा चुकी थी। यह स्पष्ट था कि समस्त एकत्र धन इस राज्य के लिए निर्धारित १,४०,००० रुपये लक्ष्य से पर्याप्त अधिक था।

**नये डाक एवं तारघरों की स्थापना तथा पुरानो को परिचालित रखना**

राज्य सरकार अपने खजाने से बागेश्वर (जिला अल्मोड़ा) के डाकखाने, भैरवा (जिला मिर्जापुर) के ब्रांच पोस्ट आफिस, कोन (जिला मिर्जापुर) के ब्रांच पोस्ट-आफिस, भिनगा (जिला बहराइच) के तारघर और सतपुरी से बद्रीनाथ की टंक-टेलीफोन लाइन पर होने वाले घाटे को पूरा करती रही। यद्यपि डाक और तार की सुविधाओं की व्यवस्था का उत्तरदायित्व भारत सरकार के तार एवं डाक विभाग का है फिर भी राज्य सरकार ने विभिन्न प्रशासनिक एवं अन्य आधारों पर इन डाक और तारघरों में होने वाले घाटे को पूरा करने की गारंटी ली थी। डाक और तार विभाग उनको चलाने और उनकी देख-रेख इस गारंटी के आधार पर ही करने को तैयार था।

**याचिकाएं एवं शिकायते**

याचिका विभाग में इस वर्ष कुल २६,५५६ याचिकाएं तथा शिकायते प्राप्त हुईं जबकि इसके पूर्व वर्ष इनकी संख्या ३१,०७० थी। इनमें से २,१७७ याचिकाएं राष्ट्रपति के माध्यम से, ५,३३३ प्रधान मन्त्री तथा अन्य केन्द्रीय मन्त्रियों के माध्यम से और २२,०४६ सीधे सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भेजी गयी थी।

कुल प्राप्त याचिकाओं में से १८,०२६ याचिकाएं सम्बन्धित अधिकारियों के पास उचित कार्यवाही के लिए भेज दी गयी और इसकी सूचना याचिका भेजने वालों को दे दी गयी, जबकि इसके पूर्व वर्ष २२,३२७ याचिकाएं इस प्रकार भेजी गयी थी। २,६७२ मामलों के या तो सीधे उत्तर भेज दिये गये या उन्हें स्थानीय सम्बन्धित अधिकारियों के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए भेजने वालों के पास लौटा दिया गया। इसके पूर्व वर्ष ऐसी २,४६१ याचिकाएं या तो लौटायी गयी थी या उनके उत्तर दे दिये गये थे। ऐसी याचिकाएं और शिकायते जिन पर बेनाम की या गलत नाम से भेजी गयी होने अथवा बहुत ही महत्वहीन होने के कारण कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं था, उनकी संख्या ८,८५८ थी जबकि इसके पूर्व वर्ष ऐसी ६,२५२ याचिकाएं और शिकायते प्राप्त हुई थी।

इस बात का प्रयत्न किया गया कि याचिकाएं देने वाले तथा शिकायत करने वालों की शिकायते दूर की जायें। ऐसे मामलों को जिनके सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की याचिका विभाग द्वारा रिपोर्ट मांगी गयी थी, की संख्या १,०६५ थी। आलोच्य वर्ष वास्तव में प्राप्त रिपोर्टों की संख्या १,००१ थी, जिनमें अंतरिम रिपोर्टें और ऐसी याचिकाओं की रिपोर्टें भी सम्मिलित थी, जो इसके पूर्व वर्ष आवश्यक कार्यवाही के लिए संबद्ध अधिकारियों के पास भेजी गयी थी। ये रिपोर्टें जिन मामलों से संबद्ध थी, उनमें से १२७ मामलों में शिकायत करने वालों की वास्तविक सहायता की जा सकती थी।

जैसा सामान्यतः होता था, ये याचिकाएं और शिकायते इस वर्ष भी प्रायः ऐसे सभी मामलों से संबद्ध थीं, जिनकी कल्पना की जा सकती थी। इनमें से सबसे अधिक गांव के झगड़ों से संबद्ध थीं या भूमि संबंधी अभिलेखों में गलत इन्दराज के कारण उत्पन्न झगड़ों या भूमि के दखल-कब्जे से संबंधित थी और कुल शिकायतों का प्रतिशत २०.४ था जबकि इनका प्रतिशत इससे पूर्व वर्ष २१.३ था।

आलोच्य वर्ष राजनीतिक पीड़ितों द्वारा पेशन या भूमि आदि के सबंध में भेजे गये आवेदन-पत्रों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इनकी संख्या कुल याचिकाओं की १५.६ प्रतिशत थी, जबकि इसके पिछले वर्ष इनकी संख्या केवल ६.६ प्रतिशत थी।

गाव-पंचायतो के सदस्यों एवं कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध तथा पंचायत चुनाव के समय भ्रष्टाचार के विरुद्ध की गयी शिकायतों की संख्या इस वर्ष कुल प्राप्त याचिकाओं एवं शिकायतों की ८.५ प्रतिशत थी। इससे पूर्व वर्ष पंचायतों के सदस्यों एवं कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की संख्या कुल शिकायतों की केवल १.५ प्रतिशत थी।

टी० बी० तथा अन्य रोगों की चिकित्सा के लिए आर्थिक सहायता तथा लघु उद्योगों की स्थापना के हेतु अनुदानों के लिए ही पर्याप्त संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और उनकी संख्या कुल याचिकाओं और शिकायतों की क्रमशः १०.७ और ७.२ प्रतिशत थी।

स्थानीय पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार और परेशान करने तथा अपराधों के विरुद्ध उचित कार्य-वाही करने में असफलता के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या में इस वर्ष कमी हुई और इनकी संख्या कुल याचिकाओं की ७.६ प्रतिशत थी, जबकि इसके पूर्व वर्ष इनकी संख्या २१.२ प्रतिशत रही।

बाढ़, सूखा तथा आगिकांड के विरुद्ध सहायता संबंधी याचिकाओं की संख्या कुल की ६.१ प्रतिशत थी, जबकि इससे पूर्व वर्ष इनकी संख्या ३.३ प्रतिशत थी। इन याचिकाओं को बराबर की भांति प्राथमिकता दी गयी और इन्हें अविलम्ब सहायता के लिए संबंधित अधिकारियों के पास भेज दिया गया। जिन व्यक्तियों ने याचिकाएं भेजी थी, उनको भी सूचित कर दिया गया कि वे जिले के संबंधित अधिकारियों से सहायता के लिए अविलम्ब संपर्क स्थापित करें।

अन्य स्पष्ट विषयों के संबंध में भेजी गयी याचिकाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत है :—

याचिकाओं के विषय	कुल याचिकाओं के सदर्थ में इनका अनुपात	
	१९६०-६१	१९५९-६०
	प्रतिशत	प्रतिशत
(१) छात्र वृत्तियों अथवा पुस्तकों के क्रयार्थ आर्थिक सहायता के लिए .. .. .	७.९	४.९
(२) नौकरी की व्यवस्था के लिए .. .. .	४.३	१०.२
(३) वृद्धावस्था पेंशन के लिए .. .. .	५.००	९.१
(४) चक्रबन्दी के विरुद्ध असतोष से संबंध .. .. .	५.३	२.७५
(५) विभिन्न विभागों के प्रशासकीय नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करने वाले राज कर्मचारियों के विरुद्ध .. .. .	१.१	१.१
(६) विविध .. .. .	०.३	१.३

## अध्याय २

### भूमि प्रशासन

#### १—जमींदारी विनाश और भूमि सुधार

जौनसर् बावर जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६

आलोच्य वर्ष जौनसार बावर जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अध्याय २ के अन्तर्गत प्रस्तावित बन्दोबस्त कार्य बन्द कर दिये गये ।

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र अधिनियम के अध्याय २ के अन्तर्गत २०६ नागर इकाइयों में कृषि क्षेत्रों की हदबन्दी की नोटिस दी गयी । इस प्रकार राज्य के ४५४ नागर इकाइयों में से ४३० इकाइयों इस कार्यक्रम में आ गयीं । आलोच्य वर्ष १९७७ इकाइयों में हदबन्दी का कार्य पूरा कर लिया गया, जिसके फलस्वरूप ऐसी इकाइयों की संख्या १९५ हो गयी; किन्तु वर्ष के अंत में इनमें से कुछ क्षेत्रों में उच्चरदारिया फैसले के लिये बाकी रह गयी थी ।

ऐसे क्षेत्र, जिनमें अधिनियम की धारा लागू नहीं की गयी

आलोच्य वर्ष के अंत तक उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५०, तराई भावर राजकीय आस्थानों, उपनिवेश क्षेत्रों, केन्द्रीय सरकार या अन्य किसी स्थानीय निकायों के आस्थानों, सार्वजनिक कार्यों के लिए ली गयी भूमि, नैनीताल जिले की पर्वतीय पट्टियों और अल्मोड़ा, गढ़वाल, देहरी-गढ़वाल, पिठौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के जिलों में लागू नहीं किया गया था ।

#### भूस्वामित्व सीमा-निर्धारण

उत्तर प्रदेश भूस्वामित्व सीमा-निर्धारण अधिनियम, १९६० आलोच्य वर्ष में १९६१ का अधिनियम संख्या १ के रूप में पारित किया गया ।

कुमायूँ उत्तराखंड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९६०

कुमायूँ तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश और भूमि सुधार व्यवस्था अधिनियम, १९६० उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १७, १९६० के रूप में पारित किया गया । उन क्षेत्रों में, जहाँ के लिए यह अधिनियम लागू था, अर्थात् कुमायूँ और उत्तराखंड डिवीजनों की पर्वतीय पट्टियों में सर्वेक्षण तथा भूमि अभिलेखन कार्य जारी रहा ।

#### भूतपूर्व मध्यवर्तियों को मुआविजा

१९६०-६१ के अंत में मुआविजा की अंतिम रूप से निर्धारित रकम ६८,८७,९८,२९९ रु० थी । आलोच्य वर्ष निम्न विवरण के अनुसार मुआविजा की रकमें बाटीं गयीं—

	रु०
(१) बांडो के रूप में दिया गया मुआविजा .. ..	५४,०४,०००
(२) नकद के रूप में दी गयी मुआविजा की रकम—	
(क) शेष रकमों के भुगतान .. ..	३,५१,१४८
(ख) उन लोगों को भुगतान, जिन्हें ५० रु० या उससे कम मिलते थे १९,१९,८००	
(ग) अंतरिम मुआविजा के रूप में .. ..	४०,०७५

योग .. .. ७७,१५,०२३



वर्ष के अंत तक मुआविजा के रूप में दी गयी कुल रकम ६४,७३,८५,३७३ रु० थी, जिसमें से ४८,४२,२५,६०० रु० बाडों के रूप में तथा १६,३१,५६,४७३ रु० नकद दिये गये थे ।

### सार्वजनिक ऋण कार्यालय-मुआविजा के बाडों की मांग तथा वितरण

मुआविजा तथा पुनर्वास अनुदान की विभिन्न रकमों के १२,४४,१५,८०० रु० के बाड इस वर्ष लखनऊ के सार्वजनिक ऋण कार्यालय द्वारा वितरित किये गये । इस प्रकार अब तक कुल ६४,२३,५८,२०० रु० मूल्य के बाड वितरित किये गये थे ।

### वक्फों, ट्रस्टों तथा धर्मादा खातों को अन्तरिम वार्षिकी तथा ब्याज का भुगतान

वक्फों, ट्रस्टों तथा धार्मिक एवं दातव्य कार्यों के उद्देश्य से धर्मादा खातों को अन्तरिम वार्षिकी के रूप में ४३,७७,६३३ रु० दिये गये । इनको लेकर अब तक इस मद में २,१६,८६,६२६ रु० दिये जा चुके हैं ।

उपर्युक्त वक्फों, ट्रस्टों तथा धर्मादा खातों को मुआविजा के रूप में उन्हें देय धन पर ढाई प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी दिया गया । आलोच्य वर्ष के अंत तक कुल १५,५८६ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से १५,४८२ आवेदन-पत्रों पर अंतिम रूप से कार्यवाही की गयी, जिनमें कुल ५४,७५,६१८ रु० के भुगतान की व्यवस्था थी । अन्तरिम ब्याज की रकम का अंत में उस रकम में समाधान किया जाना था जो इन सस्थाओं को अंत में ब्याज के रूप में मिलने वाली थी ।

### सुन्नी तथा शिया वक्फ बोर्डों को अन्तरिम शुल्क का भुगतान

अभी तक राज्य के सुन्नी और शिया वक्फों को देय शुल्क का अनुमान लगाना संभव नहीं हो पाया था अतः आलोच्य वर्ष इन बोर्डों को अन्तरिम शुल्क के तौर पर क्रमशः २१,००० रु० और ६,५०० रु० का भुगतान किया गया ।

### पुनर्वास अनुदान का निर्धारण एवं भुगतान

वर्ष के अंत तक पुनर्वास अनुदान के निर्धारण एवं भुगतान के संबंध में ७,५३,६०६ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे । इनमें से ७,४१,८०५ आवेदन-पत्र स्वीकार किये गये । प्रस्तुत वर्ष ५५,१६,७०,५६ रुपये को पुनर्वास अनुदान देने का निश्चय किया गया । ये १,१८,७११ आवेदन पत्रों के संबंध में थे । इनका विवरण नीचे दिया जा रहा है :-

(१) ५० रु० या उससे कम की मदों के संबंध में	..	८,३६,६७३
(२) ५० रु० से ऊपर के मदों के संबंध में	..	५,४३,२७,०८३
योग		५,५१,६७,०५६

प्रस्तुत वर्ष ६,२२,८७,००० रु० मूल्य के बाडों की मांग की गयी थी और नीचे लिखे अनुसार बाडों तथा नगदी में भुगतान किये गये :-

(क) बाडों द्वारा किया गया भुगतान	..	१५,२६,७६,६००
(ख) नकद के रूप में, जिसमें सरकार की बाकी रकम का समाधान भी सम्मिलित है, भुगतान	..	७,७५,६०७
(ग) अवशेष पुनर्वास अनुदान नकद के रूप में बाड पाने वालों को भुगतान जिसमें सरकार की बकाया रकम का समाधान भी सम्मिलित है	..	५४,०५,१२३
योग		१५,८८,५०,६३०

२. आलोच्य वर्ष के अंत तक वार्षिकी के लिए ३,६७४ आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से प्रस्तुत वर्ष १,०१० आवेदन-पत्र विचारार्थ स्वीकृत किये गये और १,३०० वार्षिकी नामावली निकाली गयी जिसमें कुल ६,७०,३४४ रुपयों के अनुदान का विवरण था। आरंभ से इस वर्ष तक प्रकाशित कुल वार्षिकी नामावलियों की संख्या का योग १,६७३ था। इनमें से कुल १२,५६,८६६ रुपयों का विवरण था।

**उन बांड प्राप्त अधिवासियों को मुआविजा जो सीरदार बन गये**

१६५६ के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमिसुधार अधिनियम की १६-क के अन्तर्गत उन बांड प्राप्त अधिवासियों के, जो सीरदार बन गये, मुआविजा के निर्धारण एवं भुगतान से संबंधित कार्य जारी रखा गया। आलोच्य वर्ष में भूमि पर काबिज लोगो तथा उनके खातों की संख्या क्रमशः ४०,४२,७०२ तथा २३,२६,६०७ थी। भूमि पर काबिज ४०,४०,४२६ लोगो की नामावली उज्जरदारी के लिये प्रकाशित की गयी, उज्जरदारियों से सम्बन्धित दायर किये गये ६,६१,३७० मुकदमों में से ६,६०,६८८ का फैसला करने के बाद ४०,३७,१८० नामावलियों को अंतिम रूप से स्वीकार किया गया। इन अंतिम रूप से स्वीकृत नामावलि यो के लिए प्रस्तुत वर्ष में निर्धारित मुआविजा ११,८१,६०,५१२ रु० थे, जिनमें से २३,२५,२०० रु० बांडो के रूप में तथा ६,८८,६३,४८३ रु० नकद तथा समाधान द्वारा दिये गये।

**जोतों की चकबंदी**

१९६०-६१ के अंत में जोतों की चकबंदी से संबंधित योजना राज्य के ३८ जिलों में चल रही थी। इस योजना के अंतर्गत २३,५६८ गांवों के २,४८,३५,२६६ खेतों का कुल ६६,६२,०५५ एकड़ क्षेत्रफल मजसूमा क्षेत्र था।

१९५६-६० तक १६ तहसीलों में चकबंदी का कार्य पूरा किया जा चुका था। आलोच्य वर्ष में यह कार्य जौनपुर, फैजाबाद, हरदोई, इलाहाबाद, गोरखपुर, बाराबंकी, इटावा (३ राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों में), फतेहपुर जिलों की प्रथम तहसीलों तथा मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा और मुरादाबाद जिलों की द्वितीय तहसीलों में पूरा किया गया। ३,६८८ गांवों में इन प्रस्तावों के विवरणों की पुष्टि की गयी, जिसको लेकर इस योजना के आरम्भ से अब तक कुल १४,२८४ गांवों के संबंध में चकबंदी के प्रस्ताव स्वीकृत किये जा चुके थे। ४,४०४ गांवों में नये चको का स्वामित्व हस्तांतरित किया गया, जिसको लेकर अब तक कुल १४,२३५ गांवों के ५३,६३,६२८ एकड़ मजसूमा क्षेत्र के स्वामित्व का हस्तांतरण किया जा चुका था।

आलोच्य वर्ष में २ पूरे वर्ष चलने वाले प्रशिक्षण केन्द्र कार्य करते रहे।

**२—सर्वेक्षण, बन्दोबस्त तथा भूमि अभिलेखन कार्य**

राज्य के किसी भी भाग में भूमि राजस्व अधिनियम की ५६ धारा के अन्तर्गत कोई बन्दोबस्त कार्य नहीं किया गया।

सर्वेक्षण तथा भूमि अभिलेखन कार्य राज्य के विभिन्न मैदानी एवं पहाड़ी जिलों में या तो आरम्भ किये गये या जारी रहे अथवा पूरे किये गये। प्रत्येक जिले के संबंध में कार्य की स्थिति नीचे दी जा रही है—

(१) मेरठ—इस जिले के ६० गांवों में चल रहे सर्वेक्षण एवं भूमि अभिलेखन कार्य के सिवाय ६६ गांवों के अभिलेखन तथा प्रमाणीकरण के कार्य आलोच्य वर्ष में पूरे कर लिये गये।

इसके पूर्व वर्ष के कुल अनिर्णीत मामले, जिनपर निर्णय देना बाकी था, २७ थे। आलोच्य वर्ष में १,१६८ मामले फैसले के लिए आये, जिनको लेकर कुल १,१६५ मामले फैसले के लिए थे। इनमें से १,१८७ मामलों का फैसला कर दिया गया और वर्ष के अंत में केवल ८ मामले शेष रह गये थे।

प्रस्तुत वर्ष में हुए व्यय का कुल योग २५,८६८ रुपये था ।

(२) मिर्जापुर—परगना विजयगढ़ के ३६५ गावों में कार्य आरम्भ किया गया । कुल २,६७,३७२ एकड़ क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया । इस प्रकार प्रस्तुत वर्ष इन गांवों का समूचा सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया ।

कुल १,७६,८३८ खेतों में से ७२,५२३ खेतों के संबंध में खसरा तैयार कर लिया गया और १,०४,३१५ खेतों का खसरा तैयार करना शेष बचा ।

आलोच्य वर्ष में इन कार्यों पर कुल २,११,६२३ रुपये व्यय हुए ।

(३) देवरिया—४० गावों में आरम्भ किया गया, समस्त कार्य, भूमि अभिलेखन, प्रमाणीकरण तथा एक गांव के अभिलेखों को साफ-साफ तैयार करना छोड़कर इससे पूर्व ही समाप्त किया जा चुका था । आलोच्य वर्ष अभिलेखन तथा प्रमाणीकरण कार्य पूरे कर लिये गये थे । केवल एक गांव के अभिलेखों के साफ प्रतिलिपि तैयार करने का काम शुरू नहीं किया गया था । आजमगढ़ तथा देवरिया जिलों के बीच सीमा के सबंध में कुछ समस्याएँ उत्पन्न हो जाने के कारण सहायक अभिलेख अधिकारी इतने व्यस्त रहे कि इस गांव के संबंध में प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं कर सके, इसीलिए उस गांव के अभिलेख साफ नहीं किये जा सके ।

इस वर्ष जिले के इन कार्यों में कुल २३५ रुपये व्यय हुये ।

(४) हरदोई—इस जिले के ४५ गांवों में कार्य जारी रखा गया । एक गांव के अभिलेखों की दुरुस्ती छोड़कर शेष सभी कार्य पूरे कर लिये गये ।

कुल मिलाकर २७,७६६ एकड़ भूमि का सर्वेक्षण हुआ । १२,६०० खातों को प्रमाणित किया गया और ४४ गावों के अभिलेख दुरुस्त किये गये । इन सब कार्यों में कुल ५६,१२० रु० व्यय हुए ।

(५) बहराइच—इस जिले के ३५३ गावों में भिन्न-भिन्न समय भूमि अभिलेखन कार्य किये गये । अधिकांश कार्य इससे पूर्व वर्ष में ही समाप्त कर लिये गये थे और शेष अर्थात् खानापुरी, प्रमाणीकरण और अभिलेखों की दुरुस्ती तथा १७० गावों से संबंधित मामलों के निर्णय आलोच्य वर्ष में पूरे कर लिये गये । उन २५ गांवों के अभिलेख भी फिर से पूरे कर लिये गये जो आग लगने से नष्ट हो गये थे । इन कामों में कुल १,०६,२०८ रु० व्यय हुए ।

(६) बाराबंकी—जिले के ८० गावों में कार्य आरम्भ किया गया । आलोच्य वर्ष में केवल पुनर्सर्वेक्षण किया गया और ६२,०२७ एकड़ भूमि का पुनर्सर्वेक्षण पूरा हुआ तथा १५,५६७ एकड़ भूमि का पुनर्सर्वेक्षण शेष रह गया । इस वर्ष और कोई कार्य हाथ में नहीं लिया गया । इन कार्यों में कुल ४०,८७० रु० व्यय हुए ।

(७) तराई भावर राजकीय आस्थान (जिला नैनीताल)—तराई और भावर राजकीय आस्थान के समस्त क्षेत्र में भूमि अभिलेखन कार्य जारी रहा । इसके अतिरिक्त काशीपुर तहसील के ११६ गांव भी भूमि-अभिलेखन अभियान के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिये गये । आलोच्य वर्ष में ६७,६३० एकड़ भूमि का पुनः सर्वेक्षण कर लिया गया ।

चार सौ बत्तीस गावों का खसरा तैयार कर लिया गया और २२५ गांवों के खसरा "क" की जांच कर ली गयी । ४२१ गावों से संबंधित फर्दमुताबिकत तैयार की गयी और ५७४ गावों की फर्द, मुताबिकत की जांच की गयी । इसी प्रकार ३४१ गांवों के संबंध में प्रारम्भिक नकशा तैयार करने का कार्य पूरा किया गया । १८६ गावों की खतौनी पुर्जियां तैयार की गयीं और १३१ गावों की खतौनी पुर्जियों की जांच की गयी । इसी प्रकार १८६ गावों की तेरीज तैयार की गयी तथा १३४ गावों की तेरीज की जांच की गयी ।

पिछले वर्ष के अंत में ६१ मामले निर्णय के लिए बाकी रह गए थे । आलोच्य वर्ष ८२ नये मामले दाखिल किए गये । इस प्रकार कुल १४३ मामले निर्णय के लिए दाखिल थे जिनमें से ११२ पर निर्णय दे दिया गया और ३१ शेष रह गये ।

इन सब कार्यों पर कुल १,२०,६२६ रु० व्यय हुए ।

(८) नैनीताल—जिले के पहाड़ी हिस्सों का सर्वेक्षण तथा भूमि अभिलेखन कार्य पिछले वर्ष ही पूरा हो गया था । आलोच्य वर्ष कोई नया काम हाथ में नहीं लिया गया ।

• (९) अल्मोड़ा—इस जिले के ३५७ गावों के भूमि अभिलेख दुरुस्त किये गये । ३८१ गांव, जिनमें १,४४,४६३ एकड़ क्षेत्र सम्मिलित था, का सर्वेक्षण एवं भूमि अभिलेखन कार्य पूरा कर दिया गया और ४०१ गावों के भूमि अभिलेखों को प्रमाणित किया गया । ४५८ गावों के खसरा तथा मुन्तखिब भी दुरुस्त किया गया । आलोच्य वर्ष में ५०८ गावों, जिनमें १,५०,७०९ खेत थे, के नक्शे भी बनाये गये । ३,६७१ मामले, जिनका मौको पर ही तसफिया कर दिया गया, के अतिरिक्त ८५३ मामलों का निर्णय किया गया । इन कार्यों पर आलोच्य वर्ष ६,०६,०७७ रुपये खर्च हुए ।

(१०) देहरी-गढ़वाल—५०,३२७ एकड़ नाप भूमि और १२,२१९ एकड़ बेनाप भूमि का पुनर्सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया । ४०७ गाव के खसरे तथा ४८२ गाव के मुन्तखिब दुरुस्त कर लिये गये और ४०८ गावों के नक्शे पूरे कर लिये गये । इसके अतिरिक्त ४५७ गावों के दुरुस्त किये गये खसरे और मुन्तखिब तथा ६७२ गावों के तैयार नक्शों की जाच की गयी । २७६ गावों के संबंध में खानापूरी का कार्य समाप्त हुआ और कुल ६१२ मुकदमों का फैसला किया गया । आलोच्य वर्ष में किये गये इन सब कार्यों पर कुल ४,१९,६२४ रु० व्यय हुए ।

(११) पौड़ी-गढ़वाल—७२६ गावों के पुनर्सर्वेक्षण, नक्शा दुरुस्ती तथा खानापूरी कार्य पूरा किया गया तथा ६९० गावों के भूमि अभिलेख प्रमाणित किये गये । इसके अतिरिक्त ७,८०० गावों के खेत संबंधी अभिलेखों की जाच-पड़ताल की गयी और ८८९ गावों की सरहद मिलान का कार्य किया गया । इस वर्ष मौको पर उत्पन्न १८,०७६ विवादों का फैसला भी किया गया । इसके अतिरिक्त १,५८१ नियमित मुकदमों तथा ३२ अपीलों का भी फैसला किया गया । इन कार्यों पर कुल ३,८०,१२५ रु० व्यय हुए ।

(१२) उत्तरकाशी—६७४ गावों, जिनमें ४१,१३१ एकड़ नाप तथा ५५,०८० एकड़ बेनाप भूमि थी, का पुनर्सर्वेक्षण कार्य पूरा किया गया । इसी प्रकार १८६ गावों की खानापूरी तथा ४२६ के भूमि अभिलेखों को प्रमाणित किया गया और १,२२६ मामलों पर फैसले दिये गये । आलोच्य वर्ष में किये गये इन कार्यों पर कुल २,०९,८१२ रुपये खर्च हुए ।

(१३) चमोली—७३४ गावों के खसरे तथा ६४२ गावों के मुन्तखिब दुरुस्त किये गये । इसी प्रकार ५८४ गावों के नक्शे तैयार किये गये और ४० मामलों पर फैसले सुनाये गये । प्रस्तुत वर्ष में किये गये इन सब कार्यों पर कुल १,९०,०६३ रु० खर्च हुए ।

(१४) पिठौरागढ़—१९,४१६ एकड़ भूमि नाप तथा १७,६६४ एकड़ बेनाप भूमि का सर्वेक्षण किया गया । १६९ गावों का भूमि अभिलेखन तथा ९० गावों का प्रमाणीकरण कार्य पूरा किया गया । इसके अतिरिक्त कुल ५१ मामलों का फैसला किया गया । इस वर्ष किये गये कार्यों पर कुल ९१,३६१ रुपये व्यय हुए ।

### ३—भूमि अभिलेखन

सन् १९०१ के भूमि राजस्व अधिनियम में सशोधन के द्वारा १९५८ में सुपरवाइजर कानूनगो को यह अधिकार दे दिया गया कि वे भूमि स्वामित्व के बिना विवाद वाले मामलों पर निर्णय दे दिया करें । प्रस्तुत वर्ष पी० ए०—११ ए० फार्म पर उल्लिखित ऐसे समस्त मामलों की सख्या

३,३७,३०० थी। इनमें से ३,०३,७६८ मुकदमों पर सुपरवाइजर कानूनगो लोगो ने फंसले दे दिये और ६,१६३ मामले विवादग्रस्त पाये गये। इस प्रकार कुल २७,३३६ मुकदमों फंसले केलिये शेष रह गये। पी० ए०-१० फार्म पर दर्ज २४,७२,१३० प्रविष्टियों में से २४,४६,०४१ सुपरवाइजर कानूनगो लोगो द्वारा जाचे गये तथा २,७५,६७१ प्रविष्टियों को जांच पुनर्जांच निरीक्षण अधिकारियों द्वारा हुई। सुपरवाइजर कानूनगो लोगो ने इन्दराज की १,७७० तथा निरीक्षा अधिकारियों ने १,४०७ गलतियां जांच-पड़ताल के दौरान में पकड़ीं। खसरा में परिवर्तन के कारण भूमि स्वामित्व के १,६३,१६२ मुकदमों दायर किये गये। इसके अतिरिक्त ८,७६,६१६ मुकदमों उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत नियमों के अन्तर्गत चलाये गये। सहायक निदेशक भूमि अभिलेख तथा सहायक भूमि व्यवस्था आयुक्तों ने मिश्रित दौरे किये और जिला अधिकारियों को भूमि अभिलेखन कार्य में सुधार के सुझाव दिये।

#### ४—काश्तकारी क्षेत्र\*

राज्य में कुमायूँ डिवीजन की पहाड़ी पट्टियों को छोड़कर जोत का कुल क्षेत्रफल नीचे के विवरण से स्पष्ट हो जायगा। इससे पूर्व वर्ष के सम्बन्धित आंकड़े भी दिये गये हैं।

विवरण	१९५८-५९	१९५९-६०
	(लाख एकड़ों में)	
(१) कुल जोत का क्षेत्रफल .. ..	४६५	४६६
(२) जोत का कुल क्षेत्र, जिस पर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम लागू था .. ..	४५६	४५८
(३) जोत का वह क्षेत्र, जिसपर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम लागू नहीं था .. ..	८.८२	८.१७

राज्य के उस भाग में, जहां जमींदारी का विनाश हो चुका था, जोतों का वर्गीकरण निम्न प्रकार था :

	१९५८-५९	१९५९-६०
	(लाख एकड़ों में)	
१—भूमिधरो के कब्जे में .. ..	१५२	१५३
२—सौरदारों के कब्जे में .. ..	२६८.६	२८६
३—जमींदारी विनाश अधिनियम की १३७वीं धारा की व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्तियों के कब्जे में .. ..	१.६	१.७
४—खतौनी के भाग १ में अभिलिखित असामियों के कब्जे में .. ..	१.८	१.८
५—खतौनी के भाग १ में दर्ज स्वत्वहीन किसानों के कब्जे में .. ..	२.१८	२.५

\*यह विवरण ३० जून, १९६० को समाप्त होने वाले फसली सालके सम्बन्ध में है।

२ राज्य के उन भागों में जहाँ जमींदारी विनाश नहीं हुआ था, जोतों का वर्गीकरण निम्न प्रकार था .

जोत की किस्म	१९५८-५९		१९५९-६०	
	(एकड़ों में)			
१—सीर के रूप में जमींदारों के कब्जे में ..	२५,५००		२५,४३३	
२—जमींदारी की खुदकाशत .. ..	७१,७८२		७२,६४०	
३—ठेकेदार या मुर्तहिन की जोत ..	२,२१३		१,६००	
४—जिन व्यक्तियों को भूमि उठाने का अधिकार था बिना उनकी मर्जी के काबिज किसान ..	६२,८२२		६६,८६८	
५—माफीदार किसानों के कब्जे में ..	५,७३१		४,५७७	
६—सीर और खुदकाशत के रूप में ज़िम्मेदारी मालिकों के कब्जे में .. .. .	४,८३७		४,८२६	
७—इस्तमरारी, सरहमोइयन, साकितुलमिल्कियत, दखीलकार और ऐसे काश्तकार, जिनका कब्जा १३३३ फसली को १२ वर्ष से कम अवधि का था .. .. .	१,८८,१३५		१,७६,७६०	
८—विशेष अधिकार वालों सहित मौखसी काश्तकारों के कब्जे में .. ..	३,६३,४३१		३,४४,५३७	
९—गैर-दखीलकारों के कब्जे में ..	८०,४३४		७१,७६५	
१०—रियायती दरो के काश्तकार तथा बगीचेदारों के कब्जे में .. ..	१०,४३७		६,८४६	
११—जिन्सी लगान वाले काश्तकार ..	७,३५१		५,५५७	
योग ..	८,८२,६७३		८,१७,४७२	

#### ५—राजकीय आस्थान

सन् १९५७ में राज्य सरकार ने राजकीय आस्थानों की व्यवस्था के लिए अलग संगठन का अन्त करके उसे जिले के सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मिला देने का निश्चय किया। इस निश्चय के अनुसार राज्य के दो बड़े आस्थानों—तराई एवं भावर राजकीय आस्थान तथा गढ़वाल भावर राजकीय आस्थान—को सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों के नियन्त्रण में हस्तांतरित कर दिया गया। अतः आलोच्य वर्ष में राजकीय आस्थान संगठन की सीधी देख-रेख में विकास कार्यों के कार्यान्वयन का प्रश्न उठा ही नहीं। उक्त क्षेत्र में विभिन्न विकास-कार्य सम्बन्धित जिला नियोजन अधिकारियों की देख-रेख में किये जा रहे थे। गढ़वाल-भावर राजकीय आस्थान रगड़ी की जल सप्लाई योजना की पाइप लाइनें तथा नहरें अगस्त, १९६० में अत्यधिक वर्षा होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गयी थीं। सैनिक अधिकारियों की सहायता से उनकी आवश्यक मरम्मत की गयी।

मिर्जापुर जिले के दुद्धी राजकीय आस्थान में आस्थान अधिकारियों द्वारा संचालित २० प्राइमरी स्कूल संतोषजनक ढंग से कार्य करते रहे।

नैनीताल जिले के बाजपुर तहसील में गदरपुर में एक मुनियोजित केन्द्रीय हाट की स्थापना की योजना के अन्तर्गत नगर एवं ग्राम नियोजन अधिकारी द्वारा तैयार नकशे के अनुसार ८४ प्लॉटों की हदबन्दी की गयी। इनमें से ७६ प्लॉट उन लोगों को दिये गये, जो पहले से ही गदरपुर में रोजगार कर रहे थे और नगर एवं ग्राम नियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नकशे के अनुसार दुकाने बनवाने के लिये तैयार थे। शेष ८ प्लॉट सार्वजनिक नीलाम द्वारा एलाट किये जाने वाले थे।

---

## अध्याय ३

### शांति एवं व्यवस्था

#### १—पुलिस

##### सामान्य

लखनऊ में छात्रों के एक दल द्वारा आन्दोलन, समाजवादी दल द्वारा आरम्भ तथा कथित सविनय अवज्ञा आन्दोलन तथा केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के प्रयास के फलस्वरूप पुलिस दल पर काफी बड़ा उत्तरदायित्व आ पड़ा था। उसको सौंपे गये विभिन्न कार्यों को उसने सफलतापूर्वक निभाया।

पुलिस दल का इन व्यवस्थाओं के बावजूद राज्य भर में अपराधों पर भली-भांति नियंत्रण रहा। कई सशस्त्र डाकू दलों से इसकी मुठभेड़ हुई, जिसमें कई कुख्यात डाकू पकड़े गये और कई बल समाप्त कर दिये गये। इस सिलसिले में अच्छी संख्या में शस्त्रास्त्र तथा गोली बारूद भी बरामद हुए।

राज्य में साम्प्रदायिक स्थिति सतोषजनक रही। कुछ छिट-पुट दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ घटीं, लेकिन शीघ्र ही उन पर नियंत्रण कर लिया गया। एक अवसर पर फैजाबाद शहर में उत्तेजित भीड़ को नियंत्रित करने के लिये पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी।

जनता तथा पुलिस में परस्पर अच्छे सम्बन्ध बने रहे और इस बात का विशेष प्रयत्न जारी रहा कि ये दोनों एक-दूसरे के अधिकाधिक निकट लाये जा सकें।

थानों में मुकदमों की ठीक रिपोर्ट दर्ज की जाय, यह देखने तथा जनता से सम्पर्क बढ़ाने की दृष्टि से गजेटेड पुलिस अधिकारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर किये गये दौरे बहुत लाभदायक सिद्ध हुए।

##### उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग

जनवरी, १९६० में सरकार ने पुलिस आयोग की नियुक्ति की ताकि राज्य के पुलिस दल और पुलिस प्रशासन के विभिन्न पहलुओं की जाच-पड़ताल की जा सके। आयोग से इन पहलुओं में सुधार सम्बन्धी सुझाव देने की भी अपेक्षा की गयी, जिससे कि पुलिस दल को आधुनिक आवश्यकताओं के अधिक उपयुक्त बनाया जा सके। आशा थी कि आयोग अपनी अन्तिम रिपोर्ट सरकार को शीघ्र प्रस्तुत कर देगा।

##### शिकायत की योजना

वर्ष के दौरान में शिकायत की योजना को कुछ सफलता मिली। यह योजना डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल, अपराध अनुसंधान विभाग के अधीन रखी गयी। इनकी सहायता के लिए मुख्यालय (लखनऊ) में एक पुलिस सुपरिटेण्डेंट और तीन स्टाफ अधिकारियों की व्यवस्था की गयी और अधिकांश जिलों में एक पुलिस के डिप्टी सुपरिटेण्डेंट ( शिकायत ) की नियुक्ति की गयी।

वर्ष में ४,९१० मामले डिप्टी सुपरिटेण्डेंट पुलिस (शिकायत) को जाच-पड़ताल हेतु सौंपे गये। इनमें से ४,६८३ मामले पुलिस विभाग से सम्बन्धित थे और १,२२७ अन्य विभागों से। पुलिस विभाग से सम्बन्धित मामलों में २,६८८ मामले घूसखोरी या भ्रष्टाचार, १,२७१ मामले पुलिस द्वारा परेशान किये जाने और ३८ मामले जान-बूझ कर प्रतिशोध लेने के सिलसिले



में थे। अन्य विभागों के कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों में से १,१६२ मामले घूसखोरी और भ्रष्टाचार तथा ३२ बलात् घूस लेने के बारे में थे।

### अनुशासनीय कार्यवाही

पुलिस संगठन से भ्रष्टाचार निर्मूल करने की दिशा में किये गये प्रयत्नों में राज्य पत्रित अधिकारियों द्वारा छापा मारना भी सम्मिलित था। भ्रष्टाचारपूर्ण कार्यों पर कड़ी नजर रखी गयी। अपराधों को हल्का करने और उनको छिपाने, कर्मचारियों की बेईमानी और अकुशलता के विरुद्ध तुरन्त कार्रवाई की गयी और जो कर्मचारी गलती पर पाये गये उनके विरुद्ध कार्रवाई की गयी।

### जन-कल्याण कार्य

उड़ाका दल और खोये बच्चों को ढूँढ़ने वाले दलों का कार्य जनता ने काफी पसन्द किया। पुलिस वालों ने देवी आपदाओं तथा अग्निकांड, बाढ़ आदि की दुर्घटना के समय मानव-जीवन और संपत्ति की रक्षा की।

ऐसे अनेक उदाहरण मिले जहां पुलिस वालों ने स्वेच्छापूर्वक व्यक्तिगत रूप से वृद्धों और रोगियों की सहायता दी तथा डूबतों को बचाया।

वर्ष में पुलिस वालों ने खोये हुए बच्चों का बड़ी संख्या में पता लगाया और खोयी हुई संपत्ति बरामद की। पुलिस वालों ने ३१४ व्यक्तियों को उनकी संपत्ति बरामद करायी और ७,६७६ खोये बच्चों का पता लगाया और उनके माता-पिता के पास पहुंचाया।

### कर्तव्यपालन के दौरान मे दुर्घटना

वर्ष में तीन डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस, एक इन्स्पेक्टर, तीन सब-इन्स्पेक्टर, दो हेड-कास्टेबुल ६ कास्टेबुल और एक फायरमैन की मृत्यु उनके कर्तव्यपालन के दौरान में हुई और कई पुलिस वाले घायल हुए। इसके बावजूद भी पुलिस-दल में नैतिकता और अनुशासन की प्रबल भावना बनी रही।

### ग्राम सुरक्षा समितियां

पहले की भांति ग्राम-सुरक्षा समितियों ने शांति व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस दल को महत्वपूर्ण सहयोग दिया। इन समितियों के सदस्यों ने अपनी जान पर खेल कर सशस्त्र अपराधियों के विरुद्ध लड़ने में बड़ी बहादुरी, उत्साह और साहस का परिचय दिया।

### अपराध संबंधी आंकड़े

विभिन्न प्रकार के अपराधों सम्बन्धी १९५८-५९ और १९६० के तुलनात्मक आंकड़े नीचे की तालिका में दिये जा रहे हैं:—

वर्ष	डाका	बटमारी	कत्ल	दंगा	नकबजनी
१९५८ ..	८२५	४७७	१,६३७	३,०४५	१७,५८६
१९५९ ..	८४६	५०४	१,६६४	२,६००	१५,५७०
१९६० ..	९५२	५४२	१,६५६	२,७४३	१४,७२४

उक्त तालिका में भारतीय दंड-विधान की धारा ३९९/४०२ के अधीन मामले सम्मिलित हैं, जिनमें १९६० में डाकू-दलों से मुठभेड़ हुई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। डाकू-दलों

को नष्ट करने के सिलसिले में १९५६ और १९६० में किये गये कार्यों का व्योरा नीचे दिया जा रहा है :—

वर्ष	मारे गये डाकुओं की संख्या	गिरफ्तार डाकुओं की संख्या	भारतीय दंड-विधान की धारा ३६६/४०२ के अधीन मामले
१९५६ . . . . .	५२	५,४६३	१२३
१९६० . . . . .	७३	६,७३५	१२२

डकैती और बटमारी के मामलों की संख्या पहले वर्षों की तुलना में १९६० में अधिक रही। इसका मुख्य कारण मामलों की सही रिपोर्ट देने और उनकी रजिस्ट्री कराने पर अधिकाधिक बल देना था।

### डाकू दलों के विरुद्ध कार्रवाई

पुलिस द्वारा मारे अथवा गिरफ्तार किये गये कुख्यात और भयंकर डाकुओं में बरेली के विक्रम सिंह और बलिस्तर सिंह, आगरा में चम्बल घाटी के डाकू दफेदार सिंह, रामनाथ (प्रथम) रामनाथ (द्वितीय), क्षिगुरिया, नन्हे, चितलिया और बलवता, गोरखपुर के बंसराज मितऊ अहीर, राम कृपाल, विभूति, मोहन राय और बघेल सिंह, गोडा के राजाराम और मिठाई लाल, बलिया के रामचीज भर, हरदोई के बिन्दा सिंह, जालौन के कुख्यात डाकू गुज्जी मल्लाह का दाहिना हाथ मोती मल्लाह और झांसी के सूरत सिंह सलीता, करनासिंह भन्ना और रामसेवक थे। इनके अतिरिक्त सशस्त्र डाकू दलों से सफल मुठभेड़ की गयी, जिसके फलस्वरूप कई डाकू दलों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया और अच्छी मात्रा में आग्नेयास्त्र तथा गोली-बारूद बरामद की गयी।

२ मई, १९६० को प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस दल और जिला एक्जीक्यूटिव फोर्स ने पुलिस सर्किल बाह से मिलकर रूपा के बचे हुए दल के साथ मुठभेड़ की और इसमें दल के तीन प्रमुख कुख्यात डाकू मारे गये। वर्ष में इस दिशा में यह उल्लेखनीय सफलता रही। मारे गये डाकुओं में रूपा डाकू दल के शीर्षस्थ डाकुओं में से एक रामनाथ ब्राह्मण, मानसिंह गिरोह का एक भूतपूर्व सदस्य नन्हे चमार और चितलिया थे। आगे चल कर मालूम हुआ कि मुठभेड़ में घायल होकर गिरोह का एक चौथा सदस्य (रामनाथ द्वितीय) मर गया था।

मैनपुरी में शिकोहाबाद थाने के कास्टेबुल राजबहादुर को एक कुख्यात व्यक्ति से बन्दूक की लड़ाई करते हुए गहरी चोट आयी जो उनके लिये विनाशकारी सिद्ध हुई। बरेली के ही आंवला कस्बे में हेड-कास्टेबुल शंकर सहाय की मृत्यु उस समय बन्दूक की लड़ाई में हुई जबकि वह एक भयानक दंगे को रोकने की कोशिश कर रहे थे।

### महत्वपूर्ण मामलों का सफल संचालन

विभिन्न जिलों में महत्वपूर्ण मामलों की जाच-पड़ताल में पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया।

आगरा की नगर पुलिस ने नकबजनी के एक मामले को तत्काल हल किया और २६,५०० रु० मूल्य की चोरी गयी संपूर्ण संपत्ति बरामद की।

अलीगढ़ में भी पुलिस ने नकबजनी के एक मामले में सहायनीय कार्य किया और चोरी गयी २६,०६५ रु० मूल्य की संपूर्ण संपत्ति को अविलम्ब बरामद किया।

आगरा में फिरोजाबाद पुलिस ने एक शीर्षस्थ व्यवसायी को चोरी-चोरी लायी गयी तरल सोने की ७४ विदेशी बोतलों के साथ पकड़ा, जिसका मूल्य लगभग ६,००० रु० था।

नैनीताल में एक दूकान से चोरी गयी लगभग १०,००० रु० की नकदी और संपत्ति का अधिकांश रामनगर पुलिस ने चोरी के बाद कुछ ही दिनों में बरामद किया।

चोरी के एक सनसनीखेज मामले में अमृतसर के एक व्यापारी के अटैची केस, जिसमें ५८,०७०.५६ रु० के मूल्य की संपत्ति थी, के चोरी जाने की रिपोर्ट जिला देवरिया से मिली। इस मामले को सफलतापूर्वक हल किया गया और परिणामस्वरूप चोरो को गिरफ्तार किया गया और ३२,००० रु० मूल्य की संपत्ति बरामद की गयी।

मुगलसराय पुलिस ६ सदस्यों के एक बावरिया गिरोह को गिरफ्तार करने में सफल हुई और उनसे ५,००० रु० मूल्य का चोरी का माल बरामद किया।

देवरिया जिले की कसिया पुलिस ने ८२ व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और उनके खास तौर पर सिले गये जैकेटों से २२ मन १८ सेर गैर-कानूनी गांजा बरामद करने में सफलता पायी। इसी प्रकार कोतवाली पुलिस ने १४ मन गांजा बरामद किया। वर्ष में कुल मिला कर पुलिस वालों ने ४४ मन ७ छटाक गांजा बरामद किया, जिसका मूल्य २,६०,००० रु० था।

इनके अतिरिक्त जिले में कई अन्य महत्वपूर्ण मामलों में पुलिस ने सफलतापूर्वक हल किया।

### जिला पुलिस

पुलिस संगठन की कर्मचारी संख्या प्रायः ज्यों की त्यों बनी रही। “शांति और व्यवस्था” तथा तफतीश के कर्मचारियों की पृथक् व्यवस्था करने सम्बन्धी प्रयोग महत्वपूर्ण नगरों में जारी रखा गया और इसके परिणामों का मूल्यांकन किया जा रहा था।

राज्य में आने वाले विदेशी महानुभावों के दौरे के समय पुलिस दल ने कड़ा परिश्रम किया। हर मौके पर कुशलतापूर्वक कर्तव्यपालन किया गया।

जिलों में सूचना-कक्ष और उड़न दस्ते अच्छा काम करते रहे। उड़न दस्तों द्वारा की गयी तात्कालिक कार्रवाइयों के फलस्वरूप कई अवसरों पर स्थिति को बिगड़ने से बचाया गया।

### राजकीय रेलवे पुलिस

राजकीय रेलवे पुलिस ने कई महत्वपूर्ण मामलों को सफलतापूर्वक हल किया और आबकारी तथा अफीम अधिनियमों के अधीन कई गिरफ्तारियां भी कीं।

रेलवे पुलिस ने अपनी ईमानदारी और कार्यकुशलता की ख्याति को अक्षुण्ण रखा और १७,५६४ रु० की भूली हुई और चोरी गयी संपत्ति उनके मालिकों को बरामद करायी। इसके अतिरिक्त १,००,६७८ रु० के मूल्य की चोरी के ११ महत्वपूर्ण मामलों में से ६०,०६५ रु० मूल्य की संपत्ति बरामद की।

राजकीय रेलवे पुलिस ने मेलों और त्योहारों के अवसर पर, जिसमें इलाहाबाद का अर्द्ध-कुम्भ भी सम्मिलित था, यात्रा के दौरान में यात्रियों को सहायता भी दी।

### अपराध अनुसंधान विभाग

(क) अपराध शाखा—अपराध तफतीश विभाग की अपराध शाखा ने कई उलझे और पेचीदे मामलों का कुशलतापूर्वक संचालन किया। इस शाखा की लोकप्रियता और बढ़ी तथा इसके द्वारा महत्वपूर्ण मामलों की जांच पड़ताल कराने की मांग में बराबर वृद्धि होती रही। वर्ष

में २०५ मामले जांच-पड़ताल के लिए आए, जबकि पूर्वगामी वर्ष में १६८ मामले आये थे। इस शाखा को ५२३ मामलों की जांच-पड़ताल का भार सौंपा गया, जबकि १६५६ में उनकी संख्या ४४६ थी। इन मामलों में ३१८ मामले पिछले वर्ष के भी सम्मिलित हैं।

इस शाखा ने डकैती के एक सनसनीखेज मामले को सफलतापूर्वक हल किया। यह मुजफ्फरनगर के लाला बृजभूषण शरण के घर में पड़े डाके का मामला था, जिसमें एक लाख ६० से अधिक मूल्य की संपत्ति लूटी गयी थी। लूट के माल और चोरी गये आग्नेयास्त्रों का अधिकांश बरामद किया गया और आठ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

वर्ष की दूसरी उल्लेखनीय सफलता उस मामले के सफल संचालन में मिली, जिसमें लखनऊ डी० ए० वी० कालेज की ११ राइफिलें चोरी गयी थीं। सभी राइफिलें एक कुख्यात डाकू के कब्जे से बरामद की गयीं। इस मामले में ७ व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चल रहा था।

बरेली स्थित इलाहाबाद बैंक की डकैती के मामले को, जिसमें २४,४४५ ६० की धनराशि लूटी गयी थी, सफलतापूर्वक हल करके अपराधियों के विरुद्ध अदालत में चार्जशीट भेज दी गयी।

(ख) पुलिस कुत्ता-दल—महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाने में पुलिस कुत्ता-दल से बहुमूल्य सहायता मिलती रही। लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, बाराबंकी, हरदोई और उन्नाव के ३० से अधिक मामलों में इस दल की सेवाएँ मांगी गयी और इसने कई मामलों में महत्वपूर्ण सूत्रों का पता लगाया।

लखनऊ जिले के एक मामले में नेशनल कार्बन कंपनी से चोरी गयी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा चोरी के बाद जल्द ही बरामद कर लिया गया।

(ग) राज्य अपराध सूचना-ब्यूरो—राज्य अपराध सूचना ब्यूरो ने अनेक मामलों में अपराध की खोज करने वाले अधिकारियों से सूचनाएँ उपलब्ध कीं। विशेषकर राज्य के भीतर और बाहर के विभिन्न जिलों को आग्नेयास्त्रों तथा अन्य शिनाख्त वाली संपत्ति के बारे में सूचना दी गयी।

(घ) उंगली निशान ब्यूरो तथा वैज्ञानिक शाखा—पहले की भांति उंगली निशान ब्यूरो तथा वैज्ञानिक शाखा ने अपना स्तर ऊँचा बनाये रखा और इसने जिलों में अपराध की तफतीश के लिये बहुमूल्य वैज्ञानिक सहायता पहुँचायी। प्रदर्शन वस्तुओं के परीक्षण के लिये इस शाखा से बराबर भाग बढ़ती रही।

### प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस दल

प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस दल ने अपनी ईमानदारी, शुद्धाचरण, कार्य-कुशलता, अनुशासन और नैतिकता का स्तर ऊँचा बनाये रखा और राज्य के बाहर और भीतर अपनी कार्य-कुशलता का परिचय देता रहा।

प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस का बड़ा दल उत्तर प्रदेश—मध्य प्रदेश—राजस्थान की सीमाओं पर डाकू विरोधी अभियान में लगा रहा। इस दल को विशेषकर कठिन अभियान, घरातलीय बनावट, विषम जीवन दशाओं और खतरनाक परिस्थितियों में अपना कर्तव्य पालन करना पड़ा। सशस्त्र पुलिस दल ने जिला पुलिस को बड़े पैमाने की डकैतियों को सुलझाने में काफी सहायता दी। साथ ही पहले की भांति बड़े-बड़े त्योहारों और इलाहाबाद माघ-मेला जैसे मेलों, विधान-सभा और विधान-परिषद् तथा आने वाले महानुभावों (डिगनीटरीज) से संबंधित कर्तव्यों का पालन भी किया।

### पुलिस रेडियो शाखा

वर्ष में पुलिस रेडियो शाखा का पर्याप्त विस्तार किया गया। शांति और व्यवस्था बनाये रखने, डाकू विरोधी अभियानों, भीड़-भाड़ नियंत्रण, प्रसिद्ध महानुभावों के आगमन, बाढ़-सुरक्षा कार्य आदि की दिशा में यह शाखा बड़ी उपयोगी साबित हुई।

जुलाई, १९६० ने इस शाखा ने उस समय बहुमूल्य कार्य किया, जबकि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के निर्णय के परिणामस्वरूप राज्य की सवहन-व्यवस्था के अस्त-व्यस्त हो जाने का खतरा पैदा हो गया था। इस शाखा ने सरकारी तारों के भेजने और प्राप्त करने का काम किया और सभी विभागों की खबरें भेजीं।

वर्ष के अन्य उल्लेखनीय कार्यों में भारत सरकार के लिये ऋतु विषयक स्टेशन के रूप में अधिक उचाई पर स्थित पंच स्टेशनों का संचालन और लखनऊ में उच्च शक्ति वाले ध्वनि प्रसारक यंत्रों की स्थापना, जिससे सवहन कार्य में काफी सुधार हुआ, सम्मिलित थे।

कारखाना और अनुसंधान एवं विकास शाखा ने वर्ष में अधिक साज-सामान तैयार किया। इस प्रकार लगभग २३ लाख रु० की विदेशी मुद्रा की बचत हुई।

### उत्तर प्रदेश फायर सर्विस

राज्य फायर सर्विस पंच-महानगरियों में कार्य करती रही। इसने अग्निकांडों का मुकाबला करने के साथ ही ढही हुई इमारतों के मलबे से दबे व्यक्तियों और संपत्ति को बचाने का काम भी किया। यह कार्य परिचालन की कठिन दशाओं में संपन्न किया गया।

कानपुर में आगजनी के एक गंभीर मामले में स्थानीय फायर यूनिट ने अनुकरणीय साहस और वीरता का परिचय दिया और राम सरन लाल नामक एक फायरमैन ने अपने कर्तव्य पालन में जान तक गँवा दी।

इलाहाबाद स्थित राज्य फायर सर्विस प्रशिक्षण केन्द्र ने जनता और फायर सर्विस के कर्मचारियों में से चुने गये व्यक्तियों को ट्रेनिंग देने का काम जारी रखा।

### शिक्षा और प्रशिक्षण

वर्ष में मुरादाबाद पुलिस ट्रेनिंग कालेज और सीतापुर ग्रामर्ड ट्रेनिंग सेंटर में पदोन्नति, विशेषज्ञ और रिक्रेशर के कई पाठ्यक्रम चालू किये गये।

मुरादाबाद पुलिस ट्रेनिंग कालेज में वर्ष में कुल ४६० अधिकारियों और व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को अच्छा व्यावहारिक पुलिस अधिकारी बनाने के उद्देश्य से बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार की ट्रेनिंग पर विशेष बल दिया गया।

प्राविधिक पुलिस विषयों को यथोचित महत्व देना जारी रखा गया। इसके अतिरिक्त सामान्य ज्ञान के विषयों और व्यावहारिक पुलिस प्रणाली के मान्य अधिकारियों द्वारा लेक्चरों की व्यवस्था की गयी। पुलिस अधिकारियों में सच्चाई और ईमानदारी के महत्व पर भी बल दिया गया। पैर और उंगलियों के निशान और अंगूठे के निशान उठाने की व्यावहारिक ट्रेनिंग देने की विशेष व्यवस्था की गयी।

ग्रामर्ड ट्रेनिंग सेंटर राज्य पुलिस की सशस्त्र शाखा के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने के साथ ही समस्त प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस यूनिट को ट्रेनिंग देने के लिए "ड्राफ्टिंग यूनिट" भी बन गयी।

### कल्याण कार्य

पुलिस कर्मचारियों और उनके परिवारों को अधिकाधिक सुविधा देने के प्रयास जारी रहे। पुलिस कर्मचारियों के परिवारों को सांस्कृतिक, शैक्षिक और व्यावसायिक ट्रेनिंग देने की ओर भी ध्यान दिया गया। यह कल्याण योजना पुलिस वालों के बच्चों और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध हो रही थी।

सभी जिलो और यूनियो में परिवार कल्याण केन्द्र चालू रहे। इन केन्द्रों में पुलिस अधि-कारियों और कर्मचारियों की पत्नियों को चित्रकारी, बुनाई, सिलाई और कसीदाकारी आदि की ट्रेनिंग दी जाती थी, जो उनके लिये आर्थिक दृष्टि से भी लाभदायक थी।

शिमला में आयोजित अखिल भारतीय कल्याणकारी प्रदर्शनी और सांस्कृतिक सम्मेलन में 'चैम्पियनशिप' ट्राफी (विजेता ट्राफी) उत्तर प्रदेश ने जीती। इसमें कला और हस्त-शिल्प संबंधी २८ व्यक्तिगत इनाम उत्तर प्रदेश ने जीते थे। सांस्कृतिक प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश पुलिस टीम "रनर्स-अप" में आयी और उसने १४ इनाम जीते।

पुलिस दल में आत्म-सहायता की भावना के उदय और विकास से ठोस परिणाम निकलते रहे। सभी जिलो/यूनियो में पुलिस इमारतों के निर्माण, मरम्मत और रख-रखाव श्रमदान के आधार पर करके दूसरा उपयोगी कार्य किया गया, जिससे काफी मात्रा में सरकारी रकम की बचत हुई। सभी जिलो/यूनियो में वन-महोत्सव के अवसर पर वृक्षारोपण किया गया और विभिन्न पुलिस लाइनो, थानो और चौकियों के अहातों को आकर्षक बनाने के प्रयास किये गये।

### पुलिस इमारतें

पुलिस-इमारतों की दशा में सुधार और पुलिस कर्मचारियों के लिए आवास-व्यवस्था करने संबंधी राज्य सरकार के प्रयत्न जारी रहे। आलोच्य वर्ष में ५८,२०,५०० रु० की पूजी-लागत की नयी इमारतों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी। इनमें चौदहवीं बटालियन, कानपुर प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस दल, आठवीं बटालियन, बरेली प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस दल, देहरादून रिजर्व पुलिस लाइंस, मेरठ कोतवाली आदि के लिए नयी बनायी जाने वाली इमारतें शामिल थीं।

### पुलिस ड्यूटी सम्मेलन

आठवा अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी सम्मेलन, सीतापुर में आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के पुलिस दलों ने रिवाल्वर और बन्दूक चलाने की प्रतियोगिताओं, प्राथमिक सहायता प्रतियोगिताओं, वैज्ञानिक सहायता प्रतियोगिताओं और बेतार के तार की प्रतियोगिताओं में भाग लिया। प्राथमिक सहायता एम्बुलेंस ड्रिल में उत्तर प्रदेश पुलिस दल ने चैम्पियनशिप जीती। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य-मंत्रों ने किया था और इनाम वितरण राज्यपाल द्वारा किया गया। जीवन-रक्षा के लिये पौड़ी-गढ़वाल के थानेदार श्री मोहनसिंह डगवाल और हमीरपुर जिले के पुलिस ड्राइवर श्री जैनुल आबदीन को प्रधान मंत्री पदक इनाम मिले।

### पुलिस वालों को इनाम

राज्य के चार पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस तथा आगजनी सेवा पदक और अन्य ८ व्यक्तियों को पुलिस पदक उनकी बहादुरी के लिए प्रदान किये गये। दीर्घकालिक और अद्वितीय सेवाओं के लिये दो अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस तथा आगजनी सेवा पदक और अन्य १० पुलिस जनों को उनके कुशल कार्य के लिये पुलिस पदक दिये गये। एक अधिकारी को राज्य-पाल स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ।

### वित्तीय पहलू

वर्ष में पुलिस संगठन के लिए ६,८५,६५,६०० रु० का बजट अनुदान दिया गया, जो १६५६-६० के वित्तीय-वर्ष की तुलना में ४४.११ लाख रु० अधिक था। यह वृद्धि प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस की एक बटालियन बढ़ाने और चम्बल के खारो में डाकू-विरोधी अभियान को प्रगाढ़ करने के कारण की गयी। शांति व्यवस्था को अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से कायम रखने के उद्देश्य से वर्ष में कई पुलिस चौकियाँ और थाने खोले गये। यातायात की समस्या आसान करने के विचार

से गाड़ियों की खरीद के लिए अधिक धनराशि का प्राविधान किया गया । राज्य-राजस्व और धन का जहा तक सबध है पुलिस बजट का प्रतिशत क्रमशः ७.५३ और ७.४० था और पुलिस पर प्रति व्यक्ति खर्च १.३ रु० था ।

## २—सार्वजनिक जुआ अधिनियम आदि\*

### सार्वजनिक जुआ अधिनियम का विस्तार

सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धाराएँ ३ और ४ का विस्तार उन्नाव, बाराबकी और बलिया जिलों के कतिपय क्षेत्रों में किया गया ।

### सब-रजिस्ट्रार, मैजिस्ट्रेट और अवैतनिक मैजिस्ट्रेट

कुछ सब-रजिस्ट्रार, जिन्हें द्वितीय श्रेणी मैजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त थे, वर्ष में फौजदारी के मामलों का फौसला करते रहे । अवैतनिक मैजिस्ट्रेट भी फौजदारी के मामलों को निपटाने में सहायता देते रहे ।

## ३—बन्दीगृह\*

### सामान्य

१९६० में नैनीताल जिला स्थित सितारगंज में एक शिविर और खोला गया, जिसे संपूर्ण-नन्द कृषि एवं औद्योगिक शिविर की सजा दी गयी । इस प्रकार विभाग के अधीन जेलों और अन्य संस्थाओं की संख्या ६३ हो गयी ।

### जन-संख्या

जेल की आबादी में थोड़ी कमी परिलक्षित हुई । १ जनवरी को जहा कैदियों की संख्या ३४,९१२ थी, वहा ३१ दिसम्बर को कैदी संख्या ३४,५५६ रह गयी । जेलों की प्रति दिन आबादी का औसत ३५,५१७ था, जबकि १९५९ के वर्ष में यह औसत ३५,८२९ था ।

### अनुशासन और स्वास्थ्य

कैदियों में अनुशासन बना रहा और कुल मिलाकर उनका स्वास्थ्य भी अच्छा था । वर्ष में पुराने कैदियों द्वारा किये गये अपराधों की संख्या ४०२ थी, जबकि पूर्वगामी वर्ष में ५०२ अपराध किये गये थे । वर्ष १९५९ के ७,५५२ अपराधों की तुलना में सामान्य और पुराने कैदियों द्वारा वर्ष में ६,६९१ अपराध किये गये ।

वर्ष में छोड़े गये कैदियों में ९४ १२ प्रतिशत की तदुरुस्ती अच्छी, ५.६० प्रतिशत का स्वास्थ्य साधारण और ०.२८ प्रतिशत की तदुरुस्ती खराब थी । वर्ष में दाखिल हुए कैदियों के सबध में ये आंकड़े क्रमशः ९१.५३ प्रतिशत, ७.९७ प्रतिशत और ०.५० प्रतिशत थे ।

### इमारतें

वाडरों के लिये ११ जिलों में ४४ नये क्वार्टरों का निर्माणकार्य आरम्भ किया गया । सुल्तानपुर जिला जेल में तपेदिक से ग्रस्त कैदियों और बिना तपेदिक वाले कैदियों के लिए अतिरिक्त आवास की तथा कच्चे गोदामों के स्थान पर पांच नये गोदामों की व्यवस्था की गयी । बारह जेलों और घुर्मा स्थित संपूर्णनन्द शिविर के २७ बैरकों की छत ए० सी० शीटों से पुनः डाली गयी ।

आगरा, गाजीपुर और उन्नाव के जिला जेलों में अस्पताल के वाडों में बिजली लगायी गयी । घुर्मा स्थित संपूर्णनन्द शिविर तथा २२ जेलों के लिए ५२ सीलिंग पंखे और ४ टेबुल पंखे खरीदे गये ।

\*कैलेडर वर्ष १९६० से संबधित ।

१ बरेली सेंट्रल जेल और सुल्तनपुर जिला जेल के लिये पलश पाखानों की व्यवस्था की जा रही थी ।

### कृषि

१९५६-५७ के वर्ष में ४ सेंट्रल जेलों और ७ जिला जेलों के ११ फार्मों में अनाज, चारा, सब्जी और गन्ने की उपज क्रमशः २,६१६ मन, ३१,६६० मन, ५,७२६ मन और २,०४० मन थी । सितारगज स्थित संपूर्णानन्द कृषि एवं औद्योगिक शिविर से संबंधित वर्ष १९६० के आंकड़े इस प्रकार थे :—

	मन		मन
अनाज ..	१०,१७२	सब्जिया ..	४५४
चारा ..	२६,४००	गन्ना ..	७,०००

(उक्त मदों में किसानों से प्राप्त रबी फसल और शिविर में बोयी गयी खरीफ भी सम्मिलित है) ।

### नये उद्योग

जेल के लिए कई नये उद्योग स्वीकृत किये गये । इन नये उद्योगों और जेलों के नाम, जिनके लिये वे स्वीकृत हुए, नीचे की तालिका में दिये गये हैं —

१—साबुन और फिनायल ..	..	आगरा सेंट्रल जेल
२—खेल-कूद के साधारण सामान ..	..	बरेली सेंट्रल जेल
३—पेंसिल ..	..	किशोर सदन, बरेली
४—काच की गुड़िया ..	..	नारी बंदी निकेतन, लखनऊ
५—प्लम्बरिंग ..	..	नैनी सेंट्रल जेल
६—रगई, ब्लीचिंग और कैलिको प्रिंटिंग ..	..	फतेहगढ़ सेंट्रल जेल ।

### गुड़ और सरसों का तेल

मेरठ जिला जेल में लगाये गये वर्धा किस्म के दो कोल्हुओं से वर्ष में १५४ मन शुद्ध घरसों का तेल कैदियों के उपभोग के लिए तैयार किया गया और ३०६ मन सरसों की खली उपलब्ध हुई । इसी जेल में कैदियों के इस्तेमाल के लिए १६४ मन गुड़ बनाया गया ।

### सिलाई कारखाना

वर्ष में उन्नाव जिला जेल को राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों के विभिन्न विभागों से ४,२२,००० पोशाकें तैयार करने के आर्डर मिले और ३,४०,००० पोशाकें सिली गयीं ।

### सिलाई मशीनों की मरम्मत का कारखाना

उन्नाव जिला जेल में सिलाई मशीनों की मरम्मत का कारखाना खोला गया । इस कारखाने में सिलाई मशीनों के छोटे-मोटे पुर्जों का निर्माण आरंभ कर दिया गया है ।

### जेल डिपो

वर्ष में लखनऊ जेल डिपो ने १६,४८७ रु० ५० न० ५० के मूल्य का सामान बेचा ।

### अंबर चर्खा

कपड़े के मामले में जेलों की आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कैदियों द्वारा अंबर चर्खों के उपयोग और खादी बुनाई की योजना को प्रगाढ़ रूप दिया गया । जेलों में कुल ७७५ अंबर चर्खों का उपयोग किया जा रहा है :



अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने पूरा-पूरा सहयोग दिया और कैदियों को ट्रेनिंग देने के लिए निम्नांकित कर्मचारियों और साज-सामान आदि की व्यवस्था की :—

अम्बर चर्खे	..	४००	..	कर्वे	१००
अम्बर चर्खा शिक्षक	..	२१	..	बुनाई गाइड	६
अम्बर चर्खा मर-मत के लिए कारखाना	१	..			

उक्त शिक्षक और गाइड ११ विभागीय शिक्षकों और एक सुपरवाइजर के साथ मिला कर इस योजना के अधीन कार्य करते रहे । मेरठ जिला जेल के अम्बर विद्यालय में भी २५ कैदियों को योग्य शिक्षक बनाने हेतु प्रशिक्षित किया गया । खादी आयोग के निरीक्षण अधिकारी ने जेलों में अम्बर-चर्खा कार्य का निरीक्षण किया और सुधार के लिए उपयोगी सुझाव दिये ।

१९६० के वर्ष के उत्पादन का विवरण इस प्रकार है :—

अम्बर चर्खों से खादी सूत का उत्पादन	..	४८६ मन २८ सेर ११ छटाक
खादी दोमूतिया (धारीदार)	.	५३,२१० गज
खादी (सादा)	..	१५,००४ गज
खादी चादरे	..	७,५५१
खादी गमछे	..	१,२६०
खादी के तागे की कर्वे वाली आसलिया	.	५
खादी के तागे की कर्वे वाली दरिया	.	५

### महिला कैदियों का प्रशिक्षण

महिला कैदियों के लिए उपयोगी रोजगार की समस्या को हल करने के उद्देश्य से प्रयोगात्मक आधार पर उन्नाव जिला जेल में सिलई का कुल काम लखनऊ नारी निकेतन को स्थानांतरित किया गया । ऐसा अनुभव किया गया कि महिला कैदी इस कार्य में विशेष रुचि ले रही थी । नैनी सेटल जेल की महिला कैदियों के लिए सिलई और बुनाई की एक योजना आरम्भ की गयी । इसके लिए एक महिला शिक्षक की नियुक्ति की गयी । लखनऊ नारी निकेतन की महिला कैदियों ने कांच की गुरियों के निर्माण का काम शुरू कर दिया ।

### खुले शिविर की व्यवस्था

जेलों में आने वाले अधिकांश कैदी पेशे से किसान थे। ऐसे कैदियों को खेतीवारी के काम से लगाने में एक समस्या उनकी सुरक्षा की थी । उन्हें जहारदीवारी से घिरे जेलों में रहना पड़ता था, जहाँ खेती के लिए काफी जमीन की व्यवस्था नहीं की जा सकती थी । कैदियों के खुले शिविरो (सम्पूर्णानन्द शिविर) में काम देने की योजना की, जो १९५२ में आरम्भ की गयी थी, सफलता से कैदियों को खुले स्थानों में रखने के प्रति सामान्यतः जो भय बना रहता था, वह दूर हो गया । यह योजना कैदियों में उत्तरदायित्व की भावना और कड़ी मेहनत करके अपनी रोजी कमाने की इच्छा का विकास करने में भी सफल साबित हुई । इससे प्राप्त सफलता से कैदियों को कृषि फार्मों में काम देने के मार्ग की रुकावट दूर हो गयी । फलतः एक नया शिविर खोलने का निश्चय किया गया । इसके लिए जिला नैनीताल स्थित सितारगज में ३,००० एकड़ भूमि उपलब्ध की गयी, जहाँ १९ फरवरी, १९६० को सौ कैदियों से सम्पूर्णानन्द कृषि एवं औद्योगिक शिविर का समारम्भ किया गया । आगे चलकर यह तय किया गया कि पास ही ३,००० एकड़ से अधिक खाम जमीन और वन क्षेत्र उपलब्ध किया जाय, ताकि ६,००० एकड़ का फार्म बनाना संभव हो सके, जहाँ कैदियों को अपनी रुचि के काम में लगने और आधुनिक कृषि-फार्मों विषयक ज्ञान प्राप्त करने के अतिरिक्त कैदियों के उपभोग के लिए अनाज भी पैदा किया जा सके । पहली,

दफ्ता २,००० एकड़ क्षेत्र में खेती की गयी और शिविर की कैदी संख्या १ अप्रैल, १९६० से ५०० बढ़ा दी गयी। बाद में यह विभिन्न कारणों से आवश्यक समझा गया कि इसी वर्ष अगस्त १,००० एकड़ में भी खेती-बाड़ी शुरू की जाय और उसके लिए अक्टूबर, १९६० से कैदी-संख्या बढ़ाकर ८०० कर दी गयी। इसके लिए अतिरिक्त साज-सामान और कर्मचारियों की स्वीकृति दी गयी। वर्ष समाप्त होते-होते लगभग ३,००० एकड़ भूमि में कृषि-कार्य शुरू कर दिया गया। शेष जमीन को (३,००० एकड़) धीरे-धीरे कृषि योग्य बनाकर खेती-बारी के काम में लाने का विचार था। कैदियों को शिविर में आरम्भ किये गये कृषि और औद्योगिक कार्यों में लगवाया गया। शिविर में काम करने वाले कैदियों को बिचने आवश्यक जेल सेवाओं में लगे कैदी भी सम्मिलित थे, प्रति व्यक्ति प्रति दिन २५ नये पैसे की दर से मजदूरी दी गयी। इस शिविर में मुख्यतः तरीको पर पिन्की-जूली किस्म की खेती अर्थात् कुछ क्षेत्र में मशीनों और कुछ क्षेत्र में पैंनों द्वारा खेती करने का निश्चय किया गया। जो कैदी पैसे से खेतिहर थे, उन्होंने इस काम के प्रति विशेष रुचि दिखायी। इन कैदियों को बड़ईगरी, लोहारगरी, ईंट पकाने, कतारई, बुवाई, गुड़ बनाने आदि उपयोगी कुटीरउद्योगों में प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव था, ताकि कैद से उठने के बाद उन्हें अपनी प्राथमिक स्थिति सुधारने में सहायता मिल सके। साथ ही उन्हें पशुपालन, मुर्गपालन और दुग्धशाला सवधी ट्रेनिंग देने का भी प्रस्ताव था। जून, १९६० में १ लाख ८० मूल्य का गेहूँ उपजाया गया।

मिर्जापुर जिला स्थित घुर्मा मरकुंडी और नैनीताल जिले के मंझोला शिविरों का काम भी वर्ष में चालू रहा। घुर्मा मरकुंडी शिविर में ८०० कैदी थे, जो चूर्क सीनेट फैक्टरी के लिये पत्थरों की खुदाई में लगाये गये थे। जनवरी से दिसम्बर, १९६० की अवधि में इस शिविर के बांशिदों ने ४,६८,०१६ रु० ३५ न० ५० मजदूरी के रूप में कमाया और अपने रख-रखाव के खर्च के रूप में राज्य को २,४६,८६० रु० अदा किये। मंझोला शिविर में शारदा-देवहा पूरक नहर के निर्माण पर औसतन १,२६१ कैदियों को लगाया गया था, जिन्होंने जनवरी से दिसम्बर, १९६० की अवधि में ४,१०,१७६ रु० ८० न० ५० मजदूरी के रूप में कमाये और राज्य को अपने रख-रखाव का खर्च २,१६,६५५ रु० ५० न० ५० अदा किये।

शिविरों के दो सौ दो कैदियों को घर जाने की छुट्टी दी गयी, किन्तु इस सुविधा का किसी ने दुरुपयोग नहीं किया।

### तराई राजकीय फार्म में कैदियों का नियोजन

पूर्वजानी वर्ष की भांति कैदियों के दो दलों को एक साल के पैरोल पर छोड़ा गया। पहले दल में २६ कैदी थे और दूसरे में १८ कैदी। इन्हें क्रमशः २४ फरवरी, १९६० और ३० नवम्बर, १९६० को तराई राजकीय फार्म, पत्तनगर, फूलबाग (जिला नैनीताल) में काम करने के लिए भेजा गया। यहाँ पर कैदी काल के अनुसार मजदूरी के आधार पर रखे गये। इनके ऊपर किसी प्रकार की निगरानी और पहरे नहीं था और ये स्वतंत्र मजदूर की भांति काम करते रहे। नियमानुसार पैरोल पर भेजे गये कैदियों को यदि वे चाहे अपना परिवार साथ रखने की अनुमति दी गयी। साथ ही उन्हें अधिकारियों से अनुमति लेकर कुछ दिनों के लिए अपने परिवार वालों से मिलने की भी छुट दी गयी। वर्ष में कृषि भिला कर पैरोल पर भेजे गये कैदियों का काम और आचरण सतोषजनक रहा। योजना के अधीन यह प्राविधान भी किया गया कि यदि कैदी का काम और आचरण बराबर सतोषजनक बना रहाने पर पैरोल की एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पर उसको अवश्य मुक्त कर दिया जायगा।

## किशोर सदन, बरेली

१९६० में बरेली किशोर सदन की औसत दैनिक आबादी १६२ थी, जबकि वर्ष १९५६ में यह संख्या १६० थी। चौदह बच्चों को घर जाने की छुट्टी दी गयी और वे सभी समय से वापस आ गये। पांच किशोर कैदी बाहर स्कूलों और कालेजों में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। दो लड़कों ने स्नातक परीक्षा में सफलता पायी। सदन के ३५ निवासियों को बाहरी संस्थाओं में नौकरी करने का अवसर दिया गया और वर्ष में उन्होंने १५,३३१ रु० १६ न० पै० कमाया। बग नौर में आयोजित अखिल भारतीय स्काउट जम्बूरी में १०० लड़कों ने भाग लिया। वहां इनके प्रदर्शनों को पसंद किया गया।

१६ मई, १९६० को भारत के राष्ट्रपति बरेली किशोर सदन में गये। इसके पहले भारत सरकार के परराष्ट्र मंत्रालय के उप-मंत्री सदन में आये थे।

## रिफार्मेंटरी स्कूल, लखनऊ

वर्ष में लखनऊ रिफार्मेंटरी स्कूल की औसत दैनिक आबादी ४२ रही जबकि १९५६ में यह औसत ४६ का था। इस स्कूल का एक लड़का हाई स्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ और दूसरे लड़क को वोक्शेनल कालेज, लखनऊ में कक्षा ७ की पढाई जारी रखने की अनुमति दी गयी। दो लड़कों को घर जाने की छुट्टी मिली। इस स्कूल के लड़कों की नकद कमाई १,४५६ रु० हुई इनमें १,४१७ रु० जो उन्होंने स्कूल बैंड बजाकर कमाया था शामिल है।

## आमोद-प्रमोद

लखनऊ जिला जेल में एक योजना चल रही थी (जो इस उद्देश्य से चालू की गयी थी कि शाम को ताले पड़ जाने के बाद सोने के पूर्व तक के समय का लाभदायक उपयोग किया जा सके, न कि उन्हें अपने अपराधों के बारे में सोचने के लिए छोड़ दिया जाय)। जिसके अधीन ६ बजे शाम को ताले पड़ जाने के बाद ६ बजे रात तक अच्छे आचरण वाले लड़कों को वाद्य और गान, संगीत, कमरे में खेले जाने वाले खेलों आदि का अभ्यास करके मनोरंजन करने की अनुमति दी जाती थी। यह प्राविधान किया गया कि अनुशासकीय और प्रशासकीय आवश्यकताओं को देखते हुए अच्छे आचरण वाले कैदियों को चुना जाय और उन्हें एक बड़े बेरक में बंद किया जाय, जहां आमोद-प्रमोद के लिये आवश्यक सामानों को रखने हेतु दो आलमारिया दी जाय। कैदियों को उनके व्यसनो के अनुसार छोटी-छोटी टुकड़ियों में बाटा जाना था। इनमें से एक कैदी को उनका सरगना बनाकर सामानों के रख-रखाव की जिम्मेदारी उसी पर डाल दी जाय। कैदियों को निम्नलिखित वाद्यों और कमरे में खेले जाने वाले खेलों के सामान की व्यवस्था की गयी :—

१—हारमोनियम	६—ढोलक
२—तबला	७—बासुरी
३—मंजीरा	८—बेंजो
४—करताल	९—कैरम बोर्ड
५—गुंघरू	१०—शतरंज

## दंड में छूट

२ अक्टूबर १९६० को गांधी जयन्ती के अवसर पर सरकार कतिपय वर्गों के कैदियों को बकाया कंदा की अवधि में छूट देने का आदेश किया। इसके फलस्वरूप राज्य की विभिन्न जेलों से लगभग २,५०९ कैदी मुक्त किये गये।

## अध्याय ४

### विधि-निर्माण

#### १—विधि-निर्माण का क्रम

अनेक वैधानिक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित होने तथा राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत होने के बाद उत्तर प्रदेश अधिनियम बने। १९६०-६१ में जिन प्रस्तावों को विधि-सहिता में दर्ज किया गया, वे थे:—

१—उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, १९६० (१९६० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १०)।

२—उत्तर प्रदेश (भवन निर्माण-कार्यों का नियमन) (संशोधन) अधिनियम, १९६० (१९६० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ११)।

३—उत्तर प्रदेश उत्तराखंड (एप्लीकेशन आफ लाज़) अधिनियम, १९६०, (१९६० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १२)।

४—सरकारी अनुदान (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६० (१९६० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३)।

५—उत्तर प्रदेश परिचारिका, दाई, सहायक दाई और स्वास्थ्य निरीक्षिका पंजीयन अधिनियम, १९६० (१९६० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १४)।

६—उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, १९६० (१९६० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १५)।

७—मुस्लिम वक्फ अधिनियम, १९६० (१९६० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १६)।

८—कुमाऊं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९६० (१९६० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १७)।

९—उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५६-५७ के बढोत्तरियों का नियमन) अधिनियम, १९६० (१९६० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १८)।

१०—उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०-६१ प्रथम पूरक) अधिनियम, १९६० (१९६० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १९)।

११—न्यूनतम मजदूरी (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६० (१९६० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २०)।

१२—भारतीय वन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६० (१९६० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २१)।

१३—उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा निर्धारण अधिनियम, १९६० (१९६१ का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १)।

१४—उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०-६१ का) द्वितीय पूरक) अधिनियम, १९६१ (१९६१ का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २)।

१५—उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, १९६१ (१९६१ का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३)।

१६—कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६१ (१९६१ का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ४)।

१७—उत्तर प्रदेश निष्क्रांत हित (पृथक्करण) पूरक अधिनियम, १९६१ (१९६१ का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५)।

१८—उत्तर प्रदेश अंतरिम जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, १९६१ (१९६१ का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ६)।

१९—उत्तर प्रदेश पूर्ति नियंत्रण (अस्थायी अधिकार) (संशोधन) अधिनियम, १९६१ (१९६१ का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ७)।

२०—उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मंडल के अधिकारी, मंत्री, उपमंत्री और सभा-सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९६१ (१९६१ का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८)।

२१—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ (१९६१ का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ९)।

२२—उत्तर प्रदेश भूमि-कानून (संशोधन) अधिनियम, १९६१ (१९६१ का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १०)।

२३—उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट बिक्रय-कर (संशोधन) अधिनियम, १९६१ (१९६१ का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ११)।

२४—उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखों पर मतदान) अधिनियम, १९६१ (१९६१ का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १२)।

विधान-मंडल के सत्रावसान की अवधि में राज्यपाल द्वारा निम्नांकित ७ अध्यादेश जारी किये गये —

१—उत्तर प्रदेश निष्क्रांत हित (पृथक्करण) पूरक अध्यादेश, १९६० (१९६० का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १)।

२—कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९६० (१९६० का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २)।

३—उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९६० (१९६० का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ३)।

४—उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मंडल अधिकारी, मंत्री, उपमंत्री, तथा सभा सचिव (वेतन, भत्ते तथा प्रकीर्ण) अध्यादेश, १९६० (१९६० का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ४)।

५—उत्तर प्रदेश अंतरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६० (१९६० का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ५)।

६—उत्तर प्रदेश पूर्ति नियंत्रण (अस्थायी अधिकार) अध्यादेश, १९६१ (१९६१ का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १)।

७—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अध्यादेश, १९६१ (१९६१ का उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २)।

इन सभी अध्यादेशों को बाद में विधान मंडल से अधिनियमित कर दिया गया।

## अध्याय ५

### न्याय प्रशासन

#### १—अदालतें

\*न्याय (क) विभाग दीवानी न्याय प्रशासन, दीवानी कानून, अपराधियों को छोड़ने के विरुद्ध सरकारी अपीलों और दंडित कैदियों की जीवन-रक्षा याचिकाओं संबंधी कार्य करता रहा। साथ ही इस विभाग ने उच्च न्यायालय और अधीनस्थ दीवानी तथा सेशस अदालतों के बजट, कर्मचारी और इमारतों तथा अन्य विभिन्न प्रशासकीय विषयों संबंधी कार्य भी किया।

पूर्वगामी वर्ष की भांति कानूनों में संशोधन से संबंधित कार्य सीमित थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश न्याय सुधार समिति की सिफारिशों पर कतिपय जाबने से संबंधित कानूनों में पहले संशोधन कर दिये गये थे और मौजूदा कानूनों में भारत सरकार द्वारा नियुक्त कानून आयोग ने पुनरीक्षण कार्य आरंभ कर दिया था। कानून आयोग की विभिन्न रिपोर्टों पर विचार किया गया और उनमें से कुछ के बारे में राज्य सरकार ने अपना दृष्टिकोण और विचार भारत सरकार को भेज दिये थे।

उत्तर प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में भ्रष्टाचार के कारणों की खोज-बीन समिति ने, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की गयी थी, जाबने सत्रवी तथा अन्य कानूनों का इस दृष्टि से परीक्षण किया कि यह पता लगाया जा सके कि इनमें भ्रष्टाचार, मुकदमों में अधिक खर्च, अनावश्यक विलंब और परेशानियों को कहा तक प्रश्रय मिलता था और इस बात का सुझाव दे कि उनमें ऐसे कौन से परिवर्तन किये जाय जिससे, इन बुराइयों को दूर करने में सहायता मिले।

#### २—दीवानी न्याय\*

##### (क) उच्च न्यायालय

न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या २४ थी और ३ अतिरिक्त न्यायाधीश भी थे। वर्ष में वस्तुतः औसतन २६ न्यायाधीश कार्य करते रहे।

उच्च-न्यायालय में दायर होने वाले सभी किस्मों के मुकदमों की संख्या ३०,०५७ से घट कर २६,६१४ हो गयी। मुकदमों के फैसलों की संख्या पूर्ववर्ष के २८,७२२ से घट कर २७,७१२ रह गयी।

उच्च-न्यायालय के समक्ष निर्णीत होने वाली नियमित अपीलों की संख्या ३०,५६४ थी, जबकि पूर्व वर्ष में यह संख्या २८,०२५ रही। वर्ष में कुल ७,२८७ अपीलों दायर हुईं, जबकि पूर्व वर्ष में ६,६०३ अपीलों दायर हुई थीं। अपील में किये गये फैसलों के विरुद्ध अपीलों की संख्या ५,५२६ से बढ़ कर ६,१६६ हो गयी और उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के फैसलों की अपीलों की संख्या ६३१ से बढ़ कर ६५० हो गयी। किन्तु मूल फैसलों की अपीलों की संख्या ७४६ से घट कर ४६८ हो गयी।

---

\*१९६० के कैलेंडर वर्ष से सम्बन्धित।

वर्ष में अदालत द्वारा निर्णीत सभी प्रकार के मामलों की संख्या ४,७५६ थी, जबकि पूर्व वर्ष में ४,७१८ मामले में फैसला दिया गया था। अदालत के मूल फैसलों के विरुद्ध अपील की संख्या पूर्वगामी वर्ष के ७३७ से घट कर ५७३ हो गयी और अपील में फैसले के विरुद्ध अपील, जिनमें फैसले किये गये, की संख्या ३,५०५ से बढ़ कर ३,६३६ हो गयी। एक न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपील की संख्या ५४७ थी, जबकि पूर्व वर्ष में ४७६ अपील में फैसला किया गया था।

वर्ष के अन्त में अनिर्णीत अपील की संख्या २५,८३८ थी, जबकि पूर्वगामी वर्ष में यह संख्या २३,३०७ थी।

#### फुल बेंच के हवाले

फुल बेंच के सामने हवाले के मामले की संख्या ४९ थी, जिसमें १३ पूर्व वर्ष के अनिर्णीत मामले थे। इनमें से २१ का फैसला किया गया और वर्ष के अन्त में २८ मामले अनिर्णीत रहे।

#### बकाया

वर्ष में उच्च-न्यायालय में सभी प्रकार के मामलों की बकाया संख्या में २,२०२ की वृद्धि हुई।

#### इमारतें

कतिपय आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के प्रश्न पर ध्यान दिया गया। एडवोकेटों के लिए मोटर गाड़िया खड़ी करने के स्थान और एक साइकिल स्टैंड के निर्माण के नक्शे और धन स्वीकृत किये गये।

#### (ख) दीवानी अदालतें

अधिकार क्षेत्र—उच्च-न्यायालय की अधीनस्थ दीवानी अदालतों के अधिकार क्षेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ।

दायर किये गये मुकदमों—अधीनस्थ अदालतों में दायर किये गये मुकदमों की संख्या ८१,८४७ से घट कर ७४,९५८ हो गयी। जिनमें इन्कम्बर्ड स्टेट ऐक्ट, १९३४ और पंचायत राज अधिनियम, १९५० के अधीन दायर किये गये मामले नहीं शामिल हैं, किन्तु कृषक सुविधा अधिनियम, १९३४ के अधीन दायर किये गये मामले शामिल हैं।

अचल संपत्ति से संबंधित मामले में २,४९३ की कमी हुई (१९,०११ से घटकर, १६,५१८)। इसका मुख्य कारण उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की कतिपय धाराओं के अधीन मामले का अधिकार-क्षेत्र बदल जाना तथा न्याय-पंचायतों में इन अधिकारों का निहित होना था, जिसके फलस्वरूप कतिपय मामले जिनका निर्णय दीवानी अदालत में होना था, उन्हें माल अदालतों अथवा न्याय पंचायतों के क्षेत्र में ला दिया गया।

अधीनस्थ अदालतों में दायर किये गये मुकदमों के मूल्यों का अन्तर निम्न प्रकार था :—

अदालतें	अन्तर
मुंसिफी अदालतों में	१७,४३,१७७ रु० की कमी
खफीफा अदालतों में	१,८६,४१३ रु० की कमी
सिविल जज की अदालतों में	२१,७२,५४७ रु० की वृद्धि
जिला जज की अदालतों में	४,८६,४३३ रु० की वृद्धि

समस्त अदालतों में मुकदमों के मूल्य में ७,२६,३८६ रु० की वृद्धि हुई।

### • मुकदमों का निर्णयन

निर्णीत मामलों की संख्या (स्थानांतरणों के मामले) में १७,१६८ रु० की कमी हुई (१,२०,५८२ से घट कर १,०३,३८४)। मुकदमों के दायर होने की संख्या की अपेक्षा मुकदमों के निर्णय की संख्या अधिक रही। जिन मामलों में निर्णय होता था, उनकी संख्या में ४१,००० की कमी हुई (२,४६,६६२ से घट कर २,०८,८६२)। पूरी सुनवाई के बाद निर्णीत मामलों की संख्या १६५६ के ३५,३८५ मामलों की तुलना में ३४,५६६ थी।

पूरी सुनवाई के अलावा अन्य प्रकार से निर्णीत मामलों की संख्या (स्थानांतरण द्वारा निपटायें गये मामलों को छोड़कर) ६८,७८५ थी।

जिला जजों द्वारा पूरी सुनवाई के बाद निर्णीत मूल मुकदमों की संख्या ६८ से घट कर ८७ हो गयी। पुनः यह देखा गया कि जिला जजों की दीवानी कार्यों में कम समय लगाने का अवसर मिलता था। उनके पास बहुत बड़ी संख्या में सेशन के मुकदमों, फौजदारी अपीलों और चुनाव याचिकाओं का काम बड़ी मात्रा में बकाया पड़ा था।

सिविल जजों द्वारा निपटायें गये नियमित और खकीफा अदालत के मुकदमों की कुल संख्या (स्थानांतरण द्वारा निपटायें गये मामलों को छोड़कर) में १,६४६ की कमी हुई और पूरी सुनवाई के बाद इस प्रकार के निर्णीत मामलों की संख्या में भी २५१ की कमी हुई (२,७६८ से घट कर २,५१७)। मुसिकों द्वारा निपटायें जाने वाले इस किस्म के मामलों में १५,२६८ की (८८, ६७१ से घट कर ७३, ७०३) तथा फुल बैच द्वारा निर्णीत ऐसे मामलों में ६३६ की कमी हुई (२६,२६२ से घट कर २८,३२३)।

### कालावधि

मुसिक की अदालतों में पूरी सुनवाई के बाद निर्णीत मामलों की कालावधि पूर्व वर्ष के ६११ दिनों की तुलना में घटकर आलोच्य वर्ष में ३६३ दिन और सिविल जजों की अदालतों में यह अवधि ६६६ दिनों से घट कर ६७३ दिन हो गयी। जिला जजों की अदालतों में यह कालावधि ५६७ दिन से बढ़कर ६७७ दिन हो गयी। राज्य में सभी प्रकार के मामलों की पूरी सुनवाई के बाद निर्णीत मामलों की औसत कालावधि ५४५ दिन से घटकर ३७३ दिन हो गयी। यह देखा गया कि सिविल जजों और जिला जजों की अदालतों में एक मुकदमे को निपटाने में एक वर्ष से कहीं अधिक समय लगता था।

### अपीलें

अधीनस्थ अदालतों में दायर की गयी नियमित और लगान अपीलों की संख्या में ७३८ की वृद्धि हुई (१६,४८५ से बढ़कर २०,२२३)। अदालतों के समक्ष निपटायें जाने वाले मुकदमों की कुल संख्या में ४,७३२ की कमी हुई (७०,१८४ से घट कर ६५,४५३)। स्थानांतरणों के निपटायें गये मामलों की संख्या ४६० से बढ़ी (२२,१४२ से २३,६३२), फिर भी निपटायी गयी अपीलों की संख्या निपटायी जाने वाली अपीलों की १/३ थी, जिन अपीलों को निपटारा गया उनकी संख्या दायर की जाने वाली अपीलों की तुलना में अधिक थी। निपटारे के लिए दायर की जाने वाली नियमित दीवानी अपीलों की संख्या में ५,६३३ की कमी हुई (६४,१५४ से घट कर ५८,६२१)। इनमें २१,६०६ अपीलें निपटायी गयीं। निपटायी जाने वाली माल अपीलों की संख्या ६,५३१ थी, जिनमें से २,०२६ अपीलें निपटायी गयीं। जाब्ता दीवानी १,६०८ के आदेश ४१, नियम ११ के अधीन सरसरी तौर पर मसूल की गयी अपीलों की संख्या १८२ से बढ़कर २५० हो गयी।



### विविध अपीलें

अधीनस्थ अदालतों के दायर की गयी विविध अपीलों की संख्या में १६ की वृद्धि हुई (३,२१२ से बढ़कर ३,२२८)। जिन अपीलों का निपटारा किया जाना था, उनमें ३१० की कमी हुई (८,३७१ से घट कर ८,०६३)। स्थानान्तरणों द्वारा निपटारे जाने वाले मामलों को छोड़कर विविध अपीलों की संख्या में ४६७ की वृद्धि हुई (३,०८५ से बढ़कर ३,५५२)।

### निर्णयों का कार्यान्वयन

अधीनस्थ अदालतों के समक्ष निर्णयों को कार्यान्वित करने के आवेदनो की संख्या में ३,१६० की कमी हुई (१,००,९५४ से घट कर ९७,७९४) और वर्ष में दायर किये गये आवेदनो की संख्या में ३,५४२ की कमी हुई (६९,३०८ से घट कर ६५,७६६)।

निपटारे गये आवेदनो में २,०६१ की कमी हुई (६४,५११ से घट कर ६२,४८०)। इनमें से २,९७२ आवेदनो को स्थानान्तरण द्वारा निपटारा गया।

प्रभावी आवेदनो का प्रतिशत ४५ से घट कर ४४ रह गया।

### दिवालियापन और भुगतान

प्रादेशिक दिवालियापन अधिनियम, १९२० के अधीन न्याय-प्रशासन २५ सिविल जजों और क्लर्क जजों के मुमिफो के अधिकार-क्षेत्र में आ गया। अधीनस्थ अदालतों के समक्ष दिवालियापन के मामलों की संख्या में ३८ की कमी हुई (१,७६८ से घट कर १,७३०) मुक्त किये गये दिवालियों की संख्या १६७ से घट कर १८७ हो गयी। रिसीवरो द्वारा बाटी जाने वाली धनराशि में ११,७०४ रु० की वृद्धि हुई (२,६८,३५८ रु० से बढ़ कर २,८०,०६२ रु०) और रिसीवरो के पास बाकी बची रकम में १,६४,०६२ रु० की वृद्धि हुई (१०,५२,८७९ रु० से बढ़कर १२,१६,९४१ रु०)।

### खफीफा अदालतें

खफीफा अदालतों की संख्या पहले की भांति १० बनी रहा। उन्होंने (स्थानान्तरित मामलों को छोड़कर) २१,८०१ मामलों में निर्णय किया। यह संख्या पूर्व वर्ष की तुलना में ८५ कम थी। जिन अन्य अदालतों में खफीफा अदालतों के अधिकार निहित थे, उन्होंने १३,३५४ (स्थानान्तरित मुकदमों को छोड़कर) अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में ३,४७५ कम मुकदमों का निर्णय किया।

उन अदालतों में कार्यान्वयन के लिए प्रभावी आवेदनो का प्रतिशत ३० से बढ़कर ३१ हो गया।

### अवैतनिक मुन्सिफ

चम्पावत और खाइन के तहसिलदारों की अदालतें मात्र राज्य में अवैतनिक मुन्सिफों की अदालतें थी। इन्होंने वर्ष में कोई मुकदमा फंसल नहीं किया। वे सामान्यतः मालियत वाले कतिपय मुकदमों का निपटारा करती थी किन्तु अब मालियत के मुकदमों की सुनवाई पंचायतों द्वारा की जाने लगी थी।

### बकायें

अधीनस्थ अदालतों में दीवानी मुकदमों के बकायें में शनैः शनैः होने वाली कमी जारी रही किन्तु प्रति वर्ष फौजदारी सम्बन्धित काम बढ़ता रहा। अधिक परिमाण में फौजदारी सम्बन्धी कार्यों, जोत चक्रबन्दी अधिनियम, १९५६ के अधीन सदमों और स्थानीय निकायों से सम्बन्धित चुनाव याचिकाओं के तत्काल निपटारा करने के फलस्वरूप अधिकतर जिला और सिविल जज दीवानी के नियमित कार्य की ओर पूरा-पूरा ध्यान नहीं दे सके।

(१) मुकदमों—वर्ष के अन्त में कुल अनिर्णीत मामलों की संख्या में १६,०६४ की कमी हुई (६५,६७७ से घट कर ७६,८८३)। एक वर्ष से अधिक समय के अनिर्णीत मामलों में पर्याप्त कमी हुई (४८,१५२ से घट कर ३५,५५८)। इसी प्रकार नव महीने से अधिक समय के अनिर्णीत मामलों में भी कमी हुई (६१,४२६ से घट कर ४६,६५०)। मुस्लिमों की अदालतों में एक साल से अधिक अवधि वाले अनिर्णीत मामलों में १०,१५८ की कमी हुई (४३,०१५ से घट कर ३२,८५७)। सिविल जजों की अदालतों में ऐसे मामलों की संख्या २,५६५ से घट कर २,२२७ और खफीफा अदालतों में २,३१८ से घट कर २,३११ हो गयी। फिर भी मुसिफ और जिला जजों की अदालतों में ३ या ४ वर्ष से अनिर्णीत मामलों की संख्या काफी अधिक थी।

(२) अपीलें—नियमित और लगातार अपीलों के अनिर्णीत मामलों की संख्या में ३,३६५ की कमी हुई और वे १६,८४६ रह गयी। इनमें से १७,०२० नियमित अपीलों और २,६३८ माल सम्बन्धी अपीलों थीं। एक वर्ष से अधिक समय की अपीलों की संख्या में भी १,५६५ की कमी हुई (७,५१४ से घट कर ५,९४९)। फिर भी दो-तीन वर्षों से अनिर्णीत अपीलों एक बड़ी संख्या में बच रही।

(३) विविध अपीलें—विविध अपीलों की कुल संख्या में ३६१ की कमी हुई (२,६०८ से घट कर २,२१७)। इस प्रकार की जो अपीलें एक वर्ष से अधिक समय से अनिर्णीत थीं, उनकी संख्या पूर्व वर्ष के ८७६ की तुलना में ४६३ थी।

(४) डिप्रियो के इजरा के लिए दरखास्तें—विचाराधीन पत्रावलियों की कुल संख्या में ३३३ की वृद्धि हुई अर्थात् इनकी संख्या ३२,००६ से बढ़ कर ३२,३४२ हो गयी। पर तीन महीने से अधिक समय से विचाराधीन दरखास्तों की संख्या में ५६६ की कमी हुई, अर्थात् इनकी संख्या १८,२२० से घट कर १७,६२४ हो गयी।

#### फरीकों और गवाहों के बयान

जाब्ता दीवानों के आदेश ५ नियम ३ के अधीन जिन व्यक्तियों को अदालत में स्वयं हाजिर होने के आदेश जारी किये गये उनकी संख्या ६,२८२ से बढ़ कर ११,७३६ हो गयी। इनमें से ५,६६० व्यक्तियों के बयान लिये गये।

गवाहों की संख्या, जिनके नाम सम्मन जारी किये गये, १,५६,८६७ से घट कर १,३६,२६७ रह गयी। इनमें से १,०५,०६७ के बयान लिये गये।

#### सम्मन तामील करने वाले कर्मचारी

सम्मन तामील करने वाले कर्मचारियों द्वारा तामील किये गये सम्मनों की संख्या में १,०६,६३७ की कमी हुई अर्थात् इनकी संख्या १०,५०,६६० से घट कर ६,४४,०२३ हो गयी। जाब्ता दीवानों के आदेश १६, नियम ८ के अधीन फरीकों द्वारा स्वयं तामील किये गये सम्मनों की संख्या में १७,३६० की कमी हुई, अर्थात् इनकी संख्या १,४२,११७ से घट कर १,२४,७५७ हो गयी।

#### पंचायतराज अधिनियम का कार्य

आलोच्य वर्ष में राज्य में कुल ८,६६१ न्याय पंचायतें कार्य करती रही।

न्याय पंचायतों के समक्ष दायर किये गये और निपटायें गये मुकदमों की संख्या इस वर्ष घट कर क्रमशः ६४,१५५ से ८२,३२१ और ८७,८३७ से ७६,१६८ हो गयी। विचाराधीन मुकदमों की संख्या २५,७३० रही, जब कि गत वर्ष यह संख्या २२,६०७ थी।

### इमारतें

राज्य में दीवानी अदालतों की इमारतों की दशा सामान्यतः असन्तोषजनक बनी रही। कुछ जगहों में इमारतें अनुपयुक्त थीं और कार्य बढ़ने के फलस्वरूप स्थापित की गयी। अतिरिक्त अदालतों के लिये भी काफी जगह न थी। फलस्वरूप इन अदालतों के बैठने की व्यवस्था दीवानी अदालत की इमारत से दूर किराये की इमारतों में अथवा बरांडों में घेर-घार कर करनी पड़ी। पर यह प्रबन्ध वकीलों, मुस्तारों, मुवक्किलों और अदालत के हाकिमों और उनके कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक न था।

फतेहपुर में दीवानी अदालत की एक नयी इमारत के निर्माण की स्वीकृति दी गयी पर इमारत के लिए जमीन न मिल सकने के फलस्वरूप निर्माण-कार्य आरम्भ न किया जा सका।

सन् १९५५-५६ के वर्ष में निर्माण के हेतु जिन चार निर्माण-कार्यों की स्वीकृति दी गयी थी, उन्हें सन् १९६० के वर्ष में पूरा कर लिया गया।

जहाँ तक सन् १९५६-५७ में स्वीकृत निर्माण-कार्यों का सम्बन्ध है—(१) एटा में अदालत के कमरों के एक खण्ड का, (२) मुजफ्फरनगर में अदालत के कमरों के एक खण्ड का, और (३) मथुरा में अदालत के कमरों के एक खण्ड का निर्माण-कार्य चल रहा था।

रामपुर में एक अभिलेख कक्ष का निर्माण-कार्य पूरा किया गया। इस कार्य की स्वीकृति सन् १९५७-५८ में मिली थी।

अन्य निर्माण-कार्यों में, जिनके लिए सन् १९५७-५८ में ३ लाख ६० की धनराशि स्वीकार की गयी थी, देहरादून, फँजाबाद और कानपुर में अदालतों के दो-दो कमरों का निर्माण-कार्य पूरा किया गया। देवरिया में अदालतों के लिए दो कमरों का निर्माण-कार्य चल रहा था और बाराबंकी में जिला जज की अदालत खण्ड का निर्माण-कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका।

इटावा, झांसी, वाराणसी और बलिया की दीवानी अदालतों की इमारतों में परिवर्तन एवं परिवर्द्धन करने और मैनपुरी की दीवानी अदालत की इमारत में बिजली लगाने के लिए सन् १९५८-५९ में ४ लाख ६० की एक धनराशि स्वीकृत की गयी थी। इस योजना के अधीन वाराणसी की दीवानी अदालत की मुख्य इमारत और नये खण्ड को जोड़ने के लिए एक छायादार रास्ता बनाया गया और मैनपुरी की दीवानी अदालत की इमारत में बिजली लगाने का कार्य चालू रहा। शेष स्थानों में, अर्थात् इटावा, झांसी और बलिया में वर्ष की समाप्ति तक कार्य आरम्भ न किया जा सका।

बस्ती में दीवानी अदालत की इमारत की फिर से छत बनाने का कार्य पूरा किया गया। इस कार्य की स्वीकृति सन् १९५५ में दी गयी थी।

सन् १९५६-६० के वर्ष में दीवानी अदालतों की इमारतों में परिवर्तन एवं परिवर्द्धन के लिए कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी।

### गवाहों के लिये बरामदे

सन् १९५७-५८ के वर्ष में सरकार ने गवाहों के लिए बहराइच, बलिया, बुलन्दशहर, गाजीपुर, ज्ञानपुर और शाहजहापुर में एक-एक और वाराणसी में दो, और इस प्रकार कुल आठ बरामदों के निर्माण के हेतु धन की स्वीकृति दी। केवल बहराइच को छोड़कर शेष सभी स्थानों में सन् १९५६ के अन्त तक गवाहों के लिए बरामदे बन कर तैयार हो गये थे। बहराइच में स्वीकृत डिजाइन के आधार पर निर्माण-कार्य पूरा करने में कुछ कठिनाई थी। फलस्वरूप अदालत ने गवाहों के लिए छोटे आकार का बरामदा बनाने की स्वीकृति दी। किन्तु आलोच्य वर्ष के अन्त तक निर्माण-कार्य आरम्भ न किया जा सका।

सन् १९५८-५९ में बाराबंकी, देवरिया, झांसी, लखनऊ, मुरादाबाद और रामपुर में गवाहों के लिए बरामदे बनाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। देवरिया, झांसी, मुरादाबाद और

रौमपुर में गवाहों के लिए बरामदों का निर्माण-कार्य पूरा किया गया जब कि लखनऊ और बाराबंकी में आलोच्य वर्ष के अन्त तक निर्माण-कार्य आरम्भ न किया जा सका।

सन् १९५६-६० में सरकार ने गवाहों के लिए ५ और बरामदे बनवाने की स्वीकृति दी। यह बरामदे चन्दौसी, गोरखपुर, हाथरस, कासगंज और टिहरी में बनने थे। किन्तु वर्ष के अन्त तक कार्य आरम्भ न किया जा सका।

### आवास

जुडिशियल सर्विस के अधिकारियों के लिए सरकारी आवासों की बेहद कमी थी और उन्हें उपयुक्त आवास तलाश करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था।

बलिया में जिला जज के आवास का निर्माण-कार्य उपयुक्त जमीन न मिल सकने के फल-स्वरूप आरम्भ न किया जा सका। इस निर्माण-कार्य की स्वीकृति सरकार ने सन् १९५७-५८ में दी थी।

सन् १९५८-५९ में सरकार ने उस बंगले की खरीद के लिए, जिसमें जिला जज रहते थे, धन की स्वीकृति दी, किन्तु वर्ष के अन्त तक खरीद की कार्रवाई पूरी न की जा सकी।

सन् १९५९-६० में सरकार ने मेरठ के जिला जज के आवास के लिए निर्माण-कार्य की स्वीकृति दी, किन्तु उपयुक्त जमीन न मिलने के कारण कार्य आरम्भ न किया जा सका।

बहराइच में दो अधिकारियों के आवास के लिए एक मकान खरीदने के हेतु सरकार ने धन की स्वीकृति प्रदान की। पर वर्ष के अन्त तक खरीद सम्बन्धी रस्मों के पूरा न हो सकने के कारण मकान की खरीद पूरी न हो सकी।

सन् १९६०-६१ में सरकार द्वारा किसी भी आवासीय इमारत के लिए धन की स्वीकृति नहीं दी गयी।

स्टाम्प फरोशो और अरायज नवीसों के लिए स्थान के सम्बन्ध में स्थिति पूर्ववत् बनी रही।

## **३—फौजदारी न्याय व्यवस्था\***

### **अधिकार-क्षेत्र**

आलोच्य वर्ष में सेशन डिप्टीजनों की संख्या ४० रही। फौजदारी के बड़े काम को निपटाने के लिए ३६ जिलों में सिविल और सेशन जजों की अस्थायी अदालतें स्थापित की गयीं। यदि इन अदालतों के काम का कुल समय जोड़ लिया जाय तो इन्होंने ४० वर्ष, ४ महीने और २८ दिन कार्य किया।

### **अपराधों की संख्या**

आलोच्य वर्ष में भारतीय दण्ड-विधान के अधीन अपराधों की संख्या सन् १९५६ में ६४,८६६ से बढ़कर ६७,००४ तक पहुँच गयी। राज्य के विरुद्ध अपराधों, जन-स्वास्थ्य और सुरक्षा से सम्बन्धित अपराधों और चोरी, डकैती, राहुजनी, जालसाजी और जायदाद हड़पने आदि के अपराधों में कमी हुई, किन्तु साजिश, अदालतों की मानहानि, झूठी गवाही, जाली सिक्के व नकली बाट आदि के अपराधों तथा बलात् रोक रखने, मारपीट, जबरदस्ती अपहरण, बलात्कार, अप्राकृतिक अपराध, धोखा, नाजायज धमकी देना और जायदाद पर नाजायज ढग से अधिकार कर लेने के अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई।

---

\*सन् १९६० के कलेडर वर्ष से सम्बन्धित।

### अभियुक्त

इस वर्ष ७,११,५१५ व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमों चले, जब कि सन् १९५९ में यह संख्या ७,०३,७८८ थी। इनमें से ७०१ अभियुक्त मुकदमों के दौरान में मर गये, १,४४६ भाग गये और ३७२ का सामला अन्य जिलों में भेज दिया गया। इस वर्ष कितने अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई, इसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है :—

	१९५९	१९६०
छोड़े दिये गये अभियुक्त ..	३,१९,८९०	३,३०,९८८
दण्डित किये गये अभियुक्त ..	२,५५,८२८	२,४४,४२९
सेशन सुपुर्द अभियुक्त ..	२४,६४५	२४,७७८
आलोच्य वर्ष के अन्त में विचाराधीन मामलों	८८,४१३	९८,४४८

भारतीय दण्ड-विधान और विशेष तथा स्थानीय कानूनों के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों के चालान हुए या जो दण्डित या मुक्त हुए उनका विवरण इस प्रकार है—

भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अभियोग	१९५९	१९६०
चालान किये गये व्यक्तियों की संख्या ..	३,०२,३२४	३,११,५५४
मुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या ..	१,८६,९५२	१,९२,७७६
दण्डित व्यक्तियों की संख्या ..	४६,६९८	४६,३७०
आलोच्य वर्ष के अन्त में विचाराधीन मुकदमों से सम्बन्धित व्यक्तियों की संख्या ..	६७,६८४	७१,३९५

जाता फौजदारी और विशेष अथवा स्थानीय कानूनों के अन्तर्गत अभियोग—

	१९५९	१९६०
चालान किये गये व्यक्तियों की संख्या ..	४,१८,४०५	४,१५,१९३
मुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या ..	१,५१,७६३	१,५६,५८६
दण्डित व्यक्तियों की संख्या ..	२,२९,३८०	२,१५,१७४
आलोच्य वर्ष के अन्त में विचाराधीन मुकदमों से सम्बन्धित व्यक्तियों की संख्या ..	३५,७४८	४१,९२७

### निर्णीत मामले

इस वर्ष कुल जितने मुकदमों का निर्णय किया गया, उनकी संख्या ३,१२,७६६ थी, जबकि पूर्वगामी वर्ष में यह संख्या ३,३५,७७७ थी। आनरेरी मजिस्ट्रेटों की अदालतों द्वारा निर्णीत मुकदमों से १,३५,४५२ व्यक्तियों का सम्बन्ध था, जबकि विगत वर्ष यह संख्या १,४३,७६३ थी। इस वर्ष ६,१३,०६७ व्यक्तियों के मामले निर्णीत हुए।

### गवाह

आलोच्य वर्ष में मैजिस्ट्रेटों की अदालतों में जितने गवाह गुजरे उनकी संख्या पूर्वगामी वर्ष के ४,९९,५०५ से घट कर ४,८४,५२६ रह गयी। सेशन अदालतों में गुजरने वाले गवाहों की संख्या भी पूर्वगामी वर्ष के १,०१,१९० से घट कर ९८,२०७ रह गयी। मैजिस्ट्रेटों की अदालतों में गुजरने वाले ऐसे गवाहों की संख्या, जिनसे जिरह नहीं की गयी, पूर्वगामी वर्ष के २५,२२१ से बढ़ कर आलोच्य वर्ष में ३३,९९६ हो गयी। इसी प्रकार सेशन की अदालतों में भी इनकी संख्या २०,३३२ से बढ़ कर २०,७८१ हो गयी।

## मुकदमों की अवधि

मजिस्ट्रेटों की अदालतों में एक मुकदमा चलने की औसत अवधि २१ दिन बनी रही। पर सेशन की अदालतों में यह अवधि १६५ दिन से घट कर १८० दिन हो रह गयी।

## मुकदमों के फैसले और सजाये

मजिस्ट्रेट और सेशन की अदालतों में जो व्यक्ति दण्डित हुए उनमें से ३३,२६५ को कारावास की सजाए, १,६५,२६१ को जुर्माने और २६,२३० व्यक्तियों को जमानते देने के आदेश हुए। सेशन की अदालतों द्वारा दी गयी प्राणदण्ड की मजा सन् १९५६ के ३८६ से घट कर आलोच्य वर्ष में ३७४ रह गयी। अपील में हाईकोर्ट द्वारा १२६ की सजा बहाल रही, १३३ व्यक्ति छोड़ दिये गये और ६३ व्यक्तियों की मजाओं में रद्दोबदल कर दी गयी। आलोच्य वर्ष की समाप्ति पर ५२ व्यक्तियों के मामले विचाराधीन थे। इस वर्ष २४ व्यक्तियों को फांसी दी गयी, जबकि पूर्वगामी वर्ष यह संख्या १५ थी।

आज्ञा कारावास पाने वाले व्यक्तियों की संख्या सन् १९५६ के १,५३७ से घट कर १,५२६ रह गयी। कठोर कारावास का दण्ड पाने वाले व्यक्तियों की संख्या सन् १९५६ के ३०,७२७ से घट कर २६,५७५ रह गयी।

सेशन की अदालतों द्वारा किये गये जुर्माने की कुल धनराशि गत वर्ष के ६,०३,३७६ रु० से घट कर इस वर्ष ३,३३,७६६ रु० रह गयी। मजिस्ट्रेटों की अदालतों द्वारा किये गये जुर्माने की कुल धनराशि पूर्वगामी वर्ष के ४८,६७,५५४ रु० से बढ़ कर ५५,४२,२७७ रु० हो गयी।

## शांति एवं सच्चरित्रता के लिये जमानत

शान्ति बनाये रखने लिए जितने व्यक्तियों से इस वर्ष मुचलके लिये गये, उनकी संख्या पूर्वगामी वर्ष के २३,२८४ से घट कर २२,७५५ रह गयी। जिन जिलों में बड़ी संख्या में लोगों के मुचलके लिये गये वे थे—रायबरेली (१,७२७), बाराबंकी (१,६८६), इलाहाबाद (१,३२७) और मथुरा (१,२६५)। सच्चरित्रता के लिए जितने लोगों से मुचलके लिये गये उनकी संख्या सन् १९५६ के ११,०५० से घट कर ६,७५६ रह गयी। जिन जिलों में बड़ी संख्या में लोगों से मुचलके लिये गये वे थे—गोरखपुर (६२६), इलाहाबाद (५५१), कानपुर (५३०) और आगरा (४८२) के जिले।

## प्रथम बार के तथा बाल अपराधी

आलोच्य वर्ष में प्रथम बार अपराध करने के आधार पर चेतावनी देकर या उत्तर प्रदेश फर्स्ट आफेंडर्स प्रोबेशन ऐक्ट, १९३८ के अधीन रिहा कर दिये गये अभियुक्तों की संख्या सन् १९५६ की ११,३६४ से घट कर ८,१७३ रह गयी।

हाई कोर्ट में अपील करने वालों की संख्या १४,६५५ से घट कर १०,३२८ रह गयी। सरकार की ओर से दायर की गयी अपीलों की संख्या, जिनमें पिछले वर्ष की विचाराधीन अपीलों भी शामिल हैं, इस वर्ष २८८ थी, जब कि सन् १९५६ में इनकी संख्या २६४ थी। इनमें से २ अपीलों वापस कर दी गयीं, ४० मजूर कर ली गयीं, १३० खारिज कर दी गयीं, ११ में फिर से सुनवाई करने के आदेश दिये गये और वर्ष की समाप्ति पर १०३ विचाराधीन थीं। अन्य अदालतों में अपील करने वालों की संख्या ५०,८६७ थी, जब कि पूर्वगामी वर्ष में इनकी संख्या ५२,६०१ थी।

## ४—माल की अदालतें

## कब्जा आराजी के मुकदमों

आलोच्य वर्ष में उत्तर प्रदेश टेनेसी अधिनियम, १९३६ के अन्तर्गत दायर किये गये मुकदमों की संख्या पूर्वगामी वर्ष के २०,१६६ से घटकर १५,७४५ रह गयी। विभिन्न प्रकार के मुकदमों की संख्या ४,३१४ से घटकर ३,७६० रह गयी लेकिन बकाया लगान की नगलिशों का संख्या पूर्वगामी वर्ष की १,०४६ से बढ़कर १,१३४ हो गयी। बेदखली के मुकदमों ६,२६२ से घटकर ३,६०२ रह गये। १,१२६ मामलों में बेदखल करने के आदेश दिये गये, जब कि पूर्वगामी वर्ष में २,२०१ मामलों में ऐसे आदेश दिये गये थे। बेदखली से संबंधित भूमि का क्षेत्र पिछले वर्ष के १,८५६ से घटकर १,७५१ एकड़ रह गया।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम, १९५० के अधीन दाखिल किये गये आवेदन-पत्रों की संख्या ६१,३५२ थी, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या १,१६,६६८ थी। भूमिधारी अधिकार उपाजित करने के संबंध में दिये गये प्रार्थना-पत्रों की संख्या इस वर्ष ३३,७६७ से बढ़कर ३६,६४७ तक पहुंच गयी। कब्जे के पुनर्ग्रहण के लिये इस वर्ष १,४३१ प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुए जब कि पिछले वर्ष इनकी संख्या २,१६६ थी। उक्त अधिनियम की धारा १४३ और १४४ के अधीन घोषणार्थ गत वर्ष के ३,००६ की अपेक्षा इस वर्ष केवल २,१६४ प्रार्थना पत्र दिये गये। असामियों और अधिवासियों की बेदखली के लिये पेश किये गये प्रार्थना-पत्रों की संख्या १०,४२६ थी, जब कि पिछले वर्ष यह संख्या २०,१०० थी। इस संबंध में इस वर्ष ७,६८६ एकड़ से बेदखलियों के आदेश हुए जब कि गत वर्ष ११,४६८ एकड़ से बेदखली के आदेश हुए थे।

## मूल टेनेसी अधिनियम के अधीन मुकदमों का निपटारा

उत्तर प्रदेश टेनेसी अधिनियम के अधीन मुकदमों के निपटारे के लिए दायर मुकदमों और प्रार्थना-पत्रों की संख्या ३३,००८ से घटकर २७,०८८ रह गयी। इनमें से इस वर्ष कुल १६,५५२ मुकदमों निपटाये गये जबकि पिछले वर्ष इनकी संख्या २१,७०५ थी। इस प्रकार वर्ष की समाप्ति पर १०,५३६ मुकदमों निपटाने को शेष रहे।

उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू अधिनियम सहित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के कुल ८,५२,८८४ प्रार्थना-पत्र और मुकदमों पेश हुए जबकि पिछले वर्ष यह संख्या ६,७०,३६१ थी। इनमें से गत वर्ष के ७,८६,६७१ की अपेक्षा इस वर्ष ७,१८,०७८ मामले निर्णीत हुए। इस प्रकार वर्ष की समाप्ति पर विचाराधीन मामलों की संख्या १,३४,८०६ रही।

## अपील और निगरानी

आलोच्य वर्ष में उत्तर प्रदेश टेनेसी अधिनियम के अन्तर्गत कलेक्टर के समक्ष पेश की गयी अपीलों की संख्या पूर्वगामी वर्ष के २३१ की तुलना में २३२ थी। निपटारे के लिये कुल ३११ अपीलें पेश थीं, जिनमें पिछले वर्ष के विचाराधीन ७६ (संशोधित संख्या) मामले भी थे। इनमें से इस वर्ष १६५ मामलों को निपटाया गया और इस प्रकार वर्ष की समाप्ति पर ११६ मामले निपटाने को शेष रहे। इस शेष संख्या में ३३ मुकदमों तीन महीने से अधिक पुराने थे।

† ३० सितम्बर, १९६० को समाप्त होने वाले राजस्व वर्ष से सम्बन्धित।

उत्तर प्रदेश टेनेसी अधिनियम, कुमायूँ टेनेसी नियम और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन कमिश्नरों एवं अतिरिक्त कमिश्नरों द्वारा निपटारे के लिये पेश अपीलों की संख्या आलोच्य वर्ष में विगत वर्ष की १६,६६२ से बढ़कर २०,७८६ हो गयी। इनमें से १२,६२५ अपीलों का फैसला हो गया और वर्ष की समाप्ति पर ८,१६४ अपीलों फैसले के लिए शेष रही। ३,३८८ अपीलों में अप्रवा लगभग २६.८ प्रतिशत में नीचे की अदालतों के आदेश उलट दिये गये, संशोधित किये गये या उन्हें वापस भेज दिया गया।

उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू अधिनियम के अधीन कमिश्नरों तथा अतिरिक्त कमिश्नरों द्वारा निर्णय के लिये ७,४८० अपीलें पेश थीं। जिनमें से ५,०६७ अपीलों का फैसला किया गया और वर्ष की समाप्ति पर २,३८३ अपीलों फैसले के लिए शेष रही।

माल बोर्ड के द्वारा फैसले के लिये १२,०५१ अपीलें पेश थीं, जिनमें से ५,५२४ पर फैसले दिये गये और वर्ष के अन्त में ६,५२७ अपीलों फैसले के लिए शेष रह गयीं।

### बंटवारा

राज्य के जिन भागों में जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम लागू नहीं था वहां बंटवारा संबन्धी १४६ मामले विचाराधीन थे। आलोच्य वर्ष में बंटवारा संबन्धी २५ मामले और पेश किये गये। इस प्रकार इस वर्ष निपटारे के लिए कुल १७१ मामले थे। इनमें से २४ मामलों को निपटाया गया और वर्ष के अन्त में १४७ मामलों विचाराधीन रहे।

### दाखिल खारिज

राज्य के जिन भागों में जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम लागू नहीं था, वहां आलोच्य वर्ष में हक मालिकाना विषय में जो दाखिल खारिज हुए उनकी संख्या ३,१६७ थी। इस वर्ष अदालती आदेशों के अनुसार ६१ मामलों में, वैयक्तिक हस्तान्तरण द्वारा १,५२० मामलों में और उत्तराधिकार के कारण १,२२६ मामलों में दाखिल खारिज हुए। इस वर्ष दो बंधक के मामले थे। बंधक छड़ाने के कारण ५ मामलों में दाखिल खारिज हुए। अन्य प्रकार के हस्तान्तरण के ३५३ मामले थे।

उन क्षेत्रों में जहां उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम लागू था २,५३,६३७ मामलों में दाखिल खारिज हुए। २५६ मामलों में अदालती आदेशों के द्वारा और १,७८,६३० मामलों में वैयक्तिक हस्तान्तरण द्वारा दाखिल खारिज हुए। अन्य मामलों के मद के अन्तर्गत ७५,०४८ मामलों में दाखिल खारिज हुए।

### ५—रजिस्ट्रेशन

रजिस्ट्रेशन विभाग की आय सन् १९६०-६१ में सन् १९५६-६० के ७६ लाख ३७ हजार रु० से घटकर ७७ लाख ४६ हजार रु० रह गयी। पर इसी अवधि में व्यय १७ लाख ६२ हजार रु० से बढ़कर १६ लाख १२ हजार रु० तक पहुंच गया।

वर्ष की समाप्ति पर रजिस्ट्रेशन कार्यालयों की संख्या, जिनमें जिला रजिस्ट्रारों के कार्यालय भी सम्मिलित थे, २५६ थी।



एटा, अजुवा, सुल्तानपुर, लखीमपुर मुजफ्फरनगर, बिजनौर और बहराइच में जिला रजिस्ट्रारों के नये कार्यालय स्थापित किये गये।

#### ६—लीगल रिमेम्बरेंसर की शाखा

पूर्वगामी वर्षों की भांति आलोच्य वर्ष में भी लीगल रिमेम्बरेंसर की शाखा का मुख्य कार्य दीवानी और फौजदारी (मुकदमा उठा लेने और जमानत रद्द कर देने) के सभी प्रकार के मुकदमों से संबंधित कार्यों की, माल की अपील सानी से संबंधित संविधान की धारा ३२ के अन्तर्गत दाखिल किये गये ऐसे सभी समादेश याचिकाओं (रिट पेटिशनों) से संबंधित कार्यों की, जिनमें राज्य सरकार एक फरीक हो, निगरानी करना था। ऐसे सभी मामले भी जिनमें राज्य सरकार के विभागों या भारत सरकार द्वारा कानूनी सलाह की आवश्यकता थी, लीगल रिमेम्बरेंसर के पास आये। लीगल रिमेम्बरेंसर की शाखा उत्तर प्रदेश की समस्त न्याय अदालतों और दूसरे राज्यों की अदालतों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर ऐसे सभी दीवानी के मुकदमों में, जिनमें राज्य सरकार फरीक थी, पैरवी करती रही। शाखा ने केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा मशविरे के लिए भेजे गये सभी मामलों में अपनी राय दी और ऐसे मामलों की भी पैरवी की, जिनमें भारत सरकार या अन्य राज्यों की सरकारें फरीक थीं।

विधि-विभाग के पास सचिवालय के विभिन्न विभागों द्वारा मशविरे के लिए भेजे गये कुल मामलों की संख्या सन् १९५६-६० में ११,६१४ थी।

संविधान की धारा २२६ के अधीन समादेश याचिकाओं (रिट पेटिशनों) से संबंधित समस्त कार्यों को जिन्हें पहले विकेंद्रित कर दिया गया था, आंशिक रूप से न्याय (ख) विभाग में केन्द्रित कर दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत सभी समादेश याचिकाएँ इस विभाग को इस आदेश के लिये भेजी जानी थी कि उनकी या उनसे संबंधित अपीलों की पैरवी की जाय अथवा नहीं। राज्य न्यायाधिकारियों से प्राप्त समादेश याचिकाओं संबंधी शिकायतों पर भी न्याय (ख) विभाग उसी प्रकार विचार करेगा, जैसे कि वह अन्य किसी असाधारण त्वरापेक्षी विषय के संबंध में विचार करता है।

यह निश्चय किया गया कि प्रयोग के रूप में उन दस जिलों में जहां नियमित पुलिस दल के बरिष्ठ पब्लिक प्रासिक््यूटर होते थे, वहां फौजदारी के उन मामलों की पैरवी जिनमें निर्धारित सजा बस साल से अधिक नहीं है, जिलाधीश की स्वीकृति पर उपरोक्त पब्लिक प्रासिक््यूटर करेंगे।

#### ७—उत्तर प्रदेश के महाप्रशासक और शासकीय न्यासधारी कार्यालय

लगभग १३ लाख ६० के सरकारी सिक्कोरिटियों और शेयरों के लगभग ७ लाख ६० आमदनी के १३ न्यास और १७५ आस्थान प्रशासन के अधीन थे। आस्थान का प्रशासन न्यासधारी तथा महाप्रशासक के अधिनियम (१९१३ के २ और ३) की व्यवस्थाओं के अनुसार होता रहा। सन् १९६०-६१ में इस कार्यालय में मृत्यु संबंधी लगभग ६० सूचनाएँ प्राप्त हुईं। महाप्रशासक के अधिनियम की धारा २५ के अन्तर्गत कई आस्थान इसके प्रशासन के अधीन थे।

महाप्रशासक को, महाप्रशासक के अधिनियम की धारा ३१ के अधीन २,००० ६० मूल्य तक के प्रशासन या उत्तराधिकार संबंधी प्रमाण-पत्र स्वीकृत करने के भी अधिकार थे और आलोच्य वर्ष में ऐसे २३ प्रमाण-पत्र स्वीकृत किये गये। प्रशासन या

उत्तराधिकार संबंधी प्रमाण-पत्र जारी करने की व्यवस्था प्रार्थियों के लिए अधिक सुविधाजनक और कम खर्चीली पायी गयी ।

प्रशासन के सिलसिले में बहुत से दावों के संबंध में निर्णय किया गया और उनका भुगतान भारत में या भारत के बाहर रहने वाले दावेदारों को किया गया । विदेश में रहने वाले दावेदारों को उन देशों में स्थित भारतीय उच्चायुक्त द्वारा भुगतान किया गया । उच्चायुक्त ने महा प्रशासक के सरकारी एजेंट के रूप में भुगतान किया । कुछ ऐसे आस्थान, जिनमें कोई उत्तराधिकारी नहीं था, राज्य सरकार के अधिकार में ले लिये गये ।

**अध्याय ६**  
**स्वायत्त-शासन**  
**१—पंचायतें**

**विधान**

आलोच्य वर्ष के अन्त में गांव सभाओं की कुल संख्या ७२,१२८ थी। गांव-पंचायतों के तीसरे आम-चुनाव के पूर्व गांव सभाओं की सीमाओं में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप इनकी संख्या घट गयी।

(न्याय पंचायतों में संबंधित विवरण दीवानी अदालतों के विवरण के साथ दिया गया है)

**गांव पंचायतों का चुनाव**

आलोच्य वर्ष में राज्य के ४६ जिलों में गांव-पंचायतों के आम निर्वाचन हुए। गांव पंचायतों के सदस्य निर्वाचन करने के लिये इन जिलों के पूरे ग्राम क्षेत्र को १,२६,६२३ निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया था। प्रधान के चुनाव के संबंध में गांव सभा के पूरे क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिया गया।

निर्वाचन, निर्वाचन निदेशक (पंचायत) की प्रत्यक्ष देख-रेख में और उनके निदेशन में हुए। जिला स्तर पर, जिलाधीश के प्रशासकीय नियंत्रण में जिला पंचायत अधिकारी पंचायत निर्वाचनों के संचालन के लिये उत्तरदायी था। पंचायत निर्वाचनों से संबंधित कार्यों में सहायता पहुंचाने के लिये एक सहायक जिला पंचायत अधिकारी (निर्वाचन), कुछ लिपिक और चपरासियों की नियुक्ति की गयी।

प्रधानों के लगभग ४२ प्रतिशत स्थानों पर और गांव पंचायत के सदस्यों के लगभग ५४ प्रतिशत स्थानों पर निर्विरोध निर्वाचन हुए। कुल मिलाकर ६६,५६५ प्रधान और ६,२५,२८५ सदस्य निर्वाचित हुए। प्रधानों के १०६ स्थान और सदस्यों के १,०२,६४६ स्थान रिक्त रहे। परिगणित जाति के सदस्यों के लिये सुरक्षित स्थानों पर गांव-पंचायतों के कुल १,६६,७७६ सदस्य चुने गये। महिला उम्मीदवारों ने प्रधानों के २०७ स्थान और सदस्यों के ८०६ स्थान प्राप्त किये।

**प्रशासन**

राज्य के मुख्यालय पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या इस वर्ष भी पूर्ववत् बनी रही, जहां एक निदेशक तथा चार उप-निदेशक पंचायत, जिनमें एक उप-निदेशक पंचायत (लेखा) भी थे, कार्य करते रहे।

इस वर्ष देहरादून स्थित राजपुर इंस्टीट्यूट में २४ सहायक जिला पंचायत अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया, जब कि चार सहायक जिला पंचायत अधिकारी भारत सरकार के सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित ओरियंटेशन ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षित किये गये। बकशी का-तालाब के प्रशिक्षण केन्द्र में भी बीस पंचायत निरीक्षकों को सोशल एजुकेशन आर्गनाइजर के रूप में प्रशिक्षित किया गया।

पंचायत निर्वाचनों के संचालन के लिए नवम्बर, १९६० से ३१ मार्च, १९६१ तक के लिये सहायक जिला पंचायत अधिकारियों (निर्वाचन) के ४६ अस्थायी स्थान थे।

पंचायत निरीक्षको की अयोग्यता के आधार पर अलग करते हुए, ज्येष्ठता के अनुसार उक्त पदों पर पदोन्नति की गयी।

इस वर्ष एक जिला पंचायत अधिकारी बरखास्त कर दिया गया और एक नौकरी से हटा दिया गया। इसी प्रकार दो पंचायत निरीक्षको को नौकरी से हटा दिया गया और एकको बरखास्त कर दिया गया। ६ पंचायत निरीक्षको के विरुद्ध जिनमें उपरोक्त तीन भी थे, अदालत में जांच की कार्यवाही चल रही थी।

### विधि-निर्माण

आलोच्य वर्ष में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, १९४७ का दो बार संशोधन किया गया। परिगणित जातियों के लिये स्थान सुरक्षित रखने के संबंध में इस अधिनियम में जो व्यवस्थाएं थी, उन्हें भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप बनाया गया। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन न्याय पंचायतों के पंचों की नियुक्ति की प्रणाली के संबंध में किया गया। संशोधित व्यवस्था के अनुसार पंचों की नियुक्ति गांव-पंचायतों के सदस्यों में से ही की जानी थी। गांव पंचायतों के सदस्यों की और प्रधानों की निर्वाचन प्रणाली के संबंध में स्पष्ट नियम बनाये गये। गांव-पंचायतों के सदस्यों का चुनाव हाथ उठा कर किया जाता था और प्रधान का निर्वाचन गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होना था।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, १९४७ में किये गये संशोधनों के फलस्वरूप गांव पंचायतों के सदस्यों और प्रधानों तथा उप-प्रधानों के निर्वाचन से संबंधित पंचायत-राज नियमावली के अध्याय १-डी और १-ई का पूर्ण रूप से संशोधन किया गया।

गांव पंचायतों और न्याय पंचायतों के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण के संबंध में एक नया नियम, नियम ६०-ए बनाया गया।

गांव-पंचायतों के सदस्यों, गांव-सभा के प्रधानों और न्याय पंचायतों के पंचों को शपथ दिलाने से संबंधित नियम ८६ का भी संशोधन किया गया, जिससे कि विभिन्न पदाधिकारियों को शपथ दिलाने में शीघ्रता की जा सके।

### पंचायत कर निर्धारण

इस वर्ष पंचायतों द्वारा ८७,२१,६०० रु० के कर निर्धारण का अनुमान था और गांव पंचायतों को कर में १४,१८,३०० रु० की छूट दी गयी। पंचायत-करों की कुल उगाही ८८,१०,२०० रु० की थी। पंचायत-करों के निर्धारण के अनुमान में और उगाही में कुछ कमी रही, क्योंकि पंचायतों के मंत्री तीसरी पंचवर्षीय योजना की तैयारी, गांव सभाओं के सदस्यों के रजिस्ट्रार (भाग १ व २) के संशोधन, जन-गणना और पंचायत चुनाव संबंधी कार्यों में व्यस्त रहे। पंचायत करों के बकाया में, फिर भी कुछ कमी हुई और ३१ मार्च १९६१ को यह बकाया २,४३,३४,००० रु० था।

### लेखा और लेखा-परीक्षण

आलोच्य वर्ष में गांव-पंचायतों और न्याय पंचायतों के लेखा रखने के कार्य में काफी सुधार हुआ। लेखा परीक्षको द्वारा बताया गया लेखा संबंधी त्रुटियों को दूर किया गया। ठीक ढंग से हिसाब-किताब रखने की दिशा में पंचायत मंत्रियों, पंचायत निरीक्षको और सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) द्वारा प्रशिक्षण, व्यय और रोकड़ बाकी के संबंध में जारी किये जाने वाले तिसाही प्रमाण-पत्रों से काफी सहायता मिली।

लेखा परीक्षक संस्थाओं द्वारा ४०,६४४ के गांव-पंचायतो और ४,६३४ न्याय पंचायतों के लेखों का परीक्षण किया गया।

आलोच्य वर्ष में क्षेत्र-कर्मचारियों को हिसाब-किताब रखने के संबंध में प्रगाढ़ रूप से प्रशिक्षित किया गया। एक उप-निदेशक पंचायत (लेखा) की देख-रेख में प्रशिक्षित करनेवालों के एक दल ने प्रत्येक कमिशनरी के मुख्यालय में जाकर सहायक जिला पंचायत अधिकारियों और लेखा लिपिकों को हिसाब-किताब रखने के संबंध में प्रशिक्षित किया।

### गांव पंचायतों की कार्यकारी समितियां

गांव-पंचायतों की दो कार्यकारी समितियां, अर्थात् कृषि उत्पादन समिति और लोक कल्याण समिति अपना कार्य संतोषजनक रूप से करती रहीं। उत्तर प्रदेश के अर्थ एवं संस्था विभाग के निदेशक द्वारा सन् १९६० में संचालित एक सर्वेक्षण से यह पता चला कि उपरोक्त कार्यकारी समितियां स्थापित की जा चुकी थीं और लगभग ६३.५ प्रतिशत गांव-पंचायतों में यह समितियां कार्य कर रही थीं।

### गांव सभा और गांव पंचायतों की बैठकें

गांव-सभाओं और गांव पंचायतों की बैठकों में सामान्य रूप से स्पष्ट सुधार हुआ। उत्तर प्रदेश के अर्थ एवं संस्था विभाग के निदेशक द्वारा संचालित एक सर्वेक्षण से यह पता चला कि अधिकांश गांव पंचायतों में सामान्य रूप से कोरम पूरा रहता था। गांव पंचायतों की ६२.२ प्रतिशत बैठकों में कोरम सदा पूरा रहता था। गांव सभाओं की २०.२ प्रतिशत बैठकें ६ महीनों में केवल एक बार ही कोरम के अभाव में स्थगित की गयीं और गांव सभाओं की ११.३ प्रतिशत बैठकें ६ महीनों में केवल २ बार कोरम के अभाव में स्थगित हुईं। गांव-पंचायतों की शेष ५३ प्रतिशत बैठकें ५ महीने में कोरम के अभाव में ३ या ४ अथवा इससे भी अधिक बार स्थगित की गयीं।

इस सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि ५५.६ प्रतिशत गांव पंचायतों में ६ महीनों की अवधि में ५ से ६ बैठकें तक हुईं और २६.७ प्रतिशत गांव पंचायतों में ६ मास की अवधि में ३ से ४ बैठकें हुईं। इस प्रकार ८५ प्रतिशत गांव-पंचायतों में या तो प्रति मास या हर दो महीनों में एक बार बैठकें हुईं, जो कि काफी संतोषजनक है।

### २—अन्तरिम जिला परिषद्

अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ को संशोधित कर अन्तरिम जिला परिषदों का कार्यकाल ३१ दिसम्बर, १९६२ तक बढ़ा दिया गया। यह कदम इसलिये उठाया गया कि लोगो में प्रबल भावना जाग उठी थी कि इन संस्थाओं के अध्यक्ष निर्वाचित गैर-सरकारी व्यक्ति होने चाहिए और उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत होने में समय लगने की संभावना थी। अन्तरिम जिला परिषदों के सरकारी अध्यक्षों के स्थान पर गैर-सरकारी निर्वाचित अध्यक्ष बनाये गये। केवल कुछ जिलों को छोड़कर गैर-सरकारी अध्यक्षों का निर्वाचन पूरा हो चुका था।

(पहले के जिला बोर्डों के स्थान पर मई, १९५८ में अन्तरिम जिला परिषदों की स्थापना की गयी, जिससे कि बलवेन्त राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर नियमित जिला परिषदों की स्थापना सहूलियत से की जा सके। उपरोक्त जिला परिषदों का कार्यकाल ३१ दिसम्बर, १९६० को समाप्त होना था।)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् विधेयक, जिसके अनुसार खन्ड और जिला स्तर पर क्रमशः क्षेत्र समिति और जिला परिषद् की स्थापना की जानी थी, बाद में विधान मण्डल द्वारा पास कर दिया गया। अधिकार के लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना के कार्यान्वयन में बिलंब न होने देने के उद्देश्य से विधेयक में उचित व्यवस्था की गयी। इसके अनुसार नियमित जिला परिषदों की स्थापना हो जाने तक अन्तरिम जिला परिषद क्षेत्र समितियों से, जिनकी शीघ्र ही स्थापना होनी थी, संबद्ध कर दिये जाने थे। ऐसा अनुमान था कि तब अन्तरिम जिला परिषद्, विधेयक में बताये गये, जिला परिषद् के अधिकारों और कर्तव्यों को निबाहेंगे।

### वित्तीय सहायता

राज्य सरकार, अपनी विषम वित्तीय स्थिति के बावजूद भी जिला परिषदों की सहायता करती रही। सन् १९६०-६१ के वित्तीय वर्ष में जो विभिन्न आवर्तक और अनावर्तक अनुदान दिये गये, उनका विवरण निम्नप्रकार है—

#### सहायक अनुदान

(१) अल्मोड़ा, नैनीताल और बहराइच की अन्तरिम जिला परिषदों को सड़कों और डाकबंगलों के रख-रखाव के लिए आवर्तक अनुदान ..	७,३१२
(२) राज्य सरकार द्वारा परिषदों को पुनः हस्तांतरित कच्ची सड़कों के रख-रखाव के लिए अन्तरिम जिला परिषदों को आवर्तक अनुदान ..	८,१३,६२५
(३) कुछ अन्तरिम जिला परिषदों को ठेके तथा कुछ अन्य प्रकार के योगदान के हेतु आवर्तक अनुदान ..	६,३०,३६५
(४) कतिपय नियमों के अधीन जमाने से अन्तरिम जिला परिषदों की आय सम्बन्धी घाटे की पूर्ति हेतु अनुदान ..	३,०८,१६०
(५) कांजी-हाउस में बन्द मवेशियों पर जुर्माना और उनकी बिक्री से होने वाली अतिरिक्त आय के घाटे की पूर्ति हेतु अनुदान ..	२०,५०,०२०
(६) अन्तरिम जिला परिषदों द्वारा प्रबन्धित सार्वजनिक नाव घाटों से होने वाली प्राप्तियों के बदले अनुदान ..	१५,७८,१००
(७) स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते सम्बन्धी खर्च की पूर्ति हेतु अनुदान ..	६०,००,०००
(८) सेस और स्थानीय दर से होने वाली आय के घाटे की पूर्ति हेतु अनुदान ..	१,३५,०२,६४
(९) जमींदारी विनाश के बाद अन्तरिम जिला परिषदों के प्रबन्ध में आये हाटों, बाजारों और मेलों के प्रबन्ध हेतु अनुदान ..	१३,२८२

#### विशेष अनुदान

(१) पहाड़ी क्षेत्रों की प्रांतीय जिला परिषदों को अनावर्तक अनुदान ..	७,५०,०००
(२) रामपुर और टोहरी-गढ़वाल की अन्तरिम जिला परिषदों को अनावर्तक अनुदान ..	२,६५,०००

### ३—नगरमहापालिकाएं

राज्य के ५ बड़े नगरों—कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा और लखनऊ में नगर महापालिकाओं की स्थापना से इन नगरों में नागरिक प्रशासन सम्बन्धी एक बड़ी आवश्यकता

की पूर्ति हुई। १ फरवरी, १९६० से नगर महापालिकाओं ने अपना कार्य आरम्भ किया। सन् १९४५ तक कानपुर, लखनऊ और इलाहाबाद में नगरपालिका के अतिरिक्त इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट नामक और एक संस्था थी। उसी वर्ष कानपुर के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के स्थान पर विकास बोर्ड बना दिया गया और सन् १९४६ में आगरा और वाराणसी में दो और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट स्थापित किये गये। इन इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों को और कानपुर के विकास बोर्ड को उन्हीं नगरों की नगरपालिकाओं में मिला दिया गया है, जहाँ नगरमहापालिकाएं बनीं, जिनमें इन दोनों संस्थाओं के कार्य सम्मिलित थे।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५६ के द्वारा प्रत्येक नगर के लिए नगरिक प्रशासन का अधिकार नगरमहापालिका के निम्नलिखित अंगों में निहित था —

- (१) महापालिका,
- (२) महापालिका की कार्यकारिणी समिति,
- (३) महापालिका की विकास समिति,
- (४) महापालिका के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक मुख्य नगर अधिकारी,
- (५) यदि महापालिका बिजली की सप्लाई स्थापित करती है अथवा उसे प्राप्त कर लेती है या सार्वजनिक यातायात या सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी अन्य किसी भी कार्य को करती है तो राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से वह इन कार्यों के लिए इस प्रकार की अन्य समिति या समितियां बना सकती है।

महापालिका में एक नगर-प्रमुख, एक उप-नगर प्रमुख, सभासद और विशिष्ट सभासद थे। विशिष्ट सभासदों की संख्या सभासदों की संख्या का नवा भाग होता था।

सभासदों का चुनाव बालिग मताधिकार के अनुसार होता है और वे लोग अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल मताधिकार द्वारा विशिष्ट सभासदों का चुनाव करते हैं। नगर प्रमुख और उप-नगरप्रमुख का भी चुनाव सभासद तथा विशिष्ट सभासद अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल मताधिकार द्वारा करते हैं। नगर प्रमुख (मेयर) का कार्यकाल एक वर्ष का होता है और उपनगर प्रमुख (डिप्टी मेयर) का कार्यकाल नगर महापालिका के कार्यकाल के समान ही अर्थात् ५ वर्ष का होता है।

नगरमहापालिकाओं का गठन निम्नलिखित आधार पर किया गया है —

नगर महापालिका				बोर्डों की संख्या	सभासदों की संख्या	विशिष्ट सभासदों की संख्या
कानपुर	..	..	..	३६	७२	८
लखनऊ	..	..	..	३२	६३	७
आगरा	..	..	..	२७	५४	६
वाराणसी	..	..	..	२७	५४	६
इलाहाबाद	..	..	..	२७	५४	६

अधिनियम में महापालिका में परिगणित जातियों के लिए जन-संख्या के अनुसार स्थान सुरक्षित रखने की भी व्यवस्था की गयी है। सुरक्षित स्थानों की संख्या इस प्रकार है—

					संख्या
कानपुर	३	००	००	००	६
आगरा	३	००	००	००	८
इलाहाबाद	००	००	००	००	५
लखनऊ	००	००	००	००	५
वाराणसी	००	००	००	००	४

#### ४—नगरपालिकाएं

##### नगरपालिकाओं की संख्या

राज्य में नगरपालिकाओं की संख्या १३२ रही। आलोच्य वर्ष में किसी नयी नगरपालिका की स्थापना नहीं की गयी।

अधिकांश नगरपालिकाएं सतोषजनक रूप से अपना कार्य करती रहीं। कुछ नगरपालिकाओं, अर्थात्, नोमसार, मिसरिख, फर्रुखाबाद, बिलसी और फैजाबाद की नगरपालिकाओं को निलम्बित (मुअत्तल) कर दिया गया, क्योंकि उनका प्रशासन निरन्तर गिरता जा रहा था। इसी कारण सीतापुर की नगरपालिका भंग कर दी गयी। मुरादाबाद, नजीबाबाद, हाफुड़, गाजियाबाद और खुरजा की नगरपालिकाएं पूर्ववत् निलम्बित रहीं।

जहागीराबाद, रामनगर (नैनीताल), कैराना, पिलखुआ, धामपुर, चंदौसी, हसनपुर, शाहजहापुर, जौनपुर, चरखारी, अमरोहा, बिलासपुर, मऊनाथ भजन और इटावा की नगरपालिकाओं के अध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव आये, किन्तु वे या तो कोरम के अभाव में या अन्य कारणों द्वारा स्वीकृत न हो सके।

##### नियम और विनियम

इस वर्ष नगरपालिका के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन की कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में बनाये गये नियमों को अन्तिम रूप दिया गया। इस सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियमों के समान ही नगरपालिका के कर्मचारियों के लिये भी विस्तृत नियमावली तैयार करने के लिए कुछ समय पहले से ही आवश्यक कदम उठाये गये थे, क्योंकि सामान्य रूप से ऐसी शिकायत थी कि इन नियमों के अभाव में बहुधा नगरपालिका के कर्मचारियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। आलोच्य वर्ष में नगरपालिका के कर्मचारियों की उनकी प्रथम नियुक्ति के समय उनके आचरण और पूर्ववत् की जांच के सम्बन्ध में बनाये गये नियमों को अन्तिम रूप दिया गया। इस प्रकार के नियमों के अभाव में अक्सर सदिग्ध आचरण के व्यक्ति अथवा अव्यवस्थित पूर्ववत् वाले व्यक्ति नगरपालिका की सेवा में भरती हो जाते थे और जब वास्तविक तथ्यों का पता चलता था, तब उन्हें नौकरी से हटाने में कठिनाई होती थी। कर्मचारियों के प्रोबेशन के सम्बन्ध में भी नियम बनाये गये। इस सम्बन्ध में अब तक कोई नियम न था और इन नियमों के बन जाने से बहुत समय से अनुभव की जा रही एक आवश्यकता की पूर्ति हुई।

##### विधि निर्माण

नगरपालिका अधिनियम को सशोधित करने के सम्बन्ध में कार्रवाई की गयी। अधिनियम की विभिन्न धाराओं को सशोधित करने के सम्बन्ध में अनेक प्रस्ताव थे। कुछ प्रस्तावित संशोधनों द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जाने थे और उनके द्वारा नगरपालिका के प्रशासन स्तर को ऊंचा उठाना था। वर्ष की समाप्ति पर संशोधन करने वाले विधेयक को अन्तिम रूप दिया जा रहा था।



## ५—टाउन एरिया

### नये टाउन एरिया का निर्माण

आलोच्य वर्ष में केवल बादा जिले के बनेरू में एक नया टाउन एरिया स्थापित किया गया। बनौरा टाउन एरिया (जिला मुरादाबाद) का स्तर उठा कर उसे नोटीफाइड एरिया बना दिया गया। राज्य में इस वर्ष टाउन एरियाओं की कुल संख्या २७८ थी।

सामान्यतः जैसा होता था टाउन एरिया कमेटियां अपने कार्य संचालन के लिए नियमित रूप से बैठकें किया करती थीं। विभिन्न सदस्य उन कार्यों की निगरानी करते थे, जो उन्हें उनकी कमेटियों द्वारा सुपुर्द किये जाते थे। सामान्य रूप से कमेटियां बहुत ही सुविधाजनक ढंग से कार्य करती थीं। केवल उन्हीं कमेटियों के कार्य में बाधा पड़ी जहां गुटबन्दी थी। तालबेहट (शासी), चिट बड़ा गांव (बलिया) और फूलपुर (इलाहाबाद) की टाउन एरिया कमेटियों के अध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव आये और स्वीकृत हुए। फूलपुर की टाउन एरिया कमेटी के अध्यक्ष ने, टाउन एरिया अधिनियम की व्यवस्थाओं को अनुसार, अपने पद से त्यागपत्र नहीं दिया और सरकार को उन्हें हटाना पड़ा।

### विधि-निर्माण

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, की धारा २२८ से २३६ तक, पुखरायां (कानपुर), पिठौरागढ़ (जिला पिठौरागढ़), टनकपुर (नैनीताल) और चोहड़पुर (देहरादून) की टाउन एरियाओं में लागू करने का प्रश्न, जिससे कि यह टाउन एरियायें अपनी जल-सप्लाई की योजनायें कार्यान्वित कर सकें, विचाराधीन था।

### वित्तीय स्थिति

सामान्य रूप से टाउन एरिया कमेटियों की वित्तीय स्थिति सतोषजनक नहीं थी। टाउन एरिया कमेटियों की आय का मुख्य स्रोत हैसियत और आमदनी-कर था। किन्तु फिर भी सरकार ने अनेक टाउन एरिया कमेटियों को "टोल टैक्स" लगाने की अनुमति दे दी, जिससे कि वे अपनी आय में वृद्धि कर सकें। इन कमेटियों के वित्तीय साधनों को सहायता पहुंचाने के हेतु सरकार ने इन स्थानीय निकायों को दो हजार २० प्रति टाउन एरिया की दर से उनकी सड़कों की मरम्मत एवं निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी। कुछ टाउन एरियाओं को उनकी विशेष मांग पर इसी उद्देश्य के लिए इससे बड़ी धनराशि दी गयी। कुछ कमेटियों को मेहतरों के प्रयोग के लिये लोहे की गाड़ियां या ठेलों की खरीद के लिये भी आर्थिक अनुदान दिये गये। सरकार की अब यह सामान्य नीति थी कि मेहतरों को सिर पर मेला न डोने दिया जाय। कुछ टाउन एरियाओं में वसूली न होने के फलस्वरूप करों का काफी बकाया इकट्ठा हो गया था और सरकार ने बकाया को वसूली के लिए इन कमेटियों के नाम आदेश जारी किये।

### निलम्बन

कछवा (मिर्जापुर) और जलालाबाद (मुजफ्फरनगर) की टाउन एरिया कमेटियों को, लगातार अपना कार्य सुचारु-रूप से संचालन न करने के फलस्वरूप निलम्बित कर दिया गया। बहजोई (मुरादाबाद), तालबेहट (शासी), और मुबारकपुर (आजमगढ़) की टाउन एरियाओं को निलम्बित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था।

### मेलों का प्रबन्ध

टाउन एरियाओं की सीमा में अनेक पशु-मेले तथा वार्षिक, कृषि तथा औद्योगिक रूप के मेले हुए। इन मेलों के सम्बन्ध में कमेटियों द्वारा जो विभिन्न प्रबन्ध किये गये वे काफी संतोषजनक थे।

## ६—नोटोफाइड एरिया

राज्य में नोटोफाइड एरिया कमेटियो की संख्या २८ रही। आलोच्य वर्ष में जन-गणना की सुविधा के लिए, नयी नोटोफाइड एरियाओं के निर्माण का प्रश्न स्थगित कर दिया गया।

इन कमेटियो की व्यवस्था उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ की कुछ धाराओं के अनुसार, जिन्हें कि नोटोफाइड एरियाओं पर भी लागू कर दिया गया था, होता था। इन कमेटियों के सदस्यों की संख्या ६ से १५ तक होती थी। कमेटियों के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन होता था और सदस्यों का चुनाव मतदाताओं द्वारा होता था अथवा वे सरकार द्वारा नामजद किये जाते थे।

विकेन्द्रीकरण की नीति के अनुसार, नोटोफाइड एरिया कमेटियो के कर-निर्धारण प्रस्ताव की स्वीकृति का अधिकार, केवल टोल-टैक्स लगाने के अधिकार की स्वीकृति को छोड़कर, जिलाधीश को दे दिया गया। अब केवल टोल टैक्स लगाने का प्रस्ताव ही सरकार की स्वीकृति के लिए आता था। यद्यपि सरकार इस टैक्स को प्रोत्साहित नहीं करती, फिर भी श्रीनगर और उत्तर-काशी की नोटोफाइड एरिया कमेटियों को यह कर लगाने व इससे सम्बन्धित नियम बनाने की आज्ञा सरकार द्वारा दे दी गयी, जिससे कि वहां के स्थानीय निवासियों तथा पर्यटकों को अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

नोटोफाइड एरिया कमेटियो का कार्य सामान्य रूप से सतोषजनक रहा। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि सन् १९५७ के साधारण निर्वाचन के बाद से अब तक किसी भी नोटोफाइड एरिया को निलम्बित नहीं करना पड़ा।

## अध्याय-७

### सार्वजनिक राजस्व और वित्त

#### १—केंद्रीय राजस्व

उत्तर प्रदेश में ६३,७८० व्यक्तियों पर आय-कर लगाया गया और इस मद में कुल शुद्ध वसूली, जिसमें अतिरिक्त लाभ-कर एवं व्यवसाय लाभ-कर (एक्सेस प्राफिट टैक्स और बिजनेस प्राफिट टैक्स) भी सम्मिलित हैं, आलोच्य वर्ष में ७ करोड़ ६४ लाख रु० हुई। मृत्यु कर (इस्टेट ड्यूटी), व्यय-कर (एक्स्पेंडीचर टैक्स), सम्पत्ति कर (वैल्यू टैक्स) और उपहार-कर (गिफ्ट टैक्स) के द्वारा कुल मिलाकर ४२ लाख ३३ हजार रु० की वसूली हुई।

#### २—राज्य का राजस्व

##### सन् १९५६-६० के वास्तविक तख्तीने

कुल ११,६६१ लाख रु० की मूल राजस्व प्राप्ति का अनुमान था, जिसमें ६६४ लाख रु० की वृद्धि हुई। फलस्वरूप राजस्व प्राप्ति १२,६५५ लाख रु० तक पहुँच गयीं। इसी प्रकार राजस्व व्यय का मूल तख्तीना १२,१७७ लाख रु० का था, जिसमें कि ६६६ लाख रु० की वृद्धि हुई। इस प्रकार राजस्व-व्यय १२,८१६ लाख रु० रहा। इस वर्ष इस प्रकार १३६ लाख रु० की बचत हुई।

##### राजस्व प्राप्ति

बिक्री-कर की वसूली अच्छी रही और ३२५ लाख रु० अधिक रही। इसका मुख्य कारण यह था कि पिछले बकाया की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाये गये, कुछ विलास की सामग्रियों पर पूरे वर्ष तक बढ़ी हुई दर से कर की वसूली की गयी और दशमलव मुद्रा प्रणाली के अन्तर्गत बहुपदीय बिक्री-कर की सामान्य दर १.५६ प्रतिशत से बदलकर २ प्रतिशत कर दी गयी। राजस्व की स्थिति में इस कारण भी सुधार हुआ कि राजकीय बस सविस (+११३ लाख रु०), वन (+१०७ लाख रु०), टिकटो की बिक्री (+४६ लाख रु०), और दस्तावेजों के निबन्धन (+१४ लाख रु०) से अधिक आय हुई। राजकीय आबकारी से प्राप्ति ११८ लाख रु० अधिक रही। मनोरंजन कर और विद्युत्-शुल्क, दोनों से मिलाकर ६५ लाख रु० अधिक प्राप्त हुए। केन्द्रीय आबकारी शुल्क और रेल-भाड़ा करों में राज्य सरकार का हिस्सा इस वर्ष ६४ लाख अधिक रहा। मोटर गाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्ति में ५३ लाख रु० की वृद्धि हुई। राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिम धनो पर व्याज-प्राप्ति में १०६ लाख रु० की वृद्धि हुई। चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत भी प्राप्ति २३ लाख रु० अधिक हुई और कृषि के अन्तर्गत भी प्राप्ति में ५२ लाख रु० की वृद्धि हुई। इनके अतिरिक्त प्राप्ति में अन्य छोटी-मोटी वृद्धि भी हुई। दूसरी ओर, पिछले बकायों की कम वसूली होने के फलस्वरूप गन्ना सेस की प्राप्ति में ११६ लाख रु० की कमी हुई। सिचाई की शुद्ध-प्राप्तियों में भी १४२ लाख रु० घट गये।

##### राजस्व व्यय

ऋण घटाने या टाल जाने के कारण व्यय में ६२७ लाख रु० की वृद्धि हुई। बुभिक्ष सहायता के अन्तर्गत व्यय बढ़ कर १०६ लाख हो गया। पुलिस पर व्यय में ३८० लाख की वृद्धि हुई और शिक्षा पर ५४ लाख की। यातायात विभाग के व्यय में भी ६३ लाख रु० की वृद्धि हुई। दूसरी ओर व्याज १६२ लाख रु० कम रहा। भूमि-राजस्व के अन्तर्गत व्यय ५१ लाख

₹० कम रहा। जन-स्वास्थ्य, श्रम, उद्योग, नागरिक कार्य और प्रकीर्ण खर्चों की मद में ₹०.७ लाख ₹० बढ़े।

#### पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय, ₹२,२१४ ₹० के मूल तख्तीनी की तुलना में ₹२,२५२ लाख ₹० रहा। इस प्रकार इसमें ₹२८ लाख ₹० की वृद्धि हुई। रिहन्द बांध परियोजना पर पूँजी-लागत मूल-अनुमान से ₹४८ लाख ₹० अधिक रही। राजकीय व्यापार की योजनाओं के अन्तर्गत मूल व्यय में ₹२४ लाख ₹० की वृद्धि हुई। दूसरी और सिंचाई कार्यों पर व्यय ₹२२० लाख ₹० कम रहा। कृषि सुधार और अनुसंधान पर भी लागत ₹०.१ लाख ₹० कम रही।

#### सन् १९६०-६१ के लिये बजट के तख्तीनी

राजस्व-प्राप्ति और राजस्व-व्यय क्रमशः ₹३,०६० लाख ₹० और ₹३,३२३ लाख ₹० था। इस प्रकार ₹३३ लाख ₹० का राजस्व में घाटा रहा।

#### राजस्व प्राप्तियाँ

सन् १९५६-६० के राजस्व प्राप्तियों के संशोधित तख्तीनी की तुलना में सन् १९६०-६१ के बजट के तख्तीनी में प्राप्तियाँ ८४० लाख ₹० अधिक थीं। राजस्व प्राप्तियों के तख्तीनी में वृद्धि के लिए निम्नलिखित कारण थे:—

- (१) चक्रवर्ती शुल्क के बकाया की वसूली का अनुमान (११४ लाख ₹०)।
- (२) गन्ना सेस के बकाया की वसूली का अनुमान (६३ लाख ₹०)।
- (३) अधिक प्रगाढ़ सिंचाई और फलस्वरूप प्राप्तियों में सुधार (१०० लाख ₹०)।
- (४) व्याज-प्राप्ति में वृद्धि (६० लाख ₹०)।
- (५) राजकीय बस सर्विस के यात्रा मीलों (माइलेज) की और यात्रियों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अधिक प्राप्तियों की आशा (७५ लाख ₹०)।
- (६) चुर्क की राजकीय सीमेंट फैक्ट्री की नयी भट्टियों द्वारा उत्पादित सीमेंट की अतिरिक्त मात्रा की बिक्री से अतिरिक्त अनुमानित प्राप्तियाँ (७६ लाख ₹०)।
- (७) राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना और कृषि, शिक्षा, सहकारिता और हज़िजन सहायक आदि विभागों से सम्बन्धित योजनाओं के लिए भारत सरकार से अधिक आर्थिक सहायता की आशा (२६६ लाख ₹०)।

#### राजस्व व्यय

सन् १९६०-६१ में राजस्व व्यय के सन् १९५६-६० के राजस्व व्यय के मूल तख्तीनी की तुलना में ₹१,१७६ लाख ₹० अधिक होने की आशा थी। यह वृद्धि अंशतः वर्तमान सेवाओं पर होने वाले सामान्य व्यय में बढ़ती और अंशतः पहले की स्वीकृत वर्तमान परियोजनाओं के कार्यक्षेत्र में विस्तार के फलस्वरूप हुई। ऋण घटाने या टालने की मद के अन्तर्गत व्यय में ₹२२६ लाख ₹० की वृद्धि का अनुमान था। गांव पंचायतों और गांव सभाओं के आम चुनाव के लिये की गयी व्यवस्थाओं के फलस्वरूप ₹६१ लाख ₹० की वृद्धि की आशा थी और डाकू विरोधी अभियान के लिये प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस के एक अतिरिक्त बटालियन के लिए ₹४४ लाख ₹० की वृद्धि की आशा की जाती थी। शिक्षा के अन्तर्गत ₹०.३ लाख ₹० अधिक खर्च का अनुमान था क्योंकि छठी कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा के कारण सहायता प्राप्त सस्थाओं को होने वाले घाटे की पूर्ति करनी थी। राजकीय बस-सर्विस के रख-रखाव पर होने वाले व्यय में ₹३६ लाख ₹०

की वृद्धि का अनुमान था। परिगणित एवं पिछड़ी जातियों के सुधार एवं उत्थान पर होने वाले व्यय में १०१ लाख रु० की और व्यवस्था की गयी। युद्धोत्तर नियोजन एवं विकास के अन्तर्गत भी व्यय में ४३ लाख रु० की वृद्धि हुई।

### सन् १९६०-६१ के संशोधित तखमीने

संशोधित तखमीनों में १३,८५५ लाख रु० की राजस्व प्राप्तियों का अनुमान था। राजस्व व्यय का अनुमान १३,८२६ लाख रु० का था। इस प्रकार २९ लाख रु० की अल्प बचत रही।

#### राजस्व प्राप्तियाँ

केन्द्रीय आबकारी शुल्क, मृत्यु-कर, आय-कर और रेलभाड़ा कर में राज्य सरकार के हिस्से में ६०९ लाख रु० की वृद्धि होने की संभावना थी। किन्तु इसमें १२२ लाख रु० की कमी हो गयी। केन्द्रीय सरकार द्वारा आय-कर कोष से धन का जो वितरण होता है उसके अनुमानों में सन् १९५९-६० में कम्पनी टैक्स में परिवर्तन होने के कारण यह आशिक कमी हुई।

राजकीय आबकारी के अंतर्गत प्राप्तियों में ४० लाख रु० की वृद्धि की संभावना थी। इमारती लकड़ी और अन्य बनोपज की बिक्री से होने वाली प्राप्तियों में ६१ लाख रु० की वृद्धि की संभावना थी। बिक्री-कर द्वारा होने वाली प्राप्तियों में २५० लाख रु० की वृद्धि की सम्भावना थी। राजकीय रोडवेज और अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियों द्वारा ११९ लाख रु० अधिक प्राप्त होने की आशा थी। दूसरी ओर सिचाई प्राप्तियों की मद में ३२ लाख रु० की कमी की आशा थी। चूर्क की राजकीय सीमेन्ट फैक्टरी की नयी यूनिट, जो सन् १९६०-६१ से अपना उत्पादन कार्य आरंभ करने वाली थी, चालू न की जा सकी और इस प्रकार उद्योग विभाग की प्राप्तियों में ५१ लाख रु० की कमी हुई। अन्य कर एवं शुल्क मद के अन्तर्गत प्राप्तियों में भी गन्ना सेस के बकाया की कम वसूली के फलस्वरूप १६५ लाख रु० की कम वसूली हुई।

#### राजस्व व्यय

संशोधित तखमीनों के अनुसार ऋण और अन्य संबद्ध मदों के व्याज में २०६ लाख रु० की वृद्धि होने की आशा थी। दुर्भिक्ष सहायता मद के अन्तर्गत १४२ लाख रु० की वृद्धि का अनुमान था। सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ६० लाख रु० की वृद्धि मुख्यतः इस कारण से थी कि उत्तराखण्ड डिबोजन के विकास के लिये मूल बजट में केवल नाममात्र की धनराशि रखी गयी थी। पुलिस की मद में अनुमानित व्यय ७० लाख रु० अधिक रखा गया। शिक्षा के अन्तर्गत व्यय में ५२ लाख रु० का वृद्धि का अनुमान था। प्रकीर्ण विभागों के अन्तर्गत ९६ लाख रु० की वृद्धि होनी थी। इसका मुख्य कारण राजकीय रोडवेज के व्यय में वृद्धि होने की आशा थी। नागरिक कार्यों के संशोधित तखमीनों में ५३ लाख रु० अधिक थे। दूसरी ओर ऋण घटाने या टालने की मद में होने वाले व्यय के अनुमान में ७९ लाख रु० की कमी थी। सामुदायिक विकास योजनाएं, राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना और स्थानीय विकास कार्यों के अन्तर्गत भी व्यय में ४४ लाख रु० की कमी की संभावना थी।

#### पूँजीगत व्यय

राज्य विद्युत् परिषद् को ऋण के रूप में हस्तांतरित विद्युत् कारखानों की सम्पत्ति के मूल्य की वसूली के रूप में ६,८८८ लाख रु० के संभावित समाधान को दृष्टि में रखते हुए आरंभिक अनुमान में शुद्ध पूँजीगत व्यय (-) ४,१८९ लाख रु० निर्धारित किया गया था। संशोधित अनुमान में हस्तांतरित कारखानों के सम्पत्ति-मूल्य के रूप में ६,८९२ लाख रु० के समाधान के पश्चात् शुद्ध पूँजीगत-व्यय की रकम (-) ४,३१३ लाख रु० रही।

भूल तखमीने की तुलना में सिंचाई कार्यों का अनुमानित पूंजीगत व्यय ३२ लाख ६० कम था। कृषि सुधार और शोध तथा नागरिक कार्यों का अनुमानित व्यय भी १५७ लाख ६० कम था। यह भी अनुमान किया गया कि राज्य व्यापार योजनाओं का शुद्ध-व्यय भी १५६ लाख ६० कम होगा। दूसरी ओर विद्युत योजनाओं के अनुमानित पूंजीगत-व्यय में १७२ ६० की वृद्धि हुई। पुनर्वास योजनाओं के अधीन भूमि और भवनों की बिक्री से हुई प्राप्तियाँ जो कि व्यय में कमी के अन्तर्गत हैं, भी कम रखी गयी, जिसके फलस्वरूप अन्य कार्यों के पूंजी लेख में शुद्ध-व्यय में ५४ लाख ६० तक वृद्धि हुई।

### ऋण

सरकार ने ४ प्रतिशत वार्षिक व्याज वाला एक ७६६ लाख ६० का ऋण जारी किया जो कि १९६९ में वापस होगा। अनुमान था कि वर्ष में लगभग १० करोड़ ६० तक "उपाय और साधन" के अन्तर्गत लिये और वर्ष के अन्त तक वापस कर दिये जायेंगे।

### राज्य व्यापार योजनाएं

राज्य व्यापार की अनेक योजनाओं में इस वर्ष खाद्यान्न पूर्ति योजना महत्वपूर्ण रही। सस्ते गन्ने की दूकानों में बिक्री कम होने के कारण वर्ष में सरकार द्वारा खाद्यान्न कम खरीदे गये किन्तु कमी वाले क्षेत्रों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में खाद्यान्नों की इन दूकानों पर सहायता-प्राप्त निर्धारित दर पर बिक्री जारी रही। इस मद में वर्ष में कुल ३५,१४,००० ६० की आर्थिक सहायता दी गयी।

### ३—भूमि राजस्व, नहर बकाया आदि की वसूली\*

#### भूमि राजस्व

गत वर्ष की २४५८ करोड़ ६० (लगभग) की मांग के विरुद्ध इस वर्ष की मालगुजारी की कुल मांग २६.४३ करोड़ ६० (लगभग) थी। यह वृद्धि मुख्य रूप से भूमि-राजस्व मांग सुधार योजना के कार्यान्वयन तथा पिछले वर्षों के लेखों की जाच और सुधार के कारण हुई। २६.४३ करोड़ ६० की कुल मांग में से २६.२६ (लगभग) करोड़ ६० उन क्षेत्रों से, जहाँ जमींदारी का विनाश हो चुका है और १७ लाख ६० राज्य के शेष स्थानों से संबंधित थे।

वर्ष में कुल २१७० करोड़ ६० (लगभग) भूमि-राजस्व वसूल किया गया, जिसमें से २१.५६ करोड़ ६० (लगभग) जमींदारी विनाश क्षेत्रों के तथा १४ लाख ६० (लगभग) शेष क्षेत्रों के थे।

भूमि-प्रबंधक समितियों द्वारा वसूली की योजना सतोषजनक होने के कारण वर्ष के आरम्भ में बन्द कर दी गयी।

भूमि-राजस्व मांग सुधार योजना, जो कि जमींदारी विनाश वाले क्षेत्रों में १ अप्रैल, १९५९ को शुरू की गयी तथा ३१ मार्च, १९६० को पूरी होने की थी, वर्ष १९६०-६१ में भी जारी रखी गयी। कागज और फार्मों की कमी तथा लेखपालों के फसल कटाई प्रयोगों, जमाबंदी तैयारी, सहायता खतौनी और चकबन्दी आदि में लग जाने के कारण कार्य पूरा नहीं किया जा सका। योजना के अधीन १९६०-६१ में नियुक्त अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या में काफी कमी की गयी।

---

\*भूमि राजस्व और नहर बकाया वसूली संबंधी पैराग्राफ ६, ३० सितम्बर, १९६०, को समाप्त होने वाले राजस्व वर्ष से संबंधित हैं।

निम्नलिखित तालिका में योजना की ३१ मार्च, १९६१ तक की प्रगति दी जा रही है :—

सब	भूमि राजस्व की कुल वृद्धि	भूमि राजस्व में कमी	भूमि राजस्व की शुद्ध वृद्धि
( रुपये में )			
वार्षिक भूमि-राजस्व			
मांग	७६,६६,६६७	२१,५६,५६०	५५,१०,१०७
बकाया	४,७६,१८,६०८	१,२२,०४,८४८	३,५४,१४,०६०

[विवरण तैयार करने का काम ७२८ में से ५१ सुपरवाइजर कानूनगो-क्षेत्रों (२,६४५ ग्राम) में बाकी रहा तथा अमल-दरामद और आपत्तियों के निराकरण का कार्य अधिकांश तहसीलों में समाप्तप्राय था। कुछ चकबन्दी के क्षेत्रों को छोड़कर यह योजना ३० सितम्बर, १९६१ तक पूरी होने की आशा थी। चकबन्दी क्षेत्रों में इस योजना को चकबन्दी कार्यों के साथ-साथ अन्तिम रूप दिया जायगा। यह सोचा गया कि बाकी आपत्तियों पर निर्णय हो जाने के बाद वार्षिक-वृद्धि और बकाया में भी कुछ और कमी हो सकती है। योजना की समाप्ति पर आपत्तियों को अन्तिम रूप मिल जाने पर ही वस्तुस्थिति के संबंध में सूचना पायी जा सकती है। योजना के अन्तर्गत पता लगे बकाये की वसूली किस्तों में इस प्रकार की जा रही थी कि काश्तकार वर्ष की चालू मांग के साथ एक वर्ष का ही पुराना बकाया अदा करें।]

#### नहर बकाया

भूमि के कब्जेदारों से वसूल होने वाली काबिजाना-दर की मांग ६.६५ करोड़ रु० (लगभग) से बढ़कर ८.६५ करोड़ रु० (लगभग) हो गयी। पिछले वर्ष की ७,०४,८२-६८८ रु० की मांग के विरुद्ध इस वर्ष की कुल मांग, जिसमें पिछले वर्ष का बकाया भी शामिल है ८.६० करोड़ रु० (लगभग) थी। इसमें से ८.६० करोड़ रु० (लगभग) वसूल किया गया और १८.४० लाख रु० (लगभग) शेष रहा, जिसका विवरण इस प्रकार है—

	रु०
नाममात्र का बकाया .. .. .	१,२६,६०४
न वसूल हो सकने वाला .. .. .	१५,४५६
वसूल करने के लिसिले में कार्यवाही हो रही थी .. .. .	१६,६७,५४४

योग .. १८,३६,६०४  
या १८.४० लाख रु०  
(लगभग)

#### तकावी\*

अधिनियम १६, १८८३ तथा अधिनियम १२, १८८४ दोनों के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में वसूली की शुद्ध मांग ४४६.१७ लाख रु० थी जिसमें से २६७.१७ लाख रु० वसूल किये गये। यह रकम शुद्ध मांग की ५९.८ प्रतिशत थी।

\*३० सितम्बर, १९६० को समाप्त होने वाले राजस्व-वर्ष से संबंधित कैलेन्डर वर्ष १९६० से संबंधित।

## ४—वृहद् जोतकर\*

उत्तर प्रदेश वृहद् जोतकर अधिनियम, १९५७ जो कि राज्य में १ जुलाई, १९५७ से उत्तर प्रदेश कृषि आय-कर के स्थान पर लागू किया गया था, आलोच्य वर्ष में भी जारी रहा। इस अधिनियम में यह व्यवस्था है कि १९४८ के अधिनियम के जो मामले चल रहे हैं वे जारी रहेंगे।

कृषि आय-कर और वृहद् जोतकर संबंधी कार्यों का शासकीय अधिकार लखनऊ के प्रधान कार्यालय में माल बोर्ड के पास बना रहा। हाकिम परगना अपने क्षेत्र के कर निर्धारण अधिकारी बने रहे तथा इनके निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई कमिशनरी के आयुक्त के कार्यालय में होती रही। कर निर्धारण अधिकारी तथा आयुक्त के आदेशों के विरुद्ध निगरानी की सुनवाई लखनऊ में माल बोर्ड में होती रही।

३१ दिसम्बर, १९६० तक के फसली वर्षों १३५५-१३६३ के लिये ६४० करोड़ रु० कुल कृषि आयकर निर्धारित किया गया था जिसमें से ६०७ करोड़ रु० वसूल किया गया।

१३६५-१३६७ फसली तथा १३६८ फसली के कुछ भाग के लिये निर्धारित और वसूल हुए वृहद् जोतकर का विवरण इस प्रकार है—

फसली वर्ष	निर्धारण	वसूली
	रु०	रु०
१३६५	८७,६८,०४६	६४,०४,०२२
१३६६	८८,०३,२२०	५७,०३,२७१
१३६७	७४,८३,१३६	३३,५८,७४१
१३६८	१८,८०,६५४	१८,८६६

१ जनवरी, १९६० से ३१ दिसम्बर, १९६० के बीच दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत अपील और निगरानी के मामलों की विस्तृत जानकारी निम्नलिखित तालिका में दी जा रही है—

अपील	१ जनवरी, १९६० को अर्जित मुकदमों की संख्या	१ जनवरी, १९६० से ३१ दिसम्बर, १९६० के बीच दायर मुकदमों की संख्या	निर्णय के लिये कुल मामलों की संख्या	कालम न० २ में दी गयी अधि में निपटाये गये मामलों की संख्या	शेष
कृषि आयकर	१८१	३२६	५१०	३७६	१३१
वृहद् जोतकर	७२१	२,४३२	३,१५३	२,४६३	६९०

\*वर्ष १९६० से सम्बन्धित।



	१ जनवरी, १९६० को अनिर्णित मुकदमों की संख्या	१ जनवरी, १९६० से ३१ दिसम्बर, १९६० के बीच दायर मुकदमों की संख्या	निर्णय के लिये कुल मामलों की संख्या	कालम न० २ में दी गयी अवधि में निपटाये गये मामलों की संख्या	शेष
निगरानी					
कृषि आयकर ..	३३४	१५१	४८५	१९४	२९१
वृहद् जोतकर ..	३१२	५११	८२३	१०७	७१६

#### ५—स्टाम्प

इस वर्ष स्टाम्प राजस्व में १३.२२ लाख रुपये की वृद्धि हुई। १९५९-६० में ४०१.२८ लाख रुपये (सशोधित) स्टाम्प राजस्व प्राप्त हुआ था। इस वर्ष ४१४.५० लाख रुपये स्टाम्प राजस्व मिला। भूमिदारी अधिकारों के हस्तांतरण और बिक्री के मामलों तथा अन्य मुकदमों में वृद्धि होने के कारण ही यह बढोत्तरी संभव हुई। भारतीय स्टाम्प अधिनियम और कोर्टफोर्स अधिनियम के कार्यान्वयन पर होने वाला व्यय भी १९५९-६० से व्यय ९.५८ लाख रुपये की तुलना में घटकर १९६०-६१ में ७.२० लाख रुपये हो गया। यह मुख्य रूप से खजानों को भेजे गये स्टाम्पों के मूल्यों पर कम खर्च होने के कारण संभव हुआ।

#### ६—आबकारी†

आलोच्य वर्ष में मद्य-निषेध बदायूँ, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, कानपुर, उन्नाव, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर और रायबरेली जिलों तथा हरद्वार, ऋषिकेश और वृन्दावन में लागू रहा। उपर्युक्त ११ जिलों तथा वृन्दावन में मद्य-निषेध संबंधी अपराधों को पता लगाने की जिम्मेदारी पुलिस विभाग पर रही। कानपुर में १२ ऐक्साइज इन्स्पेक्टर और ८० ऐक्साइज चपरासी सीनियर सुपरिण्डेंडेंट पुलिस के सहायतार्थ तैनात रहे। ऋषिकेश और हरद्वार में मद्य-निषेध लागू करने के काम आबकारी कर्मचारियों को दिया गया।

गाजा और अफीम का निषेध जारी रहा। उन सभी जिलों में, जहाँ मद्य-निषेध लागू नहीं था, देशी शराब और भाग की दुकानें नीलाम प्रणाली पर स्थापित की गयीं, जबकि गाजा की दुकानें परमिट पर गाजा देने के लिये सरचार्ज प्रणाली के अन्तर्गत खोली गयीं। डाक्टरी परमिट पर लोगों को अफीम खजानों या उप-खजानों के तहविलदार तथा राज्य प्रबंधित दुकानों के बिक्री सम्बन्धी कर्मचारी देते रहे।

गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी १९ जिलों में ताड़ी की दुकानें नीलाम प्रणाली द्वारा दी गयीं तथा ८ जिलों में वृक्ष-कर प्रणाली चालू रही। वृक्षकर प्रणाली वाले ८ जिले

† कैलेंडर वर्ष १९६० से संबंधित।

हैं—गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, गजपुर, बलिया, वाराणसी, आजमगढ़ और मिर्जापुर।  
नीलाम एवं वृक्ष-कर प्रणाली आजमगढ़ और बलिया में तथा गोरखपुर, देवरिया, बस्ती,  
वाराणसी, आजमगढ़ और मिर्जापुर जिलों के सभी कैंटनमेंट क्षेत्रों और नगरपालिकाओं  
में लागू रही।

अफीम, भांग और शराब के व्यापार द्वारा सप्लाई किये जाने के भाव में कोई परिवर्तन  
नहीं हुआ। देश में ही बनी हुई विदेशी शराब की परमिट फीस और महसूल की दर भी  
अपरिवर्तित रही। देशी शराब और भांग की खपत इस वर्ष कुछ बढ़ गयी।

### सम्पूर्ण आबकारी राजस्व

कैलेंडर वर्ष १९६० में आबकारी का कुल राजस्व ७१८ करोड़ रु० था, जबकि गत  
वर्ष यह केवल ६.३७ करोड़ रु० था।

### खपत

(क) देशी शराब—देशी शराब की खपत १०,८८,६६६ (१,२६,८६६) एल्०पी०-नौलन  
थी। इस प्रकार खपत में २५.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ख) भांग—भांग की कुल खपत १,६४,०८६ (१,५६,५०४) सेर थी। भांग की  
खपत में २.८ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ग) ताड़ी—ताड़ी में कुल ३६.४६ (३६.६०) लाख रुपये राजस्व प्राप्त हुआ।  
इस मद में ४.३ प्रतिशत की वृद्धि रही।

कैलेंडर वर्ष १९६० में एक्ससाइज ओपियम ऐण्ड ड्रंजरस ड्रग्स ऐक्ट के अन्तर्गत पता लगाये  
गये मामलों की संख्या १६,६८६ थी, जबकि गत वर्ष १६,३६६ मामलों का पता लगाया गया  
था। इस सख्या में गाजा दस्ता द्वारा पता लगाये गये नये नये मामले भी शामिल हैं। इसमें  
से ३,०३२ (२,७३१) गैरकानूनी ढंग से शराब बनाने, ५,१५८ (४,५२६) शराब संबंधी  
अन्य अपराधों, ५,६२१ (६,१३८) भांग, १,५८७ (१,६५६) अफीम से, १,१७५ (१,२१६)  
अफीम पीने से और ५३ (६०) विविध अपराधों से संबंधित थे।

आलोच्य वर्ष में जितने मामलों का पता लगा, उनमें २०,०७३ (१७,३०६) क्वार्ट  
शराब, २४१ मन ३४ सेर ३ छटाक (१८८ मन २० सेर १२ छटाक) गाजा, ४३ मन २५  
सेर ४ छटाक (३४ मन ५ सेर ५ छटाक) भांग, ११ मन २० सेर ७ छटाक (६ मन  
६ सेर १५ छटाक) अन्य शराब, १६ सेर १२ छटाक (३ मन ३६ सेर) अफीम  
पकड़ी गयी।

आलोच्य वर्ष में भांग और शराब के ५ दस्ते काम करते रहे। प्रत्येक दस्ता एक्ससाइज  
सुपरिटेण्डेंट के अधीन तथा सहायक एक्ससाइज कमिशनर (दस्ते) की देख रेख में रहा।

आलोच्य वर्ष में गाजा और शराब दस्तों ने १,४८१ (१,६१२) मामलों का पता लगाया,  
जिनमें से ४ (१५) गैरकानूनी ढंग से शराब बनाने, ५६ (४४) शराब विषयक अन्य अपराधों

\*ब्रैकेट में दिये गये आंकड़े कैलेंडर वर्ष १९५६ से संबंधित हैं।

६८४ (१,१३१) भांग, ३८५ (३६४) अफीम, ४५ (५३) अफीम पीने तथा ४ (५) विविध अपराधों से सबधित थे।

दस्तो ने जिन मामलो का पता लगाया उनमें ४०५ ७ (४१५ ६) क्वार्ट शराब, ८० मन ११ छटांक (६७ मन ३३ सेर २ छटांक) गाजा, ८ मन २ सेर १५ छटांक (४ मन १० सेर ११ छटांक) भांग, २ मन १७ सेर १४ छटांक (३ मन ३१ सेर) चरस और ६ मन ३४ सेर (३ मन ११ सेर ४ छटांक) अफीम पकड़ी गयी।

### चालक मद्यसार

आलोच्य वर्ष में मसूरपुर में एक नयी भट्ठी खुलने के कारण राज्य में चालक मद्यसार की भट्ठियों की कुल सख्या १६ हो गयी। गैर-चालक मद्यसार की पाचो भट्ठिया पूर्णवत् जारी रही। चालक मद्यसार पेट्रोल मिश्रण योजना समस्त राज्य में लागू रही। पेट्रोल में मिश्रण के लिये इस वर्ष कुल ५३,५५,३५० (५८,८१,७३८) बल्क गैलन चालक मद्यसार दिया गया। इसमें दिल्ली और पंजाब की विभिन्न डिपो को दिया गया २५,०२,३७३ (२८,६७,६५५) बल्क गैलन तथा उत्तर प्रदेश की विभिन्न डिपो को दिया गया २८,५२,६७७ (२६,८३,७०३) बल्क गैलन भी शामिल है। इसके अतिरिक्त २४,८८,०५५ (१७,०६,०६८) बल्क गैलन चालक मद्यसार औद्योगिक कार्यों के लिये तथा २४,८८,०५५ बल्क गैलन चालक मद्यसार भारत से निर्यात करने के लिये दिया गया।

### सीरा

सीरा के नियंत्रण और वितरण का कार्य आबकारी आयुक्त के अधीन पूर्ववत् रहा।

### ७—बिक्री-कर

बन्धी फर्मों पर बिक्री-कर लगाने और प्रार्थनापत्रों पर फीस लगाने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम में आलोच्य वर्ष में कुछ संशोधन किये गये।

आलोच्य वर्ष में विभिन्न वस्तुओं पर लागू बिक्री-कर दरों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ। १ अप्रैल, १९६० से खराब हुई वस्तुओं पर भी बिक्री-कर लगाया गया और १०० रु० के लिये २५ नये पैये कर निर्धारित किया गया। वर्ष १९६०-६१ में अड़ो और उन सिलक के कपड़ों पर, जिन पर अतिरिक्त आबकारी कर लागू है, बिक्री-कर नहीं लगाया गया।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर और केंद्रीय बिक्री-कर से हुई प्राप्तिया वर्ष १९६०-६१ में ११६६.८८ लाख रु० हो गयी, जब कि वर्ष १९५६-६० में यह केवल ६६०.७७ लाख रु० थी। व्यय में १९५६-६० के अपेक्षा कुछ वृद्धि हुई। १९५६-६० में व्यय ४०.११ लाख रु० तथा १९६०-६१ में ४२.१७ लाख रु० था।

### ८—मनोरंजन और बाजी-कर

आलोच्य वर्ष (१९६०-६१) में मनोरंजन और बाजी-कर से कुल १,५६,८४,०५५ रु० की आय हुई जबकि वर्ष १९५६-६० में १,४५,४६,७८७ रु० (संशोधित) की आय हुई

है। आय में १४,३४,२६८ रु० की वृद्धि मुख्यरूप से कर के खंड प्रणाली पर न लगाकर प्रतिशत प्रणाली पर लगाने के कारण हुई। प्रतिशत प्रणाली १ फरवरी, १९५६ को लागू की गयी। आलोच्य वर्ष में वसूली नकद रूप में की गयी।

आलोच्य वर्ष में कुल व्यय ३,२८,१०० रु० था, जबकि १९५६-६० में व्यय ३,१८,६०४ रु०<sup>१</sup> (सशोधित) था।

आलोच्य वर्ष में प्रदेश में दो सहायक मनोरंजन और बाजी-कर आयुक्त और ७० मनोरंजन कर इस्पेक्टर, जिनमें कि १४ वरिष्ठ इस्पेक्टर भी थे, प्रदेश में मनोरंजन और बाजी-कर आयुक्त की सहायतार्थ नियुक्त थे।

मनोरंजन और बाजी-कर विभाग ने आलोच्य वर्ष में २५८ मुकदमे चलाये। गत वर्ष २३० मुकदमे दायर किये गये थे। आलोच्य वर्ष चलाये गये मुकदमों में १८५ मामले निर्णीत हुए और ६७ विचाराधीन रहे। ६ मुकदमों की कार्यवाही अभियुक्तों के उपलब्ध न होने के कारण स्थगित कर दी गयी। निर्णीत मामलों में से १७३ में जुर्माना किया गया, ५ में लाइसेंस रद्द किया गया, ४ में चेतावनी दी गयी और ३ छोड़ दिये।

मनोरंजन और बाजी-कर अधिनियम की व्यवस्थाओं को अस्थायी रूप से ५४ मेलों और प्रदर्शनियों पर लागू किया गया। इससे ६०,००० रु० की राजस्व की प्राप्ति हुई।

३०४ मामलों में मनोरंजन और बाजी-कर वसूल नहीं किया गया, क्योंकि इनकी आय पुण्यार्थ, दानार्थ या खेल-कूद या संगीत के प्रोत्साहन के लिये व्यय होनी थी।

## अध्याय ८

### राजनीतिक

#### १—चुनाव

आलोच्य वर्ष में निर्वाचन विभाग (चुनाव विभाग) (संसदीय विभाग) द्वारा सम्पन्न कार्यों में मुख्य थे—मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण, लोक-सभा और विधान मंडल के उप-चुनाव तथा विधान-परिषद के द्वि-वार्षिक चुनाव सम्बन्धी कार्य और तृतीय आम चुनाव और चुनाव याचिकाओं विषयक कार्य।

आलोच्य वर्ष में १७८ विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियां संशोधित की गयी। मतदाता सूचियां तैयार करने की संशोधित योजना के अन्तर्गत उपर्युक्त सूचियां जिला चुनाव कार्यालय में डुप्लिकेट मशीनों पर तैयार की गयी। इस वर्ष योजना से तृतीय आम चुनाव में मतदाता सूचियां तैयार करने के मद में १६ लाख रुपये की बचत होने की आशा है।

१९६०-६१ में कुल ८ उप-चुनाव हुए, जिनमें से ३ विधान सभा के, ३ लोक सभा के और २ राज्य सभा के थे। ५ उप-चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवार और एक में सोशलिस्ट पार्टी का उम्मीदवार विजयी हुआ। निम्नलिखित तालिका में इन उपचुनावों का विवरण दिया जा रहा है—

निर्वाचन क्षेत्र	उस सदस्य का नाम जिसका स्थान रिक्त हुआ	चुनाव की तिथि	विजयी उम्मीदवार और उसकी पार्टी
विधान सभा—			
(१) अकबरपुर जि० कानपुर।	श्री बलवन्त सिंह	६-५-१९६०	श्री राम दुलारे मिश्र, कांग्रेस।
(२) बहराइच (दक्षिण)	श्री वीरेंद्रविक्रम सिंह	२८-११-१९६०	श्री बदलू राम-प्रजा सोशलिस्ट पार्टी।
लोकसभा			
(१) उन्नाव	श्री विशम्भर दयाल	१२-४-१९६०	श्री लीलाधर, कांग्रेस।
(२) सीतापुर	श्री प्राणिलाल	२३-११-१९६०	श्री भवानी प्रसाद, कांग्रेस।
(३) रायबरेली	श्री फीरोज गांधी	२२-११-१९६०	श्री राजेंद्र प्रताप, सिंह, कांग्रेस।
विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गये	श्री धरम दास	१०-११-१९६०	श्री ए० सी० गिलबर्ट।
	श्री बालकृष्ण शर्मा	१-८-१९६०	श्री अर्जुन अरोरा।

आलोच्य वर्ष में फरवरी-मार्च १९६२ में सम्पन्न आम चुनाव के आरम्भिक प्रबन्ध किये गये।

- १९६० में विधान परिषद के ३६ सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हुआ। अप्रैल, १९६० में ३२ स्थानों के लिये द्वि-वार्षिक चुनाव हुये और ४ सदस्य नाम दर्ज किये गये।

#### स्थानीय निकायों के चुनाव

१९६०-६१ में अनूपशहर नगरपालिका (जिला बुलन्दशहर) और नवाबगंज और कर्नलगंज नगरपालिकाओं (जिला गोडा) के ग्राम चुनाव हुये। उसके अतिरिक्त जत्तारी (अलीगढ़), लोहम्याट (अल्मोड़ा), ओएल ढकवा, घोरेशरा, सिघई भरोरा (खोरी) और निवारी (मेरठ) की टाउन एरिया कमेटियों के भी चुनाव सम्पन्न हुये। १९६१ में नगर-पालिकाओं के नगर-प्रमुखों का द्वितीय वार्षिक चुनाव हुआ। इनके अलावा सदस्यों, अध्यक्षों आदि की मृत्यु या इस्तीफे के कारण रिक्त हुये स्थानों को भरने के लिये नगरपालिकाओं, नोटोफाइड एरिया कमेटियों और टाउन एरिया कमेटियों में अनेक उप-चुनाव हुये।

अन्तरिम जिला परिषदों के लिये गांव सभाओं के प्रतिनिधि निर्वाचित करने तथा खुर्जा (बुलन्दशहर), सीतापुर और मुहमदी (खोरी) की नगरपालिकाओं, तुलसीपुर टाउन एरिया एवं मुगलसराय रेलवे बस्ती नोटोफाइड एरिया (वाराणसी) के ग्राम चुनाव आयोजित करने के सम्बन्ध में आरम्भिक प्रबन्ध किये गये।

#### २४—राजनीतिक कार्य-कलाप

आलोच्य वर्ष में प्रदेश के राजनीतिक क्षेत्र में काफी चहल-पहल थी, क्योंकि वर्ष १९६२ के ग्रामचुनाव की दृष्टि से सभी राजनीतिक पार्टियाँ सक्रिय रही। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने राज्य के व्यापक दौरे किये तथा अपनी-अपनी विचार-धाराओं के प्रचारार्थ पुस्तिकाएँ वितरित की। विभिन्न पार्टियों के चिन्तन और कार्यकलापों पर उत्तरी सीमा पर चीन के आक्रमण, केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल और पंजाबी सूबा की मांग ने थोड़ा-बहुत प्रभाव डाला। एक देश व्यापी आन्दोलन के भाग के रूप में सोशलिस्ट पार्टियाँ ने अपनी विभिन्न मांगों के सिलसिले में, जिनमें अंग्रेजी का वहिष्कार तथा कुछ जिलों की माल-गुजारी से छुट देने की मांग शामिल थी, वर्ष के आरम्भ में एक आन्दोलन संगठित किया। विभिन्न विरोधी दल स्थानीय मामले उठाते रहे और कुछ अवसरों पर प्रदर्शन, हड़तालें और आन्दोलन संगठित करने के प्रयत्न भी किये गये। प्रजा सोशलिस्ट पार्टियाँ और कम्युनिस्ट पार्टियाँ ने केन्द्रीय कर्मचारियों के कुछ वर्गों द्वारा संगठित हड़तालों में विशेष रूप से दिलचस्पी ली और कुछ स्थानों पर उन्होंने इस सम्बन्ध में संयुक्त सभाये भी की। भारत-चीन-सीमा विवाद पर कम्युनिस्ट पार्टियों के रुख की अन्य राजनीतिक पार्टियों और जनता ने भी आलोचना की। आलोच्य वर्ष में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की शक्ति बढ़ी, क्योंकि सोशलिस्ट यूनिटी पार्टी का उससे विलयन हुआ। विधान मंडल में स्वतन्त्र पार्टी को विरोधी पार्टियों में से एक स्वीकार किया गया। प्रदेश कांग्रेस के चुनावों में भी विभिन्न पार्टियों ने काफी दिलचस्पी दिखायी। प्रदेश कांग्रेस के चुनाव सम्पन्न होने के बाद उत्तर प्रदेश मन्त्रिमंडल में परिवर्तन हुआ।

मऊ (आजमगढ़) में मई, १९६० को हुये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पंचम वार्षिक सम्मेलन में आर्थिक स्थिति पर चिन्ता प्रकट की गयी। सरकार की श्रम-नीति की आलोचना की गयी तथा गन्ने का मूल्य बढ़ाने की मांग की गयी।

शुरू में कुछ जिलों में पार्टियाँ से चुने सदस्यों ने जुलूस निकाले और सभायें की तथा सीमा-विवाद पर भारत और चीन के प्रधान मन्त्रियों की बातों आयोजित करने के सम्बन्ध में विरोध प्रकट किया।

जून, १९६० में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने नैनीताल में कुछ मिनिस्टीरियल कर्मचारियों और चपरासियों का एक सम्मेलन संगठित करने में विशेष दिलचस्पी प्रकट की। उन्होंने एक वेतन आयोग नियुक्त करने तथा आवास सुविधा आदि की मांग की।

सितम्बर, १९६० के पहले हफ्ते में पार्टी के सदस्यों ने कुछ जिलों में मजदूर अधिष्ठात्री दिवस मनाया। ट्रेड यूनियनों में बाहर के लोगों के पद-ग्रहण करने पर लगे प्रतिबन्ध की आलोचना की गयी तथा १५वें श्रम-आयोग द्वारा निर्दिष्ट राजकीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन की मांग की गयी।

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की कार्यकारिणी ने अपना अधिवेशन लखनऊ में दिसम्बर, १९६० में किया, जिसमें विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श हुआ। सरकार पर यह आरोप लगाया गया कि वह चीनी उद्योग द्वारा अर्जित लाभ में से गन्ना उत्पादकों को उनका उचित हिस्सा दिलाने में असफल हुई है।

जनवरी, १९६१ में कुछ जिलों में पार्टी के सदस्यों ने नेपाल में निर्वाचित सरकार भग की जाने के विरोध में नेपाल दिवस मनाया।

अपनी विभिन्न मांगों की पूर्ति में सोशलिस्ट पार्टी ने मई, १९६० के आरम्भ में राज्यस्तर पर एक आन्दोलन शुरू किया, जिसे उन्होंने 'सविनय अवज्ञा भग आन्दोलन' की संज्ञा दी। यह आन्दोलन आरम्भ में १९ तथा बाद में २३ अन्य जिलों में शुरू किया गया। पार्टी के सदस्यों ने खाली भूमि, गोदाम और सस्ते गल्ले की दुकानों पर कब्जा करने की कोशिश की, अंग्रेजी वाले साइनबोर्डों पर कालिख पोती और अदालतों की पिकेटिंग की। जनता की सुरक्षा और प्रशासन के सुचारु स्थान तथा शांति-व्यवस्था बनाये रखने के लिये कदम उठाने पड़े और कानून के विरुद्ध कार्य करने वाले लगभग २,००० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। क्षमा याचना करने पर इनमें से अनेक छोड़ दिये गये। आन्दोलन को जनता का सहयोग नहीं मिला और कुछ सप्ताहों में ही वह केवल नाममात्र को रह गया। पार्टी ने नवम्बर, १९६० में आन्दोलन को औपचारिक ढंग से स्थगित कर दिया। सरकार ने सद्भावना के इंगित के रूप में दिसम्बर, १९६० में आन्दोलन के बंदियों की आम रिहाई, विचाराधीन मामलों वापस लेने तथा जुर्मानों की वसूली बन्द करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किये।

इस आन्दोलन से पहले पार्टी के नेताओं ने जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये प्रदेश का व्यापक दौरा किया था।

केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले छात्रों को चित्रकूट (बादा) में हुई एक सार्वजनिक सभा में नवम्बर, १९६० में यह सलाह दी गयी कि वे स्कूलों और कालेजों के सामने धरना दें तथा मांग करें कि उन्हें परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाय।

पार्टी के सदस्यों ने अक्टूबर, १९६० में गाजीपुर में कृषक पुरुषों और महिलाओं की एक सामूहिक भूख हड़ताल चकबन्दी कर्मचारियों द्वारा की गयी कार्यवाही के विरोध में संगठित करने की भी कोशिश की। देवरिया और गोरखपुर जिलों में दिसम्बर, १९६० में कई चीनी मिलों में आन्दोलन संगठित किये गये।

सोशलिस्टों ने श्रम के क्षेत्र में आलोच्य वर्ष में काफी दिलचस्पी प्रकट की और उनके कार्यों से ऐसा लगा कि वे केन्द्रीय राजकीय कर्मचारियों, राजकीय रोडवेज और चूर्क सीमेंट फ़ैक्टरी आदि के कर्मचारियों की मांगों का समर्थन कर रहे थे।

कम्युनिस्ट पार्टी की प्रादेशिक पार्टी की बैठक लखनऊ में जून, १९६० में हुई थी, जिस में एक प्रस्ताव पारित कर पार्टी की इकाइयों से कहा गया कि वे उन कदमों को सशक्त करें, जो सूती कपड़ा मिलों के मजदूर सूती कपड़ा वेतन-बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये उठाये।

मई, १९६० में अखिल भारतीय किसान सभा का १७वां वार्षिक अधिवेशन गाजीपुर में हुआ। किसानों से कहा गया कि वे सरकार से अपने अधिकारों की मांग करें। ऐसा कहा जाता है कि पार्टी से कुछ नेताओं ने सार्वजनिक सभाओं में, जिनको उन्होंने ही

आयोजित किया था, यह बहस करने की कोशिश की थी कि भारत और चीन के बीच सीमा के सम्बन्ध में कोई झगड़ा है ही नहीं और लागजू केवल तीन वर्ग मील क्षेत्रफल वाला एक झहत्त्वहीन स्थान है।

सदा की तरह अनेक जिलों में 'मई दिवस' मनाया गया, जिसमें सरकार पर यह आरोप लगाया गया कि वह ऐसी नीति का पालन कर रही है, जिसमें पूँजीवादियों को समर्थन मिलता है। पार्टियों के सदस्यों ने अप्रैल, १९६० में आजमगढ़ में एक पुलिस विरोधी प्रदर्शन किया, जिसमें लाठियों और बल्लों से लेस लोगों का एक जुलूस निकाला गया। सदस्यों ने झाँसी में नवम्बर, १९६० में एक किसान-सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें किसानों के लिये कहा गया कि वे पचायतो के अपने प्रतिनिधि स्वयं चुने। नवम्बर, १९६० में वाराणसी में 'गोआ दिवस' मनाया गया। सरकार से विदेशी-फर्मों का राष्ट्रीकरण करने का भी अनुरोध किया गया।

आलोच्य वर्ष के प्रारम्भ में टेहरी गढ़वाल में पार्टियों की एक जिला शाखा स्थापित की गयी। अखिल भारतीय जनसंघ का त्रिदिवसीय वार्षिक सम्मेलन लखनऊ में ३० दिसम्बर, १९६० से आरम्भ हुआ, जिसके अध्यक्षपदीय भाषण में सरकार की नीतियों और कार्य-कलापों को दुर्लभ और परम्पर विरोधी घोषित किया गया।

आरम्भ में अप्रैल, १९६० में पार्टियों ने प्रदेश के विभिन्न भागों में एक 'दृढ़ रहो सप्ताह' मगठित किया। चीनी प्रधान मन्त्री को वार्ता के लिये भारत बुलाने के सुझाव का विरोध किया गया और विभिन्न जिलों में पार्टियों के सदस्यों ने जिला मजिस्ट्रेटों को इस आशय के स्मृतिपत्र दिये कि भारतीय प्रधान मन्त्री दृढ़ नीति अपनावें। इसी प्रकार अक्तूबर, १९६० में पार्टियों ने एक कश्मीर दिवस आयोजित किया। इस अवसर पर संगठन ने सार्वजनिक सभाओं में सरकार पर यह आरोप लगाया कि वह कश्मीर के मामले में कंट्रोल नीति का पालन कर रही है।

पार्टियों के संसदीय बोर्ड की बैठक जुलाई, १९६० में लखनऊ में हुई। संसदीय बोर्ड ने उन केन्द्रीय राजकीय कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति प्रकट की, जिन पर केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल में भाग लेने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही होने की सम्भावना थी। ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की आलोचना की गयी और यह मांग भी की गयी कि मामले हटा दिये जायें।

प्रदेश के अनेक स्थानों में पार्टियों के सदस्यों ने 'डा० एस० पी० मुखर्जी दिवस' जून, १९६० में मनाया। सितम्बर, १९६० में इलाहाबाद में हुई एक सभा में पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये विदेशी सहायता लेने की नीति के प्रति असन्तोष प्रकट किया गया और सरकार पर आवश्यक वस्तुओं का दाम बढ़ाने का आरोप लगाया गया। जनसंघ के नेतागण भारत पर पाक नहर जल-संधि के आलोचक रहे और यह कहा गया कि इस संधि में पाकिस्तान से बकाये का समाधान नहीं हुआ है और मंगला बांध के बारे में भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यह मांग की गई कि जब तक कश्मीर में पाकिस्तानियों का अनधिकार तथा गैर-कानूनी कब्जा खतम नहीं होता, इस संधि को कार्यान्वित न किया जाय।

स्वतन्त्र पार्टियों के सदस्यों ने विभिन्न जिलों में सितम्बर, १९६० में मुद्रास्फीति विरोधी दिवस मनाया और जुलूस तथा सभाएँ आयोजित कीं। सरकार पर मुद्रास्फीति को रोकने में असफल होने का आरोप लगाया गया। पार्टियों के उद्देश्यों के प्रचारार्थ पुस्तिकाओं का व्यापक वितरण किया गया। कुछ स्थानों में हवाई जहाज से भी पुस्तिकाएँ गिरायी गयीं। पुस्तिकाओं में शामिल अन्य विषयों में सहकारी कृषि की आलोचना की गयी थी और पूर्णतया श्रमिकों द्वारा नियंत्रित श्रमिक यूनियनों का पृष्ठपेक्षण किया गया था।

पार्टियों का प्रदेशीय सम्मेलन वर्ष के आरम्भ में अगस्त, १९६० में लखनऊ में हुआ। सम्मेलन में पारित प्रस्तावों में यह मांग की गयी कि आम चुनावों के पांच महीने पहले मंत्रिमंडल इस्तीफा दे दिया करे और उस काल में राष्ट्रपति का शासन स्थापित किया जाय।



अप्रैल, १९६० में पार्टी के अखिल भारतीय नेताओं ने प्रदेश के अनेक जिलों का दौरा किया और सभाओं में भाषण दिये। अपने भाषणों में उन्होंने सरकार की सामान्यतः आलोचना की और जनता से यह अनुरोध किया कि वह पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। जून १९६० में देहरादून में हुई एक सभा में नेताओं ने सरकार पर यह आरोप लगाया कि यह चीनियों द्वारा किये गये भारतीय सीमा अतिक्रमण के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे रही है।

आलोच्य वर्ष में हिन्दू महासभा के कार्य-कलाप विभिन्न अवसरों पर सम्मेलन करने तक ही समिति रहे।

हिन्दू महासभा ने गोबध बन्द करने, साम्प्रदायिक मुस्लिम संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने, भारत-पाक नहर जल-संधि को भंग करने और उच्च न्यायालयों में हिन्दी का प्रयोग आरम्भ करने की मांग की। पंजाबी सूबा की मांग की निन्दा की गयी और दक्षिण-पंथी पार्टियों का एक संयुक्त मोर्चा साम्यवाद के प्रचार को रोकने के लिये बनाने का समर्थन किया गया। हिन्दू महासभा भारत सरकार की परराष्ट्र नीति की आलोचक रही।

आलोच्य वर्ष में प्रदेश के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्य-कलाप शाखायें ड्रिल और रैलियाँ आदि संगठित करने तक ही सामान्यतः सीमित रहे। वर्ष में आयोजित कुछ रैलियों और सार्वजनिक सभाओं में पहले के समान ही देश के बटवारे और अखंड भारत विचारधारा का उल्लेख किया गया। अखिल भारतीय नेतृत्व में पंजाबी सूबा की मांग की निन्दा की गयी। देश सशक्त करने पर विशेष बल दिया गया।

प्रदेश के सिक्ख समुदाय के कुछ लोगो ने पंजाबी सूबा की मांग का समर्थन किया और कुछ स्वयंसेवक आन्दोलन में भाग लेने के लिये दिल्ली भी गये। जमीयत-ए-इस्लामी के कार्यकर्त्ताओं ने साप्ताहिक और मासिक इजतेमा विभिन्न स्थानों में किये। जमीयत के सिद्धान्त और विचारधारा का प्रचार किया गया और लोगो को यह बतलाया गया कि वह इस्लामी सस्कृति और धर्म का कड़ाई से पालन करें। दिल्ली में नवम्बर, १९६० में हुये अखिल भारतीय जमीयत-ए-इस्लामी सम्मेलन में भाग लेने के लिये काफी जनसंख्या में कार्यकर्त्ता प्रदेश से गये।

आलोच्य वर्ष में मुस्लिम जमात की कार्रवाई सभाओं तक ही सीमित रही। लखनऊ जमात की कार्यकारिणी की बैठक लखनऊ में मई, १९६० में और प्रदेशीय कार्यकारिणी की बैठक भी लखनऊ में ही नवम्बर, १९६० में हुई। जमात में मुस्लिम लीग के पुनर्गठन पर असंतोष प्रकट किया गया किन्तु अकालियों की पृथक सूबा संबंधी मांग का समर्थन किया गया।

आलोच्य वर्ष में प्रदेश के कुछ स्थानों में खाकसारों के पुनर्जीवित होने के संकेत मिले और कुछ जिलों में वह अपना सामान्य कार्रवाई करते रहे।

## अध्याय ६

### समाचार-पत्र

#### समाचार-पत्रों की निरीक्षा

—सरकार को समाचार-पत्रों में प्रकाशित मतों और समाचारों से अवगत कराने के लिये सूचना विभाग की निरीक्षाशाखा ने कुल ३२,०६६ समाचार-पत्रों की प्रतियों की, जिनमें प्रदेशीयतर समाचार-पत्र भी शामिल थे निरीक्षा की और १,३०,३६३ कतरने वर्ष १९६०-६१ में प्रस्तुत कीं । निरीक्षा-शाखा ने १२८ से अधिक विवरण, जिनमें विशेष विवरण भी शामिल थे और समाचारपत्रों की टिप्पणियों की पाक्षिक आलोचनाएं आदि भी प्रस्तुत कीं । टेलीप्रिंटर पर प्राप्त ६७९ समाचार संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किये गये ।

कानून भंग करने संबंधी नियमों और भारत-पाक समझौते तथा प्रेस-संहिता के नियम तोड़ने के मामलों की जांच के लिये समाचार-पत्रों का निरीक्षण जारी रहा ।

#### प्रेस और पुस्तक अधिनियम के रजिस्ट्रेशन का कार्यान्वयन

प्रेस और पुस्तकों के रजिस्ट्री संबंधी अधिनियम, १८६७ की व्यवस्थाओं को लागू करने का कार्य पूर्ववत् जारी रहा । जहां भी आवश्यक था, इस अधिनियम की व्यवस्थाओं को भंग करने वाले समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं के प्रकाशकों और मुद्रकों को चेतावनी दी गयी, किन्तु इस वर्ष कोई मुकदमा नहीं चलाया गया ।

#### समाचार पत्रों की टिप्पणियों की समीक्षा

आलोच्य वर्ष में तृतीय पंचवर्षीय योजना के केन्द्रीय और राजकीय स्तरों पर कार्यान्वयन के लिये किये गये प्रयासों की समाचार-पत्रों ने सराहना की और उनमें विशेष दिलचस्पी दिखायी ।

प्रथम पंच-वर्षीय आयोजनों तथा आदर्श कल्याणकारी राज्य की सफलता के लिये त्याग करने के निमित्त जनता से अनुरोध किया गया । गणराज्य-दिवस के अवसर पर गत वर्ष की प्रगति की समीक्षा की गयी और देश की राजनैतिक दृढ़ता पर संतोष प्रकट किया गया । भारत की उत्तरीय सीमा पर घिरते खतरे का विशेष रूप से उल्लेख हुआ, किन्तु साथ-साथ यह भी कहा गया कि जब तक देश की जनता मुकाबला करने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ है और हम आपस के झगड़ों से मुक्त हैं, हमारा गणराज्य सुदृढ़ रहेगा । राष्ट्रीय भावना और एकता कायम रखने पर विशेष बल दिया गया ।

सीमा की स्थिति पर नवम्बर, १९६० में लोक-सभा में हुए विचार-विमर्श में सभी वर्गों के समाचार-पत्रों ने विशेष रुचि दिखायी । इस मत की पुष्टि की गयी कि चीनियों को यह अच्छी तरह समझने पर बाध्य कर दिया जाय कि भारत पर आक्रमण करना उनके लिये लाभदायक नहीं होगा । इस संबंध में भूटान के बारे में भारत द्वारा दिये गये निर्णय का समर्थन किया गया । यह इंगित स्पष्ट रूप से किया गया कि भूटान यह समझ चुका है कि सीमा की घटना से उसकी आंतरिक शांति प्रभावित न हो ऐसा हो ही नहीं सकता । यह अनुरोध किया गया कि सभी आवश्यक मामलों में भारत का सहयोग प्राप्त किया जाय ।

बेखुबारी को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने के प्रश्न पर समाचार-पत्रों ने व्यापक रूप से टिप्पणियां कीं । एक वर्ग ने पश्चिमी बंगाल के विधान-मंडल के सदस्यों से यह कहा कि वे इस मसले पर पश्चिमी बंगाल के ही नहीं, एक व्यापक और अखिल भारतीय दृष्टिकोण से

विचार करें। एक अन्य वर्ग ने इस मत का समर्थन नहीं किया कि बरेली का विभाजन बंगाल के लिये हितकर नहीं होगा।

भारत और पाकिस्तान के बीच जल-संधि पर हस्ताक्षर होना आलोच्य वर्ष की एक महत्वपूर्ण घटना मानी गयी। यह आशा प्रकट की गयी कि भारत के इस मैत्रीपूर्ण संकेत पर पाकिस्तान भी सद्भावनापूर्ण रुख अपनायेगा। किंतु समाचार-पत्रों के एक वर्ग ने यह अनुभव किया कि पाकिस्तान ने अभी तक नियमपूर्वक भारत से लिया ही है, उसे दिया कुछ नहीं है।

भारत और पाकिस्तान के पुराने वित्तीय मसलों के बारे में पाकिस्तान के रुख पर खेद प्रकट किया गया और भारत सरकार से यह कहा गया कि वह तुष्टिकरण की नीति त्याग दे।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारंभिक मसविदे पर काफी ध्यान दिया गया। आयोजना में कृषि को प्राथमिकता देने के विचार पर जोरदार समर्थन किया और विभिन्न योजनाओं के उचित कार्यान्वयन तथा जन-सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता पर विशेष रूप से बल दिया गया।

सितम्बर १९६० में हुए राष्ट्रीय विकास परिषद् के द्वि-दिवसीय अधिवेशन की अधिकांश पत्रों ने चर्चा की। इस सुझाव की कि राज्य सरकार कम से कम ५५० करोड़ रु० लगाये और ग्रामीणवर्ग आयोजना के खर्च का एक बड़ा भाग वहन करे, समाचार-पत्रों के एक वर्ग ने आलोचना ~~की~~ कुछ समाचार-पत्रों ने राज्यों से यह कहा कि वे अपने लिये साधन स्वयं जुटायें।

तृतीय पंच-वर्षीय आयोजना के प्रारम्भिक मसविदे और उसकी कुल धनराशि में कृषि के लिये निर्धारित हिस्से पर काफी टिप्पणियाँ निकली। समाचार-पत्रों के एक वर्ग ने एक और औद्योगिक विकास योजनाओं का स्वागत किया तथा यह आशा प्रकट की कि तृतीय आयोजना के अंत तक उत्तर प्रदेश खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जायगा, तो दूसरी ओर एक दूसरे वर्ग ने यह मत प्रकट किया कि आयोजना में बड़े उद्योगों की समस्याओं की उपेक्षा हुई है और पूंजी लगाने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार और निजी क्षेत्रों पर छोड़ दी गयी। इसी वर्ग ने यह भी तर्क दिया कि उत्तर प्रदेश के लिये निर्धारित कुल धनराशि उसकी समस्याओं को हल करने की दृष्टि से नहीं निर्धारित की गयी है।

दिसम्बर १९६० में श्री चन्द्रभानु गुप्त के नेतृत्व में पदग्रहण करने वाले नये मंत्रि-मंडल का भी स्वागत हुआ। जिस साहस, योग्यता और विनम्रता से श्री गुप्त कार्य शुरू करते हैं, उसकी सराहना की गयी तथा सभी कांग्रेस सदस्यों और नागरिकों से यह अनुरोध किया गया कि वे सभी श्री गुप्त को सहयोग प्रदान करें। विधान मंडलीय और संगठन संबंधी शाखाओं की एकता कायम रखने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया।

प्रदेश कांग्रेस के मामलों पर काफी दिनों तक ध्यान दिया गया। कांग्रेस और देश दोनों की भलाई के लिये सस्था के भीतर झगड़ा हटाने तथा एकता बनाये रखने पर बल दिया गया।

नये मंत्रिमंडल के विरुद्ध, रखे गये अविश्वास के प्रस्ताव, जिसे विधान-मंडल ने विचार-विमर्श के बाद अस्वीकृत कर दिया था, का उल्लेख किया गया।

समाचार-पत्रों के एक वर्ग ने यह मत प्रकट किया कि अविश्वास का प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध असंतोष का प्रमाण है तथा दूसरे वर्ग ने यह अनुभव किया कि इसे प्रस्तुत करने में विरोधी दल ने अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वाह नहीं किया तथा उसने जो दलीलें दीं वे तर्क संगत नहीं थीं।

फरवरी, १९६१ में लोकसभा में पेश किये गये केन्द्रीय आय-व्यय की आलोचना और सराहना दोनों की गयी, जबकि समाचार-पत्रों के एक वर्ग ने इसे एक उत्साहबर्धक बजट माना है, दूसरी ओर कुछ पत्रों ने अप्रत्यक्ष करों पर असंतोष प्रकट किया तथा यह मत प्रकट किया कि इनसे साधारण जन और मध्यम वर्ग की कठिनाइयाँ बढ़ेंगी।

• सहकारी समितियों को कर से छूट देने संबंधी घोषणा की समाचार-पत्रों में काफी चर्चा हुई। यह सामान्य मत था कि सहकारी सस्थाओं को कर से मिलने वाली छूट का विरोध नहीं करना चाहिये क्योंकि सहकारी आन्दोलन सामान्य रूप में और व्यापारिक सहकारी संगठन विशेष तौर पर अभी हमारे देश में पूर्णतया विकसित नहीं हुए हैं। एक वर्ग सहकारी सस्थाओं के व्यापारिक लाभ को कर से छूट देने के पक्ष में नहीं था।

वर्ष १९६१-६२ में प्रस्तुत राज्य के आय-व्यय का मिला-जुला स्वागत हुआ। कुछ पत्रों ने यह विचार प्रकट किया कि इसने हमारी आशाओं को झूठा कर दिया है और इससे कर देने वालों का बोझ और बढ़ने की संभावना है। अन्य पत्रों का यह मत था कि राज्य की समृद्धि बढ़ेगी, साधारण जन पर बोझ नहीं बढ़ेगा, इसमें सन्निहित विकास की बहुमुखी योजनाओं के कारण हमें इसका स्वागत करना चाहिये।

कोयले की पूर्ति और उसके उद्योगों पर पड़ने वाले प्रभाव संबंधी कठिन स्थिति का उल्लेख किया गया। इस संबंध में कानपुर के उद्योगों के सहायतार्थ सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की सामान्य रूप से सराहना हुई तथा भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा होने की संभावना के विरुद्ध प्रदेश को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

अक्टूबर, १९६० से लेकर मार्च १९६१ तक की अवधि के लिये घोषित देश की नयी आयात नीति पर पत्रों ने व्यापक रूप से ध्यान दिया जबकि एक वर्ग ने यह अनुभव व्यक्त किया कि इससे देश के औद्योगीकरण को सहायता मिलेगी तथा योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। दूसरे वर्ग ने सावधानीपूर्वक प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे कि विस्तार और उत्पादन की क्षति न हो और वस्तुओं के मूल्य बढ़ने के कारण उत्पन्न होने वाली कमी से बढ़ने वाली कठिनाइयों से उपभोक्तागण बचे।

भारतीय वाणिज्य और उद्योग चेम्बर के ३३ वे अधिवेशन की कार्यवाही में काफी दिलचस्पी ली गयी। आयोजना के कार्यान्वयन में सरकार को निजी क्षेत्र द्वारा सहयोग दिये जाने के प्रश्न पर चेम्बर के अध्यक्ष द्वारा व्यक्त विचारों की सराहना की गयी। कुछ पत्रों ने यह कहा कि इस बात की आवश्यकता है कि सरकार और उद्योगपति अपनी नीतियों और कार्यों को समयानुसार समन्वित करें। एक वर्ग ने पूँजीपतियों पर इस तथ्य की उपेक्षा करने का आरोप लगाया कि मजदूर तब तक अधिक उत्पादन नहीं कर सकते, जब तक उद्योगी जीने की समुचित सुविधाएं नहीं दी जाती।

नवम्बर, १९६० में दिल्ली में हुए राज्यपालों के सम्मेलन पर पत्रों ने काफी ध्यान दिया। कुछ पत्रों ने इस पक्ष का समर्थन किया कि राज्यपालों को और ज्यादा अधिकार दिये जायें तथा कुछ ने यह मत प्रकट किया कि इससे स्थिति में शायद ही कोई सुधार हो। पत्रों ने ऐसी स्वस्थ परम्पराओं के निर्माण पर सामान्य रूप से बल दिया, जिनसे राज्यपालों और मंत्रियों के बीच एक स्वस्थ साझेदारी की भावना विकसित हो।

फूलबाग में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित होने का व्यापक रूप से स्वागत किया गया और यह कहा गया कि इस प्रयोग से भविष्य में प्रदेश को अनेक लाभ होने की संभावना है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अणुशक्ति केन्द्र स्थापित करने की संभावना संबंधी रिपोर्टों का सभी वर्गों के पत्रों ने स्वागत किया।

यह कहा गया कि भारत की जन-संख्या में वृद्धि (जिसका संकेत जन-संख्या के अस्थाई आंकड़ों से मिलता है) अच्छे खाने और चिकित्सा आदि के कारण बतायी गयी, क्योंकि इनके फलस्वरूप आयु बढ़ गयी थी। कुछ क्षेत्रों में यह चिंता प्रकट की गयी कि शायद नये आंकड़ों की वृद्धि में खाद्य-उत्पादन के लक्ष्यों में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो। इन क्षेत्रों में औद्योगिक और कृषि-उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया जिससे कि जीवन-स्तर गिरे नहीं। यह संकेत किया गया कि परिवार नियोजन आज एक बहुत बड़ी आवश्यकता है।

कि इसमें कर देने वालों के हितों का आवश्यक ध्यान नहीं रखा गया। किन्तु पत्रों के एक वर्ग ने मन्त्रि-मंडल को आपत्तियों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का समय देने के पूर्व ही रिपोर्ट प्रस्तुत करने की परम्परा का विरोध किया और यह मत प्रकट किया कि लोक सभा में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तरीके से प्रधान मंत्री और सुरक्षा मंत्री को परेशानी हो सकती है।

जून १९६० में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के विचार-विमर्श सम्बन्धी अपनी टिप्पणियों में पत्रों ने सामान्य रूप से कांग्रेस जन में एकता स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया, जबकि एक वर्ग ने यह कहा कि संगठन को सशक्त करने वाले कदम उठाये जायें, दूसरे वर्ग ने संतोष प्रकट करते हुए यह मत प्रकट किया कि अखिल भारतीय कांग्रेस ने ऐसे प्रस्ताव स्वीकृत कर लिये हैं जो कि ठोस हैं और जिनसे संस्था का सुचारु संचालन होगा।

जहाँ तक अखिल भारतीय कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन का प्रश्न है पत्रों ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति संबंधी प्रस्ताव पर विशेषरूप से ध्यान दिया। इस बात पर बल दिया गया कि दोनों प्रबल गुटों की पारस्परिक खींचतान को दृष्टि में रखते हुए भारत को तटस्थ नीति अपनानी चाहिये। अधिकांश समाचार-पत्रों ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के संबंध में प्रधान मंत्री के विचारों की पुष्टि की।

भावनगर कांग्रेस अधिवेशन के निश्चयों की ओर काफी ध्यान दिया गया। इस प्रस्ताव को अधिक प्रश्रय नहीं मिल सका, कि सार्वजनिक अथवा निर्वाचित पदों पर दस वर्ष तक जो लोग कार्य कर चुके हैं, उन्हें स्वेच्छापूर्वक वहाँ से हट जाना चाहिये।

संयुक्त-राष्ट्र की जनरल असेम्बली में किये गये प्रधान-मंत्री के भाषण और परिस्थितियों से विवश होकर पंच-राष्ट्रीय प्रस्ताव, जिसमें अमरीका और रूस के प्रधानों के बीच पुनः संपर्क स्थापित करने की बात कही गयी थी, कि वापसी पर व्यापक रूप से टीका-टिप्पणी की गयी। अफ्रीकी-एशियायी प्रस्ताव की वापसी को शीत-युद्ध की कूटनीति का विषय माना गया और इसे अवांछनीय घटना कहा गया।

संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेम्बली के १५ वें सत्र के अवसर पर अपने देश का प्रतिनिधि मंडल ले जाने का सोवियत प्रधान-मंत्री श्री खुश्चेव के निश्चय की आलोचना और सराहन दोनों की गयी। सभी समाचार-पत्रों ने इस सत्र को, जिसमें कई राज्यों के प्रधान भाग ले रहे थे, संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में युगांतरकारी माना। एक तीन व्यक्तियों के सचिवालय की स्थापना और संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय को न्यूयार्क से हटाने के संबंध में सोवियत प्रधान मंत्री के तर्कों का सामान्यतः विरोध किया गया। इस बात का संकेत किया गया कि ऐसे प्रस्ताव कभी स्वीकृत नहीं हो सकते थे और ऐसे प्रस्ताव संयुक्त-राष्ट्र को उपहासास्पद बना सकते थे।

जनेवा में निशस्त्रीकरण वार्ता की असफलता पर चतुर्विध खेद प्रकट किया गया। जहाँ कतिपय समाचार-पत्रों ने पश्चिम को निहित स्वार्थों तथा निशस्त्रीकरण के विषय में सुस्ती बरतने का दोषी ठहराया, वहाँ अन्य पत्रों ने निशस्त्रीकरण वार्ता से सोवियत संघ के अलग हो जाने को अदूरदर्शितापूर्ण और अनुचित कहा।

नवम्बर, १९६० में श्री जान एफ० कॅनेडी के अमरीकी राष्ट्रपति निर्वाचित होने का स्वागत किया गया।

जनवरी, १९६१ में महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप के भारत आगमन का सभी समाचार-पत्रों ने खुले हृदय से स्वागत किया। यह आशा व्यक्त की गयी कि इससे भारत और इंग्लैन्ड के संबंध और मजबूत होंगे।

जून, १९६० में रूस में राष्ट्रपति के अभ्यागम को एक महत्वपूर्ण घटना माना गया जो भारत-रूस मैत्री का द्योतक था और जिससे विश्व-शांति की दिशा में योग मिलने की आशा की जाती थी ।

समाचार-पत्रों ने संयुक्त अरब संघ के राष्ट्रपति और जापान के राजकुमार तथा उनकी साम्राज्ञी के अभ्यागत का स्वागत किया ।

लाओस के गृह-कलह और नेपाल के निर्वाचित मंत्रिमंडल के भंग कर दिये जाने पर खेद प्रकट किया गया ।

हाल ही में बेल्जियम से स्वतंत्र हुए कांगों में घटनाओं का रुख बराबर चिन्ता का विषय बना रहा । समाचार-पत्रों ने इसे एक नवजात-राष्ट्र के संक्रमणकालीन कठिनाइयों से अधिक माना और कतिपय पत्रों के विचार में तो वहाँ आजादी के बाद भी उपनिवेशवादी तत्व युद्धरत थे । कांगों में बेल्जियम के सैनिकों की उपस्थिति का विरोध किया गया किन्तु सुरक्षा परिषद् ने जिस गति और सरलता से कांगों में कार्रवाई की उसकी सराहना की गयी ।

कांगोई प्रधानमंत्री श्री पेट्रिस लुमुम्बा के कत्ल पर व्यापक रूप से क्षोभ प्रकट किया गया ।

समाचार-पत्रों ने जापान के समाजवादी नेता, श्री असानुमा के गुप्त वध की निन्दा की ।

समाचार-पत्रों ने संघ के गृह-मंत्री, पं० गोबिन्द बल्लभ पंत की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और उनकी स्मृति में पावन श्रद्धांजलि अर्पित की । पत्रों ने ससद सदस्य श्री फिरोज गांधी और हिन्दी के मान्य कवि तथा संसद-सदस्य पं० बालकृष्ण शर्मा नवीन की स्मृति में भी श्रद्धांजलि अर्पित की ।